



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026

वित्त मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2025-2026

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

प्रस्तावना

vii

अध्याय I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग	1
2. बजट प्रभाग	1
3. वित्तीय बाजार प्रभाग	5
4. वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा प्रभाग	23
5. वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग	28
6. अवसंरचना नीति और योजना (आईपीपी) प्रभाग	29
7. निवेश प्रभाग	35
8. एफबी एवं एडीबी प्रभाग	38
9. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध (आईआईआर) प्रभाग	42
10. सहायता लेखा और लेखा-परीक्षा प्रभाग (एएएडी)	49
11. प्रशासन प्रभाग	50
12. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	53
13. एकीकृत वित्त प्रभाग	58
14. सिक्का और मुद्रा प्रभाग	62
15. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)	68
अनुलग्नक	70
संगठन चार्ट	76

अध्याय II

व्यय विभाग

1. कार्मिक प्रभाग	77
2. लोक वित्त-राज्य प्रभाग	78
3. लोक वित्त केन्द्रीय प्रभाग	81
4. प्रापण नीति प्रभाग	82
5. राजभाषा	82
6. एकीकृत वित्त एकक (आईएफयू)	84
7. महालेखा नियंत्रक	84
8. मुख्य सलाहकार लागत	89
9. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम)	90
10. मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त)	92
11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	93
अनुबंध I से III	96
संगठनात्मक चार्ट	101

अध्याय III

राजस्व विभाग

1. संगठन एवं प्रकार्य	103
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	104
3. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड	118
4. राजस्व मुख्यालय-प्रशासन	135
5. एकीकृत वित्तीय एकक (आईएफयू)	178
अनुबंध - I - अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व	180
अनुबंध - II - दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व	191
अनुबंध - III - लेखा परीक्षा रिपोर्ट/पैरा का सार	199
अनुबंध - IV - संगठनात्मक चार्ट	202

अध्याय IV

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

I.	कार्य	203
II.	दृष्टिकोण	203
III.	लक्ष्य	203
IV.	संगठनात्मक ढांचा	203
V.	सीपीएसईस के विनिवेश से संबंधित मौजूदा नई नीति	203
VI.	सीपीएसई में मूल्य सृजन	205
VII.	विनिवेश कार्य निष्पादन	205
VIII.	अन्य पहलकदमियां	208
IX.	पूंजी प्रबंधन एवं लाभांश प्राप्ति	209
X.	दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए की गई पहल	209
XI.	जेण्डर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहलें	209
XII.	राजभाषा नीति	209
XIII.	ई-गवर्नेन्स	209
XIV.	लोक शिकायतों का निवारण	210
XV.	सतर्कता तंत्र	210
XVI.	सूचना का अधिकार, अधिनियम, 2005	210
XVII.	बेहतर प्रशासन के लिए की गई पहलें	210
XVIII.	लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां	210
XIX.	एकीकृत वित्त इकाई	210
XX.	विशेष अभियान 5.0	211
XXI.	न्यायलयी मुकदमों की निगरानी	211
	परिशिष्ट I	212
	परिशिष्ट II - संगठनात्मक ढांचा	214
	अनुबंध I एवं II	215
	अनुबंध III	216

अध्याय V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्तर्गत संगठन/संस्थान/विनियामक	217
2. संगठनात्मक चार्ट	219
3. अनुभागों के बीच कार्य आबंटन	220
4. बैंकिंग क्षेत्र में विकास	228
5. डिजिटल भुगतान	243
6. वित्तीय समावेशन	246
7. कृषि ऋण	259
8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल)	262
9. बीमा क्षेत्र	265
10. पेंशन क्षेत्र	269
11. वित्तीय संस्थान	278
12. विशेष न्यायालय और अभिरक्षक का कार्यालय	286
13. लोक शिकायतों का निपटान	286
14. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005	288
15. सतर्कता	289
16. ऋण वसूली अधिकरण/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण	289
17. साइबर सुरक्षा और फिनटेक	290
18. समन्वय	292
19. वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व	294
20. राजभाषा	294
21. लेखा परीक्षा पैरा	295
अनुबंध	296

अध्याय VI

लोक उद्यम विभाग

1. लोक उद्यम सर्वेक्षण	305
2. सीपीएसई का संगठन और स्वायत्तता	305
3. मजूरी नीति और जनशक्ति युक्तिकरण	306
4. सीपीएसई का वर्गीकरण	307
5. निगरानी और मूल्यांकन	308
6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)	309
7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनः अभिविन्यास स्कीम (आरडीसीआर)	309
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की नई नीति का कार्यान्वयन	311
9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)	311
10. कार्यकारी विकास कार्यक्रम	311
11. सीपीएसई में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य के लिए आरक्षण	312
12. राजभाषा नीति	313
13. एमएसई से सीपीएसई द्वारा अधिप्रापण	313
14. महत्वपूर्ण पहल	314
15. साइबर सुरक्षा अनुपालन रिपोर्ट	314
अनुलग्नक 1 संगठन चार्ट	316
अनुलग्नक 2 से 8 तक	317

प्रस्तावना

यह मंत्रालय छः विभागों से मिलकर बना है :-

- 1. आर्थिक कार्य विभाग
- 2. व्यय विभाग
- 3. राजस्व विभाग
- 4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
- 5. वित्तीय सेवाएं विभाग
- 6. लोक उद्यम विभाग

1. आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक विकास

पिछले एक साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई झटके लगे हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक साझेदारों से आयातित माल पर शुल्क लगाना है। हालांकि इन उपायों से शुरुआत में अनिश्चितता बढ़ी और वैश्विक विकास पूर्वानुमानों में कमी आई, लेकिन निकट भविष्य में आर्थिक गतिविधियां स्थिर बनी रहीं। आईएमएफ के जनवरी 2026 के अनुमानों के अनुसार, 2025 और 2026 दोनों वर्षों में वैश्विक विकास दर 3.2 प्रतिशत रहेगी, जो कि जनवरी 2025 के अनुमानों के लगभग समान है, हालांकि प्रशुल्क युद्ध शुरू होने के बाद जनवरी 2025 में इसे घटाकर 3.1 प्रतिशत कर दिया गया था। मुद्रास्फीति के भी नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। फिर भी, अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और उनके बीच अंतर्निहित कमजोरियां मध्यम से दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर असर डाल सकती हैं।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत में 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वास्तविक सकल लाभ वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में नाममात्र जीडीपी में 8.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

सेवा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि का एक प्रमुख चालक साबित हुई है, जिसमें प्रमुख उप-खंडों में लगभग 7.5 प्रतिशत से 9.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और निर्माण में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र (3.1 प्रतिशत) और बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र (2.1 प्रतिशत) में मध्यम वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मांग के परिप्रेक्ष्य से, स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो स्थिर ग्रामीण मांग और शहरी मांग में सुधार से प्रेरित है। सकल घरेलू

उत्पाद (जीडीपी) में पीएफसीई का हिस्सा (वर्तमान कीमतों पर) 2024-25 में 61.4 प्रतिशत से बढ़कर 2025-26 में 61.5 प्रतिशत होने का अनुमान है। यह हिस्सा 2002-03 के बाद से उच्चतम स्तर पर है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) (स्थिर कीमतों पर) में 2025-26 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

विकास के मांग पक्ष के कारक और जीडीपी में योगदान

व्यय के घटक	वास्तविक विकास दर (%)		नोमिनल जीडीपी में प्रतिशत हिस्सेदारी	
	वित्त वर्ष 25 (पीई)	वित्त वर्ष 26 (एफएई)	वित्त वर्ष 25 (पीई)	वित्त वर्ष 26 (एफएई)
निजी अंतिम उपभोग व्यय	7.2	7.0	61.4	61.5
सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	2.3	5.2	10.0	9.9
सकल स्थिर पूंजी निर्माण	7.1	7.8	29.9	30.0
निर्यात	6.3	6.4	21.2	21.5
जीडीपी	6.5	7.4		

वृद्धि के आपूर्ति पक्ष के कारक और सकल मूल्य वर्धन में योगदान

सेक्टर	वास्तविक विकास दर (%)		नोमिनल सकल मूल्य (जीवीए) में प्रतिशत हिस्सेदारी	
	वर्ष 25 (पीई)	वर्ष 26 (एफएई)	वर्ष 25 (पीई)	वर्ष 26 (एफएई)
कृषि, पशुपालन, वानिकी और मत्स्य पालन	4.6	3.1	17.8	17.9
उद्योग	5.9	6.2	27.8	27.1
खनन और उत्खनन	2.7	-0.7	1.9	1.8
विनिर्माण	4.5	7.0	14.3	13.9
बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं	5.9	2.1	2.8	2.7
निर्माण	9.4	7.0	8.8	8.8
सेवाएं	7.2	9.1	54.4	54.9
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं	6.1	7.5	17.6	17.5
वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं	7.2	9.9	22.8	22.9
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.9	9.9	14.0	14.5
मूल कीमतों पर सकल मूल्य (जीवीए)	6.4	7.3		

कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन

वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमानों के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2024-25 के दौरान रिकॉर्ड 3577.32 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 में हासिल किए गए 3322.98 लाख मीट्रिक टन के खाद्यान्न उत्पादन से 254.34 लाख मीट्रिक टन अधिक है। चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न (बाजरा) के अच्छे उत्पादन के कारण खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है।

2024-25 के दौरान कुल चावल उत्पादन का अनुमान रिकॉर्ड 1501.84 लाख मीट्रिक टन है। यह पिछले वर्ष के 1378.25 लाख मीट्रिक टन चावल उत्पादन से 123.59 लाख मीट्रिक टन अधिक है। 2024-25 के दौरान गेहूं उत्पादन का अनुमान रिकॉर्ड 1179.45 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष के 1132.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं उत्पादन से 46.53 लाख मीट्रिक टन अधिक है। मक्का और श्री अन्न का उत्पादन क्रमशः 434.09 लाख मीट्रिक टन और 185.92 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह क्रमशः 376.65 लाख मीट्रिक टन और 175.72 लाख मीट्रिक टन था।

देश में 2024-25 के दौरान तिलहन का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 429.89 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो 2023-24 में उत्पादित 396.69 लाख मीट्रिक टन से 33.20 लाख मीट्रिक टन अधिक है। तिलहन उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि मूंगफली और सोयाबीन के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण हुई है, जिसका अनुमान क्रमशः 119.42 लाख मीट्रिक टन और 152.68 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष के 101.80 लाख मीट्रिक टन और 130.62 लाख मीट्रिक टन की तुलना में क्रमशः 17.62 लाख मीट्रिक टन और 22.06 लाख मीट्रिक टन अधिक है। सरसों और रेपसीड का उत्पादन 126.67 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है।

कृषि उत्पादन (लाख टन)					
फसलें	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
चावल	1243.68	1294.71	1357.55	1378.25	1501.84
गेहूं	1095.86	1077.42	1105.54	1132.92	1179.45
पोषक/मोटे अनाज	513.24	511.01	573.19	569.26	639.21
कुल दालें	254.63	273.02	260.58	242.46	256.83
कुल नौ तिलहन	359.46	379.63	413.55	396.69	429.89
कपास #	352.48	311.18	336.60	325.22	297.24
स्रोत: कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग नोट: अंतिम अनुमान (दिनांक 20 नवंबर 2025 तक) # लाख गांठों में, 1 गांठ = 170 किलोग्राम					

गन्ने का उत्पादन 4546.11 लाख टन होने का अनुमान है। कपास का उत्पादन 297.24 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम की) होने का अनुमान है, और जूट और मेस्ता का उत्पादन 88.02 लाख गांठ (प्रत्येक गांठ 180 किलोग्राम की) होने का अनुमान है।

भारतीय पशुधन क्षेत्र तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है, जिसने पिछले दशक में निरंतर और मजबूत वृद्धि दर्ज की है। पशुधन क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 2014-15 से 2023-24 तक लगभग 195 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसकी वर्तमान कीमतों पर 12.77 प्रतिशत की सीएजीआर है।

मौजूदा कीमतों पर, पशुधन से कुल सकल मूल्य (जीवीए) 2014-15 में ₹5.10 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹15.06 लाख करोड़ हो गया। इन वर्षों में दूध समूह का योगदान सबसे अधिक रहा है, जिसका उत्पादन मूल्य 2014-15 में ₹4.96 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹12.21 लाख करोड़ हो गया है। यह वृद्धि बेहतर मूल्य श्रृंखलाओं के बीच दूध उत्पादन में वृद्धि के कारण हुई है। अन्य प्रमुख पशुधन उत्पादों में, मांस और अंडों के सकल मूल्य में पिछले दशक में लगातार वृद्धि देखी गई है। मांस उत्पादन का मूल्य 2014-15 में ₹1.54 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹4.72 लाख करोड़ हो गया है, जबकि अंडों का उत्पादन इसी अवधि में ₹0.24 लाख करोड़ से बढ़कर ₹0.66 लाख करोड़ हो गया है।

कृषि एवं संबद्ध सकल लाभ मूल्य (जीवीए) में पशुधन क्षेत्र की हिस्सेदारी में भी पिछले 10 वर्षों में वृद्धि देखी गई है, और 2023-24 में इस क्षेत्र का योगदान 31 प्रतिशत रहा, जो 2014-15 में 24 प्रतिशत था। यह बदलाव कृषि आय में पशुधन की बढ़ती भूमिका का एक महत्वपूर्ण संकेत है।

भौतिक उत्पादन के संदर्भ में, दूध उत्पादन 2014-15 में 146.31 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 247.87 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से गाय के दूध उत्पादन के कारण हुई, जो 2014-15 में 66.42 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग दोगुना होकर 132.69 मिलियन टन हो गया। भैंस के दूध उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हुई और यह 2014-15 में 74.71 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 106.95 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 43 प्रतिशत की वृद्धि है।

भारत में मांस उत्पादन में पिछले एक दशक में निरंतर और उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। कुल उत्पादन 2024-25 में बढ़कर 10.50 मिलियन टन हो गया, जो 2014-15 में दर्ज 6.69 मिलियन टन से 57 प्रतिशत अधिक है। मुर्गी मांस का इसमें प्रमुख योगदान रहा है, जो अब कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। भारत में अंडा उत्पादन 2014-15 और 2024-25 के बीच लगभग दोगुना होकर 149.11 बिलियन अंडे तक पहुंच गया 90 प्रतिशत की वृद्धि, जो मुख्य रूप से व्यावसायिक मुर्गी फार्मों के विकास और घरेलू मुर्गी पालन की उत्पादकता में लगातार सुधार के कारण हुई है। भारत में ऊन उत्पादन में पिछले एक दशक में उतार-चढ़ाव के बावजूद संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रुझान देखा गया है, जिसका कुल उत्पादन 2024-25 में 34.57 मिलियन किलोग्राम रहा।

जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई

जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई (सीसीएफयू) जलवायु परिवर्तन वित्त से संबंधित सभी मामलों के लिए वित्त मंत्रालय में नोडल प्रभाग है। यह जलवायु वित्त के मुद्दों पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फोरमों में मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत जलवायु वित्त पर अंतरराष्ट्रीय वार्ता में देश का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह इकाई ब्रिक्स और जी20 कार्य समूहों को जलवायु वित्त पर इनपुट प्रदान करती है, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप (ईटीडब्ल्यूजी), सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (एसएफडब्ल्यूजी) और फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) शामिल हैं। यह जलवायु परिवर्तन वित्त और जलवायु कार्बाई के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय साधनों के उपयोग पर भारत सरकार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त विवरण और स्थिति तैयार करता है।

सीसीएफयू राष्ट्रीय सरकारों द्वारा जलवायु वित्त पर प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करता है जो यूएनएफसीसीसी के पक्षकार हैं और यूएनएफसीसीसी, सीओपी सीएमए के तहत वार्ता में भाग लेते हैं, और वैश्विक प्लास्टिक संधि के तहत वित्तीय तंत्र पर चर्चा में भाग लेते हैं। यह इकाई नीतिगत समर्थन करती है और आर्थिक समीक्षा, नीति आयोग के परिवर्तन मार्ग, भारत का कार्बन बाजार (सीसीटीएस), पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 और 6.4 के तहत सहकारी दृष्टिकोण, वित्तीय खुलासे और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ढांचा सहित प्रमुख क्षेत्रों पर आंतरिक विवरण तैयार करती है। यह पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (एनडीआईपीए), पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष समिति (एआईपीए), राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) 2035, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएम) पर अंतर-मंत्रालयी कार्य बल सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समितियों के लिए भारत की स्थिति तैयार करने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), और भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी-आईसीएम) में इनपुट भी प्रदान करता है।

यह इकाई जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन बाजारों और अन्य उभरते जलवायु संबंधी मुद्दों पर विश्लेषणात्मक कार्य के लिए जिम्मेदार है। यह आर्थिक समीक्षा के लिए जलवायु और पर्यावरण अध्याय का मसौदा तैयार करता है और ग्रीन क्लाइमेट फंड

(जीसीएफ), ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (जीईएफ) और बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच करता है। यह जलवायु परिवर्तन वित्त से संबंधित घरेलू प्रस्तावों की भी समीक्षा करता है और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जैसी राष्ट्रीय नीतियों पर इनपुट प्रदान करता है।

नई पहल

जलवायु कार्यों के लिए संसाधन जुटाना, इकाई का व्यापक उद्देश्य होने के नाते, आर्थिक कार्य विभाग की विभिन्न पहलों का नेतृत्व करता है। भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण का एक मसौदा तैयार किया गया था और हितधारकों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। इनकी जांच की जा रही है। इकाई को जलवायु वित्त के लिए वर्गीकरण के विकास के संबंध में केंद्रीय बजट 2024-25, पैरा सं.104 के कार्यान्वयन का काम सौंपा गया है। यह इकाई भारत में जलवायु कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों के आकलन के संबंध में आर्थिक कार्य विभाग के एडीबी सहायता प्राप्त अध्ययन के लिए नोडल भी है।

इकाई वर्ष 2018 से सभी आवश्यक आधिकारिक कार्यों के लिए ई-फाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही है। इकाई की पुरानी भौतिक फाइलों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में बदल दिया गया है और अप्रासंगिक पुरानी फाइलों को हटा दिया गया है।

सतत वित्त प्रभाग

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

भारत वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) का संस्थापक सदस्य है। भारत जीईएफ फंड का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। 2022 से 2026 तक चलने वाले संसाधनों की आठवीं पुनःपूर्ति (जीईएफ-8) के तहत, भारत ने 18.75 मिलियन अमरीकी डालर का वादा किया है। नौवें पुनःपूर्ति चक्र (जीईएफ-9) के लिए बातचीत वर्तमान में चल रही है, जो 2026 से 2030 की अवधि के लिए संसाधनों के स्तर को निर्धारित करेगी।

अंतरराष्ट्रीय सतत वित्त प्लेटफार्म (आईपीएसएफ)

अंतरराष्ट्रीय सतत वित्त प्लेटफार्म (आईपीएसएफ) को यूरोपीय आयोग द्वारा 18 अक्टूबर 2019 को आईएफएफ मुख्यालय, वाशिंगटन डीसी में लॉन्च किया गया था। भारत अर्जेंटीना, चिली, चीन, कनाडा, केन्या,

मोरक्को और यूरोपीय संघ के साथ संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसके लॉन्च के बाद से ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एसएआर, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सेनेगल, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड और यूके आईपीएसएफ में शामिल हो गए हैं। आईपीएसएफ के कार्य को बारह पर्यवेक्षकों द्वारा सूचित किया जाता है जिसमें आईएमएफ, विश्व बैंक समूह, ओईसीडी, यूएनडीपी, यूएनडीपी, ईबीआरडी, ईआईबी आदि शामिल हैं। आईपीएसएफ नीति निर्माताओं के बीच संवाद के लिए एक बहुपक्षीय फोरम प्रदान करता है जो सूचना के आदान-प्रदान और प्रसार के लिए स्थायी वित्त विनियामक उपायों को विकसित करने, सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने, विभिन्न पहलों की तुलना करने और स्थायी वित्त के लिए बाधाओं और अवसरों की पहचान करने के प्रभारी हैं। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से संधारणीय निवेश की दिशा में निजी पूंजी जुटाना है।

भारत यूके सतत वित्त फोरम

वर्ष 2020 में 10वीं भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता में, भारत और यूके ने सतत वित्त पर यूके और भारत के बीच गहरे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक द्विपक्षीय सतत वित्त फोरम स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। तदनुसार, फोरम की स्थापना वित्त मंत्रालयों/कोषागार के सदस्यों और दोनों पक्षों के अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ की गई थी। भारत के प्रतिनिधियों में एमएनआरडी, एमओईएफसीसी, विद्युत मंत्रालय, आरबीआई, सेबी के अधिकारी और यूके भारत सतत वित्त कार्य समूह में सह-अध्यक्ष (भारत की ओर से) शामिल हैं।

जलवायु वित्त अग्रणी पहल (सीएफएल) भारत

जलवायु वित्त अग्रणी पहल (सीएफएल) भारत भागीदारी को 2 सितंबर 2021 को आयोजित 11^{वां} भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता में लॉन्च किया गया था। सीएफएलआई जलवायु महत्वाकांक्षा और समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत श्री माइकल ब्लूमबर्ग के नेतृत्व में अग्रणी वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। सीएफएलआई भारत का लक्ष्य विशिष्ट निम्न-कार्बन क्षेत्रों में सतत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत में पूंजी जुटाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट्स और मौजूदा स्थायी वित्त पहलों के साथ काम करना है। एन. चंद्रशेखरन, अध्यक्ष,

टाटा संस और शेमारा विक्रमनाथ, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मैक्वेरी ग्रुप सीएफएलआई भारत के सह-अध्यक्ष हैं।

किसी विशेष क्षेत्र के विकास के लिए वर्ष के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण विकास/नीतिगत निर्णय, जिसमें सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार और "समावेशी विकास" सुनिश्चित करने के लिए पहल शामिल हैं

डीईए-यूएनडीपी एसएफएफ परियोजना: आर्थिक कार्य विभाग ने हाल ही में सतत वित्त सुविधा (एसएफएफ) को मंजूरी दी है, जिसे भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 सतत वित्त कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी) की सिफारिशों को लागू करने के लिए यूएनडीपी के परामर्श से विकसित किया गया था। एसएफएफ विशेष रूप से एसएफडब्ल्यूजी की दो प्राथमिकताओं पर सिफारिशों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे (क) सामाजिक प्रभाव साधनों को बढ़ाना और (ख) अभिनव सामाजिक प्रभाव साधनों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करके जी20 सतत वित्त तकनीकी सहायता कार्य योजना (टीएएपी)। इस परियोजना का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 4 वर्षों (2024-28) में न्यूनतम 8 वित्तपोषण साधनों को तैयार करना है, जिससे सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

उद्योगों का प्रदर्शन

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान कुल औद्योगिक विकास दर 3.3 प्रतिशत (अस्थायी) रही, जबकि वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर)¹ में यह 4.1 प्रतिशत थी।

तीन प्रमुख क्षेत्रों में से, विनिर्माण वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान औद्योगिक विकास का प्रमुख कारक बना रहा। उपयोग-आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान विकास मुख्य रूप से अवसंरचना/निर्माण सामग्री, पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं द्वारा संचालित था।

¹नवंबर 2025 महीने के लिए आईआईपी और उपयोग-आधारित सूचकांक के त्वरित अनुमान पर एमओएसपीआई प्रेस विज्ञप्ति <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2209434&reg=3&lang=1> पर उपलब्ध है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि (प्रतिशत में) (आधार वर्ष 2011-12=100)				
उद्योग समूह	वजन	2024-25	2024-25 (अप्रैल-नवंबर)	2025-26 (अप्रैल-नवंबर)*
खनन	14.37	3.0	3.3	-0.9
विनिर्माण	77.63	4.1	4.1	4.4
बिजली	7.99	5.2	5.3	-0.2
प्राथमिक वस्तुएँ	34.05	3.9	4.0	0.3
पूँजीगत वस्तुएँ	8.22	5.6	4.4	7.2
मध्यवर्ती वस्तुएँ	17.22	4.3	4.3	5.3
अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ	12.34	6.7	6.1	9.0
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	12.84	7.9	8.8	4.6
उपभोक्ता अटिकाऊ वस्तुएँ	15.33	-1.5	-0.5	-1.0
सामान्य सूचकांक		4.0	4.1	3.3
*अस्थायी स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)।				

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सूचकांक (आईआईपी) में लगभग 40 प्रतिशत भार रखने वाले आठ प्रमुख उद्योगों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - के सूचकांक में वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) में 2.4 प्रतिशत (अस्थायी) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में यह वृद्धि 4.4 प्रतिशत थी। नवंबर 2025 में सीमेंट, इस्पात, उर्वरक और कोयले के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

आठ प्रमुख उद्योगों में वृद्धि (प्रतिशत में)				
उद्योग समूह	वजन	2024-25	2024-25 (अप्रैल-नवंबर)	2024-25 (अप्रैल-नवंबर)
कोयला	10.33	5.1	6.4	-1.4
कच्चा तेल	8.98	-2.2	-2.3	-1.3
प्राकृतिक गैस	6.88	-1.2	1.1	-3.0
पेट्रोलियम शोधन उत्पाद	28.04	2.8	2.8	0.2
उर्वरक	2.63	2.9	1.6	1.3
इस्पात	17.92	6.8	6.7	9.7
सीमेंट	5.37	6.3	3.1	8.2
बिजली	19.85	5.2	5.3	-0.3
समग्र विकास दर		4.5	4.4	2.4
*अस्थायी स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति, जो https://eaindustry.nic.in/eight_core_infra/eight_infra.pdf पर उपलब्ध है।				

सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन

पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र में 2025-26 के दौरान 9.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। दो उप-क्षेत्रों - 'वित्तीय, अचल

संपत्ति और पेशेवर सेवाएं' और 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं' - में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित 'व्यापार, आतिथ्य, परिवहन, संचार और संबंधित सेवाएं' में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कुल रोजगार में सेवाओं का हिस्सा लगभग 30 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2026 की पहली दो तिमाहियों के लिए पीएलएफएस के आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी रोजगार में सेवाओं का हिस्सा बढ़कर औसतन 61.9 प्रतिशत हो गया, जो वित्त वर्ष 2021-2022 के औसत 61.7 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान सेवा क्षेत्र में अपेक्षाकृत मजबूत भर्ती हुई थी। इसी के अनुरूप, अप्रैल-जुलाई वित्त वर्ष 2026 के लिए ईपीएफओ के आंकड़े औपचारिक रोजगार सृजन में निरंतरता दर्शाते हैं, जिसमें सेवाओं का निवल रोजगार वृद्धि में 51.7 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें विशेषज्ञ सेवाएं, व्यापारिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और सफाई सेवाएं प्रमुख हैं। ये सभी रुझान मिलकर वैश्विक अनिश्चितता के बीच श्रम बाजार की मजबूती को सुनिश्चित करने में सेवाओं की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हैं।

भारत के सेवा निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। 2025-26 की पहली छमाही में सेवा निर्यात 199.0 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाओं का भारत के कुल सेवा निर्यात में लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा था।

खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति के रुझान

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) द्वारा आंकी गई खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2025 में 4.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) में 1.7 प्रतिशत हो गई। जबकि मुख्य मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) में बढ़ी, कृषि उत्पादन में वृद्धि, बुवाई में वृद्धि और बागवानी उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) में 0.04 प्रतिशत थी। डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) में औसतन (-)0.79 प्रतिशत रही।

खुदरा और थोक मूल्य मुद्रास्फीति में रुझान (प्रतिशत में)		
वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति - सामान्य	थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति
2019-20	4.8	1.7
2020-21	6.2	1.3
2021-22	5.5	1.3
2022-23	6.7	9.4
2023-24	5.4	-0.7
2024-25	4.6	2.3
2025-26 (अप्रैल-दिसंबर)	1.7	0.04

स्रोत: एसपीआई मंत्रालय और पीआईआईटी विभाग

मौद्रिक विकास

वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर 2024) के दौरान, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अप्रैल से दिसंबर 2025 तक अपनी बैठकों में रेपो दर में संचयी रूप से 100 आधार अंक की कमी की। दिसंबर 2025 तक, रेपो दर 5.25 प्रतिशत रहा है। मौजूदा और अपेक्षित मुद्रास्फीति-विकास की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने जून 2025 में अपनी प्रवृत्ति 'अनुकूल' से 'तटस्थ' में बदल दी। तब से यह तटस्थ प्रवृत्ति अभी भी है। आरबीआई ने नकद आरक्षित अनुपात में 100 आधार अंक की कमी की घोषणा की, जिसे निवल मांग और सावधि देनदारियों के 3.0 प्रतिशत तक लाया गया, जिसे सितंबर-नवंबर 2025 के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इस निर्णय से दिसंबर 2025² तक बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹2.5 लाख करोड़ की प्राथमिक तरलता जारी होने की आशा है।

तरलता की स्थिति और इसका प्रबंधन

अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न मापों, अर्थात् तरलता के विभिन्न स्तरों को दर्शाने वाले विभिन्न समुच्चयों में रुझान का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि मौद्रिक आधार, अर्थात् मुद्रा का सबसे तरल रूप (एमओ), 31 दिसंबर 2025 तक वार्षिक आधार पर 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 27 दिसंबर 2024 तक यह 4.9 प्रतिशत थी। एम3 में वृद्धि, एक गैर-बैंक के बैंक में विलय (1 जुलाई 2023 से प्रभावी) के प्रभाव को छोड़कर, 31 दिसंबर 2025 तक वार्षिक आधार पर 12.1 प्रतिशत थी, जबकि एक वर्ष पहले यह 9 प्रतिशत थी। घटक-वार³, कुल जमा सबसे महत्वपूर्ण घटक था और एम3 के विस्तार में इसका सबसे अधिक योगदान था। स्रोतों⁴ में, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण एम3 में वृद्धि का एक प्रमुख योगदानकर्ता था। 31 दिसंबर 2025 तक, मनी मल्टीप्लायर (एमएम)⁵, यानी एम3 और एम0 का अनुपात, एक वर्ष पहले के 5.70 के मुकाबले 6.21 था।

² आरबीआई की 6 जून 2025 की प्रेस विज्ञप्ति, 'गवर्नर का वक्तव्य', <https://tinyurl.com/yymx7rsdy1>

³ व्यापक मुद्रा के घटक = जनता के पास मुद्रा + कुल जमा (बैंकों में मांग जमा + बैंकों में सावधि जमा + रिजर्व बैंक में 'अन्य' जमा)।

⁴ व्यापक मुद्रा के स्रोत = सरकार को बैंकों का शुद्ध ऋण + वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंकों का ऋण + बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां + जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देनदारियां - बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देनदारियां।

⁵ मुद्रा गुणक केंद्रीय बैंक की मुद्रा की प्रत्येक इकाई से बैंकिंग प्रणाली द्वारा उत्पन्न अधिकतम राशि को मापता है।

रिवर्स रेपो/स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा (जो विश्लेषणात्मक रूप से केंद्रीय बैंक के पास बैंकों की जमा राशि के समान है) को समायोजित करने के बाद, 31 दिसंबर 2025 तक समायोजित एमएम घटकर 6.0 हो गया।

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात वित्त वर्ष 2018 में अपने उच्चतम स्तर से लगातार घटते हुए सितंबर 2025 के अंत तक बहुदशकीय निम्नतम स्तर 2.2 प्रतिशत पर पहुंच गया है। सितंबर 2025 तक, एससीबी के लिए राइट-ऑफ-टू-जीएनपीए अनुपात 33.5 प्रतिशत रहा। अर्धवार्षिक अपव्यय अनुपात 0.7 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। हाल के वर्षों में कम जीएनपीए और उच्च प्रावधानों के संघर्ष ने निवल एनपीए में गिरावट में भी योगदान दिया है, जो सितंबर 2025 के अंत तक 0.5 प्रतिशत है। आस्ति गुणवत्ता मापदंडों में सुधार सभी व्यापक आर्थिक क्षेत्रों और सभी प्रमुख बैंक समूहों में देखा गया।

अगस्त से नवंबर 2015 तक आयोजित आस्ति गुणवत्ता समीक्षा के बाद की अवधि में एससीबी (एससीबी) के सीआरएआर (पूजी-से-जोखिम-भारित आस्ति अनुपात) में वृद्धि हुई है। सितंबर 2025 के अंत में, एससीबी का सीआरएआर 17.2 प्रतिशत और कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी अनुपात 14.8 प्रतिशत रहा। सभी बैंक समूहों में सीआरएआर और सीईटी-1 पूंजी अनुपात मजबूत बने रहे।

सितंबर 2025 में एससीबी के मुनाफे में वृद्धि की गति धीमी हो गई, हालांकि कर पश्चात लाभ में सितंबर 2025 तक 3.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। एससीबी का इक्विटी पर प्रतिफल सितंबर 2025 में 12.5 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2025 में यह 13.6 प्रतिशत था। एससीबी का आस्ति पर प्रतिफल सितंबर 2025 में 1.3 प्रतिशत रहा, जबकि मार्च 2025 में यह 1.4 प्रतिशत था। निवल ब्याज मार्जिन में मार्च 2025 की तुलना में सितंबर 2025 में 20 आधार अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण निधि की लागत की तुलना में आस्ति पर प्रतिफल में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट थी। एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात मार्च 2025 के 76.3 प्रतिशत की तुलना में सितंबर 2025 में 76.0 प्रतिशत रहा।

ऋण वृद्धि

दिसंबर 2025 तक, एससीबी द्वारा बकाया ऋण में वृद्धि दिसंबर 2024 के 11.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गई।

28 नवंबर, 2025 तक, कृषि क्षेत्र को बैंक ऋण में वार्षिक आधार पर 8.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो एक वर्ष पहले के 15.3 प्रतिशत से कम है। औद्योगिक ऋण में वार्षिक आधार पर 9.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 8.3 प्रतिशत थी। बड़े और मध्यम उद्योगों को ऋण वितरण में वृद्धि धीमी रही है। बड़े उद्योगों के लिए, ऋण वितरण में वृद्धि वार्षिक आधार पर 4.6 प्रतिशत रही, जो एक वर्ष पहले 6.4 प्रतिशत थी। वहीं, मध्यम उद्योगों के लिए यह वृद्धि 15.7 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष

पहले यह 20.0 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए इसमें वृद्धि हुई है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए, ऋण वितरण में वार्षिक आधार पर 24.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एक वर्ष पहले यह वृद्धि 10.2 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों में, पेय पदार्थ, तंबाकू और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में ऋण वितरण में वार्षिक आधार पर 22.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और परमाणु ईंधन, रत्न और आभूषण तथा खनन और उत्खनन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी ऋण वितरण में उच्च वृद्धि दर्ज की गई।

सेवा और व्यक्तिगत ऋण क्षेत्रों में ऋण वृद्धि दो अंकों में बनी रही, हालांकि नवंबर 2025 में इसमें कुछ कमी आई और यह क्रमशः 11.7 प्रतिशत और 12.8 प्रतिशत रही, जबकि एक वर्ष पहले यह 12.8 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत थी। गैर-राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) को दिए गए ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर 2025 में 9.5 प्रतिशत हो गई। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में, वाहन ऋण में वृद्धि एक वर्ष पहले के 10.3 प्रतिशत की तुलना में नवंबर 2025 में बढ़कर 12.4 प्रतिशत हो गई। आवास ऋण में वृद्धि नवंबर 2024 के 12.2 प्रतिशत से घटकर नवंबर 2025 में 9.9 प्रतिशत हो गई।

पूंजीगत बाजार में विकास

भारत की विकास गाथा में पूंजीगत बाजार की केंद्रीय भूमिका है, जो वास्तविक अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी निर्माण को गति प्रदान करती है, घरेलू बचत के वित्तीयकरण को बढ़ाती है और निधि सृजन को सक्षम बनाती है। अमेरिकी टैरिफ प्रतिबंधों, वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आशा से कम कॉर्पोरेट आय और विदेशी पूंजी बहिर्वाह ने सामूहिक रूप से बाजार की स्थिति को प्रभावित किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में व्यक्तिगत आयकर में कटौती, जीएसटी में संशोधन, मौद्रिक नीति में नरमी, घटती मुद्रास्फीति और बेहतर कॉर्पोरेट प्रदर्शन ने इस अवधि के दौरान बाजार को सहारा दिया।

अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स ने क्रमशः लगभग 11.1 प्रतिशत और 10.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, जो पिछले वित्तीय वर्ष में देखी गई मजबूत तेजी के बाद सुधार और समेकन की अवधि को दर्शाती है। वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) में प्राथमिक बाजार लचीला और जीवंत बना रहा है और प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश जारी करने में विश्व में अग्रणी रहा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का यह सशक्त प्रदर्शन सुदृढ़ वृहद आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, निवेशकों की प्रबल भागीदारी और सेबी द्वारा विनियामक फ्रेमवर्क में निरंतर सुधार के कारण संभव हुआ। भारत के प्राथमिक बाजारों ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को आकर्षित किया, जिससे वैश्विक पूंजी निर्माण के प्रमुख चालक के रूप में देश की स्थिति और मजबूत हुई।

वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान प्राथमिक बाजारों से जुटाई गई कुल धनराशि, जिसमें ऋण और इक्विटी दोनों शामिल हैं, ₹10.7 लाख करोड़ रही। पिछले पांच वर्षों में, वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, भारत के प्राथमिक बाजारों ने बचत

को उत्पादक निवेशों में लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके तहत इक्विटी और ऋण निर्गमन के माध्यम से कुल ₹53 लाख करोड़ जुटाए गए। इसमें से ₹14 लाख करोड़ इक्विटी निर्गमन के माध्यम से जुटाए गए।

वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) में आईपीओ की मात्रा वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक थी, और जुटाई गई धनराशि वित्त वर्ष 2025 की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक थी। मुख्य बोर्ड पर सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 69 से बढ़कर 94 हो गई, और जुटाई गई धनराशि ₹1,46,534 करोड़ से बढ़कर ₹1,60,273 करोड़ हो गई। वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) में आईपीओ गतिविधि की एक उल्लेखनीय विशेषता ऑफर-फॉर-सेल घटक थी, जो कुल आय का 58 प्रतिशत थी।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र में भी सकारात्मक रुझान जारी रहा, जो उभरते उद्यमों में निवेशकों की निरंतर रुचि और बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) में सूचीबद्ध एसएमई कंपनियों की संख्या वित्त वर्ष 2025 (दिसंबर 2024 तक) के 190 से बढ़कर 217 हो गई। जुटाई गई राशि ₹7,453 करोड़ से बढ़कर ₹9,635 करोड़ हो गई। अपनी स्थापना के बाद से, बीएसई और एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 1,380 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हो चुकी हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर ₹35,000 करोड़ से अधिक की राशि जुटाई है, जो औपचारिक पूंजीगत बाजार फ्रेमवर्क के तहत भारत के उद्यमशीलता आधार के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता करता है। इनमें से लगभग 350 कंपनियां मेनबोर्ड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो चुकी हैं।

वित्त वर्ष 2026 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान, 235 लाख डीमैट खाते जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 21.6 करोड़ से अधिक हो गई। सितंबर 2025 में अद्वितीय निवेशकों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंचना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिनमें से लगभग एक चौथाई महिलाएं थीं। म्यूचुअल फंड उद्योग का भी विस्तार हुआ, दिसंबर 2025 के अंत तक 5.9 करोड़ अद्वितीय निवेशक थे, जिनमें से 3.5 करोड़ (नवंबर 2025 तक) गैर-स्तरीय प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शहरों से थे।

वैश्विक व्यापार रुझान

आईएमएफ के विश्व आर्थिक आउटलुक (जनवरी 2026) के अनुसार, विश्व व्यापार में वृद्धि वर्ष 2025 में 4.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 2.6 प्रतिशत होने और फिर वर्ष 2027 में बढ़कर 3.1 प्रतिशत होने की आशा है। इस रुझान का कारण व्यापार की अग्रिम तैनाती और नई नीतियों के जवाब में व्यापार प्रवाह में समायोजन है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए, व्यापार की मात्रा वर्ष 2025 में 3.0 प्रतिशत, वर्ष 2026 में 1.9 प्रतिशत और वर्ष 2027 में 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, व्यापार की स्थिति वर्ष 2025 में 5.7 प्रतिशत, वर्ष 2026 में 3.6 प्रतिशत और वर्ष 2027⁶ में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024, वित्त वर्ष 2025 और वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) के लिए भारत के व्यापारिक गतिविधियों का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है। देश का व्यापारिक प्रदर्शन गतिशील वैश्विक व्यापारिक परिवेश के बीच अच्छी स्थिति को दर्शाता है।

⁶ डब्ल्यूटीओ की ग्लोबल ट्रेड आउटलुक और स्टेटिक्स, अक्टूबर 2025 <https://tinyurl.com/bdz3mr7p>.

भारत के व्यापारिक रुझान						
	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2025	वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2025 में परिवर्तन	वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर)	वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) (पी)	वित्त वर्ष 2025(अप्रैल-दिसंबर) से वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) अंतिम
कुल निर्यात	437.1	437.7	0.1	284.6	291.8	2.5
कुल आयात	678.2	721.2	6.3	487.9	515.1	5.6
पीओएल आयात	178.7	185.8	3.9	127.8	121.0	-5.3
गैर-पीओएल आयात	499.5	535.4	7.2	360.1	394.1	9.4
व्यापार शेष	-241.1	-283.5	17.6	-203.3	-223.3	9.8
स्रोत: एफटीपीए, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय: https://tinyurl.com/3b3txy						
नोट: पी: अंतिम						

वित्त वर्ष 2024 में 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 283.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हो गया। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान, व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 224.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 248.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2026 के पहले आठ महीनों में माल निर्यात में 2.4 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) और माल आयात में 5.9 प्रतिशत (वार्षिक आधार पर) की वृद्धि थी।

वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) के दौरान भुगतान संतुलन में घटनाक्रम भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) और वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) के लिए भारत के भुगतान संतुलन में घटनाक्रम नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किए गए हैं।

भारत के भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)						
	वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) पीआर			वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) पी		
	क्रेडिट	डेबिट	निवल	क्रेडिट	डेबिट	निवल
क. चालू खाता	491.8	517.1	-25.3	523.1	538.1	-15.0
1. वस्तु	215.8	364.1	-148.3	222.1	378.4	-156.3
जिसमें:						
पीओएल	36.6	93.1	-56.4	30.4	92.1	-61.7
2. सेवाएं	182.0	97.7	84.3	199.0	100.2	98.8
3. प्राथमिक आय	29.2	49.2	-20.0	28.9	53.8	-25.0
4. द्वितीयक आय	64.8	6.0	58.8	73.1	5.6	67.5
B. पूंजी खाता और वित्तीय खाता	580.2	555.2	25.0	673.5	658.6	14.9
जिसमें:						
1. प्रत्यक्ष निवेश	45.1	41.7	3.4	53.2	45.4	7.7
2. पोर्टफोलियो निवेश	342.0	321.2	20.8	281.9	286.1	-4.1
3. अन्य निवेश	180.4	146.7	33.7	315.8	301.6	14.2
जिसमें:						
एनआरआई जमा	52.3	42.2	10.2	47.1	41.0	6.1
भारत के लिए ईसीबी	20.9	14.3	6.6	17.7	12.4	5.3
4. आरक्षित आस्ति [वृद्धि (-)/ कमी (+)]	0	23.8	-23.8	10.9	4.5	6.4
ग. अशुद्धि एवं चूक (-) (क+ख)	0.3	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1
स्रोत: आरबीआई, https://tinyurl.com/368hue97						
नोट 1: पीआर का अर्थ है आंशिक रूप से संशोधित, और पी का अर्थ है अंतिम।						
नोट 2: राजड ऑफ के कारण उप-घटकों का योग कुल योग के समान नहीं है।						

भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) में घटकर 15.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 0.8 प्रतिशत) हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) में (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) था। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) में 141.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल अदृश्य प्राप्तियां, मुख्य रूप से निवल सेवाओं की प्राप्तियों और निवल व्यक्तिगत अंतरण के कारण एक वर्ष पहले के 123.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिक थीं।

पूँजीगत खाते और वित्तीय खाते में, वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) में निवल एफडीआई प्रवाह बढ़कर 7.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-सितंबर) में 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। एफडीआई ने वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में 20.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल प्रवाह था। वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-सितंबर) में विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में 6.4 अरब डॉलर की कमी आई, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में इसमें 23.8 अरब डॉलर की वृद्धि हुई थी।

वित्त वर्ष 2026 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सामान्य वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा भंडार 2 जनवरी, 2026 तक 686.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि मार्च 2025 के अंत में यह 668.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके अलावा, अप्रैल 2025 और दिसंबर 2025 के बीच, भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 5.7 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा, पाउंड स्टर्लिंग और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये में भी क्रमशः 6.3 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की गिरावट आई। इसी अवधि के दौरान जापानी येन के मुकाबले रुपया 3.7 प्रतिशत मजबूत हुआ।⁷

श्रम बाजार संकेतक

जैसा कि एनएसओ द्वारा 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)⁸ रिपोर्ट में बताया गया है, अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर (यूआर)⁹ 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए¹⁰ वर्ष 2018-19 में 5.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2 प्रतिशत हो

गई है। बेरोजगारी दर (यूआर) में रिकवरी होने से उच्च श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर)¹¹ और कामगार-जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर)¹² में वृद्धि हुई है। एलएफपीआर वर्ष 2018-19 में 50.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 60.1 प्रतिशत हो गया। वहीं, इसी अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआर 47.3 प्रतिशत से बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गया। विशेष रूप से, महिलाओं के लिए एलएफपीआर वर्ष 2018-19 में 24.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गया है।

त्रैमासिक और मासिक पीएलएफएस डेटा¹³ सामयिक बदलावों के साथ एक स्थिर श्रम बाजार दिखाते हैं। यह इंगित करता है कि अप्रैल से सितंबर 2025 (छमाही 1 वित्त वर्ष 2026) की अवधि में स्थिर श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और पर्याप्त रोजगार स्तर के साथ बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई, जो रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत देती है।¹⁴ वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में लगभग 8.7 लाख नई नौकरियों के सृजन को दर्शाता है।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए त्रैमासिक रोजगार संकेतक			
तिमाही	एलएफपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात	यूआर
अप्रैल-जून 2025	55.0	52.0	5.4
जुलाई-सितंबर 2025	55.1	52.2	5.2
अक्टूबर-दिसंबर 2025	55.8	53.1	4.8

स्रोत: त्रैमासिक पीएलएफएस रिपोर्ट।

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए मासिक रोजगार संकेतक			
तिमाही	एलएफपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात	यूआर
अप्रैल	55.6	52.8	5.1
मई	54.8	51.7	5.6
जून	54.2	51.2	5.6
जुलाई	54.9	52.0	5.2
अगस्त	55.0	52.2	5.1
सितंबर	55.3	52.4	5.2
अक्टूबर	55.4	52.5	5.2
नवंबर	55.8	53.2	4.7
दिसंबर	56.1	53.4	4.8

स्रोत: मासिक पीएलएफएस रिपोर्ट।

⁷ सारणी: एसडीआर, अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग (मासिक औसत और अंतिम-महीने की दरें), डीबीआईई, आरबीआई, <https://tinyurl.com/53eebmb8> की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर।

⁸ पीएलएफएस सर्वेक्षण वर्ष जुलाई-जून से मेल खाता है। उदाहरण के लिए, 2023-24 के लिए डेटा जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि को संदर्भित करता है।

⁹ किसी व्यक्ति को सामान्य स्थिति (पीएस + एसएस) के अनुसार नियोजित के रूप में वर्गीकृत करने के लिए, व्यक्ति को सर्वेक्षण की तारीख से पहले 365 दिनों के दौरान कम से कम 30 दिनों के लिए आर्थिक गतिविधि का पीछा करना चाहिए।

¹⁰ यूआर को श्रम बल में व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹¹ एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल में व्यक्तियों (यानी काम करने या काम करने या काम करने या उपलब्ध) के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹² डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹³ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने अप्रैल 2025 में संशोधित पीएलएफएस का पहला मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया। बुलेटिन में व्यक्तियों की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रमुख श्रम बाजार संकेतक प्रस्तुत किए गए हैं। मासिक पीएलएफएस के साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अखिल भारतीय और ग्रामीण अनुमानों के साथ-साथ शहरी अनुमानों को शामिल करने के लिए त्रैमासिक सर्वेक्षण को नया रूप दिया है। <https://tinyurl.com/ap6twwkw>

¹⁴ पीएलएफएस सितंबर 2025 बुलेटिन: <https://tinyurl.com/3s77aa9s>

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के आंकड़े अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण का संकेत देते हैं। ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में निवल एडिशन दोगुने से अधिक हो गए हैं, वित्त वर्ष 2019 में 61 लाख से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 129.8 लाख हो गए हैं। वित्त वर्ष 2026 में, अप्रैल से जुलाई 2025 तक ईपीएफओ में संचयी निवल वृद्धि 69.0 लाख तक पहुंच गई, जो वित्त वर्ष 2025 में इसी अवधि के दौरान दर्ज 44.7 लाख की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग

भारत को वित्त वर्ष 2026 में एसएंडपी, मॉर्निंगस्टार, डीबीआरएस और आर एंड आई इंफॉर्मेशन सहित तीन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुए, जिससे इसकी रेटिंग "बीबीबी-" से "बीबीबी" हो गई। इन एजेंसियों ने निरंतर मजबूत घरेलू विकास, बेहतर राजस्व संग्रहण, सब्सिडी युक्तिकरण द्वारा समर्थित एक विश्वसनीय राजकोषीय समेकन रणनीति, निरंतर घाटे में कमी और विकास-बढ़ाने वाले पूंजी निवेश की दिशा में सार्वजनिक व्यय में स्पष्ट बदलाव पर अपना सामान्य मूल्यांकन किया। रेटिंग एजेंसियों ने आगे कहा कि बाह्य तन्यकता प्रबंधनीय चालू खाता गतिशीलता, कम बाहरी उत्तोलन और पर्याप्त विदेशी मुद्रा बफर के माध्यम से अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता है। अंत में, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि भारत की सुनियंत्रित विनियमित वित्तीय प्रणाली, विश्वसनीय मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण व्यवस्था और नम्य विनियम दर भी अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव के प्रति तन्यकता को बढ़ाती है, जिससे समग्र वृहद-वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है। इन एजेंसियों द्वारा जारी की गई नवीनतम सॉवरेन रेटिंग इस प्रकार है:

रेटिंग एजेंसी	क्रेडिट रेटिंग	दृष्टिकोण	अंतिम मूल्यांकन	मूल्यांकन की अगली देय तिथि
फिच	बीबीबी-	स्थिर	अगस्त 2025	मार्च 2026
मूडीज	बीएए3	स्थिर	सितंबर 2025	2026
एसएंडपी	बीबीबी	स्थिर	अगस्त 2025	2026
मॉर्निंग स्टार डीबीआरएस	बीबीबी	स्थिर	मई 2025	2026
केयर एज	बीबीबी+	स्थिर	अक्टूबर 2025	2026
आरएंडआई इंफॉर्मेशन इंक	बीबीबी	स्थिर	सितंबर 2025	2026

2. व्यय विभाग

व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग वित्त आयोग और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अभ्युक्तियों की मॉनीटरिंग, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निर्गमों और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की सहायता भी करता है। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखना और वित्तीय नियमों/विनियमों/आदेशों को लागू करना, प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं का संस्वीकृति-पूर्व मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

व्यय विभाग को आबंटित कार्य इसके कार्मिक एवं स्थापना प्रभाग, लोक वित्त-राज्य और लोक वित्त केन्द्रीय प्रभागों, मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, महालेखानियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद, जो एक स्वायत्त निकाय है, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

3. राजस्व विभाग

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित राजस्व मामलों के संबंध में नियंत्रण रखता है। विभाग को माल और सेवा कर (जीएसटी), केन्द्रीय बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और अन्य प्रासंगिक वित्तीय विधियों से संबंधित अधिनियमों में प्रदान किए गए नियामक उपायों के प्रशासन और प्रवर्तन का भी काम सौंपा गया है। अफीम और इसके उत्पादों के उत्पादन और निपटान का नियंत्रण भी इसी विभाग में निहित है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय, एफआईयू-भारत, जीएसटीएन, सीबीएन, सीसीएफ, सीईआईबी, एनआईपीएफपी राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

विनिवेश विभाग की स्थापना दिनांक 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में दिनांक 06 सितम्बर, 2001 से इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। दिनांक 27 मई, 2004 से, विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

निवेश विभाग का नया नाम दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग कर दिया गया है।

5. वित्तीय सेवाएं विभाग

कार्य आबंटन नियमावली (एओबीआर) के अनुसार, वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के कार्यों में बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधार के वित्तीय सेवाएं क्षेत्रों से संबंधित विधायी और प्रशासनिक मामले शामिल हैं। इनमें वित्तीय सेवाएं क्षेत्र से संबंधित विभिन्न अधिनियमों का प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य विकास वित्त संस्थानों, जैसे नाबार्ड, सिडबी आदि, के कार्यनिष्पादन की निगरानी शामिल है।

वित्तीय क्षेत्र के तीन विनियामकों अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) से संबंधित सभी मामलों पर इस विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। यह ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) के प्रशासनिक विभाग के रूप में भी कार्य करता है।

यह विभाग वित्तीय सेवाएं क्षेत्र के प्रमुख अधिकारियों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर, इरडाई तथा पीएफआरडीए के अध्यक्ष/सदस्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों तथा अन्य विकास वित्त संस्थानों के बोर्ड में अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ)/कार्यपालक निदेशक (ईडी)/गैर-सरकारी निदेशकों को नियुक्त करने के लिए उत्तरदायी है।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र और पेंशन सुधार क्षेत्र से संबंधित सरकार के कई प्रमुख कार्यक्रमों/पहल की निगरानी करता है। वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित की जा रही प्रमुख योजनाओं में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की वित्तीय समावेशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अर्थात् प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री वय वंदना योजना और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्टैंड अप इंडिया (एसयूआई) जैसी ऋण योजनाएं शामिल हैं।

6. लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1. प्रस्तावना: -

तीसरी लोक सभा की प्राक्कलन समिति (1962-67) ने अपनी 52वीं रिपोर्ट में सार्वजनिक उद्यमों के कार्य-निष्पादन का निरंतर मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीकृत समन्वय इकाई स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 1965 में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की, इसे वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया। सितंबर 1985 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के पुनर्गठन के बाद, बीपीई उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा बन गया। मई 1990 में और सुधार हुए, और बीपीई को एक पूर्ण विभाग बना दिया गया जिसे लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के नाम में जाना जाता है। लोक उद्यम

विभाग को भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। दिनांक 6 जुलाई, 2021 की मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना के माध्यम से डीपीई को वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन रहते हुए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकाज और उनके कार्य-निष्पादन से संबंधित दिशानिर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. कार्य:

डीपीई द्वारा निम्नलिखित विषयों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं:

- 2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को प्रभावित करने वाली सामान्य नीतिगत मामलों का समन्वय।
- 2.2 सीपीएसई के निदेशक मंडलों (बोर्डों) की संरचना।
- 2.3 'रत्न' का दर्जा देने सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वर्गीकरण।
- 2.4 सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) से संबंधित मामले।
- 2.5 सीपीएसई की वेतन नीति और जनशक्ति युक्तिकरण।
- 2.6 समझौता ज्ञापन तंत्र सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी।
- 2.7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा।
- 2.8 सार्वजनिक उद्यमों का सर्वेक्षण।
- 2.9 स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण तथा पुनर्वास।
- 2.10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरुद्धार, पुनर्गठन या बंद करने से संबंधित सलाह देना जिसमें इसके लिए तंत्र भी शामिल है।
- 2.11 लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
- 2.12 लोक उद्यम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र से संबंधित मामले।
- 2.13 गैर-रणनीतिक क्षेत्र के तहत सीपीएसई को बंद करना/निजीकरण के लिए उनकी पहचान करना और बंद करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना।
- 2.14 सीपीएसई और अन्य सरकारी संगठनों की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण।

3. संगठनात्मक संरचना: -

लोक उद्यम विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव द्वारा किया जाता है, जिन्हें समग्र स्वीकृत 118 अधिकारियों/कर्मियों की जनशक्ति की

संस्थापना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। डीपीई की संगठनात्मक संरचना अनुलग्नक-1 में दी गई है। विभाग में निम्नलिखित घटक प्रभाग हैं:

3.1 नीति एवं समझौता ज्ञापन प्रभाग

नीति प्रभाग सीपीएसई की रत्न योजना से संबंधित मामलों का निरीक्षण करता है, जिसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन, वर्गीकरण, बोर्ड स्तर के पदों का सृजन, बोर्ड स्तर से नीचे के पदों का सृजन और तत्काल समावेश से छूट शामिल है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू): यह विभाग सीपीएसई के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने और समझौता ज्ञापन (एमओयू) ढांचे को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति संकलित करता है। यह प्रभाग चुनिंदा सीपीएसई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर डाटा संकलित करता है।

3.2 सामान्य प्रबंधन और क्षमता निर्माण

सामान्य प्रबंधन और क्षमता निर्माण प्रभाग सीपीएसई में रोजगार और आरक्षण से संबंधित मुद्दों को देखता है; अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनर्विन्यास (आरडीसीआर) योजना का निर्माण या संशोधन और इस योजना के तहत प्रशिक्षण का संचालन और समन्वय; गैर-सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) के डाटाबैंक का रख-रखाव और सीपीएसई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रस्तावों की प्रक्रिया; निदेशक मंडलों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास; क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत से संबंधित मामलों सहित डीपीई कर्मचारियों का प्रशिक्षण; इंटरन की सहभागिता; तथा ओटीएनएस से संबंधित कार्यों के लिए आरडीसीआर योजना के तहत प्रोग्रामर की नियुक्ति।

जहां तक वेतन नीति और जनशक्ति युक्तिकरण का संबंध है, डीपीई बोर्ड में सीपीएसई के अधिकारियों के साथ-साथ बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। लोक उद्यम विभाग सीपीएसई में कार्यगारों के लिए वेतन निपटान वार्ताओं के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई को कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन से संबंधित मामलों और कार्यगारों की वेतन नीति वार्ताओं के बारे में भी परामर्श देता है।

सीपीएसई मुख्य रूप से वेतनमानों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आईडीए) पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तथापि, कुछ सीपीएसई में केन्द्रीय महंगाई भत्ते (वेतनमानों के सीडीए पैटर्न) का भी अनुसरण किया जाता है। डीपीई आईडीए कर्मचारियों के संबंध में त्रैमासिक डीए आदेश जारी करता है, जबकि सीपीएसई के सीडीए कर्मचारियों के लिए डीए आदेश छह माह की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।

सीपीएसई के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र दिनांक 14.12.2022 के संशोधित एएमआरसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई के बीच और सीपीएसई और सरकारी विभागों/संगठनों (रेलवे, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच सभी वाणिज्यिक विवादों से निपटता है।

3.3 सर्वेक्षण प्रभाग

सर्वेक्षण प्रभाग सभी सीपीएसई की महत्वपूर्ण भौतिक और वित्तीय विशेषताओं पर जानकारी को एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट "लोक उद्यम सर्वेक्षण" में एकत्र करता है और इसे प्रत्येक वर्ष संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है।

सर्वेक्षण प्रभाग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) (वाणिज्यिक) की रिपोर्टों को संसद में रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अनुरोध किए जाने पर लेखा परीक्षा पैराओं पर कृत कार्यवाई टिप्पणियां (एटीएन) प्रस्तुत करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ भी अनुवर्ती कार्यवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, प्रभाग चुनिंदा सीपीएसई द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पर आंकड़े संकलित करता है।

3.4 विनिवेश, क्लोजर और परिसंपत्ति मुद्रीकरण

विनिवेश प्रभाग गैर-रणनीतिक क्षेत्र में नई पीएसई नीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ताकि गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई को बंद करने या निजीकरण के लिए उनकी पहचान की जा सके।

3.5 प्रशासन, स्थापना, संसद और समन्वय प्रभाग

यह प्रभाग लोक उद्यम विभाग के कार्मिक प्रबंधन, उनकी छुट्टी, वेतन, सेवा पुस्तिका सहित कार्मिक अभिलेखों के रखरखाव और संसदीय मामलों से संबंधित सभी प्रशासनिक और समन्वय मामलों को संभालता है।

सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ विभाग के पोर्टलों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों की देखभाल करता है। आईटी सेल डैशबोर्ड के रखरखाव और उन्नयन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के विकास और अनुरक्षण, आईटी सेल के पर्यवेक्षण और सोशल मीडिया प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

4. राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी)

एनएलएमसी को अन्य सरकारी संस्थाओं और सीपीएसई को उनकी गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को कुशल और पेशेवर तरीके से मुद्रीकृत करने, उनकी मूल्य प्राप्ति को अधिकतम करने में सहायता करने के लिए शामिल किया गया है। यह आईएमजी/एएम की बैठकों के लिए सचिवीय सहायता, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सीपीएसई और सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

अध्याय - I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 आर्थिक प्रभाग प्रमुख आर्थिक नीति मुद्दों पर सरकार को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। यह प्रभाग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों की जांच करता है और आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था के प्रबंधन पर प्रभाव डालने वाले अनुसंधान अध्ययन करता है, और नीतिगत सलाह प्रदान करता है।

1.2 प्रभाग का कार्य प्रत्येक वर्ष आर्थिक समीक्षा के वार्षिक प्रकाशन के साथ समाप्त होता है, जिसे वार्षिक केंद्रीय बजट के पूर्वावलोकन के रूप में संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक प्रदर्शन का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, प्रभाग बजट प्रभाग में प्रमुख इनपुट का योगदान देता है, जिसमें वृहद-आर्थिक फ्रेमवर्क विवरण, अर्ध-वार्षिक समीक्षा विवरण के लिए वृहद आर्थिक अवलोकन, जीडीपी अनुमान और बहुत कुछ शामिल है। यह प्रभाग माननीय वित्त मंत्री और विभिन्न हितधारकों के बीच बजट-पूर्व परामर्श का समन्वय भी करता है।

1.3 यह प्रभाग मासिक आर्थिक समीक्षा (एमईआर) भी प्रकाशित करता है, जो हाल के वृहद आर्थिक रुझानों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर नवीनतम उच्च-आवृत्ति डेटा की समीक्षा प्रदान करता है। यह भारत के विदेशी ऋण पर एक वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, और सितंबर और दिसंबर को समाप्त होने वाली दो तिमाहियों के लिए भारत के विदेशी ऋण पर त्रैमासिक रिपोर्ट के प्रकाशन में भी लगा हुआ है (शेष दो तिमाहियों की रिपोर्ट आरबीआई द्वारा प्रकाशित की जाती है)।

1.4 यह प्रभाग आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) में देश की भागीदारी का समन्वय करता है और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर राष्ट्रीय सारांश डेटा पृष्ठ को अपडेट करता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग का कार्य समन्वय आर्थिक प्रभाग द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, आर्थिक प्रभाग के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन वित्त इकाई सभी जलवायु परिवर्तन वित्त संबंधी मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।

1.5 यह प्रभाग समय-समय पर वृहद आर्थिक रुझानों, मूल्य की स्थिति, कृषि और औद्योगिक उत्पादन के प्रदर्शन, कर संग्रह के रुझान, भुगतान संतुलन, व्यापार और मौद्रिक स्थिति के बारे में जानकारी तैयार करता है। इसके अलावा, प्रभाग प्रमुख आर्थिक चर का अल्पकालिक पूर्वानुमान लगाता है। अपने सलाहकार कार्यों के हिस्से के रूप में, आर्थिक प्रभाग महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषणात्मक नोट्स और पृष्ठभूमि पत्र तैयार करता है और सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों और कार्य समूहों की बैठकों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों की यात्राओं के लिए संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। यह प्रभाग आरबीआई, नीति आयोग, सांख्यिकी

और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और विभिन्न अन्य मंत्रालयों के साथ निकट सहयोग से काम करता है।

1.6 आर्थिक प्रभाग का कार्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार निम्नलिखित 11 इकाइयों के तहत आयोजित किया जाता है:

1. कृषि और खाद्य प्रबंधन इकाई
2. जलवायु परिवर्तन और सतत वित्त इकाई
3. बाह्य क्षेत्र इकाई
4. उद्योग और अवसंरचना इकाई
5. मैक्रो इकाई
6. वित्तीय क्षेत्र इकाई
7. मूल्य इकाई
8. सार्वजनिक वित्त इकाई
9. सेवा इकाई
10. सामाजिक क्षेत्र इकाई
11. समन्वय इकाई

2. बजट प्रभाग

2.1 जिम्मेदारियाँ

2.1.1 बजट प्रभाग वार्षिक बजट के साथ-साथ केंद्र सरकार और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुदानों की पूरक मांगों और अतिरिक्त मांगों को तैयार करने और संसद में प्रस्तुत करने आदि के लिए जिम्मेदार है।

2.1.2 बजट प्रभाग “राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003” के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है। एफआरबीएम अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार राजकोषीय नीति के विवरण, अर्धवार्षिक समीक्षा जिसमें मध्यावधि समीक्षा और प्रकटीकरण विवरण शामिल हैं, संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं।

2.1.3 यह प्रभाग लोक ऋण, केंद्र सरकार के बाजार ऋण और भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों और भारत की आकस्मिकता निधि के प्रशासन से संबंधित मुद्दों का भी निपटान करता है। बचत के पुनर्विनियोजन के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों जहां, वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, से प्रस्तावों पर कार्रवाई का कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई), लघु बचत योजनाओं और राष्ट्रीय रक्षा कोष से संबंधित मामले का भी निपटान करता है। कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ बंदोबस्ती से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग को सौंपा गया है।

2.1.4 बजट प्रभाग चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों और आगामी वित्त वर्ष के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व बैठकों का समन्वय भी करता है।

2.2 वर्ष 2025-26 के दौरान प्रमुख उपलब्धियाँ

2.2.1 केंद्रीय बजट 2025-26 दिनांक 01 फरवरी, 2025 को कागज रहित रूप में पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, संसद में वर्ष 2025-26 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच दिसंबर 2025 में प्रस्तुत और पारित किया गया। पूरक अनुदान मांगों 2025-26 का द्वितीय बैच मार्च 2026 में संसद में प्रस्तुत किया गया।

2.2.2 वित्त आयोग की अनुमोदित सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्से को जारी करने का काम भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सभी राज्यों को कुल 12,86,885.44 करोड़ रुपए अंतरित किए गए हैं। जबकि बजट अनुमान 2024-25 में 12,47,211.28 करोड़ रुपए अंतरित करने का अनुमान लगाया गया था।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 में 10 फरवरी, 2026 तक सभी राज्यों को 12,66,369 करोड़ रुपए अंतरित किए गए, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में 13,92,971 करोड़ रुपए अंतरित करने का अनुमान लगाया गया था।

2.2.3 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 32 रिपोर्टें संसद के समक्ष रखी गईं और उक्त अवधि के दौरान इस प्रभाग द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) को विभिन्न निकायों की लेखापरीक्षा सौंपने/पुनः सौंपने के 28 प्रस्तावों पर कार्य किया गया।

2.2.4 राष्ट्रीय बचत खंड

2.2.4.1 लघु बचत योजनाएँ:

आर्थिक कार्य विभाग में बजट प्रभाग द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित लघु बचत योजनाएँ संचालित की जाती हैं: -

- डाकघर बचत खात
- राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (1,2,3 और 5 वर्ष)
- राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा
- राष्ट्रीय बचत मासिक आय योजना

- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (VIII-अंक)
- लोक भविष्य निधि
- किसान विकास पत्र
- सुकन्या समृद्धि खाता।

2.2.4.2. लघु बचत संग्रह:

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹15,10,694.20 करोड़ जमा की तुलना में वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न लघु बचत योजनाओं के तहत सकल जमा ₹15,66,952.19 करोड़ है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को निवल लघु बचत संग्रह और प्रतिभूतियों के मोचन पर प्राप्त राशि के हिस्से के रूप में ₹10,060.62 करोड़ (अंतिम अनुमान) की राशि का निवेश किया जाएगा, जबकि वर्ष 2024-25 के दौरान इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा वाले) में ₹13,325.96 करोड़ की राशि का निवेश किया गया था।

2.2.4.3 राष्ट्रीय लघु बचत निधि:

केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत सभी मौद्रिक लेन-देन को एकत्रित स्कीम के अंतर्गत रखने के लिए, दिनांक 1 अप्रैल, 1999 से भारत के लोक लेखा में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई थी। लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत निवल अभिवृद्धि का राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधानसभा सहित) की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जा रहा था। तथापि, चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, दिनांक 01.04.2016 से केवल इच्छुक राज्यों को ही अग्रिम एनएसएसएफ ऋण देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, केवल दो राज्य नामतः केरल और मध्य प्रदेश तथा एक विधानसभा सहित संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली ने एनएसएसएफ ऋण का विकल्प चुना है।

2.2.4.4 लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें:

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में निर्धारित/अधिसूचित की जाती हैं। श्यामला गोपीनाथ समिति की सिफारिशों और सरकार के विकास/राजकोषीय प्रतिफल के मद्देनजर लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर निर्धारित की जाती है। समिति ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर को समान परिपक्वता की जी-सेक दरों के साथ संरेखित करने की सिफारिश की है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर नीचे दी गई है: -

वित्त वर्ष 2025-26 में ब्याज दर (% में)				
लिखत	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही
बचत जमा	4.0	4.0	4.0	4.0
1 वर्ष का सावधि जमा	6.9	6.9	6.9	6.9
2 वर्ष का सावधि जमा	7.0	7.0	7.0	7.0
3 वर्ष का सावधि जमा	7.1	7.1	7.1	7.1
5 वर्ष का सावधि जमा	7.5	7.5	7.5	7.5
5 वर्ष का आवर्ती जमा	6.7	6.7	6.7	6.7
5 वर्ष का एससीएसएस	8.2	8.2	8.2	8.2
5 वर्ष का एमआईएस	7.4	7.4	7.4	7.4
5 वर्ष का एनएससी	7.7	7.7	7.7	7.7
पीपीएफ	7.1	7.1	7.1	7.1
सुकन्या समृद्धि खाता	8.2	8.2	8.2	8.2
किसान विकास पत्र	7.5(115 महीने में परिपक्व होगा)	7.5(115 महीने में परिपक्व होगा)	7.5(115 महीने में परिपक्व होगा)	7.5(115 महीने में परिपक्व होगा)

2.2.5. लोक ऋण प्रबंधन:

2.2.5.1 बजट प्रभाग भारतीय रिजर्व बैंक और लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) के समन्वय/परामर्श से सरकारी बाजार उधार (टी-बिल सहित) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

2.2.5.2 बजट प्रभाग के तहत पीडीएमसी भारत सरकार के उधार की योजना बनाने, ऋण प्रबंधन कार्यनीति तैयार करने, नकदी की निगरानी और प्रबंधन, बाजार सहभागियों के साथ अधिक संपर्क आदि के माध्यम से लोक ऋण प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.2.5.3 लोक ऋण प्रबंधन प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में, वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी ऋण पर एक स्थिति पत्र (स्टेट्स पेपर) 29 अगस्त, 2025 को जारी किया गया था। यह रिपोर्ट देश की समग्र ऋण स्थिति, ऋण स्थिरता के पहलुओं से संबंधित आकलन, विभिन्न जोखिमों को कवर करने वाली ऋण प्रबंधन कार्यनीति आदि सहित लोक ऋण के विभिन्न

पहलुओं को कवर करती है। पीडीएमसी लोक ऋण पर त्रैमासिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) का पालन करते हुए राष्ट्रीय सारांश डेटा पेज पर लोक ऋण से संबंधित डेटा अपलोड करने के लिए भी जिम्मेदार है।

2.2.5.4 भारत सरकार ने अपने समग्र बाजार उधार के हिस्से के रूप में, हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्रमशः वर्ष 2024-25 में कुल मिलाकर ₹21697 करोड़ की राशि के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) जारी किए। आय को बजट वित्तपोषित योजनाओं/परियोजनाओं में लगाया जाता है जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक एसजीआरबी के माध्यम से ₹15,000 करोड़ जुटाए गए हैं।

2.2.5.5 बजट प्रभाग दो विनियोजनों अर्थात् ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती का प्रबंधन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार की सकल उधारी 14.61 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) थी।

2.2.5.6 सरकारी ऋण मुख्य रूप से (लगभग 95%) भारतीय मुद्रा में रखा जाता है। बकाए विदेशी ऋण को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों द्वारा रियायती दरों पर वित्तपोषित किया जाता है। आंतरिक ऋण में बड़े पैमाने पर विपणन योग्य और गैर-विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ शामिल हैं। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफाइल ऋण पोर्टफोलियो में अपेक्षाकृत कम रोल-ओवर जोखिम को इंगित करती है। स्विच/बायबैक के रूप में सक्रिय ऋण प्रबंधन संचालन भी परिपक्वता प्रोफाइल को बढ़ाने और रोल-ओवर जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। सरकार के मौजूदा ऋण और देनदारियों का विस्तृत विश्लेषण वार्षिक ऋण पत्रों (<https://dea.gov.in/public-debt-management> पर उपलब्ध) में प्रस्तुत किया गया है।

2.2.6. राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन:

2.2.6.1 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम), 2003 और उसके तहत बनाए गए नियमों का प्रशासन एफआरबीएम अनुभाग का मुख्य कार्य है। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी तय करता है कि वह राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-पीढ़ीगत समानता और दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें। यह मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन में राजकोषीय रुकावटों को हटाकर और राजकोषीय निरंतरता के साथ विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन करके किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार की उधारी, ऋण और घाटे पर सीमाएं, केंद्र सरकार के राजकोषीय संचालन में अधिक पारदर्शिता और मध्यावधि फ्रेमवर्क में राजकोषीय नीति का संचालन शामिल है, तथा इससे जुड़े या संबंधित मामलों के लिए भी यह लागू होता है।

2.2.6.2 1 अप्रैल, 2025 से 29 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान एफआरबीएम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज तैयार किए गए और संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए गए:

- क) बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत राजकोषीय नीति के विवरण
 - क) मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति सह राजकोषीय नीति कार्यनीति विवरण
 - ख) वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण
- ख) बजट 2025-26 के साथ प्रस्तुत प्रकटीकरण विवरण
 - क) जुटाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए कर राजस्व
 - ख) गैर-कर राजस्व का बकाया
 - ग) आस्ति रजिस्टर
 - घ) सरकार द्वारा दी गई गारंटी
 - ङ) वार्षिक परियोजनाओं पर देयताएं

ग) बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझानों की समीक्षा पर अर्धवार्षिक विवरण-

क) वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही

ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही

2.2.6.3 राजकोषीय संकेतक संशोधित अनुमान 2024-25 और बजट अनुमान 2025-26 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

(जीडीपी के % के रूप में)

वित्तीय संकेतक/वर्ष	2024-25 (सं.अ.)	2025-26 (ब.अ.)
राजकोषीय घाटा	4.8	4.4
केन्द्र सरकार का ऋण*	57.1	56.1

टिप्पणी:

- (i) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 07.01.2025 को जारी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 324.11 लाख करोड़ रुपये है।
- (ii) बजट अनुमान 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 356.98 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो 2024-25 (संशोधित अनुमान) के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद के 324.11 लाख करोड़ रुपये से 10.1% अधिक है।
- (iii) जीडीपी वर्तमान बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है।

*केंद्र सरकार के ऋण में वर्तमान विनिमय दरों पर मूल्यांकित विदेशी लोक ऋण, एनएसएसएफ के तहत राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश सहित सार्वजनिक खाते पर कुल बकाया देयताएं और ईबीआर देयताएं आदि शामिल हैं।

2.2.7 बजट प्रेस

2.2.7.1. बजट प्रेस केंद्रीय बजट से संबंधित सभी बजट दस्तावेजों को छापने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वित्त मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांग, अनुदानों की अनुपूरक मांगों और वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी/हिंदी) शामिल हैं।

2.2.7.2. ऊपर वर्णित कार्यों के अलावा, बजट प्रेस में आयकर विधेयक 2025 के साथ साथ वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच और दूसरा बैच, कार्रवाई रिपोर्ट, मंत्रिमंडल टिप्पणी (हिंदी और अंग्रेजी) और कई चर्चा पत्र मुद्रित किए।

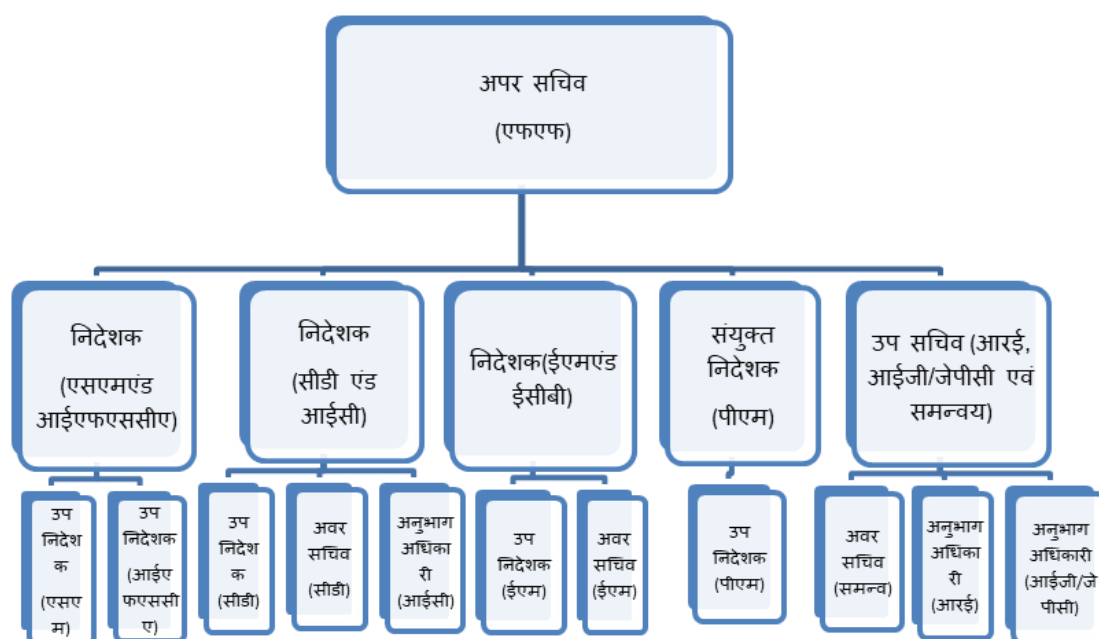
3. वित्तीय बाजार प्रभाग

3.1 परिचय

वित्तीय बाजार (एफएम) प्रभाग मुख्य रूप से प्रतिभूति बाजारों के विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों और उनसे संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। वर्ष 2013 से, प्रभाग को वस्तु व्युत्पन्न बाजारों के विकास का काम सौंपा गया है। यह प्रभाग भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के प्रशासनिक मामलों की

देख-रेख करता है। यह प्रभाग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जापान और यूरोपीय संघ के साथ वित्तीय विनियामक वार्ता में भी भाग लेता है।

वित्तीय बाजार (एफएम) प्रभाग सेबी अधिनियम 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019, प्रतिभूति अनुबंध विनियम (एस. सी. आर. ए.) अधिनियम 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 और संबंधित नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। एफएम प्रभाग का ऑर्गनोग्राम नीचे दिया गया है:



3.2 वित्तीय बाजार प्रभाग के अनुभाग

विभिन्न अनुभागों और उनके कार्य आवंटन नीचे दिए गए हैं (प्रत्येक अनुभाग अपने कार्य क्षेत्रों से संबंधित संसद प्रश्नों, शिकायतों, आरटीआई, अदालती मामलों, विविध संदर्भों आदि की देख-रेख करता है):

1. प्राथमिक बाजार (पीएम) अनुभाग

1. पूंजी के प्रारंभिक और आगे के निर्गम से संबंधित मुद्दों और इससे जुड़ी मध्यवर्ती संस्थाएं निर्माण जैसे कि:

- (क) म्यूचुअल फंड,
- (ख) सामूहिक निवेश योजनाएं,
- (ग) वैकल्पिक निवेश निधि,
- (घ) घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां,
- (ङ) मर्चेन्ट बैंक आदि।

2. निगमित प्रशासन और न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित मामले।
3. सूचीबद्धता नियमों, न्यूनतम सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित मामले।
4. विलय, अधिग्रहण और अर्जन से संबंधित नीतिगत मुद्दे
5. कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार का विकास
6. वित्तीय साक्षरता
7. कंपनियों का निगमित प्रशासन
8. सेबी की बोर्ड बैठकों के एजेंडा मदों पर नीतिगत अभिव्यक्ति (प्राथमिक उत्तरदायित्व)
9. सेबी अधिनियम, संबंधित नियम और विनियम
10. गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और ग्रेच्युटी निधि के लिए निवेश दिशानिर्देश

11. डीईए-एजेएनआईएफएम अनुसंधान कार्यक्रम और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना।
 - II. **द्वितीयक बाजार अनुभाग**
 1. द्वितीयक बाजार और संबंधित बाजार अवसंरचना संस्थानों (एम. आई. आई.), मध्यस्थों और प्रतिभागियों (स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, डिपॉजिटरी, उनके प्रतिभागी, व्यापार सदस्य और निवेश सलाहकार आदि) के नीतिगत मुद्दे, उनके स्वामित्व और शासन के मुद्दे आदि।
 2. प्रतिभूतियों/क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्मों में व्यापार के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज/एसएमई एक्सचेंज/नए सेगमेंट/प्लेटफॉर्म
 3. प्रतिभूति बाजार में कर और स्टाम्प शुल्क
 4. प्रतिभूति बाजार/क्षमता निर्माण पहलों में कौशल
 5. कंपनियों को सूची से हटाना और संबंधित नीतिगत मुद्दे
 6. सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एकल डीमैट खाता बनाना
 7. प्रतिभूति बाजार से संबंधित डेटाबेस
 8. शेयर बाजार की गतिविधियों की निगरानी
 9. स्व-नियामक संगठन
 10. प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में साइबर सुरक्षा संबंधी मामले
 11. सुमित बोस समिति की सिफारिशों के संदर्भ में वितरकों का विनियमन/वित्तीय उत्पादों का वितरण
 12. निवेशक शिक्षा और संरक्षण से संबंधित मामले
 13. अवरूद्ध डीमैट खातों संबंधी नीति
 14. यूएनआईडीआरओआईटी/जिनेवा प्रतिभूति समझौते का अनुसमर्थन
 15. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और संबंधित नियम और विनियम
 16. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और **संबंधित नियम और विनियम**
 - III. **कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट अनुभाग**
 1. **कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट और सामान/कॉमोडिटी पर अन्य कॉमोडिटी उत्पादों के विकास से संबंधित नीतिगत मामले।**
 2. स्टॉक एक्सचेंजों में व्यापार के लिए वस्तुओं को अधिसूचित करने से संबंधित मुद्दे: विभिन्न अधिसूचित वस्तुओं/विकल्प संविदा आदि में वायदा कारोवार को फिर से शुरू/निलंबित करना।
 3. आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आदि पर अंतर-मंत्रालयी समितियों में कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स बाजार से संबंधित मामलों में आर्थिक कार्य विभाग का प्रतिनिधित्व करना।
 4. कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से संबंधित मामले: हेरफेर/सट्टेबाजी आदि के मामले
 5. कॉमोडिटी मार्केट के नीतिगत मामलों जैसे वितरण व्यवस्था, डब्ल्यू. डी. आर. ए. और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के द्वारा डब्ल्यूडीआरए प्रत्याशित मामलों की देखरेख।
 6. सेबी बोर्ड एजेंडा में प्रासंगिक मदों का मूल्यांकन।
 7. इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) और गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज से संबंधित नीतिगत मामले।
 8. एनएसई, बीएसई के विनिमय का वस्तु खंड और एनसीडीईएक्स और एमसीएक्स से संबंधित मामले।
 9. कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट से संबंधित कौशल, क्षमता निर्माण और जागरूकता पहलें
 10. एनएसईएल में भुगतान संकट में जांच और प्रवर्तन एजेंसियों और विनियामक प्राधिकरणों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करना, एनएसईएल मामले पर पीएमओ को रिपोर्ट भेजना, एनएसईएल से संबंधित सतर्कता मामलों पर सतर्कता विभाग को इनपुट देना।
- IV. **बाह्य बाजार (ईएम) अनुभाग**
 1. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999
 2. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों से संबंधित सभी संदर्भों, मामलों और प्रस्तावों पर कार्रवाई।
 3. विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय/परियोजना कार्यालय की स्थापना से संबंधित मामले
 4. विदेशियों/अनिवासियों द्वारा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी (एनआरओ) और नॉन रेजिडेंट रुपी (एनआरई) खाते खोलने से संबंधित मामले
 5. ईरान के साथ व्यापार भुगतान निपटान तंत्र से संबंधित मामले
 6. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों/विधायकों/प्रशासकों/अधिकारियों की विदेश यात्रा से संबंधित मामले
 7. विदेशियों/अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अचल संपत्ति की खरीद के लिए अनुमोदन
 8. विधानसभाओं के अध्यक्षों और सदस्यों की यात्राओं से संबंधित वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन की सुविधा प्रदान करना।

V. बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) अनुभाग

1. बाह्य वाणिज्यिक ऋण, विदेशी मुद्रा बांड और व्यापार ऋण से संबंधित नीतिगत मुद्दे
2. ऑफशोर मार्केट (मसाला बॉन्ड) में रुपये मूल्यवर्ग के बॉन्ड जारी करने की संबंधी फ्रेमवर्क
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 से संबंधित नीतिगत मामले
4. सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉन्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवेश संबंधी फ्रेमवर्क
5. डिपॉजिटरी रिसीट स्कीम (एडीआर/जीडीआर) से संबंधित मामले
6. भारत डिपॉजिटरी रिसीट/इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट (बीएचडीआर/आईडीआर) से संबंधित मामले
7. भारतीय ऋण प्रतिभूतियों के अंतरराष्ट्रीय निपटान से संबंधित मामले (यूरोक्लियर और क्लियर स्ट्रीम के माध्यम से)
8. स्थानीय मुद्रा निपटान तंत्र से संबंधित संदर्भ
9. भारत में करेंसी कम्पोजिटी मार्केट (ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड) और ब्याज दर वायदा से संबंधित नीतिगत मुद्दे
10. सुकुक बॉन्ड से संबंधित मुद्दे
11. द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्रा विनियम समझौतों से संबंधित मुद्दे
12. भारत और विदेशों में विदेशी निवेशकों के साथ रोड-शो और निवेशक बैठकों का आयोजन करना
13. वित्तीय बाजारों से संबंधित ब्रिक्स और जी-20 मामले

VI. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

1. आई. एफ. एस. सी. ए. अधिनियम, 2019 का क्रियान्वयन और अधिनियम के तहत अधीनस्थ विधायन तैयार करना
2. आईएफएससीए अधिनियम, 2019 और संबंधित नियमों और विनियमनों से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्माण
3. आईएफएससीए प्राधिकरण की बैठकों के एजेंडा मदों पर नीतिगत व्याख्या
4. आईएफएससीए के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में कोर और नीश सेगमेंट के समग्र विकास को निम्नलिखित क्षेत्रों पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सुविधाजनक बनाना
5. विमान लीजिंग और वित्तपोषण
6. बुलियन ट्रेडिंग
7. फिन टेक

8. बीमा/पुनर्बीमा
9. बैंकिंग
10. निधि प्रबंधन
11. ग्लोबल-इन-हाउस सेंटर
12. अन्य
13. विदेशी वित्तीय विनियमकों/प्राधिकरणों के साथ आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए आईएफएससीए द्वारा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिमंडल नोट तैयार करना
14. आईएफएससीए और जीआईएफटी सिटी द्वारा अंतरराष्ट्रीय पहुंच को सुगम बनाना
15. आईएफएससीए में व्यापक विनियमनों और नए वित्तीय उत्पादों/सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए सेबी, आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए के बीच अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाना
16. आई. एफ. एस. सी. ए. के लिए बजटीय सहायता और प्राधिकरण के वेतन, भत्तों और अन्य स्थापना व्यय पर खर्च के लिए केंद्र सरकार से अनुदान का अंतरण
17. आईएफएससीए मुख्यालय परियोजना, सुपर-टेक परियोजना और फिनटेक प्रोत्साहन योजना सहित आईएफएससीए को स्वीकृत परियोजनाओं और योजनाओं का पर्यवेक्षण करना
18. सभी मसौदा मंत्रिमंडल नोटों के मसौदों की जांच और इस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना
19. विभिन्न आर्थिक और वित्तीय वार्ताओं के तहत आईएफएससीए के विकास से संबंधित एजेंडा मदों को ठीक से तैयार करना

VII. विनियामक अवस्थापना (आरई) अनुभाग

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के पीठासीन अधिकारी, सदस्यों और रजिस्ट्रार की नियुक्ति और संबंधित नियमों और विनियमनों का प्रशासन करना
2. वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति सर्च समिति (एफएसआरएससी) का गठन
3. सेबी के अवस्थापना संबंधी मामले जैसे लेखा परीक्षा, सीवीओ की नियुक्ति आदि
4. एस. ए. टी. के आवासीय सुविधा, एस. ए. टी. को बजट अनुदान और संबंधित मामले, एस. ए. टी. में अधिकारियों को वाहन अनुदान आदि जैसे अवस्थापना मामले

5. एस. ए. टी. का सुदृढीकरण-अतिरिक्त पीठों का सृजन/पदों का सृजन/एस. ए. टी. के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान का सृजन/एस. ए. टी. आदि में ई-न्यायालय का कार्यान्वयन।
6. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रशासन (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2003
7. सेबी और विदेशी राष्ट्रों के प्रतिभूति बाजार नियामकों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन।
8. सेबी से भारत की संचित निधि में प्रेषण
9. सेबी अध्यक्ष की विदेश यात्राएं; विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की बैठकों की मेजबानी-आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करना

VIII. अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) अनुभाग

1. भारत-अमेरिका वित्तीय विनियामक वार्ता
2. भारत-ब्रिटेन वित्तीय बाजार वार्ता
3. भारत-ब्रिटेन वित्तीय साझेदारी
4. भारत-जापान वित्तीय वार्ता के विनियामक पहलू
5. मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के लिए वित्तीय सेवा ट्रेक के तहत वार्ता विशेष रूप से पूंजी बाजार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से संबंधित।
6. विभिन्न द्विपक्षीय वृहद आर्थिक संवादों और अंतरराष्ट्रीय समझौतों के लिए इनपुट सुविधा
7. अन्य अंतरराष्ट्रीय मामले

IX. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और निवेशक शिकायत (आईजी) अनुभाग

1. भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 से संबंधित मामले
2. शेयर बाजार घोटालों और उससे संबंधित मामलों पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करना।
3. निजाम ट्रस्ट से जुड़े मामले
4. एफएम डिवीजन से संबंधित निवेशकों की शिकायतों (इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक) का प्रबंधन/संबंधित प्राधिकरण को अन्य अभ्यावेदनों का हस्तांतरण
5. प्रतिभूति बाजारों के संदर्भ में निवेशकों की शिकायत निवारण तंत्र में आवश्यक सुधारों पर अध्ययन/सर्वेक्षण
6. 5 राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड) का आंतरिक प्रभार

X. समन्वय अनुभाग

1. विभिन्न विभागों/मंत्रालयों को आवधिक इनपुट/रिपोर्ट प्रदान करने, वार्षिक रिपोर्टों, आर्थिक समीक्षा आदि के लिए सामग्री प्रस्तुत करने के लिए एफएम प्रभाग के अंतर्गत आंतरिक समन्वय।
2. सचिव (आर्थिक कार्य) द्वारा लंबित वीआईपी संदर्भ, पीएमओ संदर्भ और संसदीय मूल्यांकन के लिए हर सप्ताह सोमवार को वरिष्ठ प्रबंधन समूह (एसएमजी) पर बैठक। एफएम डिवीजन से संबंधित शिकायतों, वीआईपी/पीएमओ संदर्भों, कैबिनेट नोट्स, अदालती मामलों, वरिष्ठ प्रबंधन समूह की बैठकों आदि के संबंध में ई-समीक्षा और पोर्टलों का प्रबंधन।
3. वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति से संबंधित मामला - वित्तीय बाजार प्रभाग से संबंधित विषयों पर उनके अध्ययन दौरों से संबंधित
4. आर्थिक कार्य विभाग में की गई गतिविधियों, प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सारांश मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजा जाता है
5. एफएम प्रभाग के अंतर्गत कार्य प्रबंधन/आवंटन के मुद्दे
6. एफएम प्रभाग के मामलों के संबंध में वेबसाइट प्रबंधन
7. एफएम प्रभाग के अंतर्गत युवा पेशेवर/सलाहकारों और इंटरनशिप प्रबंधन की नियुक्ति का मामला

क. प्राथमिक बाजार

- 1.1 भारत के पूंजी बाजारों ने प्राथमिक बाजार में बेहतर गतिविधि के कारण मजबूत गति बनाए रखी। वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड वर्ष के बाद, वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान जुटाई गई पूंजी पहले से ही पिछली ऊंचाई को पार कर चुकी है, जो आर्थिक विस्तार को सुविधाजनक बनाने में भारत के पूंजी बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- 1.2 इस अवधि के दौरान, 354 सार्वजनिक-इक्विटी और अधिकार निर्गमों के माध्यम से कुल ₹1,63,390 करोड़ जुटाए गए। वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) में आईपीओ गतिविधि को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) घटक की बढ़ती प्रमुखता द्वारा चिह्नित किया गया था, जो मेनबोर्ड आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई कुल निधि का 59 प्रतिशत और एसएमई आईपीओ में 23 प्रतिशत था।
- 1.3 पिछले वित्त वर्ष की तुलना में, क्वालिफाइड इस्टीमेटेड प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से जुटाई गई निधि में गिरावट देखी गई और वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान ₹52,406 करोड़ हो गई, जबकि प्रेफरेंशियल 53 लाख 47 हजार आवंटन में मामूली वृद्धि हुई, जिसमें कुल राशि ₹95,892 करोड़ थी।
- 1.4 कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में, सूचीबद्ध निजी प्लेसमेंट संसाधन जुटाने के लिए पसंदीदा मार्ग बने रहे, जबकि सार्वजनिक निर्गम कुल निर्गमों का केवल

एक छोटा भाग था। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान ₹6,09,183 करोड़ जुटाए गए।

1.5 वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स, आरईआईटी और आईएनवीआईटीएस के माध्यम से जुटाई गई निधि ₹13,893 करोड़ थी।

1.6 कई नगर निगमों ने म्युनिसिपल बांड के वादे को पूरा करना शुरू कर दिया है और चालू वर्ष में भी यह गति जारी है। वित्त वर्ष 26 (नवंबर 2025 तक) में, 9 नगर पालिकाओं ने सामूहिक रूप से म्युनिसिपल बांड की कई किशतों के माध्यम से ₹1,000 करोड़ जुटाए। इसमें टिकाऊ परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं आदि के वित्तपोषण के लिए जारी किए गए ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड भी शामिल हैं।

तालिका 1: सार्वजनिक और अधिकार निर्गम के माध्यम से प्राथमिक बाजार से जुटाई गई पूंजी

वित्त वर्ष	कुल (सार्वजनिक + अधिकार)		श्रेणी-वार (इक्विटी)				मुद्दे का प्रकार			
			सार्वजनिक#		अधिकार		अधिमान्य मुद्दा		क्यूआईपी	
	निर्गम की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	निर्गम की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	निर्गम की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	निर्गम की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)	निर्गम की संख्या	राशि (करोड़ रुपये)
2023-24	340	83,093	273	67,982	67	15,110	689	45,155	61	68,972
2024-25	464	2,10,190	322	1,90,478	142	19,712	988	84,084	91	1,35,597
2025-26 (अप्रैल-नवंबर)	354	1,63,390	261	1,46,462	93	16,927	853	95,892	28	52,406

टिप्पणियाँ:

इक्विटी सार्वजनिक निर्गम में एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध निर्गम भी शामिल हैं।

डेटा लिस्टिंग तिथि पर आधारित है।

स्रोत: एक्सचेंज

तालिका 2: भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने के माध्यम से जुटाई गई धनराशि

वित्त वर्ष	सार्वजनिक निर्गम की संख्या	सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जुटाई गई राशि (करोड़ रुपये)	निजी प्लेसमेंट की संख्या	प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई राशि (करोड़ रुपये)	सार्वजनिक निर्गम और प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई कुल राशि (करोड़ रुपये)
2023-24	45	19,167	1,347	8,37,756	8,56,923
2024-25	43	8,149	1,659	9,86,735	5,38,416
2025-26 (अप्रैल-नवंबर)	29	6,503	1,288	6,02,680	6,09,183

टिप्पणियाँ:

जारी करने की अंतिम तिथि के आधार पर सार्वजनिक ऋण संबंधी मुद्दे

स्रोत: एक्सचेंज

तालिका 3: नगरपालिका बांड के माध्यम से संसाधन जुटाना

वित्त वर्ष	नगरपालिका बांड मुद्दों की संख्या	उठाई गई राशि (करोड़ रुपये)
2022-23	1	244
2023-24	3	500
2024-25	1	100
2025-26 (अप्रैल-नवंबर)	9	1,000

तालिका 4: आरईआईटी और आईएनवीआईटीएस के माध्यम से संसाधन जुटाना

वित्त वर्ष	आरईआईटी	आईएनवीआईटीएस #@	कुल
	राशि (करोड़ रुपये)	राशि (करोड़ रुपये)	राशि (करोड़ रुपये)
2023-24	5,905	33,119	39,024
2024-25	4,728	26,715	31,442
2025-26 (अप्रैल-नवंबर)	5,800	8,093	13,893

टिप्पणियाँ:

InvITs में सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों InvITs शामिल हैं

@ में पब्लिक इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, तरजीही इश्यू, इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, राइट्स इश्यू के माध्यम से जुटाई गई फंडिंग शामिल है।

स्रोत: सेबी

1.7 वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक, 22,100 करोड़ रुपये के शेयरों का 92 पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण हुए, जबकि वित्त वर्ष 25 के दौरान 15,457 करोड़ रुपये के 71 ऐसे अधिग्रहण शामिल थे।

2. म्यूचुअल फंड

2.1 म्यूचुअल फंड ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान पूंजी बाजारों में घरेलू और संस्थागत बचत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा, नवंबर 2025 तक 7,91,533 करोड़ रुपये जुटाए। समीक्षाधीन अवधि के

दौरान, आय/ऋण उन्मुख योजनाओं में 3,29,777 करोड़ रुपये (कुल निवल प्रवाह का 42 प्रतिशत) का उच्चतम प्रवाह देखा गया, इसके बाद विकास/इक्विटी उन्मुख योजनाओं में 2,27,876 करोड़ रुपये, हाइब्रिड योजनाओं में 1,31,261 करोड़ रुपये और समाधान उन्मुख और अन्य योजनाओं में 1,02,619 करोड़ रुपये का प्रवाह हुआ।

2.2 नवंबर 2025 तक, म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत एसेट (एयूएम) ₹80 लाख करोड़ था, जो मार्च 31, 2025 से 22 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

तालिका 5: म्यूचुअल फंड एयूएम में तीव्र विस्तार

अवधि	फोलियो की संख्या	सकल संसाधन जुटाना	प्रतिदान	जुटाए गए कुल संसाधन	एयूएम
	(करोड़)		(₹ लाख करोड़)		
वित्त वर्ष 23	14.57	105.07	104.31	0.76	39.42
वित्त वर्ष 24	17.79	114.48	110.94	3.55	53.4
वित्त वर्ष 25	23.45	137.03	128.88	8.15	65.74
वित्त वर्ष 26*	25.86	99.81	91.9	7.91	80.8

*30 नवंबर, 2025 तक

तालिका 6: योजना श्रेणी-वार म्यूचुअल फंड में/से निवल प्रवाह (₹ करोड़ रुपये)

अवधि	आय/ऋण केंद्रित योजनाएं	विकास/इक्विटी केंद्रित योजनाएं	हाइब्रिड योजनाएं	समाधान केंद्रित योजनाएं	अन्य योजनाएं	कुल
2023-24	-34,588	1,81,362	1,44,954	2,284	60,689	3,54,701
2024-25	1,35,794	4,16,676	1,19,032	3,292	1,40,320	8,15,115
2025-26 (अप्रैल-नवंबर)	3,29,777	2,27,876	1,31,261	2,060	1,00,559	7,91,533

3. पोर्टफोलियो प्रबंधक

3.1 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ (पीएमएस) उद्योग वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान लगातार विस्तार करता रहा, जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड ऑफरिंग से परे कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट रणनीतियों की मांग करने वाले हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) की बढ़ती संख्या द्वारा

समर्थित है। आस्ति एप्रिसिएशन और बढ़े हुए क्लाइंट बेस से प्रेरित, नवंबर 2025 के अंत तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ का संचयी एयूएम ₹41 लाख करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक था। यह वृद्धि मुख्य रूप से विवेकाधीन पोर्टफोलियो जनादेश द्वारा संचालित थी, जो कुल आस्तियों का लगभग 84 प्रतिशत था।

तालिका 7: पीएमएस द्वारा प्रबंधित आस्तियों में वृद्धि

अवधि	एयूएम (₹ करोड़ में)				कुल
	विवेकाधीन	गैर-विवेकाधीन	सह-निवेश	सलाहकार **	
नवंबर-25	34,43,597	3,15,240	6,000	3,43,273	41,08,110
अक्टूबर-25	34,19,490	3,15,020	5,533	3,44,255	40,84,298
नवंबर-24	30,65,854	2,97,892	3,649	2,97,385	36,64,780

टिप्पणियाँ:

- **आस्तियों का मूल्य जिसके लिए सलाहकार सेवाएं दी जा रही हैं।
- उपरोक्त एयूएम में से, ₹29,04,662/करोड़ का योगदान ईपीएफओ/पीएफ से कोष द्वारा किया जाता है।
- उपरोक्त डेटा 480 पीएमएस द्वारा किए गए प्रस्तुतियों के अनुसार है।

स्रोत: सेबी

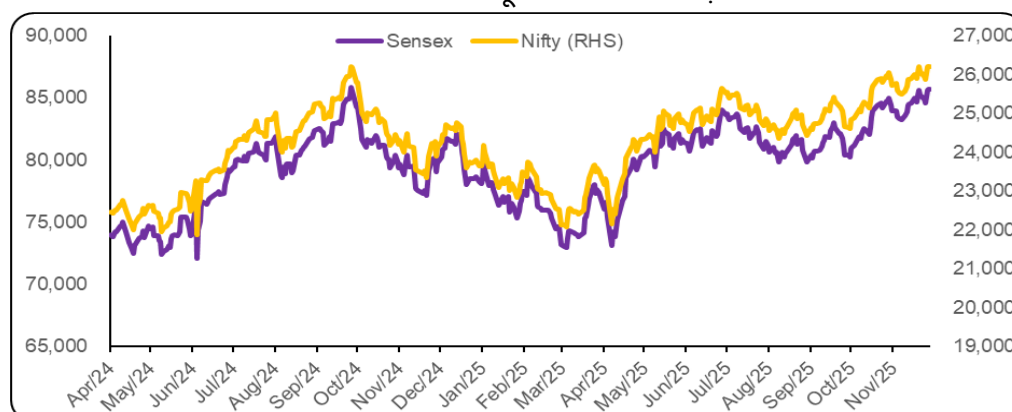
ख. द्वितीयक बाजार

4.1 वर्ष 2025-26, अब तक, भारत सहित दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों के लिए घटनापूर्ण रहा है। व्यापार नीतियों में निरंतर बदलाव और बढ़ती अनिश्चितताओं के बीच, भारत के इक्विटी बाजारों ने लचीला प्रदर्शन का एक चरण प्रदर्शित किया, जो सहायक नीतियों, व्यापक आर्थिक स्थितियों और निरंतर घरेलू निवेशक भागीदारी की परस्पर क्रिया को दर्शाता है। भारतीय इक्विटी के लिए, वित्त वर्ष की शुरुआत, अप्रैल की शुरुआत में यूएस रेसिप्रोकल-टैरिफ फ्रेमवर्क की घोषणा के साथ, निर्यात-उन्मुख और वैश्विक रूप से जुड़े क्षेत्रों में जोखिम से बचने के लिए नरम स्तर

पर हुई। दिनांक 7 अप्रैल, 2025 को निफ्टी 50 इंडेक्स 3.2 प्रतिशत तक गिर गया, जो अप्रैल 2024 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। फिर भी, वित्तीय वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के बाद से, नरम मुद्रास्फीति रीडिंग और घरेलू कारकों ने अधिक सहायक भूमिका निभाई और बाद के महीनों के माध्यम से जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार किया।

4.2 भारतीय इक्विटी बेंचमार्क, निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान 11.4 प्रतिशत और 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 1: भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों का उतार-चढ़ाव



4.3 हालांकि, दक्षिण कोरिया (कोस्पी), जापान (निक्केई), यूएस (नैस्डैक), ताइवान (टीएआईईएक्स) आदि जैसे वैश्विक समकक्षों की तुलना में, भारत का इक्विटी बाजार प्रदर्शन कम था। इन वैश्विक सूचकांकों का बेहतर प्रदर्शन सेमीकंडक्टर, पूंजीगत उपकरण और एआई संबंधी हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर आपूर्ति श्रृंखलाओं में केंद्रित लाभ - ऐसे क्षेत्र जो मजबूत एआई निवेश और मजबूत अंतःबाजार मांग से लाभान्वित हुए थे, से निकटता से जुड़ा हुआ था।

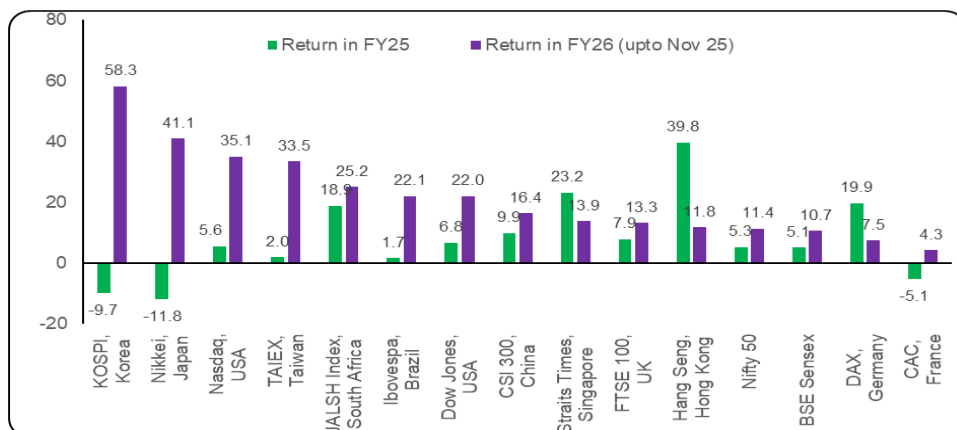
तालिका 8: विश्व के प्रमुख इक्विटी सूचकांकों का प्रदर्शन

सूचकांक	वित्त वर्ष 2023-24 (31 मार्च, 2024 को बंद होगा)	वित्त वर्ष 2024-25 31 मार्च, 2025 तक बंद होगा)	वित्त वर्ष 2025-26 (30 नवंबर, 2025 को बंद होगा)	वित्त वर्ष 2024- 25 में रिटर्न	वित्त वर्ष 2025-26 में रिटर्न (25 नवंबर तक)
भारतीय बाजार					
बीएसई सेंसेक्स	73,651	77,415	85,707	5.1%	10.7%
निफ्टी 50	22,327	23,519	26,203	5.3%	11.4%
उभरते बाजार					
जलश सूचकांक, दक्षिण अफ्रीका	74,536	88,637	1,10,959	18.9%	25.2%
टीएआईईएक्स, ताइवान	20,294	20,696	27,626	2.0%	33.5%
शंघाई कम्पोजिट, चीन	3,537	3,887	4,527	9.9%	16.4%
इबोवेस्पा, ब्राजील	1,28,106	1,30,260	1,59,072	1.7%	22.1%
कोस्पी, कोरिया	2,747	2,481	3,927	-9.7%	58.3%
विकसित बाजार					
हैंग सेंग, हांगकांग	16,541	23,120	25,859	39.8%	11.8%
नैस्डैक, यूएसए	16,379	17,299	23,366	5.6%	35.1%
डॉव जोन्स, यूएसए	5,254	5,612	6,849	6.8%	22.0%
स्ट्रेट्स टाइम्स, सिंगापुर	3,224	3,972	4,524	23.2%	13.9%
डैक्स, जर्मनी	18,492	22,163	23,837	19.9%	7.5%
एफटीएसई 100, यूके	7,953	8,583	9,721	7.9%	13.3%
निक्केई, जापान	40,369	35,618	50,254	-11.8%	41.1%
सीएसी, फ्रांस	8,206	7,791	8,123	-5.1%	4.3%

स्रोत: ब्लूमबर्ग

4.4 सबसे ज्यादा रिटर्न दक्षिण कोरिया की कोस्पी को मिली, उसके बाद जापान की निक्केई और अमेरिका की नैस्डैक का नंबर रहा।

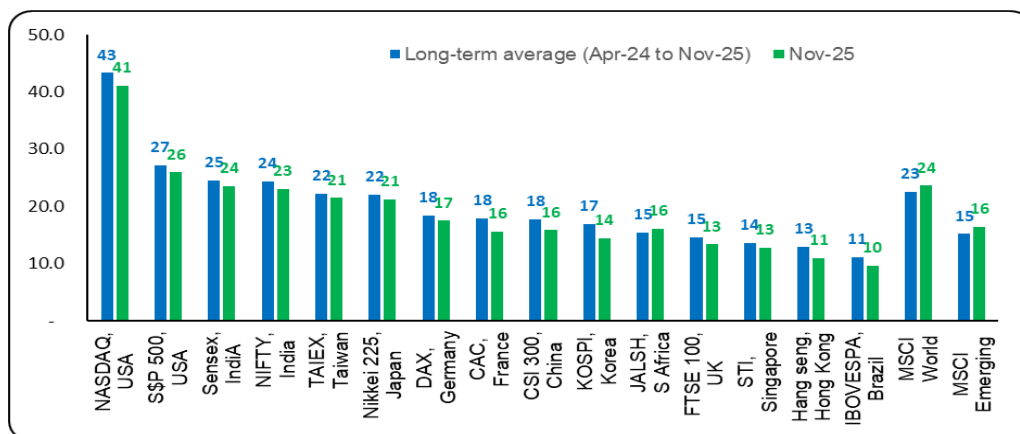
चार्ट 2: प्रमुख विश्व सूचकांकों का रिटर्न



4.5 नवंबर 2025 के अंत में, निफ्टी 50 का 24.3 पर बारह महीनों का पी/ई अनुपात प्रमुख वैश्विक इक्विटी सूचकांकों में मध्यम रूप से बढ़ गया था। भारतीय इक्विटी ने प्रीमियम पर ट्रेड करना जारी रखा (अमेरिका

मार्केट के पीछे ट्रेलिंग) उन्हें अधिक महंगा बना दिया जैसा कि वित्त वर्ष 2026 में अब तक ₹27,101 करोड़ की एफपीआई इक्विटी सेल द्वारा देखा गया है।

चार्ट 3: दीर्घावधिक औसत के साथ प्रमुख सूचकांकों के पी/ई अनुपात की तुलना



स्रोत: ब्लूमबर्ग, एनएसई

4.6 वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशक की हिस्सेदारी 34.2 प्रतिशत थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से मामूली कमी है।

तालिका 9: एनएसई में इक्विटी कैश सेगमेंट टर्नओवर में व्यक्तिगत निवेशकों का हिस्सा

वर्ष	व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी (प्रतिशत)
2024-25	34.3
2024-25*	34.9
2025-26*	34.2

नोट:

i. व्यक्तिगत निवेशकों में व्यक्तिगत घरेलू निवेशक, एनआरआई, एकल स्वामित्व फर्म और एचयूएफ शामिल हैं

ii. उपरोक्त प्रतिशत शेयर नीलामी ट्रेडों के साथ कारोबार को बाहर रखता है।

iii. *संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए अप्रैल से नवंबर के दौरान प्रतिनिधित्व करता है

स्रोत: एनएसई

4.7 वित्त वर्ष 2026 के दौरान डीमैट खातों की क्रमिक वृद्धि लगातार बढ़ रही है। मार्च 2025 के अंत में डीमैट खातों की संख्या 19.24 करोड़ की तुलना में नवंबर 2025 के अंत तक 10.6 प्रतिशत से बढ़कर 21.28 करोड़ हो गई।

तालिका 10: डीमैट खातों के रुझान (करोड़)

अवधि	डीमैट खातों की कुल संख्या	इस अवधि के दौरान जोड़े गए डीमैट खातों की कुल संख्या
2023-24	15.12	3.67
2024-25	19.24	4.12
2025-26*	21.28	2.03

*30 नवंबर, 2025 तक प्रतिनिधित्व करता है

स्रोत: एनएसडीएल, सीडीएसएल

टर्नओवर

4.8 वित्त वर्ष 2026 में समग्र ट्रेडिंग परिदृश्य में परिवर्तन के एक चरण परिलक्षित हुआ है, जो इक्विटी बाजार एक्टिविटी में मॉडरेशन और कुछ मार्केट खंड में नई गति द्वारा चिह्नित किया गया है। नवंबर 2025 के अंत तक, कमोडिटी डेरिवेटिव को छोड़कर अधिकांश खंड में टर्नओवर वित्त वर्ष 2025 की तुलना में अस्वीकार कर दिया गया है। कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में वृद्धि मुख्य रूप से बुलियन में मजबूत व्यापार और बाजार की भागीदारी में वृद्धि से प्रेरित थी।

तालिका 11: टर्नओवर के रुझान (मासिक औसत षलाख करोड़ में)

खंड	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 26*	वित्त वर्ष 25 से वित्त वर्ष 26* तक भिन्नता (प्रतिशत)
इक्विटी नकद खंड	25.1	22.6	▼ -10
इक्विटी डेरिवेटिव-काल्पनिक	8,826.3	8,446.4	▼ -4
इक्विटी डेरिवेटिव्स-प्रीमियम	14.8	14.1	▼ -5
मुद्रा डेरिवेटिव	1.4	0.7	▲ -51
वस्तु डेरिवेटिव	48.3	97.3	101

* नवंबर के अंत तक प्रतिनिधित्व करता है

स्रोत: एक्सचेंज

4.9 कमोडिटी डेरिवेटिव कुल कारोबार वित्त वर्ष 2025 की तुलना में वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-नवंबर) के दौरान 34 प्रतिशत बढ़ गया, जो बुलियन खंड में टर्नओवर में वृद्धि से प्रेरित है।

तालिका 12: कमोडिटी डेरिवेटिव कुल कारोबार

	वित्त वर्ष 24	वित्त वर्ष 25	वित्त वर्ष 25*	वित्त वर्ष 26*	वित्त वर्ष 26* वित्त वर्ष 25* से अधिक भिन्नता (प्रतिशत)
एमसीएक्स	2,76,55,480	5,65,18,177	3,53,19,615	7,67,74,264	▲ 117
एनसीडीएक्स	2,06,112	1,48,048	1,03,006	99,046	▼ -4
एनएसई	2,01,699	13,05,456	6,69,396	9,68,739	▲ 45
बीएसई	36	281	281	0	▼ -100
कुल	2,80,63,327	5,79,71,961	3,60,92,297	7,78,42,049	▲ 116

* नवंबर 2025 तक प्रतिनिधित्व करता है

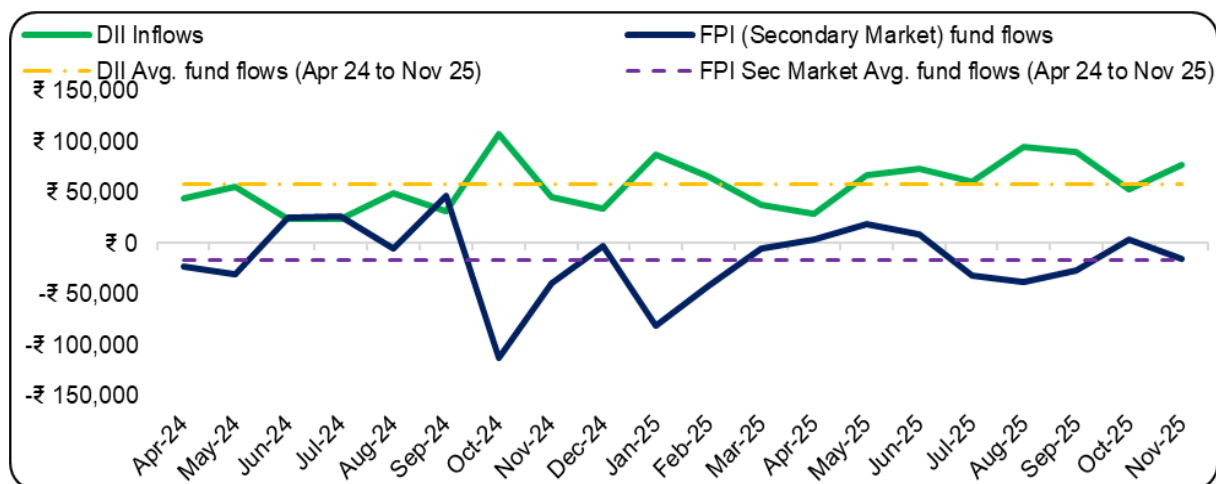
स्रोत: एक्सचेंज

घरेलू संस्थागत निवेशक अपनी प्रतिकारी भूमिका से आगे बढ़ रहे हैं

4.10 वित्त वर्ष 26 (अप्रैल-नवंबर) में, बैंकों, डीएफआई, बीमा, म्यूचुअल फंड और एनपीएस सहित डीआईआई प्रभावी रूप से एफपीआई बहिर्वाह की भरपाई करते हुए इक्विटी के निवल खरीदार बने हुए हैं। डीआईआई ने 6 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जो वित्त वर्ष 2025 में इसी अवधि के

दौरान 3.6 लाख करोड़ रुपये से तेज वृद्धि है। डीआईआई द्वारा निवल निवेश में वृद्धि (अप्रैल-नवंबर 2024 में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये बनाम 3.4 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड उच्च निवल निवेश), डीआईआई द्वारा कुल निवल निवेश में लगभग 75 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ म्यूचुअल फंडों द्वारा की गई थी।

चार्ट 4: डीआईआई एफपीआई आउटफ्लो को संतुलित करना



स्रोत: एनएसडीएल, बीएसई, एनएसई

प्रमुख बातें:

4.11 कारोबार/निवेश करने की सुगमता को सुविधाजनक बनाना

- आईपीओ प्रक्रिया में संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, आईआरडीएआई के साथ पंजीकृत जीवन बीमा कंपनियों और पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन फंड को घरेलू म्यूचुअल फंड सहित एकीकृत भाग की आरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है।
- संस्थागत निवेशकों और बाजार भागीदारों के लिए कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, एकल मात्रा भारित औसत मूल्य के साथ सामान्य संविदा

नोट को अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुधार कई एक्सचेंजों में निष्पादित ट्रेडों को एक एकल, सामंजस्यपूर्ण दस्तावेज में समेकित करके व्यापार के बाद की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सरल बनाएगा, जिससे कई संविदा नोटों को संसाधित करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

- दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल केवाईसी की पहुंच और समावेशन में सुगमता सुनिश्चित करने हेतु, दिव्यांगजनों सहित ग्राहकों के लिए डिजिटल पहुंच को सक्षम करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए मध्यस्थों को अनिवार्य किया गया था। मध्यस्थों के मार्गदर्शन हेतु दिव्यांगजनों द्वारा खाता खोलने के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सेबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

- कारोबारी सुगमता में सुधार, जोखिम में कमी लाने और एंजेल फंड्स को परिचालन संबंधी स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से, **एंजेल फंड के लिए एक संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क निर्धारित** किया गया है।
- एफपीआई के पंजीकरण, केवाईसी आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के लिए दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया ताकि **केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले एफपीआई** के लिए विनियामक अनुपालन को आसान बनाया जा सके।
- एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग के लिए एनआरआई हेतु निवेश करने में आसानी और सुविधा की दिशा में एक कदम के रूप में, **अनिवासी भारतीयों की भुगतान सदस्य के नाम अधिसूचित करने और बाद में एक्सचेंज द्वारा अनिवासी भारतीयों को कस्टोडियल पार्टिसिपेंट (सीपी) कोड के सुपुर्दगी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।**
- निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) में सूचीबद्ध सामाजिक उद्यमों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए, **एसएसई फ्रेमवर्क** को गैर-लाभकारी संगठन (एनपीओ) पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करके और एनपीओ द्वारा वार्षिक प्रकटीकरण को मजबूत करके संशोधित किया गया था।
- आरईआईटी और इनविट के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की समीक्षा के लिए कार्य समूह की कारोबारी सुगमता सिफारिशों के आधार पर, **प्रस्ताव दस्तावेज/प्लेसमेंट झापन में वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण और आरईआईटी और इनविट द्वारा निरंतर प्रकटीकरण और अनुपालन को संशोधित किया गया था।**
- कारोबारी सुगमता के साथ-साथ निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए, निक्षेपागार प्रणाली में गिरवी रखने/पुनः गिरवी रखने के माध्यम से दिए जाने वाले मार्जिन दायित्वों के मामले में, **मांग और बिक्री को एक संयुक्त स्वचालित प्रक्रिया के रूप में बनाने** का निर्णय लिया गया।
- कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ-साथ सभी एमआईआई में इकाई के परिचालन का व्यापक दृष्टिकोण रखने के लिए, एमआईआई द्वारा अलग-अलग निरीक्षण के बजाय एक **संयुक्त वार्षिक निरीक्षण** करने का निर्णय लिया गया।
- निवेश सलाहकारों और अनुसंधान विश्लेषकों को जमा आवश्यकता के अनुपालन के लिए बैंक जमा के विकल्प के रूप में **लिव्ज्ड म्यूचुअल फंड और ओवरनाइट म्यूचुअल फंड का उपयोग** करने की अनुमति दी गई थी।
- **श्रेणी I और श्रेणी II एआईएफ को मान्यता प्राप्त निवेशकों को सह-निवेश सुविधा प्रदान करने वाली एक अलग सह-निवेश योजना (सीआईवी योजना) शुरू करने की अनुमति दी गई थी।**
- एआईएफ विनियमों में संशोधन किया गया था ताकि एआईएफ योजनाओं की विशेष रूप से केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए (केवल एआई-योजनाएं) के लिए, कम निवेशक सुरक्षा अनुपालन और परिचालन तन्त्र्यता के साथ एक अलग श्रेणी शुरू की जा सके, जिन्हें मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए बड़े मूल्य के फंड (एलवीएफ) तक भी बढ़ाया गया था।
- उच्च निवेशक भागीदारी की सुविधा के लिए, एआईएफ के तहत बड़े मूल्य की योजनाओं के लिए न्यूनतम निवेश सीमा को 70 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
- सरलीकरण और कारोबारी सुगमता के उद्देश्य से, **पीएमएस व्यवसाय को एक पोर्टफोलियो मैनेजर से दूसरे में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।**
- निवेश सलाहकारों को **असेट्स अंडर एडवायज (एयूए)** आधारित शुल्क लेने और पहले से मौजूद वितरण व्यवस्था के तहत आस्तियों के संबंध में ग्राहकों को दूसरी राय प्रदान करने की अनुमति दी गई है।
- स्टॉक ब्रोकरों के लिए कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए, **स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्टॉक ब्रोकरों पर जुर्माना लगाने के लिए दंड फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत और मानकीकृत किया गया है।**
- निवेशक आधार के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में म्यूचुअल फंड वितरकों की सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए, **बी-30 शहरों से नए व्यक्तिगत निवेशकों और महिला निवेशकों को शामिल करने के लिए वितरकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन शुरू करके प्रोत्साहन संरचना को नया रूप दिया गया था।**
- म्यूचुअल फंड और विशेष निवेश फंड (एसआईएफ) द्वारा बढ़ी हुई भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, 1 जनवरी, 2026 से **म्यूचुअल फंड और एसआईएफ द्वारा आरईआईटी में किए गए किसी भी निवेश को इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश माना जाएगा।** हालांकि, इसी उद्देश्य के लिए इनविट को हाइब्रिड उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा।
- **सेबी (डिबेंचर ट्रस्टीज) विनियम, 1993 में संशोधन किया गया था ताकि किसी डीटी के लिए अनुमत कार्यकलापों पर स्पष्ट किया जा सके।** डीटी को अब वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामक (आरबीआई, आईआरडीए, पीएफआरडीए, आईएफएससीए आदि) के विनियामक दायरे में आती हैं और ऐसी गतिविधियां भी जो वर्तमान में किसी भी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा विनियमित नहीं हैं। दोनों गतिविधियों को एक चाइनीज वॉल द्वारा अलग की गई अलग-अलग व्यावसायिक इकाइयों (एसबीयू) के माध्यम से एक थोड़ी दूरी के आधार पर किया जाएगा और सेबी द्वारा विनियमित गतिविधियों से अलग किया जाएगा।

4.12 निवेशक संरक्षण और सशक्तिकरण

- प्रतिरूपण के इस बढ़ते मुद्दे को हल करने और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए, सेबी ने सभी सेबी पंजीकृत मध्यस्थों के लिए एक नया यूपीआई एड्रेस स्ट्रक्चर अनिवार्य किया है, जो 01 अक्टूबर, 2025 से निवेशकों से धन एकत्र करते हैं। यह अभिनव तंत्र एक सत्यापित और सुरक्षित भुगतान चैनल प्रदान करके प्रतिभूति बाजार के भीतर वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा और पहुंच में काफी सुधार करने के लिए तैयार है।
- निवेशकों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, सेबी ने 01 अक्टूबर, 2025 से “सेबी चेक” नामक एक नई कार्यक्षमता विकसित की है। यह टूल निवेशकों को सेबी पंजीकृत मध्यस्थों यूपीआई आईडी की प्रामाणिकता को या तो क्यूआर कोड स्कैन करके या मैन्युअल रूप से यूपीआई आईडी दर्ज करके सत्यापित करने की अनुमति देता है और बैंक विवरण जैसे बैंक खाता संख्या और पंजीकृत मध्यस्थ के आईएफएससी की पुष्टि भी करता है।
- जुलाई 2025 में एमआईआई के सहयोग से सेबी द्वारा “सेबी वर्सेज स्कैम” शीर्षक से एक संयुक्त मीडिया अभियान शुरू किया गया था। इस एकीकृत पहल का उद्देश्य निवेशक सुरक्षा को मजबूत करना और प्रतिभूति बाजार के भीतर वित्तीय धोखाधड़ी और घोटालों का समाधान करना है। अभियान के लिए फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में रेड फ्लैग, सत्यापन प्रोटोकॉल, विश्वसनीय निवारण तंत्र और बेहतर डिजिटल पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।
- सेबी ने पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के सहयोग से आधारभूत स्तर पर वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण पहल शुरू की, जिससे पूरे भारत में ग्रामीण समुदायों को शिक्षित करने के लिए ज्ञान के साथ प्रतिनिधियों को सशक्त बनाया जा सके।
- दिव्यांगजनों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, यह अधिदेशित किया गया है कि विनियमित संस्थाओं के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।
- निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, वास्तविक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को फिर से दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।
- निवेशक सुरक्षा बढ़ाने और वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के प्रयास में, सेबी ने अपनी विनियमित/पंजीकृत संस्थाओं को सलाह दी है कि वे अपने मौजूदा ग्राहकों को विशेष रूप से सेवा और संव्यवहार वॉयस कॉल के लिए केवल ‘1600’ फोन नंबर

श्रृंखला का उपयोग करें। यह निवेशकों की सुरक्षा को बढ़ाएगा और नियमित 10 अंकों के नंबरों का उपयोग करने वाली बेईमान संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी के जोखिम को कम करेगा।

4.13 बॉन्ड बाजार को मजबूत करना और पहुंच का विस्तार करना

- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) ऋण प्रतिभूतियों (हरित ऋण प्रतिभूतियों के अलावा) के लिए नया फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया था, जो सामाजिक, स्थिरता और स्थिरता से जुड़े बांड (एसएलबी) के जारीकर्ताओं के लिए विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
- प्रभावकारिता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए, निजी प्लेसमेंट आधार पर विभिन्न प्रतिभूतियों को प्राथमिक रूप से निर्गमन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुक प्रोवाइडर (ईबीपी) फ्रेमवर्क से संबंधित कुछ प्रावधानों को संशोधित किया गया था। इसमें अनिवार्य ईबीपी सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये करना, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों के निजी प्लेसमेंट की अनुमति देना, आरईआईटी, एसएम आरईआईटी और इनविट की अनुमति देना, प्रकटीकरण में वृद्धि आदि शामिल हैं।
- बॉन्ड बाजारों को विकसित करने के लिए सेबी की पहल के हिस्से के रूप में, नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं की समस्याओं, निवेशकों की आवश्यकताओं, मौजूदा विनियामक फ्रेमवर्क पर चर्चा करने और नगरपालिका ऋण प्रतिभूतियों के लिए बाजार में जागरूकता बढ़ाने और सुधार के उपायों की सिफारिश करने के लिए हितधारकों को एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए नगरपालिका बांड और नगरपालिका वित्त पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
- उद्धरण के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) प्लेटफॉर्म की समीक्षा के बाद, कॉर्पोरेट बॉन्ड डेटाबेस में नकदी प्रवाह प्रकटीकरण के लिए परिचालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया था। यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि आय से मूल्य गणना के उद्देश्य से आरएफक्यू प्लेटफॉर्म पर कारोबार की गई गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए ब्याज/लाभांश/मोचन के भुगतान के संबंध में नकदी प्रवाह की तारीखों को दिन की गणना के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा और तदनुसार नकदी प्रवाह अनुसूची के अनुसार भुगतान की नियत तारीख पर आधारित होगा, न कि भुगतान की तारीख के अनुसार।
- कारोबारी सुगमता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों (एसडीआई) को जारी करने के लिए निवेशकों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को डेटा के प्रसार के लिए, एसडीआई जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए दिशानिर्देशों को मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के साथ संरेखित की गई थी।

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को सलाह दी गई थी कि वे नगरपालिका बॉन्ड की रेटिंग के लिए ईएल-आधारित रेटिंग स्केल का विस्तार करें, जो मानकीकृत रेटिंग स्केल के अलावा, अवसंरचना आस्तियों के वित्तपोषण के लिए जारी किए जाते हैं।

4.14 विनियामक फ्रेमवर्क को मजबूत करना

- सेबी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों को एक अलग व्यवसाय इकाई (एसबीयू) के तहत गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (जीआईएफटी-आईएफएससी) में प्रतिभूति बाजार से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने की सुविधा के लिए, सेबी से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- सूचीबद्ध संस्थाओं को संबंधित पक्षकार संव्यवहार के अनुमोदन के लिए लोक लेखा समिति और शेयरधारकों की समीक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली “न्यूनतम जानकारी” पर उद्योग मानकों का पालन करना अनिवार्य किया गया था।
- एक निजी सूचीबद्ध इनविट को सार्वजनिक इनविट में बदलने के लिए इकाइयों के सार्वजनिक निर्गम में प्रायोजक (ओं) और प्रायोजक समूहों से न्यूनतम योगदान से संबंधित आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित किया गया था।
- पंजीकृत मध्यस्थों को आधार आधारित ई-केवाईसी प्रमाणीकरण करने के लिए एक अतिरिक्त वैकल्पिक तंत्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की ‘ई-केवाईसी सेतु प्रणाली’ का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।

4.15 बाजार के विकास को बढ़ावा देना

- निवेशकों को आईए, आरए और एल्गोरिथम ट्रेडिंग प्रदाताओं के जोखिम और रिटर्न मेट्रिक्स दावों का स्वतंत्र सत्यापन प्रदान करने के लिए, जोखिम-वापसी प्रदर्शन सत्यापन के लिए एक “पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी (परवा)” प्रस्तुत की गई थी। इसे प्रचालित करने की प्रक्रिया चल रही है।
- एनएसई पर मासिक फ्यूचर्स ट्रेडिंग से शुरू होने वाले विद्युत डेरिवेटिव जुलाई 18, 2025 को लॉन्च किए गए थे। सेबी और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्युत डेरिवेटिव अनुचित परिकल्पना के बजाय प्रतिरक्षा के लिए उपकरण बने रहें, अनुबंध विनिर्देशों और जोखिम प्रबंधन मानदंडों को डिजाइन करने के लिए एक मजबूत, परामर्शी और डेटा-संचालित दृष्टिकोण का पालन किया।

4.16 इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय

- समाप्ति तिथि की अस्थिरता पर अंकुश लगाने और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए, एक्सचेंजों को इक्विटी डेरिवेटिव के लिए

समाप्ति तिथि के रूप में मंगलवार या गुरुवार का चयन करने का निर्देश दिया गया था।

- इक्विटी डेरिवेटिव खंड में ट्रेडिंग सुविधा में सुधार और जोखिम निगरानी को मजबूत करने के लिए उपाय शुरू किए गए थे। प्रमुख संशोधनों में डेल्टा समायोजन का उपयोग करके पोर्टफोलियो स्तर पर फ्यूचर इक्वालेट ओपन इंटररेस्ट (एफयूटीईक्यू ओआई) के रूप में ओपन इंटररेस्ट (ओआई) की गणना करने और एकल शेयरों के लिए मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट (एमडब्ल्यूपीएल) को पुनः कैलिब्रेट करने के लिए एक नई पद्धति शामिल है। नॉन-बेंचमार्क सूचकांकों पर डेरिवेटिव के लिए नए पात्रता मानदंड परिभाषित किए गए हैं, और नई एमडब्ल्यूपीएल परिभाषा के आधार पर व्यक्तिगत इकाई-स्तर की स्थिति सीमा को फिर से कैलिब्रेट किया गया है।
- अंतिम तिथि की निगरानी व्यवस्था के अलावा, स्टॉक एक्सचेंजों को इंटराडे आधार पर इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए स्थिति सीमा की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था।
- मौजूदा नॉन-बेंचमार्क सूचकांकों पर डेरिवेटिव के लिए पात्रता मानदंड यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि ऐसे सूचकांक व्यापक और विविध हैं। परिपत्र में यह अधिदेशित किया गया है कि प्रत्येक इंडेक्स में कम से कम 14 घटक स्टॉक शामिल होने चाहिए, जिसमें संकेद्रण जोखिम को रोकने के लिए व्यक्तिगत और शीर्ष-तीन स्टॉक वेटेज पर सीमा रखी गई है।

ग. कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट

5.1 सेबी कमोडिटी एक्सचेंजों (अर्थात् एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स) के सहयोग से कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार पर सिक्योरिटीज मार्केट ट्रेनर्स (स्मार्ट) कार्यक्रम और जागरूकता के लिए क्षेत्रीय निवेशक सेमिनार (आरआईएसए) के प्रमुख के तहत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान, लगभग 1,866 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 98,000 से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, मार्च 2026 तक लगभग 3,350 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की संभावना है।

5.2 अप्रैल 2025 से आगे की अवधि के दौरान कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार के विकास के लिए सेबी द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं:

- क) कृषि वस्तु व्युत्पन्न बाजार को मजबूत करने के लिए सेबी ने विभिन्न हितधारकों और बाजार प्रतिभागियों के साथ एक बैठक की थी। इसी के आधार पर निम्नलिखित दो कार्य समूहों का गठन किया गया:

- कृषि वस्तु व्युत्पन्न खण्ड पर लागू वर्तमान विनियामक मानदंडों की समीक्षा के लिए कार्य समूह।
- कृषि वस्तु व्युत्पन्न खण्ड में निपटान और वितरण तंत्र के वर्तमान ढांचे की समीक्षा के लिए कार्य समूह।

ख) सेबी ने गैर-कृषि वस्तु व्युत्पन्न खण्ड पर लागू मौजूदा विनियामक मानदंडों की समीक्षा के लिए एक कार्य समूह का गठन भी किया है। इस कार्य समूह से गैर-कृषि वस्तु व्युत्पन्न खण्ड को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श करने की अपेक्षा की जाती है।

ग) इसके अलावा, उक्त अवधि के दौरान, कृषि वस्तु व्युत्पन्न को निम्नलिखित नीतिगत पहलों से भी लाभ हुआ:

- कृषि वस्तु व्युत्पन्न बाजारों में किसानों/किसान उत्पादक संगठनों ("एफपीओ") की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सेबी ने कृषि वस्तु व्युत्पन्न में कारोबार के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों पर विनियामक शुल्क कम कर दिया है। इसका उद्देश्य विनियामक शुल्क में कमी के कारण शेयर बाजारों द्वारा बचाई गई राशि से किसानों/किसान उत्पादक संगठनों पर लागत का बोझ कम करना था। तदनुसार, सेबी ने बाजारों के लिए माफ किए गए विनियामक शुल्क के उपयोग के लिए ढांचा भी निधारित किया है। इस निधि का उपयोग, अन्य बातों के अलावा, उन किसानों/किसान उत्पादक संगठनों की बिक्री स्थितियों पर समाशोधन निगमों द्वारा मार्क-टू-मार्केट फंडिंग की लागत के लिए किया जा सकता है, जो अनुमोदित गोदामों में वस्तुओं का शीघ्र भुगतान करते हैं।
- एनसीडीईएक्स ने नाबार्ड के साथ मिलकर अप्रैल 2024 में वस्तु व्युत्पन्न बाजार में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों की मदद के लिए विकल्प प्रीमियम पर सब्सिडी देने की एक संयुक्त पहल शुरू की है। वर्तमान में, जीरा, धनिया और हल्दी जैसी तीन वस्तुओं पर प्रीमियम सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस पहल के लिए लगभग 15 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

घ. बाह्य बाजार और बाह्य वाणिज्यिक उधार

6.1 वित्त वर्ष 2026 (अप्रैल-दिसंबर) में अब तक, एफपीआई इक्विटी बाजार में निवल विक्रेता रहे हैं, दिसंबर 2025 के अंत तक कुल ₹49712 करोड़ का बहिर्वाह हुआ है। इसके विपरीत, वे ऋण क्षेत्र में निवल खरीदार रहे हैं, दिसंबर 2025 के अंत तक ₹9471 करोड़ का निवल अंतर्वाह हुआ है।

6.2 भारतीय बाजारों में ऋण क्षेत्रों में निवल विदेशी निवेश (एफपीआई) प्रवाह देखा गया, जिसका मुख्य कारण 28 जून, 2024 से जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम सूचकांक में भारतीय संप्रभु बांडों का समावेश था। सितंबर 2025 से, भारतीय संप्रभु बांडों को एफटीएसई इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स (ईएमजीबीआई), क्षेत्रीय एफटीएसई एशियन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स (एजीबीआई) और एफटीएसई एशियन-पैसिफिक गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स (एपीजीबीआई) और उनसे सदस्यता प्राप्त करने वाले सूचकांकों में शामिल किया गया, जिससे संभावित रूप से अधिक विदेशी निवेश आकर्षित होगा।

6.3 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) संशोधन नियम, 2025 अधिसूचना संख्या सा.का. 3732(अ) 11 जून, 2025 के तहत यह डीपीआईआईटी द्वारा प्रेस नोट 2 (2025 श्रृंखला) के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण को शामिल करने के लिए किया गया था, जिसमें भारतीय कंपनियों को मौजूदा पीआरओआई शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने की अनुमति दी गई थी, यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी जहां एफडीआई अन्यथा प्रतिबंधित है।

तालिका 13: एफपीआई का निवल निवेश - वित्तीय वर्ष

वित्तीय वर्ष	₹ करोड़					कुल
	इक्विटी	ऋण	ऋण - वीआरआर	ऋण- एफएआर	हाइब्रिड	
2014-15	1,11,333	1,66,127	0	0	0	2,77,461
2015-16	-14,172	-4,004	0	0	0	-18,176
2016-17	55,703	-7,292	0	0	0	48,411
2017-18	25,635	1,19,036	0	0	11	1,44,682
2018-19	-88	-42,357	0	0	3,515	-38,930
2019-20	6,153	-48,710	7,331	0	7,698	-27,528
2020-21	2,74,032	-50,443	33,265	0	10,247	2,67,101
2021-22	-1,40,010	1,628	12,642	0	3,498	-1,22,242
2022-23	-37632	-8937	5814	0	-181	-40936
2023-24	208212	121059	-2972	0	12767	339066
2024-25	-127041	55734	6737	80691	4425	20018
2025-26*	-49712	8052	-3676	5095	1433	-37754

* 31 दिसंबर, 2025 तक

स्रोत: एनएसडीएल

तालिका 14: मासिक एफपीआई निवल निवेश

माह (कैलेंडर वर्ष 2025)	मासिक एफपीआई निवल निवेश (करोड़ रुपये में)					कुल
	इक्विटी	ऋण	ऋण - वीआरआर	ऋण- एफएआर	हाइब्रिड	
जनवरी	-78027	-3424	-4197	8192	206	-77211
फरवरी	-34574	-5508	1531	14494	-318	-24301
मार्च	-3973	9711	-966	29044	-15	32981
अप्रैल	4223	-13314	-5649	-5421	-388	-20190
मई	19860	19615	1899	-9359	-689	30950
जून	14590	-6121	-6366	-10040	150	-7563
जुलाई	-17741	-234	4296	7750	-463	-5538
अगस्त	-34993	6766	-872	6768	151	-20505
सितंबर	-23885	1085	1213	9956	223	-12539
अक्टूबर	14610	3507	-427	15144	2869	35598
नवंबर	-3765	-3969	4485	4158	104	2836
दिसंबर	-22611	717	-2255	-13861	-532	-38568
कुल	-166286	8831	-7308	56825	1298	-104050

स्रोत एनएसडीएल:

6.4 अभिरक्षा में रखी गई आस्ति (एफपीआई की अभिरक्षा में रखी गई जमा पूंजी जो जमा पूंजी के कुल बाजार मूल्य को दर्शाती हैं) 31 मार्च, 2025 की तुलना में 30 नवंबर, 2025 को 11 प्रतिशत बढ़ गई।

तालिका 15: एफपीआई के लिए अभिरक्षित आस्तियां

Period	इक्विटी	ऋण	ऋण - वीआरआर	ऋण - एफएआर	हाइब्रिड	कुल
	(लाख करोड़ रुपये में)					
वित्तीय वर्ष 24	64.2	3.5	1.5	0.0	0.4	69.5
वित्तीय वर्ष 25	66.8	1.8	1.6	2.8	0.5	73.7
वित्तीय वर्ष 26*	74.5	1.8	1.7	2.9	0.6	81.8

*30 नवंबर, 2025 तक

स्रोत: एनएसडीएल

तालिका 18: भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार (निवल अंतर्वाह)

वित्तीय वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
राशि	29916	97412	5015	77204	215665	82543

*अक्टूबर 2025 तक

ड. जीआईएफटी आईएफएससी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

7.1 केंद्रीय बजट घोषणा (2015-16) ने जीआईएफटी सिटी मल्टी-सर्विस एसईजेड, गुजरात में पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के संचालन का मार्ग प्रशस्त किया। भारत सरकार ने गुजरात के जीआईएफटी सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) की स्थापना और संचालन करके वित्तीय क्षेत्र में एक प्रमुख सुधार लागू किया।

7.2 सरकार का दृष्टिकोण जीआईएफटी आईएफएससी को विश्वसनीय व्यापार नियमों, प्रतिस्पर्धी कर संरचना और व्यवसाय करने में सुगमता के साथ एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना है। आईएफएससी को एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में नामित किया गया है, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों के तहत एक अनिवासी क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जिससे किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संव्यवहार की सुविधा मिलती है।

7.3 भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2022 में जीआईएफटी आईएफएससी की अपनी यात्रा के दौरान जीआईएफटी सिटी के लिए अपने विजन के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि "भारत के भविष्य का दृष्टिकोण जीआईएफटी सिटी से जुड़ा है, जो भारत को वैश्विक अवसरों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रवेशद्वार है। उन्होंने आगे कहा कि "यदि कोई जीआईएफटी सिटी के साथ एकीकृत जुड़ता है, तो वह पूरी दुनिया के साथ जुड़ "जाएगा"।

7.4 व्यापार करने में सुगमता को और बढ़ावा देने और समर्पित विनियामक पहल करने के लिए, भारत सरकार ने 2019 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत में आईएफएससी में वित्तीय बाजारों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत विनियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना की। आईएफएससीए ने 1 अक्टूबर 2020 से, संबंधित आईएफएससी के तहत वित्तीय उत्पादों, वित्तीय संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जैसे चार घरेलू क्षेत्रीय विनियामकों की शक्तियां प्राप्त कर ली हैं।

7.5 स्थापना के बाद से नवीन आईएफएससी ने बैंकिंग, पूंजी बाजार, बीमा, निधि प्रबंधन, एयरक्राफ्ट लीजिंग आदि सहित वित्तीय सेवा गतिविधियों के पूरे स्पेक्ट्रम में पर्याप्त वृद्धि देखी है। आईएफएससीए ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरेखित विनियामक व्यवस्था शुरू की है, जिसने बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय सेवा फर्मों को जीआईएफटी आईएफएससी में उपस्थिति दर्ज करने में सक्षम बनाया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरेखित विनियामक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धी कर संरचना और व्यवसाय करने में सुगमता के साथ, जीआईएफटी आईएफएससी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए एक पसंदीदा क्षेत्राधिकार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

7.6 इस दिशा में पिछले पांच वर्षों में, आईएफएससी ने आईएफएससी के लिए एक विनियामक संरचना विकसित करने का प्रयास किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है और इसमें बेहतर अनुपालन के लिए समझना भी आसान है। आईएफएससी ने अपनी स्थापना के बाद से आईएफएससी के तहत बैंकिंग, पूंजी बाजारों, बीमा, बुलियन, निधि उद्योग, ग्लोबल इन हाउस सेंटर, विदेशी विश्वविद्यालय/विदेशी संस्थानों आदि को विनियमित करने के लिए 35 से अधिक विनियम बनाए हैं। भारत में आईएफएससी के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण होने के नाते, आईएफएससी ने बीमा, निधि उद्योग, पूंजी बाजारों आदि से संबंधित घरेलू विनियमों को काफी हद तक समेकित किया है, जो भारतीय विनियामक ढांचे में अद्वितीय है।

7.7 जीआईएफटी आईएफएससी में सितंबर 2025 तक विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में 1000 से अधिक पंजीकृत संस्थाएं हैं। बैंकों, पूंजीगत बाजारों, बीमा, फिनटेक, एयरक्राफ्ट लीजिंग, बुलियन एक्सचेंज आदि सहित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वित्तीय संस्थानों की स्वस्थ और बढ़ती भागीदारी के साथ वित्तीय सेवा बाजार तेजी से बढ़ रहा है।

7.8 हाल के दिनों में जीआईएफटी आईएफएससी में काफी तेजी आई है। मुख्य प्रगति पिछले एक वर्ष में हुई है। पिछले एक वर्ष कुछ प्रमुख उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं -

(क) जीआईएफटी आईएफएस में पहले विदेशी कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गम की सूचीबद्धता –

श्रीलंका के डीएफसीसी बैंक पीएलसी के 2.5 बिलियन एलकेआर¹¹ के ग्रीन बॉन्ड 9 जून, 2025 को एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (एनएसई IX) पर जीआईएफटी आईएफएस के तहत सूचीबद्ध किए गए। यह जीआईएफटी आईएफएस के तहत किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली किसी विदेशी कंपनी की पहली लिस्टिंग है।

(ख) विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) का शुभारंभ और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निगमों की प्रत्यक्ष भागीदारी –

माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 7 अक्टूबर, 2025 को जीआईएफटी आईएफएस में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (एफसीएसएस) का शुभारंभ किया। एफसीएसएस आईएफएस बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के बीच विदेशी मुद्रा लेनदेन के स्थानीय निपटान को सक्षम बनाती है, जिससे विदेशी कॉर्पोरेट बैंकों के माध्यम से निपटान की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह भारत के वित्तीय बाजार के अवसरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो लेनदेन को तेज, सुरक्षित और अधिक लागत प्रभावी बनाती है, साथ ही सीमा पार भुगतान में भविष्य के नवाचार की नींव रखती है।

एफसीएसएस स्थानीय वाणिज्यिक बैंक को निपटान बैंक के रूप में नियुक्त करती है, और प्रणाली के अंतर्गत अन्य सभी सदस्य बैंकों को इसके साथ खाते खोलने होते हैं। सदस्य बैंकों के बीच लेनदेन सीधे इन निपटान खातों के माध्यम से निपटाए जाते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड (सीसीआईएल आईएफएससी) को भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 के तहत आईएफएससीए द्वारा एफसीएसएस प्रणाली के संचालक के रूप में अधिकृत किया गया है।

यह प्रणाली वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय के आधार पर लेनदेन निपटान में सक्षम होगी, जिससे कॉर्पोरेट बैंकिंग की तुलना में निपटान का समय काफी कम हो जाएगा। सीसीआईएल आईएफएससी ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज (आईएफटीएस) को एफसीएसएस प्रणाली सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य सौंपा है। खुली बोली प्रक्रिया के आधार पर, सीसीआईएल आईएफएससी लिमिटेड ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को, उसकी आईबीयू के माध्यम से, निपटान बैंक के रूप में चुना है।

आईएफएससीए ने आईबीयूएस को पूर्व विनियामक अनुमोदन के बिना सीधे अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों में भाग लेने की अनुमति भी दी है। यह नीति वैश्विक वित्तीय संस्थानों से और उनके साथ निर्बाध भुगतान को सक्षम बनाती है, साथ ही स्पष्ट सीमाएं भी स्थापित करती हैं: अंतरराष्ट्रीय

प्रणालियों के माध्यम से घरेलू आईएफएससी लेनदेन के लिए पीएसएस अधिनियम के तहत स्पष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यह उपाय निपटान संबंधी बाधाओं को काफी हद तक कम करता है, जिससे आईबीयूएस भारतीय और वैश्विक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच एक सक्रिय प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित होते हैं।

(ग) वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वीसीआईपी) को सक्षम करना और सीकेवाईसीआर रजिस्ट्री पर आईएफएसए द्वारा विनियामक का दर्जा प्राप्त करना।

आईएफएससीए ने 31 अक्टूबर, 2025 को “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन निवारण, आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी और अपने ग्राहक को जानें) दिशानिर्देश, 2022 में संशोधन” शीर्षक से एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निर्दिष्ट अधिकारक्षेत्रों से कम जोखिम वाले अप्रवासी भारतीयों को शामिल करने के लिए वीडियो-आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी) को सक्षम बनाया गया है। यह परिपत्र विनियमित इकाई, उसके विनियमित वित्तीय समूह संस्थाओं या केआरए के अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-आधारित और कागज रहित ऑनबोर्डिंग और आवधिक केवाईसी अद्यतन की अनुमति देकर वी-सीआईपी फ्रेमवर्क को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत और विस्तारित करता है। यह अनुमत पहचान तंत्रों की श्रेणी को विस्तृत करता है जिसमें ऑफलाइन और बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (चेहरे के प्रमाणीकरण सहित), सीकेवाईसीआर डेटा, उन्नत साइबर सुरक्षा, जीवंतता, धोखाधड़ी और एंटी- डीप फेक रोधी कंट्रोल द्वारा समर्थित डिजी लॉकर-आधारित ओवीडी शामिल हैं। कुल मिलाकर, यह फ्रेमवर्क विनियामक सुरक्षा उपायों को कमजोर किए बिना ग्राहक सुविधा और व्यापार सुगमता को बढ़ाते हुए, एक पायलट दृष्टिकोण के तहत कम जोखिम वाले एनआरआई ग्राहकों को शामिल करने की सुविधा प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, अनुपालन संबंधी अवसरचना में एक महत्वपूर्ण सुधार के तहत, आईएफएससीए को सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) पर एक नियामक के रूप में शामिल किया गया है, जो सीकेवाईसीआर भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी सीआईआरएसएआई द्वारा प्रबंधित केवाईसी के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस है। इससे आईएफएससी विनियमित संस्थाओं को सीकेवाईसीआर पोर्टल पर पंजीकरण करने और धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के नियम 9 (1क) के तहत अनिवार्य रूप से सीकेवाईसीआर पोर्टल पर ग्राहक/उपभोक्ता केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड/अपडेट/डाउनलोड करने के दायित्वों का अनुपालन करने में सक्षम बनाता है। इस विकास से दोहराव में काफी कमी आती है, उचित परिश्रम की दक्षता बढ़ती है और जीआईएफटी आईएफएससी की एएमएल/सीएफटी संरचना वैश्विक मानकों के अनुरूप सशक्त होती है।

(घ) सह-निवेश और प्लेटफॉर्म प्ले फ्रेमवर्क के माध्यम से फंड प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना

वैकल्पिक आस्ति के लिए यह अग्रणी सह-निवेश फ्रेमवर्क (21 मई, 2025) वेंचर कैपिटल स्कीमों और प्रतिबंधित स्कीमों को अन्य बाजार

¹¹ श्रीलंकाई रूपया

प्रतिभागियों के साथ सह-निवेश करने और एसपीवी स्तर पर लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। आईएफएससी अधिनियम की धारा 12 और 13 को सुव्यवस्थित बनाकर, प्राधिकरण ने संरचनात्मक बाधाओं को दूर किया है, जिससे उच्च-विकास के अवसरों में संस्थागत पूंजी की एक नई लहर आई है और एशिया के प्रमुख वैकल्पिक निवेश गंतव्य के रूप में जीआईएफटी आईएफएससी की भूमिका मजबूत हुई है।

इसके अलावा, फंड प्रबंधन गतिविधियों के लिए जीआईएफटी आईएफएससी को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए, आईएफएससी ने तृतीय-पक्ष फंड प्रबंधन सेवाओं के लिए एक फ्रेमवर्क पेश किया है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'प्लेटफॉर्म प्ले' के रूप में भी जाना जाता है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य प्रचालनात्मक लचिलेपन को बढ़ाना और निधि प्रबंधन इकोसिस्टम के भीतर वैश्विक संपर्कता को बढ़ावा देना है। इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, आईएफएससी ने 8 सितंबर, 2025 को एक परिपत्र

तालिका 17: व्यावसायिक विकास संख्याएँ (जीआईएफटी आईएफएससी)

सितंबर 2025 तक

क्र.सं.	पैरामीटर	सितंबर की समाप्ति तक	मार्च की समाप्ति तक	सितंबर की समाप्ति तक
1	आईएफएसए पंजीकरणों की संख्या ²	687	864	1034
बैंकिंग क्षेत्र				
2	बैंकों की कुल संख्या ³	28	29	35
3	विदेशी बैंक	12	13	18
4	भारतीय बैंक	16	16	17
5	वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ)	2	2	2
6	कुल बैंकिंग आस्ति का आकार	\$70.92 बिलियन	\$88.51 बिलियन	\$100.14 बिलियन
7	संचयी बैंकिंग लेनदेन	\$975.80 बिलियन	\$1243 बिलियन	\$1508 बिलियन
8	एनडीएफ सहित संचयी ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन ⁴	\$982.12 बिलियन	\$1194 बिलियन	\$1351 बिलियन
पूंजी बाजार क्षेत्र				
8	आईएफएससी एक्सचेंजों पर औसत मासिक टर्नओवर ⁵	\$95.81 बिलियन	\$91.70 बिलियन	\$94.49 बिलियन
9	एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कुल ऋण	\$64.31 बिलियन	\$65.10 बिलियन	\$66.6 बिलियन
10	ईएसजी लेबल वाले ऋण	\$13.93 बिलियन	\$15.43 बिलियन	\$14.3 बिलियन
फंड उद्योग				
11	निधि प्रबंधन संस्थाएँ	128	162	194
12	कुल निधियाँ/योजनाएँ	168	229	310
13	कुल जुटाई गई प्रतिबद्धताएँ	\$12.13 बिलियन	\$15.74 बिलियन	\$26.30 बिलियन
बीमा क्षेत्र				
14	बीमा कंपनियों और ब्रोकरों की संख्या	37	45	52
15	आईएफएससी में आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओ) द्वारा लिखित प्रीमियम	\$466.40 मिलियन	\$568.37 मिलियन	\$821.97 मिलियन

² सैद्धांतिक और/या अस्थायी पंजीकरण सहित

³ न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को छोड़कर

⁴ एनडीएफ का नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स है।

⁵ पिछले छह महीनों का औसत

क्र.सं.	पैरामीटर	सितंबर की समाप्ति तक	मार्च की समाप्ति तक	सितंबर की समाप्ति तक
16	आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालयों (आईआईआईओ) द्वारा आईएफएससी में किए गए प्रीमियम का लेनदेन	\$1137.34 मिलियन	\$1363.21 मिलियन	\$1578.18 मिलियन
विमान पट्टे पर देना				
17	पंजीकृत विमान पट्टेदार	27	30	33
18	पट्टे पर दी गई कुल विमानन आस्तियां	159	242	303
जहाज पट्टे पर देना				
19	पंजीकृत जहाज पट्टेदार	12	17	26
20	पट्टे पर लिए गए जहाजों की कुल संख्या	12	18	28
वित्त कंपनी (कोर और नॉन-कोर, जिसमें आईटीएफएस भी शामिल है)				
21	वित्त कंपनी (कोर और नॉन-कोर)	09	14	17
22	आईटीएफएस प्लेटफॉर्म ⁶	4	4	4
बुलियन इकोसिस्टम				
23	योग्य आपूर्तिकर्ता	28	37	40
24	योग्य ज्वेलर्स	143	167	185
25	आईआईबीएक्स पर कारोबार की गई सोने की मात्रा (संबंधित तिमाही के दौरान)	25429.30 किलोग्राम	31999 किलोग्राम	72.60 किलोग्राम
26	आईआईबीएक्स पर कारोबार की गई चांदी की मात्रा (संबंधित तिमाही के दौरान)	42270 किलोग्राम	0	0
विदेशी विश्वविद्यालय				
27	विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या ⁷	2	3	5

च. विनियामक प्रतिष्ठान

8.1 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (15 ऑफ 1992) के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, आर्थिक कार्य विभाग के वित्तीय बाजार प्रभाग के विनियामक प्रतिष्ठान अनुभाग के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है।

8.2 विनियामक प्रतिष्ठान अनुभाग बोर्ड स्तर की नियुक्तियों, अर्थात् अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का कार्य संभालता है। इस अवधि के दौरान, श्री संदीप प्रधान, आईआरएस (आईटी: 1990), आयकर महानिदेशक (जांच), पुणे और श्री एन. वेंकटराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीडीपीक्यू इंडिया, सीडीपीक्यू ग्लोबल को क्रमशः सेबी के पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

⁶ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवाएँ (आईटीएफएस)

⁷ इसमें सैद्धांतिक अनुमोदन शामिल हैं

8.3 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15 के तहत की गई है, ताकि सेबी अधिनियम 1992, पीएफआरडीए अधिनियम 2013, बीमा अधिनियम 1938 और उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग किया जा सके।

8.4 प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी, दो तकनीकी सदस्य और एक न्यायिक सदस्य होते हैं। वर्तमान में, एसएटी में न्यायिक सदस्य के रिक्त पद को भरने की प्रक्रिया उन्नत चरण में है।

8.5 एसएटी को उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रतिभूतियों, बीमा और पेंशन से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए नामित न्यायाधिकरण भी बनाया गया है।

8.6 दिनांक 31.12.2025 तक, एसएटी के समक्ष 1319 अपीलों लंबित हैं और अवधिवार उनका विवरण इस प्रकार है: -

तालिका 18: एसएटी के समक्ष लंबित अपीलें

वर्ग	प्रारंभिक जमा	दायर किए गए मामले	कुल मामले	निस्तारित मामले	लंबित मामले
सेबी	1055	573	1628	348	1280
आईआरडीए	17	03	20	09	11
पीएफआरडीए	00	00	00	00	00
समीक्षा	04	30	34	06	28
कुल	1076	606	1682	363	1319

छ. निवेशक शिकायतें (आईजी)

9.1 शेयर बाजार, स्टॉक, म्यूचुअल फंड आदि से संबंधित निवेशकों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा किया जाता है। दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, सीपीग्राम पोर्टल पर प्राप्त 1,527 शिकायतों में से 1,354 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।

4. वित्तीय स्थिरता प्रभाग

4.1 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

4.1.1 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2010 में शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-विनियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को सुदृढ़ और संस्थागत बनाना है। एफएसडीसी के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं और इसके सदस्यों में वित्त राज्य मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रमुख और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव शामिल हैं।

4.1.2 एफएसडीसी अर्थव्यवस्था के मैक्रो-प्रुडेंसियल पर्यवेक्षण की निगरानी करता है और वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-विनियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और अन्य स्टैन-डार्ड सेटिंग निकायों (एसएसबी) जैसे वित्तीय क्षेत्र के निकायों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस का समन्वय करते हुए प्रासंगिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है। आर्थिक कार्य विभाग में वित्तीय स्थिरता प्रभाग (पूर्ववर्ती वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा), एफएसडीसी को सचिवीय सहायता प्रदान करता है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के वित्तीय स्थिरता प्रभाग के प्रभारी प्रभाग-प्रमुख, एफएसडीसी के सदस्य सचिव हैं।

4.1.3 वित्त वर्ष 2025-26 में, एफएसडीसी की 10 जून 2025 को मुंबई में अपनी 29वीं बैठक की। एफएसडीसी ने 29वीं बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ वृहद वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों और उनसे निपटने के लिए भारत की तैयारी पर विचार-विमर्श किया गया। साइबर सुरक्षा नियमों, क्षेत्रीय तैयारियों और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) 2024-25 की सिफारिशों के विश्लेषण के आलोक में, एफएसडीसी ने वित्तीय क्षेत्र-विशिष्ट साइबर सुरक्षा कार्यनीति के माध्यम से भारतीय वित्तीय क्षेत्र के

साइबर रेजिलिएंस फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने पर विचार किया। एफएसडीसी ने विगत निर्णयों और बजट घोषणाओं को लागू करने के लिए कार्यनीति तैयार करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें विनियमन और सहायक निर्देशों की जवाबदेही का मूल्यांकन और बढ़ाने के लिए विनियामकों द्वारा उपयुक्त फ्रेमवर्क; वित्तीय क्षेत्र में अदावाकृत आस्तियों (बैंक जमा, लाभांश, शेयर, डाकघर खाते, बीमा और पेंशन फंड आदि) को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाना और सही मालिकों को ऐसी आस्तियों की शीघ्र और निर्बाध वापसी करना; भारतीय प्रतिभूति बाजार में पीआईओ और ओसीआई सहित अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग सहित केवाईसी प्रक्रिया के सामान्य केवाईसी मानदंडों को निर्धारित करना, सरलीकरण और डिजिटलीकरण; निवेश अनुपात को बढ़ाने की कार्यनीति के हिस्से के रूप में वित्तपोषण प्रवाह में रुझानों का विश्लेषण करना, फैक्टरिंग सेवाओं की पहुंच और दायरे में सुधार के उपाय करना और खाता एग्रीगेटर नेटवर्क का प्रभावी उपयोग स्थापित करना शामिल है।

4.1.4 एफएसडीसी ने घरेलू और वैश्विक वृहद-वित्तीय स्थिति से उभरते रुझानों पर विचार-विमर्श किया और सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। परिषद ने वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय प्रयासों की आवश्यकता को स्वीकार किया। सदस्यों ने वित्तीय क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए अंतर-नियामक समन्वय को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया।

4.2 एफएसडीसी उप-समिति (एफएसडीसी-एससी)

4.2.1 एफएसडीसी को आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता वाली एक उप-समिति (एफएसडीसी-एससी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वित्त मंत्री (एफएसडीसी के अध्यक्ष) और वित्त राज्य मंत्री को छोड़कर, एफएसडीसी के सभी सदस्य भी एफएसडीसी-एससी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के सभी चारों डिप्टी गवर्नर (डीजी) और सचिव (एफएसडीसी), एफएसडीसी-एससी के सदस्य भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, जो वित्तीय स्थिरता के प्रभारी हैं, सदस्य सचिव हैं, और भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) एफएसडीसी-एससी का सचिवालय है। एफएसडीसी-एससी की अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं।

4.2.2 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, एफएसडीसी-एससी ने 4 सितंबर 2025 को अपनी 32वीं बैठक आयोजित की। उप-समिति ने प्रमुख वैश्विक

और घरेलू समष्टि आर्थिक और वित्तीय घटनाक्रमों, इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न तकनीकी समूहों की भारतीय वित्तीय क्षेत्र की कार्यविधियों से संबंधित अंतर-विनियामक समन्वय के मुद्दों की समीक्षा की। इनपुट प्रस्तुत किए जाने की तिथि तक बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

4.2.3 अर्ली वार्निंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) एफएसडीसी-एससी के अंतर्गत कार्य समूहों में से एक है, जो संकट की स्थिति में सरकार/विनियामकों की कार्रवाई का समन्वय करता है। ईडब्ल्यूजी की नियमित बैठकों की अध्यक्षता विभिन्न विनियामकों (आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) द्वारा वार्षिक रोटेशन के साथ की जाती है। वर्ष 2025-26 के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ईडब्ल्यूजी बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2025-26 (अप्रैल-नवंबर) में, ईडब्ल्यूजी ने 45वीं से 47वीं तक तीन बैठकें आयोजित कीं, जो क्रमशः 18 जून, 26 अगस्त और 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुईं। ईडब्ल्यूजी की नियमित बैठकों की चर्चा में, अन्य बातों के साथ-साथ, की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) की समीक्षा, वित्तीय प्रणाली कमजोरियों की निगरानी टेम्पलेट पर चर्चा, पिछली बैठक के बाद से प्रमुख घटनाक्रम, जोखिम दृष्टिकोण पर प्रभाव डालने वाले और अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य चर्चा बिन्दु शामिल थे।

4.3 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

4.3.1 एफएसबी एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना जी-20 के तत्वावधान में अप्रैल, 2009 में राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों, मानक निर्धारक निकायों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को एक साथ लाकर की गई थी। एफएसबी कमजोरियों का आकलन करने, नीतिगत विकास और समन्वय, कार्यान्वयन निगरानी और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन और सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में सुधारों के लिए मानकों के संग्रह के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है।

4.3.2 एफएसबी के सदस्य के रूप में, भारत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के प्राथमिकता और अन्य क्षेत्रों और जहां भी आवश्यक हो, स्थानीय दशाओं के अनुसार अंशांकित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंगीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) भारत के लिए एफएसबी के साथ समन्वय करने के लिए नोडल बिंदु है और विभिन्न एफएसबी प्रश्नावली, सर्वेक्षणों और रिपोर्टों का उत्तर देते समय वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों (अर्थात्, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए) के परामर्श से सभी भारत एफएसबी को विशिष्ट जानकारी नियमित रूप से प्रदान करता है। भारत एफएसबी की समकक्ष समीक्षाओं, बैठकों और सम्मेलन कॉल में भी भाग लेता है और एक सदस्य के रूप में अपने विचार और टिप्पणियां प्रस्तुत करता है।

4.3.3 प्लेनरी एफएसबी का एकमात्र निर्णय लेने वाला निकाय है, संचालन समिति एफएसबी के निर्देशों को आगे बढ़ाने और प्लेनरी को अपने अधिदेश को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अनुमति देने के लिए पूर्ण बैठकों को तैयार करने हेतु प्लेनरी बैठकों के बीच प्रचालनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती है। एफएसबी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विशिष्ट लेकिन पूरक जिम्मेदारियों वाली चार स्थायी समितियां (एससी) हैं। ये स्थायी समितियां हैं (क) अरक्षितताओं के आकलन (एससीएवी) संबंधी- वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की पहचान

करने और उनका आकलन करने के लिए, (ख) पर्यवेक्षी और नियामक सहयोग (एसआरसी) संबंधी - अरक्षितताओं के लिए नियामक कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षी नीति विश्लेषण के लिए, (ग) मानक कार्यान्वयन (एससीएसआई) संबंधी- एफएसबी नीतिगत पहलों और अंतरराष्ट्रीय मानकों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए और (घ) बजट और संसाधनों (एससीबीआर) संबंधी - एफएसबी के संसाधनों और बजट की निगरानी के लिए।

4.3.4 एशिया क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी एशिया) 2011 में एफएसबी द्वारा स्थापित 6 क्षेत्रीय समूहों में से एक है, जो जी20 की सदस्यता से परे एफएसबी की आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करने और औपचारिक रूप देने तथा गैर-सदस्यों के साथ बातचीत के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की वैश्विक प्रकृति को प्रतिबिंबित करना है। सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) एफएसबी प्लेनरी सत्र में और चार एफएसबी स्थायी समितियों में से दो में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् एससीएसआई और एससीबीआर। सचिव (आर्थिक कार्य विभाग) एशिया क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी एशिया) में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सेबी के अध्यक्ष और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर (डीजी) एफएसबी के मंचों में भारत के अन्य दो सदस्य हैं। डिप्टी गवर्नर (आरबीआई) एफएसबी की अन्य दो स्थायी समितियों, अर्थात् एससीएवी और एसआरसी में भारत के सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के महानिदेशक संचालन समिति में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो एफएसबी के निर्देशों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेनरी बैठकों के बीच प्रचालनात्मक मार्गदर्शन प्रदान करता है, स्थायी समितियों में समन्वय को बढ़ावा देती है और अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारण निकायों के नीतिगत विकास कार्य का समन्वय और समीक्षा करता है।

4.3.5 वर्ष 2025-26 के दौरान, एफएसबी प्लेनरी की बैठकें 11 जून, 22 सितंबर और 18-19 नवंबर, 2025 को आयोजित की गईं। एससीएसआई वर्चुअल बैठकें 4 जून, 4 सितंबर और 25-26 सितंबर, 2025 को आयोजित की गईं। इसके अलावा, आरसीजी एशिया की दो व्यक्तिगत बैठकें क्रमशः 22-23 मई और 7-8 अक्टूबर, 2025 को आयोजित की गईं। इन सभी बैठकों में उपयुक्त स्तरों पर आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

4.3.6 जी 20 के तहत, दक्षिण अफ्रीकी प्रेसीडेंसी ने पहले की जी20 अध्यक्षता से आगे बढ़ाई गई वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों पर कार्य करना जारी रखा। क्रिप्टो आस्तियों, सीमा-पार भुगतान आदि जैसी प्राथमिकताओं के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है, हालांकि एनबीएफआई और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों और वित्तीय स्थिरता पर उनके प्रभाव पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के तहत कार्य का समर्थन करने के लिए, प्लेनरी, एससीएसआई, आरसीजी आदि की विभिन्न वर्चुअल बैठकों/कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से निरंतर संपर्क बनाए रखा गया और समय-समय पर विनियामकों के परामर्श से एफएसबी द्वारा परिचालित सर्वेक्षणों और रिपोर्टों पर इनपुट प्रदान किए गए थे।

4.3.7 नई दिल्ली में जी-20 के प्रमुखों की घोषणा में, साइबर घटना की रिपोर्टिंग में अधिक अभिसरण प्राप्त करने के लिए एफएसबी की सिफारिशों, साइबर लेक्सिकॉन में अपडेट और इनसिडेंट रिपोर्टिंग एक्सचेंज

(एफआईआरई) के लिए एक प्रारूप हेतु कनसेप्ट नोट की शुरुआत की गई। इसके बाद, दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के तहत एफएसबी ने अप्रैल 2025 में अपना अंतिम संस्करण प्रकाशित किया। रिपोर्ट में इस बात को प्रकाशित किया गया है कि एफआईआरई मानकीकृत सूचना वस्तुओं का एक सेट प्रदान करता है और इसे रेजिलिएंस और अंतर-संचालनीयता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक मानकीकृत रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बिना न्यायालयों के लिए, एफआईआरई निर्माण के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। वित्तीय क्षेत्र में इनसिडेंट रिपोर्टिंग में सामंजस्य स्थापित करने के मूल्य को पहचानते हुए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के विनियामक इनसिडेंट रिपोर्टिंग (आईआर) को मानकीकृत करने और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कार्य कर रहे हैं। हालांकि, चूँकि परिचालन घटनाएं अक्सर धोखाधड़ी की घटनाओं, अनुपालन उल्लंघनों और सूचना-जोखिम रिपोर्टिंग के साथ प्रतिच्छेद करती हैं - और क्योंकि रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पूरे क्षेत्र में असमान रूप से विकसित हुए हैं - इसलिए पूर्ण अलगाव और मानकीकरण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

4.3.8 भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए, एफएसबी 2027 तक त्वरित, सरस्ते, अधिक पारदर्शी और समावेशी सीमा-पार भुगतान संबंधी वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान प्रेसीडेंसी के तहत सीमा-पार भुगतान को बढ़ाने के लिए जी 20 रोडमैप का भी सक्रिय रूप से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में एफएसबी ने अक्टूबर 2025 में अपनी समेकित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि विगत एक वर्ष में, कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं, जो प्रमुख नीतिगत विकास पहलों की समाप्ति को चिह्नित करते हैं। हालांकि, इन प्रयासों को अभी तक वैश्विक स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए ठोस सुधारों में अनुवादित नहीं किया गया है। वर्ष 2025 के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) वैश्विक स्तर पर केवल मामूली सुधार दिखाते हैं क्योंकि केपीआई की गणना पहली बार वर्ष 2023 में की गई थी। यह संभावना नहीं है कि 2027 रोडमैप समय सारिणी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर संतोषजनक सुधार हासिल किए जाएंगे।

4.3.9 जुलाई में क्रिप्टो आस्तियों के लिए एफएसबी के वैश्विक विनियामक ढांचे के जी20 के समर्थन के बाद से 2023, एफएसबी और आईएमएफ ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए मिलकर कार्य किया है। एफएसबी द्वारा क्रिप्टो-आस्तियों कार्यविधियों के लिए एफएसबी वैश्विक विनियामक फ्रेमवर्क पर नवीनतम विषयगत समीक्षा इस बात पर प्रकाश डालती है कि क्रिप्टो बाजारों और विनियमनों में विकास के आसपास महत्वपूर्ण अंतराल और विसंगतियां वित्तीय स्थिरता और रेजिलिएंस डिजिटल आस्ति पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। असमान कार्यान्वयन विनियामक मध्यस्थता के अवसर पैदा करता है और स्वाभाविक रूप से वैश्विक और विकसित क्रिप्टो-आस्ति बाजार की निगरानी को जटिल बनाता है।

4.4 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी)

4.4.1 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाने वाला पंचवर्षीय अभ्यास

है जिसमें वित्तीय स्थिरता और वित्तीय क्षेत्र के विकास का आकलन करने के लिए देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण शामिल है। भारत के लिए, मंत्रालयों/विभागों, विनियामकों, निजी क्षेत्र के संगठनों, मानक निर्धारण निकायों (एसएसबी) और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों के साथ कठोर परामर्श के पूरे एक वर्ष के बाद तृतीय और नवीनतम एफएसएपी अभ्यास 2025 में संपन्न हुआ। इस पद्धति के अनुसार, एफएसएपी के समापन भाग के रूप में, आईएमएफ ने 28 फरवरी, 2025 को अपनी वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन आईएमएफ रिपोर्ट जारी की और विश्व बैंक ने 30 अक्टूबर, 2025 को अपनी वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) रिपोर्ट प्रकाशित की।

4.4.2 दोनों रिपोर्टों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्ष 2017 में विगत एफएसएपी मूल्यांकन के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली त्वरित गति से तन्यक, विविध और समावेशी हो गई है। एफएसएपी ने नोट किया है कि समग्र रूप से, भारत का वित्तीय विकास समकक्षों के समतुल्य है। यह भारत की कुल वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों से प्रमाणित होता है, जो कई जोखिमों और कोविड-19 महामारी के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 187 प्रतिशत है। एफएसएपी के नतीजों में पाया गया कि बैंकों और एनबीएफसी के पास समग्र रूप से पर्याप्त पूंजी बफर है, जो उन्हें गंभीर मैक्रो-फाइनेंशियल स्ट्रेस परिदृश्यों में भी मध्यम क्रेडिट वृद्धि का समर्थन करने में सहायता करता है। सहकारी बैंकों के लिए विनियामक क्षेत्र का विस्तार करने, प्रमुख विवेकपूर्ण मानदंडों को सख्त करने, पर्यवेक्षी विभागों को पुनर्गठित करने और एनबीएफसी के लिए स्केल-आधारित विनियमन को लागू करने में प्राधिकरणों के प्रयासों को विशेष रूप से स्वीकार किया गया है। फिर भी, रिपोर्टों में नोट किया गया है कि वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की आकांक्षा को साकार करने के लिए निजी पूंजी जुटाने को उत्प्रेरित करने हेतु वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में निरंतर गति की आवश्यकता होगी। इसलिए, आईएमएफ ने आईएफआरएस 9 को अपनाने, पिलर 2 कैपिटल ऐड-ऑन को लागू करने और क्रेडिट जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने की सिफारिश की है। यह राज्य के स्वामित्व वाली एनबीएफसी के लिए निजी एनबीएफसी के साथ नियमों के निरंतर संरेखण, तरलता नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने और व्यापार मॉडल के आधार पर अतिरिक्त तरलता आवश्यकताओं को शुरू करने की भी सलाह देता है।

4.4.3 पूंजी बाजार के संबंध में, रिपोर्ट में यह अवलोकित किया गया है कि भारतीय पूंजी बाजार (इक्विटी, जी-सेक और कॉर्पोरेट बॉन्ड) का समग्र आकार वर्ष 2017 में सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 144 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 175 हो गया है। इस वृद्धि को बेहतर संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली, निवेशकों के लिए व्यापार निरंतरता प्रावधानों में वृद्धि, स्थिरता से संबंधित निवेश फ्रेमवर्क की शुरुआत, म्यूचुअल फंडों के लिए सुदृढ़ नकदी आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष (सीडीएमडीएफ) की स्थापना जैसे उपायों द्वारा समर्थन दिया गया है। इक्विटी बाजार का प्रभाव जारी है, इसके बाद जी-सेक बाजार और लघु कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार (सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः लगभग 130 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 16 प्रतिशत, जिसमें कई गुनक प्रभाव शामिल हैं) का स्थान है। बाजार को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, रिपोर्ट क्रेडिट वृद्धि संरचनाओं, जोखिम-

साझाकरण तंत्र और प्रतिभूतिकरण प्लेटफार्मों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है।

4.4.4 इंडिया स्टैक के रूप में जाना जाने वाला भारत का विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सरकारी कार्यक्रमों ने निर्बाध डिजिटल पहचान सत्यापन, त्वरित भुगतान और डेटा विनिमयन के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए वित्तीय सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच में महत्वपूर्ण सुधार किया है। विश्व बैंक की एफएसए रिपोर्ट में कहा गया है कि एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार हुआ है, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), आरबीआई विनियमित फैंक्टरिंग प्लेटफॉर्म (टीआरडीईएस) और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) फ्रेमवर्क जैसे सुधारों की सहायता मिली है। हालांकि, उच्च संपार्श्विक आवश्यकताओं, उच्च ब्याज लागत और जटिल आवेदन प्रक्रियाओं के कारण एमएसएमई वित्तपोषण बाधित रहता है। विभिन्न आकलन ऋण अंतर को सकल घरेलू उत्पाद के 11 से 16 प्रतिशत के सीमा में रखते हैं। इन अंतरालों को दूर करने के लिए, विश्व बैंक समर्पित एमएसएमई डेटा वेधशाला स्थापित करने और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए मांग-पक्ष संबंधी संकेतकों सहित सूक्ष्म एमएसएमई क्रेडिट डेटा प्रकाशित करने की सिफारिश करता है।

4.4.5 बीमा क्षेत्र के तहत, एफएसएपी के श्रेणीबद्ध आकलन में बीमा कोर सिद्धांतों (आईसीपी) के अवलोकन का समग्र बेहतर स्तर पाया गया। सरकार और आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए सुदृढ़ विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसे सुदृढ़ लाइसेंसिंग और प्रमाणन प्रक्रियाओं, प्रमुख लोगों और लाभकारी मालिकों के लिए उपयुक्तता अपेक्षाओं और सुदृढ़ हस्तक्षेप तथा प्रवर्तन शक्तियों द्वारा समर्थित किया गया है। आईआरडीएआई ने अन्य घरेलू और विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ कई सूचना-साझाकरण तंत्र भी स्थापित किए हैं।

4.4.6 आईएमएफ ने बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई), महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली और प्रतिभूति बाजार में अन्य प्रासंगिक व्यक्तियों में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का भी विश्लेषण किया। इसमें यह पाया गया कि भारतीय प्राधिकारियों ने साइबर सुरक्षा जोखिम, विशेषकर बैंकों के लिए, निगरानी को उन्नत किया है। हालांकि, आईएमएफ ने कहा कि साइबर सुरक्षा तन्त्रकता को और सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्र-वार और बाजार-व्यापी घटनाओं के लिए बैंकों हेतु व्यापक साइबर सुरक्षा संकट सिमुलेशन और तनाव परीक्षणों का विस्तार किया जा सकता है।

4.4.7 समग्र रूप से, वर्ष 2024 एफएसएपी की सिफारिशों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की संरचना, दक्षता और स्थिरता को निरंतर सुदृढ़ करने का समर्थन करना है। कई सिफारिशें सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के चल रहे विकास एजेंडे के अनुरूप हैं। भारत एक सुविचारित और संदर्भ-उपयुक्त वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो कि देश की विकासात्मक प्राथमिकताओं और वृहद-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप है।

साइबर सुरक्षा प्रभाग

1. कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पांस टीम- फाइनेंस सेक्टर (सीएसआईआरटी-एफआईएन)

1.1 कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पांस टीम- फाइनेंस सेक्टर (सीएसआईआरटी-एफआईएन) की स्थापना 15 मई 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल (सीआईआरटी-आईएन) की एक इकाई के रूप में की गई है। सीएसआईआरटी-एफआईएन वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं या घटनाओं के प्रति कार्रवाई के समन्वय और सहायता के लिए उत्तरदायी है। सीएसआईआरटी-एफआईएन घटना कार्रवाई बल है जो शमन प्रक्रियाओं, साइट पर जागरूकता, विशेषज्ञता और रिकवरी ओवरसाइट प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। सीआईआरटी-आईएन अपने तत्वाधान में सीएसआईआरटी-एफआईएन के संचालन के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन प्रदान करता है। रणनीतिक मार्गदर्शन रणनीतिक सलाहकार समिति के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिसकी सह-अध्यक्षता सचिव (डीईए) और सचिव (एमआईटीवाई) करते हैं, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, सीआईआरटी-आईएन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों का प्रतिनिधि शामिल है।

1.2 इस वर्ष सीएसआईआरटी-एफआईएन द्वारा की गई गतिविधियों का सनैपशॉट इस प्रकार है: क. सीआईआरटी-आईएन के सहयोग से सुरक्षा घटनाओं से निपटना जिसमें दुर्बल सेवाओं, बॉटनेट, ओपन सेवाओं और फिशिंग घटनाओं से संबंधित सुरक्षा घटनाएं शामिल थीं। मैलवेयर इनफेक्शन, बॉटनेट और दुर्बल सेवाओं के संबंध में स्वचालित फीड प्रदान करने हेतु संस्थाओं को सीआईआरटी-आईएन के साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) में भी शामिल किया गया है। ख. सीआईआरटी-आईएन के साथ भेद्यता नोट और वायरस अलर्ट जारी करना। ग. सक्रिय उपायों के लिए अनुरूप खतरे की खुफिया चेतावनी वित्तीय क्षेत्र के क्षेत्रों को भेजी गई थी और संस्थाओं को सीआईआरटी-इन के ग्रेट इंटेल् प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। घ. क्षमता निर्माण साइबर सुरक्षा के संबंध में उपयोगकर्ताओं के कौशल और जानकारी को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें नियमित प्रशिक्षण सत्र, जागरूकता कार्यक्रम और साइबर खतरों से निपटने के लिए विशेषज्ञ विशेष टीमों का विकास शामिल है।

1.3 सीएसआईआरटी-एफआईएन, सीआईआरटी-आईएन, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम), सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) और सी-डैक, हैदराबाद वित्तीय क्षेत्र/प्रतिभूति बाजारों में रुचि रखने वाले/कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म के माध्यम से “साइबर सुरक्षा फाउंडेशन पाठ्यक्रम” पर प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

1.4 इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीआईआरटी-आईएन) ने एसआईएसए और सीएसआईआरटी-एफआईएन के साथ मिलकर बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र के लिए डिजिटल ग्रेट रिपोर्ट

2024 जारी की। यह सहयोगी रिपोर्ट वर्तमान और उभरते साइबर खतरों का विश्लेषण करती है, जिससे भारत के वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जो इसकी बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, के संबंध में जानकारी मिलती है।

1.5 सीएसआईआरटी-एफआईएन नाबार्ड और आरबीआई के साथ, विभिन्न को-ओपरेटिव और ग्रामीण बैंकों के लिए वर्ष भर केंद्रित साइबर सुरक्षा जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए। इन सत्रों में वर्तमान साइबर खतरे के परिदृश्य और इन संगठनों में देखी गई विशिष्ट प्रकार की साइबर घटनाओं पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों को हाल के हमले के रुझान, प्रभावी घटना प्रतिक्रिया तंत्र और संगठनात्मक साइबर स्वच्छता को मजबूत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस पहल का उद्देश्य निरंतर लचीलेपन को बढ़ावा देना और इन संस्थानों की समग्र सुरक्षा स्थिति को बढ़ाना है। क. तकनीकी साइबर सुरक्षा ऑडिट में कमजोरियों की पहचान करने और विनियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए किसी संगठन की साइबर सुरक्षा नीतियों, प्रथाओं और बुनियादी ढांचे का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। नियमित ऑडिट कमजोरियों को उजागर करने में मदद करते हैं, इससे पहले कि दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा उनका शोषण किया जा सके। ख. संगठन की तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए साइबर हमले के परिदृश्यों का अनुकरण करने के लिए सीआईआरटी-इन और सीएसआईआरटी-फिन द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। ये अभ्यास घटना प्रतिक्रिया योजना, प्रशिक्षण अधिकारियों और वास्तविक खतरों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने में अंतराल की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग. साइबर खतरों की सीमाहीन प्रकृति के कारण साइबर सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से से उत्पन्न हो सकता है और एक साथ कई देशों को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रों के बीच समन्वित प्रयास महत्वपूर्ण खतरे की खुफिया जानकारी और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके साइबर हमलों का पता लगाने, प्रतिक्रिया देने और उन्हें कम करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सीएसआईआरटी-फिन बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रिक्स सहयोग के हिस्से के रूप में गठित ब्रिक्स रैपिड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी चैनल (बीआरआईएससी) में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

2 वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की पहचान

2.1 आर्थिक कार्य विभाग का सीएस प्रभाग वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी), और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों और सरकारी विभागों के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। सीएस प्रभाग प्रणालीगत महत्वपूर्ण सीआईआई को “संरक्षित प्रणाली” के रूप में घोषित करने का भी समन्वय करता है। एनसीआईआईपीसी की सिफारिशों के अनुसार, संरक्षित प्रणालियों को उच्च स्तर के सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिए, इसलिए, यह सुनिश्चित

करने के लिए कि सीआईआई प्रभावी रूप से सुरक्षित हैं, सूचना प्रौद्योगिकी (संरक्षित प्रणाली के लिए सूचना सुरक्षा प्रथाएं और प्रक्रियाएं) नियम 2018 का अनुपालन किया जाना चाहिए।

2.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी), यूको बैंक, सिटी यूनिन बैंक, करूर वैश्य बैंक, कर्नाटक बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा होस्ट किए गए सीआईआई और इसके आश्रित कंप्यूटर संसाधनों को “संरक्षित प्रणाली” के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, सीआईआई और इसके आश्रित कंप्यूटर संसाधनों की मेजबानी साउथ इंडियन बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बंधन बैंक और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा की गई। इसके अलावा, पहचान प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और बीएफएसआई क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियों को सीआईआई के रूप में अधिसूचित किया गया है। वित्तीय क्षेत्र में सीआईआई की पहचान और प्रत्येक दो वर्ष के बाद “संरक्षित प्रणालियों” के सत्यापन के लिए आगे के आकलन की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वर्चुअल मीटिंग और ऑनसाइट दौरों के माध्यम से संबंधित एजेंसियों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के साथ निरंतर समन्वय किया गया।

3. वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा नीति

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद् (एलएफडीसी) ने 10 जून, 2025 को आयोजित अपनी 29वीं बैठक में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समर्पित साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका उद्देश्य अंतर-नियामक अंतराल को दूर करना, पर्यवेक्षी निरीक्षण को मजबूत करना और आगामी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के अनुरूप विनियामक मानकों में सामंजस्य स्थापित करना है।

तदनुसार, माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया गया था। पहली बैठक 28 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी। आईएमजी नीतिगत विचार-विमर्श और संरचित सिफारिश के लिए एक समन्वित प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। इसने केंद्रित जांच और कार्रवाई योग्य सिफारिशें तैयार करने के लिए पांच विषयगत उप-समूहों का गठन करने का निर्णय लिया है।

4. मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)

यह प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहा है। सीआरटी-इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित साइबर संकट प्रबंधन योजना और संबंधित उपायों का कार्यान्वयन के माध्यम से आईटी अनुप्रयोगों को सुरक्षित करने के लिए संबंधित प्रभागों और विभागों के साथ समन्वय किया जा रहा है।

डीईएफटी प्रभाग

1. डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक – आई (डीईएफटी-आई) अनुभाग समावेशी और सतत विकास के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) को बढ़ावा देने के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था के संवर्धन के उद्देश्य से पहल में सक्रिय है। यह अनुभाग डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी (ग्राहक को जानो) के सरलीकरण, सीमा-पार भुगतान में दक्षता लाने, अकाउंट एग्रीगेटर को जनसंख्या के पैमाने पर लाने, डिजिटल ऋण के माध्यम से एमएसएमई में ऋण अंतराल को कम करने, वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसररचना (डीपीआई) और डीपीआई अंतर्राष्ट्रीयकरण आदि के लिए आवश्यक अंतराल और नीतिगत हस्तक्षेपों का समाधान करता है। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत के अंशदान को बढ़ाने के लिए फिनटेक क्षेत्र में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी किया जाता है।

2. यह अनुभाग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए सभी गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट वार्ताओं में भी शामिल है। वार्ता या तो त्वरित भुगतान प्रणाली के बिना देशों के लिए डिजिटल भुगतान अवसररचना के निर्माण हेतु यूपीआई स्टैक को साझा करने या अन्य देशों के साथ यूपीआई की अंतरसंचालनीयता बनाने या व्यापारिक संस्थानों में आपसी स्वीकृति के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली बनाने या सीमा-पार विप्रेषित धन कोरिडोर बनाने के लिए है। वर्तमान में, यूपीआई भूतान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में स्वीकार किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच सीमा-पार विप्रेषण की सुविधा के लिए यूपीआई-पेनाऊ इंटरलिंकेज भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा, यह अनुभाग सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) में सहयोग के लिए सीमा-पार भुगतान में दक्षता लाने हेतु आरबीआई के साथ भी समन्वय कर रहा है।

3. यह अनुभाग फिनटेक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए फिलीपींस, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के साथ तीन संयुक्त कार्य समूहों (जीडब्ल्यूजी) का सचिवालय है। इन फिनटेक जेडब्ल्यूजी का उद्देश्य प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करना और डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी और वित्तीय प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देना है।

क. भारत-सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह (जीडब्ल्यूजी) को अगस्त 2024 में छठवीं बार आयोजित किया गया है, जिसमें फिनटेक सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूपीआई-पे के उपयोग को बढ़ाना वार्ता के प्रमुख विषयों में शामिल था। अब यात्रा, पर्यटन और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के व्यापारिक संस्थान में इंटरलिंकेज और यूपीआई की स्वीकृति है। जेडब्ल्यूजी ने विभिन्न उभरते फिनटेक रुझानों, विनियामक सहयोग और एसएमई व्यापार कनेक्टिविटी बढ़ाने के मुद्दों पर भी चर्चा की।

ख. भारत और फिलीपींस के बीच संयुक्त कार्य समूह (जीडब्ल्यूजी) की उद्घाटन बैठक सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी। हितधारकों ने कई एजेंडा के मदों पर चर्चा की। इनमें नीतियों, विनियमों और फिनटेक पहलों पर अनुभव साझा करना शामिल था, जिसका

उद्देश्य वित्तीय प्रौद्योगिकी में समझ और सहयोग बढ़ाना है। बैठक में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन संबंधी सहयोग पर भी चर्चा की गई, जिसमें वित्तीय सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। चर्चा का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र फिनटेक फर्मों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था, जिससे संभावित रूप से नवीन साझेदारी और समाधान प्राप्त हो सकें। बैठक में साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी को समाहित किया गया, जिसमें वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

ग. इंडिया-यूके पेमेंट राउंडटेबल सम्मेलन की पहली राउंडटेबल बैठक अक्टूबर 2024 में हुई है। बैठक में दोनों देशों में भुगतान परिदृश्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों को सफलतापूर्वक एक साथ लाया गया। भागीदारों ने यूके भुगतान प्राथमिकताओं, भारत में विकसित खुदरा भुगतान परिदृश्य और यूपीआई के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सार्थक चर्चा की। बैठक में प्रोजेक्ट नेक्सस से मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी शामिल थी, जिससे सहयोग और सूचना साझा करने के कार्यक्षेत्र को बढ़ावा मिला।

4. डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक – II (डीईएफटी- II): केंद्रीय बजट 2022-23 में, वित्त मंत्री ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अधिक कुशल और लागत प्रभावी मुद्रा प्रबंधन प्रणाली बनाने के उद्देश्य से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसे डिजिटल रुपया या e₹ के रूप में जाना जाता है। इसे सक्षम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 में डिजिटल रूप में मुद्रा को शामिल करने के लिए 'बैंक नोट' की परिभाषा का विस्तार करने हेतु संशोधन किया गया था। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा डिजिटल प्रारूप में जारी किया गया विधिक निविदा है, जो आर्थिक मुद्रा के समरूप पूर्ण रूप से विनिमय योग्य है। आरबीआई ने क्रमशः 1 नवंबर, 2022 और 1 दिसंबर, 2022 को e₹-होलसेल (e₹-डब्ल्यू) और e₹-रिटेल (e₹-आर) पायलट लॉन्च किया। भारत में सीबीडीसी जारी करने की खोज करने हेतु प्रमुख प्रेरणाओं में कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना, भौतिक नकदी प्रबंधन में शामिल उत्पादन और परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान में लचीलापन लाना, निपटान प्रणाली में दक्षता शामिल करना, सीमा-पार भुगतान में नवाचार को बढ़ावा देना शामिल है।

5 वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग

5.1 एफएसआरएल प्रभाग पर सार:

5.1.1 एफएसआरएल प्रभाग वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की रिपोर्ट की जांच और इसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन के कार्य से संबंधित है। यह प्रभाग एफएसएलआरसी और अन्य वित्तीय मानक निर्धारण निकायों की सिफारिशों के अनुरूप नीतिगत और विधायी प्रस्तावों को शुरू करता है, जैसा कि परामर्श प्रक्रिया में संबंधित हितधारकों, विनियामकों, मंत्रालयों और जनता को शामिल करके सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।

5.2 मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति

5.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के प्रावधान के अनुसार, मौद्रिक नीति समिति के छह सदस्यों में से तीन सदस्य आरबीआई से होंगे और मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अन्य तीन सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तदनुसार, एमपीसी का पुनर्गठन किया गया और 1 अक्टूबर, 2024 को भारत के राजपत्र असाधारण में इस प्रकार अधिसूचित किया गया:

- (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर - पदेन अध्यक्ष
- (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी - पदेन सदस्य;
- (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी जिसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा - पदेन सदस्य
- (घ) प्रो. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय - सदस्य
- (ङ) श्री सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री - सदस्य;
- (च) डा नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली - सदस्य।

उप-पैराग्राफ (घ) से (च) में विनिर्दिष्ट मौद्रिक नीति समिति के बाह्य सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से चार वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सेवा करेंगे।

6 अवसंरचना वित्त सचिवालय

अवसंरचना वित्त सचिवालय (आईएफएस) के प्रमुख डा. आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव हैं। आरएफएस में दो प्रभाग हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं

- अवसंरचना नीति एवं योजना (आईपीपी) प्रभाग
- अवसंरचना सहायता एवं विकास (आईएसडी) प्रभाग

6.1 अवसंरचना नीति और योजना (आईपीपी) प्रभाग

अवसंरचना नीति और योजना (आईपीपी) प्रभाग में निम्नलिखित इकाइयाँ हैं:

नीति और योजना इकाई (पीपीयू)

वित्त इकाई (एफयू)

क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू)

प्रत्येक इकाई का नेतृत्व निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है और उप निदेशक/सहायक निदेशक आदि द्वारा सहायता की जाती है।

6.1.1 वित्त इकाई (एफयू)

6.1.1 प्रमुख कार्य:

6.1.1 (क) वित्त इकाई अवसंरचना वित्तपोषण और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने से संबंधित नई पहलों की परिकल्पना सहित अवसंरचना की वित्तपोषण आवश्यकताओं से संबंधित है। यह इकाई निम्नलिखित कार्य करती है:

1. घरेलू स्रोतों और विदेशी पूंजी, विकास वित्त संस्थानों और वित्तीय बाजारों से वित्तपोषण की दीर्घकालिक उपलब्धता के लिए वित्तीय क्षेत्र में सुधार।
2. राजकोषीय संसाधनों, पीएसई के आईबीआर और निजी क्षेत्र से अवसंरचना वित्तपोषण।
3. अवसंरचना साधनों के विकास और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने सहित अवसंरचना वित्तपोषण से संबंधित मामलों।
4. अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईआईटी)/इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी), टैक्स फ्री बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और अवसंरचना वित्तपोषण के लिए अभिप्रेत अन्य लिखतों से संबंधित मामलों।
5. अवसंरचना परियोजनाओं की ऋण वृद्धि और अवसंरचना के लिए नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली से संबंधित मामलों।
6. अवसंरचना वित्तपोषण (पीपीपी के अलावा) से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्य।
7. पीपीपी और गैर-पीपीपी परियोजनाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा म्यूनिसिपल बांड के निर्गमन से संबंधित मामलों।
8. जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) से संबंधित मामलों।
9. आईआईएफसीएल, एआईएचएल, हुडको के निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित मामलों संयुक्त सचिव (आईपीपी) जोकि सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं

6.1.1 (ख) प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धियाँ:

6.1.1 (ख) (i) जी-20 अवसंरचना कार्य समूह (जी-20-आईडब्ल्यूजी)

अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) जी20 फाइनेंस ट्रैक के तहत एक कार्य समूह है जो जी20 के अवसंरचना की कार्यसूची को आगे बढ़ाता है। आईडब्ल्यूजी अवसंरचना से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं

पर विचार-विमर्श करता है। कार्य समूह की सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील द्वारा की जाती है।

वित्त इकाई ने निम्नलिखित प्रमुख प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) में जी20 दक्षिण अफ्रीका प्रेसीडेंसी के साथ सहयोग किया:

1. निवेश योग्य अवसंरचना पाइपलाइन विकसित करना;
2. मिश्रित वित्त दृष्टिकोण के माध्यम से सतत अवसंरचना को बढ़ावा देना;
3. क्षेत्रीय विकास के लिए सीमा-पार अवसंरचना प्रदान करना

आईडब्ल्यूजी में आम सहमति बनी और इन प्राथमिकताओं से संबंधित डिलिवरेबल्स का समर्थन किया गया।

6.1.1 (ख) (ii) रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी)/ इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी)

आरईआईटी/आईएनवीआईटी विश्वास-आधारित संरचनाएँ हैं जो एफीसिएंट टैक्स पास-थ्रू और बेहतर शासन प्रबंधन के माध्यम से अधिकतम रिटर्न देती हैं। आईएनवीआईटी और आरईआईटी के लिए दिशा-निर्देश/विनियम सेबी द्वारा 26 सितंबर, 2014 को अधिसूचित किए गए थे। सेबी के विनियमों में आईएनवीआईटी/आरईआईटी को ट्रस्ट और विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) या ट्रस्ट, होल्डको (होलडिंग कंपनी) और एसपीवी से युक्त दो-स्तरीय संरचना वाली एकल स्तरीय संरचना की अनुमति है। वर्तमान में, सेबी के पास 29 पंजीकृत आईएनवीआईटी हैं। आईएनवीआईटी ने अब तक सार्वजनिक निर्माण, निजी स्थान या अधिकार निर्माण के माध्यम से लगभग 1,46,101 करोड़ रुपये की संचयी निधि एकत्र की है। इसी तरह, कुल 7 आरईआईटी सेबी के साथ पंजीकृत हैं। आरईआईटी ने सार्वजनिक निर्माण के माध्यम से वाणिज्यिक रियल एस्टेट खंड में लगभग 29,368 करोड़ रुपये की संचयी निधि एकत्र की है।

6.1.1 (ख) (iii) अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ)

आईडीएफ को अनिवार्य रूप से अवसंरचना कंपनियों के मौजूदा ऋण के पुनर्वित्तपोषण करने के लिए साधन के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था, जिससे बैंकों के लिए नई अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण देने के लिए नए अवसरो का सृजन हुआ। आईडीएफ से उम्मीद की जाती थी कि वे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए बीमा और पेंशन निधि, सॉवरेन निधि कोष आदि से पेंशन निधि का उपयोग करेंगे, जो उनकी आस्ति-देयता विसंगति और जोखिम सीमाओं के कारण उत्तरोत्तर रूप से बाधित हो रहे हैं।

आईडीएफ की स्थापना प्रायोजक निकायों द्वारा या तो एनबीएफसी के रूप में- जो आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं और म्यूचुअल फंड के रूप

में जो सेबी द्वारा विनियमित होते हैं, द्वारा की जाती है। आज की तारीख में, एनबीएफसी रूट के तहत तीन आईडीएफ कार्यरत हैं।

6.1.1 (ख) (iv) सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क

भारत सरकार ने जलवायु-अनुकूल और समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए प्रगति और विकास की आकांक्षाओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई कि हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इस मुद्दे से प्राप्त आय का सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करना था जो अर्थव्यवस्था संबंधी उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने में मदद करते हैं।

वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में, भारत सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड (एसजीआरबी) के निर्माण के माध्यम से क्रमशः 16,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये और 21,697.40 करोड़ रुपये प्राप्त किए। वित्त वर्ष 2025-26 में, एसजीआरबी के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। इन बॉन्डों से प्राप्त आय को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पात्र हरित योजनाओं/परियोजनाओं के तहत आवंटित किया जाता है, जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के फ्रेमवर्क के अनुसार अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में मदद करते हैं।

6.1.2. नीति और योजना इकाई (पीपीयू)

6.1.2 (क) प्रमुख कार्य:

1. अवसंरचना निवेश नीति
2. अवसंरचना उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची संबंध संस्थागत तंत्र
3. मंत्रालयों/विभागों का क्षेत्रीय प्रभार:
 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय,
 - नागर विमानन मंत्रालय,
 - रेल मंत्रालय,
 - आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
 - दूरसंचार विभाग,
 - डाक विभाग
 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और
 - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।

4. निम्नलिखित से संबंधित गैर-पीपीपी निवेश प्रस्तावों का विश्लेषण

- पत्तन, पोत परिवहन अंतर्देशीय जल परिवहन,
- रेल,
- दूरसंचार,
- नागर विमानन
- सूचना और प्रसारण
- डाक
- शहरी विकास क्षेत्र
- सड़क परिवहन और राजमार्ग

5. संस्थान:

- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट और इम्प्लेमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी)
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई),
- डिजिटल संचार आयोग (पूर्ववर्ती दूरसंचार आयोग),
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीटी) लिमिटेड (पूर्व दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएमआईसीडीसी) लिमिटेड)।

6.1.2 (ख) प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धिया:

6.1.2 (ख) (i) अवसंरचना उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर सूची

19 सितंबर, 2025 को, “परिवहन और लॉजिस्टिक्स” की श्रेणी के तहत अवसंरचना के उप-क्षेत्र को “बड़े जहाजों” के रूप में जोड़ा गया था, जिसकी परिभाषा निम्नानुसार है:

“बड़े जहाजों” का अर्थ है दस हजार या उससे अधिक के सकल टन भार वाले वाणिज्यिक जहाज, जो भारतीय स्वामित्व और फ्लैग के अधीन हैं, या एक हजार पांच सौ या उससे अधिक के सकल टन भार वाले वाणिज्यिक जहाज, जो भारत में निर्मित हैं और भारतीय स्वामित्व तथा ध्वज के तहत हैं।”

6.1.2 (ख) (ii) अवसंरचना मंत्रालयों द्वारा पूंजीगत व्यय में तीव्रता लाना

विकसित भारत 2047 के भाग के रूप में, केंद्र ने निजी निवेशों में वृद्धि लाने और आर्थिक विकास में असाधारण वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि लाने के महत्व पर बल दिया है।

बजट 2025-26 के अनुसार, पूंजीगत व्यय ₹11,21,090 करोड़ होने का अनुमान है, जिसमें से दिसंबर 2025 तक 7,82,079 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है; इसके अलावा, पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता 4,27,192 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें से दिसंबर, 2025 तक 1,77,631 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जिससे सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 15,48,282 करोड़ रुपये के कुल बजटीय अनुमानों में से 9,59,710 करोड़ रुपये है, जो अवसंरचना के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

बड़े पैमाने पर सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं में इस पर्याप्त निवेश का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना और इसके महत्वपूर्ण गुणक प्रभावों के माध्यम से दीर्घकालिक उत्पादकता को बढ़ाना है। अवसंरचना में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवसरों का सृजन करके, सरकार का संकेंद्रित दृष्टिकोण व्यापक और सुदृढ़ आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है।

6.1.2 (ख) (iii) अवसंरचना निवेश प्रस्ताव

कुल 46 सीसीईए/कैबिनेट/जीओएम नोट, 23 पीआईबी/ईएफसी ज्ञापन और 82 एसएफसी/डीआईबी ज्ञापन और 11 समझौता ज्ञापन/द्विपक्षीय करार/विविध मामले, जो संबंधित मंत्रालयों/विभागों अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पूर्वोत्तर मंत्रालय और डाक विभाग से प्राप्त हुए हैं, की जांच की गई है। ये सभी निवेश प्रस्ताव कई अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित थे, जिनका कार्यान्वयन अवसंरचना सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्वतः उस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास लाएगा जहां परियोजना को लागू किया जाएगा।

6.1.3 क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू)

6.1.3 (क) प्रमुख कार्य:

क्षमता निर्माण इकाई (सीबीयू) को परियोजना की तैयारी, डिजाइन और संरचना, परियोजना मूल्यांकन, परियोजना वित्तपोषण, परियोजना-पूर्व गतिविधियों, प्रापण, कार्यान्वयन योजना और प्रबंधन आदि के लिए प्रशिक्षण/कार्यशालाओं/सेमिनारों के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों में क्षमता निर्माण से संबंधित कार्य सौंपा गया है।

कार्य क्षमता में सुधार के लिए एक बड़े कार्यक्रम संबंधी दृष्टिकोण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/कार्यशाला प्रदान करना और रियायतों/अनुबंधों आदि का मसौदा तैयार करना वांछनीय है ताकि उनको हमारी अवसंरचना के प्रबंधन तंत्र (इकोसिस्टम) का मार्गदर्शन करने वाले फ्रेमवर्क, सिद्धांतों, विनियमों की गहन जानकारी हो सके। इस तरह के कार्यक्रमगत

प्रशिक्षण डिजाइन की आवश्यकता आधारभूत स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की कार्य क्षमता के मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए है, और साथ ही परियोजनाओं की बेहतर अवधारणा और फ्रेमवर्क में भी सहायता करने के लिए है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जहां पीपीपी अवसंरचना, परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया, उपयोग मूल्य विश्लेषण लागत लाभ विश्लेषण, परियोजना चयन दृष्टिकोण, डेटा विश्लेषण और विधिक बोली खंड आदि जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

कार्य क्षमता निर्माण कार्यक्रम, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच एक-दूसरे के परियोजना अनुभवों की चूक और सफलता से सीखने के लिए आवश्यक वार्ता को बढ़ावा देने में भी सहायक है।

6.1.3 (ख) प्रमुख नीतिगत पहलें/उपलब्धियां

इस वित्तीय वर्ष (अर्थात 2025-26) में 31 दिसंबर, 2025 तक, एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद के सहयोग से सीबीयू, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 8 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन प्रशिक्षणों में देश भर के केंद्रीय मंत्रालयों, सीपीएसई, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 300 अधिकारियों ने भाग लिया है।

ई-पाठ्यक्रम- व्यापक पहुंच और अपनी क्षमता निर्माण पहल की अधिक प्रभावशीलता के लिए, सीबीयू ने अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित 21 क्षेत्र-विशिष्ट और क्षेत्र-गहन ई-पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) के साथ सहयोग किया है। अब तक आठ (8) ई-पाठ्यक्रम अर्थात परियोजना वित्त; भारत में वित्तीय और ऋण बाजार; नगर पालिका बांड; परियोजना व्यवहार्यता और बैंकबिलिटी; संरचित वित्त उपकरण और आस्ति मुद्रीकरण; सड़कों और राजमार्गों में अवसंरचना का वित्तपोषण; वित्तीय साधन और मॉडल; और अवसंरचना वित्तपोषण को आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा विकसित "सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी)- शुरुआतकर्ता" पर एक ई-पाठ्यक्रम भी आई-जीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। अब तक, देश भर के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के कुल 26,677 अधिकारियों ने उक्त 9 ई-पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन कराया है।

संयुक्त अरब अमीरात, वित्त मंत्रालय के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ज्ञान साझा करने का सत्र आयोजित किया – यूएई (एमओएफ) के अनुरोध पर, इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सचिवालय, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने दो दिनों यर्थात 29 से 30 सितंबर, 2025 तक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर ज्ञान साझाकरण सत्र आयोजित किया। हमने उनके साथ अपने पीपीपी अनुभव साझा किए। विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अवसंरचना और प्रमुख क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए समर्पित पीपीपी इकाई की स्थापना की है। इसलिए, इस दौरे का उद्देश्य परियोजना की जांच, व्यवहार्यता अध्ययन, शासन, जोखिम आवंटन और क्षमता निर्माण सहित भारत सरकार के पीपीपी फ्रेमवर्क में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था।

6.2 अवसंरचना सहायता और विकास प्रभाग (आईएसडी प्रभाग)

परिचय:

अवसंरचना सहायता और विकास प्रभाग, जो आर्थिक कार्य विभाग में अवसंरचना वित्त सचिवालय का एक भाग है, देश में अवसंरचना विकास में निवेश को बढ़ावा देने, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) आदि के माध्यम से अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए पहल से संबंधित है। इस प्रभाग में निम्नलिखित इकाइयाँ निजी जैसे निवेश: इकाई, ऊर्जा इकाई और एनआईपी सुविधा इकाई हैं। प्रत्येक इकाई का नेतृत्व एक सलाहकार/निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक द्वारा किया जाता है और एक अवर सचिव/उप निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

6.2.1 एनआईपी सुविधा इकाई

एनआईपी सुविधा इकाई के प्रमुख कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. आस्ति मुद्रीकरण (सीजीएम) पर सचिवों के कोर ग्रुप की सिफारिशों और एनएमपी पर अन्य बैठकों का कार्यान्वयन;
2. राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) पर मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन की निगरानी;
3. अवसंरचना के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने हेतु एक सक्षम व्यवस्था बनाने के लिए सामान्य सुधार पहल;
4. ईरान, साइप्रस, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन के पश्चिम एशियाई देशों का देश प्रभार;
5. महाराष्ट्र और गुजरात का राज्य प्रभार
6. प्रभाग के अंतर्गत समन्वय कार्य, आदि;

निजी निवेश इकाई (पीआईयू)

6.2.2 पीआईयू के प्रमुख कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

1. केन्द्रीय क्षेत्र की पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन से संबंधित मामले।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की स्वीकृति से संबंधित मामले और प्रस्ताव।
3. अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (व्यवहार्यता अंतर

वित्तपोषण (वीजीएफ)) योजना के लिए वित्तीय सहायता की योजना से संबंधित मामले और प्रस्ताव।

4. भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) के लिए योजना से संबंधित मामले और प्रस्ताव।
5. पीपीपी को मुख्यधारा में लाने और राज्य और स्थानीय सरकारों को समर्थन देने के लिए द्विपक्षीय/बहुपक्षीय एजेंसियों से तकनीकी सहायता और कार्यक्रम सहित देश में पीपीपी को सुविधाजनक बनाने के लिए बहु-आयामी और अभिनव हस्तक्षेप और समर्थन तंत्र विकसित करना।
6. पीपीपी को मुख्यधारा में लाने के लिए पीपीपी के लिए क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यनीतियों, एक्सपोजर और संस्था निर्माण से संबंधित अन्य मामलों का प्रबंधन करना।
7. पीपीपी और अवसंरचना पर ब्रिक्स कार्यबल सहित पीपीपी और पीपीपी से संबंधित अन्य मामलों पर सभी अंतर्राष्ट्रीय इंटरफेस।
8. www.pppinindia.gov.in सहित पीपीपी से संबंधित सूचना के प्रबंधन से संबंधित मामले ।

पीआईयू की प्रमुख नीतिगत पहल/उपलब्धियां

1. अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी (वीजीएफ योजना) के लिए वित्तीय सहायता
- (i) आर्थिक कार्य विभाग वर्ष 2006 में शुरू की गई अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण) योजना आर्थिक रूप से वांछनीय लेकिन वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य पीपीपी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आर्थिक क्षेत्र की परियोजनाओं को वीजीएफ अनुदान के रूप में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 40% तक प्राप्त हो सकता है, जबकि सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाएं पांच साल के बाद के संचालन के लिए पूंजीगत व्यय का 80% और परिचालन व्यय (ओपेक्स) का 50% तक अनुदान के लिए पात्र हैं।
- (ii) सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं को दो योजनाओं के तहत वीजीएफ मिलता है: उप-योजना-1: अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति और टोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में कम से कम 100% परिचालन लागत वसूली के साथ परियोजनाओं का समर्थन करता है। वित्त पोषण में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का 30% तक और परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त 30% शामिल है। उप-योजना-2: स्वास्थ्य और शिक्षा

क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें कम से कम 50% परिचालन लागत वसूली की आवश्यकता होती है। भारत सरकार परिचालन के पहले पांच वर्षों के लिए कैपेक्स का 40 प्रतिशत और ओपेक्स का 25% प्रदान करती है और इसका मिलान परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा भी किया जा सकता है।

- (iii) व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना के तहत, कुल 72 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 7,941.838 करोड़ रुपये का वीजीएफ (4 दिसंबर, 2025 तक) स्वीकृत किया गया है। इसमें से 6,314.86 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

2. सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)

सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करती है। इसका सुव्यवस्थित मूल्यांकन तंत्र समय पर मूल्यांकन सुनिश्चित करने, देरी को खत्म करने, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धति को शामिल करने और प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के सचिव की अध्यक्षता में, इसके सदस्यों में व्यय विभाग और विधिक विभाग, प्रायोजक मंत्रालय/विभाग के सचिव और नीति आयोग के सीईओ शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 (4 दिसंबर, 2025 तक) तक, पीपीपीएसी ने 5,60,965.71 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत (टीपीसी) के साथ 129 परियोजनाओं की सिफारिश की है।

3. पीपीपी परियोजना पाइपलाइन:

केंद्रीय बजट 2025-26 के पैरा 52 के कार्यान्वयन में, 3 साल की पीपीपी परियोजना पाइपलाइन बनाई गई है। पीपीपी परियोजना पाइपलाइन में केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 852 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

4. पीपीपी नीति से संबंधित उपाय:

देश में पीपीपी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) में आईएफएस और आईएसडी ने जून 2024 से दिसंबर 2025 के बीच अनेक पहल की हैं। इन प्रयासों को पीपीपी लेनदेन में शामिल हितधारकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका उद्देश्य पीपीपी फ्रेमवर्क की दक्षता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। यह पहल पीपीपी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए अधिकारियों की आंतरिक क्षमता निर्माण करने, आवश्यक मानकीकरण शुरू करने और पीपीपी के लिए एक अनुशासित और संरचित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- खरीद प्रक्रिया को कारगर बनाने और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए एकल चरण की बोली प्रक्रिया के लिए मॉडल अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) अधिसूचित किया गया है।
- पीपीपी परियोजनाओं में जोखिम आवंटन, संतुलन और संभावित जोखिम शमन रणनीतियों के लिए एक विस्तृत फ्रेमवर्क प्रदान करके परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (पीएसए) और अन्य हितधारकों की सहायता करने के लिए इष्टतम जोखिम आवंटन के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की संस्थागत तैयारियों का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना सक्षमता सूचकांक (एनआईई-1) विकसित किया गया है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं में रियायत सिद्धांतों के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका** प्रकाशित की गई है, ताकि परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों (पीएसए) और अन्य हितधारकों को मानक रियायत संरचनाएं, प्रमुख जोखिम-आवंटन सिद्धांतों और सामान्य संविदात्मक प्रावधानों के लिए सुझाए गए प्रारूपण दृष्टिकोण प्रदान करके सहायता प्रदान की जा सके।

5. ज्ञान का प्रसार और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना

- क. दिसंबर 2025 तक, पीपीपी परियोजनाओं की संरचना में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों, पीपीपी मामलों से निपटने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संभालने के लिए, चार पीपीपी संरचना टूलकिट कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। इन कार्यशालाओं में सड़क और राजमार्ग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन, जल और स्वच्छता और बंदरगाह जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन कार्यशालाओं का आयोजन व्यक्तिगत रूप से किया गया, जिसमें कुल सौ से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, विजयवाड़ा में ब्रिटिश उच्चायोग के सहयोग से क्रमशः एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इन कार्यशालाओं ने पीपीपी पर ज्ञान का प्रसार किया, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाते हुए और सर्वोत्तम पद्धतियों, वित्तपोषण कार्यनीतियों और नीतिगत फ्रेमवर्क की उनकी समझ को गहरा करते हुए क्षेत्र-विशिष्ट पीपीपी पाइपलाइनों के निर्माण के लिए केंद्रित सलाहकार इनपुट प्रदान किए।
- ख. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) का वर्ष 2023 में शुभारंभ किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी बिगिनर्स ई-कोर्स को पीपीपी को समझने और उनसे जुड़ने के इच्छुक

विविध दर्शकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पीपीपी से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने वाला एक व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें 51 वास्तविक दुनिया के केस स्टडीज से प्राप्त व्यावहारिक अंतर्दृष्टि पर जोर दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम से विभिन्न क्षेत्रों के 2,500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ महत्वपूर्ण रुचि प्राप्त हुई है, और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के लिए इसकी गहन सामग्री और व्यावहारिक प्रयोज्यता व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

- ग. वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एक मजबूत पीपीपी ढांचा विकसित करने के बारे में ज्ञान का प्रसार करने के लिए श्रीलंका का दौरा किया। इस बातचीत का उद्देश्य पीपीपी को लागू करने में भारत के अनुभव को साझा करना और एक संरचित और कार्यनीतिक तरीके से द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना था।

क. पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता [भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि (आईआईपीडीएफ) योजना]:

दिनांक 3 नवंबर 2022 को अधिसूचित भारत अवसंरचना परियोजना विकास कोष (आईआईपीडीएफ) योजना का उद्देश्य व्यवहार्य, केबल परियोजनाओं की एक पाइपलाइन बनाने के लिए लेनदेन सलाहकारों को वित्त पोषित करके गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं को विकसित करने में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों का समर्थन करना है। वित्त वर्ष 2023-वित्त वर्ष 2025 के लिए ₹150 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ, यह योजना कंसल्टेंट और ट्रांज़ैक्शन एडवाइजर लागतों के लिए प्रति प्रोजेक्ट (टैक्स सहित) ₹5 करोड़ तक की निधियन करती है, जिसमें प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च होते हैं। निधियन गैर-वसूली योग्य है। इस योजना के तहत (25 दिसंबर तक) 64.13 करोड़ रुपये की राशि के कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। स्वीकृत पोर्टफोलियो योजना की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है, जिसमें नामसाई (अरुणाचल प्रदेश) में एक मेडिकल कॉलेज के रूप में विविध परियोजनाएं जैसे पंजाब में पर्यटक परिसर; त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में एक समर्पित पीपीपी सेल; हिमाचल प्रदेश में एक यात्री रोपवे; आंध्र प्रदेश में एक फ्लोटिंग सौर-फोटोवोल्टिक संयंत्र; आईआईएम मुंबई में एकीकृत छात्र-और-संकाय सुविधाओं के साथ उत्कृष्टता का एक फिनटेक केंद्र; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इको-टूरिज्म रिसॉर्ट्स; मिजोरम में एक हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर परियोजना; और दिल्ली पुलिस के लिए आवास इकाइयां और कश्मीर में परियोजनाएं शामिल हैं।

^[1] सेबी की वेबसाइट

7. निवेश प्रभाग

निवेश प्रभाग में निम्नलिखित चार अनुभाग शामिल हैं:

- क. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं प्रत्यक्ष विदेशी (ओवरसीज) निवेश नीति (एफडीआई एवं ओडीआई) अनुभाग
- ख. घरेलू निवेश (डीआई) अनुभाग
- ग. अंतरराष्ट्रीय निवेश संधियाँ और फ्रेमवर्क (आईआईटीएफ) अनुभाग,
- घ. विदेशी व्यापार एवं सेवाएँ (एफटी) अनुभाग और

निवेश प्रभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:

- i. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/घरेलू निवेश नीति में नई नीतिगत पहलों सहित विदेशी/घरेलू निवेश नीतियों पर नीतिगत सहायता प्रदान करना, साथ ही एफडीआई/डीआई नीति स्पष्टीकरण और संबंधित मामलों पर भी सहायता प्रदान करना।
- ii. 16 दिसंबर, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि पाठ के आधार पर अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) और एफटीए/सीईसीए/सीईपीए के निवेश अध्याय पर बातचीत करना और उन्हें अंतिम रूप देना तथा भारत सरकार में नोडल विभाग के रूप में विदेशी देशों के साथ हस्ताक्षरित बीआईटी/एफटीए से उत्पन्न निवेशक राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) नोटिस/मामलों का निपटान करना।
- iii. व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं, जिनमें ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों शामिल हैं, में अवसंरचना विकास के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्रोतों से इक्विटी निवेश से संबंधित मामले, जिनमें राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के माध्यम से रुकी हुई परियोजनाएं और एस डब्ल्यूएमआईएच निधि-1 से संबंधित कार्य शामिल हैं।
- iv. स्वर्ण संबंधी विदेशी मुद्रा पहलू, जिसमें स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, भारतीय स्वर्ण सिक्के आदि शामिल हैं।
- v. आर्थिक मुद्दों पर इस्पात मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, निवेश एवं सार्वजनिक आरिष्ठ प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम), उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), वाणिज्य विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार विभिन्न मामलों पर उन्हें टिप्पणियाँ/सुझाव देना। इस विभाग के पास मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों का बाह्य प्रादेशिक प्रभार है।

क. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई एवं ओडीआई) अनुभाग

इस अनुभाग का कार्य विदेशी निवेश नीतियों पर नीतिगत सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में नई नीतिगत पहल और एफडीआई नीति स्पष्टीकरण एवं संबंधित मामले शामिल होने के साथ-साथ, आर्थिक कार्य विभाग में प्राप्त एफडीआई प्रस्तावों का प्रसंस्करण भी इस अनुभाग का कार्य है। यह अनुभाग विदेशी निवेश संबंधी मुद्दों पर डीपीआईआईटी, राजस्व विभाग, आरबीआई और सेबी के साथ समन्वय स्थापित करता है और एफडीआई नीति में किसी भी संशोधन पर उन्हें टिप्पणियाँ/सुझाव प्रदान करता है। यह एफडीआई नीति के संबंध में भारत में निवेश के स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाता है। यह अनुभाग आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर विभिन्न क्षेत्रों और देशों से आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़ों को मासिक आधार पर प्रकाशित करता है।

आर्थिक कार्य विभाग को (एफडीआई नीति, 2020 के अनुसार) निम्नलिखित के लिए एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन/जांच का दायित्व सौंपा गया है:

- i. "वित्तीय सेवाएं जो किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित नहीं हैं या जहां वित्तीय सेवाओं की गतिविधि का केवल एक हिस्सा विनियमित है या जहां नियामक निरीक्षण के संबंध में संदेह है"; और
- ii. मुख्य निवेश (कोर इन्वेस्टमेंट) कंपनी या किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश के लिए आवेदन, जो केवल अन्य भारतीय कंपनी/ कंपनियों की पूंजी में निवेश करने की गतिविधि में लगी हो।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक निवेशक-अनुकूल नीति लागू की है जो पारदर्शी, पूर्वानुमानित और आसानी से समझ में आने वाली है। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर, अधिकांश क्षेत्रों को ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार या आरबीआई से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। निवेशकों को केवल आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना और दस्तावेज जमा करना होता है। सरकार के अनुमोदित माध्यम के तहत, आवेदन विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल (एफआईएफपी) में जमा किए जाते हैं, जो निवेशकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार का नया ऑनलाइन सिंगल प्वाइंट इंटरफ़ेस है, और जो संबंधित विषय मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। स्पेस सेक्टर को वर्ष 2024 में निर्धारित उपक्षेत्रों/ गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए मुक्त बनाया गया है।

विदेशी निवेश नियमों और विनियमों को अधिसूचित करना:

भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी निवेश नियमों और विनियमों को सरल बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। अंतिम विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी निवेश) विनियम,

2022 को अधिसूचित किया गया था। अधिसूचना की प्रति दिसंबर 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई थी। विदेशी निवेश के लिए संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क विदेशी निवेश के मौजूदा फ्रेमवर्क को सरल बनाता है और इसे वर्तमान व्यापार और आर्थिक गतिशीलता के अनुरूप बनाया गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश पर स्पष्टता लाई गई है और विदेशी निवेश से संबंधित विभिन्न लेनदेन जो पहले अनुमोदन के माध्यम से होते थे, अब स्वचालित माध्यम से हो रहे हैं, जिससे व्यापारिक सुगमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ख. घरेलू निवेश (डीआई) अनुभाग

घरेलू निवेश (डीआई) अनुभाग भारत के लिए राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों, विशेष रूप से अवसंरचना और मध्यम आय वर्ग के आवास क्षेत्रों में निवेश को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दो निधियों राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) और एसडब्ल्यूएएमआईएच निधि का प्रबंधन करता है। यह अनुभाग निधि प्रबंधकों से निधि जारी करने के अनुरोधों पर कार्रवाई करता है।

एनआईआईएफ निधि

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड ('एनआईआईएफ लिमिटेड') वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एआईएफ) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत 4 निधियों का प्रबंधन करता है।

(क) राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष ('एनआईआईएफ मास्टर फंड')

यह निधि मुख्य रूप से सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, विद्युत आदि जैसे मूलभूत अवसंरचना क्षेत्रों की आवश्यकताओं में निवेश करता है। निवेश मुख्य रूप से उन व्यवसायों में होता है जो अक्सर विनियमित वातावरण में या रियायत या दीर्घकालिक समझौतों के तहत काम करते हैं। निवेशकों में भारत सरकार, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण, ओटारियो टीचर्स, ऑस्ट्रेलियन सुपर, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, टेमासेक, पीएसपी इन्वेस्टमेंट्स, यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन और अन्य घरेलू वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

पोर्टफोलियो इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	दिनांक 31.12.2025 तक की राशि
कुल पूंजी प्रतिबद्धता	15,998
निकाली गई पूंजी	12,970

(ख) एनआईआईएफ निधियों का निधियन-I ("एनआईआईएफ एफओएफ")

यह निधि तृतीय-पक्ष द्वारा प्रबंधित निधियों में निवेश करता है, जिनके प्रमुख क्षेत्र हरित अवसंरचना, मध्यम आय/किफायती आवास, अवसंरचना सेवाएं, सामाजिक अवसंरचना, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक और दूरसंचार हैं। यह निधि विभिन्न क्षेत्रों, उत्पादों और निवेश शैलियों में विविधतापूर्ण कार्यनीति अपनाता है। भारत सरकार द्वारा समर्थित इस निधि को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी), एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) सहित बहुपक्षीय संस्थानों से प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।

पोर्टफोलियो इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	दिनांक 31.12.2025 तक की राशि
कुल पूंजी प्रतिबद्धता	4,281
निकाली गई पूंजी	3,986

(ग) भारत जापान फंड ('आईजेएफ')

एनआईआईएफ ने अगस्त 2023 में भारत सरकार और जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) के सहयोग से 4,900 करोड़ रुपये (लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के भारत-जापान कोष (आईजेएफ) की शुरुआत की। यह कोष नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी व्यवसायों और अपशिष्ट प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था क्षेत्रों सहित भारत के पर्यावरण क्षेत्र में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह कोष विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय और जापानी कंपनियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के अवसरों में भी निवेश करेगा।

पोर्टफोलियो इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	दिनांक 31.12.2025 तक की राशि
कुल पूंजी प्रतिबद्धता	4,908
निकाली गई पूंजी	1,659

(घ) राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष-II (स्ट्रेजिक ऑपर्ट्युनिटिज फंड, 'एसओएफ'):

यह निधि उच्च विकास के अवसरों और नवोन्मेषी कंपनियों पर केंद्रित है। यह निधि व्यवसायों में या तो बड़ी हिस्सेदारी (इनक्यूबेशन डील/ नियंत्रण-उन्मुख डील) या सक्रिय अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के माध्यम से निवेश करता है।

एनआईआईएफ इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एनआईआईएफ आईएफएल): एनआईआईएफ एसओएफ ने एनआईआईएफ आईएफएल में निवेश किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के रूप में पंजीकृत एक गैर-वित्तीय वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। एनआईआईएफ आईएफएल देश भर में उन परिचालनशील अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक पुनर्वित्त समाधान प्रदान करती है जिन्होंने कम से कम एक वर्ष का संतोषजनक संचालन पूरा कर लिया है।

असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एआईएफएल): एनआईआईएफ एसओएफ ने एक एनबीएफसी-आईएफसी, असीम इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड (एआईएफएल) में भी निवेश किया है, जो परिचालन, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड संपत्तियों के मिश्रण के साथ बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाओं में निवेश करता है।

एआईएफएल और एनआईआईएफ आईएफएल भारत में अवसंरचनासे संबंधित ऋण वित्तपोषण की पूरी श्रृंखला को कवर करने के लिए एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। (दोनों गैर-लाभकारी संस्थाओं एनबीएफसी) के कुल ऋण का आकार लगभग 45,000 करोड़ रुपये है, और दोनों कंपनियों के पोर्टफोलियो में कोई भी गैर-लाभकारी संस्था (एनपीए) नहीं है।

किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष विंडो (एसडब्ल्यूएमआईएच) निवेश कोष ।

माननीय वित्त मंत्री द्वारा श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में एक 'विशेष विंडो' स्थापित करने की घोषणा के बाद दिसंबर 2019 में इस कोष की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य रुके हुए/संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्तपोषण प्रदान करना था। इस कोष का प्रबंधन भारतीय स्टेट बैंक की सहायक कंपनी एसबीआई वेंचर्स लिमिटेड (पूर्व में एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड) द्वारा किया जाता है। कोष का निवेश उद्देश्य भारत भर में विभिन्न क्षेत्रों में रुके हुए/संकटग्रस्त आवासीय विकास परियोजनाओं का निर्माण पूरा करना है।

यह निधि आरईआरए(रेरा)-पंजीकृत आवास परियोजनाओं में निवेश करता है, जहां फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) का 90% हिस्सा किफायती/मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए आरक्षित है, इकाइयों का रेटा कारपेट एरिया 200 वर्ग मीटर से कम है और मुंबई महानगर क्षेत्र में घरों की कीमत 2.0 करोड़ रुपये से कम है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बंगलुरु और अहमदाबाद में 1.5 करोड़ रुपये से कम है और शेष भारत में 1.0 करोड़ रुपये से कम है। परियोजनाओं की कुल लागत का सकारात्मक होना भी आवश्यक है और परियोजना लागत का कम से कम 30% पूरा होना चाहिए।

एसडब्ल्यूएमआईएच में निवेश करने वाले चौदह निवेशकों में से प्रत्येक द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं का विवरण

क्र.सं.	निवेशक	राशि (करोड़ रुपये में)
1	भारत सरकार	10,000
2	भारतीय स्टेट बैंक	1,250
3	जीवन बीमा निगम	1,250
4	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	500
5	इंडियन बैंक	400
6	पंजाब नेशनल बैंक	400
7	केनरा बैंक	400
8	बैंक ऑफ बड़ौदा	400
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	400
10	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्व में एचडीएफसी लिमिटेड)	250
11	बैंक ऑफ इंडिया	100
12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	100
13	पंजाब एंड सिंध बैंक	75
14	एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड (निवेश प्रबंधक)	6
	कुल	15,531

एसडब्ल्यूएमआईएच निधि । का पोर्टफोलियो निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	दिनांक 31.01.2026 तक की राशि
कुल पूंजी प्रतिबद्धता	15,531.0
निकाली गई पूंजी	10,772.9

31 जनवरी, 2026 तक, निधि ने पूरे भारत में 161 निवेश किए हैं। परियोजना पूर्ण होने पर, फंड ने 55 निवेशों से लाभप्रद रूप से पूर्ण निकास प्राप्त किया है। लगभग 61,673 आवास इकाइयों के लिए आवेदन किया गया है/निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

ग. अंतरराष्ट्रीय निवेश संधियाँ और फ्रेमवर्क(आईआईटीएफ) अनुभाग

आईआईटीएफ अनुभाग का मुख्य कार्य 16 दिसंबर, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संशोधित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) के प्रारूप के आधार पर अन्य देशों के साथ मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर बातचीत करना और उन्हें अंतिम रूप देना है। यह अनुभाग विदेशी देशों के साथ हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौतों एफटीए/सीईपीए/सीईपीए के अंतर्गत बीआईटी/निवेश संरक्षण अध्याय से उत्पन्न निवेशक-

राज्य विवाद निपटान (आईएसडीएस) नोटिस/मामलों का भी निपटान करता है। इस अनुभाग द्वारा यूएनसीआईटीआरएएल, यूएनसीटीएडी, जी20, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों में निवेश संबंधी मुद्दों को भी निपटाया जाता है। इसके अतिरिक्त, बीआईटी मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए क्षमता निर्माण पहल भी आयोजित की जाती हैं।

उपलब्धियों

भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में एक देश के साथ व्यापार समझौता (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए हैं और अन्य देशों के साथ 3 व्यापार समझौते (बीआईटी) वित्त वर्ष 2025-26 में लागू हो गए हैं:

क्र.सं.	देश और करार का नाम	करार पर हस्ताक्षर करने की तिथि	लागू होने की तिथि
1.	ब्राजील: निवेश सहयोग एवं सुविधा संधि	25 जनवरी, 2020	21 दिसंबर, 2025
2.	इजराइल: द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईए)	08 सितंबर, 2025	लंबित
3.	किर्गिज गणराज्य: द्विपक्षीय निवेश संधि	14 जून, 2019	05 जून, 2025
4.	उज्बेकिस्तान: द्विपक्षीय निवेश संधि	27 सितंबर, 2024	15 मई, 2025

भारत वर्तमान में कई अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहा है।

घ. विदेशी व्यापार एवं सेवाएँ (एफटी) अनुभाग

निवेश प्रभाग के विदेशी व्यापार (एफटी) अनुभाग का मुख्य कार्य सोने/चांदी से संबंधित विदेशी मुद्रा पहलुओं से संबंधित नीतिगत मामलों, सोने से संबंधित नीतिगत मामलों जैसे स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस), भारतीय स्वर्ण सिक्का (आईजीसी) और स्वर्ण धातु ऋण (जीएमएल) की देखरेख करना और वित्तीय आस्ति वर्ग के रूप में सोने को बढ़ावा देने के लिए नीति का मसौदा तैयार करना है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

भारत सरकार ने 5 नवंबर, 2015 को स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य घरों और संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े सोने को जुटाना, उसे उत्पादक कार्यों में लगाना (जैसे रत्न और आभूषण क्षेत्र को सोने की आपूर्ति करना) और धीरे-धीरे सोने के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना था। इस योजना में तीन मुख्य घटक शामिल हैं:

क. अल्पकालिक बैंक जमा (1-3 वर्ष)

ख. मध्यम अवधि की सरकारी जमा (5-7 वर्ष)

ग. दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष)

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के कार्य निष्पादन की समीक्षा और बाजार की बदलती परिस्थितियों के आधार पर, जीएमएस के मध्यम

अवधि और दीर्घकालिक सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) घटकों को 26 मार्च, 2025 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जीएमएस के तहत बैंकों द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी) एकल बैंकों के विवेकानुसार, उनके द्वारा मूल्यांकन की गई व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर जारी रहेंगी।

नवंबर 2025 तक, जीएमएस के तहत लगभग 39,044 किलोग्राम सोना जुटाया जा चुका है। विवरण इस प्रकार है:

जीएमएस के तहत जुटाए गए सोने का विवरण (30 नवंबर 2025 तक)

क्र.सं.	जमा के प्रकार	30.11.2025 तक जमा किया गया सोना (किलोग्राम में)
1.	सोने की कुल मात्रा (किलोग्राम में)	39,044.40
2.	अल्पकालिक स्वर्ण जमा	9311.72
3.	मध्यम अवधि स्वर्ण जमा	10541.32
4.	दीर्घकालिक स्वर्ण जमा	19191.36
5.	भागीदार बैंकों की संख्या	10
6.	जमाकर्ताओं की संख्या	6531

8. फंड बैंक एवं एडीबी प्रभाग

8.1 परिचय

8.1.1 निधि बैंक प्रभाग विश्व बैंक समूह, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और संबंधित संस्थानों जैसे बहुपक्षीय संस्थानों के नीतिगत मामलों से संबंधित है। फंड बैंक प्रभाग बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (पूरे भारत में केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं) की सुविधा और निगरानी के लिए नोडल बिंदु भी है, जिन्हें बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य संबंधित ट्रस्ट फंडों / ऋणों / अनुदानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

8.2 विश्व बैंक समूह

8.2.1 विश्व बैंक दुनिया के अग्रणी विकास संस्थानों में से एक है, जिसका उद्देश्य ऋण, गारंटी, जोखिम प्रबंधन उत्पादों और (गैर-ऋण) विश्लेषणात्मक और सलाहकार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देकर गरीबी का सामना करने और विकासशील देशों में लोगों के लिए जीवन स्तर में सुधार करने है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। विश्व बैंक सतत गरीबी में कमी लाने के उद्देश्य से सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता है।

8.2.2 भारत विश्व बैंक समूह के चार संस्थानों अर्थात् अंतराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी); अंतराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए); अंतराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश

गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) का सदस्य है। भारत विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक (मुख्य रूप से आईबीआरडी के माध्यम से) से निधि प्राप्त कर रहा है। विश्व बैंक समूह से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ विश्व बैंक (आईबीआरडी) की सहायता से परियोजनाएं शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श के लिए विश्व बैंक समूह की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए फंड बैंक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग भारत का मुख्य केंद्र है।

8.3. विश्व बैंक भारत पोर्टफोलियो

8.3.1. दिनांक 10.12.2025 तक विश्व बैंक के भारत पोर्टफोलियो (राज्य परियोजनाओं) में 9,726.42 मिलियन अमरीकी डालर की निवल प्रतिबद्धता के साथ 53 परियोजनाएं शामिल हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त तीन (03) परियोजनाएं: मणिपुर इन्फोटेक विकास परियोजना, कर्नाटक जल सुरक्षा और तन्यकता कार्यक्रम और तमिलनाडु महिला रोजगार और सुरक्षा (टीएन डब्ल्यूईएसएफई) ऑपरेशन, दिनांक 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के दौरान 622 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि पर हस्ताक्षर किए गए।

8.3.2 दिनांक 30.11.2025 तक विश्व बैंक के भारत पोर्टफोलियो (केंद्रीय क्षेत्र) में 6279.09 मिलियन अमरीकी डालर (सीटीएफ ऋण/सीटीएफ अनुदान/जीपीजी अनुदान सहित) की निवल प्रतिबद्धता के साथ 18 परियोजनाएं शामिल हैं और 1 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 के दौरान किसी परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

8.3.3. नई दिल्ली में 18-20 नवंबर 2025 तक चल रही और पाइपलाइन परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की गई।

8.4 विश्व बैंक से संबंधित प्रमुख गतिविधियाँ

8.4.1 विश्व बैंक पोर्टफोलियो की निगरानी: चालू परियोजनाओं के लिए त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकों और पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए लगातार चल रही समीक्षा बैठकों जैसी समीक्षा बैठकों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में पोर्टफोलियो के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। ये बैठकें भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाती हैं और इनमें आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), विश्व बैंक और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों के अधिकारी भाग लेते हैं। विश्व बैंक की चल रही और पाइपलाइन परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए त्रिपक्षीय बैठक दिनांक 18 नवंबर से दिनांक 20 नवंबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

8.4.2 आईडीए के दाता के रूप में भारत; वर्ष 1960 में अपनी स्थापना के बाद से, आईडीए में 20 नियमित पुनःपूर्ति हुई है। वर्ष 2014 (आईडीए 17) में, भारत एक आत्मविश्वासी दाता बन गया है। यद्यपि, इसे आईडीए 17 (2014-17) के दौरान ट्रांजिशन समर्थन प्राप्त करना जारी रहा। आईडीए 18 के दौरान भारत केवल दाता राष्ट्र बन गया। अत्यधिक गरीबी को खत्म करने, भेद्यता को कम करने और देशों में लचीलापन बढ़ाने के भारत के साझा उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, भारत ने आईडीए 17 पुनःपूर्ति में 200 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान करने का निर्णय लिया। आईडीए देशों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, भारत ने आईडीए 18 पुनःपूर्ति के लिए

अपने योगदान के रूप में 12.25 बिलियन रुपये की प्रतिबद्धता की घोषणा की। आईडीए 19, आईडीए 20 और आईडीए 21 पुनःपूर्ति के दौरान, भारत ने क्रमशः 15 बिलियन रुपये, 17.48 बिलियन रुपये और 23.21 बिलियन रुपये की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

8.5 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)

8.5.1 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), जो विश्व बैंक समूह का एक सदस्य है, विकासशील देशों में निजी क्षेत्र में निवेश करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। वर्ष 1956 में स्थापित, आईएफसी में 186 सदस्य हैं। भारत आईएफसी का संस्थापक सदस्य है। आईएफसी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकास भागीदार है, जिसका संचालन देश में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण और सलाह पर केंद्रित है। भारत कुल सदस्यता के 4.18% और कुल मतदान शक्ति के 3.98% के साथ आईएफसी का छठा सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत के कार्यकारी निदेशक 4.79% मतदान शक्ति के बराबर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईएफसी में भारत के निर्वाचन क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका हैं। आईएफसी ने वर्ष 1958 में अपने पहले निवेश के बाद से भारत में 37 बिलियन अमरीकी डालर (लामबंदी सहित) से अधिक की प्रतिबद्धता दिखाई है। आईएफसी ने भारत में वित्त वर्ष 2025 (जुलाई 2024-जून 2025) में अपने खाते और जुटाव के माध्यम से 5.366 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक वितरित करना जारी रखा। जुलाई 2024-जून 2025 के दौरान, आर्थिक कार्य विभाग ने कुल 38 अनुच्छेद III अधिसूचनाओं को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य विभाग ने जुलाई 2024 और जून 2025 के बीच आईएफसी के 2 सलाहकार कार्यक्रमों के लिए मंजूरी दी। 31 अगस्त, 2025 तक आईएफसी के पोर्टफोलियो में 210 ग्राहकों के साथ 278 परियोजनाएं शामिल थीं, जिनमें 10.354 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पोर्टफोलियो एक्सपोजर था, जिससे भारत आईएफसी का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बन गया, जो इसके वैश्विक एक्सपोजर का 11 प्रतिशत है। भारत आईएफसी के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, साथ ही दक्षिण एशिया के लिए आईएफसी क्षेत्रीय केंद्र भी है। भारत में आईएफसी के निवेश का विस्तार अवसंरचना, विनिर्माण, वित्तीय बाजारों, एमएसएमई, किरायाती आवास, नवीकरणीय ऊर्जा, लैंगिक विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में है। विश्व बैंक समूह के कंटी पार्टनरशिप फ्रेमवर्क (सीपीएफ) के अनुरूप, आईएफसी अपनी निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए करता है जो समावेशी, उत्पादक और टिकाऊ है।

8.6 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

8.6.1 भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य है, जिसे एक सहकारी और स्थिर वैश्विक मौद्रिक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। वर्तमान में, 191 देश आईएमएफ के सदस्य हैं। आईएमएफ की स्थापना के बाद से, इसके उद्देश्य अपरिवर्तित रहे हैं, लेकिन इसके संचालन - जिसमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है - एक विकसित विश्व अर्थव्यवस्था में अपने सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित हुए हैं। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में

प्रत्येक सदस्य देश से एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर होता है। भारत के लिए, वित्त मंत्री आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पदेन गवर्नर होते हैं। आईएमएफ में भारत के निर्वाचन क्षेत्र में तीन अन्य देश बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका हैं। गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारत का वैकल्पिक गवर्नर है।

8.6.2 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठकें

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आमतौर पर वर्ष में दो बार बैठक करता है जैसे कि संबंधित संस्थानों के कार्य पर चर्चा करने के लिए आईएमएफ और विश्व बैंक की स्प्रिंग बैठकें और वार्षिक बैठकें हैं। बैठक के केंद्र में आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठकें हैं। भारत का प्रतिनिधित्व आईएमएफसी में माननीय वित्त मंत्री और विश्व बैंक-आईएमएफ विकास समिति (डीसी) द्वारा किया जाता है, जो आईएमएफ और विश्व बैंक के कार्य पर प्रगति पर चर्चा करता है।

8.6.3 आईएमएफ/विश्व बैंक, विश्व बैंक-आईएमएफ की स्प्रिंग बैठकें, जी-20 की बैठकें, द्विपक्षीय बैठकें और निवेश बैठकें और अन्य संबंधित बैठकें दिनांक 21 अप्रैल से दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गईं। इन बैठकों में माननीय वित्त मंत्री, सचिव (आर्थिक कार्य), मुख्य आर्थिक सलाहकार, अपर सचिव (एफबी, ओएमआई और क्रिप्टो), संयुक्त सचिव (एफबी), सलाहकार (आईआईआर), निदेशक (निवेश) और संयुक्त निदेशक (आईआईआर) ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

8.6.4 भारत ने आईएमएफ में कार्यकारी निदेशकों के वर्ष 2025 के उपचुनाव में आईएमएफ में डॉ. उज्जित पटेल ईडी भारत के पक्ष में मतदान किया।

8.6.5 भारत ने एसएआरटीटीएसी संचालन के चरण II (जनवरी 2024 – अप्रैल 2029) के लिए 25 मिलियन की दो किस्तों में 50 मिलियन अमरीकी डालर का योगदान दिया है। 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त 29 मई, 2024 को दो किस्तों में पूरी की गई थी। 25 मिलियन अमरीकी डालर की दूसरी किस्त 10 जुलाई, 2025 को पूरी तरह से वितरित की गई थी।

8.6.6 आईएमएफ आर्टिकल IV स्टाफ का दौरा 4-18 सितंबर, 2025 के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें रैप अप बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सचिव (ईए) ने की थी और इसमें सभी संबंधित विभागों ने भाग लिया था। वृहद आर्थिक मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों और डेटा पर्याप्तता मूल्यांकन पर चर्चा की गई। कर्मचारियों के निष्कर्षों की अंतिम रिपोर्ट भी 26 नवंबर, 2025 को प्रकाशित की गई है।

8.6.7 आईएमएफ/विश्व बैंक की वार्षिक बैठकें, जी-20 की बैठकें, द्विपक्षीय बैठकें और निवेश बैठकें और अन्य संबंधित बैठकें 13 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गईं। सचिव (आर्थिक कार्य), मुख्य आर्थिक सलाहकार, संयुक्त सचिव (एफबी), सलाहकार (सीसीएफयू), निदेशक (एफबी) और संयुक्त निदेशक (आईआईआर) ने इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

8.7 वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन (जीएवीआई एलायंस)

8.7.1 जीएवीआई एलायंस (पूर्व में वैक्सीन और टीकाकरण के लिए वैश्विक गठबंधन) की स्थापना वर्ष 2000 में जीवन रक्षक टीकों तक पहुंच में ऐतिहासिक अंतर को कम करने और बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए की गई थी। जीएवीआई का मिशन गरीब देशों में टीकाकरण तक पहुंच बढ़ाकर बच्चों के जीवन को बचाना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। भारत न केवल प्राप्तकर्ता है, बल्कि जीएवीआई गठबंधन में योगदानकर्ता भी है। 30 जून 2021 को भारत सरकार और जीएवीआई के बीच हस्ताक्षरित 'योगदान समझौते' के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 2021-25 के माध्यम से पांच साल के पुनःपूर्ति चक्र के दौरान जीएवीआई गठबंधन के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर (3 मिलियन अमरीकी डॉलर) का योगदान दिया। 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पांचवीं और अंतिम किस्त 30 जनवरी, 2025 को दी गई थी।

8.7.2 पांच साल के अगले पुनःपूर्ति चक्र अर्थात वर्ष 2026-30 में जीएवीआई में भारत के योगदान को बढ़ाने के लिए मई 2025 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार वर्ष 2026-2030 की अवधि के दौरान जीएवीआई के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात प्रत्येक वर्ष 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देगी।

8.8 एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष (जीएफएटीएम)

8.8.1 एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष (वैश्विक कोष/जीएफएटीएम) एक अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी और एड्स, तपेदिक और मलेरिया को रोकने और इलाज के लिए अतिरिक्त संसाधनों को आकर्षित करना और वितरित करना है। यह संगठन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में सचिवालय के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी है। संगठन ने जनवरी 2002 में परिचालन शुरू किया। जीएफएटीएम समर्थित कार्यक्रमों ने वर्ष 2002 के बाद से 65 मिलियन लोगों का जीवन सुरक्षित करने का अनुमान लगाया है।

8.8.2 6 फरवरी, 2023 को भारत सरकार और जीएफएटीएम के बीच हस्ताक्षरित 'बहु-वर्षीय योगदान समझौते' के अनुसार, भारत ने सातवें स्वैच्छिक पुनःपूर्ति चक्र (वर्ष 2023-25) के दौरान जीएफएटीएम में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जैसा कि निम्नलिखित अनुसूची में कहा गया है: (i) वर्ष 2023 और वर्ष 2024 प्रत्येक में 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर और (ii) वर्ष 2025 में 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ष 2025-26 के लिए जीएफएटीएम को भारत की 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान 18 जुलाई 2025 को किया गया था।

8.8.3 जीएफएटीएम के 8वें पुनःपूर्ति चक्र में भारत के योगदान पर निर्णय के संबंध में जून 2025 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी के साथ, भारत सरकार ने जीएफएटीएम (2026-28) के आठवें पुनःपूर्ति चक्र के लिए 30 मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई।

8.9. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)

8.9.1 बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) की स्थापना वर्ष 1988 में विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। एमआईजीए में वर्तमान में 182 सदस्य हैं। यह विशेष रूप से संघर्ष प्रभावित देशों में निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं को निवेश गारंटी प्रदान करता है। वर्तमान में, भारत में 3.03% पूंजी सदस्यता है और एमआईजीए बोर्ड में 2.53% की मतदान शक्ति है। निर्वाचन क्षेत्र के रूप में, भारत के पास कुल मतदान शक्ति का 3.41% है। एमआईजीए विकासशील देशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और साथ ही विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी और जानकारी को प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों में उनकी मदद करता है। एमआईजीए का मिशन विकासशील देशों में सीमा पार निजी निवेश जुटाकर आर्थिक विकास का समर्थन करना, गरीबी को कम करना और लोगों के जीवन में सुधार करना है। एमआईजीए गारंटी उधारकर्ताओं (सब-सॉवरेन और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों) को भारत सरकार की प्रति-क्षतिपूर्ति की आवश्यकता के बिना बेहतर वित्तपोषण नियमों और शर्तों के साथ अपने वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने में मदद करती है। एमआईजीए ने देश और व्यापक दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी भागीदारी को और बढ़ाने के लिए नवंबर 2022 में भारत में अपना प्रथम कार्यालय स्थापित किया।

8.9.2 अप्रैल 2024 में, भारत ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के लिए एसबीआई को दिए गए मौजूदा आईबीआरडी ऋण के 200 मिलियन अमरीकी डालर के पुनर्वित्त के लिए एसबीआई के साथ एमआईजीए के मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) को मंजूरी दी। एमआईजीए गारंटी भारत में रूफटॉप सौर परियोजनाओं के संचालन के पुनर्वित्त का समर्थन करेगी। इसके अतिरिक्त, 5 दिसंबर 2025 को, भारत सरकार ने ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के लिए एसबीआई को दिए गए आईबीआरडी ऋण के अतिरिक्त 163 मिलियन अमरीकी डालर के पुनर्वित्त के लिए एमआईजीए और एसबीआई के बीच साझेदारी के लिए मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्रदान किया।

8.10 एशियाई विकास बैंक

8.10.1 भारत वर्ष 1966 में सॉवरेन स्थापित एशियाई विकास बैंक का संस्थापक सदस्य है। एडीबी ने वर्ष 1986 में भारत में अपना संप्रभु संचालन शुरू किया, जो एक विकास साझेदारी को चिह्नित करता है और जो वर्ष 2026 में 40 वर्ष पूरे कर लेगी। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश सहित एडीबी के साथ भारत सरकार के सभी कार्यों के समन्वय के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

8.10.2 भारत के पास एडीबी की सब्सक्राइब्ड पूंजी का 6.32% है, जो 672,030 शेयरों के अनुरूप है, और 5.34% वोटिंग पावर का उपयोग करता है, जिससे यह संस्था में चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाता है। भारत एशियाई विकास कोष (एडीएफ) में भी योगदान देने वाला दाता है, जिसके माध्यम से एडीबी अपने विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) को सहमत मानदंडों के आधार पर रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है। भारत द्वारा किए

गए योगदान में एडीएफ 11 पुनःपूर्ति के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एडीएफ 12 के लिए 41.74 मिलियन अमेरिकी डॉलर, एडीएफ 13 के लिए 51.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर और एडीएफ 14 (वर्ष 2025-2028) के लिए 58.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता शामिल है। ये योगदान बहुपक्षीय रियायती वित्तपोषण में एक उत्तरदायी हितधारक के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करते हैं।

8.10.3 भारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रतिनिधित्व के माध्यम से एडीबी की शासन संरचना में भाग लेता है, जहां भारत के माननीय वित्त मंत्री गवर्नर के रूप में कार्य करते हैं। एडीबी के निदेशक मंडल में, भारत का प्रतिनिधित्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी निदेशक (ईडी) के माध्यम से किया जाता है, और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा समर्थित होता है, जिसमें दो सलाहकार और एक कार्यकारी सहायक शामिल हैं। आर्थिक कार्य विभाग, ईडी के माध्यम से, एडीबी के बोर्ड के समक्ष रखे गए नीतिगत दस्तावेजों, ऋण प्रस्तावों, तकनीकी सहायता और संस्थागत मामलों पर भारत की स्थिति का समन्वय करता है।

8.10.4 एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की वार्षिक बैठकें, जो प्रत्येक वर्ष मई की शुरुआत में आयोजित की जाती हैं, नीति, वित्तीय और परिचालन से संबंधित मामलों पर एडीबी के साथ भारत के मंत्रिस्तरीय जुड़ाव के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती हैं। भारत ने नई दिल्ली में 46 वीं वार्षिक बैठक (2-5 मई 2013) की मेजबानी की। माननीय वित्त मंत्री ने मिलान, इटली में 58वीं वार्षिक बैठक (4-7 मई 2025) में भाग लिया और भारत की विकास दृष्टि, आर्थिक प्रगति और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ाव पर प्रकाश डाला। भारत समरकंद, उज्बेकिस्तान में निर्धारित 59वीं वार्षिक बैठक (3-6 मई 2026) में भाग लेगा।

8.10.5 एडीबी एक प्रमुख बहुपक्षीय भागीदार है जो सॉवरेन ऋण और तकनीकी सहायता के माध्यम से भारत की विकास प्राथमिकताओं का समर्थन करता है। संचयी रूप से, एडीबी ने भारत को 330 सॉवरेन ऋणों में 63.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। चल रहे सॉवरेन पोर्टफोलियो में 18.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर के 85 ऋण शामिल हैं। हाल की वार्षिक प्रतिबद्धताओं में वर्ष 2021 में 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं, जिसमें एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी (एपीवीएक्स) के तहत 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, वर्ष 2024 में 4.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2025 में 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं। एडीबी समर्थित परियोजनाओं को कौशल विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना, मेट्रो रेल प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा गया है।

8.10.6 आर्थिक कार्य विभाग त्रिपक्षीय पोर्टफोलियो समीक्षा बैठकों (टीपीआरएम) के माध्यम से निष्पादन एजेंसियों और एडीबी के समन्वय में एडीबी पोर्टफोलियो की निरंतर निगरानी करता है। निरंतर पोर्टफोलियो निरीक्षण के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में कार्यान्वयन प्रदर्शन में सुधार हुआ है। सॉवरेन ऋण वितरण वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 3.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, इसके बाद वर्ष 2023 में 2.69 बिलियन अमेरिकी

डॉलर और वर्ष 2024 में 2.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दिसंबर 2025 के मध्य तक, सॉवरेन लोन डिस्बर्समेंट 2.42 बिलियन था।

8.10.7 भारत को एडीबी की सहायता सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और देश भागीदारी रणनीति (सीपीएस) द्वारा निर्देशित है। मई 2023 में अनुमोदित सीपीएस वर्ष 2023-2027, ज्ञान, क्षमता विकास और नवाचार के माध्यम से मूल्यवर्धन पर जोर देने के साथ जलवायु-अनुकूलन हरित विकास, संरचनात्मक परिवर्तन और रोजगार सृजन, और सामाजिक और आर्थिक समावेशन पर केंद्रित है। आर्थिक कार्य विभाग (आर्थिक कार्य विभाग) सीपीएस निर्माण, कार्यान्वयन और राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ संरेखण की देखरेख करता है।

8.10.8 भारत एडीबी द्वारा समन्वित दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएसईसी) कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाता है, जिसमें आर्थिक कार्य विभाग एसएसईसी शासन तंत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें कार्य समूह और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें शामिल हैं। दिसंबर 2025 में, भारत ने आर्थिक कार्य विभाग के माध्यम से, परिवहन, व्यापार सुविधा और ऊर्जा में एसएसईसी कार्यनीति 2035 का समर्थन किया, और अगली रोलिंग योजना (वर्ष 2026-2028) तैयार करने के अधिदेश के साथ एसएसईसी पहल (वर्ष 2025-2027) की कार्य योजना को अद्यतन करने का समर्थन किया। एसओएम के माध्यम से भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार, क्षेत्रीय बिजली कनेक्टिविटी, विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं और हरित ईंधन पर जोर देते हुए परिवहन, व्यापार सुविधा, ऊर्जा और आर्थिक गलियारों (पर्यटन और खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र सहित) में डिजिटल परिवर्तन के लिए एक मजबूत सहयोग का समर्थन किया।

8.10.9 एडीबी विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में परियोजना तैयारी वित्तपोषण (पीआरएफ) ऋणों और ज्ञान सहायता तकनीकी सहायता (केएसटीए) के माध्यम से परियोजना तैयार करने और संस्थागत सुदृढ़ीकरण का समर्थन करता है। पीआरएफ कार्यान्वयन तत्परता के उच्च स्तर के साथ बैंक योग्य परियोजनाओं की तैयारी की सुविधा प्रदान करते हैं। सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में कई पीआरएफ वर्तमान में कार्यान्वयन या प्रसंस्करण के अधीन हैं।

8.10.10 आर्थिक कार्य विभाग के सहयोग से स्थापित एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन में क्षमता विकास संसाधन केंद्र (सीडीआरसी), संरचित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से निष्पादन एजेंसियों का समर्थन करता है। वर्ष 2025 में, सीडीआरसी ने 29 क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे एडीबी के भारत पोर्टफोलियो को कवर करने वाली 95 परियोजनाओं के 1,835 अधिकारियों को लाभ हुआ, जिससे बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान मिला।

9. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध प्रभाग

9.1 आर्थिक कार्य विभाग का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध (आई ई आर) प्रभाग निम्नलिखित मंचों से संबंधित मामलों को संभालता है, जिसमें विषयवस्तु और हितधारक विभागों/मंत्रालयों के साथ समन्वय शामिल है:

- जी20 वित्त कार्यक्रम;
- ब्रिक्स;
- जी-24;
- ओईसीडी;
- जी7;
- सार्क, एसडीएफ;
- बिम्स्टेक;
- आसियान;
- डब्ल्यूईएफ;
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ);
- वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन;

आईईआर प्रभाग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) से संबंधित मामलों को भी संभालता है, जिसमें भारत में कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम या परियोजनाओं के साथ-साथ विकास के लिए वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एफएफडी) शामिल हैं।

इस प्रभाग के अंतर्गत स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) देशों, दक्षिण एशियाई देशों, दक्षिणपूर्व एशियाई देशों और मैक्सिको तथा रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का क्षेत्रीय प्रभार है।

ई-गवर्नेंस:

आईईआर प्रभाग ने ई-फाइल सिस्टम को पूरी तरह से चालू कर दिया है।

I. जी-20

एशियाई वित्तीय संकट के बाद, 1999 में जी20 का गठन वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के मंच के रूप में किया गया था। जी20 को वर्ष 2008 में तब प्रमुखता मिली जब इसे वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए जी20 राष्ट्राध्यक्षों के स्तर तक उन्नत किया गया।

पहला जी20 शिखर सम्मेलन नवंबर वर्ष 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। इसके बाद सोलह शिखर सम्मेलन लंदन (अप्रैल 2009), पिट्सबर्ग (सितंबर 2009), टोरंटो (जून 2010), सियोल (नवंबर 2010), कान्स (नवंबर 2011), लॉस कैबोस (जून 2012), सेंट पीटर्सबर्ग (सितंबर 2013), ब्रिस्बेन (नवंबर 2014), अंताल्या (नवंबर 2015), हांगजो (सितंबर 2016), हैम्बर्ग (2017), ब्यूनस आयर्स (2018), ओसाका (2019), रियाद (2020), रोम (अक्टूबर 2021) और बाली (2022) में आयोजित किए गए। भारत की अध्यक्षता में 18वां जी20 शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर,

2023 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। ब्राजील की अध्यक्षता में 19वां जी20 शिखर सम्मेलन 18-19 नवंबर, 2024 को रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, और दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 20वां जी20 शिखर सम्मेलन 22-23 नवंबर, 2025 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था।

जी20 के मुद्दों पर दो समानांतर ट्रैक, अर्थात् वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक के माध्यम से चर्चा की जाती है। जी20 का वित्त ट्रैक वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करता है। इस ट्रैक का नेतृत्व जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा किया जाता है, जिन्हें जी20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर सहायता प्रदान करते हैं। भारत में जी20 वित्त ट्रैक का नेतृत्व माननीय वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर संयुक्त रूप से करते हैं। उन्हें क्रमशः आर्थिक कार्य के सचिव (जो भारत के जी20 वित्त उप-गवर्नर हैं) और आरबीआई के उप-गवर्नर (जो भारत के जी20 केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर हैं) सहायता प्रदान करते हैं। जी20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर आमतौर पर साल में तीन से चार बार मिलते हैं। वे अंततः जी20 के नेताओं को रिपोर्ट करते हैं, जो जी20 में सर्वोच्च निर्णय लेने वाले हैं। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की प्रत्येक बैठक से पहले वित्त और केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नरों (एफसीबीडी) की बैठकें आयोजित की जाती हैं। तकनीकी स्तर की चर्चाएं कार्य समूहों की बैठकों के माध्यम से आयोजित की जाती हैं, जो आमतौर पर साल में तीन से चार बार होती हैं।

वित्त ट्रैक 8 कार्यक्षेत्र शामिल हैं। इनमें से 5 कार्यक्षेत्रों के लिए कार्य समूह और एक संयुक्त वित्त-स्वास्थ्य कार्यबल है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1. फ्रेमवर्क कार्य समूह (एफडब्ल्यूजी)
2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी)
3. अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी)
4. सतत वित्त कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी)
5. वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे
6. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई)
7. अंतर्राष्ट्रीय कराधान
8. संयुक्त वित्त एवं स्वास्थ्य कार्य बल (जेएफएचटीएफ)

जी20 वित्त ट्रैक के कार्यक्षेत्रों के जनादेश और संबंधित विवरण निम्नलिखित हैं:

1. फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडब्ल्यूजी) वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा करता है, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी करता है और जी20 देशों में मजबूत, संधारणीय, संतुलित और समावेशी विकास (एसएसबीआईजी) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों की सिफारिश करता है।

सह-अध्यक्ष: भारत वर्ष 2009 में इस समूह की स्थापना से ही

इसकी सह-अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2009 से वर्ष 2019 तक, भारत ने कनाडा के साथ मिलकर समूह की सह-अध्यक्षता की। ब्रिटेन वर्ष 2020 से इस समूह का सह-अध्यक्ष है।

2. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना (आईएफए) कार्य समूह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की स्थिरता और सामंजस्य को बढ़ाने के लिए सुधारों पर चर्चा करता है, जिसमें ऋण स्थिरता और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे; वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल (जीएफएसएन) को मजबूत करना, आईएमएफ कोटा और शासन सुधार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर); पूंजी प्रवाह प्रबंधन उपाय, विकास वित्त और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं (सीबीडीसी) शामिल हैं।

सह-अध्यक्ष: आईएफए-कार्य समूह की सह-अध्यक्षता फ्रांस और दक्षिण कोरिया करते हैं। इस समूह की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी।

3. अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) अवसंरचना के लिए वित्त जुटाने और अवसंरचना को एक आस्थि वर्ग के रूप में विकसित करने पर चर्चा करता है। यह समूह गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना निवेशों की तैयारी, वित्तपोषण और प्रबंधन में सुधार के लिए नीतियों पर विचार-विमर्श कर रहा है।

सह-अध्यक्ष: वर्तमान में, अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सह-अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील कर रहे हैं। इस समूह की स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी।

4. सतत वित्त कार्य समूह (एसएफडब्ल्यूजी) को वैश्विक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा हरित, अधिक लचीले और समावेशी समाजों और अर्थव्यवस्थाओं की ओर परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देने के लिए सतत वित्त जुटाने की दिशा में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। समूह को सतत वित्त के लिए संस्थागत और बाजार संबंधी बाधाओं की पहचान करने और ऐसी बाधाओं को दूर करने के विकल्प विकसित करने तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को वर्ष 2030 के एजेंडा और पेरिस समझौते के उद्देश्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने में योगदान देने का कार्य सौंपा गया है।

सह-अध्यक्ष: जी20 सतत वित्त अध्ययन समूह को वर्ष 2021 में एसएफडब्ल्यूजी के रूप में पुनः स्थापित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। इससे पहले, एसएफडब्ल्यूजी की सह-अध्यक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन द्वारा की जाती थी। 2025 के मध्य में, इटली ने संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान लेते हुए सह-अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।

5. वित्तीय क्षेत्र का एजेंडा वित्तीय बाजार विनियमन के कार्यान्वयन की निगरानी करने और वित्तीय स्थिरता के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न होने पर उनके समाधान खोजने पर केंद्रित है। यह कार्य वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा संचालित है, जिसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करने वाली अक्षमताओं का आकलन करने के साथ-साथ व्यापक विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में इन कमियों और उनके परिणामों से निपटने के लिए आवश्यक विनियामक, पर्यवेक्षी और संबंधित कार्यों की समयबद्ध और निरंतर समीक्षा

करने का दायित्व सौंपा गया है। एफएसबी द्वारा इस कार्य की रिपोर्ट सीधे जी20 के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों को दी जाती है। जी20 वित्त ट्रैक के अंतर्गत इस एजेंडा पर कोई कार्य समूह नहीं है।

6. वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई)
को सतत औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और उनके उपयोग को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है, जिससे वंचित और बहिष्कृत परिवारों और उद्यमों के लिए अवसरों का विस्तार हो सके। जीपीएफआई के कार्यक्षेत्र और समग्र उद्देश्यों को जी20 वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसे हर तीन साल में तैयार और स्वीकृत किया जाता है।

सह-अध्यक्ष: भारत और इटली जीपीएफआई के सह-अध्यक्ष हैं।

7. अंतर्राष्ट्रीय कराधान: वर्ष 2015 में अंताल्या शिखर सम्मेलन में, जी20 नेताओं ने आधार क्षरण (बेस ईरोजन) और लाभ अंतरण (प्रॉफिट शिफ्टिंग) को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया और ओईसीडी को आधार क्षरण और लाभ अंतरण पर समावेशी फ्रेमवर्क (बीईपीएस) नामक एक नए अंतर्राष्ट्रीय कराधान एजेंडा को विकसित और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय कराधान में आधार क्षरण और लाभ अंतरण के मुद्दों का समाधान करने; डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान; कर पारदर्शिता; कर चोरी; कर निश्चितता और अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में सुधार पर केंद्रित है। वर्तमान में, यह कार्य 141 सदस्यों वाले जी20 में ओईसीडी के बीईपीएस पर समावेशी ढांचे द्वारा संचालित है। ओईसीडी द्वारा इस कार्य की रिपोर्ट सीधे जी20 के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों को दी जाती है। इस एजेंडा पर जी20 वित्त ट्रैक के अंतर्गत कोई कार्य समूह नहीं है।

8. जी20 रोम नेताओं के शिखर सम्मेलन, 2021 के दौरान संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य कार्य बल की स्थापना की गई थी। इस कार्य बल का उद्देश्य महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) से संबंधित मुद्दों पर संवाद और वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, अनुभवों और सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, वित्त और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच समन्वय व्यवस्था विकसित करना, सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना, सीमा पार प्रभाव वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों का आकलन और समाधान करना और महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया (पीपीआर) के लिए संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करना है, साथ ही एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को अपनाना है।

सह-अध्यक्ष: इस कार्य बल की सह-अध्यक्षता इटली और इंडोनेशिया कर रहे हैं और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में स्थित सचिवालय द्वारा विश्व बैंक के समर्थन से सहायता प्रदान की जाती है।

दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता 2025

दक्षिण अफ्रीका ने 1 दिसंबर, 2024 को ब्राजील से एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता "एकजुटता, समानता और स्थिरता" विषय पर केंद्रित है और इसकी चार प्रमुख प्राथमिकताएं हैं:

- क. आपदा से निपटने की क्षमता और प्रतिक्रिया को मजबूत करना
- ख. निम्न आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता को बढ़ावा देना
- ग. न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना
- घ. समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का उपयोग करना

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 22-23 नवंबर 2025 को जी20 दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर आए माननीय प्रधानमंत्री के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में सचिव (आर्थिक कार्य) ने बैठक में भाग लिया।

बैठक का प्रमुख परिणाम "जी20 दक्षिण अफ्रीका शिखर सम्मेलन नेताओं की घोषणा" (<https://g20.org/wp-content/uploads/2025/11/2025-G20-Summit-Declaration.pdf>) है। यह घोषणा 2025 में दक्षिण अफ्रीका की जी20 अध्यक्षता के दौरान शेर्पा और वित्त दोनों क्षेत्रों में सहमत हुए मुख्य परिणामों को समाहित करती है। वित्त क्षेत्र के तत्व मुख्य रूप से जुलाई 2025 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) के विज्ञप्ति (<https://g20.org/g20-media/3rd-finance-ministers-central-bank-governors-meeting/>), अक्टूबर 2025 के एफएमसीबीजी अध्यक्ष के सारांश (<https://g20.org/g20-media/chairs-summary-4th-finance-ministers-central-bank-governors-meeting/>) और ऋण स्थिरता पर अक्टूबर 2025 की मंत्रिस्तरीय घोषणा से लिए गए हैं। (<https://g20.org/g20-media/ministerial-declaration-on-debt-sustainability-4th-finance-ministers-central-bank-governors-meeting/>)।

2026 में जी20 की अमेरिकी अध्यक्षता

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 दिसंबर, 2025 से एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की।

प्राथमिकताएं

1. जी20 की अमेरिकी अध्यक्षता वित्त संबंधी विषयों को उन प्रमुख वैश्विक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों पर पुनः केंद्रित करेगी जिनके समाधान के लिए जी20 का गठन किया गया था।
2. शेरपा और वित्त दोनों ट्रैक में तीन मुख्य विषय होंगे:
 - आर्थिक विकास: सतत और स्थायी आर्थिक विकास को गति देने और वैश्विक समृद्धि की सीमाओं का विस्तार करने के लिए उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना।
 - विनियमन में ढील: अनावश्यक बोझ को कम करने और आर्थिक गतिविधि और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना।

- ऊर्जा की प्रचुरता: वैश्विक विकास को गति देने के लिए सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले निवेश और नीतियों को बढ़ावा देना।
3. जी20 वित्त ट्रैक के अंतर्गत, वर्ष 2026 के लिए आठ प्राथमिकताएं होंगी, जो इस प्रकार हैं:
- वैश्विक विकास को बढ़ावा देना
 - वैश्विक असंतुलन
 - अंतर्राष्ट्रीय संप्रभु ऋण से जुड़ी चुनौतियों का समाधान
 - एक व्यवसायिक डिजिटल आर्स्ति व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना
 - वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए विनियमों का आधुनिकीकरण
 - सीमा पार भुगतान को बेहतर बनाना और भुगतान धोखाधड़ी से निपटना
 - वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना
 - वर्तमान परिवेश में मौद्रिक नीति

अमेरिकी अध्यक्षता में पहली जी20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों (एफसीबीडी) की बैठक 15-16 दिसंबर, वर्ष 2025 को वाशिंगटन डीसी में व्यक्तिगत रूप से आयोजित की गई थी। भारतीय वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव ने किया।

II. ब्रिक्स

- ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संघ का संक्षिप्त नाम है। वर्ष 2023 में, इस समूह में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया। ब्रिक्स समूह का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और विकासशील देशों की साझा चिंताओं, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय कराधान, जलवायु वित्तपोषण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (आईएफआई) की शासन संरचना में सुधार आदि के समाधान के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण विकसित करना है।
- विदेश मंत्रालय ब्रिक्स मामलों का नोडल मंत्रालय है। डीईए का आईईआर प्रभाग भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य प्रमुख हितधारकों के परामर्श से ब्रिक्स वित्तीय सहयोग एजेंडा पर समन्वय करता है।
- ब्रिक्स की घूर्णनशील अध्यक्षता वर्ष 2024 में रूस और वर्ष 2025 में ब्राजील के पास थी। भारत ने जनवरी 2026 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है।

ब्रिक्स वित्तीय सहयोग

वित्तीय सहयोग ब्रिक्स मंच के प्रमुख सहयोग क्षेत्रों में से एक है। ब्रिक्स वित्तीय सहयोग के अंतर्गत आने वाले मुद्दों और पहलों पर ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक कार्य करते हैं। इन मुद्दों पर ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठकों में उनके वित्त और केंद्रीय बैंक उप-गवर्नरों की सहायता से चर्चा की जाती है। सचिव (आर्थिक कार्य) भारत के ब्रिक्स वित्त उप-गवर्नर हैं और उप-गवर्नर (आरबीआई) भारत के ब्रिक्स केंद्रीय बैंक उप-गवर्नर हैं।

ब्राजील द्वारा 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता

ब्राजील ने 1 जनवरी, 2025 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की और 6-7 जुलाई, 2025 को रियो डी जनेरियो, ब्राजील में सत्रहवें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन "वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना और अधिक समावेशी एवं सतत वैश्विक शासन को बढ़ावा देना" विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें छह प्रमुख एजेंडा मदों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनमें वैश्विक स्वास्थ्य, व्यापार, निवेश और विकास वित्तपोषण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के उपाय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शासन, वैश्विक सुरक्षा संरचना में सुधार और ब्रिक्स तंत्र का संस्थागत विकास शामिल थे।

वित्त मंत्रालय के मुद्दे

1. ब्रिक्स आर्थिक दृष्टिकोण
2. अंतर्राष्ट्रीय मोद्रिक एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार
3. सीमा शुल्क एवं कर संबंधी सहयोग
4. अवसंरचना एवं निवेश
5. वित्त के लिए ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क

सेंट्रल बैंक के मुद्दे

1. आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था (सीआरए)
2. ब्रिक्स रैपिड इन्फॉर्मेशन सिन्क्रोरेटी चैनल (ब्रिक्स)
3. ट्राजिशन वित्त, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन
4. ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (बीपीटीएफ)
5. फिनटेक अनुसंधान समूह (इनोवेशन हब)
6. ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सेमिनारों के लिए मंच

वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक का संयुक्त मुद्दा

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली में सुधार

क. वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और बहुपक्षीय सहयोग

इस क्षेत्र में वैश्विक और ब्रिक्स देशों के आर्थिक रुझानों की निगरानी करने, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख जोखिमों की पहचान करने और व्यापक आर्थिक नीति समन्वय के अवसरों की खोज करने पर विशेष बल दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत, ब्रिक्स ने वर्षों से नीतिगत मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे कि संरचनात्मक सुधार, वैश्विक जोखिमों से निपटने के लिए नीति समन्वय, अधिक सशक्त, हरित और संतुलित वैश्विक विकास आदि का पहचान की है।

ख. कर संबंधी मामलों में सहयोग

कर प्राधिकरणों के ब्रिक्स प्रमुखों और कर विशेषज्ञों की वार्षिक बैठकें ब्रिक्स अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाती हैं। विशेषज्ञों की बैठक के निष्कर्ष ब्रिक्स कर प्राधिकरणों के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जो संयुक्त विज्ञप्ति में शामिल किए जाने वाले कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप देते हैं, जिस पर सभी सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। कर प्राधिकरणों के प्रमुखों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्व सचिव करते हैं। कर विशेषज्ञों के कई कार्य समूह हैं, जिनकी वर्ष के दौरान 3-4 बैठकें होती हैं। इस वर्ष के दौरान, इन कार्य समूहों के नेताओं और सह-नेताओं द्वारा सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों और वर्ष भर की गतिविधियों को कार्य समूह की एक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है, जिसे कर प्रमुखों की बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे दो कार्य समूहों की रिपोर्टें ब्राजील के मानाउस में आयोजित ब्रिक्स कर प्रमुखों और कर विशेषज्ञों की बैठक 2025 में प्रस्तुत की गईं।

ग. सीमा शुल्क सहयोग

वर्ष 2012 में ब्रिक्स देशों के बीच सीमा शुल्क सहयोग की शुरुआत हुई। वर्ष 2013 में, ब्रिक्स देशों के सीमा शुल्क प्रशासन प्रमुखों की पहली बैठक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई थी। सीमा शुल्क प्रशासन प्रमुखों की वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है, साथ ही ब्रिक्स सीमा शुल्क विशेषज्ञ बैठकों के 3-4 दौर भी होते हैं। सीमा शुल्क विशेषज्ञों के कई कार्य समूह हैं, जिनकी वर्ष के दौरान 1-2 दौर की बैठकें होती हैं।

सीबीआईसी, ब्रिक्स सीमा शुल्क ढांचे से संबंधित कार्यों के लिए ब्रिक्स मंचों में भाग लेता है, जिसमें सीमा शुल्क पारस्परिक प्रशासनिक सहायता (सीएमएए) संबंधी बहुपक्षीय समझौते के मसौदा पाठ की वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व करना शामिल है। सीमा शुल्क सहयोग के अन्य क्षेत्रों में विधि प्रवर्तन सहयोग, क्षमता निर्माण, डिजिटलीकरण और बौद्धिक विकास, प्रशासनिक सहायता और ब्रिक्स सीमा शुल्क प्रशिक्षण केंद्रों के बीच सहयोग को मजबूत करना तथा ब्रिक्स उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना शामिल है।

घ. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और अवसंरचना संबंधी कार्य बल

वर्ष 2018 में चीन और दक्षिण अफ्रीका की सह-अध्यक्षता में पीपीपी और अवसंरचना संबंधी कार्य बल (टीएफपीपीआईआई) की स्थापना हुई थी, जो पीपीपी पर ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण और परामर्श में सहयोग को प्रोत्साहित करने और प्रभावी पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया था। अपनी स्थापना के बाद से, कार्य बल ने प्रासंगिक विषयों पर तकनीकी रिपोर्ट तैयार करके और ब्रिक्स देशों में पीपीपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्रदान करके पीपीपी मामलों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। प्रत्येक ब्रिक्स कार्यकाल में आम तौर पर कार्य बल की तीन बैठकों का एक दौर शामिल होता है। इन बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त सचिव (आईएसडी), आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ड. आईएमएफ और विश्व बैंक के शासन और संसाधन संवर्धन संबंधी मुद्दों पर सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में सामान्यतः पांच वर्षों के अंतराल पर कोटा की सामान्य समीक्षा (जीआरक्यू) की जाती है। जीआरक्यू में दो मुद्दों: आईएमएफ के कोटा में कुल वृद्धि की मात्रा और सदस्यों के बीच इस वृद्धि का वितरण पर विचार किया जाता है। कोटा में किसी भी परिवर्तन को कुल मतदान के 85 प्रतिशत बहुमत से अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, और किसी सदस्य देश की सहमति के बिना उसका कोटा नहीं बदला जा सकता है। 15 दिसंबर, 2023 को 16वीं जीआरक्यू संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्य देशों के कोटा में 50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था, बशर्ते कि उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) के तहत ऋण व्यवस्था में कमी ("रोलबैक") की जाए।

ब्रिक्स लगातार सहमत समयसीमा के भीतर जीआरक्यू को पूरा करने के लिए सर्वसम्मति से आवाज़ उठाता रहा है। वर्ष 2025 में, कोटा और शासन संबंधी महत्वपूर्ण सुधार ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकों में चर्चा के एजेंडा मदों में से एक थे। सदस्यों ने दोहराया कि आईएमएफ में कोटा के पुनर्निर्धारण से विकासशील देशों की पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों की सापेक्ष स्थिति को दर्शाता हो और (ईएमडीई) की हिस्सेदारी बढ़ाता हो। वे सार्थक कोटा हिस्सेदारी पुनर्निर्धारण और शासन सुधारों को 17वें जीआरक्यू में शामिल करने हेतु अन्य आईएमएफ सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत के लिए तैयार हैं।

ब्राजील ने 6-7 जुलाई, 2025 को रियो डी जनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान आईएमएफ कोटा और शासन सुधार के लिए ब्रिक्स रियो डी जनेरियो विजन को अपनाया। आईएमएफ कोटा और शासन सुधार के लिए ब्रिक्स रियो डी जनेरियो विजन

को <https://brics.br/en/documents/economy-finance-trade-and-infrastructure> पर देखा जा सकता है।

च . न्यू डेवलपमेंट बैंक

ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) विकास बैंक की स्थापना का प्रस्ताव सर्वप्रथम भारत द्वारा मार्च 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रखा गया था और 2012 में डरबन शिखर सम्मेलन में नेताओं की घोषणा के तहत इसे स्वीकार किया गया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) पर अंतर-सरकारी समझौते और समझौते के अनुच्छेदों (एओए) पर ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं ने 15 जुलाई 2014 को फोर्टलेजा, ब्राजील में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

एनडीबी की स्थापना ब्रिक्स देशों के साथ-साथ दुनिया के अन्य ईएमडीसी में अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी। बैंक ने 2015 में परिचालन शुरू किया, जिसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है और वर्तमान में इसका नेतृत्व सुश्री दिलमा रूसेफ़ कर रही हैं। एनडीबी बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर माननीय वित्त मंत्री हैं और सचिव (आर्थिक कार्य) वैकल्पिक गवर्नर हैं। एनडीबी बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में भारत के निदेशक अपर सचिव (ओएमआई) हैं।

प्रमुख परिणाम: 31 मार्च, 2025 तक, वैश्विक स्तर पर एनडीबी द्वारा कुल 109 परियोजनाओं को 36.80 अरब डॉलर के वित्तपोषण के साथ मंजूरी दी गई है। भारत एनडीबी ऋण प्रप्तकर्ता से दूसरा सबसे बड़ा ऋणी है और कुल पोर्टफोलियो राशि का 25% हिस्सा, 28 परियोजनाओं और 9.13 बिलियन डॉलर के परिव्यय के साथ, भारत का है। मार्च 2025 तक, एनडीबी द्वारा वित्तपोषित 5.012 अरब बिलियन के ऋण राशि वाली 20 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं भारत में चल रही हैं। इन परियोजनाओं में शामिल क्षेत्र शहरी केंद्रों के लिए परिवहन अवसंरचना, एकीकृत जल संरक्षण, जल आपूर्ति और बाढ़ क्षेत्र प्रबंधन, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार आदि हैं, जो भारत की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।

छ. ब्रिक्स जलवायु वित्त

वर्ष 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान, ब्राजील ने जलवायु वित्त पर एक दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाया, जो लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस पर आधारित था। इस एजेंडा का उद्देश्य संसाधनों को जुटाने और वित्तीय प्रणालियों को सतत और समावेशी विकास के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में नेशनल ट्रांजिशन कार्यक्रमों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान शामिल था ताकि आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, अनुकूलन और लचीलेपन के लिए वित्त जुटाया जा सके, और

सतत वित्त के लिए वर्गीकरण और सत्यापन मानकों को विकसित करने के अनुभवों को साझा किया जा सके। चर्चाओं में राष्ट्रीय विकास बैंकों और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के बीच समन्वय बढ़ाने, मिश्रित वित्त तंत्रों के उपयोग को बढ़ावा देने, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत कार्बन बाजार सहयोग के संभावनाओं का पता लगाने और पर्यावरणीय आधार पर लागू किए गए एकतरफा और संरक्षणवादी उपायों के आर्थिक प्रभावों का समाधान करने पर भी जोर दिया गया।

ब्राजील ने ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में सतत और जलवायु वित्त वर्गीकरणों के बीच अंतरसंचालनीयता और कार्बन बाजार एकीकरण पहल की स्थापना पर तकनीकी चर्चाओं का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रणालियों में पारदर्शिता, तुलनीयता और सहयोग को बढ़ाना था। ब्राजील ने 6-7 जुलाई, 2025 को रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को अपनाया। लीडर्स फ्रेमवर्क डेक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस <https://brics.br/en/documents/economy-finance-trade-and-infrastructure> पर देखी जा सकती है।

ब्राजील की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत प्राप्त प्रमुख परिणाम

ब्राजील ने 5 जुलाई, 2025 को रियो डी जनेरियो में आयोजित पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया और 6-7 जुलाई, 2025 को रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान "अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ग्लोबल साउथ सहयोग को बढ़ाना" विषय पर नेताओं की घोषणा को अपनाया। संयुक्त वक्तव्य और नेताओं की घोषणा <https://brics.br/en/documents/presidency-documents> पर देखी जा सकती है।

ब्राजील की अध्यक्षता में चौथी और अंतिम ब्रिक्स एफसीबीडी बैठक 1 दिसंबर, 2025 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई थी। बैठक के एजेंडे में ब्रिक्स थिंक टैंक नेटवर्क फॉर फाइनेंस (बीटीटीटीएनएफ) पर अद्यतन जानकारी, 2025 के परिणामों सहित केंद्रीय बैंक के मुद्दे और वित्त मंत्रालय के मुद्दों पर अद्यतन जानकारी पर चर्चा करना शामिल था। इसके बाद वित्त क्षेत्र का हस्तांतरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत को 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई, जहां भारत की आगामी अध्यक्षता के लिए व्यापक प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी दी गई।

वर्ष 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा

भारत ने 'समुत्थानशीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण (ब्रीक्स)' विषय के तहत 1 जनवरी, 2026 से ब्रीक्स की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है।

III जी-24

अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों और विकास पर अंतरसरकारी चौबीस सदस्यीय समूह, जिसे ग्रुप ऑफ 24 (जी-24) भी कहा जाता है, की स्थापना 1971 में ग्रुप ऑफ 77 की एक शाखा के रूप में की गई थी। जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और विकास वित्त संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के विचारों में समन्वय स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक मामलों पर होने वाली वार्ताओं में उनके हितों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से, जी-24 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्तीय समिति (आईएमएफसी) और विकास समिति (डीसी) के एजेंडे में शामिल मुद्दों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि मूल रूप से इसका नाम संस्थापक सदस्य देशों की संख्या के आधार पर रखा गया था, लेकिन अब इसमें 28 सदस्य और चीन भी शामिल है, जो 1981 से विशेष आमंत्रित सदस्य है।

जी-24 की शासी निकाय की बैठकें वर्ष में दो बार होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्त समिति और विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की संयुक्त विकास समिति की वसंत और शरदकालीन बैठकों से पहले आयोजित की जाती हैं। जी-24 की पूर्णकालिक बैठकों को आईएमएफ और विश्व बैंक समूह के प्रमुखों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधित किया जाता है। मुद्दों पर पहले प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाती है और मंत्रिस्तरीय स्तर पर सदस्य देशों के सर्वसम्मत दृष्टिकोण को दर्शाने वाले दस्तावेज के अनुमोदन के साथ इसका समापन होता है। मंत्रिस्तरीय दस्तावेज को बैठकों के अंत में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक विज्ञप्ति के रूप में जारी किया जाता है। जी-24 के भीतर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

आईएमएफ और डब्ल्यूबीजी की वार्षिक बैठकों के दौरान, 14 अक्टूबर, 2025 को वाशिंगटन डीसी में 114वीं जी-24 मंत्रियों और राज्यपालों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का परिणाम एक विज्ञप्ति के रूप में सामने आया।

IV. ओईसीडी

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दों पर काम करता है। इसके सदस्यों में कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं और कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। सभी ओईसीडी सदस्य 1960 के ओईसीडी सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता हैं और लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

भारत और ओईसीडी के बीच सहयोग कराधान और राजकोषीय मामलों, प्रतिस्पर्धा नीति और वित्तीय शिक्षा एवं साक्षरता जैसे विविध मुद्दों को कवर करता है। ओईसीडी भारत के आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रकाशित करता है। अब तक 5 सर्वेक्षण प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से अंतिम दिसंबर 2019

में जारी किया गया था। वर्ष के दौरान, आईईआर प्रभाग ने विदेश मंत्रालय से ओईसीडी राजकोषीय नेटवर्क, आर्थिक नीति समितियों और अन्य विभिन्न ओईसीडी संदर्भों से संबंधित मामलों पर समन्वय किया।

V. जी7

आर्थिक लचीलेपन पर जी7 वित्त मंत्रियों की बैठक 8 दिसंबर, 2025 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में जी7 वित्त मंत्रियों, आईएमएफ, विश्व बैंक, वित्तीय स्थिरता बोर्ड और ओईसीडी के प्रमुखों और कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने भाग लिया। भारत के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व सचिव (आर्थिक कार्य) द्वारा किया गया।

VI. सार्क और एसडीएफ

सार्क सदस्य देशों के लिए फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट 2024-27

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून, 2024 को सार्क देशों के लिए फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट संबंधी नई व्यवस्था (2024-27) को मंजूरी दी। इस नए फ्रेमवर्क ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर पुराने ढांचे (2019-22) को प्रतिस्थापित किया। सार्क देशों के लिए फ्रेमवर्क ऑन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट 2012 से लागू है, जिसका उद्देश्य सार्क देशों को अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के लिए वित्तपोषण प्रदान करना है।

नए फ्रेमवर्क के तहत, भारतीय रुपये में निकासी को प्रोत्साहित करने और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा 2 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी डॉलर /यूरो स्वैप विंडो के अतिरिक्त, 25,000 करोड़ रुपये का एक अलग आईएनआर स्वैप विंडो शुरू किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, भूटान ने पिछले वर्ष से 15 अरब रुपये की राशि को रोलओवर किया और मई 2025 में 15 अरब रुपये की अतिरिक्त राशि का लाभ उठाया, जिसे बाद में नवंबर 2025 में रोलओवर किया गया। मालदीव ने 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को रोलओवर किया, जिसका लाभ उसने पहली बार अक्टूबर 2024 में उठाया था, फिर अप्रैल 2025 में और उसके बाद अक्टूबर 2025 में प्राप्त किया था।

सार्क विकास कोष

सार्क विकास कोष (एसडीएफ) जिसका मुख्यालय भूटान के थिम्फू में मुख्यालय स्थित है। की स्थापना और उद्घाटन 2010 में सार्क सदस्य देशों (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) द्वारा सार्क क्षेत्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और सार्क क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और गरीबी उन्मूलन को गति देने के लिए किया गया था। यह कोष सार्क परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए एक छत्र वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य परियोजना सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग और

एकीकरण में योगदान देना है। एसडीएफ द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं तीन व्यापक श्रेणियों/क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं, अर्थात् सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना। भारत में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का आईईआर प्रभाग एसडीएफ से संबंधित सभी मामलों के लिए समकक्ष एजेंसी है।

VII. बिम्सटेक

बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बे ऑफ बंगाल पहल (बीआईएमएसटीईसी), एक क्षेत्रीय संगठन, 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया। इसमें बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित सात सदस्य देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। वित्त मंत्रालय के डीईए का आईईआर प्रभाग बीआईएमएसटीईसी फोरम के तहत वित्तीय सहयोग से संबंधित मुद्दों का समन्वय करता है।

VIII. आसियान

दक्षिणपूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणापत्र (बैंकॉक घोषणापत्र) पर आसियान के संस्थापक सदस्यों - इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड - द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी।

वर्तमान में आसियान के ग्यारह सदस्य देश हैं: ब्रुनेई दारुस्सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का आईईआर प्रभाग आसियान के अंतर्गत वित्तीय सहयोग से संबंधित मामलों का समन्वय करता है।

IX. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)

वर्ष 2025 के लिए यूएनडीपी में भारत का वार्षिक योगदान 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विकासशील देशों में सबसे अधिक है। यूएनडीपी का कट्टी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट (सीपीडी) यूएनडीपी रणनीतिक योजना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा (यूएनएसडीसीएफ) द्वारा निर्देशित है। सीपीडी (2023-27) के अंतर्गत तीन कार्यक्रमगत प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं: (क) सतत विकास लक्ष्यों की त्वरित प्राप्ति के लिए सशक्त, जवाबदेह और साक्ष्य-आधारित संस्थाएं; (ख) हाशिए पर स्थित लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए असमानता को कम करने के लिए आर्थिक अवसरों और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि; (ग) जलवायु-अनुकूल समाधान, सतत पारिस्थितिकी तंत्र और संवेदनशीलता को कम करने के लिए लचीला विकास। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, दिसंबर 2025 तक, यूएनडीपी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल करते हुए 7 परियोजनाओं को आर्थिक कार्य विभाग की स्थानीय परियोजना मूल्यांकन समिति (एलपीएसी) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

X. संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस)

यूएनओपीएसपी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के अंतर्गत एक

स्वतंत्र, स्व-वित्तपोषित संस्था है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। यूएनओपीएसपी को शांति और सुरक्षा, मानवीय सहायता और विकास प्रयासों में कार्यान्वयन क्षमता बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। बुनियादी ढांचा, खरीद, परियोजना प्रबंधन, मानव संसाधन और वित्तीय प्रबंधन सेवाओं सहित अपनी परियोजना सेवाओं के माध्यम से, यूएनओपीएसपी सदस्य देशों के वैश्विक विकास लक्ष्यों और स्थानीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकारों, संयुक्त राष्ट्र और अन्य भागीदारों का समर्थन करता है। यूएनओपीएसपी परियोजनाओं को डीईए में स्थित परियोजना अनुमोदन और निगरानी समिति (पीएएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

XI. विकास के लिए वित्तपोषण (एफएफडी)

विकास वित्तपोषण जुटाने के माध्यम से 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाने के वैश्विक प्रयासों में एफएफडी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विकास वित्तपोषण पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एफएफडी3) 2015 में अदीस अबाबा में आयोजित किया गया था। विकास वित्तपोषण पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (एफएफडी4) 30 जून से 3 जुलाई, 2025 तक स्पेन में आयोजित किया गया था। एफएफडी4 की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया गया था। माननीय वित्त मंत्री ने एफएफडी4 में भाग लिया और विस्तृत का वक्तव्य दिया। परिणाम दस्तावेज, 'कॉम्प्रोमिसो डी सेविल्ला', एफएफडी4 पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। परिणाम दस्तावेज में 7 कार्य क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् - (क) घरेलू सार्वजनिक संसाधन; (ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निजी व्यवसाय और वित्त; (ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग और विकास प्रभावशीलता; (घ) विकास के इंजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार; (ङ) ऋण और ऋण स्थिरता; (च) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना और प्रणालीगत मुद्दे और (छ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण।

10. सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग (एएएडी): -

10.1.1 वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग (एए एंड एडी) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों (एमडीबी/बीए) से प्राप्त ऋणों/अनुदानों के वितरण, एमडीबी/बीए के ऋणों की डेट सर्विसिंग और बाह्य सहायता के लेखांकन के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, एएएडी सरकारी ऋणों/ऋण/अनुदानों के लिए बाह्य सहायता बजट (प्राप्तियों और भुगतानों दोनों के लिए) तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी है।

10.1.2 इसके अतिरिक्त, एएएडी ऋण अभिलेखों के रखरखाव, वार्षिक आधार पर बाह्य सहायता विवरणिका के प्रकाशन और सॉवरन बाह्य ऋण पोर्टफोलियो के वेब प्रकाशन के लिए भी उत्तरदायी है। साथ ही, एएएडी डीजीएफटी द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के प्राधिकार का लेखा परीक्षा भी करता है।

10.1.3 सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित कुछ चुनिंदा आईएसओ 9001-2000 प्रमाणित लेखा संस्थानों में से एक है।

10.2 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कार्य निष्पादन/उपलब्धियाँ (30 नवंबर, 2025 तक)

10.2.1 सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा कुल 1443 चालू/सक्रिय ऋण/खातों का प्रबंधन किया जा रहा है। इनमें से 456 ऋण/अनुदान खाते संवितरण प्रक्रिया में हैं। डेट सर्विसिंग के दृष्टिकोण से शेष ऋण चालू/सक्रिय हैं।

10.2.2 वित्त वर्ष 2025-26 (30 नवंबर, 2025 तक) के दौरान सरकारी खाते पर ऋण की बाहरी प्राप्ति ₹ 56,318 करोड़ हैं। ऋण प्राप्ति के अतिरिक्त, नकद अनुदान के रूप में ₹ 730 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

10.2.3 विगत वित्त वर्ष और 30 नवंबर, 2025 तक की अवधि के संदर्भ में चालू वर्ष में प्राप्ति और भुगतान/वापसी की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है: -

₹ करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2024-25 (31 मार्च, 2025 तक)	वर्ष 2025-26 (30 नवंबर, 2025 तक)	संशोधित अनुमान के अनुसार अनुमान (दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए)
1	प्राप्ति (ऋण और अनुदान)	109,454	57,048	55936
2	भुगतान (मूलधन और ब्याज)	89,600	62,994	38479
3	निवल अंतरण (1-2)	19,854	-5,946	17,457

10.3 आयात प्राधिकार और डीजीएफटी की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की लेखापरीक्षा

10.3.1 श्री वी.के.आर.वी. राव समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत जारी विभिन्न आयात प्राधिकारों का नमूना आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए, विदेशी मुद्रा के मुख्य लेखापरीक्षक के अधीन वर्ष 1963 में आर्थिक कार्य विभाग में एक विभागीय लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना की गई थी। समय के साथ, सहायता लेखा एवं लेखापरीक्षा प्रभाग को यह जिम्मेदारी हस्तांतरित कर दी गई।

10.3.2 एए एंड एडी द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य अग्रिम प्राधिकार धारकों द्वारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का आकलन करना और संबंधित योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।

10.3.3 एए एंड एडी देश भर के 24 शहरों में स्थित विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालयों द्वारा जारी किए गए माल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात प्राधिकारों की लेखापरीक्षा करती है।

10.3.4 समझौतों के परिणामस्वरूप, 30 नवंबर, 2025 तक विभिन्न फर्मों से ₹ 22,17,776/- की राशि वसूल की गई है।

11. प्रशासन प्रभाग

11.1 कार्य

11.1.1 प्रशासन प्रभाग कार्मिक एवं कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के

कार्यान्वयन, जन शिकायतों के निवारण, अधिकारियों के प्रशिक्षण, अभिलेख प्रतिधारण अनुसूची, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति आदि के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन प्रभाग आर्थिक कार्य विभाग में संवर्ग बाह्य पदों के लिए भर्ती नियम बनाने और ऐसे पदों पर भर्ती के लिए भी उत्तरदायी है।

11.2 कर्मचारियों की संख्या

आर्थिक कार्य विभाग और उसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/वैधानिक निकायों में कर्मचारियों की संख्या, तथा इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः अनुलग्नक I और II में दिया गया है।

11.3 महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायत समिति

आर्थिक कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का पुनर्गठन दिनांक 19.09.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-60011/1/2022-प्रशासन III के तहत किया गया था, जिसे दिनांक 18.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-60011/1/2022-प्रशासन III के तहत एक सदस्य के स्थानांतरण के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से संशोधित किया गया था।

11.4 कर्मचारियों का प्रशिक्षण

आर्थिक कार्य विभाग अपने अधिकारियों को आईएसटीएम और अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त करता है ताकि उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो और उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार हो। दिनांक

01.01.2025 से 31.12.2025 की अवधि के दौरान कुल 115 अधिकारियों को विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षणों के लिए नामित किया गया, जिनका संचालन आईएसटीएम, नई दिल्ली और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा किया गया।

11.5 लोक शिकायतों का निवारण:

सरकार में एक केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) कार्यरत है, जो विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सभी जन शिकायतों का समाधान करती है। वर्ष 2025 के दौरान, विभाग में पिछले वर्ष से लंबित 403 मामलों के अतिरिक्त 3024 नए लोक शिकायत मामले प्राप्त हुए। इन 3427 मामलों में से 3024 मामलों का निपटान वर्ष के दौरान किया गया। इसके अतिरिक्त, शिकायतों के निपटान के उपरांत 160 अपील प्राप्त हुईं, जिनमें से 135 अपीलों का निपटारा किया गया। आर्थिक कार्य विभाग में लोक शिकायतों के लिए सलाहकार (प्रशासन) नोडल अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

11.6 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) आर्थिक कार्य विभाग में एक आरटीआई अनुभाग कार्यरत है जिसका उद्देश्य आवेदकों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत उनके आरटीआई आवेदनों के उत्तर/जानकारी संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय प्राधिकरणों/लोक प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त कराना और केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति और निपटान के संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
- (ii) 2025 में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग की वेबसाइट (www.dea.gov.in) पर जानकारी अपलोड की गई थी। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के तहत यथा अपेक्षित विभाग के कार्यों और उसके पदाधिकारियों आदि का विवरण भी शामिल है।
- (iii) विभाग के अवर सचिवों/उप निदेशकों/सहायक निदेशकों/वरिष्ठ लेखा अधिकारियों/अनुभाग अधिकारियों और आर्थिक अधिकारी स्तर के अधिकारियों को अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत उनके द्वारा देखे जा रहे विषय(विषयों) के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।
- (iv) उप सचिव/संयुक्त निदेशक/निदेशक स्तर के अधिकारियों को अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में नामित किया गया है, ताकि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा दी गई जानकारी/उत्तर से

व्यथित/असंतुष्ट आवेदकों द्वारा दायर अपीलों का निपटान किया जा सके।

- (v) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की सूची समय-समय पर अद्यतन की जाती है और आम जनता की जानकारी के लिए आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। आरटीआई सेल, ए-विंग, पांचवीं मंजिल कर्तव्य भवन पर कार्यरत है। जहां आरटीआई आवेदन किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है।
- (vi) आरटीआई आवेदन www.rtiononline.gov.in ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। आरटीआई आवेदक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति और केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी/उत्तर देख सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप आरटीआई आवेदनों पर कार्रवाई में लगने वाले समय में काफी कमी आई है।
- (vii) वर्ष 2025 के दौरान, 1 जनवरी 2025 से 10 दिसंबर 2025 तक, विभाग को कुल 3096 (संख्या) आरटीआई आवेदन और 80 (संख्या) प्रथम अपील प्राप्त हुए। आरटीआई अधिनियम के तहत आरटीआई शुल्क और दस्तावेज शुल्क के रूप में 2130/- रुपये (दो हजार एक सौ तीस रुपये मात्र) की राशि प्राप्त हुई।

11.7 सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग

वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जा रही है।

संसद में सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963; राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा जारी अन्य सभी निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, विभाग में आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभाग में राजभाषा से संबंधित की गई गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

(i) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आर्थिक कार्य विभाग में सितंबर 2025 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा" का आयोजन किया गया। 14 सितंबर 2025 को "हिंदी दिवस" के अवसर पर संदेश जारी करते हुए माननीय वित्त राज्य मंत्री ने वित्त मंत्रालय और उसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे सरकारी कार्य हिंदी में करें। विभाग में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ii) **राजभाषा निरीक्षण**

अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण: राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, आर्थिक कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 के दौरान आठ अधीनस्थ कार्यालयों, अर्थात् बैंक नोट प्रेस, देवास; सिक्योरिटी पेपर मिल, नर्मदापुरम; भारत सरकार टकसाल, कोलकाता; भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कोलकाता; सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद; भारत सरकार टकसाल, हैदराबाद; भारत सरकार टकसाल, मुंबई और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई का निरीक्षण किया गया और राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग की स्थिति की समीक्षा की गई।

(iii) **तिमाही प्रगति रिपोर्ट का प्रेषण**

विभाग के सभी अनुभागों/प्रभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई। आर्थिक कार्य विभाग का हिंदी पत्राचार लगभग 55.37% रहा। समेकित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेज दी गई।

(iv) **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें**

विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए, वर्ष 2025-26 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विभिन्न अनुभागों और प्रभागों के प्रमुखों ने भाग लिया।

(v) **वार्षिक कार्यक्रम का परिचालन**

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम को मंत्रालय के सभी प्रभागों/अनुभागों सहित अधीनस्थ कार्यालयों को परिचालित किया गया था और इसका ऑनलाइन लिंक मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी के लिए ई-ऑफिस के डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया गया ताकि राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

(vi) **हिन्दी कार्यशाला**

विभाग में दिनांक 26.06.2025 को "तकनीकी सहायता के साथ सरकारी कार्यों के लिए हिंदी में काम को बढ़ावा देने हेतु ई-टूल्स का उपयोग" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए।

(vii) **अनुवाद कार्य**

केंद्र की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अतिरिक्त, आर्थिक कार्य विभाग के हिंदी अनुभाग में अनुवाद से संबंधित व्यापक कार्य किया गया। इस व्यापक कार्य में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल थे। वर्ष 2025-26 के दौरान हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके तहत बनाए गए

नियमों में विनिर्दिष्ट सरकारी दस्तावेजों का अनुवाद भी सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इनमें सभी बजट संबंधी दस्तावेज, वार्षिक रिपोर्ट, विदेश सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समझौते, मंत्रिमंडल नोट, संसदीय प्रश्न-उत्तर/आश्वासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति संबंधी कार्य, की गई कार्रवाई रिपोर्ट, मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए मासिक सारांश, सरकारी पत्र और विदेशी वित्तपोषण रिपोर्ट शामिल हैं। इन सभी कार्यों में अनुवाद, टाइपिंग, जांच और प्रूफरीडिंग शामिल हैं।

(viii) **हिंदी सलाहकार समिति**

दिनांक 10.12.2025 को माननीय राज्य मंत्री (वित्त) श्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

11.8 वित्त पुस्तकालय एवं प्रकाशन अनुभाग

11.8.1 वित्त पुस्तकालय एवं प्रकाशन अनुभाग की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय के केंद्रीय अनुसंधान एवं संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है और वित्त मंत्रालय के सभी विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत एवं विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

11.8.2 यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है, जो भारत एवं विदेश में मांग के अनुसार विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों के साथ आधिकारिक दस्तावेजों को प्रापण एवं वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

11.8.3 दिनांक 2 अप्रैल, 1959 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1 (1) — एलवाई/59 के तहत एक प्रकाशन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था, जिसे बाद में पुस्तकालय में एकीकृत कर वित्त पुस्तकालय एवं प्रकाशन अनुभाग बनाया गया।

व्यय विभाग के दिनांक 24.07.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19(1)/आईसी/85 के आधार पर वित्त पुस्तकालय को श्रेणी III पुस्तकालय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पुस्तकालय के सभी पद संवर्ग बाह्य पद हैं।

(i) **संग्रह**

वित्त पुस्तकालय में आर्थिक और वित्तीय मामलों संबंधी लगभग दो लाख दस्तावेजों का विशेष संग्रह है और यह सालाना 800 से अधिक पत्रिकाओं/अखबारों की सदस्यता लेता है तथा एग्रीवॉच, सीएमआईई, जस मुंडी, ब्लूमबर्ग, ग्रामरली जैसे डेटाबेस तक एक्सेस रखता है और जेएसटीओआर के माध्यम से ई-पत्रिकाओं और बैक-फाइल्ड संग्रह तक एक्सेस भी उपलब्ध है।

(ii) सेवाएँ

वित्त पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पुस्तकें उधार देना, अंतर-पुस्तकालय ऋण, परामर्श, प्रतिलिपि प्रस्तुत करना, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का वितरण, संदर्भ सेवा, "साप्ताहिक बुलेटिन" के माध्यम से समसामयिक जानकारी सेवा, साथ ही ईमेल के माध्यम से सेवाएं और ई-गवर्नेंस सेवाएं।

वित्त पुस्तकालय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशनों का वितरण राज्य सरकारों, विदेशी सरकारों और भारत एवं विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों को भी करता है। पुस्तकालय द्वारा इंटरनेट पर उपयोगी लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो पाठकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और आंकड़ों के पूर्ण पाठ को खोजने और डाउनलोड करने में सहायता करते हैं।

(iii) प्रकाशन

वित्त पुस्तकालय दो (मुद्रित + ऑनलाइन) प्रकाशन प्रकाशित करता है, अर्थात् "साप्ताहिक बुलेटिन" और "समसामयिक जानकारी विषयवस्तु"।

(iv) डिजिटल रिकॉर्ड

आर्थिक एवं वित्त विषय से संबंधित भारतीय आधिकारिक दस्तावेज (स्वतंत्रता के बाद से केंद्र एवं राज्य स्तर पर) और वित्त मंत्रालय के राजपत्र में भाग 2 खंड 3 उपखंड (i) (साधारण) में वर्ष 1955 से 1990 तक प्रकाशित अधिसूचनाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। अब तक लगभग 2 टेराबाइट डेटा का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और यह डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है।

(v) कम्प्यूटरीकरण

पुस्तकालय डेटाबेस प्रबंधन, डेटा पुनर्प्राप्ति, पुस्तकालय स्वचालन और अन्य आंतरिक कार्यों के लिए एलआईबीएसवाईएस और केओएचए लाइब्रेरी पैकेज का उपयोग करता है। पुस्तकालय में इंटरनेट सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सूचना प्रदान की जाती है।

(vi) अन्य कार्य

- पुस्तकालय द्वारा आधुनिकीकरण और अवसंरचना सुधार का कार्य किया गया।
- आर्थिक कार्य विभाग के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की प्रतिपूर्ति का कार्य भी वित्त पुस्तकालय द्वारा किया जाता है।
- यह पुस्तकालय विशेष रूप से मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है; भारत और विदेश में मांग के अनुसार विभिन्न संस्थानों/व्यक्तियों के साथ आधिकारिक दस्तावेजों का प्रापण और वितरण में समन्वय करता है।

12. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग**12.1 द्विपक्षीय सहयोग एवं सतत वित्त प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:**

क. **द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति:** सभी जी-8 देशों, नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ तथा यूरोपीय संघ और दक्षिण कोरिया गणराज्य से द्विपक्षीय विकास सहायता और इससे संबंधित नीति।

ख. **रणनीतिक विदेशी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट और रियायती वित्त के माध्यम से भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के अंतर्गत भागीदार देशों को भारत सरकार द्वारा रियायती ऋण दिया जाना।**

ग. **आर्थिक नीतिगत संवाद और मंच:** बीसी प्रभाग निम्नलिखित वार्ताओं/बैठकों से संबंधित कार्य करता है-

- भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता
- भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी
- आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर भारत-फ्रांस द्विपक्षीय वार्ता
- भारत-कोरियाई वित्त मंत्रियों की बैठक
- आर्थिक मुद्दों पर भारत-जापान रणनीतिक वार्ता,
- भारत-जापान वित्तीय वार्ता
- भारत-स्विट्जरलैंड वित्तीय वार्ता
- भारत-यूरोपीय संघ मैक्रो-इकोनॉमिक वार्ता
- भारत-चीन वित्तीय वार्ता
- भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक नीति वार्ता
- भारत-न्यूजीलैंड आर्थिक नीति वार्ता
- भारत-जर्मन वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक
- भारत-कोरिया कार्य समूह की बैठक

घ. **विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम:** यह प्रभाग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित चार सप्ताह तक की अवधि के सभी अल्पकालिक विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के प्रबंधन का प्रमुख केंद्र बिंदु है।

क. द्विपक्षीय सरकारी विकास सहायता नीति:

12.2 भारत केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर अवसंरचना, सामाजिक

क्षेत्र के विकास और भारतीय नागरिकों के ज्ञान/कौशल को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय साझीदारों से ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में बाह्य वित्तपोषण प्राप्त करता रहा है। इस विभाग द्वारा वर्ष 2005 में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, द्विपक्षीय विकास सहायता तत्कालीन जी-8 देशों अर्थात् यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी संघ के साथ-साथ यूरोपीय आयोग से प्राप्त की जा सकती है। जी-8 के बाहर के यूरोपीय संघ के देश भी भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते वे न्यूनतम 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की वार्षिक विकास सहायता देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करें। द्विपक्षीय साझीदारों के साथ विकास सहयोग के लिए सरकारी विकास सहायता संबंधी दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट दिसंबर, 2015 में जारी किया गया था। संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद, दक्षिण कोरिया गणराज्य को उनसे सरकारी विकास सहायता प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय साझीदार देश के रूप में मान्यता दी गई है।

12.3. जापान के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.3.1 जापान-सरकारी विकास सहायता:

12.3.1.1 जापान वर्ष 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता रहा है। भारत को ऋण सहायता, अनुदान सहायता और तकनीकी सहायता के रूप में जापानी ओडीए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के माध्यम से प्राप्त होता है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय डोनर है।

12.3.1.2 दिनांक 30 नवंबर, 2025 तक, 66 ओडीए ऋण परियोजनाएं जापानी सहायता से कार्यान्वयन के अधीन हैं। इन परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध ऋण राशि 3648.96 बिलियन येन (लगभग 2,21,347.73 करोड़ रुपये) है। भारत के लिए ओडीए ऋण की संचयी प्रतिबद्धता 30 नवंबर, 2025 तक प्रतिबद्धता के आधार पर 8.4 ट्रिलियन जापानी येन तक पहुंच गई है।

12.3.1.3 दिनांक 1 जनवरी, 2025 से दिनांक 30 नवंबर, 2025 तक भारत को ओडीए ऋण संवितरण 274.43 बिलियन जापानी येन (लगभग 16175.10 करोड़ रुपये) था।

12.3.2 सहायता-अनुदान

12.3.2.1 जापान सरकार निम्नलिखित क्षेत्रों और मानदंडों के तहत भारत को सहायता-अनुदान प्रदान करती है:

i) मानदंड:

क) विकास पर प्रभाव;

ख) जापानी प्रौद्योगिकी/ज्ञान का उपयोग और अन्य क्षेत्रों में इसके प्रसार की संभावना।

ii) क्षेत्र:

क) परिवहन क्षेत्र, जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करने वाली परियोजनाएं और ढलान (स्लोप) सुरक्षा उपायों वाली सड़क परियोजनाएं शामिल हैं

(संभावित संबंधित मंत्रालयों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय आदि शामिल हो सकते हैं।)

ख) विद्युत क्षेत्र, जिसमें लघु स्तर की जल विद्युत परियोजनाएं और सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं (संभावित संबंधित मंत्रालयों में विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि शामिल हो सकते हैं)

12.3.2.2 सहायता अनुदान की चार (4) परियोजनाएं चल रही हैं। (क) कोर बेंगलुरु में उन्नत सूचना और प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए परियोजना (ख) आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम (चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था) (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विद्युत आपूर्ति में सुधार और (घ) मानव संसाधन विकास छात्रवृत्ति (जेडीएस)।

12.3.3 तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

12.3.3.1 तकनीकी सहयोग का उद्देश्य मानव संसाधनों के विकास और सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और ज्ञान का अंतरण करना है और इस प्रकार इससे भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान प्राप्त होता है। तकनीकी सहयोग में बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से लेकर कृषि और औद्योगिक विकास तक के व्यापक क्षेत्र शामिल हैं।

12.3.3.2 तकनीकी सहयोग के मुख्य घटक हैं (i) तकनीकी सहयोग परियोजनाएं, (ii) विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सहयोग, (iii) प्रशिक्षण द्वारा तकनीकी सहयोग, (iv) विकासात्मक नियोजन द्वारा तकनीकी सहयोग।

12.3.3.3 तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के तहत 19 परियोजनाएं चल रही हैं।

12.3.4 जे ओ सी वी कार्यक्रम

12.3.4.1 जे आई सी आई के स्वयंसेवी कार्यक्रम जैसे कि जापान ओवरसीज कोऑपरेशन वालंटियर (जेओसीवी) ऐसे जापानी नागरिकों द्वारा व्यापक स्थानीय कार्यालयों में सहायता प्रदान करते हैं जो उभरते देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास तथा पुनर्निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। इन सहयोगात्मक कार्यक्रमों के जरिए, प्रतिभागी स्वयंसेवक न केवल भागीदार देशों के विकास में योगदान दे सकते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, पारस्परिक समझ तथा उनके अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणों विस्तार के संदर्भ में मूल्यवान अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं।

12.3.4.2 दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 30 नवंबर, 2025 के दौरान जापान के दूतावास को 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और 03 स्वयंसेवकों को अनापत्ति जारी की गई।

12.3.5 जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम

12.3.5.1 अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गैर-सरकारी संगठनों के बढ़ते महत्व को स्वीकार करते हुए, वर्ष 2002 में जेआईसीए भागीदारी कार्यक्रम (जेपीपी) की शुरुआत की गई थी। जेपीपी एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम है, जिसे जापान स्थित गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, स्थानीय सरकारों और सार्वजनिक

हितकारी निगमों जैसे भागीदारों के सहयोग से विकासशील देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में जमीनी स्तर पर योगदान देने के लिए जेआईसीए द्वारा कार्यान्वित किया गया है। जेपीपी के लिए आवेदन करते समय, योजना में भाग लेने के लिए भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को एक जापानी भागीदार की तलाश करने की सलाह दी जाती है। इसके दो घटक हैं:

- जेआईसीए के माध्यम से जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार भारतीय संगठन को एफसीआरए मार्ग से जापानी विशेषज्ञ कर्मियों, उपकरण की व्यवस्था और वित्तीय सहायता के साथ समर्थन करेगी;
- जापानी एनजीओ/संस्था/स्थानीय सरकार जेआईसीए के माध्यम से जापान में भारतीय कर्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

12.3.6 जमीनी स्तर पर वित्त पोषण

12.3.6.1 जापान सरकार आर्थिक कार्य विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने पर एफसीआरए मार्ग से अपने जमीनी स्तर के वित्त पोषण कार्यक्रम के तहत भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को छोटे स्तर पर सहायता भी प्रदान करती है।

12.3.7 हरित अनुदान योजना

12.3.7.1 जापान सरकार (अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय), एमईटीआई के एक संगठन, न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन(एनईडीओ) जैसी एजेंसियों के माध्यम से हरित अनुदान योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता प्रदान करती है। सहयोग के क्षेत्र हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, अपशिष्ट का प्रशोधन एवं पुनर्चक्रण तथा ऊर्जा का संरक्षण और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। मॉडल योजनाएं नीडो द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, जो कि संबद्ध लाइन मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसी है, के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर संचालित की जाती हैं।

12.4. जर्मनी के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.4.1 जर्मनी अपने आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के माध्यम से 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 2008 में, जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय (बीएमयूबी) ने जर्मन सरकार की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संरक्षण पहल (आईकेआई) के तहत भी सहायता शुरू की, जो जर्मनी सरकार के सरकारी विकास सहायता के मौजूदा स्रोतों से अलग और सरकारी विकास सहायता के मौजूदा स्रोतों को प्रभावित किए बिना एक अतिरिक्त सहायता साधन है। सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऊर्जा, सतत शहरी विकास के साथ-साथ पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

12.4.2 जर्मनी अपने वित्तीय सहायता कार्यक्रमों को जर्मन सरकार के विकास बैंक (केएफडब्लू) के माध्यम से कार्यान्वित करता है। तकनीकी सहायता कार्यक्रम जीआईजेड (पूर्ववर्ती जीटीजेड) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं, जो जर्मन सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला निगम है। वित्तीय

सहायता कम ब्याज दर वाले ऋण (ईयूआरआईबीओआर- आधारित ऋण) के साथ-साथ वित्तपोषण अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तकनीकी सहायता, परियोजना विशेषज्ञों द्वारा अनुदान और सेवाओं के रूप में प्रदान की जाती है।

12.4.3 मई, 2022 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर श्री ओलाफ स्कॉलज़ परसुआंत ने हरित और सतत विकास (जीएसडीपी) पर संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए। जीएसडीपी के तहत, जर्मनी ने भारत के जलवायु और सतत विकास लक्ष्यों में सहायता प्रदान करने के लिए 2030 तक 10 बिलियन यूरो की नई और अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं जताई हैं। तदनुसार, जर्मनी ने अब तक 4.889 बिलियन यूरो की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जिसमें दिसंबर 2025 में आयोजित भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ता बैठक के दौरान प्रतिबद्ध 1.242 बिलियन यूरो भी शामिल हैं।

12.4.4. द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत दो वार्षिक बैठकें अर्थात् भारत-जर्मनी वार्षिक परामर्श और भारत-जर्मनी वार्षिक वार्ताएं सामान्यतः क्रमशः वर्ष की दूसरी तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान आयोजित की जाती हैं। वार्षिक परामर्श में नीतिगत मुद्दों के अलावा, चालू परियोजनाओं और नई परियोजनाओं पर चर्चा की जाती है और चालू परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। वार्षिक वार्ताओं में, जर्मनी सरकार नई परियोजनाओं के साथ-साथ चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियन के लिए निधियों की वचनबद्धता करती है। औसतन जर्मनी 1 बिलियन यूरो की वार्षिक प्रतिबद्धता करता है। भारत-जर्मन वार्षिक वार्ता बैठक 2025 दिनांक 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। वर्ष 2025 में तकनीकी और वित्तीय सहयोग परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए जर्मन पक्ष द्वारा प्रतिबद्ध धन की मात्रा 1,242.05 मिलियन यूरो है।

12.4.5 वर्तमान में, जर्मनी से कुल 6.47 बिलियन यूरो की मुद्रा में केएफडब्ल्यू से बाह्य वित्तपोषण/ऋण प्राप्त करने वाली 47 चालू परियोजनाएं हैं। 2025 तक द्विपक्षीय तकनीकी और वित्तीय सहयोग के लिए जर्मनी द्वारा की गई प्रतिबद्धता की संचयी मात्रा 26.62 बिलियन यूरो है।

12.5. एफडी, फ्रांस के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.5.1 फ्रांस सरकार 1968 से भारत को विकास सहायता प्रदान कर रही है।

12.5.2 वर्ष 2006 में फ्रांस सरकार ने विकास के लिए फ्रांसीसी एजेंसी (एफडी) के माध्यम से भारत को अबद्ध विकास सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया था। इस संबंध में, फ्रांस के राष्ट्रपति श्री निकोलस सरकोजी की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान 25-01-2008 को दोनों सरकारों के बीच एक अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

12.5.3 एफडी को भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप एक रणनीतिक जनादेश सौंपा गया है। इसे सहयोग के लिए तीन मुख्य फोकस के माध्यम से लागू किया जाता है: सतत और एकीकृत शहरी विकास को बढ़ावा देना; ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा विकास को प्रोत्साहित करना; देश की जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें।

12.5.4 2008 के बाद से, एफडी द्वारा कुल शुद्ध संचयी वित्तपोषण 3.3 बिलियन यूरो है। यह वित्तपोषण ओडीए-अनुपालन ऋणों के माध्यम से संप्रभु और गैर-संप्रभु आधार पर प्रदान किया गया था। औसतन एफडी 250 मिलियन यूरो की वार्षिक प्रतिबद्धता करता है। चल रहे सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं:

- i. सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में सहयोग;
- ii. स्मार्ट सिटी मिशन;

जल, पर्यावरण और जैव विविधता क्षेत्र।

12.5.5 वर्तमान में, एफडी से वित्तीय सहायता के साथ 1.6 बिलियन यूरो के 21 ऋण चल रहे हैं।

12.5.6 फ्रांस सरकार एफएसईपी सुविधा योजना के रूप में तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। एफएसईपी सुविधा का प्रबंधन फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, वित्त और उद्योग मंत्रालय के ट्रेजरी और आर्थिक नीति महानिदेशालय द्वारा किया जाता है। इस सुविधा के तहत, अवसंरचना परियोजनाओं (जल, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट, पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा) के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के वित्तपोषण के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।

12.6. भारत और यूरोपीय संघ के बीच विकास सहयोग

12.6.1 यूरोपीय संघ (ईयू) भारत को अनुदान के रूप में विकास सहायता प्रदान करता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं। 2014 से, यूरोपीय संघ (ईयू) से विकास सहायता के वित्तीय घटक को बंद कर दिया गया था, तथापि तकनीकी सहयोग और सर्वोत्तम पद्धतियों का आदान-प्रदान तीन पंक्तियों में सक्रिय रहता है (i) पारस्परिक हित के क्षेत्रों में (ii) नागरिक समाज संगठनों के साथ सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित क्षेत्रों में और (iii) वैश्विक चुनौतियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान करना।

12.6.2 यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) द्वारा भारत में विदेशी वित्तपोषण

12.6.2.1 यूरोपीय निवेश बैंक यूरोपीय संघ की वित्तपोषण संस्था है जिसे पूंजी निवेश के लिए वित्तपोषण प्रदान करने हेतु रोम की संधि (1957) के तहत वर्ष 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी के सदस्य यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य हैं, जिन्होंने सभी बैंक की पूंजी की सदस्यता ली है। यूरोपीय संघ के बाहर, ईआईबी वित्तपोषण संचालन मुख्य रूप से बैंक के अपने संसाधन से संचालित किया जाता है, लेकिन अधिदेश के तहत, संघ या सदस्य राज्यों के बजटीय संसाधनों से भी संचालित किया जाता है। इन व्यवस्थाओं के तहत, ईआईबी के धन का उपयोग यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में निवेश के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।

12.6.2.2 भारत में ईआईबी की गतिविधियां यूरोपीय संघ और भारत के बीच सामरिक भागीदारी की संयुक्त कार्य योजना (जेएपी) द्वारा संचालित होती हैं। ईआईबी का उद्देश्य एफडीआई, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जानकारी के

माध्यम से मुख्य रूप से पर्यावरणीय स्थिरता और बड़ी अवसंरचना परियोजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ऋण गतिविधियों को बढ़ाना है। भारत में ईआईबी निवेश वित्तीय सहयोग के लिए फ्रेमवर्क समझौते द्वारा शासित होता है। इस समझौते पर भारत और ईआईबी के बीच 25 नवंबर 1993 को ब्रसेल्स में भारत की ओर से मामलों के प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेमवर्क समझौता शुरू में तीन साल की अवधि के लिए वैध था और बाद में इसे 24 नवंबर 1998 के संशोधन के तहत अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया था।

12.6.2.3 वर्ष के दौरान, निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए आर्थिक कार्य विभाग और ईआईबी के बीच तीन वित्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- क. उत्तराखंड जल और स्वच्छता (191 मिलियन अमरीकी डालर) पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए
- ख. पुणे मेट्रो रेल परियोजना ई (49.5 मिलियन यूरो) पर अगस्त 2025 में हस्ताक्षर किए गए
- ग. पुणे मेट्रो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन (235 मिलियन यूरो) पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए

12.7. संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग:

12.7.2 संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार और विकास एजेंसी (यूएसटीडीए)

12.7.2.1 यूएसटीडीए मेजबान देशों में प्राथमिकता विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में अमेरिकी व्यवसायों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, यूएसटीडीए हिसार में एकीकृत विमानन हब की मास्टर योजना में आगे के विकास के लिए एक परियोजना के लिए 1.25 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग) के तकनीकी सहयोग/सहायता का समर्थन कर रहा है।

12.7.3 अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी)

12.7.3.1 भारत को कनाडा की द्विपक्षीय विकास सहायता आईडीआरसी के माध्यम से प्राप्त की जाती है - जो कनाडा की संसद द्वारा बनाई और वित्त पोषित इकाई है। आईडीआरसी विकासशील देशों में विकास को बढ़ावा देने, गरीबी कम करने और बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अनुसंधान गतिविधियों में सहायता करता है। भारत में, आईडीआरसी कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है।

12.8. यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.8.1 यूनाइटेड किंगडम (यूके) वर्ष 1958 से भारत को विकास सहायता प्रदान कर रहा है। यूके से मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार,

स्लम विकास आदि के क्षेत्रों में सहस्रवर्षीय विकास लक्ष्य (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए विकास सहायता प्राप्त हुई थी।

12.8.2 यूके से सहायता, इसके विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ), पूर्ववर्ती अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के माध्यम से, निवेश और तकनीकी सहायता के रूप में पारस्परिक रूप से सहमत सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों को प्रदान करती है। एफसीडीओ विश्व बैंक, एडीबी और यूनिसेफ नामक बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ-साथ सिविल सोसाइटी कार्यक्रमों के माध्यम से भी सहायता प्रदान करता है। यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग के तहत पहल में वर्ष 2018 में एफसीडीओ, यूके के सहयोग से राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) द्वारा भारत में हरित निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त निवेश ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (जीजीईएफ) लॉन्च करना शामिल है। एफसीडीओ, यूके भारत में जलवायु के अनुकूल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई के सहयोग से संयुक्त निवेश कार्यक्रम भी लागू कर रहा है।

12.9. कोरिया गणराज्य के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग

12.9.1 18-19 मई, 2015 के दौरान प्रधान मंत्री की कोरिया गणराज्य (आरओके) की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित विशेष भागीदारी के लिए संयुक्त वक्तव्य में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अपग्रेड करने और इसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तारित करने पर सहमति हुई थी। तदनुसार, अक्टूबर, 2016 के दौरान कोरिया गणराज्य को विकास सहयोग के लिए द्विपक्षीय भागीदार के रूप में स्वीकार किया गया। सियोल में 14 जून, 2017 को आयोजित 5वीं भारत-कोरिया वित्त मंत्रियों की बैठक में, भारत को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) के लिए दोनों सरकारों के बीच एक आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ) करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

12.9.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत सरकार और कोरिया गणराज्य की सरकार के बीच 20 जनवरी 2025 को "भारत में मेक्ट्रोनिक्स में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करना" नामक परियोजना प्रस्ताव के लिए तकनीकी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ख. भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के तहत भारत सरकार द्वारा रियायती ऋण दिया गया।

12.10.1 ऋण सहायता (एलओसी) भारत की राजनयिक कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है और सद्भावना पैदा करने और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने में बहुत उपयोगी रही है। भारत सरकार ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के माध्यम से विकासशील अफ्रीकी और गैर-अफ्रीकी देशों को ऋण प्रदान किया। मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) को नया रूप दिया गया है और यह 31 मार्च, 2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखा गया है।

12.10.2 एलओसी का संचालन भारतीय निर्यात-आयात बैंक के माध्यम से किया जा रहा है, जो बाजार से संसाधन जुटाता है और प्राप्तकर्ता सरकार

को रियायती दरों पर एलओसी प्रदान करता है। भारत सरकार ऋण देने वाले बैंक को ब्याज और मूलधन के भुगतान में उधार लेने वाली सरकार द्वारा किसी भी चूक से बचाने के लिए ऋण देने वाले बैंक के पक्ष में गारंटी विलेख के माध्यम से एलओसी का समर्थन करती है। भारत सरकार ऋण देने वाले बैंक को रियायती शर्तों पर ऋण देने में सक्षम बनाने के लिए ब्याज समानीकरण सहायता (आईईएस) भी प्रदान करती है।

12.10.3 31 दिसंबर, 2025 तक, 26,119.11 मिलियन अमरीकी डालर और 4,850 करोड़ रुपये की राशि के लिए 62 देशों में 293 एलओसी बढ़ाए गए हैं।

ग. आर्थिक संवाद और मंच

12.11. वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्नलिखित संवाद/बैठकें आयोजित की गईं:

12.11.1 भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय भागीदारी (ईएफपी)

12.11.1.1 दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2010 से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ईएफपी मंत्रिस्तरीय बैठकों का एक तंत्र मौजूद है। अब तक दोनों पक्षों के बीच 9 मंत्रिस्तरीय ईएफपी बैठकें हो चुकी हैं। 9वीं ईएफपी बैठक के तहत विचार-विमर्श के अनुवर्ती कार्यवाई के रूप में, 9वीं भारत-यूएस ईएफपी से अपडेट का आदान-प्रदान करने और विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए तीन उप-मंत्रालयी स्तर की बैठकें आयोजित की गई हैं।

12.11.2 भारत-यूरोपीय संघ वृहद आर्थिक वार्ता

12.11.2.1 12वीं भारत-यूरोपीय संघ वृहद आर्थिक वार्ता 20.02.2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली आयोजित की गई थी। दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रों के विषयों पर चर्चा की, जिसमें वृहद अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, हरित और डिजिटल परिवर्तन और जी20 अध्यक्षता के लिए प्राथमिकताएं शामिल थीं। विचार-विमर्श से प्रमुख राजकोषीय और संरचित सुधारों और भारत-यूरोपीय संघ के वृहद आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर अंतर्दृष्टि के समृद्ध आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।

12.11.3 भारत-स्विट्जरलैंड वित्तीय वार्ता

12.11.3.1 5वीं भारत-स्विट्जरलैंड वित्तीय वार्ता 20 मार्च 2024 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ ने किया और स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय वित्त की राज्य सचिव सुश्री डेनिएला स्टॉफेल ने किया। इस संवाद में निवेश, अवसंरचना के वित्तपोषण, डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सहयोग और नवाचार जैसे पारस्परिक हित के क्षेत्रों में चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान और भारतीय और स्विस् अर्थव्यवस्थाओं के लिए आशाजनक अवसरों की खोज की गई। इस संवाद में सेबी, आरबीआई और आईएफएससीए जैसे विनियामकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

12.11.4 भारत-यूके वार्ता

12.11.4.1 भारत-यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता

12.11.4.1.1 भारत-यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता (13वीं ईएफडी) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 9 अप्रैल 2025 को लंदन में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया और यूके के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजकोष की चांसलर माननीय रेचल रीव्स ने किया। इस संवाद में भारत की ओर से आरबीआई, सेबी और आईएफएससीए और यूके की ओर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और एफसीए सहित दोनों पक्षों के वित्तीय विनियामकों ने भी भाग लिया।

दोनों पक्षों ने वित्तीय सेवा क्षेत्र, फिनटेक और डिजिटल अर्थव्यवस्था और संबंधित विनियामक निकायों के बीच सहयोग जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की; कम कार्बन आर्थिक विकास, कराधान मामलों और अवैध वित्तीय प्रवाह के लिए किफायती वित्त और निवेश जुटाने सहित पारस्परिक और वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के चांसलर ऑफ एक्सचेंजर द्वारा वार्ता के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया गया।

12.11.4.2 भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद

12.11.4.2.1 भारत-यूके वित्तीय बाजार संवाद की तीसरी बैठक 12 दिसंबर 2024 को गुजरात के गिफ्ट सिटी में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा हाइड्रिड मोड में आयोजित की गई। भारत और यूके दोनों के प्रतिभागियों ने पूंजी बाजार, बीमा और पुनर्बीमा, पेंशन, फिनटेक, सतत वित्त और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सहित संबंधित वित्तीय सेवा क्षेत्रों में सुधारों पर चर्चा की। द्विपक्षीय व्यापार और वित्तीय सेवाओं में निवेश बढ़ाने के लिए अंतर-विनियामक सहयोग और निजी क्षेत्र के सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा की गई। चौथा एफएमडी अगले वसंत, 2026 में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

12.11.5 भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक नीति वार्ता

12.11.5.1 भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक नीति वार्ता का 10वां दौर 14 अगस्त 2025 को वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी सह-अध्यक्षता सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और श्री जस्टिन बागुले, कार्यवाहक प्रथम सहायक सचिव, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और सुरक्षा प्रभाग, ऑस्ट्रेलियाई ट्रेजरी की सह-अध्यक्षता में किया गया। प्रतिभागियों ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक दृष्टिकोण, अवसंरचना, निवेश प्रवाह, ऊर्जा संक्रमण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक सहयोग पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। भारत ने अवसंरचना और डिजिटल भुगतान में विकास की गति, सुधारों और अवसरों पर प्रकाश डाला, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने लचीलापन,

उत्पादकता और अपनी भविष्य में निर्मित ऑस्ट्रेलिया नीति पर दृष्टिकोण साझा किया।

घ. विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम

12.12. आर्थिक कार्य विभाग द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के तहत कुछ द्विपक्षीय भागीदार देशों और कुछ बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा पेश किए जाने वाले अल्पकालिक विदेश प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए नोडल बिंदु है। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, शासन, प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, कृषि, प्रकृति संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन आदि जैसे क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों/गतिविधियों के क्षेत्रों में अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए है। सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। नामांकन की जांच आर्थिक कार्य विभाग में एक चयन समिति द्वारा की जाती है और उसके बाद स्वीकृति के लिए प्रायोजक सरकार/एजेंसी को सिफारिश की जाती है। वर्ष 2025-26 के दौरान, आर्थिक कार्य विभाग को सिंगापुर सहयोग कार्यक्रम प्रशिक्षण पुरस्कार (एससीपीटीए), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) और मलेशियाई तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (एमटीसीपी) से 67 अल्पकालिक विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों (चार सप्ताह से कम) के लिए प्रशिक्षण के प्रस्ताव प्राप्त हुए और इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त आवेदकों की सिफारिश की गई।

13. एकीकृत वित्त प्रभाग

13.1 प्रभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

- आर्थिक कार्य विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग तथा उनके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों जैसे कि प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी)/राष्ट्रीय बचत संस्थान/जी-20 सचिवालय/विशेष न्यायालय कार्यालय, मुंबई/अभिरक्षक का कार्यालय/ऋण वसूली न्यायाधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और न्यायालय परिसमापक कार्यालय, कोलकाता से संबंधित व्यय से जुड़े प्रस्तावों के लिए वित्तीय सलाह और सहमति देना।
- व्यय नियंत्रण और प्रबंधन करना, व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार व्यय के युक्तिकरण और आर्थिक उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसमें मासिक/त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से व्यय की नियमित निगरानी और संबंधित सचिवों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है।
- प्रभाग दो विस्तृत मांगों अर्थात् मांग सं. 30- आर्थिक कार्य विभाग और मांग सं. 32- वित्तीय सेवाएं विभाग के विस्तृत अनुदानों को भी प्रशासित करता है। इसमें बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देना/अंतिम आवश्यकताओं का अनुमान लगाना/

बचत का अभ्यर्पण, पुनर्विनियोजन और शीर्षवार विनियोजन लेखों की जांच शामिल है।

- iv. संसद में ₹500.00 करोड़ से कम के पूंजीगत परिव्यय वाली सीएस/सीएसएस योजनाओं के संबंध में वित्त मंत्रालय की 'अनुदान के लिए विस्तृत मांग (डीजीजी)' और 'आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ)' का समन्वय, संकलन, मुद्रण और प्रस्तुत करना।
- v. वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा वित्त मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित सभी मामलों का समन्वय।

- vi. आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों से संबंधित लंबित पीएसी/सी और एजी लेखापरीक्षा पैरा/ईएन की संख्यात्मक निगरानी।
- vii. अनुदान मांगों पर वित्त संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्टों के कार्यान्वयन के संबंध में लोक सभा में नियम 73-ए/राज्यसभा में नियम 266 के अनुसरण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य का समन्वय, संकलन, मुद्रण और उसे प्रस्तुत करना।
- viii. प्रभाग द्वारा प्रशासित अनुदानों के संबंध में बजटीय स्थिति नीचे दी गई है:

13.2 अनुदानों का बजटीय आवंटन (निवल आधार पर)

(₹ करोड़ में)

अनुदान		बजट अनुमान 2025-26	संशोधित अनुमान 2025-26	बजट अनुमान 2026-27
30-आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	2400.24	9845.19	3249.65
	पूंजीगत	46613.63	39168.68	4009.47
	कुल	49013.87	49013.87	7259.12
32-वित्तीय सेवाएँ विभाग	राजस्व	1620.01	2141.84	3684.62
	पूंजीगत	68.13	68.14	62.33
	कुल	1688.14	2209.98	3746.95

प्रभावी व्यय नियंत्रण के लिए अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) संबंधित सचिवों के साथ मुख्य शीर्ष/योजना वार विवरण के साथ त्रैमासिक समीक्षा की गई व्यय संबंधी प्रगति।
- (ख) वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित आंकड़ों की तुलना में मुख्य शीर्ष वार और योजना वार व्यय संबंधी प्रगति।

- (ग) आंतरिक लेखा परीक्षा करवाकर आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।
- (घ) परिणामी बजट में शामिल विभाग की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों की मासिक निगरानी।
- (ङ) नियमित और गह्व निगरानी के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान सी एंड एजी ऑडिट पैरा के संबंध में की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) के पर्याप्त मामलों को अंतिम रूप दिया गया।

सी एंड एजी की ऑडिट रिपोर्ट के पैरा-विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के पास लंबित एटीएन लेखापरीक्षा पैरा का विवरण और उनके निपटान की स्थिति- 01.12.2024 से 31.01.2026 तक

मंत्रालय/विभाग का नाम : वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

क्र.सं.	रिपोर्ट सं. और वर्ष	पैरा की संख्या /पी.ए.सी. रिपोर्टें जिनके ए.टी.एन. लेखापरीक्षा द्वारा जाँच के बाद पी.ए.सी. को प्रस्तुत की गई है	पैरा/पी.ए. रिपोर्टों का विवरण जिस पर एटीएन लंबित हैं		
	सी एंड एजी रिपोर्ट		एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए	ए.टी.एन. की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ वापस किए गए लेखापरीक्षा (आडिट) मंत्रालय द्वारा उन्हें पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा है।	ए.टी.एन. की संख्या जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांचा गया है लेकिन पी ए सी को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2021 का 7	16	1	-	-
2.	2022 का 31	23	-	-	-
3.	2023 का 21	6	-	-	-
4.	2024 का 01	-	-	संपूर्ण रिपोर्ट	-
5.	2025 का 03	-	2	-	-
6.	2025 का 04	9	-	-	-
7.	2025 का 16	7	16	-	-
8.	2025 का 19	-	2	-	-

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार: -

रिपोर्ट नं. 2025 का 16 (वित्तीय लेखा परीक्षा)-वर्ष 2023-24 के लिए संघ सरकार के संघ सरकार खाते

संसद में सभा पटल पर रखा गया: 12 अगस्त, 2025

रिपोर्ट में वित्त लेखों की जांच लेखापरीक्षा और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संघ सरकार के विनियोगजन लेखों से उत्पन्न मामले शामिल हैं।

कार्यकारी सारांश

वित्त वर्ष 2023-24 सतत विकास का वर्ष था। जीडीपी के मामले में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी (वास्तविक जीडीपी) में 9.19 प्रतिशत की वृद्धि और वर्तमान मूल्य (सांकेतिक जीडीपी) में 12.02 की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्ति में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके कारण गैर कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2019-20 से सकल कर प्राप्ति में वृद्धि का रुझान रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 से प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में लगातार सकारात्मक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी बढ़कर 55.46 प्रतिशत हो गयी और जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़कर

6.38 प्रतिशत हो गया। यह प्रगतिशील कर प्रणाली को दर्शाता है।

प्रत्यक्ष करों में, आयकर से प्राप्त राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सकल घरेलू उत्पाद (जीटीआर) और (जीडीपी) में इसका योगदान क्रमशः 29.17 प्रतिशत और 3.36 प्रतिशत तक बढ़ गया। हालांकि, वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निगम कर (3.07 प्रतिशत से 3.02 प्रतिशत) और जीटीआर में योगदान (27.04 प्रतिशत से 26.29 प्रतिशत) में वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में थोड़ी कमी आई है। वित्त वर्ष 2021-22 से जीएसटी संग्रह में वृद्धि का रुझान रहा है, इसके साथ ही जीडीपी के प्रतिशत के रूप में योगदान में भी वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में गैर-कर राजस्व में 23.81 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप सकल राजस्व प्राप्ति में योगदान के मामले में (16.59 प्रतिशत से 17.83 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। गैर-कर राजस्व में यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में लाभांश और लाभ में 71 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

यद्यपि, सरकार का व्यय वित्त वर्ष 2020-21 में 39,07,647 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 48,52,572 करोड़ रुपये हो गया, फिर भी इस अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप

में क्रमशः 19.68 प्रतिशत से 16.11 प्रतिशत की कमी आई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है (वित्त वर्ष 2020-21 में 1.73 प्रतिशत से वित्त वर्ष 2023-24 में 2.68 प्रतिशत) जो सकारात्मक संकेत है। ऋण का पुनर्भुगतान भारत की समेकित निधि से प्रमुख बिंदु रहा है, जिसने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल व्यय में 60.60 प्रतिशत का योगदान दिया है।

यह देखा गया है कि कुल राजस्व व्यय के भाग के रूप में वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर राजस्व व्यय का स्थिर घटक वित्त वर्ष 2022-23 में 38.93 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 42.37 प्रतिशत हो गया है। राजस्व व्यय की स्थिर प्रतिबद्धताओं में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि में मुख्य योगदान ब्याज भुगतान का था, जिसमें 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मामूली वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में परिवहन क्षेत्र पर पूंजीगत व्यय में 269.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि के कारण केंद्र सरकार की कुल देनदारियों में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 आंतरिक ऋण में 12.43 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में उच्च वृद्धि दर के कारण वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजकोषीय मानदंडों में सुधार हुआ। राजस्व प्राप्ति में 13.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष 1.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राजस्व और राजकोषीय घाटे पिछले वर्ष की तुलना में कम थे जो विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में राजस्व घाटे में 28.45 प्रतिशत की कमी आई, जो राजस्व व्यय पर नियंत्रण और राजस्व प्राप्तियों में सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

केंद्र सरकार के वित्त खातों (यूजीएफए) में 16 विवरण होते हैं जो वर्ष के लिए संघ के वित्त परिणामों को दर्शाते हैं। केंद्र सरकार की वित्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट (यूजीएफएआर) का अध्याय 3 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों की गुणवत्ता पर केंद्रित है।

1.44% मुद्रास्फीति सूचकांक जी-एस. 2023 के निर्वहन के लिए गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के आंतरिक ऋण में ₹ 372.64 करोड़ की कमी आई (पैरा 3.1.1)। प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता प्रभाव राज्य कैम्पा प्राधिकरण द्वारा एकत्र किया जाना था और 90: 10 के अनुपात में जमा किया जाना था राज्य और केंद्रीय प्राधिकरणों के बीच उनके संबंधित प्रतिपूरक आरक्षित निधि में जमा किया जाना था। हालांकि, हमने पाया कि राष्ट्रीय/राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में आगे वितरण के लिए निधि को भारत के लोक लेखा में अंतरित कर दिया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों के संवितरण के लिए 15,103 करोड़ रुपये लंबित थे। लोक लेखा में दर्शायी गई शेष राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखों में दर्शाए गए संबंधित आंकड़ों की तुलना में कम दर्शायी गई थी जिससे संभावना है की लोक लेखा में 866.41 करोड़ रुपये (पैरा 3.1.2) का आंकलन किया गया।

यूजीएफए का विवरण 13 केवल उच्चतम शीर्षों के तहत निवल बकाया को दर्शाता है, जिससे समाशोधन के लिए लंबित वास्तविक शेष राशि को कम आंका गया है, और उच्चतम खाते (सिविल) में यह 68.01 प्रतिशत और रिजर्व बैंक उच्चतम केंद्रीय खाता कार्यालय में यह अल्प आंकलन 54.89 प्रतिशत था (पैरा 3.2.1 ग)। इसी प्रकार नकद शेष राशि के नेटिंग के परिणामस्वरूप आरबीआई के पास समायोजन हेतु लम्बित नकद शेष राशि को कम दर्शाया गया है और समायोजन हेतु कुल नकद शेष राशि 3,793.74 करोड़ रुपये है (पैरा 3.4.3)।

'विभागीय चेक' के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 में 441.02 करोड़ रुपये (डेबिट) से वित्त वर्ष 2023-24 में 3796.87 करोड़ रुपये (क्रेडिट) की वृद्धि देखी गई (पैरा 3.2.ख)। विभिन्न निधियों और जमा राशियों में प्रतिकूल शेष के 53 मामले पाए गए जिनमें से 43 मामले पांच वर्षों से अधिक समय तक अनसुलझे रहे (पैरा 3.2.2)। ऋण, जमा और विप्रेषण शीर्षों के तहत शेष राशि और प्रतिकूल शेष राशि को जमा करने से खातों की सटीकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (पैरा 3.2)।

आरक्षित निधियां भारत के लोक लेखा खाते का भाग हैं। ये निधियां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं और आम तौर पर उपकर या लेवी के माध्यम से वित्तपोषित की जाती हैं, जिसे, भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और संसद की मंजूरी के साथ विनिर्दिष्ट आरक्षित निधि में अंतरित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 में, उपकर/प्रभार/लेवी के रूप में 3,79,598 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी, जो केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व का 10.95 प्रतिशत था। अभिलेखों की नमूना जांच से 31 मार्च 2024 तक लोक लेखों में विनिर्दिष्ट आरक्षित निधियों में 3,69,307 करोड़ रुपये के अल्प अंतरण के कुल प्रभाव का पता चला (पैरा 3.3.1)। साथ ही, 834.37 करोड़ रुपये के संचित निवल जमा शेष के साथ निष्क्रिय आरक्षित निधियों और जमाओं की निरंतरता यह दर्शाती है कि इसने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया और जिसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है (पैरा 3.3.2)।

वित्त वर्ष 2023-24 क्रमशः 6,024.15 करोड़ रुपये और 2,231.42 करोड़ रुपये के व्यय और प्राप्ति के 50 प्रतिशत से अधिक के विभिन्न प्रमुख शीर्षों के 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' और 'लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों' के तहत दर्ज किया गया, जिससे खातों में पारदर्शिता से समझौता हुआ (पैरा 3.3.3)।

वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य निकायों से ₹9,41,560 करोड़ ऋण और अग्रिम वसूली के लिए बकाया थे, जिनमें वसूली बकाया (मूलधन और ब्याज) ₹86,174 करोड़ था (पैरा 3.2.3)। हमने ₹178.81 करोड़ के गारंटी शुल्क की कम वसूली देखी है (पैरा 3.4.2)।

हमने यह भी पाया कि लेखांकन में ₹4,214.07 करोड़ के गलत वर्गीकरण के उदाहरण हैं। इनमें से ₹3,283.50 करोड़ प्राप्तियों से संबंधित थे और शेष गलत वर्गीकरण, कुल मिलाकर ₹930.57 करोड़, व्यय से संबंधित थे और मुख्यतः पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और इसके विपरीत (₹654.88 करोड़) गलत वर्गीकृत करने से संबंधित थे (पैरा 3.5)।

यूजीएफए में ₹16,133 करोड़ (मेसर्स वोडाफोन इंडिया लिमिटेड) के इक्विटी शेयरों का गैर-लेखांकन था, वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा प्राप्त 'लाभांश और लाभ' से संबंधित यूजीएफए के दो विवरणों (8 और 11) के बीच ₹2.30 करोड़ का अंतर था तथा यूजीएफए और पीएसयू खातों के बीच जानकारी का बेमेल होना था। (पैरा 3.4.1)।

मार्च 2024 के अंत में, 'सेबी सामान्य निधि' के अंतर्गत सरकारी खाते से बाहर ₹5,573 करोड़ का अधिशेष शेष रखा गया (पैरा 3.3.4)। डाक जीवन बीमा निधि (पीएलआईएफ) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि (आरपीएलआईएफ) के दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश से प्राप्त ₹941.91 करोड़ (पीएलआईएफ- ₹502.05 करोड़) और आरपीएलआईएफ- ₹439.86 करोड़ की आय को यूजीएफए में अतिरिक्त रूप से दर्ज किया गया (पैरा 3.3.5)। दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) ने नियमित पेंशन भुगतान के ₹3,443.08 करोड़ को "वृद्धिशील पेंशन भुगतान" के रूप में गलत वर्गीकृत किया है (पैरा 3.5.2.1)।

केंद्र सरकार के विनियोग खातों में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 102 अनुदान/विनियोग शामिल हैं। संसद ने ₹1,47,56,796.55 करोड़ के विनियोगों को मंजूरी दी, जिसके सापेक्ष सरकार ने ₹1,29,74,923.11 करोड़ खर्च किए, जिससे कुल ₹17,81,873.44 करोड़ की बचत हुई (पैरा 4.1.1)।

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की संचित निधि से कुल भारित (संसद द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं) प्रावधान ₹1,02,66,792.77 करोड़ (69.57 प्रतिशत) था, जिसके सापेक्ष व्यय ₹87,53,015.54 करोड़ (67.46 प्रतिशत) था। कुल स्वीकृत प्रावधान ₹44,90,003.78 करोड़ (30.43 प्रतिशत) था और वास्तविक व्यय ₹42,21,907.57 करोड़ (32.54 प्रतिशत) था, जिसमें ₹2,68,096.21 करोड़ (15.05 प्रतिशत) की बचत हुई। वित्त वर्ष 2020-21 में मामूली कमी दर्शाने के बाद भारित व्यय में वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि हुई, जबकि स्वीकृत व्यय में वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में वृद्धि और वित्त वर्ष 2023-24 में मामूली कमी देखी गई (पैरा 4.1.2)।

सिविल मंत्रालयों/विभागों के संबंध में, प्रमुख भारित संवितरण में दो विनियोजन शामिल हैं: ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान, और प्रमुख स्वीकृत माँग राज्यों को अंतरण (पैरा 4.1.2)। 'राज्यों को अंतरण (स्वीकृत पूंजी)' के संबंध में, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹31,308.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के तहत विनियोग से अधिक व्यय को विनियमित किया जाना आवश्यक है। (पैरा 4.2.1.1)

हमने निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण 9 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 14 लघु/उप-शीर्षों से संबंधित ₹25 करोड़ या उससे अधिक का अतिरिक्त व्यय देखा (पैरा 4.2.1.2)। हमने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 14 अनुदानों/विनियोजनों में ₹5,000 करोड़ या उससे अधिक की बचत भी देखी, जबकि छह अनुदानों/विनियोजनों में वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में भी लगातार बचत हुई (पैरा 4.2.2.1)। इसके अलावा, 70 अनुदानों/विनियोजनों के 95 खंडों में ₹100 करोड़ या उससे अधिक की बचत हुई (पैरा 4.2.2.2)।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 16 अनुदानों के अंतर्गत 28 लघु/

उप-शीर्षों से संबंधित अधिक व्यय की प्रत्याशा में, प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए क्योंकि अंतिम व्यय संबंधित लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधानों से कम था (पैरा 4.3.1)। पुनर्विनियोजन के संबंध में, हमने देखा कि 14 अनुदानों/विनियोजनों में 20 लघु/उप-शीर्षों में प्रत्येक में ₹10 करोड़ से अधिक का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण तरीके से किया गया था, क्योंकि जिन लघु/उप-शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से वृद्धि की गई थी, उनके अंतर्गत स्वीकृत प्रावधान पर्याप्त थे और पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार, चार अनुदानों में 12 लघु/उप-शीर्षों से अविवेकपूर्ण तरीके से पुनर्विनियोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन लघु/उप-शीर्षों में परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ (पैरा 4.4.1)।

हमने यह भी पाया कि संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी बजट प्रावधान के 18 अनुदानों/विनियोजनों में 34 लघु/उप-शीर्षों के अंतर्गत 66,507.20 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई, जिनमें से प्रत्येक का व्यय एक करोड़ रुपये से अधिक था (पैरा 4.5.2)।

22 विभागों/मंत्रालयों द्वारा प्रदान की गई जानकारी से, हमने पाया कि दिनांक 31 मार्च 2024 तक कुल ₹72,764.09 करोड़ मूल्य के 37,986 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे, जिनमें से ₹62,199.11 करोड़ मूल्य के 16,596 उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) पिछले तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23) से संबंधित हैं और स्वीकृत अनुदानों की प्रारंभिक अवधि, जिसके लिए उपयोगिता प्रमाण (यूसी) पत्र बकाया थे, वर्ष 1977-78 से संबंधित है। इससे जीएफआर 2017 (पैरा 4.7) के नियम 238 (1) और (2) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

14.1 सिक्का एवं मुद्रा प्रभाग

14.1 सिक्का और मुद्रा प्रभाग भारत की मुद्रा और सिक्का निर्माण के सभी पहलुओं से संबंधित नीति के लिए उत्तरदायी है। प्रभाग का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) और बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) के साथ घनिष्ठ समन्वय से किया जाता है। प्रभाग में तीन अनुभाग हैं अर्थात् मुद्रा, सिक्का और एसपीएमसी अनुभाग। इन अनुभागों के बीच उत्तरदायित्व इस प्रकार विभाजित है:

14.1.1 मुद्रा अनुभाग सुरक्षा विशेषताओं सहित मुद्रा नोटों/बैंक नोटों के डिजाइन, स्वरूप और सामग्री से संबंधित सभी नीतिगत मामलों, तथा उत्पादन से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों, बैंक नोटों की छपाई की योजना, मुद्रा से संबंधित कानून, बैंक नोट सामग्री का स्वदेशीकरण, मुद्रणालय, कागज कारखानों, स्याही कारखाने आदि का विस्तार, उन्नयन और आधुनिकीकरण, तथा एसबीएन (देयता समाप्ति) अधिनियम, 2017 और उसके तहत बनाए गए नियमों को लागू करने से संबंधित सभी नीतिगत मामलों की देखरेख करता है।

14.1.2 सिक्का अनुभाग सर्कुलेशन सिक्कों के डिजाइन, आकार और माप, सिक्कों के उचित विक्रय मूल्य का निर्धारण, सिक्कों से संबंधित कानून और स्मारक सिक्के जारी करने, प्रतिभूति उत्पादों जैसे पासपोर्ट, डाक टिकट, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, सिक्कों की उत्पादन योजना और

सिक्कों के मांगपत्र का निर्धारण, टकसालों और प्रतिभूति मुद्राणालयों के विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण से संबंधित नीतिगत मामलों से संबंधित कार्य करता है।

14.1.3 एसपीएमसी अनुभाग एसपीएमसीआईएल से संबंधित मामलों की देखरेख करता है, जो विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। यह अनुभाग इस कंपनी के बोर्ड स्तर के पदों पर नियुक्ति, समझौता ज्ञापन, इसकी नौ इकाइयों के शेष अवस्थापना संबंधी मामलों और एसपीएमसीआईएल बोर्ड, एसपीएमसीआईएल पेंशन फंड ट्रस्ट आदि की बैठकों के समन्वय से संबंधित मुद्दों की देखरेख करता है।

14.2 प्रभाग की प्रमुख उपलब्धियां:

14.2.1 जालसाजी से बचने के लिए भारत सरकार ने आरबीआई के परामर्श से भारतीय बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं लागू करने की प्रक्रिया

शुरू की है। सरकार ने आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार बैंक नोटों में सुरक्षा विशेषताओं के संशोधित मैट्रिक्स पर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने सुरक्षा विशेषताओं के इस संशोधित मैट्रिक्स को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई सुरक्षा विशेषताओं के इस संशोधित मैट्रिक्स से करेंसी नोटों की जालसाजी से बचा जा सकेगा।

14.2.2 यह प्रभाग बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा बैंक नोटों के उत्पादन की निगरानी की जाती है। बैंक नोटों और सिक्कों के इंडेंट और उत्पादन तथा जनता को उनकी निर्बाध आपूर्ति की समीक्षा के लिए रणनीतिक योजना समूह और उत्पादन योजना समिति की बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2025-26 में दिनांक 18.12.2025 तक मुद्रा मुद्रणालय द्वारा नोटों का संचयी उत्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष 2025-26 के दौरान 18.12.2025 तक बीआरबीएनएमपीएल और एसपीएमसीआईएल द्वारा नोटों के इंडेंट की स्थिति

प्रेस	2025-26 के लिए आवंटित कुल इंडेंट (मिलियन पीस में)	01.04.2025 से 18.12.2025 तक संचयी उत्पादन (मिलियन पीस में)	2025-26 के लिए शेष उत्पादन (मिलियन पीस में)
बीआरबीएनएमपीएल	16860	11512.82	5347.18
एसपीएमसीआईएल	11240	7138.40	4101.60
अंकित मूल्य (करोड़)			
बीआरबीएनएमपीएल	401160	311115.57	90044.43
एसपीएमसीआईएल	267440	192752.40	74687.60

14.2.3 प्रचलित नोट (एनआईसी) के रुझानों पर नज़र रखी जाती है। 4 नवंबर, 2016 तक 17,74,187 करोड़ रुपये मूल्य के नोट प्रचलन (एनआईसी) में थे, जो अब दिनांक 18.12.2025 तक बढ़कर 38,73,810 करोड़ रुपये हो गए हैं।

14.2.4 प्रचलित सिक्कों (सीएनआईसी) के रुझानों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। दिनांक 18.12.2025 तक 39,018.93 करोड़ रुपये मूल्य के सिक्के प्रचलन में थे। दिनांक 04 नवंबर, 2016 तक (जब यह 22,769.71 करोड़ था) प्रचलित सिक्कों की तुलना में प्रचलित सिक्कों के मूल्य में ₹16,249.22 करोड़ की वृद्धि हुई है।

14.2.5. सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, स्मारक सिक्के का अर्थ है सरकार या सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकार प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट अवसर या घटना के उपलक्ष्य में जारी किया गया कोई भी सिक्का और भारतीय मुद्रा में अंकित किया गया सिक्का। तदनुसार, सरकार ऐसे प्रतिष्ठित हस्तियों/व्यक्तियों/ संस्थाओं/ घटनाओं/ कार्यक्रमों/इतिहास आदि पर स्मारक सिक्के जारी करती है, जिनका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय

स्वरूप होता है और जिन्होंने स्थायी योगदान दिया है या प्रभाव डाला है। व्यक्ति/संगठन/कार्यक्रम/घटना द्वारा किया गया योगदान दलगत राजनीति, क्षेत्र, समुदाय, भाषा या धर्म की बाधाओं से ऊपर होना चाहिए। हालांकि, बलिदान के प्रति सहानुभूति/शोक/सम्मान प्रदर्शित करने के अवसर पर, स्मारक सिक्के जारी किए जाएंगे। इस संबंध में दिनांक 29.09.2020 को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

14.2.6 वर्ष 2025-26 (18.12.2025 तक) के दौरान, सरकार ने 28 स्मारक सिक्कों के जारी करने संबंधी राजपत्रित अधिसूचना जारी की हैं अर्थात् न्यू मंगलौर पोर्ट अथॉरिटी का स्वर्ण जयंती, भगवान श्री सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी, राज्य का दर्जा - सिक्किम के 50 गौरवशाली वर्ष, पंथ रतन स्वर्गीय श्री गुरुचरण सिंह तोहरा की जन्म शताब्दी, श्री रामनासराम शताब्दी, अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती, राजभाषा विभाग का स्वर्ण जयंती समारोह, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, प्रो. एम.एस. स्वामीनाथन की 100वीं जयंती, मेक इन इंडिया की 10वीं जयंती, आचार्य श्री महाप्रज्ञा की 105वीं जयंती, सम्राट राजेंद्र चोल-1 के नौसेना अभियान के 1000 वर्ष, भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का प्लैटिनम जयंती समारोह, श्री सत्यप्रमोदा तीर्थ स्वामी जी की 108वीं जयंती, डॉ. भूपेन हजारिका की जन्म शताब्दी, आचार्य जवाहर लाल जी महाराज की 150वीं जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं वर्षगांठ, रानी चन्नम्मा की किन्नूर में विजय की 200वीं वर्षगांठ, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती, आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ, एनएचपीसी लिमिटेड के पचास वर्ष पूरे होने का उत्सव, 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वां शहादत दिवस, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ की 550वीं वर्षगांठ, नासिक में भारतीय प्रतिभूति प्रेस की शताब्दी वर्षगांठ

14.3 भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

14.3.1 भारतीय प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), एक मिनीरल्टन श्रेणी-I, अनुसूची-क' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) है, जिसकी स्थापना 13 जनवरी 2006 को भारत सरकार के चार टकसालों, दो मुद्रा मुद्रणालयों, दो प्रतिभूति मुद्रणालय और एक प्रतिभूति कागज कारखाना के प्रबंधन के लिए निगमित किया गया था, जिन्हें पहले भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित किया जाता था। कंपनी पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्वाधीन में है, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 2500 करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी 987.50 करोड़ रुपये है।

14.3.2 भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) कंपनी के दो मुद्रा मुद्रणालयों, अर्थात् बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास और चलार्थ पत्र मुद्रणालय (सीएनपी), नासिक द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले करेंसी नोटों का खरीददार है। विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) क्रमशः पासपोर्ट और वीजा स्टिकर के ग्राहक हैं और राज्य सरकारें गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर और संबद्ध स्टाम्प के ग्राहक हैं और डाक विभाग कंपनी के दो प्रतिभूति मुद्रणालयों, अर्थात् प्रतिभूति मुद्रण मुद्रणालय (एसपीपी), हैदराबाद और भारत प्रतिभूति मुद्रणालय (आईएसपी), नासिक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली डाक स्टेशनरी, टिकटों आदि का खरीददार है। ये प्रतिभूति मुद्रणालय विभिन्न ग्राहकों के लिए चेक, रेलवे वारंट, आयकर रिटर्न ऑर्डर फॉर्म, बचत लिखत, स्मारक टिकट, उत्पाद शुल्क हेतु चिपकने वाला लेबल, प्रमाण पत्र आदि जैसी विभिन्न प्रतिभूति मदों का उत्पादन भी करते हैं। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) इस कंपनी के मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा स्थित चार भारत सरकार टकसालों (आईजीएम) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले प्रचलित सिक्कों का खरीददार है। कंपनी के पास नर्मदापुरम में एक प्रतिभूति कागज कारखाना (एसपीएम) है जो मुद्रा/प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा उपयोग के लिए प्रतिभूति कागज बनाता है। कंपनी के पास देवास में एक इंक फैक्ट्री भी है जो एसपीएमसीआईएल के प्रेस द्वारा उपयोग के लिए ऑफसेट इंक, यूवी इंक और विक्कसेट इंटालियो इंक बनाती है।

14.3.3 विश्वसनीय लिखतों के निर्माता के रूप में, एसपीएमसीआईएल प्रमुख दक्षता और डिजाइन बिलडिंग संबंधी क्षमताओं का उपयोग करते हुए

अत्याधुनिक प्रतिभूति उत्पादों के निर्माण की अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के विजन से प्रेरित है। विश्व स्तरीय और अत्यधिक सुरक्षित बैंकनोट, सिक्के और प्रतिभूति दस्तावेजों के निर्माण द्वारा राष्ट्र की सहायता करने की प्रतिबद्धता के साथ, एसपीएमसीआईएल के पास प्रतिभूति मुद्रण में लगभग 100 वर्षों का और मुद्रा निर्माण के क्षेत्र में दो शताब्दियों से अधिक का अनुभव है।

14.3.4 एसपीएमसीआईएल ने 12,064.54 मिलियन बैंक नोटों का उत्पादन किया है और आरबीआई को 12,120 मिलियन बैंक नोटों की आपूर्ति की है। यह विगत वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2023-24 में उत्पादित 9707.34 मिलियन बैंक नोटों की तुलना में उत्पादन में 24.28% की वृद्धि और पिछले वर्ष में 9,720 मिलियन नोटों की आपूर्ति में 24.69% की वृद्धि दर्शाता है। प्रति कर्मचारी बैंक नोट उत्पादन में 29.06% की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 4.99 मिलियन नोटों से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.44 मिलियन नोट हो गए।

14.3.5 एसपीएमसीआईएल ने 1477.55 मिलियन प्रचलित सिक्कों का उत्पादन किया है और आरबीआई को 1500.00 मिलियन प्रचलित सिक्कों की आपूर्ति की है, जो एक सुदृढ़ विकास को दर्शाता है। पिछले वर्ष के 1200.99 मिलियन सिक्कों की तुलना में उत्पादन में 23.03% की वृद्धि हुई, जबकि 2023-24 में 1205.64 मिलियन सिक्कों की तुलना में आपूर्ति में 24.42% की वृद्धि हुई। प्रति कर्मचारी प्रचलित सिक्कों का उत्पादन 38.71% बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 0.93 मिलियन नोटों से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 1.29 मिलियन नोट हो गए।

14.3.6 वर्ष 2024-25 के दौरान, एसपीएम, नर्मदापुरम (एसपीएमसीआईएल की एक इकाई) ने 7661.61 मीट्रिक टन (एमटी) प्रतिभूति पेपर का उत्पादन किया है और मुद्रणालयों को 7815.37 मीट्रिक टन प्रतिभूति पेपर की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान 7113.75 मीट्रिक टन प्रतिभूति पेपर के उत्पादन से 7.70% की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति की गई 7375.40 मीट्रिक टन की तुलना में आपूर्ति में 5.97 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। प्रतिभूति पेपर का उत्पादन वर्ष 2024-25 में प्रति कर्मचारी बढ़कर 9.60 मीट्रिक टन हो गया है, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान 8.72 मीट्रिक टन प्रतिभूति पेपर का उत्पादन हुआ था।

14.3.7 एसपीएमसीआईएल ने वर्ष 2024-25 के दौरान इंक फैक्ट्री, देवास में 601.31 मीट्रिक टन (एमटी) सिक्योरिटी इंक का उत्पादन किया है और मुद्रण मुद्रणालयों को 574.24 मीट्रिक टन इंक की आपूर्ति की है। यह पिछले वर्ष 2023-24 के दौरान 592.18 मीट्रिक टन सिक्योरिटी इंक के उत्पादन की तुलना में 1.54 प्रतिशत की वृद्धि और पिछले वर्ष आपूर्ति की गई 595.37 मीट्रिक टन की तुलना में आपूर्ति में 3.55 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, प्रति कर्मचारी सिक्योरिटी इंक का उत्पादन पिछले वर्ष 2023-24 में 10.21 मीट्रिक टन की तुलना में 2024-25 में बढ़कर 10.37 मीट्रिक टन हो गया है।

14.3.8 एसपीएमसीआईएल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 15.63 मिलियन पीस यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाएं तैयार की हैं और वर्ष 2024-25 के

दौरान विदेश मंत्रालय (एमईए) को 15.74 मिलियन पीस यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाओं की आपूर्ति की हैं। यह वर्ष 2023-24 के दौरान 14.03 मिलियन पीस यात्रा दस्तावेज/पासपोर्ट पुस्तिकाओं के उत्पादन से 11.40% अधिक है। एसपीएमसीआईएल ने वर्ष 2024-25 के दौरान 193.13 मिलियन पीस गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (एनजेएसपी) भी तैयार किए हैं और विभिन्न राज्य सरकारों को 197.67 मिलियन पीस गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर की आपूर्ति की है।

14.3.9 पिछले वर्ष 2023-24 में एसपीएमसीआईएल के परिचालन से राजस्व 4712.86 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ष 2024-25 में यह 5481.91 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2023-24 के लिए कुल व्यय 3695.50 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2024-25 के लिए यह 4396.99 करोड़ रुपये है। वर्ष 2024-25 के लिए मौजूदा कार्यों से प्राप्त कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) वर्ष 2023-24 के 1383.84 करोड़ रुपये की तुलना में 1487.03 करोड़ रुपये है। कंपनी ने वर्ष 2023-24 में 1006.55 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय (टीसीआई) अर्जित की है, जिसकी तुलना में, वर्ष 2024-25 के दौरान यह 1005.09 करोड़ रुपये रही। संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की 50% हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023-24 में समेकित टीसीआई 1067.79 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2024-25 में समेकित टीसीआई 1070.15 करोड़ रुपये है।

14.3.10 निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) द्वारा जारी सीपीएसई के कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को 31 मार्च 2025 तक कंपनी के निवल मूल्य के 4% के रूप में 317.32 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है।

14.3.11 वर्ष 2024-25 के दौरान, एसपीएमसीआईएल ने परिचालन दक्षता, उत्पाद गुणवत्ता और तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी उत्पादन इकाइयों में कई उन्नत मशीनें चालू की। करेंसी नोट प्रेस(सीएनपी), नासिक में, तीन ऑफसेट बैंकनोट प्रिंटिंग मशीनें, एक इंटैग्रेलियो बैंकनोट प्रिंटिंग मशीन, दो बैंकनोट नंबरिंग मशीनें और दो बैंकनोट फिनिशिंग मशीनें स्थापित की गईं। बैंक नोट प्रेस (बीएनपी), देवास को एक ऑफसेट बैंकनोट प्रिंटिंग मशीन और एक बैंकनोट फिनिशिंग मशीन मिली। सिक्क्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस (एसपीपी), हैदराबाद में एक स्मार्ट कार्ड निर्माण मशीन स्थापित की गई थी, और इंडिया सिक्क्योरिटी प्रेस (आईएसपी), नासिक में एक पूरी तरह से एकीकृत पासपोर्ट निर्माण लाइन चालू की गई थी। ये अपग्रेड सुरक्षित प्रिंटिंग में अत्याधुनिक अवसंरचना को अपनाने के लिए एसपीएमसीआईएल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

14.3.12 टकसाल, करेंसी प्रेस, सिक्क्योरिटी प्रेस, और पेपर मिल सहित एसपीएमसीआईएल की सभी नौ इकाइयों ने गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रत्येक इकाई को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईएसओ 9001:2015 और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001:2015 से प्रमाणित किया गया है। एसपीएम नर्मदापुरम, बीएनपी देवास, आईजीएम नोएडा, आईजीएम मुंबई, एसपीपी हैदराबाद,

आईएसपी नासिक और सीएनपी नासिक जैसी इकाइयों ने भी व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन प्राप्त किया है। एसपीएम नर्मदापुरम, सीएनपी नासिक, बीएनपी देवास, आईएसपी नासिक और एसपीपी हैदराबाद को ऊर्जा प्रबंधन के लिए आईएसओ 50001:2018 प्रमाणन भी दिया गया है। इसके अलावा, एसपीएम नर्मदापुरम, एसपीपी हैदराबाद, आईजीएम मुंबई, आईजीएम नोएडा, आईजीएम कोलकाता, और आईजीएम हैदराबाद ने प्रयोगशाला मानकों के लिए आईएसओ/आईसी 17025:2017 प्रमाणन प्राप्त किया है, जबकि आईजीएम मुंबई में गोल्ड सर्टिफाइड रेफरेंस मेटिरियल के लिए आईएसओ 17034:2016 मान्यता प्राप्त की है। कारपोरेट कार्यालय, सीएनपी नासिक और आईएसपी नासिक को भी बीआईएस से एंटी-ब्राइब्री मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो अखंडता और वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

14.3.13 दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की जनशक्ति 5395 है, जिसमें 9 इकाइयों और कारपोरेट कार्यालय में काम करने वाले 399 कार्यकारी, 839 पर्यवेक्षक और 4157 कार्यालय कर्मचारी और श्रमिक शामिल हैं।

14.3.14 एसपीएमसीआईएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, कौशल विकास आदि के क्षेत्रों में कई सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। एसपीएमसीआईएल ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को आकांक्षी जिले के रूप में अपनाया था। इसने झारखंड राज्य के सिमडेगा और गुमला के आकांक्षी जिलों में सीएसआर पहल भी शुरू की है।

14.3.15 स्वदेशीकरण: संयुक्त उद्यम कंपनी, बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) ने वर्ष 2024-25 के दौरान 16651 मीट्रिक टन सिक्क्योरिटी पेपर का उत्पादन किया है।

14.4 भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कारपोरेट कार्यालय, बंगलुरु

14.4.1 भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्राइवेट) लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो देश भर में भारतीय बैंक नोट के मुद्रण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। 1995 में आरबीआई द्वारा स्थापित, कंपनी का मिशन अत्याधुनिक, विश्व स्तरीय उत्पादन सुविधाओं के माध्यम से मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

14.4.2 कंपनी दो मुद्रण मुद्रणालयों पहली पश्चिम बंगाल के सालबोनी में और दूसरी मैसूर, कर्नाटक में अपने कारपोरेट कार्यालय के साथ-साथ बंगलुरु, कर्नाटक का प्रबंधन करती है। दोनों मुद्रणालयों ने बैंक नोटों की छपाई में नवीनतम प्रौद्योगिकी स्थापित की है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नवीनतम प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरंतर उन्नयन किया जा रहा है।

14.4.3 दोनों मुद्रणालयों में नवीनतम सुरक्षा निगरानी प्रणाली भी स्थापित

है। वर्तमान में, बीआरबीएनएमपीएल अपने मुद्रणालय में अपनी उत्पादन लाइनों में व्यापक स्वचालन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के चरण में है, जिसमें नई उद्यम संसाधन योजना प्रणालियों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

14.4.4 बीआरबीएनएमपीएल ने अपनी स्थापना के बाद से लगातार देश की बैंक नोट आवश्यकता को प्राप्त किया है। वर्ष 2024-25 के लिए प्रदर्शन नीचे विस्तृत है:

दिनांक 18.12.2025 तक वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान बीआरबीएनएमपीएल द्वारा नोटों के मांगपत्र की स्थिति			
मुद्रणालय	वर्ष 2025-26 के लिए आवंटित कुल मांगपत्र (एमपीसीएस में)	दिनांक 01.04.2025 से 18.12.2025 तक संचयी उत्पादन (एमपीसीएस में)	वर्ष 2025-26 के लिए शेष उत्पादन (एमपीसीएस में)
बीआरबीएनएमपीएल	16860.00	11512.82	5347.18
अंकित मूल्य (करोड़)			
बीआरबीएनएमपीएल	401160.00	311115.57	90044.43

14.4.5 बीआरबीएनएमपीएल ने एसपीएमसीआईएल के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में वर्ष 2016 में "बैंकनोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड" की स्थापना प्रमुख कच्चे माल के बैंकवर्ड इंटीग्रेशन के रूप में की है, जिससे करेंसी पेपर का स्वदेशीकरण के साथ बैंक नोट निर्माण में लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई है। इसने इस उद्योग में वैश्विक शक्तियों के बराबर इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण को भी सक्षम बनाया है।

14.4.6 दूसरे प्रमुख कच्चे माल, सुरक्षा स्याही निर्माण इकाई (अर्थात्, वर्णिका) की आंतरिक स्थापना ने आयात निर्भरता को सफलतापूर्वक कम कर दिया है। यह नोट करने योग्य है कि दोनों कच्चे माल कुल बैंकनोट लागत का लगभग 70% से 80% हिस्सा हैं।

14.4.7 वर्णिका की अनुमानित वार्षिक विनिर्माण क्षमता 1200 मीट्रिक टन (एमटी) है। यह बैंकनोट निर्माण के विभिन्न चरणों के लिए सभी आवश्यक स्याही का उत्पादन करता है, साथ ही वार्निश और मीडियम जैसे कच्चे माल का भी उत्पादन करता है। वर्णिका वर्तमान में इस क्षेत्र में वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रचालन का विस्तार करने के लिए कार्य कर रही है।

14.4.8 अपनी वैश्विक आउटरीच कार्यनीति के हिस्से के रूप में, बीआरबीएनएमपीएल ने विश्व स्तरीय बैंकनोट निर्माण समाधानों की आपूर्ति के लिए विभिन्न देशों को औपचारिक प्रस्ताव प्रदान किया है।

14.4.9 बीआरबीएनएमपीएल ने इसके सभी तीन स्थानों अर्थात् बेंगलुरु कारपोरेट कार्यालय, मैसूर मुद्रणालय और सालबोनी मुद्रणालय में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके संधारणीयता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए स्वेच्छा से हरित ऊर्जा पहलों को अपनाया है।

14.4.10 अपनी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति के तहत, कंपनी शिक्षा, स्थायी आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और समुत्थानशील अवसंरचना के निर्माण का संवर्धन करती है।

14.5 बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल)

14.5.1 बीएनपीएमआईपीएल की स्थापना वर्ष 2010 में मैसूर में एसपीएमसीआईएल और बीआरबीएनएमपीएल के बीच 50:50 आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य स्वदेशी बैंक नोट पेपर (सीडब्ल्यूबीएन पेपर) का उत्पादन करना था। कंपनी ने प्रति वर्ष 12000 मीट्रिक टन की स्थापित क्षमता वाली दो पेपर मिल स्थापित की हैं। कंपनी ने वर्ष 2016 के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और भारतीय बैंक नोट पेपर की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा किया है।

14.5.2 वर्ष 2024-25 के दौरान, बीएनपीएमआईपीएल ने 16651 मीट्रिक टन सीडब्ल्यूबीएन पेपर (स्थापित क्षमता का 138%) का उत्पादन किया है और भारतीय बैंक नोटों को मुद्रित करने के लिए सभी चार बैंकनोट मुद्रण मुद्रणालयों को उनकी पेपर की संपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए 18391 मीट्रिक टन सीडब्ल्यूबीएन पेपर की आपूर्ति की है। कंपनी को गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन और स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए क्रमशः आईएसओ 9001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 45001: 2018 से प्रमाणित किया गया है। कंपनी ने सभी प्रकार के लेखांकन, भंडार प्रबंधन और लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण के लिए ईआरपी प्रणाली भी लागू की है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	अजजा/अजा/अपिव का कुल प्रतिनिधित्व (31.03.2025 तक)					वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या												
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			अन्य माध्यमों से				
	कुल कर्मचारियों की संख्या	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह 'क'	399	51	19	97	3	22	2	0	4	0	23	2	0	0	0	0	0	0
समूह 'ख'	839	124	81	192	8	8	0	4	1	11	64	12	2	0	0	0	0	0
समूह 'ग'	4157	813	360	874	57	193	30	13	111	16	658	124	53	84	19	15	22	0
कुल	5395	988	460	1163	68	223	32	17	116	27	745	138	55	84	19	15	22	0

दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

समूह	दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार कुल प्रतिनिधित्व						सीधी भर्ती					पदोन्नति					प्रतिनियुक्ति				
	कुल कर्मचारी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी
समूह 'क'	399	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
समूह 'ख'	839	2	0	13	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह 'ग'	4157	11	30	44	0	15	0	1	2	0	0	2	6	5	0	0	0	0	0	0	0
कुल	5395	14	30	62	0	18	0	1	2	0	0	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0

नोट:

पी- दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि

क्यू- बधिर और न्यून श्रवण क्षमता

आर- लोकोमोटर दिव्यांगता जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, उपचारित कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमले से पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं

एस- ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक बीमारी

पी से एस तक की विभिन्न दिव्यांगता

15. अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी)

15.1 आईएफएडी ने वर्ष 1979 से अब तक भारत में 34 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है, जिनके लिए कुल लगभग 1.375 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता की गई है। इनमें से 30 परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 4 परियोजनाएँ, जिनकी कुल सहायता राशि 325.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन हैं। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान आईएफएडी बोर्ड की स्वीकृति हेतु भारत की 02 परियोजनाएँ, जिनकी कुल राशि 132.03 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, पाइपलाइन में शामिल की गई हैं।

15.2 यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी)

15.2.1 यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी), जिसका मुख्यालय लंदन में है, की स्थापना वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद मध्य एवं पूर्वी यूरोप की पूर्व अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करने तथा उन्हें बहुदलीय लोकतंत्र और बहुलवाद के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध खुले, बाजार-आधारित अर्थतंत्रों में विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

15.2.2 ईबीआरडी मध्य यूरोप से लेकर मध्य एशिया तथा दक्षिणी एवं पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र तक 30 से अधिक देशों में कार्यरत है। इसके संचालन क्षेत्र का विस्तार अब उत्तरी अफ्रीकी देशों तक भी हो गया है। ईबीआरडी बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) में एकमात्र ऐसा बैंक है जो मुख्य रूप से गैर-संप्रभु परिचालनों पर केंद्रित है।

15.2.3 ईबीआरडी का एक स्पष्ट राजनीतिक जनादेश है—पहला, लोकतंत्र निर्माण गतिविधियों का समर्थन करना; दूसरा, ईबीआरडी के पास कोई रियायती ऋण खिड़की नहीं है। वर्तमान में, बैंक के 77 सदस्य देश (पाँच महाद्वीपों से), यूरोपीय संघ तथा यूरोपीय निवेश बैंक इसके सदस्य हैं।

15.2.4 भारत जुलाई 2018 में ईबीआरडी का 69वाँ शेयरधारक बना और वर्तमान में बैंक में भारत की हिस्सेदारी 0.033 प्रतिशत है। भारत एक गैर-उधारकर्ता सदस्य है तथा पुर्तगाल निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें पुर्तगाल, ग्रीस और सैन मरिनो शामिल हैं।

15.2.5 भारत ने अपने चुकता अंश के रूप में 1.79 मिलियन यूरो (₹14.74 करोड़) का भुगतान किया है तथा इसकी प्रारंभिक सदस्यता 986 शेयरों की है। भारत बैंक का सदस्य 179 चुकता शेयरों तथा 807 कॉल योग्य शेयरों के साथ बना। वर्ष 2024 में, ईबीआरडी की सामान्य चुकता पूंजी वृद्धि के अंतर्गत भारत ने ईबीआरडी के अतिरिक्त 132 शेयरों की सदस्यता ली है।

15.2.6 भारत का प्रतिनिधित्व ईबीआरडी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के वित्त मंत्री द्वारा किया जाता है तथा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के सचिव वैकल्पिक गवर्नर होते हैं।

15.3 न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)

15.3.1 भारत न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से वित्तपोषण प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, जिसमें विद्युत, जल, परिवहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सतत विकास एवं सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2016 (एनडीबी के परिचालन काल) से अब तक, एनडीबी द्वारा भारत में 29 परियोजनाएँ (25 संप्रभु तथा 4 गैर-संप्रभु परियोजनाएँ) स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल वित्तीय सहायता 9.127 अरब अमेरिकी डॉलर है।

15.3.2 इसमें कोविड-19 संकट से उबरने एवं आर्थिक सुदृढ़ता हेतु भारत को प्रदान की गई 2 अरब अमेरिकी डॉलर की पुनर्प्राप्ति सहायता भी शामिल है। 25 संप्रभु परियोजनाओं में से 18 परियोजनाएँ (5.7 अरब अमेरिकी डॉलर) प्रगति पर हैं, जबकि 7 परियोजनाएँ (2.8 अरब अमेरिकी डॉलर) पूर्ण हो चुकी हैं।

15.3.3 इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत ने 02 परियोजनाओं (731 मिलियन अमेरिकी डॉलर) पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही, NDB की स्थापना से अब तक 4 गैर-संप्रभु/निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को 588 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वीकृति प्रदान की गई है।

15.4 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)

15.4.1 एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के अंतर्गत स्वीकृत वित्तपोषण के संदर्भ में भारत सबसे बड़ा ग्राहक देश है। वर्ष 2016 से अब तक, एआईआईबी द्वारा भारत में 34 संप्रभु परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनकी कुल वित्तीय सहायता 10.76 अरब अमेरिकी डॉलर है। ये परियोजनाएँ ऊर्जा, परिवहन, जल, शहरी विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।

15.4.2 इन 34 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाएँ (7.4 अरब अमेरिकी डॉलर) कार्यान्वयनाधीन हैं, 8 परियोजनाएँ (3 अरब अमेरिकी डॉलर) पूर्ण हो चुकी हैं तथा 2 परियोजनाएँ (522 मिलियन अमेरिकी डॉलर) एआईआईबी बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं और हस्ताक्षर प्रक्रिया में हैं।

15.4.3 इसके अतिरिक्त, एआईआईबी की स्थापना से अब तक 26 गैर-संप्रभु/निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को 2.18 अरब अमेरिकी डॉलर की स्वीकृति प्रदान की गई है।

15.5 अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी)

15.5.1 अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास वित्त संस्थान है, जिसकी स्थापना अफ्रीकी देशों (क्षेत्रीय सदस्य देश – आरएमसी) के आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान देने के उद्देश्य से की गई थी। एएफडीबी की स्थापना 14 अगस्त 1963 को सूडान के खार्तूम में हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर हुई, जो 10 सितंबर 1964 को प्रभावी हुआ। एएफडीबी समूह में तीन संस्थाएँ शामिल हैं—अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी), अफ्रीकी विकास कोष (एडीएफ) और नाइजीरिया ट्रस्ट फंड (एनटीएफ)। इसका मुख्यालय आबिदजान, कोट डी'वोआर में स्थित है।

15.5.2 बैंक के 54 अफ्रीकी देश क्षेत्रीय सदस्य देश (आरएमसी) हैं तथा 27 गैर-अफ्रीकी देश गैर-क्षेत्रीय सदस्य देश (एनआरएमसी) हैं। प्रारंभ में केवल स्वतंत्र अफ्रीकी देश ही इसके शेयरधारक बन सकते थे, परंतु वर्ष 1982 में गैर-अफ्रीकी देशों के लिए भी सदस्यता खोल दी गई।

15.5.3 भारत एएफडीबी का एक दीर्घकालिक भागीदार है। भारत ने 1982 में अफ्रीकी विकास कोष (एडीएफ) तथा 1983 में अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) में गैर-क्षेत्रीय/गैर-उधारकर्ता सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की। एएफडीबी के सभी 81 सदस्य (54 RMCs एवं 27 एनआरएमसी) 20 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित हैं। भारत NIIC – नॉर्डिक इंडिया आयरलैंड निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड शामिल हैं।

15.5.4 भारत के पास एएफडीबी में कुल 42,001 शेयर तथा 0.289 प्रतिशत मतदान हिस्सेदारी है। एडीएफ में भारत की मतदान हिस्सेदारी 0.182 प्रतिशत है। भारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) की वार्षिक बैठकों में

भाग लेता है तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (बीओडी) की बैठकों में अपने विचार प्रस्तुत करता है। भारत का प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में वित्त मंत्री द्वारा तथा वैकल्पिक गवर्नर के रूप में आर्थिक कार्य विभाग के सचिव द्वारा किया जाता है।

15.5.5 एडीएफ-15 तक भारत ने ₹601.9 करोड़ की प्रतिबद्धता की है। एडीएफ-16 के लिए भारत ने ₹152.64 करोड़ शुद्ध अनुदान के रूप में तथा ₹3.69 करोड़ अनुदान क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किए। आगामी चक्र एडीएफ-17 (2026-28) के लिए भारत ने हाल ही में ₹176.29 करोड़ शुद्ध अनुदान तथा ₹9.23 करोड़ अनुदान क्षतिपूर्ति के रूप में योगदान देने की प्रतिबद्धता की है। इसके अतिरिक्त, अब तक बहुपक्षीय ऋण राहत पहल (एमडीआरआई) के अंतर्गत ₹54.74 करोड़ का योगदान किया गया है।

15.5.6 समग्र रूप से, इन योगदानों से बैंक की दस वर्षीय रणनीति और "हाई 5" प्राथमिकताओं के अनुरूप अफ्रीका की विकास दृष्टि से संबद्ध गतिविधियों को वित्तपोषित करने में सहायता मिली है।

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य)

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूह-वार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	339	94	40	114	10	13	03	02	05	02	12	-	02	03	-	20	02	01	03	-
समूह-ख	255	50	34	56	08	31	11	06	07	07	19	04	04	01	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	182	65	05	32	03	02	-	-	-	01	06	03	-	03	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	776	209	79	202	21	46	14	08	12	10	37	07	06	07	-	20	02	01	03	-

अनुलग्नक II

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य)

विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व																							
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					फैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क	104	01	-	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ख	102	-	-	05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	24	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	230	01	-	09	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट:-

- (i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
(ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति)।
(iii) ओएच का अर्थ है अस्थि विकलांग (गतिशील अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति) या
(iv) आईडी का अर्थ है बौद्धिक अक्षमता।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	83	7	3	16	3	15	2	1	4	2	6	1		2		11	1	1	1	
समूह-ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए)

दिनांक 30.11.2025 तक विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व																							
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क	1	1	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1	1					1	1		2		1	1										

राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई)

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का समूहवार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	2	1	0	0	0	शून्य					शून्य					शून्य				
समूह-ख	15	2	0	4	0															
समूह-ग	23	2	2	8	0															
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	लागू नहीं																			
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	लागू नहीं																			
कुल	40	5	2	12	0	शून्य					शून्य					शून्य				

अनुलग्नक II

राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई)

दिनांक 30.11.2025 तक विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व																							
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-ख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-ग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	लागू नहीं					लागू नहीं				लागू नहीं					लागू नहीं				लागू नहीं				
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	लागू नहीं					लागू नहीं				लागू नहीं					लागू नहीं				लागू नहीं				
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- नोट: -
- (i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
 - (ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति)।
 - (iii) ओएच का अर्थ है अस्थि विकलांग (गतिशील अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति) या
 - (iv) आईडी का अर्थ है बौद्धिक अक्षमता।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े 30.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार।																		
श्रेणी**	कुल प्रतिनिधित्व (दिनांक 30.11.2025 तक)					वर्ष 2025 के दौरान सीधी भर्ती (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)					वर्ष 2025 के दौरान पदोन्नति द्वारा (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)			वर्ष 2025 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
अधिकारी	1044**	147	62	299	30	18	2	0	7	0	196	36	13	6	0	1	0	
सचिव	64	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कनिष्ठ सहायक	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संदेशवाहक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	1109	147	62	301	30	18	2	0	7	0	196	36	13	6	0	1	0	0

* सेबी अपने कर्मचारियों को 'क', '13', 'ग', 'घ' समूहों में वर्गीकृत नहीं करता है। बोर्ड के कर्मचारियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:-

(क) अधिकारी (श्रेणी 'क', 'ख', 'ग', 'घ', 'ड', 'च' और कार्यकारी निदेशक) (ख) सचिव (सचिवीय कर्मचारी, लेखा सहायक और पुस्तकालय सहायक (श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग')) (ग) कनिष्ठ सहायक

**इसमें संविदा/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं

दिनांक 30.11.2025 तक दिव्यांगजनों के प्रतिनिधित्व से संबंधित आंकड़े																				
श्रेणी**	कुल प्रतिनिधित्व (दिनांक 30.11.2025 तक)					वर्ष 2025 के दौरान सीधी भर्ती (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)					वर्ष 2025 के दौरान पदोन्नति द्वारा (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)					वर्ष 2025 के दौरान प्रतिनियुक्ति द्वारा (दिनांक 01.04.2025 - 30.11.2025)				
	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी	पी	क्यू	आर	एस	टी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अधिकारी	18	8	11	1	1	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
सचिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कनिष्ठ सहायक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संदेशवाहक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	18	8	11	1	1	1	0	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	

** सेबी अपने कर्मचारियों को 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' समूहों में वर्गीकृत नहीं करता है। बोर्ड के कर्मचारियों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

(क) अधिकारी (श्रेणी 'क', '13', 'ग', 'घ', 'ड', 'च' और कार्यकारी निदेशक)

(ख) सचिव (सचिव कर्मचारी, लेखा सहायक और पुस्तकालय सहायक (श्रेणी 'क', 'ख' और 'ग')) (ग) कनिष्ठ सहायक

पी - अंधापन और कमजोर दृष्टि

क्यू - बहरापन और कम सुनने की क्षमता

आर - चलने-फिरने में अक्षमताएँ, जिनमें मस्तिष्क पक्षाघात, कुछ रोग से ठीक हुए मरीज, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय विकृति शामिल हैं

एस - ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी

टी - क से घ तक की कई अक्षमताएँ, जिनमें बहरेपन और अंधेपन का संयोजन शामिल है

सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का समूहवार प्रतिनिधित्व।																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	397	51	19	97	5	15	2	1	2	2	39	5	1	5	3	0	0	0	0	0
समूह-ख	791	117	74	174	9	6	0	0	3	1	46	9	4	3	0	0	0	0	0	0
समूह-ग	3838	766	314	1026	62	22	3	0	12	4	515	91	42	91	3	56	21	7	13	0
कुल	5026	934	407	1297	76	43	5	1	17	7	600	105	47	99	6	56	21	7	13	0

अनुलग्नक II

सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल)

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का समूहवार प्रतिनिधित्व।																								
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																		
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
समूह-क	397	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह-ख	791	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
समूह-ग	3838	9	22	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	1	2	6	0	
कुल	5026	11	22	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	1	2	6	0	
(i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)। (ii) एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति)। (iii) ओएच का अर्थ है अस्थि विकलांग (गतिशील अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति) या (iv) आईडी का अर्थ है बौद्धिक अक्षम																								

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (एसएटी)

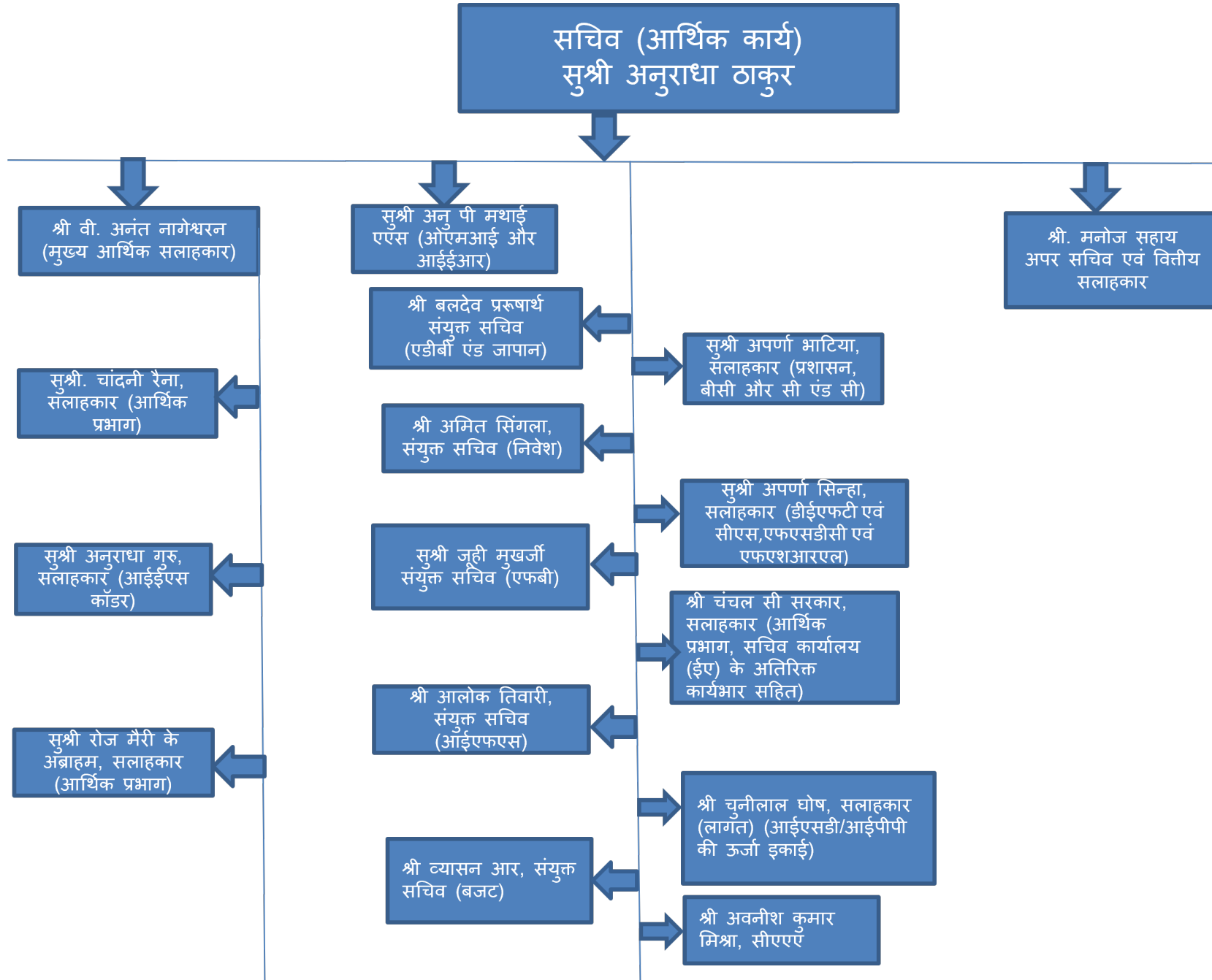
अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का समूहवार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य विधियों द्वारा नियुक्ति				
	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस	कुल	अजा	अजजा	अपिव	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ख	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	11	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	22	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई (एसएटी)

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विकलांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व																							
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेण्डर वर्ष 2025 के दौरान (अर्थात दिनांक 01.01.2025 से 31.11.2025 तक) की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या				नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)	कुल	दृष्टिबाधित (वीएच)	श्रवण बाधित (एचएच)	अस्थि विकलांग (ओएच)	बौद्धिक अक्षमता (आईडी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह-क	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ख	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-ग	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह-घ (सफाई कर्मचारी)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	22	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट:-

- वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (दृष्टिहीन या कमजोर दृष्टि वाला व्यक्ति)।
- एचएच का अर्थ है श्रवण बाधित (बहरेपन से पीड़ित व्यक्ति)।
- ओएच का अर्थ है अस्थि विकलांग (गतिशील अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति) या
- आईडी का अर्थ है बौद्धिक अक्षम



अध्याय - II

व्यय विभाग

1. कार्मिक प्रभाग

1.1 कार्मिक प्रभाग अपर सचिव (कार्मिक) के अधीन कार्य करता है और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कार्मिक मामलों जैसे वेतन और भत्तों का विनियमन, पेंशन संबंधी नीतिगत मामले, पदों के सृजन और उन्नयन के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों में स्टाफिंग, और संवर्ग की समीक्षा सहित विभिन्न वित्तीय नियमों और विनियमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

1.2 यह प्रभाग महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थ वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और अन्य लाभों में परिवर्तन के प्रस्तावों पर भी काम करता है। व्यय प्रबंधन पर व्यापक अनुदेश, जिसमें मितव्ययिता उपाय और व्यय की गुणवत्ता में सुधार के उपाय, जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) के माध्यम से, कार्मिक प्रभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।

1.3 यह प्रभाग सामान्य वित्तीय नियमावली और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमावली को प्रशासित करता है, जिसमें उसके स्पष्टीकरण/संशोधन जारी करना शामिल है, और केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करता है। सामान्य वित्तीय निहितार्थ के सभी विधायी प्रस्तावों की कार्मिक प्रभाग में जांच की जाती है।

1.4 व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को सेना, नौसेना, वायु सेना, डीआरडीओ और तटरक्षक बल से संबंधित रक्षा मंत्रालय से पूंजी अर्जन/कार्य प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय द्वारा निविदा मूल्यांकन और मूल्य वार्ता किए जाने के बाद वित्त मंत्रालय में प्राप्त होते हैं। वित्त मंत्रालय इन प्रस्तावों की मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है, हालांकि प्रस्तावों में महत्वपूर्ण वित्तीय निहितार्थ हैं। वित्त मंत्रालय की स्थिति भी अनूठी है क्योंकि विदेश मंत्रालय (एमईए) और गृह मंत्रालय (एमएचए) जैसे मंत्रालयों से आने वाले सीसीएस के अनुमोदन की आवश्यकता वाले बड़ी संख्या में प्रस्तावों की भी वित्त मंत्रालय में जांच की जाती है। वित्त मंत्रालय का यह प्रयास है कि समान सुरक्षा वातावरण को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों का कोई दोहराव न हो, जिसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कोई अन्य मंत्रालय हितधारक हो।

1.5 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएस), भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएसएस) और भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएसएस) से संबंधित सेवा मामले इस प्रभाग द्वारा निस्तारित किए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा वित्त मंत्री कार्यालय को भी प्रशासनिक सहायता प्रदान की जाती है।

1.6 यह प्रभाग व्यय विभाग के समग्र प्रशासन को भी संभालता है और वित्त मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी/निजी सचिवों के स्तर तक सभी केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस)/केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस)/केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) के संवर्ग को नियंत्रित करता है, इसके अलावा यह समग्र रूप से वित्त मंत्रालय के लिए संसदीय कार्य के साथ-साथ सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) से संबंधित मामलों का समन्वय भी करता है।

1.7 वेतन अनुसंधान एकक (पीआरयू)

1.7.1 वेतन अनुसंधान एकक की स्थापना 1968 में की गई थी और यह केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों और संघ शासित प्रशासन के कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों के साथ-साथ वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्तों पर किए गए वास्तविक व्यय के आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण से संबंधित है। यह एकक "केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट" शीर्षक का एक वार्षिक प्रकाशन निकालता है। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने नियमित सिविल कर्मचारियों के संबंध में वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्तों पर किए गए व्यय के बारे में सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करती है। यह मंत्रालय/विभाग-वार और समूह-वार स्वीकृत पदों की संख्या और पद पर विद्यमान व्यक्तियों की संख्या के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है।

1.8 आरटीआई प्रकोष्ठ

1.8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को उसकी वास्तविक भावना में क्रियान्वित किया गया है तथा अधिनियम के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा अपीलों पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार आरटीआई अनुभाग द्वारा तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा संचालित की जाती है। आरटीआई अनुभाग केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के साथ नजदीकी समन्वय में काम करता है तथा यह अनुभाग इस विभाग की आरटीआई की तिमाही रिपोर्ट सीआईसी पोर्टल पर अपलोड करता है तथा आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार सीआईसी सुनवाई नोटिसों पर आवश्यक कार्रवाई भी करता है। वर्ष 2025-26 के दौरान, 6 सीआईसी सुनवाई नोटिस प्राप्त हुए तथा उन पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसके अलावा 5807 आरटीआई आवेदन और 309 आरटीआई अपीलों 'ऑनलाइन' प्राप्त हुए तथा 704 आरटीआई आवेदन और 20 आरटीआई अपीलों 'भौतिक रूप' में प्राप्त हुई, जिनका समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया गया।

1.9 विधि प्रकोष्ठ

1.9.1 विधायी अनुभाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की केंद्रीय रजिस्ट्री, विभिन्न उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों सहित अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सभी विधायी मामलों के संबंध में व्यय विभाग के 'नोडल अनुभाग' के रूप में कार्य करता है। यह सभी न्यायालयी मामलों के संबंध में व्यय विभाग के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों और विधि और न्याय मंत्रालय के साथ समन्वय भी करता है। वर्ष 2024-25 के दौरान, कुल 192 न्यायालयी मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें व्यय विभाग प्रतिवादियों में से एक था। इसके अतिरिक्त,

व्यय विभाग के विधि प्रकोष्ठ ने विभिन्न न्यायालयों/ट्रिब्यूनलों से प्राप्त 821 पावतीयों (कानूनी नोटिस, आदेश, रिट याचिकाएं, मूल आवेदन आदि) पर कार्रवाई की और उन्हें इस विभाग के संबंधित अनुभागों/शाखाओं/प्रभागों के साथ-साथ संबंधित विभागों/मंत्रालयों को, जहां भी लागू हो, अग्रेषित किया ताकि समयबद्ध तरीके से ऐसे मामलों का उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। विधायी अनुभाग मासिक आधार पर उन लंबित न्यायालयी मामलों की जानकारी भी संकलित करता है, जिनमें व्यय विभाग प्रतिवादियों में से एक है। यह एलआईएमबीएस पोर्टल पर दर्ज किए गए सभी मामलों की निगरानी करता है और उनकी स्थिति को समय पर अद्यतन करना सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, विधायी अनुभाग द्वारा विधायी मामलों पर विधि कार्य विभाग से प्राप्त संसदीय प्रश्नों की जांच की जाती है और उनका उत्तर व्यय विभाग के अंतर्गत संबंधित अनुभागों के परामर्श से दिया जाता है।

1.10 कर्मचारी निरीक्षण एकक (एसआईयू)

1.10.1 कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.) की स्थापना 1964 में प्रशासनिक दक्षता के अनुरूप सरकारी संगठनों में कर्मचारियों को रखने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने तथा उन सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में कार्य-निष्पादन मानकों और कार्य मानदंडों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी, जो पूरी तरह या वास्तव में सरकारी अनुदानों पर निर्भर हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन जो एस.आई.यू. के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा गठित समिति, जिसमें एस.आई.यू. का एक प्रतिनिधि मुख्य सदस्य के रूप में होता है, ऐसे संगठनों का अध्ययन करती है।

1.10.2 वित्तीय सलाहकार (एफए) व्यय विभाग में एसआईयू और अन्य मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों के बीच मुख्य कड़ी होते हैं। एसआईयू द्वारा कर्मचारी अध्ययन के सभी अनुरोध विभागों में संबंधित एफए के माध्यम से भेजे जाते हैं। अध्ययन रिपोर्ट एसआईयू अध्ययन दल द्वारा 'ऑन द स्पोट' कार्य मापन अध्ययन किए जाने के पश्चात जारी की जाती है, जिसमें संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा तथा एसआईयू की मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में प्रावधान को अंतिम रूप देना शामिल है। एसआईयू की अंतिम रिपोर्ट को संबंधित संगठन द्वारा इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

1.11 वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण विकास/नीति संबंधी निर्णय

1.11.1 सामान्य वित्तीय नियमावली भारत में सार्वजनिक वित्त को नियंत्रित करने वाले नियमों और आदेशों का एक व्यापक समूह है। समय-समय पर, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने या दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए नोडल विभागों/प्रभागों द्वारा इन नियमों में विभिन्न संशोधन किए जाते हैं। इस विभाग को ऐसे सभी संशोधनों को द्विवार्षिक रूप से समेकित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और ऐसा अंतिम संकलन (31.07.2025 तक) 19.09.2025 को जारी किया गया था।

1.11.2 आठवां केंद्रीय वेतन आयोग

भारत सरकार ने दिनांक 03 नवंबर, 2025 के संकल्प के माध्यम

से निम्नलिखित को शामिल करते हुए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति का निर्णय लिया है:-

अध्यक्ष - श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई

सदस्य (अंशकालिक) - प्रो. पुलक घोष

सदस्य-सचिव - श्री पंकज जैन

इस संकल्प में आयोग के विचारार्थ विषय का भी निर्धारण किया गया है। आठवां सीपीसी इसके गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। दिनांक 03.11.2025 के संकल्प की एक प्रति अनुबंध-1 में भी संलग्न है।

2. लोक वित्त-राज्य प्रभाग

2.1 पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता:

2.1.1 अर्थव्यवस्था में पूंजीगत व्यय का गुणक कारक अधिक होता है और यह निजी निवेश को आकर्षित करता है तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आपूर्ति पक्ष की क्षमता को बढ़ाता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने अक्टूबर, 2020 में 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना' प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत पूंजीगत व्यय बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में सहायता के लिए राज्यों को 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकारों की योजना के प्रति अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया और योजना को जारी रखने के उनके अनुरोध को देखते हुए, योजना को वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में बढ़ी हुई आवंटन राशि के साथ जारी रखा गया। योजना के अंतर्गत परिव्यय वित्त वर्ष 2020-21 में 12,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,50,000 करोड़ रुपये हो गया है।

2.1.2 वर्ष 2025-26 में, योजना में भाग-I से भाग-X तक कुल दस भाग शामिल हैं। वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत, विधानमंडल वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों, अर्थात् दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पुडुचेरी को भी पहली बार योजना में शामिल किया गया है। योजना के भाग-I (शर्तरहित) के अंतर्गत 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी पसंद की पूंजीगत परियोजनाओं का प्रस्ताव कर सकते हैं, जिन्हें योजना के अंतर्गत वित्त पोषित किया जाएगा। 80,000 करोड़ रुपये का परिव्यय सुधार-केंद्रित और क्षेत्र-विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है। वर्ष 2025-26 की योजना के अंतर्गत शेष 2000 करोड़ रुपये का आवंटन उन राज्यों के लिए विशेष आवंटन होगा, जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान किसी विशेष कारण/स्थिति के कारण राजस्व संग्रह में नुकसान हुआ है।

योजना के अंतर्गत परिकल्पित सुधार निम्नलिखित हैं:

- खनन क्षेत्र सुधार
- पुराने वाहनों को स्क्रेप करना और सड़क सुरक्षा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन
- ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार
- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

- v. शहरी क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा भूमि संबंधी सुधार
- vi. वित्तीय प्रबंधन में दक्षता
- vii. शहरी नियोजन सुधार

2.1.3 दिनांक 17.11.2025 तक, एसएससीआई 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (विधानमंडल सहित) को ₹ 54902.34

करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एसएससीआई के अंतर्गत इसके प्रारंभ से, अर्थात् वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक (17.11.2025 तक) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (वर्ष 2025-26 में एसएससीआई में शामिल किए गए) को कुल ₹ 421152.34 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। एसएससीआई योजना के अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई राशि निम्नलिखित है:

(करोड़ ₹ में)

	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (17.11.2025 तक)	कुल
राज्य सरकारों को जारी की गई कुल राशि	11830	14186	81196	109554	149484	54902.34	421152.34

‘पूँजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26’ के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 2025-26 (17.11.2025 तक) के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘विशेष सहायता’ (ऋण के रूप में) के रूप में जारी की गई कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

2.2 राज्यों को विशेष सहायता:

2.2.1 14वें वित्त आयोग के कार्यान्वयन के पश्चात, राज्यों को बजट लाइन “राज्यों को विशेष सहायता” के माध्यम से स्पिलओवर प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाया गया, जिसके लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया है और अन्य आवश्यकता आधारित सहायता। तदनुसार, 2015-16 में ₹ 10,890 करोड़, 2016-17 में ₹ 10,900 करोड़, 2017-18 में ₹ 6,950.50 करोड़, 2018-19 में ₹ 4,680.81 करोड़, 2019-20 में ₹ 1,623.70 करोड़, 2020-21 में ₹ 1,948.66 करोड़ और 2021-22 में ₹ 3,766.39 करोड़, 2022-23 में ₹ 2271.233 करोड़, 2023-24 में ₹ 11695.208 करोड़ और 2024-25 में ₹ 3350 करोड़ ‘विशेष सहायता’ के रूप में जारी किए गए।

2.3 राज्यों की उधारी

2.3.1 15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के बराबर निवल उधार सीमा (एनबीसी) की अनुमति दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्यों की एनबीसी राज्यों के जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के बराबर 10,29,659 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसकी सूचना राज्य सरकारों को दिनांक 04.04.2025 के वार्षिक उधार सीमा दिशानिर्देशों के माध्यम से दी गई है। तदनुसार, राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिनांक 07.11.2025 तक राज्यों को 8,89,832 करोड़ रुपये के खुला बाजार उधार (ओएमबी) की सहमति और 98,699.16 करोड़ रुपये के परक्राम्य ऋण (एनएल) जारी किए गए हैं।

2.3.2 इसके अलावा, राज्यों को वित्तीय वर्ष 2025-26 से संबंधित अपने कर्मचारियों के अंशदान में नियुक्ता और कर्मचारी के हिस्से के बराबर अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है, जो वास्तव में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के दिशानिर्देशों

के अनुसार नामित प्राधिकारी अर्थात् ‘नेशनल सिविलीटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के पास जमा है, जो वर्ष 2025-26 के लिए जीएसडीपी के 3% की सामान्य निवल उधार सीमा के अतिरिक्त है। इस अतिरिक्त उधार की अनुमति पेंशन लेखांकन में भिन्नता को दूर करने, जहां ‘पे-एज-यू-गो’ प्रणाली का पालन करने वाले राज्यों में भविष्य की पेंशन देनदारियों को प्रतिबिंबित न करने के कारण राजकोषीय घाटा कम होता है, और साथ ही सभी अंशदान करने वाले राज्यों के लिए एक उचित, समान और पूर्ण मानक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए, राज्यों को नियुक्ता और कर्मचारी के अंशदान के बराबर 69,768.95 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई है।

2.3.3 15वें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्र में राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.50 प्रतिशत के कार्य निष्पादन आधारित अतिरिक्त उधार अन्तर की सिफारिश की है। जीएसडीपी के 0.50 प्रतिशत की यह अतिरिक्त उधारी एनबीसी से अतिरिक्त है। अतिरिक्त उधार अन्तर का उद्देश्य क्षेत्र की परिचालन और आर्थिक दक्षता में सुधार करना और मूल्य पर दी गई बिजली की खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह विशेष व्यवस्था 2021-22 से 2024-25 तक चार वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अनुशंसित की गई है। इस विशेष व्यवस्था को वर्ष 2025-26 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, राज्य जीएसडीपी के 0.5% अर्थात् 1,71,612 करोड़ रुपये के अतिरिक्त उधार के लिए पात्र हैं, जो विद्युत क्षेत्र में कार्य निष्पादन से जुड़ा है, जैसा कि इस विभाग द्वारा दिनांक 02.09.2015 को जारी दिशानिर्देशों में बताया गया है।

2.3.4 वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत क्षेत्र में राज्य के कार्य निष्पादन के आकलन के बाद विद्युत मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त उधार की अनुमति दी जाती है।

2.4 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

2.4.1 बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए) सामान्य श्रेणी के राज्यों को उन्हीं शर्तों और नियमों पर बैंक टू बैंक आधार पर दी जाती है, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा दाता एजेंसियों से

ये ऋण प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के मामले में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत उन्हें ईएपी के लिए अनुदान: ऋण अनुपात 90:10 में सहायता मिली है। आर्थिक कार्य विभाग के सहायता नियंत्रक, लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यालय की सिफारिशों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मांग संख्या 42 के अंतर्गत 07 नवंबर, 2025 तक राज्यों को 'ईएपी के लिए एसीए' के अंतर्गत कुल बजट अनुमान 52,730.00 करोड़ रुपये के सापेक्ष 27,879.71 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

2.5 नकद ऋण सीमा

2.5.1 राज्यों को खाद्यान्न खरीद कार्यों के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दिनांक 05.11.2025 तक 99,421.11 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा का लाभ उठाने की भी अनुमति दी गई है।

2.6 मांग-42 “राज्यों को अंतरण” के अंतर्गत वित्त आयोग अनुदान

2.6.1 वित्त आयोग प्रभाग (व्यय विभाग) केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर कार्रवाई और अनुवर्ती कार्रवाई करता है, जिसमें क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा अनुशंसित अनुदानों को जारी करना भी शामिल है।

2.6.2 15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) की वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अधिनिर्णय अवधि के लिए स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर, इस विभाग ने आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी किए हैं, जिनमें अंतरण-पश्च राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान (ग्रामीण और शहरी), स्थानीय निकायों के माध्यम से वितरित किए जाने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं। अभी तक, वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान, कुल बजटीय प्रावधान 145826.66 करोड़ रुपये में से राज्य सरकारों को कुल 77797.02 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान जारी किए गए सहायता अनुदानों का मद-वार विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	घटक	वर्ष 2025-26 के लिए आवंटन	वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) के दौरान जारी किए गए अनुदान
1.	अंतरण-पश्च राजस्व घाटा अनुदान	13705.00	10278.75
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए अनुदान सहायता	21575.20	18276.4
3.	राज्य आपदा शमन कोष के लिए अनुदान सहायता	5393.80	5288.8

4.	ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सहायता	48573.00	16788.3
5.	शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान सहायता	26158.00	8870.9
6.	स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान सहायता	15271.66	12968.36
7.	राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता	12048.00	4177.15
8.	राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से सहायता	3012.00	923.37
9.	साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान	90.00	224.99
	कुल योग	145826.66	77797.02

2.6.3 प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्यों के हाथ मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गृह मंत्रालय से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2025-26 के दौरान एनडीआरएफ से 4177.15 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

2.7 व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी)

2.7.1 व्यय प्रबंधन आयोग (ईएमसी) का गठन दिनांक 04.09.2014 को सार्वजनिक व्यय की दक्षता बढ़ाने के तरीकों की सिफारिश करने, केंद्र सरकार द्वारा व्यय के प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा करने और राजकोषीय अनुशासन से समझौता किए बिना विकास हेतु व्यय की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक राजकोषीय गुंजाइश बनाने के तरीकों का सुझाव देने के लिए किया गया था। आयोग ने मार्च, 2016 तक अपनी रिपोर्ट चार भागों में प्रस्तुत की। ईएमसी रिपोर्ट में कार्यान्वयन योग्य पाए गए 181 कार्रवाई योग्य बिंदुओं में से 165 को पहले ही लागू किया जा चुका है। शेष सिफारिशों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए लिया गया है और कार्यान्वयन जारी है।

2.7.2 ईएमसी की सिफारिशों के अनुसार, व्यय विभाग की वेबसाइट पर स्वायत्त निकायों (एबी) का एक डाटाबेस संकलित किया गया है और 69 मंत्रालयों/विभागों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों से संबंधित डाटा अपलोड किए हैं। पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी का उपयोग विभिन्न मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा समीक्षा और निर्णय लेने हेतु किया जा रहा है।

2.7.3 व्यय विभाग ने युक्तिकरण के लिए 23 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 231 स्वायत्त निकायों की समीक्षा भी की है। समीक्षा रिपोर्ट संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सिफारिशों को लागू करने और विलयन, विघटन तथा विनियोजन के माध्यम से स्वायत्त निकायों की संख्या कम करने के लिए आगे की कार्रवाई हेतु भेजी गई है।

2.7.4 ईएमसी की सिफारिशों के अनुसार, सरकार उधार की लागत को कम करने और स्वायत्त निकायों को निधि प्रवाह में दक्षता बढ़ाने के लिए, सरकार को सभी स्वायत्त निकायों को धीरे-धीरे ट्रेजरी एकल खाता (टीएसए) प्रणाली के अंतर्गत लाना चाहिए। सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने का निर्णय लिया और तदनुसार, दिनांक 27 जुलाई, 2017 को दिशानिर्देश जारी किए, जिन्हें दिनांक 24 फरवरी, 2022 को संशोधित किया गया और टीएसए प्रणाली के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए दिनांक 20.10.2022 को पुनः संशोधित किया गया।

3. लोक वित्त केंद्रीय प्रभाग

3.1 लोक वित्त (केंद्रीय) प्रभाग को केंद्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सभी सार्वजनिक वित्तपोषित योजनाओं और परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन का कार्य सौंपा गया है। यह प्रभाग तीन एककों अर्थात् लोक वित्त (केंद्रीय-I), लोक वित्त (केंद्रीय-II) और लोक वित्त (केंद्रीय-III) में विभाजित है।

3.2 विकास योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में, बेहतर योजना/परियोजना निर्माण, आउटपुट, डिलिवरेबल्स, प्रभाव आकलन और अभिसरण दृष्टिकोण पर जोर देकर सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

3.3 सार्वजनिक संसाधनों के इष्टतम और केंद्रित उपयोग के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएस) को युक्तिसंगत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

3.4 लोक वित्त (केंद्रीय) प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग के परामर्श से सीपीएसई के मूल मंत्रालयों/विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनको वित्तीय सहायता के लिए तौर-तरीके तैयार करने में लगा हुआ है।

3.5 खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी से संबंधित विभिन्न मुद्दे, जिनमें उनकी मात्रा और हितधारकों को सहायता प्रदान करना शामिल है, को भी प्रभाग के भीतर निपटाया जाता है। यह प्रभाग सरकार पर न्यूनतम बोझ के साथ-साथ प्रभावी लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी नीतियों को आकार देने में संबंधित विभागों/मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से शामिल है।

3.6 पीएफसी प्रभाग डीबीटी मिशन के समन्वय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के विभिन्न मुद्दों, लाभार्थियों के डेटाबेस को आधार से जोड़ने और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के उपयोग से संबंधित मामलों को भी देखता है, ताकि सीएसएस, सीएस, सब्सिडी और अन्य व्यय सहित सभी केंद्रीय व्ययों पर शुरू-से-अंत तक डिजिटल सूचना उपलब्ध हो सके।

3.7 यह प्रभाग नीति आयोग के परामर्श से सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए परिणाम बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह आउटपुट-

आउटकम फ्रेमवर्क सभी सीएसएस और सीएस के लिए होगा, जो संबंधित मध्यम-अवधि फ्रेमवर्क में चिन्हित मापनीय परिणामों के भीतर काम करेंगे। वास्तविक और वित्तीय परिणाम वर्ष-दर-वर्ष आधार पर लक्षित किए जाते हैं।

3.8 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 7,84,196.447 करोड़ रुपये (7,75,452.147 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ) की लागत वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के 40 निवेश प्रस्तावों/योजनाओं की सिफारिश की।

3.9 साथ ही, इस अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने 1,36,226.06 करोड़ रुपये (56,840.18 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ) की राशि के 25 प्रस्तावों पर विचार किया और सिफारिश की।

3.10 मूल्यांकन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, संबंधित मंत्रालयों को ईएफसी/पीआईबी/एसएफसी/ डीआईबी प्रस्तावों को अपलोड करने, टिप्पणियां प्राप्त करने, बैठक की तारीखें निर्धारित करने और अनुमोदन के बाद कार्यवृत्त को भेजने के लिए अगस्त, 2017 से एक ऑनलाइन पोर्टल कार्यशील है।

3.11 16वें वित्त आयोग चक्र (1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ) के दौरान सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं को जारी रखने के लिए व्यय विभाग द्वारा कई पहलें की गई हैं। मई, 2025 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को जारी रखने के लिए मूल्यांकन हेतु विचारार्थ विषय (टीओआर) के नमूने जारी किए गए थे। योजनाओं को जारी रखने के सभी प्रस्तावों से पहले उचित मूल्यांकन और वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु उनमें आवश्यक पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है। मई, 2025 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक वित्त पोषित योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, ताकि मंत्रालयों और विभागों को इस प्रक्रिया, समय-सीमा और मूल्यांकन एवं अनुमोदन की संपूर्ण प्रक्रिया से जुड़ी सभी उम्मीदों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके बाद जुलाई, 2025 में सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में वित्तीय सलाहकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली और 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान जारी रहने वाली योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश जून, 2025 में जारी किए गए। तत्पश्चात् अक्टूबर, 2025 में केंद्र सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण व्यय सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के अनुरूप ईएफसी ज्ञापन के साथ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, अक्टूबर, 2025 के दौरान 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाली योजनाओं के लिए अंतिम ईएफसी ज्ञापन में आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) के लक्ष्यों/उपलब्धियों को शामिल करने और 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान इसे जारी रखने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए।

4. प्रापण नीति प्रभाग

4.1 इस विभाग में लोक प्रापण समिति (सीओपीपी) की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा नियमों का मसौदा तैयार करने और केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल की स्थापना जैसे संबंधित मामलों के लिए जून, 2011 में एक सार्वजनिक प्रापण प्रकोष्ठ (पीपीसी) की स्थापना की गई थी। प्रकोष्ठ को धीरे-धीरे सुदृढ़ किया गया और प्रापण नीति प्रभाग (पीपीडी) नामक एक प्रभाग बनाया गया।

4.2 यह प्रभाग निम्नलिखित कार्य करता है:-

- (i) सार्वजनिक प्रापण विधान और नियम, अधिसूचनाएं, उसके अंतर्गत आदेश;
- (ii) वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और अनुबंध प्रबंधन पर सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रशासन सहित सार्वजनिक खरीद से संबंधित नीतियां; अनिवार्य या अधिमाम्य खरीद से संबंधित नीतियां;
- (iii) खरीद से संबंधित दस्तावेजों के मानकीकरण से संबंधित मामले;
- (iv) सार्वजनिक खरीद से संबंधित जानकारी प्रकाशित करने के लिए स्थापित केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) से संबंधित सभी मामले;
- (v) इलेक्ट्रॉनिक खरीद से संबंधित मामले;
- (vi) खरीद से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पेशेवर मानक तथा इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और प्रमाणन आवश्यकताएं;
- (vii) सार्वजनिक खरीद से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ इंटरफेस।
- (viii) सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के परिचालन संबंधी मुद्दों से संबंधित मामले।
- (ix) सभी केंद्रीय मंत्रालयों से प्राप्त वैश्विक निविदा जांच (जीटीई) से संबंधित प्रस्तावों का निपटान।

4.3 नियमावलियों में संशोधन

4.3.1 व्यय विभाग ने तीन नियमावलियां प्रकाशित की हैं, अर्थात् माल के प्रापण के लिए नियमावली, 2017, परामर्श एवं अन्य सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली, 2017 और कार्यों के प्रापण के लिए नियमावली, 2019। तत्पश्चात्, तीनों प्रापण नियमावलियों (अर्थात् माल, सेवाएं और कार्य) का अद्यतन किया गया है (जून, 2022 में) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी सभी प्रापण संबंधी निर्देशों को इन नियमावलियों में शामिल कर लिया गया है।

4.3.2 यह विभाग इन नियमावलियों के संपूर्ण संशोधन की प्रक्रिया में है और इस प्रक्रिया में माल के प्रापण के लिए नियमावली, परामर्श सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली और गैर-परामर्श सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली (नए सिरे से विकसित) पहले ही जारी की जा चुकी है।

4.3.3 नियमावली के पिछले संशोधन के बाद सार्वजनिक प्रापण नीति में हुए कई बदलाव, जैसे कि नीतिगत पहल, स्पष्टीकरण, हितधारकों के विचार-विमर्श, को संशोधित नियमावली में शामिल किए गए हैं। संशोधित नियमावली का मुख्य उद्देश्य आपूर्तिकर्ताओं के लिए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना और प्रापण संबंधी पेशेवरों को अधिक स्पष्टता प्रदान करना है।

4.3.4 विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को फिर से लिखा गया है, जैसे कि विभिन्न संस्थाओं पर प्रयोज्यता की सीमा को स्पष्ट करना, प्रापण का वर्गीकरण, हितों के टकराव, ब्याज मुक्त अग्रिम भुगतान, निष्पादन प्रतिभूतियों के नए रूप, प्रापण की आउटसोर्सिंग, बोलियों का स्वतः विस्तार, मूल्य भिन्नता और क्षतिकरण की सीमा, कार्टल गठन को समाप्त करना, रिवर्स नीलामी, दर अनुबंध, एल 1 बोलीदाताओं द्वारा वापसी आदि।

4.3.5 जुलाई, 2024 में, माल के प्रापण के लिए संशोधित नियमावली, द्वितीय संस्करण, 2024 प्रकाशित की गई है। परामर्श सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली और गैर-परामर्श सेवाओं के प्रापण के लिए नियमावली अगस्त, 2025 में जारी की गई। ये नियमावलियां व्यय विभाग की वेबसाइट, अर्थात् doe.gov.in पर उपलब्ध हैं।

4.4 क्षमता निर्माण

4.4.1 यह आवश्यक है कि सार्वजनिक प्रापण प्रक्रिया में कार्यरत कार्यपालकों/अधिकारियों को सार्वजनिक प्रापण के सभी प्रासंगिक नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान हो। इस उद्देश्य के लिए, संबंधित कार्यपालकों/अधिकारियों को सार्वजनिक प्रापण के सभी प्रासंगिक नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान, विशाखापट्टनम में सार्वजनिक प्रापण पर साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), गुरुग्राम के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक प्रापण पर पायलट आधार पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई है। प्रति वर्ष लगभग 2000 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

5. राजभाषा

5.1 राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्यकलाप

व्यय विभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। व्यय विभाग का राजभाषा अनुभाग केन्द्रीय हिंदी समिति, संसदीय राजभाषा समिति, संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति, केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति और विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिए गए सुझावों और निर्देशों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए उत्तरदायी है। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना, जांच बिन्दु स्थापित करना, राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों को अधिसूचित करना, राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत संबंधित अनुभाग में किए जा रहे समस्त कार्यों को

राजभाषा हिन्दी में ही निष्पादित किए जाने हेतु व्यक्तिशः आदेश जारी करना, हिंदी भाषा प्रशिक्षण और हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा का आयोजन करना भी इसके अन्य कार्यों में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राजभाषा अनुभाग, राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में विभाग के अनुभागों/प्रभागों/कार्यालयों के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करता है।

5.2 राजभाषा अधिनियम, नियम और सांविधिक उपबंधों का अनुपालन

5.2.1 व्यय विभाग में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचनाओं, संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों आदि जैसे सभी दस्तावेजों और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने वाले सभी कागजातों को द्विभाषी रूप से अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किया गया है। इस विभाग में राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और विशेष रूप से राजभाषा नियम, 1976 के नियम-5 का अनुपालन उसकी मूल भावना के अनुरूप किया जा रहा है।

5.3 निगरानी और निरीक्षण

5.3.1 संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाने हेतु समय-समय पर पत्र/परिपत्र जारी किए गए।

5.3.2 वर्ष के दौरान, हिंदी अनुभाग द्वारा विभाग के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीनस्थ कार्यालयों/सम्बद्ध और स्वायत्त संस्थानों आदि का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। राजभाषायी निरीक्षण तथा निरीक्षण प्रश्नावली की समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सुझाव दिए गए। राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह कहती है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के साथ बढ़ाया जाए, जिसका इस विभाग द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है।

5.4 अनुवाद कार्य

5.4.1 व्यय विभाग के राजभाषा अनुभाग द्वारा विभिन्न मंत्रिमंडल नोटों, अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों, सामान्य आदेशों, निविदाओं, बजट संबंधी दस्तावेजों, अनुदान मांगों, वार्षिक रिपोर्ट, लिखित तथा मौखिक संसदीय प्रश्नोत्तरों, संसदीय आश्वासनों, संसदीय समितियों से संबंधित कागजात, प्रेस विज्ञप्तियों तथा वित्त मंत्री एवं वित्त राज्य मंत्री के कार्यालय से प्राप्त विभिन्न कागजातों आदि का अनुवाद नियमित रूप से तथा समयबद्ध आधार पर किया जाता है। अनुभाग में प्राप्त तत्काल प्रकृति के विभिन्न दस्तावेजों का अनुवाद भी नियमित रूप से तथा समयबद्ध तरीके से किया जाता है। संसद सदस्यों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर तत्परता से दिया जाता है और उन पर अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

5.5 हिंदी कार्यशाला

5.5.1 अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए विभाग में नियमित रूप से हिंदी

कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 94 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

5.6 हिंदी पखवाड़ा एवं पुरस्कार वितरण समारोह

5.6.1 हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा 14 एवं 15 सितंबर, 2025 के दौरान गांधीनगर, गुजरात में आयोजित हिंदी दिवस समारोह एवं 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभाग तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए तथा कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्य में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभाग में 14 से 28 सितम्बर, 2025 तक "हिंदी पखवाड़े" का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं, अर्थात् हिंदी में टिप्पण-आलेखन, हिंदी निबंध, हिंदी अनुवाद एवं भाषा ज्ञान, हिंदी में टंकण, सामान्य भाषा ज्ञान (एमटीएस वर्ग के लिए), हिंदी कविता पाठ तथा हिंदी प्रश्न मंच आदि का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं/अभियान में विभाग के अनेक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

5.7 प्रोत्साहन योजना

5.7.1 व्यय विभाग में राजभाषा हिंदी में कार्य को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रचारित 'सरकारी कामकाज (भौतिक तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप में) मूल रूप से हिंदी में करने संबंधी पुरस्कार योजना' भी लागू की गई है। इस वर्ष योजना के अंतर्गत कुल 7 कर्मिकों ने भाग लिया और उन्हें पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया।

5.8 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

5.8.1 व्यय विभाग में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। इस समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में अपर सचिव (कार्मिक) एवं प्रभारी राजभाषा की अध्यक्षता में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। बैठक में विभाग के अनुभागों/कार्यालयों से हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष विस्तार से समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी किए गए।

5.8.2 इसके अलावा, बैठक में सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के संबंध में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा की जाती है। विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत अनुपालन, इसके लिए जारी किए गए विभिन्न जांच बिन्दुओं का अनुपालन, विभाग की वेबसाइट पर द्विभाषी सामग्री ही अपलोड करना आदि सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

5.9 संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति

5.9.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग, व्यय विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति गठित है। संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का गठन और बैठकों आदि का आयोजन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। व्यय विभाग भी इस समिति का सदस्य है। समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया राजस्व विभाग द्वारा की जाती है। इस संबंध में जो नामांकन आदि प्राप्त हुए थे उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए राजस्व विभाग को भेज दिया गया है।

6. एकीकृत वित्त इकाई (आईएफयू)

6.1 एकीकृत वित्त इकाई अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)

के अधीन काम करती है तथा अनुदान संख्या 31 - व्यय विभाग के अंतर्गत व्यय और बजट संबंधी प्रस्तावों पर कार्य करती है, जिसमें (i) सचिवालय सामान्य सेवाएँ, जो व्यय विभाग (मुख्य सचिवालय), महा लेखानियंत्रक कार्यालय, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय, लागत लेखा शाखा का कार्यालय तथा मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के लिए स्थापना बजट को कवर करती हैं; तथा (ii) अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, जो शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग और अंतर्राष्ट्रीय निकाय (एजीएओ) को अंशदान को कवर करती हैं।

6.2 यह इकाई अनुदान संख्या 31 - व्यय विभाग के अंतर्गत मासिक व्यय की निगरानी भी करती है। अनुदान संख्या 31-व्यय विभाग के अंतर्गत आवंटन निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

अनुदान सं.	बजट अनुमान 2025-26	संशोधित अनुमान 2025-26
31 – व्यय विभाग	603.83	510.87

6.3 एकीकृत वित्त इकाई, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए मितव्ययिता संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए व्यय विभाग से संबंधित वित्तीय और व्यय प्रस्तावों की शीघ्रता से जांच करती है और उनका निपटान करती है जिसमें परामर्शदाताओं की नियुक्ति, विदेश में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को पाठ्यक्रम शुल्क के भुगतान आदि के प्रस्ताव शामिल हैं।

6.4 अनुदान संख्या 31-व्यय विभाग के व्यय की प्रवृत्ति की लगातार निगरानी की जाती है और व्यय पर सख्त नियंत्रण रखा गया है। वित्तीय सलाहकारों की एक प्रतिक्रिया रिपोर्ट, जिसमें विभाग के कार्यकलापों की संपूर्ण शृंखला शामिल हैं, नियमित रूप से सचिव (व्यय) को मासिक आधार पर अर्ध शासकीय पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।

7. महालेखा नियंत्रक

7.1 वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महा लेखानियंत्रक (सीजीए), भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार हैं और तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं।

7.2 सीजीए का कार्यालय संघ सरकार के व्यय, राजस्व, उधार और विभिन्न राजकोषीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत, वार्षिक विनियोग लेखे (सिविल) और संघ सरकार के वित्त लेखे सीजीए द्वारा संकलित और तैयार किए जाते हैं और सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा संघ के लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट का आधार है। इन दस्तावेजों के साथ, संक्षिप्त विश्लेषण के साथ वित्तीय जानकारी का एक वृहद स्तर का वार्षिक अवलोकन, जिसका शीर्षक "लेखे एक नज़र में" है, तैयार किया जाता है और संसद में परिचालित किया जाता है।

7.3 सीजीए, सीएंडएजी के परामर्श से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, स्वरूप और प्रक्रिया से संबंधित नीतियां भी तैयार करता है। यह एक सुदृढ़ वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, प्राप्तियों और लेखांकन की प्रक्रिया चलाता है; और मजबूत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक लेखाओं (जैसे मासिक एमआईएस "संघ सरकार के लेखाओं की समीक्षा" और "वार्षिक अनंतिम लेखे") को तैयार, समेकित और प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य सरकारी राजकोषीय नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन है।

7.4 संगठन, संबंधित मंत्रालयों में अपने आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध के माध्यम से, मंत्रालयों और विभागों में आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यकलाप जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासकीय प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण से संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करती है।

7.5 वित्तीय रिपोर्टिंग - मासिक और वार्षिक

i. लेखा महानियंत्रक का कार्यालय भारत के संघ सरकार के खातों के मासिक समेकन के लिए उत्तरदायी है, प्राप्तियों, भुगतानों, घाटे और इसके वित्तपोषण के स्रोतों के मासिक रुझानों का विस्तृत विश्लेषण प्रत्येक माह केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत किया जाता है। 'संघ सरकार के खातों की समीक्षा' के रूप में ये दस्तावेज समय के साथ बजटीय अनुपालन की निगरानी के लिए एक अत्यंत उपयोगी उपकरण और निर्णय लेने के लिए एक आसान एमआईएस संदर्भ के रूप में विकसित हुए हैं। सार्वजनिक कामकाज में पारदर्शिता के प्रति सरकार की नीति के अनुरूप, संघ सरकार के खातों का एक सारांश भी हर महीने इंटरनेट पर जारी किया जाता है। मासिक

और त्रैमासिक डेटा को वेबसाइट <http://www.cga.nic.in> पर देखा जा सकता है। यह डाटा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्राष्ट्रीय डाटा मानकों के अनुरूप भी है।

- ii. प्रौद्योगिकी की उन्नति के साथ इस कार्यालय ने त्वरित प्रबंधन निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को प्राप्ति, भुगतानों और घाटे के साप्ताहिक और मासिक फ्लैश आंकड़े प्रदान करना शुरू कर दिया है। विभिन्न वित्तीय मापदंडों और लक्ष्यों की बारीकी से निगरानी करने के लिए, मार्च के महीने में भी दैनिक फ्लैश आंकड़े प्रदान किए जाते हैं।
- iii. सर्वोत्तम पद्धतियों के विकास के अनुरूप, महालेखानियंत्रक कार्यालय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो महीने के भीतर भारत सरकार के अनंतिम लेखे भी तैयार करता है। इन लेखों को जिस दक्षता के साथ तैयार किया जाता है, वह पिछले कुछ वर्षों में लगभग 99% की उच्च सटीकता के स्तर से स्पष्ट है क्योंकि अनंतिम खातों और अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के बीच केवल मामूली भिन्नताएँ देखी गई हैं।
- iv. केंद्र सरकार के वित्त लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधान के तहत संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- v. केंद्र सरकार के वित्त लेखे राजस्व और पूंजीगत लेखों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ संघ सरकार के उद्देश्य के लिए प्राप्ति और संवितरणों के खाते प्रस्तुत करते हैं, सार्वजनिक ऋण के खाते और देनदारियों और परिसंपत्तियों को खातों में दर्ज शेष राशि से तैयार किया जाता है।
- vi. केंद्र सरकार के वित्त लेखों में समग्र रूप से केंद्र सरकार के खाते शामिल होते हैं और इसमें सिविल मंत्रालयों/विभागों, रक्षा और रेलवे मंत्रालयों और डाक और दूरसंचार विभागों के लेन-देन शामिल होते हैं। यह वर्ष के लिए केंद्र सरकार की प्राप्ति और बहिर्वाहों के खातों को विभिन्न लेखों द्वारा प्रकट किए गए वित्तीय परिणामों और जांच के तहत आने वाले अन्य आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करता है। इन खातों में राजस्व और पूंजी लेखे, सार्वजनिक ऋण खाता और खातों में शेष राशि से गणना की गई अन्य देनदारियाँ और संपत्तियाँ शामिल हैं। इसे अनुदानों और प्रभारित विनियोगों के लिए विनियोग लेखों के रूप में अलग से प्रस्तुत किए गए खातों द्वारा पूरा किया जाता है। वित्त लेखे संसद में सरकार के सामान्य खातों की लेखा परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण है।
- vii. वित्त लेखों में दो भाग होते हैं – भाग-I और भाग-II। भाग-I में राजस्व, पूंजी, ऋण, जमा, उचित और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिकता निधि के संबंध में संक्षेपित विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि भाग II में इस लेनदेन के संबंध में अन्य संबंधित विवरणों के साथ विस्तृत विवरण होते हैं। वित्त लेखों के भाग II को आगे दो खंडों 'क' और 'ख' में विभाजित किया गया है। जबकि खंड 'क' में राजस्व और पूंजी खातों पर प्राप्ति और व्यय से संबंधित विस्तृत खाते और विवरण शामिल हैं, खंड 'ख' में ऋण, जमा,

उचित और प्रेषण लेनदेन और आकस्मिकता निधि से संबंधित विस्तृत खाते और विवरण हैं।

viii. वित्त लेखों के संकलन के लिए बुनियादी इनपुट इस प्रकार हैं:-

- (क) केंद्रीय लेनदेन का विवरण;
- (ख) बही खाता प्रविष्टियाँ;
- (ग) पूर्व अवधि समायोजन;
- (घ) प्रोफार्मा समायोजन; और
- (ङ) पिछले वर्ष के अंत तक के प्रगतिशील आंकड़े।

ix. चूंकि, ऊपर उल्लिखित पहले चार इनपुट विभिन्न लेखा अधिकारियों से प्राप्त होते हैं, पिछले वर्ष के अंत तक के प्रगतिशील आंकड़े वित्त लेखा अनुभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं।

x. वार्षिक संकलन "लेखे एक नज़र में" एक साथ, संक्षिप्त विश्लेषण और आलेखी प्रतिनिधित्व के साथ पाठक अनुकूल प्रारूप में, केंद्र सरकार की प्राप्ति और व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों, बचत और भंडार, निवेश, विनिवेश, ऋण और घाटे के अनुमानों और वास्तविकताओं जैसी वित्तीय सूचना का एक व्यापक स्तर का अवलोकन प्रदान करता है। इसे वित्त लेखों और विनियोग लेखों में निहित लेखापरीक्षित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

7.6 सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

व्यय विभाग के मार्गदर्शन में महालेखा नियंत्रण (सीजीए) द्वारा बनाए, विकसित और कार्यान्वित किए गए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), कुशल प्रशासन और नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने पर अधिक जोर देते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में मुख्य पहल का प्रतिनिधित्व करता है। अत्याधुनिक वेब आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में, पीएफएमएस ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थियों/विक्रेताओं और अन्य हितधारकों आदि को जारी पूरी राशि के लिए 76 सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान प्रणालियों के पूर्ण डिजिटलीकरण को सक्षम किया है।

पीएफएमएस संपूर्ण डिजिटल भुगतान, प्राप्ति का संग्रह, लेखांकन, समाधान और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए व्यापक मॉड्यूल प्रदान करता है। यह जस्ट-इन-टाइम रिलीज प्रणाली के माध्यम से प्रभावी नकदी प्रबंधन का भी समर्थन करता है, जिससे लाभार्थी के बैंक खाते में मंजूरी से लेकर क्रेडिट तक निधि का पूर्ण पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित होती है।

एक परिवर्तनीय वित्तीय सुधार के रूप में, पीएफएमएस ने भारत सरकार में वित्तीय प्रशासन को अत्यधिक सुदृढ़ किया है और डिजिटल इंडिया पहल के उद्देश्यों में सीधे योगदान दिया है।

7.6.1 जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) फंड रिलीज

जेआईटी तंत्र केवल आवश्यकता पड़ने पर ही निधि जारी करना सुनिश्चित करता है, जिससे निष्क्रिय धन के अनावश्यक संचय को रोका जा

सके। यह सुधार दो प्रमुख प्रणालियों के माध्यम से लागू किया जाता है:

- केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए एसएनए-स्पर्श
- केंद्रीय क्षेत्र के लिए (सीएस) स्कीमों के लिए ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) और हाइब्रिड टीएसए

ये तंत्र विक्रेताओं/लाभार्थियों को सीधे भुगतान करने में सक्षम बनाते हैं, और पारंपरिक क्रेडिट-पुश दृष्टिकोण से अधिक कुशल डेबिट-पुल मॉडल में परिवर्तन का समर्थन करते हैं।

7.6.2 एसएनए-स्पर्श

एसएनए-स्पर्श केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के लिए निर्बाध जस्ट-इन-टाइम (जेआईटी) निधि प्रवाह की सुविधा के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), राज्य वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (राज्य एफएमआईएस) और भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म को एकीकृत करता है। निधि के प्रवाह को सीधे वास्तविक व्यय से जोड़कर, यह प्रणाली केंद्र-राज्य वित्तीय इंटरफेस में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ाती है।

एसएनए-स्पर्श के अंतर्गत, निधि का केंद्रीय हिस्सा केवल तभी जारी किया जाता है जब राज्य संबंधित दावे प्रस्तुत करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि जारी की गई राशि मुख्य रूप से आवश्यकता-आधारित है। पहले की प्रणालियों में कार्यान्वयन एजेंसियों के बैंक खातों में भारी भरकम राशि जारी की जाती थी और राज्य सरकारों द्वारा राज्य के हिस्से के अंशदान में विलंब होता था। एसएनए स्पर्श यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को भुगतान करने से पहले राज्य का हिस्सा उपलब्ध हो, जो लाभार्थियों को समय पर और निर्बाध अदायगी की अनुमति देता है। यह प्रणाली राज्य आईटी प्रणालियों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित भुगतान निर्देशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीधे निष्पादित प्रत्यक्ष लाभार्थी अंतरण (डीबीटी) लेनदेन को सक्षम करके भुगतान प्रक्रियाओं को और सुदृढ़ करती है।

एसएनए-स्पर्श खाता-आधारित डीबीटी - जहां भुगतान खाता विवरण का उपयोग करके लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान जमा किया जाता है - और आधार-आधारित डीबीटी, जिसमें धनराशि आधार-सीडेड बैंक खातों में अंतरित की जाती है, दोनों का समर्थन करता है। आधार-आधारित डीबीटी भुगतान को और सुविधाजनक बनाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्ट एक्सेस मॉडल शुरू किया है जिससे एनपीसीआई के आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस) को लाभ मिलता है। यह एसएनए-स्पर्श के अंतर्गत डीबीटी लेनदेन में सुचारु एकीकरण, तीव्र प्रसंस्करण और अधिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है।

एसएनए स्पर्श को सभी 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाया गया है। 15 राज्यों ने स्पर्श डीबीटी के माध्यम से आधार-आधारित डीबीटी भुगतान शुरू कर दिया है। सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को दिनांक 01.11.2025 से एसएनए स्पर्श पर शामिल होने के लिए अधिसूचित किया गया है।

7.6.3 ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए)

2017-18 में विकसित टीएसए प्रणाली को स्वायत्त निकायों (एबी) में अधिक मात्रा में नकद अंतरण को समाप्त करके नकदी प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए शुरू किया गया था। इसके बजाय, स्वायत्त निकाय अपने आरबीआई खातों के माध्यम से जस्ट-इन-टाइम आधार पर असाइनमेंट के माध्यम से निधि का आहरण करते हैं। प्रायोगिक तौर पर वर्ष 2019 में आईसीएमआर और आईआईटी दिल्ली के साथ तैयार किया गया था। वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के लिए टीएसए को अपनाया गया था। टीएसए हाइब्रिड को वर्ष 2024 में द्वितीय स्तर से नीचे की एजेंसियों और निजी संस्थाओं के लिए शुरू किया गया था, जिसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बैंक खातों में भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक में लगभग 3,500 टीएसए खाते खोले गए हैं, जिनमें स्वायत्त निकायों, सीएनए और उप-एजेंसियों को शामिल किया गया है। 250 केन्द्रीय क्षेत्र/अन्य व्यय स्कीमों को टीएसए/टीएसए हाइब्रिड में शामिल किया गया है।

7.6.4 ई-बिल प्रणाली - बिलों का संपूर्ण डिजिटलीकरण और दावों का प्रसंस्करण

माननीय प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, भारत सरकार ने विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और भुगतानकर्ताओं की अन्य सभी श्रेणियों द्वारा प्रस्तुत बिलों और दावों के प्रसंस्करण को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार किया है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सभी सिविल मंत्रालयों और विभागों में कार्यान्वयन के लिए एक एंड-टू-एंड ई-बिल प्रणाली विकसित की गई थी।

- ई-बिल पहल आधिकारिक तौर पर 2 मार्च 2022 को शुरू की गई थी। भारत सरकार के सभी कार्यालयों को कवर करने के लिए एक चरणबद्ध रूप से तैयार की गई रणनीति अपनाई गई है। इसे सभी सिविल मंत्रालयों और विभागों के 530 वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। डिजिटल कार्य प्रवाह अब सभी श्रेणियों के बिलों/दावों को जमा करने, सत्यापन, प्रसंस्करण और भुगतान हेतु संचालित है।
- ई-बिल संरचना के अंतर्गत, विक्रेता/आपूर्तिकर्ता/दावेदार, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) या आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग करके अपने बिल और सहायक दस्तावेजों को डिजिटल रूप से अपलोड कर सकते हैं। यह प्रणाली आहरण और संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) और अन्य वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा निर्बाध ऑनलाइन प्रसंस्करण को सक्षम बनाती है। ई-बिल प्रणाली विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को किसी भी स्थान से बिल और दावे ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति देकर अधिक सुविधा प्रदान करती है, जिससे सरकारी कार्यालयों में वास्तविक रूप से जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। डिजिटल प्रस्तुतिकरण समग्र बिल भुगतान चक्र को भी कम करता है, जिससे वस्तुएं और सेवा उपलब्ध कराने के पश्चात् तीव्र प्रसंस्करण और त्वरित भुगतान

संभव हो जाता है। यह प्रणाली बिल की स्थिति के रियल टाईम ट्रैकिंग पर नज़र रखने में सक्षम बनाती है, जो पारदर्शिता बढ़ाती है और दावेदारों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता को कम करती है। इसके अतिरिक्त, पूरी तरह से डिजिटल कार्यप्रवाह एक व्यापक और जालसाजी रहित लेखापरीक्षा-चरण बनाता है, जो सरकारी भुगतान प्रणाली में उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है।

iii. एक मजबूत दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) ई-बिल प्लेटफॉर्म का एक अभिन्न अंग है। डीएमएस बिल और बीजक,

स्वीकृति आदेश, वाउचर, पारित आदेश/वापसी आदेश सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों को संग्रहीत करता है। ये दस्तावेज़ लेखा परीक्षा सहित प्रसंस्करण, समीक्षा और कार्यान्वित जांच हेतु अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। डिजिटल कोष रिकॉर्ड रखने की दक्षता को बढ़ाती है और वास्तविक अभिलेखागार पर निर्भरता को कम करती है।

7.7 प्रभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के संबंध में डीबीटी के साथ डीबीटी/आधार जोड़ने संबंधी प्रगति का विवरण: -

वित्तीय वर्ष	स्कीमों की संख्या (डीबीटी के लिए पीएफएमएस में पंजीकृत)	कुल लेन-देन (करोड़ में)	भुगतान की गई राशि (लाख करोड़ में)
2014-15	56	2.19	0.06
2015-16	90	6.75	0.22
2016-17	162	10.11	0.31
2017-18	296	15.90	0.85
2018-19	414	50.97	1.39
2019-20	507	102.37	2.46
2020-21	603	126.88	2.89
2021-22	891	195.08	3.12
2022-23	1,081	258.34	3.24
2023-24	1,146	266.42	3.48
2024-25	1,169	286.43	3.75
2025-26 (till 31-10-2025)	940	163.43	2.22

7.8 वित्तीय वर्ष 2025-26 की मुख्य डीबीटी स्कीमों: -

डेटा की अवधि : 01-04-2025 से 31-10-2025			
क्र.सं.	स्कीम का नाम	कुल लेन-देन (करोड़ में)	भुगतान की गई राशि (करोड़ में)
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी [मनरेगा]	23.60	40,000.53
2.	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना [पीएम किसान]	10.76	21,523.59
3.	प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ [पहल]	82.83	12,657.34
4.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम [एनएसएपी]	13.64	17,593.54
5.	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण [पीएमएवाई-आर]	0.86	33,243.95
6.	पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना-[4271]	0.09	6,971.35

7.9 वित्तीय वर्ष 2025-26 (अक्टूबर, 2025 तक) डीबीटी स्कीमों के साथ आधार जोड़ना: -

सफल लेनदेनों की संख्या	
आधार आधारित	खाता आधारित
1,32,09,46,653	31,33,63,554
कुल लेनदेन: 1,63,43,10,207	

कुल लेनदेन का 80.83% आधार पेमेंट ब्रिज चैनल के माध्यम से किया जाता है।

7.10 लेखांकन मामलों पर तकनीकी सलाह

7.10.1 संविधान के अनुच्छेद 150 में प्रावधान है कि “संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें” शासकीय लेखा नियमावली, 1990

के नियम 3 के नोट में प्रावधान है कि “यह कार्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के महालेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है।”

7.10.2 व्यय को पंद्रह अंकों के संख्यात्मक कोड का उपयोग करके कार्य, कार्यक्रम और उनकी आर्थिक प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्ति को उनकी प्रकृति और स्रोत के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

7.10.3 जीएआर, 1990 के नियम 26 के अनुसार, महालेखा नियंत्रक कार्यालय संघ और राज्यों के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची (एलएमएमएचए) को तैयार करता है, जिसमें शासकीय लेखों में लघु शीर्ष स्तर तक (और उनमें से कुछ के अंतर्गत कुछ उप/विस्तृत शीर्ष) लेखा शीर्षों का वर्गीकरण शामिल है। एलएमएमएचए में कोई भी संशोधन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की सलाह पर किया जाता है। लेखा प्रक्रिया पर नीति से जुड़े मामलों में, बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय से भी परामर्श किया जाता है।

7.10.4 वित्तीय शक्तियां नियमावली, 2024 के प्रत्यायोजन के नियम 8 के अंतर्गत भारत सरकार के आदेशों के अंतर्गत वस्तु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। मानक वस्तु शीर्षों में बदलाव या संशोधित करने और नए वस्तु शीर्ष खोलने की शक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास है। व्यय विभाग ने महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) का कार्यालय और आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) के बजट प्रभाग के परामर्श से मानक वस्तु शीर्षों की समीक्षा की है, संशोधित वस्तु शीर्षों को 16.12.2022 को अधिसूचित किया गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू किया गया है।

7.10.5 महालेखा नियंत्रक, केंद्र सरकार के लेखा (प्राप्तियां और भुगतान नियम) और उससे संबंधित नियमों और अन्य मैनुअल के निर्माण या संशोधन करता है। केंद्रीय सरकार लेखा (प्राप्तियां और भुगतान) नियमावली, 2022 को दो भागों में निर्धारित किया गया है (i) आरपीआर, 2022 और (ii) आरपीआर, 2022 के सहायक निर्देश (विस्तृत प्रक्रियाएं और प्रपत्र) आरपीआर, 2022 में भारत की समेकित निधि की अभिरक्षा, ऐसे कोषों में धन का भुगतान, वहां से धन की निकासी, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त ऐसी निधियों में जमा किए गए धन के अलावा अन्य सार्वजनिक राशि की अभिरक्षा, भारत के सार्वजनिक लेखा में उनका भुगतान और ऐसे लेखाओं से धन की निकासी और उससे जुड़े या उसके सहायक सभी अन्य मामले।

7.11 निगरानी प्रकोष्ठ

7.11.1 निगरानी प्रकोष्ठ को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई के नोट (एटीएन), पीएसी पैराग्राफों पर की गई कार्रवाई के उत्तर (एटीआर) और लोक लेखा समिति के निर्देशानुसार 100 करोड़ और उससे अधिक की बचत तथा अतिरिक्त व्यय पर व्याख्यात्मक नोट (ईएन) को समय पर प्रस्तुत करने के समन्वय का कार्य सौंपा गया है। की गई कार्यवाही नोट/की गई कार्रवाई के उत्तर तथा व्याख्यात्मक नोट प्रस्तुत करने का कार्य ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (एपीएमएस) पोर्टल के माध्यम से किया

जा रहा है, जो लोकसभा सचिवालय को एटीएन/एटीआर/ईएन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। निगरानी प्रकोष्ठ एपीएमएस पोर्टल का संचालक है जो इसके विकास, रखरखाव तथा एपीएमएस पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को त्रैमासिक प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करता है।

7.11.2 वर्ष 2025-26 के दौरान और एपीएमएस पोर्टल के माध्यम से लोकसभा सचिवालय (पीएसी शाखा) को प्रस्तुत किए जाने वाले/निपटाए गए/सीएण्डएजी/पीएसी पैराग्राफों/व्याख्यात्मक नोटों पर एटीएन/एटीआर की संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विषय	01.04.2025 से 12.11.2025 के दौरान पीएसी को प्रस्तुत पैराग्राफ/ व्याख्यात्मक नोट
1.	सीएंडएजी पैराग्राफ	689
2.	पीएसी पैराग्राफ	249
3.	व्याख्यात्मक नोट	63

7.12 शासकीय लेखा एवं वित्त संस्थान (इनगैफ)

7.12.1 सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएफ) लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की प्रशिक्षण शाखा है। प्रारंभ में यह कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता था, इसकी स्थापना फरवरी, 1992 में लेखांकन, प्रशासनिक मामलों और वित्तीय प्रबंधन के विशिष्ट क्षेत्रों में कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में, यह संस्थान सरकारी लेखा और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। इसके अतिरिक्त, चेन्नई, कोलकाता, आइजोल और मुंबई में संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आरटीसी) हैं। संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) द्वारा “अति उत्तम” केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है।

7.12.2 इनगैफ विदेश मंत्रालय के सहयोग से आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। इसी के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 में, इनगैफ 4 आईटीईसी पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिनके नाम हैं “शासकीय लेखा और वित्तीय प्रबंधन”, “लिंग और बाल बजट पर विशेष ध्यान देने के साथ बजट निर्माण और निष्पादन”, “सार्वजनिक व्यय प्रबंधन” और “भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली और अवसंरचनात्मक ढाँचा” जिसमें विभिन्न आईटीईसी भागीदार देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे।

7.13 मिशन कर्मयोगी और डिजिटल लर्निंग:

इनगैफ लगातार महत्ता और प्रतिष्ठा दोनों के संदर्भ में अपने प्रशिक्षण प्रोफाइल को बढ़ाने का प्रयास करता है। अधिकारियों की सुविधा और क्षमता निर्माण के लिए, इनगैफ ने क्षमता निर्माण आयोग के सहयोग से सतर्कतापूर्वक निम्नलिखित पाठ्यक्रमों का संग्रहण और डिजिटलीकरण

किया जो कि अब आईगॉट पोर्टल पर सीधे उपलब्ध है:- अर्थात्

- (i) बजट और संवैधानिक ढांचे की अवधारणा
- (ii) राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003
- (iii) भारत सरकार में बजट निर्माण
- (iv) मासिक, विनियोग और वित्त लेखाओं का संकलन
- (v) बजट निष्पादन और निगरानी
- (vi) बजट दस्तावेज, बजट की प्रस्तुति और पारित करना
- (vii) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का विकास और अवलोकन
- (viii) लेखांकन मानक - अवधारणा और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणाली - आईपीएसएस
- (ix) सरकारी लेखांकन के सिद्धांत, अवसंरचना और वर्गीकरण
- (x) रिकॉर्डिंग, लेखा समाधान, उचित शेष और बैंकिंग व्यवस्था
- (xi) उन्नत लेखा प्रक्रियाओं की लेखांकन प्रक्रिया।

8. मुख्य सलाहकार लागत

8.1 मुख्य सलाहकार लागत (सीएसी) का कार्यालय व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों में से एक है।

8.2 सीएसी का कार्यालय मूल्य/लागत से संबंधित मुद्दों और वित्तीय मामलों पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सलाह दे रहा है, जिसमें सेक्टरों/क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। सीएसी का कार्यालय निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है जैसे:

- i. विभिन्न समितियों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की परियोजनाओं/योजनाओं की लागत के युक्तिकरण के लिए इनपुट प्रदान करना, जैसे व्यय वित्त समितियां (ईएफसी), राज्य वित्त समितियां (एसएफसी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी), प्रमुख/मध्यम, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति;
- ii. समय और लागत में वृद्धि से संबंधित कारणों की पहचान के लिए संशोधित लागत समितियों (आरसीसी) में समय और लागत में वृद्धि या परियोजनाओं की जांच करना और लागत युक्तिकरण के लिए इनपुट प्रदान करना;
- iii. केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) के लिए प्रिंट मीडिया, एफएम रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के लिए विज्ञापन दरें तय करना;
- iv. मूल्य/लागत से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की सहायता करना, विभिन्न सेवाओं/उत्पादों के लिए उचित मूल्य तय करना और लागत मामलों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना और सरकार को आपूर्ति/प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के उचित मूल्य का निर्धारण/नियतन करना।

- v. एसपीएमसीआईएल द्वारा क्रमशः डाक विभाग और आरबीआई को आपूर्ति किए गए डाक उत्पादों/टिकटों और सिक्कों की लागत/उचित मूल्य का निर्धारण, सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेल और भेल द्वारा रेल मंत्रालय को आपूर्ति की गई ट्रेक्शन, एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को आपूर्ति किए गए गर्भनिरोधक और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रदान की गई सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) सेवाएं आदि जैसे प्रमुख अध्ययन करना;
- vi. सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आपूर्तिकर्ताओं के बीच खरीद अनुबंधों से उत्पन्न दावों की जांच/सत्यापन;
- vii. उपयोगकर्ता शुल्क की समीक्षा
- viii. व्यय विभाग द्वारा संदर्भित उच्च मूल्य वाली अवसंरचना परियोजनाओं जैसे कि रेल, राजमार्ग, बिजली, शिक्षा क्षेत्र आदि की लागत अनुमानों की जांच, वित्तीय व्यवहार्यता और अन्य वित्तीय मापदंडों की जांच।
- ix. कोयला ब्लॉकों से संबंधित अचल खान अवसंरचना परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
- x. ईवीएम नष्ट करने की कीमत और ईवीएम (बीवी/सीवी/वीवीपेट)/एम2-एम3 वीवीपेट के उत्पादन की अच्छी कीमत तय करना।
- xi. आईआरईएल द्वारा एनपीसीआईएल को आपूर्ति किए जाने वाले न्यूक्लियर ग्रेड अमोनियम-डाय-यूरेनेट (एनजीएडीयू) की दर निर्धारित करना।
- xii. विभिन्न उप-उत्पादों के मूल्य के आधार पर धान की मिलिंग शुल्क की दरों की समीक्षा करना।
- xiii. बीएसएफ टेकनपुर द्वारा उत्पादित टियर स्मोक इकाइयों का उचित मूल्य निर्धारित करना।
- xiv. यूरिया विनिर्माण इकाइयों की निर्धारित लागत में संशोधन।
- xv. केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत कोयला और लिग्नाइट की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग लागत।

8.3 कैडर प्रशासन सीएसी का कार्यालय भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएस) के लिए कैडर नियंत्रण कार्यालय है, जो मोटे तौर पर आईसीओएस अधिकारियों की भर्ती, स्थानांतरण/तैनाती और कैरियर की प्रगति को देखता है। यह विभिन्न भाग लेने वाले संगठनों में कार्यरत आईसीओएस अधिकारियों को पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करने के अलावा, उनके ज्ञान और कौशल के निरंतर उन्नयन के लिए अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी देखता है। आईसीओएस में अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 230 है, जिन्हें यूपीएससी द्वारा स्तर-10 पर पेशेवर रूप से योग्य लागत लेखाकार/चार्टर्ड एकाउंटेंट में से भर्ती किया जाता है। 2023-24 के दौरान यूपीएससी द्वारा अनुशंसित 34 अधिकारी सेवा में शामिल हुए और इन्हें आईएसटीएम, दिल्ली में दो सप्ताह के लिए प्रेरण प्रशिक्षण पर तैनात किया गया।

8.4 संवर्ग समीक्षा - मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय ने दिनांक 10.07.2025 के कार्यालय आदेश सं ए-32013/1/2025-सीएसी के माध्यम से संवर्ग समीक्षा समिति का गठन किया है। बढ़ती वित्तीय और लागत जटिलताओं को देखते हुए, उभरती चुनौतियों का समाधान करने में एमडीओ की सहायता करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों की तत्काल आवश्यकता है। भारतीय लागत लेखा सेवा के अधिकारियों की विशेषज्ञता इन संगठनों के वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संवर्ग समीक्षा समिति की चार बैठकें नवंबर, 2025 तक आयोजित की जा चुकी हैं।

8.5 संशोधित लागत समितियों में प्रतिनिधित्व:- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 05 अगस्त, 2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24(35)/पीएफ-II/2012 के अनुसरण में, मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय ने अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 तक की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में लागत अनुमानों के संशोधन के लिए 40 समितियों में प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें कुल 17,869/- करोड़ रुपये का मूल्य शामिल है। संशोधित लागत समिति में इस कार्यालय की सक्रिय भूमिका ने संशोधित लागत अनुमानों को युक्तिसंगत बनाने में सहायता की है।

8.6 ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी/डीआईबी में प्रतिनिधित्व:- इस कार्यालय ने अप्रैल, 2025 से अक्टूबर, 2025 की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 23 ईएफसी/एसएफसी/पीआईबी/डीआईबी बैठकों में प्रतिनिधित्व किया है और टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

8.7 प्रतिनिधित्व करने वाली समितियां:- लागत निर्धारण/वित्त/वाणिज्यिक लेखांकन में अपनी विशेषज्ञता के कारण सीएसी के कार्यालय ने निम्नलिखित प्रमुख बहुविषयक अंतर-मंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में भी सेवा दी है:

- केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद की सामान्य निकाय;
- वित्त सचिव की अध्यक्षता में अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के गवर्नर्स बोर्ड;
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति;
- सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में प्रमुख/मध्यम, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं (केंद्रीय जल आयोग द्वारा समन्वित) की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति;
- उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति पर विशेषज्ञ समिति;
- एनपीपीए के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए);
- महानिदेशक, बीएसएफ की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), टेकनपुर, (ग्वालियर) के टियर स्मोक यूनिट का शासकीय निकाय;

- विभिन्न कार्यों के लिए राज्यों में सीएपीएफ तैनाती शुल्क के निर्धारण/वसूली पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी नीति की समीक्षा के लिए समिति;
- पोस्ट भूसे का आधार मूल्य निर्धारित करने के लिए समिति;
- राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (एनसीआरएमपी), एनडीएमए के अंतर्गत विकसित की जा रही व्यापक मल्टी हैजार्ड रिस्क फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी (सीएमएचआरएफएस) पर समिति;
- भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एनएचआई द्वारा गठित विभिन्न परियोजना मूल्यांकन और तकनीकी जांच समितियों (पीएटीएससी) के सदस्य के रूप में।
- बीसीपीएल/असम गैस क्रैकर परियोजना को फीड स्टॉक सब्सिडी की परियोजना पर रिपोर्ट संख्या 8932 में की गई सीएसी के कार्यालय की सिफारिशों पर विचार करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा समिति का गठन किया गया।
- एलवीए सामग्री और प्रदर्शन गुणक के निर्धारण/सत्यापन के लिए समिति का गठन।
- विशेषज्ञ समूह द्वारा यूरिया इकाइयों के लिए ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करना।
- सीबीओसी (पूर्ववर्ती डीएवीपी) की दर संरचना समिति के सदस्य के रूप में।

9. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेनआईएफएम)

9.1 परिचय

एजेनआईएफएम की स्थापना 1993 में एक सोसायटी के रूप में की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री एजेनआईएफएम सोसायटी के अध्यक्ष हैं और सचिव (व्यय) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष हैं। इसकी शुरुआत छह संगठित लेखा और वित्त सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं (परिवीक्षार्थियों) को प्रशिक्षण देने के मुख्य उद्देश्य से हुई थी। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान ने चार दीर्घकालिक कार्यक्रमों और अल्पकालिक कार्यक्रमों की एक सक्रिय सूची के साथ अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है। इस प्रक्रिया में, एजेनआईएफएम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक खरीद को पेशेवर बनाने में वित्त मंत्रालय के एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी एक अनूठी पहचान बनाने में सक्षम रहा है।

9.2 कार्यनिष्पादन और उपलब्धि

मार्च, 2025 तक, एजेनआईएफएम ने 122 प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) आयोजित किए हैं और इसमें 3654 अधिकारियों ने भाग लिया है। विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के नामांकन के लिए जहां 04 कार्यक्रम खुले थे, वहीं व्यक्तिगत संगठनों के लिए उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर 118 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

9.3 महत्वपूर्ण विकास - प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.3.1 एजेनआईएफएम पाँच दीर्घकालिक कार्यक्रम संचालित करता है। ये निम्नानुसार हैं:

- i. व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - छब्बीस सप्ताह की अवधि का विभिन्न लेखा और वित्त सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए।
- ii. वित्तीय प्रबंधन में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन - केंद्र और राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और रक्षा सेवाओं के पीएसयू तथा कारपोरेट क्षेत्रों के मध्य-स्तर के अधिकारियों के लिए।
- iii. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (वित्त): इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेशेवर को प्रशिक्षित करना है जो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में नियामक, बाजार मध्यस्थों, बैंकों, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों, स्टॉक एक्सचेंजों, कमोडिटी एक्सचेंजों और इसी प्रकार के संगठनों में जिम्मेदार पदों को ग्रहण कर सकते हैं।
- iv. सरकारी लेखा और लेखा परीक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीजीएंडए) - यह लेखा विभाग के समूह-ख अधिकारियों के तकनीकी कौशल को उन्नत करने के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम है।
- v. पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) पाठ्यक्रम: यह छह माह का पाठ्यक्रम है जो कॉर्पोरेट भूमिकाओं में परिवर्तन करने वाले रक्षा अधिकारियों के लिए बनाया गया है। यह कार्यकारी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम प्रतिभागियों को कॉर्पोरेट क्षेत्र में उनके पुनः एकीकरण का समर्थन करने के लिए आवश्यक व्यवसाय और प्रबंधन कौशल से लैस करता है।
- vi. अपने नियमित दीर्घकालिक कार्यक्रमों के अलावा,
 - एजेनआईएफएम वित्त और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रतिभागियों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र सरकार, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों आदि के अधिकारी शामिल हैं। एमडीपी विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए एजेनआईएफएम द्वारा आयोजित मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक है।
 - आईओजीटी डिजिटल लर्निंग के माध्यम से क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना: एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (आईजीओटी) प्लेटफॉर्म, भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी की आधारशिला, सिविल कार्मिकों के लिए क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला रहा है। संस्थानों और विभाग को लक्षित, मापनीय और उच्च-प्रभाव वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में सक्षम बनाकर, आईजीओटी उभरती शासन चुनौतियों से निपटने के लिए सुसज्जित भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को बढ़ावा दे रहा है। क्षमता निर्माण आयोग के तत्वावधान में, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेनआईएफएम) ने इस वर्ष आईजीओटी कर्मयोगी

प्लेटफॉर्म पर 21 डिजिटल लर्निंग पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक शुरू किए हैं, जो सिविल सेवाओं में सार्वजनिक वित्त, विश्लेषण और शासन क्षमताओं को मजबूत करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में, व्यय विभाग के सचिव श्री वी. वुअलनाम द्वारा चार प्रमुख पाठ्यक्रमों का उद्घाटन किया गया, जो नवाचार आधारित क्षमता निर्माण पर सरकार के केंद्र बिंदु की पुष्टि करते हैं।

9.3.2 ये नए शुरू किए गए पाठ्यक्रम हैं:

- भारत में फिनटेक: विकास की कहानी और नियामक ढांचा
- स्क्रेप माल का निपटान
- वित्तीय विश्लेषण में नकदी प्रवाह विवरण
- निश्चित आय प्रतिभूतियों का उपयोग करके निवेश प्रबंधन

साथ ही, इन 21 पाठ्यक्रमों का शुभारंभ डिजिटल शिक्षण संसाधनों का विस्तार करने और आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के लिए निरंतर पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए एजेनआईएफएम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

9.4 विभागों/प्रभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली मुख्य स्कीमें/कार्यक्रम

- i. 'मधुसूदन दास क्षेत्रीय वित्तीय प्रबंधन अकादमी (एमडीआरएफएम) भुवनेश्वर' और एजेनआईएफएम के बीच 21.05.2024 को 02 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन।
- ii. क्षमता निर्माण, शोध परियोजनाओं, संकाय आदान-प्रदान, मिशन कर्मयोगी और संसाधन साझाकरण के लिए 1 अक्टूबर 2024 को आईएसटीएम के साथ समझौता ज्ञापन।
- iii. सीजीडीए के अंतर्गत आईडीएस अधिकारियों को एमसीटीपी चरण III, IV एवं V को प्रदान करने के लिए 07 दिसंबर, 2024 को सीजीडीए के साथ समझौता ज्ञापन।
- iv. सीजीडीए के अंतर्गत आईडीएस अधिकारी के एमसीटीपी चरण III, IV एवं V प्रदान करने के लिए उन्हें एक भागीदार संस्थान के रूप में शामिल करने के लिए आईएसबी के साथ 07 दिसंबर, 2024 को समझौता ज्ञापन।
- v. शासन और लोक प्रशासन से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए आपसी आदान-प्रदान और सहयोग के लिए दिनांक 31.01.2025 को राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) के साथ समझौता ज्ञापन, जिसमें शामिल होंगे:
 - (क) क्षमता निर्माण अनुसंधान कार्यक्रम और परामर्श परियोजनाएं पारस्परिक रूप से सहमत कार्यक्रमों के लिए संकाय आदान-प्रदान।
 - (ख) मिशन कर्मयोगी संसाधन साझाकरण

- vi. सिविल सेवकों/सरकारी अधिकारियों आदि के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग देने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहकारी संस्थागत संबंधों हेतु एक स्वास्थ्य ढांचा स्थापित करने के लिए दिनांक 05.03.2025 को भारतीय सार्वजनिक मामलों के संस्थान (आईआईपीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- vii. एक एकीकृत, कागज रहित और पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक प्रापण के आधुनिकीकरण के लिए दिनांक 24.09.2025 को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में क्षमता निर्माण और नीति सलाहकार को आगे बढ़ाने के लिए एजेनआईएफएम के जनादेश पर हस्ताक्षर किए गए।

9.5 लैंगिक बजट और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहल

अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद को वर्ष 2016 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर जेंडर रिस्रॉन्सिव बजट के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। जीआरबी प्रकोष्ठ को जनवरी, 2025 में इसरो द्वारा एक अध्ययन से सम्मानित किया गया है। इसने दिसंबर, 2024 में वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला की मेजबानी की, जिसमें शिक्षाविदों, सरकार और वित्तीय क्षेत्र की अंतर्दृष्टि शामिल थी। जीआरबी प्रकोष्ठ ने परिसर में व्यय विभाग के सहयोग से 10 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

9.6 ई-गवर्नेंस कार्यकलाप

9.6.1 सरकार की नई पहलों पर ज्ञान का प्रसार: जब भी केंद्र सरकार की कोई नई पहल होती है, एजेनआईएफएम को सभी सरकारी संस्थाओं को कवर करने के लिए विशेष प्रशिक्षण अभियान शुरू करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इस अधिदेश की पूर्ति में, एजेनआईएफएम ने जेईएम सहित सार्वजनिक प्रापण पर कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं।

9.6.2 क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने व्यय विभाग के लिए 5 क्षेत्रों की पहचान की है जिसके लिए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम तैयार किए जाने थे, जिसका मुख्य उद्देश्य आईएफडी अधिकारियों की क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करना था। एजेनआईएफएम ने 5 ई-लर्निंग पाठ्यक्रम तैयार किए और उन्हें आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर रखा गया। दूसरे चरण में, एजेनआईएफएम 5 और क्षेत्रों में ई-लर्निंग पाठ्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है, जैसे समझ, कॉर्पोरेट वित्तीय विवरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निदेशकों की भूमिका, लेखा परीक्षा प्रक्रिया, डेटा का विश्लेषण और दृश्यीकरण करना और आईटी परियोजनाओं के जीवन चक्र प्रबंधन को समझना।

10. मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त)

10.1 मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) मंत्रालय के भुगतान और लेखा व्यवस्था का पूर्ण रूप से प्रभारी हैं, जो लेखा नियंत्रक (सीए), उप लेखा नियंत्रक (डीसीए), सहायक लेखा नियंत्रक (एसीए) द्वारा समर्थित और प्रत्येक विभाग में वेतन और लेखा कार्यालयों (पीएओ) की क्षेत्रीय संरचना है।

10.2 मुख्य लेखा नियंत्रक संगठन का कार्य

- (क) वित्त मंत्रालय के छह विभागों अर्थात् आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग का भुगतान करना।
- (ख) वित्त मंत्रालय के छह विभागों से संबंधित मासिक लेखे, विनियोग लेखे और वित्त लेखे भारत सरकार के खातों में उनके समेकन के लिए महालेखा नियंत्रक के कार्यालय को भेजे जाते हैं।
- (ग) पीएओ (आंतरिक ऋण और लेखांकन) के माध्यम से भारत सरकार के लिए आंतरिक ऋण खातों का संकलन।
- (घ) व्यय विभाग की मांग 'राज्यों को अंतरण' में बजटीय आवंटन के संबंध में राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना।
- (ङ) मुख्य लेखा प्राधिकारी (अर्थात् संबंधित विभागों के सचिवों) और महालेखा नियंत्रक को वित्तीय रिपोर्टिंग करना।
- (च) वित्त मंत्रालय के 6 विभागों के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित करना।
- (छ) सरकारी स्कीमों जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि, विशेष जमा स्कीमों और वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीमों को संभालने में बैंकों के कार्य निष्पादन की आंतरिक लेखा परीक्षा करना।
- (ज) पेंशन नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पर जाने वाले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की इच्छा करने वाले अधिकारियों और मृतक कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के परिवारों को पेंशन प्राधिकरण।
- (झ) सीजीईजीआईएस (केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना) के लिए संपूर्ण केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा-जोखा और इस योजना के बचत कोष और बीमा निधि दोनों घटकों के अंतर्गत भारत सरकार की ब्याज देनदारियों की गणना और लेखांकन।
- (ञ) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा पैरा का प्रबंधन और निपटान (पीएसी, अनुपालन लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखा परीक्षा और व्याख्यात्मक टिप्पणियां)।
- (ट) एसपीएमसीआईएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय इकाइयों और मंत्रालय में प्रशासनिक प्रभाग के समन्वय में, टकसालों और मुद्रणालयों के निगमीकरण के बाद, एसपीएमसीआईएल के समाहित कर्मचारियों की संयुक्त पेंशन, आनुपातिक पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान, पेंशन मामलों में संशोधन आदि से संबंधित मामलों का निपटान।

10.3 महत्वपूर्ण कार्यों की मुख्य विशेषताएं

10.3.1 आंतरिक ऋण लेखा और रिपोर्ट करना।

- (क) केंद्र सरकार द्वारा जुटाई गई नए ऋण/सरकारी प्रतिभूतियों के जारी करने से संबंधित सभी लेन-देन, पुनर्भुगतान, पुनर्वापसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी की गई प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) द्वारा किए गए निवेश के लिए जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विस्तृत जानकारी के आधार पर अन्य विशेष प्रतिभूतियों का लेखा-जोखा, और सार्वजनिक ऋण कार्यालय, मुंबई और आईडीएमडी, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई से प्राप्त मासिक और त्रैमासिक विवरण के साथ सभी ट्रेजरी बिलों और नकद प्रबंधन बिलों का मिलान।
- (ख) ऋण देनदारियों से संबंधित विवरण (14 और 14क) तैयार करना और इसे वित्त लेखा अनुभाग, सीजीए कार्यालय को प्रस्तुत करना और भारत सरकार द्वारा जुटाई गई सरकारी प्रतिभूतियों का लेखांकन करना।
- (ग) ऐसे सभी ऋणों के संबंध में मूलधन के समय पर भुगतान और ब्याज के भुगतान की निगरानी करना।
- (घ) भारत सरकार की विभिन्न बचत योजनाओं का लेखा-जोखा।
- (ङ) केंद्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय पर प्रभार्य औसत ब्याज दर की गणना करना।

10.3.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय सलाहकारों के संशोधित चार्टर में मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय की भूमिका और उत्तरदायित्व की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्य लेखा नियंत्रक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करती है और सभी आहरण और संवितरण अधिकारी और अधीनस्थ कार्यालयों की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें बैंक भी शामिल हैं जो सरकारी योजनाओं जैसे लोक भविष्य निधि, विशेष जमा योजना और वरिष्ठ नागरिक जमा योजना को देख रहे हैं। इसमें व्यक्तिगत योजनाओं का आकलन, निगरानी और मूल्यांकन और सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, और वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और विशेष रूप से वित्तीय और लेखा रिपोर्टों की विश्वसनीयता शामिल है। वर्ष 2025-26 (30 नवंबर 2025 तक) के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा 36 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई है।

10.3.3 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- (क) वित्त मंत्रालय के सभी 6 विभागों में बिलों के प्रसंस्करण की इलेक्ट्रॉनिक बिल (ई-बिल) प्रणाली लागू की गई है और यह वित्त मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय के अंतर्गत सभी 25 वेतन एवं लेखा कार्यालयों में क्रियाशील है।
- (ख) भारत सरकार के आंतरिक ऋण के लेखांकन के लिए इंद्रा (आंतरिक ऋण और वसूली उन्नत अनुप्रयोग) सॉफ्टवेयर

विकसित किया गया है। चरण I को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा चुका है।

- (ग) पीएफएमएस तक पहुँचने के लिए एफआईडीओ उपकरणों का उपयोग करके दूसरे कारक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में पूरा किया गया है।
- (घ) सभी वेतन लेखा कार्यालयों में बिल लंबितता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और इसे कुल बिलों के 1% से भी कम कर दिया गया है।
- (ङ) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान का समय पर प्रसंस्करण और सीआरए-प्रोटीन को प्रस्तुत करने में सशक्त परिचालन दक्षता हासिल करना।
- (च) राजस्व विभाग के सचिवालय स्थित वेतन एवं लेखा कार्यालय को निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली हेतु स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा, अवसंरचना प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रणाली प्रबंधन (आईटी) आईएसओ 9001:2015 से सम्मानित किया गया है।
- (छ) वित्त मंत्रालय के सीसीए कार्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों (बाहरी वेतन एवं लेखा कार्यालयों सहित) में ई-ऑफिस लागू किया गया है।

11. केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

11.1 केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की स्थापना 1 जनवरी, 1990 को केंद्रीय (सिविल) पेंशनभोगियों और स्वतंत्रता सेनानियों, उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, पूर्व सांसदों आदि को पेंशन के भुगतान और लेखा के लिए की गई थी। सीपीएओ वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के महालेखा नियंत्रक कार्यालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसे अधिकृत बैंकों के माध्यम से रेलवे, कार्मिक एवं प्रशिक्षण और रक्षा को छोड़कर संघ राज्य क्षेत्रों एवं दिल्ली प्रशासन सहित केन्द्र सरकार (सिविल) पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान की योजना को प्रशासित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

- पेंशन वितरण बैंकों के सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र) को पेंशन के मामलों में संशोधन के साथ-साथ नए पेंशन के भुगतान को अधिकृत करने वाले विशेष सील प्राधिकरण (एसएसए) जारी करना;
- पेंशन अनुदान के लिए बजट तैयार करना और उसका लेखा-जोखा रखना;
- पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के सीपीपीसी का लेखा परीक्षा करना;
- पीपीओ और संशोधन प्राधिकरणों में दर्शाए गए सभी विवरणों वाले केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों के डेटा बैंक का अनुरक्षण करना;
- केंद्रीय सिविल पेंशनभोगियों द्वारा उठाए गए मामलों को देखना।

- इसके अलावा, इस कार्यालय को नई पेंशन स्कीम (एआर) के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों को अनंतिम पेंशन के सीधे वितरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। चूंकि, ये पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी अब पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इन एनपीएस (एआर) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगी के डीबीटी प्रणाली से बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इस कार्य को भी मौजूदा स्टाफ द्वारा अधिक प्रयास करके संभाला जा रहा है।

11.2 उपलब्धियां

सीपीएओ का प्राथमिक कार्य बैंकों के सीपीपीसी को नए पेंशन और संशोधित पेंशन के मामलों में एसएसए जारी करना है। दिनांक 01.04.2025 से 31.10.2025 की अवधि में, मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

- नए पेंशन और संशोधित पेंशन मामलों में क्रमशः 32,334 और 24,199 प्राधिकरण जारी किए गए हैं।
- सीपीएओ में एक समर्पित पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ है जिसे वर्ष 2011 के दौरान स्थापित किया गया था। इस प्रकोष्ठ द्वारा 01.04.2025 से 31.10.2025 तक कुल 10,958 शिकायतों का प्रभावी समाधान किया गया।

11.3 पेंशनभोगियों के जीवन को सरल बनाने तथा पेंशन प्राधिकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सीपीएओ द्वारा हाल ही में निम्नलिखित पहलों की गई हैं:

i. बैंकों को सूची में शामिल करना

क्र.सं.	बैंक	टिप्पणियां
1	कोटक महिन्द्रा बैंक	सीपीपीसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत
2	बंधन बैंक	सीपीपीसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत
3	करूर वैश्य बैंक लि.	सीपीपीसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत
4	सिटी यूनिन बैंक लि.	एकीकरण स्तर पर
5	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक	सीपीपीसी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत
6	कर्णाटक बैंक लि.	एकीकरण स्तर पर
7	आरबीएल बैंक	एकीकरण स्तर पर

ii. 'बैंकिंग समन्वय' अनुभाग की शुरुआत जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:-

- क) सीपीपीसी के साथ आवधिक बैठकें: दिनांक 01.04.2025 से 31.10.2025 की अवधि के दौरान 10 सीपीपीसी को सम्मिलित करने के लिए बैठकें सीपीपीसी के प्रमुख और

बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों के साथ 03 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें पेंशन से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

- ख) सीपीपीसी का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन: सीपीपीसी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन 16 प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों के आधार पर अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही अर्थात् दिनांक 01.04.2025 से 31.10.2025 तक का मूल्यांकन 44 सीपीपीसी के लिए किया गया है।

iii. पेंशन अदालतों का आयोजन:

- क) केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने विभाग/मंत्रालयों द्वारा आयोजित पेंशन अदालतों में विशेष रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आयोजित की गई अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- ख) केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 'पेंशन अदालत' भी आयोजित करता रहा है। इस वर्ष, यह पेंशन अदालत वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 20.11.2025 को आयोजित की गई थी।

11.4 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की ई-गवर्नेंस पहलें

11.4.1 केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय एक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्यालय है। पेंशन संवितरण, लेखा और शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने के लिए इस कार्यालय में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/पैकेज विकसित/कार्यान्वित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:-

- क) पेंशन प्राधिकरण पुनर्प्राप्ति एवं लेखा प्रणाली (पारस):- सभी पेंशन प्रसंस्करण कार्यकलापों प्राप्ति से लेकर प्रेषण तक का प्रबंधन पारस के माध्यम से किया जाता है। पारस का वेब इंटरफेस पेंशनभोगियों, पेंशन लेखा कार्यालयों/मंत्रालयों और बैंकों को संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा 16 लाख से अधिक केंद्रीय सिविल पेंशन मामलों को संसाधित किया गया है, जिससे इन पेंशनभोगियों के डिजिटल डेटाबेस का निर्यात हुआ है। इस सॉफ्टवेयर द्वारा निगरानी के उद्देश्य से विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट भी तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन मामले की स्थिति की जांच हेतु एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

- i. ई-एसएसए:- यह प्रणाली पेंशनभोगियों को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए सीपीएओ से एसएफटीपी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राधिकृत बैंक के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीपीसी) को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नए और संशोधन प्राधिकरणों को ऑनलाइन भेजने के लिए विकसित की गई है।

- ii. ई-स्कॉल सॉफ्टवेयर:- इस सॉफ्टवेयर को सीपीपीसी से भुगतान और रसीद सूची प्राप्त करने के लिए विकसित और प्रस्तुत किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से सीपीएओ में बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों के त्वरित लेखांकन और समन्वय हेतु सफलतापूर्वक कार्य किया गया है। ई-स्कॉल के माध्यम से प्राप्त सूचना का प्रयोग विभिन्न एमआईएस तैयार करने के लिए भी किया जा रहा है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों को उनकी शिकायत की स्थिति देखने के लिए एसएमएस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
- iii. ई-पीपीओ: ई-पीपीओ एक ऑनलाइन ऐप्लिकेशन है जिसके माध्यम से भविष्य के जरिये पीएफएमएस से सीपीएओ का अधिकृत बैंक के केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) तक एक ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। यह एक कुशल और सुरक्षित कागज रहित प्रक्रिया है।
- iv. बार-कोडिंग सॉफ्टवेयर:- सीपीपीसी को पेंशन कागजातों के त्वरित हस्तांतरण और पेंशन मामलों की प्रेषण स्थिति को देखने के लिए बार-कोडिंग मॉड्यूल को डाक विभाग की सहायता से पारस में शामिल किया गया है।
- v. सीपीएओ वेबसाइट:- www.cpao.nic.in में पीएओ, सीसीए, बैंकों और पेंशनभोगियों के लिए इंटरफेस है और यह अपने हितधारकों को विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट और डेटाबेस सेवाएं प्रदान करती है।
- vi. वेब रिस्पॉन्सिव पेंशनर्स सर्विस (डब्ल्यूआरपीएस):- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) की यह सूचना प्रौद्योगिकी पहल पेंशनभोगियों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है जिनमें पेंशन एवं भुगतान सूचना, ऑनलाइन पेंशन प्रक्रिया की ट्रैकिंग और ऑनलाइन शिकायत निवारण एवं ट्रैकिंग शामिल हैं। डब्ल्यूआरपीएस पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अनुक्रियता को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल इंडिया पहल है।
- vii. दीर्घायु पेंशनभोगियों का मोबाइल ऐप: प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए दिनांक 27 फरवरी, 2023 को विज्ञान भवन में दीर्घायु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था। विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दीर्घायु पेंशनभोगियों का मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह एप्लिकेशन पेंशनभोगियों को सीपीएओ द्वारा जारी की गई विशेष सील प्राधिकरणों को डाउनलोड करने के साथ ही एक बटन के क्लिक पर अपने खातों में प्राप्त पेंशन राशि (पिछले 24 लेनदेन) का विवरण जानने की सुविधा प्रदान कर रहा है। यह उनके द्वारा दर्ज किए गए सहायता अनुरोध को दर्ज करने और उनकी स्थिति को देखने में भी सक्षम बनाता है। यह ऐप हिंदी भाषा और एम-

पिन सुविधा से सुसज्जित है और एंड्रॉइड तथा आईओएस संस्करण में उपलब्ध है।

- viii. डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर:- पेंशनभोगियों के सीपीएओ के डेटाबेस के साथ बैंकों के डेटाबेस की तुलना के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और इसके द्वारा डेटाबेस को साफ करने तथा पूरी तरह से समान डेटाबेस स्थापित करने के लिए अपवाद रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

- ix. एसएमएस सुविधा: पेंशन लेखा कार्यालय से केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय को नए पेंशन भुगतान आदेश/संशोधन आदेश की प्राप्ति के विषय में एसएमएस के माध्यम से पेंशनभोगी को सूचित करने और भुगतान की व्यवस्था के लिए बैंकों को विशेष सील प्राधिकरण (एसएसए) भेजने की सुविधा उन पेंशनभोगियों को प्रदान की गई है, जिनके मोबाइल नंबर केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के डेटाबेस में उपलब्ध हैं।

ख.

पेंशनभोगियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र:

- i. पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ: पेंशनभोगियों की शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु, सचिव(व्यय), वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से वर्ष 2011 के दौरान सीपीएओ में पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। इसकी शुरुआत से, 4.25 लाख से अधिक पेंशनभोगियों ने 'पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ' की सेवाओं का लाभ उठाया है। इससे पेंशनभोगियों के लिए जीवन को सुगम बनाने के सरकार का उद्देश्य पूरा हुआ है।
- ii. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीपीएएफ) अर्थात् असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और गृह मंत्रालय के एसएसबी से पेंशनभोगियों/परिवारिक पेंशनभोगियों की भारी संख्या को देखते हुए विशेष रूप से सीपीएएफ पेंशनभोगियों के लिए उनकी शिकायतों के तत्काल समाधान हेतु पेंशनभोगी सुविधा प्रकोष्ठ में हाल ही में एक समर्पित उप-प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
- iii. पेंशन अदालत: सीपीएओ वर्ष 2018 से प्रति वर्ष 'पेंशन अदालत' का भी आयोजन करता आ रहा है। इस वर्ष, दिनांक 20.11.2025 को पेंशन अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इसके अलावा, सीपीएओ ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा आयोजित पेंशन अदालतों में विशेषतः विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा आयोजित पेंशन अदालतों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- (ग) **पेंशन के भुगतान हेतु और अधिक बैंकों को अधिकृत करना:** पेंशनभोगियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों के जीवन को सुगम बनाने और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार बैंक व शाखा का चयन करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए, देश भर में फैली उनकी 90,119 शाखाओं में 21 अधिकृत सार्वजनिक/निजी बैंकों (12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 9 निजी क्षेत्र के बैंकों) के 46 केंद्रीकृत पेंशन प्रसंस्करण केन्द्रों(सीपीपीसी) के माध्यम से पेंशन का वितरण किया जा रहा है।

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267353
CG-DL-E-03112025-267353

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]	नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947
No. 322]	NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

वित्त मंत्रालय
(व्यय विभाग)
संकल्प
नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

फा. सं. 01/01/2025- ई. III (ए).—भारत सरकार ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार है:-

1. अध्यक्ष	- श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
2. सदस्य (अंशकालिक)	- प्रो. पुलक घोष
3. सदस्य-सचिव	- श्री पंकज जैन

2. आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे:

- (क) कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युक्तिसंगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन, भत्ते एवं अन्य

सुविधाओं/लाभों नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना:

- (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारी - औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक;
- (ii) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कर्मिक;
- (iii) रक्षा बलों से संबंधित कर्मिक;
- (iv) संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मिक;
- (v) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी;
- (vi) संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों (आरबीआई को छोड़कर) के सदस्य;
- (vii) उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी;
- (viii) उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिनपर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है; और
- (ix) संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी।

[टिप्पणी: न्यायिक अधिकारियों के संबंध में, आयोग अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य वनाम केन्द्र सरकार और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 1993 के अपने दिए गए निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुपालन करेगा, अर्थात् न्यायाधीशों एवं प्रशासनिक कार्यपालिका की सेवा शर्तों के बीच कोई संबंध नहीं होगा और कि न्यायाधीश की सेवा शर्तों को न्यायपालिका की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।]

- (ख) सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना।
- (ग) निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर सिफारिशें करना।
- (घ) मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना।
- (ङ.)
 - (i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना सहित) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु – सह – सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी की समीक्षा और उस पर सिफारिशें करना।
 - (ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एकीकृत पेंशन योजना सहित) के अंतर्गत न आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु – सह – सेवानिवृत्ति ग्रेच्यूटी और पेंशन की समीक्षा करना तथा नीचे दिए गए पैरा च(iii) को ध्यान में रखते हुए उन पर सिफारिशें करना।
- (च) निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त के संबंध में सिफारिशें करना:
 - i. देश की आर्थिक स्थिति और राजकोपीय विवेक की आवश्यकता;

- ii. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें;
- iii. गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत;
- iv. उन राज्य सरकारों जो साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं, की वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव; और
- v. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना, लाभ और कार्य परिस्थितियां;

3. आयोग अपनी कार्यप्रणाली स्वयं विकसित करेगा और ऐसे सलाहकारों, संस्थागत परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें यह आयोग किसी प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक समझे। यह आयोग ऐसी सूचना और ऐसे साक्ष्य ले सकता है जिन्हें यह आवश्यक समझे। भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग आयोग द्वारा मांगी जाने वाली कोई सूचना और दस्तावेज तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार का यह विश्वास है कि राज्य सरकारें, सेवा संघ तथा अन्य संबंधित पक्ष, आयोग को अपना संपूर्ण सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे।

4. आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. आयोग, अपने गठन की तारीख से **18 माह की** समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। आयोग, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात्, किसी भी मामले पर, आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।

वी. बुअलनाम, सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

वी. बुअलनाम, सचिव

वर्ष 2020-21 से 2025-26 (17.11.2025 तक) में पूंजीगत व्यय/निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु योजना के अंतर्गत जारी राशि का विवरण

(रु करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (17.11.2025 तक)
1	आंध्र प्रदेश	688.00	501.79	6105.56	4090.81	7901.56	3492.40
2	अरुणाचल प्रदेश	232.97	371.19	1564.10	2363.42	2470.96	651.78
3	असम	450.00	600.00	4300.14	5804.43	7427.50	4941.94
4	बिहार	843.00	1246.50	8455.85	8814.80	14791.32	3952.39
5	छत्तीसगढ़	286.00	423.00	2941.97	3365.25	6103.57	1837.91
6	गोवा	97.66	111.04	572.75	695.20	1266.54	591.56
7	गुजरात	285.00	432.00	4045.82	4254.32	5958.26	1433.74
8	हरियाणा	91.00	135.00	1267.00	1702.05	1458.56	542.83
9	हिमाचल प्रदेश	533.00	800.00	650.80	1515.97	2381.37	570.19
10	झारखंड	277.00	246.00	2964.32	4580.61	2718.32	780.79
11	कर्नाटक	305.00	451.50	3399.35	3879.24	5296.12	1811.63
12	केरल	81.50	238.50	1902.74	0.00	2715.67	914.04
13	मध्य प्रदेश	1320.00	1512.36	7360.20	12636.21	12424.92	3809.91
14	महाराष्ट्र	514.00	771.73	6744.16	5376.31	8063.08	3077.18
15	मणिपुर	317.16	212.85	467.22	542.70	1436.82	224.26
16	मेघालय	200.00	281.20	1049.02	1293.06	2369.63	405.83
17	मिजोरम	200.00	299.99	297.50	743.28	1361.09	216.48
18	नागालैंड	200.00	300.00	504.16	973.20	1599.73	0.00
19	ओडिशा	471.50	517.12	75.00	3532.14	6943.55	1967.46
20	पंजाब	296.50	223.50	798.22	0.00	2269.31	681.36
21	राजस्थान	1002.00	692.41	5595.64	8513.42	9139.21	4113.12
22	सिक्किम	200.00	300.00	551.36	797.85	1742.14	288.97
23	तमिलनाडू	0.00	505.50	4011.27	5326.42	7345.86	2677.61
24	तेलंगाना	358.00	214.14	2500.98	1948.34	2727.24	1160.26
25	त्रिपुरा	300.00	118.54	349.79	662.92	1586.68	348.87
26	उत्तर प्रदेश	976.00	1483.00	7940.50	19215.08	17223.82	8465.03
27	उत्तराखंड	675.00	263.92	1124.01	1911.71	2455.84	597.94
28	पश्चिम बंगाल	630.00	933.00	3655.92	5015.58	10305.06	3540.52
कुल		11830.29	14185.78	81195.35	109554.30	149483.73	53096.01
1	दिल्ली						542.03
2	जम्मू और कश्मीर						1083.41
3	पुद्दुचेरी						180.89
जोड़							1806.33
कुल							54902.34

अनुबंध क

व्यय विभाग
अ.जा.अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व

समूह	अ.जा/ अ.ज.जा/ अ.पि.व.का प्रतिनिधित्व										पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	सीधी भर्ती से					पदोन्नति से					अन्य पद्धति से									
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह क	323	61	15	53	194	39	9	2	16	12	15	1	2	1	11	-	-	-	-	-
समूह ख	607	96	26	151	334	27	8	6	3	10	32	8	-	6	18	-	-	-	-	-
समूह ग	376	44	21	85	226	150	26	5	51	68	7	1	-	-	6	1	-	-	-	1
योग	1306	201	62	289	754	216	43	13	70	90	54	10	2	7	35	1	-	-	-	1

अनुबंध-ख

व्यय विभाग
दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व

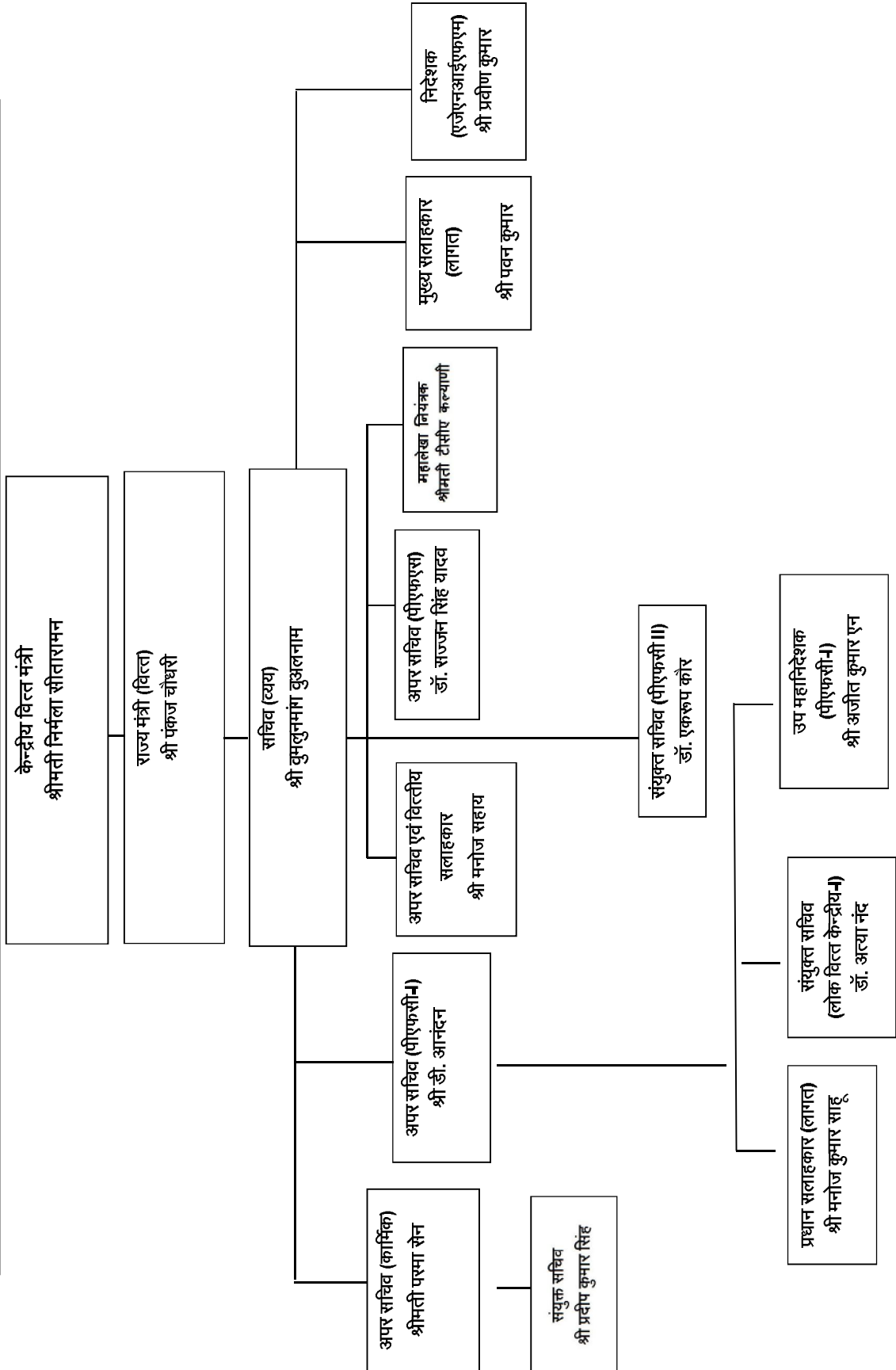
समूह	कर्मचारियों की संख्या										सीधी भर्ती										पदोन्नति									
	आरक्षित रिक्रियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या														
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19												
क	323	-	-	5	1	-	-	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
ख	607	1	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
ग	376	1	1	7	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-												
कुल	1306	2	6	19	2	-	1	21	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-												

अनुबंध-ग

लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश

क्र.सं.	वर्ष	पैराओपी.ए. रिपोर्टों की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद पी.ए.सी. को कृत कार्रवाई नोट प्रस्तुत किए गए हैं	पैराओपी.ए.सी. रिपोर्टों का ब्यौरा जिस पर कृत कार्रवाई नोट लंबित है	कृत कार्रवाई नोट की संख्या, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से जांच कर ली गई है, लेकिन मंत्रालय द्वारा पी.ए.सी. को प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।
1.	2025	शून्य	6	शून्य

व्यय विभाग का संगठनात्मक चार्ट



अध्याय - III

राजस्व विभाग

परिचय

राजस्व विभाग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित राजस्व मामलों के संबंध में नियंत्रण रखता है। विभाग को माल और सेवा कर (जीएसटी), केंद्रीय बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क और अन्य प्रासंगिक वित्तीय विधियों से संबंधित अधिनियमों में बताए गए नियामक उपायों के प्रशासन और प्रवर्तन का भी काम सौंपा गया है। अफीम और इसके उत्पादों के उत्पादन और निपटान का नियंत्रण भी इसी विभाग में निहित है। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय, एफआईयू-आईएनडी, जीएसटीएन, सीबीएन, सीसीएफ, सीईआईबी, एनआईपीएफपी राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं।

1. संगठन और प्रकार्य

1.1 राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन और नियंत्रण में कार्य करता है। यह दो वैधानिक बोर्डों, यथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के माध्यम से सभी संघीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों के संबंध में नियंत्रण रखता है। प्रत्येक बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जो भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव भी होता है। सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रह से संबंधित मामलों की देख-रेख सीबीडीटी द्वारा की जाती है, जबकि माल और सेवा कर (जीएसटी), सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और अन्य अप्रत्यक्ष करों के लगाने और उनके संग्रह से संबंधित मामले सीबीआईसी के दायरे में आते हैं। दोनों बोर्डों का गठन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक बोर्ड में सदस्यों की स्वीकृत संख्या 6 (छह) है।

1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करता है:

- i. आयकर अधिनियम, 1961;
- ii. काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियां) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015
- iii. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988;
- iv. वित्त (सं.2) अधिनियम, 2004 का अध्याय-VII (प्रतिभूति लेनदेन कर लगाने से संबंधित)
- v. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले;
- vi. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
- vii. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
- viii. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
- ix. केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985
- x. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;

- xi. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम;
- xii. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976;
- xiii. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सीमा तक);
- xiv. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974;
- xv. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;
- xvi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999.
- xvii. संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
- xviii. माल और सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017
- xix. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
- xx. राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017; और
- xxi. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

1.3 यह विभाग निम्नलिखित संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों को देखता है:

- i. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
- ii. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
- iii. केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
- iv. प्रवर्तन निदेशालय;
- v. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो;
- vi. कारखानों के मुख्य नियंत्रक;
- vii. सफेमा के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण;
- viii. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;
- ix. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण;
- x. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण
- xi. वित्तीय आसूचना एकक, भारत (एफआईयू-आईएनडी);
- xii. धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
- xiii. पुनरीक्षण आवेदन एकक।

1.4 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

1.5 दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संबंध में एटीएन का विवरण अनुबंध-III में दिया गया है।

1.7 राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-IV में दिया गया है।

2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

2.1 संगठन और कार्य

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 द्वारा बनाया गया एक शीर्ष निकाय है जिसे भारत में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अभिशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीडीटी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए सेवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण और आयकर विभाग (आईटीडी) के अधिकारियों पर नियंत्रण रखने वाला प्राधिकरण है। सीबीडीटी में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं और इसे निम्नलिखित निदेशालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है:

- 1) आयकर निदेशालय (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)
- 2) आयकर निदेशालय (प्रणाली)
- 3) आयकर निदेशालय (प्रशिक्षण)
- 4) आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)
- 5) आयकर निदेशालय (सतर्कता)
- 6) आयकर निदेशालय (विधि एवं अनुसंधान)

आयकर विभाग सीबीडीटी का एक अधीनस्थ संगठन है। जिसका क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण देश पर है इसे प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (प्र.

सीसीआईटी) की अध्यक्षता वाले 18 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और करदाता सेवाओं के पर्यवेक्षण का काम सौंपा गया है। आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) अन्वेषण कार्यों की निगरानी करते हैं और कर अपवंचन और बेहिसाबी आय का पता लगाने संबंधी कार्यों को देखते हैं। आयकर महानिदेशक (आसूचना और आपराधिक अन्वेषण) कर संबंधी अपराधों में खुफिया जानकारी जुटाने और अन्वेषण की निगरानी करते हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) देश भर में छूट और गैर-लाभकारी संगठनों/न्यासों का कामकाज देखते हैं और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) अंतर्राष्ट्रीय कर और अंतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में काम की निगरानी करते हैं।

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को मुख्य आयुक्तों, प्रधान आयुक्तों और आयकर आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तथा प्रधान महानिदेशकों/आयकर महानिदेशकों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रधान निदेशकों/अतिरिक्त आयकर महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आयकर आयुक्त (अपील) के रूप में तैनात आयकर आयुक्त अपीलीय कार्यों का निष्पादन करते हैं।

2.2 प्रत्यक्ष कर संग्रह

2.2.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 का, 30 नवंबर, 2025 तक, प्रत्यक्ष कर संग्रह:

30 नवंबर, 2025 तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि देखी गई है। निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,30,797.12 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के निवल संग्रह से 6.71% अधिक है। यह संग्रह वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रत्यक्ष करों के बजट अनुमानों (बीई) का 52.80% है।

कॉर्पोरेट आयकर (सीआईटी) और गैर-कॉर्पोरेट कर (एनसीटी) की निवल राजस्व संग्रह के संदर्भ में वृद्धि दर की बात करें तो, सीआईटी की वृद्धि दर 7.52% है जबकि पीआईटी की वृद्धि दर 6.49% है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के, नवंबर 2025 तक, प्रत्यक्ष कर संग्रह का उपरोक्त विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रमुख शीर्षक	वित्त वर्ष 2024-25 का संग्रह (30.11.2024 तक)			वित्त वर्ष 2025-26 का संग्रह (30.11.2025 तक)			निवल संग्रह पर वृद्धि का प्रतिशत
	कुल	धनवापसी	निवल	कुल	धनवापसी	निवल	
निगम कर	6,80,039.75	1,68,548.20	5,11,491.55	7,15,861.06	1,65,909.34	5,49,951.72	7.52%
व्यक्तिगत कर	8,81,550.35	1,48,572.01	7,32,978.34	8,74,610.42	94,071.08	7,80,539.34	6.49%
अन्य	2,621.30	15.76	2,605.54	314.33	8.27	306.06	-88.25%
कुल	15,64,211.40	3,17,135.97	12,47,075.43	15,90,785.81	25,99,88.69	13,30,797.12	6.71%

स्रोत: प्रधान सीसीए (सीबीडीटी)

*प्रधान सीसीए, सीबीडीटी द्वारा उपलब्ध कराए गए अंतिम आंकड़े

2.2.2 टीडीएस संबंधी मामले: कर प्रशासन में सुधार लाने और करदाताओं की कठिनाई को कम करने के लिए, इस विभाग द्वारा उठाए गए निम्नलिखित उपायों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है:

2.2.2.1 टीडीएस प्रावधानों संबंधित अधिसूचनाएँ:

- (i) दिनांक 02.01.2025 की अधिसूचना के माध्यम से, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) के उप-खंड (i) में संदर्भित केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित ऋण गारंटी निधियों के संचालन के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय ऋण गारंटी

न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्राप्त भुगतानों पर उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत आयकर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(ii) दिनांक 02.01.2025 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि उक्त अधिनियम के अध्याय XVII के अंतर्गत आयकर की कोई कटौती केंद्र सरकार द्वारा स्थापित और पूर्णतः वित्तपोषित तथा राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित ऋण गारंटी निधि द्वारा प्राप्त भुगतानों पर नहीं की जाएगी, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ख) के उप-खंड (ii) में संदर्भित है।

(iii) दिनांक 02.01.2025 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी विक्रेता, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई है, से माल की खरीद के संबंध में क्रेता के रूप में उक्त अधिनियम की धारा 194ठ के प्रावधानों के अंतर्गत कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

(iv) दिनांक 06.01.2025 की अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी की उप-धारा (1ज) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के अंतर्गत स्पष्ट किया कि विक्रेता से माल की खरीद के संबंध में उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई को क्रेता नहीं माना जाएगा।

(v) दिनांक 18.07.2025 की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया कि आयकर अधिनियम के अध्याय XVII के प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) द्वारा प्राप्त भुगतानों पर लागू नहीं होंगे।

2.2.2.2 टीडीएस प्रावधानों के संबंध में जारी परिपत्र

(i) **परिपत्र संख्या 5 दिनांक 28.03.2025** - केंद्र सरकार के खाते में टीडीएस और टीसीएस का भुगतान करते समय तकनीकी समस्याओं का सामना करने वाले और बाद में आयकर अधिनियम की धारा 201 (1ए) (ii)/206सी (7) के तहत ब्याज लगाने के नोटिस प्राप्त करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, सीसीआईटी या डीजीआईटी को ऐसे ब्याज को कम करने या माफ करने का अधिकार दिया गया था।

(ii) **परिपत्र संख्या 9 2025, दिनांक 21.07.2025** - उन करदाताओं की सुविधा के लिए जिन्हें लेन-देन करते समय टीडीएस/टीसीएस की कम कटौती/संग्रह के संबंध में नोटिस प्राप्त हुए थे, जहां कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता के पैन निष्क्रिय हो गये थे, बोर्ड ने निर्दिष्ट किया कि जहां राशि का भुगतान या क्रेडिट किया जाता है इस अधिनियम की धारा 206एए/206सीसी के तहत कर की कटौती/संग्रह करने के लिए कटौतीकर्ता/संग्रहकर्ता पर कोई दायित्व नहीं होगा और पैन (आधार से लिंक होने के परिणामस्वरूप) उसमें निर्दिष्ट अवधि से पहले सक्रिय हो जाता है।

(iii) **परिपत्र संख्या 13 2025, दिनांक 19.09.2025** - उन करदाताओं की वास्तविक कठिनाई को कम करने के लिए, जिनके रिटर्न पहले ही संसाधित हो चुके हैं और अधिनियम की धारा 87 ए के तहत विशेष दरों पर कर योग्य आय पर छूट दी गई है, बोर्ड ने निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 220(2)

के तहत देय ब्याज ऐसे मामलों में माफ कर दिया जाएगा, जहां उठाई गई मांगों का भुगतान 31.12.2025 को या उससे पहले किया जाता है।

2.3 प्रत्यक्ष कर कानूनों में हाल ही में हुए कुछ विधायी परिवर्तन

2.3.1 आयकर अधिनियम, 2025 का अधिनियमन: सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। उक्त समीक्षा के परिणामस्वरूप, आयकर विधेयक, 2025 (विधेयक संख्या 24 वर्ष 2025) 13.02.2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और लोकसभा की चयन समिति को समीक्षा के लिए भेजा गया। चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद, विधेयक अंततः संसद द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद 21.8.2025 को अधिसूचित किया गया।

आयकर विधेयक को पेश करने का उद्देश्य मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 को संक्षिप्त, स्पष्ट और पढ़ने व समझने में आसान बनाकर सरल बनाना था। सरलीकरण प्रक्रिया तीन मुख्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित थी: -

1. सुस्पष्टता और सुसंगति में और सुधार के लिए पाठ्य और संरचनात्मक सरलीकरण।
2. निरंतरता और निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए कर नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना।
3. करदाताओं के लिए पूर्वानुमान बनाए रखने हेतु कर दरों में कोई संशोधन नहीं करना।

इस उद्देश्य के लिए, तीन-स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया गया: -

1. पठनीयता को बढ़ाने के लिए जटिल भाषा को हटाना।
2. बेहतर नेविगेशन के लिए अनावश्यक और दोहराव वाले प्रावधानों को हटाना।
3. संदर्भ में आसानी के लिए अनुभागों को तार्किक रूप से पुनर्व्यवस्थित करना।

सरलीकरण प्रक्रिया के दौरान, अनपेक्षित अस्पष्टता की संभावना को कम करने का सावधानी पूर्वक प्रयास किये गये हैं, जिससे नयी-नयी व्याख्याओं और मुकदमों से बचा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- क. प्रमुख शब्दों/वाक्यांशों, विशेष रूप से जहां न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं, को न्यूनतम संशोधनों के साथ बरकरार रखा गया है, और छोटे वाक्यों के प्रयोग से भाषा को सरल बनाया गया है।
- ख. अनेक व्याख्याओं की संभावना को कम करने के लिए प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। उपशर्तों और स्पष्टीकरणों को हटा दिया गया है और सरलीकृत सामग्री को उप-अनुभागों और खंडों के रूप में रखा गया है।

- ग. स्पष्टता बढ़ाने के लिए सूत्रों और तालिकाओं का उपयोग किया गया है।
- घ. समान मुद्दों और परिभाषाओं से संबंधित प्रावधान, जो वर्तमान अधिनियम के विभिन्न अध्यायों में मौजूद थे, उन्हें समेकित किया गया है।

आयकर अधिनियम, 2025, सरल, स्पष्ट और असंदिग्ध कर ढांचा प्रदान करके व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2.3.2 कर राहत प्रदान करना

2.3.2.1 वित्त अधिनियम, 2025 ने नई कर व्यवस्था के तहत नए स्लैब और कर दरों के साथ पर्याप्त राहत प्रदान की है, जो इस प्रकार हैं:-

कुल आय	कर की दर
4,00,000 रु. तक	शून्य
4,00,001 रु.से 8,00,000 रु.तक	5 प्रतिशत
8,00,001 रु.से.12,00,000 रु तक	10 प्रतिशत
12,00,001 रु से 16,00,000 रु. तक	15 प्रतिशत
16,00,001 रु.से 20,00,000 रु. तक	20 प्रतिशत
20,00,001 रु.से.24,00,000 रु तक	25 प्रतिशत
24,00,000 रु.से अधिक	30 प्रतिशत

2.3.2.2 नई कर व्यवस्था में छूट में वृद्धि

वित्त अधिनियम, 2025 के तहत नई कर व्यवस्था में निवासी व्यक्तियों के लिए छूट बढ़ा दी गई है, जिसके अनुसार यदि उनकी कुल आय 12,00,000 रुपये तक है तो उन्हें कर नहीं देना होगा। नई कर व्यवस्था के तहत पहले दी जाने वाली सीमांत राहत 12,00,000 रुपये से थोड़ी अधिक आय पर भी लागू होगी।

2.3.2.3 एकीकृत पेंशन योजना के ग्राहकों को मिलने वाली छूट और कटौतियाँ

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (दिनांक 21.08.2025 को अधिसूचित) के माध्यम से, एनपीएस (नई पेंशन योजना) के ग्राहकों को मिलने वाली कर कटौतियों और छूटों को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के ग्राहकों के बराबर विस्तारित करने के लिए संशोधन किया गया है।

2.3.3 निवेश और रोजगार प्रोत्साहन उपाय

2.3.3.1 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासियों के लिए अनुमानित कराधान योजना

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एक योजना के तहत, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधा या उससे जुड़ी सुविधा से संबंधित सेवाएं या प्रौद्योगिकी प्रदान करने के व्यवसाय में लगे अनिवासियों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

2.3.3.2 अंतर्देशीय जलयानों को टन भार कर योजना के लाभों का विस्तार

देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलयानों को टन भार कर योजना के लाभों का विस्तार किया गया है।

2.3.3.3 संप्रभु धन निधियों, पेंशन निधियों और अन्य को छूट

अधिनियम की धारा 10(23एफई) के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, ब्याज, लाभांश और पूंजीगत लाभ के रूप में आय पर छूट के लिए निवेश की अवधि 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 कर दी गई है। यह भी प्रस्तावित है कि ऐसे निर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर भी छूट उपलब्ध होगी, भले ही ऐसे पूंजीगत लाभ को धारा 50एए के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माना जाता हो।

2.3.3.4 सऊदी अरब साम्राज्य के सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को छूट

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 (दिनांक 21.08.2025 को अधिसूचित) के अनुसार, सऊदी अरब साम्राज्य के सार्वजनिक निवेश कोष (पीआईएफ) और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को भारत में अवसंरचना क्षेत्र में किए गए निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज और कुछ अन्य आय, या दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर छूट प्रदान की गई है।

2.3.3.5 आईएफएससी को प्रोत्साहन

निवेश को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससी इकाइयों को छूट, कटौती, आदि के रूप में कई प्रोत्साहन दिए गए हैं।

2.3.4 युक्तिकरण

2.3.4.1 कुछ टीडीएस दरों का युक्तिकरण

दरों की विविधता और अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, कुछ टीडीएस और टीसीएस दरों को घटाया गया है, जबकि स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रह की आवश्यकता के लिए कुछ सीमाएँ बढ़ाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 206सी(1एच) के अंतर्गत वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाला टीसीएस 1.4.2025 से समाप्त कर दिया गया है।

2.3.4.2 धर्मार्थ ट्रस्ट/संस्थाएँ

छोटे ट्रस्टों या संस्थाओं के पंजीकरण की वैधता अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए संशोधन किए गए हैं। ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण को रद्द करने के लिए निर्दिष्ट उल्लंघन की परिभाषा को तर्कसंगत बनाया गया है ताकि अपूर्ण आवेदनों जैसी छोटी चूक पर इसे लागू न किया जाए। इसके अलावा, छूट से इनकार करने के लिए ट्रस्ट या संस्था में पर्याप्त योगदान देने वाले व्यक्तियों की परिभाषा को भी तर्कसंगत बनाया गया है।

2.3.4.3 'पूंजीगत परिसंपत्ति' की परिभाषा में संशोधन

पूंजीगत परिसंपत्ति की परिभाषा में संशोधन किया गया है ताकि

इसमें श्रेणी I या श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में मान्यता प्राप्त और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत विनियमित या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के तहत विनियमित किसी भी निवेश निधि द्वारा धारित प्रतिभूतियों को शामिल किया जा सके, जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 या IFSCA अधिनियम, 2019 के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में निवेश किया है।

2.3.4.4 स्टार्टअप्स को कर लाभ प्राप्त करने की समय सीमा में विस्तार

अधिनियम में संशोधन करके धारा 80-आईएसी के अंतर्गत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले लाभ को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया गया है। तदनुसार, यह लाभ 01.04.2030 तक निगमित पात्र स्टार्टअप्स को उपलब्ध रहेगा।

2.3.4.5 बहु-वर्षीय 'आर्म्स लेंथ' मूल्य निर्धारण करने के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों का युक्तिकरण

इस अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इसी तरह के लेनदेन के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग प्रावधान अब 3 साल की अवधि के लिए लागू होंगे।

2.3.5 विधायी परिवर्तनों के माध्यम से कर प्रशासन सुधार

2.3.5.1 क्रिप्टो-परिसंपत्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का दायित्व

धारा 285खक के तहत, निर्धारित सीमा के अनुसार क्रिप्टो-परिसंपत्ति की जानकारी प्रस्तुत करना करदाता का दायित्व है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (47ए) में 'वर्चुअल डिजिटल एसेट्स' की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि 'वर्चुअल डिजिटल एसेट्स' में, सीए आरएफ के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार सभी क्रिप्टो-एसेट्स भी आते हैं।

2.3.5.2 अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ाना

अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से मौजूदा 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दी गई है।

2.4 विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग

2.4.1 भारत-ब्राजील दोहरे कराधान से बचाव कन्वेंशन:

भारत और ब्राजील के बीच डीटीएसी पर 26-04-1988 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। डीटीएसी को भारत की हालिया संधियों के साथ समरूप करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से ओईसीडी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) एक्शन प्लान और उसके बाद बहुपक्षीय लिखत (एमएलआई) के संबंध में, संशोधन प्रोटोकॉल पर बातचीत शुरू की गई जो 2022 में पूरी हुई। दोनों पक्षों द्वारा 24 अगस्त, 2022 को संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

किए गए थे। डीटीएसी में अन्य परिवर्तनों के अलावा, जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट चेंजिंग (बीईपीएस) परियोजना की कार्यवाई 6 और कार्यवाई 14 के तहत न्यूनतम मानकों को संशोधित प्रोटोकॉल के माध्यम से पूरा किया गया था। संशोधन प्रोटोकॉल के लिए अनुसमर्थन दस्तावेज पर 13 जून, 2023 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जो संशोधन प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए आवश्यक भारतीय पक्ष की आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करता है।

ब्राजील की राष्ट्रीय कांग्रेस ने 11 सितंबर 2025 को दोहरे कराधान से बचने और आयकर के संबंध में कर चोरी की रोकथाम के लिए ब्राजील संघीय गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच कन्वेंशन में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल के पाठ को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, समझौते को उद्घोषित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश, जो ब्राजीलियाई कानूनी प्रणाली में इसके पूर्ण समावेश के लिए एक आवश्यक कदम है, 13 अक्टूबर 2025 को प्रकाशित किया गया था और इस समझौते को 18 अक्टूबर 2025 तक ब्राजीलियाई पक्ष द्वारा लागू माना गया था। अब, भारत में, यह भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया में है।

2.4.2 ओईसीडी एफटीए एमएपी फोरम अवार्ड:

2002 में बनाया गया ओईसीडी फोरम ऑन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफटीए), 50 से अधिक ओईसीडी और गैर-ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के कर आयुक्तों और कर प्रशासन अधिकारियों को एक साथ एक मंच पर लाता है। एफटीए एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से कर प्रशासक दुनिया भर में कर प्रशासन को बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान साझा करते हैं, अनुसंधान करते हैं और अपने नए विचारों को विकसित करते हैं।

भारत और जापान को संयुक्त रूप से मान्यता दी गई और सभी भाग लेने वाले न्यायालयों के बीच कई क्षेत्राधिकारों द्वारा पूरी तरह से हल किए गए ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों की सबसे अधिक संख्या के लिए सम्मानित किया गया। एफटीए में दुनिया भर की उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के 50 से अधिक सदस्य हैं।

2.4.3 भारत और जापान के बीच करों के संग्रह में सहायता पर समझौता ज्ञापन:

भारत और जापान ने दोहरे कराधान से बचाव कन्वेंशन (डीटीएसी) के अनुच्छेद 26ए के तहत करों के संग्रह में सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जहां डीटीएसी से दोनों देशों के बीच कर सहयोग की सुविधा मिलती है वहीं यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश के निवासी किसी भी देश से अर्जित आय पर दोहरे कराधान से बच सकें और कर चोरी के उद्देश्य से तैयार की गई व्यवस्थाओं को ठीक कर सकें, समझौता ज्ञापन में कहा गया है कि दोनों देश अनुरोध करने वाले राज्यों में देय राजस्व दावों के संग्रह में एक-दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे। समझौता ज्ञापन के मसौदे के लिए बातचीत 2018 में शुरू हुई थी और कई दौर की चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है। माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी से 8 जुलाई, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन को अब आगे की आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत ने 96 देशों के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता/कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिनलैंड आदि जैसे कई देशों के साथ करों के संग्रह में सहायता से संबंधित एक विशिष्ट लेख को शामिल करने के लिए दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। भारत वर्तमान में इन दोनों देशों के साथ डीटीए से प्राप्त करों के संग्रह में सहायता के लिए यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी प्रकार के एक समान समझौता ज्ञापन पर बातचीत कर रहा है। तथापि, जापान के साथ समझौता ज्ञापन दोहरे समझौते में परिकल्पित करों के संग्रहण में पारस्परिक सहायता को प्रचालित करने वाला पहला हस्ताक्षरित करार है।

2.4.4 भारत ने कर पारदर्शिता पर 18वें वैश्विक मंच के पूर्ण सत्र की मेजबानी की:

भारत ने 1-5 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में कर उद्देश्यों के लिए पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान पर वैश्विक मंच की 18वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी की। इस पूर्ण सत्र का उद्घाटन भारत के माननीय वित्त मंत्री द्वारा किया गया था और इसमें 11 वीवीआईपी, 63 महाआयुक्त/महानिदेशकों सहित 76 वीआईपी, पर्यवेक्षक संगठनों के 3 प्रमुख, ओईसीडी/सीटीपीए से 3, यूरोपीय संघ से 1 और गैर-सदस्य क्षेत्राधिकार से 3 लोगों ने भाग लिया।

यह कार्यक्रम "कर पारदर्शिता: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक साझा दृष्टिकोण प्रदान करना" विषय के तहत आयोजित किया गया था। यह इस बढ़ती मान्यता को दर्शाता है कि कर चोरी और अन्य अवैध वित्तीय प्रवाह के खिलाफ लड़ाई के लिए सामूहिक प्रयासों और तालमेल की आवश्यकता है। पूर्ण सत्र से संबंधित सभी व्यवस्थाओं और गतिविधियों का समन्वय एफटीएंडटीआर-IV डिबीजन द्वारा किया गया था, जो ग्लोबल फोरम से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल डिबीजन है।

ग्लोबल फोरम, जिसमें सभी जी20 देशों सहित 172 सदस्य क्षेत्राधिकार शामिल हैं, कर पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन की देखरेख करने वाला दुनिया का प्रमुख निकाय है। इसके मुख्य मानकों में अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान (ईओआईआर) और वित्तीय खाता सूचना का स्वचालित आदान-प्रदान (ईओआई) शामिल हैं। प्रभावी सूचना विनिमय को बढ़ावा देकर और पारदर्शिता ढांचे को मजबूत करके, ग्लोबल फोरम कर चोरी और अवैध वित्तीय प्रवाह के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2.4.5 सीमा रहित कर निरीक्षक (टीआईडब्ल्यूबी) कार्यक्रम:

टीआईडब्ल्यूबी पहल के तहत, भारत ने नाइजीरिया और जॉर्जिया को उनकी कर लेखा परीक्षा और अनुपालन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ सहायता प्रदान की। टीआईडब्ल्यूबी का उद्देश्य विकासशील देशों के कर प्रशासनों को उनके कर अधिकारियों को तकनीकी जानकारी और कौशल हस्तांतरित करके और अच्छी लेखा परीक्षा प्रथाओं को साझा करके और उनके साथ ज्ञान के प्रसार के माध्यम से मजबूत करना है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने संयुक्त रूप से 'टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट

बॉर्डर्स' (टीआईडब्ल्यूबी) नाम से एक परियोजना शुरू की, जिसे विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता के निर्माण के माध्यम से अपने राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत करने और इस ज्ञान को अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टीआईडब्ल्यूबी कार्यक्रम के तहत, साझेदार प्रशासनों के कर ऑडिट विशेषज्ञ कर संबंधी मुद्दों पर विकासशील देशों के कर प्रशासन (मेजबान प्रशासन) के स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करते हैं। भारत हमेशा टीआईडब्ल्यूबी कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने में भी मदद करता है।

2.4.6 सेशेल्स सेकेंडमेंट

सेशेल्स के लिए प्रस्तावित अनुमोदन, भारतीय अधिकारियों की एक अल्पसूची को अंतिम रूप दे दिया गया है, और सेशेल्स के अधिकारी अब तैनाती के लिए अधिकारी के चयन के अंतिम चरण में हैं।

2.4.7 सूचना का आदान-प्रदान (ईओआई):

निवासी भारतीयों द्वारा काले धन और अघोषित अपतटीय आय और संपत्ति के खिलाफ चल रही लड़ाई के संदर्भ में, इस प्रभाग के तहत ईओआई इकाई द्वारा 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान कुल 12 संदर्भ भेजे गए थे।

2.4.8 भारत-श्रीलंका डीटीए

भारत-श्रीलंका डीटीए में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर दिसंबर 2024 में हस्ताक्षर किए गए थे ताकि प्रस्तावना को अद्यतन किया जा सके और न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए डीटीए में मुख्य उद्देश्य परीक्षण (पीपीटी) प्रावधान भी शामिल किए जा सकें। श्रीलंका ने अभी तक प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है। भारत के कर आधार के क्षरण को रोकने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपाय है।

2.4.9 भारत-ओमान डीटीए में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल

भारत-ओमान डीटीए को अपडेट करने वाले संशोधन प्रोटोकॉल पर जनवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और जून 2025 में इस अधिसूचित कर दिया गया था। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से कर पारदर्शिता को बढ़ाने और कर निश्चितता प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपाय है।

2.4.10 भारत-कतर द्वारा डीटीए और प्रोटोकॉल का संशोधित किया जाना

संशोधित डीटीए ओईसीडी/जी 20 बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना के न्यूनतम मानकों को लागू करता है और प्रोटोकॉल पर फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा अक्टूबर 2025 में इसे अधिसूचित कर दिया गया था। सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से कर पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपाय है।

2.5. जांच प्रभाग

वित्तीय वर्ष के दौरान 2024-25 तथा 2025-26 में सरकार ने काले धन के मुद्दे से निपटने के लिए नीतिगत स्तर पर की गई पहलों और जमीनी

स्तर पर अधिक प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में क्षमता निर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग पर उचित ध्यान देने के साथ और अधिक उन्नत प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण शामिल है।

2.5.1 खोज और जब्ती और सर्वेक्षण कार्रवाई:

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 1437 समूहों के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई, जिससे 2503.73 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। जबकि, वित्त वर्ष के दौरान वित्त वर्ष की घोषणा की गई है। 2025-26* (अक्टूबर, 2025 तक) में 440 समूहों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की गई। इन मामलों में की गई कार्रवाई में 876.88 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 465 सर्वेक्षण किए गए, जिससे 30444.17 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला। जबकि, वित्त वर्ष 2025-26* (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान, 285 से अधिक सर्वेक्षण किए गए, जिससे 795.36 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला।

(*आंकड़े अनंतिम हैं)

2.5.2 अभियोजन और माफी देना (कंपाउंडिंग):

आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा हाल ही में अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ताकि अभियोजन योग्य मामलों की यथाशीघ्र पहचान की जा सके और उन्हें पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाया जा सके।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, 611 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं और 71 मामलों में, अदालत द्वारा दोषसिद्धि के आदेश पारित किए गए हैं और 1017 मामलों में माफी देना (कंपाउंडिंग) के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। जबकि, वित्त वर्ष 2025-26* (अक्टूबर, 2025 तक) के दौरान 283 मामले, अभियोजन की शिकायतें दर्ज की गई हैं और 24 मामलों में दोषसिद्धि के आदेश पारित किए गए हैं और 579 मामलों में माफी देना (कंपाउंडिंग) के आवेदन स्वीकार किए गए हैं।

(*आंकड़े अनंतिम हैं)

2.5.3 काले धन के तहत कार्रवाइयां (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 ("बीएम अधिनियम")

विदेशों में जमा काले धन से निपटने में आयकर अधिनियम, 1961 आदि की सीमाओं को स्वीकार करते हुए, सरकार ने एक व्यापक और अधिक कठोर नया कानून बनाया जो 01.07.2015 से लागू हो गया है। बीएम अधिनियम के तहत आयकर विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, 30.09.2025 तक, अधिनियम की धारा 10(3)/10(4) के तहत लगभग 1147 मामलों में आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें 40,695 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक के कर और जुर्माने की मांग की गई है और 170 अभियोजन शुरू किए गए हैं।

2.5.4 बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 ("बेनामी अधिनियम") के तहत कार्रवाइयां

अंतराल को पाटने और उचित प्रभावी कानून बनाने के लिए, मौजूदा अधिनियम को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से संशोधित किया गया था, और 1 नवंबर 2016 से लागू हुआ। संशोधित अधिनियम बेनामी लेनदेन और बेनामी संपत्ति को परिभाषित करता है। यह निषिद्ध बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के परिणामों का प्रावधान करता है, जिसमें बेनामी संपत्ति की कुर्की, बेनामीदार और लाभकारी मालिक दोनों की जब्ती और अभियोजन शामिल है। आयकर विभाग (आईटीडी) ने बेनामी अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए पूरे भारत में 24 बेनामी निषेध इकाइयों की स्थापना की है।

आयकर विभाग ने संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद से बेनामी लेनदेन/संपत्तियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है।

संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद से, 29900.97 करोड़ रुपये की 10124 संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया और 379 अभियोजन शुरू किए गए हैं।

2.5.5 सक्षम – 'नज़' (मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए डेटा का गैर-दखल देने वाला उपयोग) - ई-गवर्नेंस के लिए एक दृष्टिकोण

2.5.5.1 हाल के वर्षों में, भारत में आयकर प्रणाली ने करदाता आधार और राजस्व जुटाने के मामले में महत्वपूर्ण विस्तार का प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों की संख्या 8.09 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 22.2 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस प्रगति को विभिन्न माध्यमों से विभाग द्वारा प्राप्त डेटा की मात्रा और गुणवत्ता, दोनों में पर्याप्त वृद्धि द्वारा समर्थित किया गया है। उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की बढ़ती उपलब्धता ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को इन सूचना स्रोतों का रणनीतिक रूप से लाभ उठाने और उन्हें सार्थक राजस्व परिणामों में बदलने में सक्षम बनाया है। इस दिशा में एक प्रमुख पहल सक्षम नज़ (मार्गदर्शन और सक्षम करने के लिए डेटा का गैर-दखल उपयोग) रणनीति है - जो सीबीडीटी के प्रत्यक्ष कर सुधारों के केंद्रीय स्तंभों में से एक है। नज़ ढांचा दो मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है: (1) "पहले विश्वास करें, बाद में जांच करें" और (2) "डेटा को राजस्व में बदलना।"

2.5.5.2 नज़ एक गैर-हस्तक्षेपकारी, पारदर्शी और कुशल तरीके से नागरिक व्यवहार को प्रभावित करने के लिए डिजिटल सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी-सक्षम संचार के उपयोग के कारण एक अभिनव ई-गवर्नेंस ढांचा है। केवल मैन्युअल प्रक्रियाओं या जबरदस्ती प्रवर्तन पर निर्भर रहने के बजाय, नज़ कमियों की पहचान करने, हस्तक्षेपों को व्यक्तिगत करने और नागरिकों को समय पर मार्गदर्शन देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, डेटा वेयरहाउस, एनालिटिक्स इंजन और स्वचालित संचार उपकरण (एसएमएस, ईमेल, डैशबोर्ड) जैसे ई-प्लेटफॉर्म का लाभ उठाता है। प्रौद्योगिकी के साथ व्यवहार संबंधी अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके, नज़ सक्रिय शासन को सक्षम बनाता है - करदाता को एक आसान वेब-आधारित अनुपालन मशीनरी प्रदान करता है। यह अनुपालन में आसानी, प्रशासनिक बोझ को कम करना और

बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। निरंतर डिजिटल निगरानी और फीडबैक लूप एनयूडीजीई हस्तक्षेप को वास्तविक समय में परिष्कृत करने की अनुमति देते हैं, जिससे यह एक राजस्व में रिसाव लक्ष्य हासिल करने योग्य, नागरिक-केंद्रित और डेटा-संचालित ई-गवर्नेंस पहल बन जाती है जो स्वायत्तता को कम किए बिना पारदर्शिता, विश्वास और परिणामों को बढ़ाती है। एनयूडीजीई एक अभिनव दृष्टिकोण है क्योंकि यह शासन को एक नियम-केंद्रित, प्रवर्तन-संचालित मॉडल से एक व्यवहार-केंद्रित, सुविधाजनक मॉडल में स्थानांतरित करता है जो परिणामों में सुधार करते हुए नागरिकों की पसंद का सम्मान करता है। निरीक्षण, दंड या दोहराए जाने वाले अनुपालन कार्यों पर निर्भर करने वाले पारंपरिक हस्तक्षेपों के विपरीत, एनयूडीजीई गैर-अनुपालन की पहचान करने के लिए व्यवहार अंतर्दृष्टि, डेटा विश्लेषण और डिजिटल संचार का उपयोग करता है और फिर ऐसे पहचाने गए लक्ष्यों को सही समय पर और सही संदर्भ में वांछित कार्यों की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसका नवाचार घर्षण और संज्ञानात्मक बोझ को कम करने के लिए डिजिटल

प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले सरलीकृत विकल्प बनाने के लिए मनोविज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी के संयोजन में निहित है।

2.5.5.3 सक्षम: एनयूडीजीई की कार्यान्वयन रणनीति – सक्षम-नज़ एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य संपूर्ण व्यवहार अनुपालन मूल्य श्रृंखला में सरकार की क्षमताओं को मजबूत करना है। सक्षम अपने सात परस्पर जुड़े स्तंभों के माध्यम से एनयूडीजीई की समग्र प्रगति को समाहित करता है:

सक्षम-एनयूडीजीई के ढांचे का उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार, नागरिक अनुभव को बढ़ाने, राजस्व रिसाव को कम करने और कर प्रशासन प्रणाली में विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से एनयूडीजीई अभियानों की अवधारणा, निष्पादन और मूल्यांकन के लिए एक संरचित, सुसंगत और पारदर्शी ढांचा स्थापित करना है। यह ढांचा डेटा एनालिटिक्स, जोखिम पहचान और करदाताओं तक पहुंच के आधार पर लक्षित व्यवहार संबंधी हस्तक्षेपों के लिए सीबीडीटी और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई सभी एनयूडीजीई

SANKALAN	Collection & Compilation	• Systematic compilation and collection of data/information from diverse sources
ANUSANDHAN	Research & Analytics	• Robust research, analysis and insight generation for risk identification
KRIYANVYAN	Action & Execution	• Converting insight into actionable interventions for targeted outcomes.
SAMPARK	Communication	• Proactive communication to create awareness and guide compliance behaviour
HASTAK	Handholding	• Handholding and facilitation to assist taxpayers in fulfilling obligations
ADHIKAAR	Empowerment	• Ensuring rights, transparency and enablement, fostering trust and fairness
MULYANKAN	Evaluation & Feedback	• Continuous monitoring and evaluation to measure impact and refine actions

पहलों पर लागू होता है। इसका व्यापक उद्देश्य व्यावहारिक हस्तक्षेपों के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण को संस्थागत बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नज़ को अलग-थलग करके लागू नहीं किया जाता है, बल्कि डेटा-संचालित, परिणाम-उन्मुख और स्वैच्छिक अनुपालन के नीतिगत लक्ष्यों के साथ अनुरूप किया जाता है।

2.5.5.4 नज़ करदाताओं को सूचित करने, शिक्षित करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कर प्रशासन के लिए एक प्रौद्योगिकी-सक्षम, पारदर्शी और करदाता-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यह आईटीआर में सही रिपोर्टिंग और गैर-दखल देने वाले और सहयोगात्मक तरीके से देय करों के भुगतान को प्रोत्साहित करके स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। सीबीडीटी ने सीआरएस/एफएटीसीए के लिए सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (ईआईओ) के तहत प्राप्त डेटा का उपयोग करके करदाताओं को विदेशी संपत्ति और आय की रिपोर्टिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहला नज़ लॉन्च किया। कुल 19,501 करदाताओं

को अपने रिटर्न का पुनरीक्षण करा और संशोधन करने के लिए नज़-डी किया गया था और साथ ही पूरे भारत में संपर्क (आउटरीच) सत्र आयोजित किए गए थे। इनमें से 12406 करदाताओं (61.77%) ने अपने कर रिटर्न का अनुपालन और संशोधन किया। इसके प्रभाव के रूप में, 13,515 अतिरिक्त करदाताओं ने भी अपने आईटीआर का पुनरीक्षण किया है और अपनी विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी दी है। इसके अलावा, 5,483 करदाताओं ने भी अपना रिटर्न दाखिल किया और विदेशी संपत्ति और आय की सूचना दी। अभियान अवधि के दौरान कुल 30,161 करदाताओं ने 29,208 करोड़ रुपये की अपनी विदेशी संपत्ति और 1,089.88 रुपये की विदेशी आय की सूचना दी और अपने आईटीआर को संशोधित किया।

2.5.5.5 पहले एनयूडीजीई अभियान की सफलता से प्रेरित होकर, सीबीडीटी ने धारा 80जीजीसी के तहत कटौती के झूठे दावों से निपटने के लिए एक और एनयूडीजीई अभियान शुरू किया। करदाताओं द्वारा धारा 80जीजीसी के तहत कुल कटौती का दावा राजनीतिक दलों द्वारा अपने रिटर्न

में दिखाई गई वास्तविक प्राप्ति से बहुत अधिक था। तदनुसार, करदाताओं को कटौती के अपने दावों की समीक्षा करने के लिए कहते हुए नज़् अभियान को निष्पादित किया गया था। यह अभियान पूरी तरह से डेटा-संचालित था, जिसमें उन करदाताओं की पहचान की गई थी, जिन्होंने धारा 80जीजीसी के तहत गैर-आनुपातिक रूप से उच्च कटौतियों का दावा किया था। एसएमएस और ईमेल के माध्यम से लक्षित और व्यक्तिगत संकेत भेजे गए, जिसमें विसंगतियों को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया और करदाताओं से अपने दावों की समीक्षा करने का आग्रह किया गया।

अभियान के तहत एसएमएस और ईमेल के माध्यम से करदाताओं से अपना अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए इस अभियान के तहत 6.24 लाख करदाताओं में से 50842 करदाताओं ने अपने रिटर्न को अपडेट किया है, जिससे 1,487.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त दी गई कटौतियों को वापस लिया गया है और 681.55 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों का भुगतान किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 (15 दिसंबर, 2025 तक) में अद्यतन आईटीआर की 57 लाख से अधिक गिनती दाखिल की गई है, जिससे 6514.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों का भुगतान किया गया है। यह भी ध्यान दिया जाता है कि लगभग 1.13 लाख करदाताओं ने अध्याय VI-क के तहत 2508.16 करोड़ रुपये की कम कटौती और 1272.95 करोड़ रुपये के अतिरिक्त करों के भुगतान के साथ अद्यतन आईटीआर दाखिल किए।

2.5.5.6 इसी तरह, डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से 28,174 अलग-अलग करदाताओं की पहचान की गई, जिनके पास आकलन वर्ष 2022-23, आकलन वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर में दिखाई गई वेतन आय की तुलना में बहुत अधिक मकान किराया भत्ता (एचआरए) दावा था। सक्षम नज़् अभियान के तहत, करदाताओं से एसएमएस और ईमेल के माध्यम से धारा 139 (8क) के तहत अपना अद्यतन रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया गया है। आकलन वर्ष 2022-23, आकलन वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च 2025 तक कुल 4,286 आईटीआर अपडेट किए गए, जिसके परिणामस्वरूप 119.22 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर संग्रह हुआ और एचआरए के तहत फर्जी दावों में 216.88 करोड़ रुपये की कमी आई।

2.5.5.7 वीडिए लेनदेन करने वाले गैर-अनुपालन करदाता के लिए सक्षम नज़् भी किया गया था। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दायर आईटीआर और धारा 194एस के तहत काटे गए टीडीएस के डेटा के विश्लेषण से पता चला है कि जिन व्यक्तियों का टीडीएस धारा 194एस के तहत काटा गया था, उनकी संख्या 6,45,996 है, जबकि शेड्यूल-वीडीए में वीडिए घोषित करने वाले दाखिल आईटीआर की संख्या 1,39,653 है। इससे यह जानकारी मिली कि वीडिए में काम करने वाले कई करदाताओं ने अपने आईटीआर के एसएच-वीडीए में अपने वीडिए लेनदेन की घोषणा नहीं की है। सक्षम नज़् अभियान के तहत, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से चिन्हित करदाताओं से अनुरोध किया गया था कि वे आकलन वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर के शेड्यूल-वीडीए में अपने वीडिए लेनदेन की घोषणा करने के लिए धारा 139(8क) के तहत अपना अद्यतन रिटर्न दाखिल करें। इसके परिणामस्वरूप आईटीआर में अनुसूची वीडिए की फाइलिंग में

सुधार हुआ है, जहां आकलन वर्ष 2023-24 के लिए धारा 115बीएच के तहत कर की राशि 269 करोड़ रुपये से बढ़कर 561.98 करोड़ रुपये हो गई है, जो 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

सक्षम नज़् उन कटौतीकर्ताओं के लिए भी किया गया था, जिन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिपोर्ट की गई कटौती की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टीडीएस विवरणों में कम कटौती की सूचना दी है। अभियान के तहत, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से, चिन्हित कटौतीकर्ताओं से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपडेट किए गए अपने सही विवरण को दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 8,565 कटौतीकर्ता हुए 1.08 करोड़ अतिरिक्त कटौतियों को जोड़ा गया और इस तरह की कटौतियों के लिए 4,825.02 करोड़ रुपये का टीडीएस दर्ज किया गया।

सक्षम नज़् अधिक वैज्ञानिक, लक्ष्य हासिल करने योग्य और प्रभावी है डेटा एनालिटिक्स, लक्षित संचार और एक गैर-प्रतिकूल दृष्टिकोण का संयोजन, जो स्वैच्छिक अनुपालन को चलाने और राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रभावी और रेप्लिकेबल मॉडल साबित हुआ है।

वित्त वर्ष	किए गए सर्वेक्षणों की संख्या	पता चली अघोषित आय (लाख रुपये में)
2023-24	737	37,62,222.78
2024-25	465	30,44,417.01
2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)	285	79,535.99

2.6 लेखा परीक्षा और न्यायिक (ए एंड जे) प्रभाग:

सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण विकास/नीतिगत निर्णय/पहल की गई हैं:

2.6.1 विवाद से विश्वास योजना, 2024 : विवाद से विश्वास योजना, 2024 को लंबित आयकर मुकदमेबाजी को कम करने और करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना का लाभ 34,463 करदाताओं ने उठाया है, जिन्होंने निर्धारित राशि का भुगतान करके अपने विवादों को सुलझा लिया है, जिससे मुकदमेबाजी को उस सीमा तक कम कर दिया गया है।

2.6.2 विभागीय अपीलों की वापसी: सरकार ने सीबीडीटी परिपत्र संख्या 9/2024 दिनांक 17.09.2024 के माध्यम से विभागीय अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है, जिससे सीमा को बढ़ाकर ₹60 लाख (आईटीएटी), ₹2 करोड़ (उच्च न्यायालय) और ₹5 करोड़ (उच्चतम न्यायालय) कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, विभाग ने आयकर अपील, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय से क्रमशः 443, 4791 और 744 अपीलों वापस ले ली हैं।

2.7 ई-गवर्नेंस

2.7.1 परियोजना का नाम: पैन

वित्त वर्ष 2025-26 (31.10.2025 तक) के दौरान कुल 2,89,59,984 पैन आवंटित किए गए हैं। अक्टूबर 2025 तक आवंटित पैन

की कुल संख्या 82,96,92,487 है। 10.11.2025 तक, 69,57,80,780 व्यक्तियों को आधार डेटाबेस के साथ जोड़ा गया है जो व्यक्तियों (81,38,15,539) को आवंटित पैन की कुल संख्या का 85.49% है।

2.7.1.1 पैन 2.0 परियोजना

पैन 2.0 परियोजना को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने वित्त वर्ष 2024-25 में मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी पैन से संबंधित सेवाओं को समेकित करता है और टैन सेवाओं को भी उसी सिस्टम में लाता है। यह आवंटन, सुधार, अद्यतन, तत्काल ई-पैन, आधार-पैन लिंकिंग, शिकायत प्रबंधन और सत्यापन के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। पैन 2.0 तेजी से प्रक्रियान्वयन, डुप्लिकेट डिटेक्शन, विसंगति पहचान और बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग के लिए एआई/एमएल, क्लाउड इंटीग्रेशन और एपीआई-आधारित सिस्टम जैसी उन्नत तकनीकों का लाभ उठाता है।

2.7.2 परियोजना का नाम: टैक्सनेट 2.0

टैक्सनेट 2.0 परियोजना की परिकल्पना आयकर विभाग (आईटीडी) के सभी स्थानों के लिए मुख्य रूप से एक उन्नत, कुशल, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड एंड-टू-एंड निजी नेटवर्क कनेक्टिविटी (वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क) प्रदान करने के लिए की गई है, आयकर विभाग (आईटीडी) अनुप्रयोगों तक पहुंचने की बेहतर विश्वसनीयता और अतिरिक्त डेटाबेस के लिए दोहरी कनेक्टिविटी लिंक, अतिरिक्त 1000 के साथ 125 स्थानों पर सुविधा प्रबंधन सेवा जनशक्ति और हार्डवेयर-आधारित वीसी उपकरणों में वृद्धि टैक्सनेट से जुड़े पीसी के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर-आधारित वीसी लाइसेंस पर विचार करती है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, कुल 723 आयकर विभाग (आईटीडी) स्थानों को टैक्सनेट 1.0 नेटवर्क से टैक्सनेट 2.0 नेटवर्क में स्थानांतरित किया गया है।

2.7.3 परियोजना का नाम: ई-सत्यापन

ई-सत्यापन वर्टिकल आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) पोर्टल का प्रबंधन करता है। संसाधित और विश्लेषण किए जा रहे डेटा की मात्रा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में एआईएस पर जानकारी की 59 श्रेणियां उपलब्ध हैं, जिसमें नई सूचना श्रेणियां लगातार जोड़ी जा रही हैं। वर्ष 2025-26 में दो नई श्रेणियां जोड़ी गई हैं (जिसमें पार्टनरशिप फर्म से भागीदारों द्वारा राशि की प्राप्ति और लक्जरी वस्तुओं की खरीद से संबंधित लेनदेन शामिल हैं)।

2.7.4 परियोजना का नाम: सीपीसी-टीडीएस

आयकर निदेशालय (सिस्टम्स) के तहत काम करने वाले केंद्रीकृत प्रक्रियान्वयन प्रकोष्ठ-टीडीएस (सीपीसी-टीडीएस) को प्रौद्योगिकी सभा उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। सीपीसी-टीडीएस को सरकारी संस्थानों के बीच ग्राहक अनुभव में उत्कृष्टता के लिए मान्यता दी गई है।

सीपीसी (टीडीएस) 2.0 दिनांक 01.10.2024 को शुरू हुआ और यह मौजूदा सीपीसी (टीडीएस) सिस्टम का अगली पीढ़ी, उन्नत संस्करण है,

जिसे टीडीएस/टीसीएस अनुपालन में बेहतर कार्यक्षमता, उपयोगकर्ता अनुभव और दक्षता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य नई सुविधाओं को पेश करने और मौजूदा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मंच को फिर से डिज़ाइन, पुनः संरचना और फिर से विकसित करना है। इसमें आयकर विभाग की राष्ट्रीय वेबसाइट भी शामिल है। मौजूदा प्रणाली, सीपीसी (टीडीएस) 1.0, 2.0 परियोजना के प्रत्याशित चालू (गो-लाइव) होने तक संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) चरण के तहत रहेगी, जिसे वर्ष 2026 में अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया है। सीपीसी (टीडीएस) मॉड्यूल सीपीसी (टीडीएस) 2.0 ढांचे के तहत निम्नलिखित दूरदेशी पहल कर रहा है:

2.7.4.1 सीपीसी टीडीएस 2.0 मूल और सुधार टीडीएस/टीसीएस विवरण दोनों को ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम करेगा। टीडीएस/टीसीएस से संबंधित सभी सेवाएं ट्रेसेस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे यह सभी टीडीएस/टीसीएस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित होगा।

2.7.4.2 यह धारा 201/206, चूक, अभियोजन, सुधार, वसूली, आदेश देने के प्रभाव, संशोधन, आवेदन निपटान और जांच रिपोर्ट आदि के लिए ई-कार्यवाही, की सुविधा भी प्रदान करेगा।

2.7.4.3 अनुकूलन योग्य उपयोगकर्ता डैशबोर्ड: आगामी टीडीएस पोर्टल में उपयोगकर्ता भूमिकाओं (कटौतीकर्ता, करदाता, एओ) के अनुरूप अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड की सुविधा होगी। ये डैशबोर्ड वास्तविक समय के अपडेट, लंबित कार्रवाई, अनुपालन अलर्ट और अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे—जिससे उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम प्रयास के साथ सूचित और अनुपालन में रहने में मदद मिलेगी।

2.7.4.4 मोबाइल-उत्तरदायी और मल्टी-डिवाइस एक्सेसिबिलिटी: पुनः डिज़ाइन किए गए पोर्टल को पूरी तरह से मोबाइल-उत्तरदायी बनाया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता स्मार्टफोन, टैबलेट या डेस्कटॉप पर कभी भी, कहीं भी महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं।

2.7.4.5 सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) और यूनिफाइड इंटरफेस: विभाग कई आयकर प्लेटफार्मों पर एकीकृत लॉगिन अनुभवों की दिशा में काम कर रहा है, जिससे अलग-अलग क्रेडेंशियल्स या पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने के घर्षण को कम किया जा सके।

2.7.4.6 यह परियोजना आयकर विभाग और बाहरी प्रणालियों के अन्य मॉड्यूल के साथ तत्समय एकीकरण करने पर जोर देती है, जिससे निर्बाध डेटा विनिमय और बेहतर करदाता सेवाओं को सक्षम किया जा सके।

2.7.4.7 सीपीसी (टीडीएस) 2.0 में एक व्यापक, बहु-माध्यम वाले शिकायत निवारण तंत्र की परिकल्पना की गई है जो विभिन्न स्रोतों से शिकायतों को समेकित करेगा, उन्हें प्रकार और प्राथमिकता के आधार पर स्वतः असाइन करेगा और डैशबोर्ड और रिपोर्ट के माध्यम से शुरू से अंत तक निगरानी प्रदान करेगा। अपेक्षित सकारात्मक प्रभावों में बेहतर नेविगेशन, शिकायत प्रबंधन समय में कमी और सरलीकृत अनुपालन और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के कारण कटौतीकर्ता/करदाता संतुष्टि में वृद्धि शामिल है।

2.8 मीडिया केंद्र (मीडिया एवं तकनीकी नीति)

2.8.1 प्रत्यक्ष करों पर सूचना का प्रसार

मीडिया एवं तकनीकी नीति (सीआईटी) अगस्त 2006 में स्थापित मीडिया केंद्र का पर्यवेक्षण करता है, जो प्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों पर सार्वजनिक जानकारी प्रसारित करने के एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से, मीडिया केंद्र ने सीबीडीटी और आयकर विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों, विकासों और उपलब्धियों को उजागर करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

1 अप्रैल, 2025 से 30 नवंबर, 2025 तक, मीडिया सेंटर ने प्रमुख उपलब्धियों और जनहित से संबंधित अपडेट को कवर करते हुए 15 प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर चुका है।

2.8.2 सोशल मीडिया के माध्यम से हितधारकों की सहभागिता को मजबूत करना

डिजिटल आउटरीच के महत्व को समझते हुए, सीबीडीटी ने सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने संप्रेषण का दायरा काफी बढ़ाया है। आयकर आयकर विभाग (एम एंड टीपी) की देखरेख में मीडिया सेंटर द्वारा प्रबंधित आधिकारिक हैंडल @IncomeTaxIndia करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ दो-तरफा संचार को सुगम बनाता है। त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, जुलाई 2019 में एक ऑनलाइन प्रतिक्रिया और प्रतिष्ठा प्रबंधन (ओआरएम) प्रणाली शुरू की गई थी, जिससे कार्रवाई योग्य पोस्ट और प्रश्नों की व्यवस्थित पहचान और समाधान संभव हो सका। विचाराधीन अवधि के दौरान, इस कार्यालय ने सीबीडीटी के विभिन्न सूचना और जागरूकता अभियानों की पहुंच को और बढ़ाने के लिए आयकर विभाग (आईटीडी) की सोशल मीडिया पर उपस्थिति का भरपूर लाभ उठाया है।

अभियानवार प्रदर्शन का सारांश नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अभियान	ट्वीट्स	रीट्वीट	छापे
1	बैंक सत्यापन	4	143	328.6के
2	ई-फाइलिंग	31	14,985	9.09एम
3	अग्रिम कर	4	144	349.1के
4	आइए टैक्स सीखें	7	665	666.8के
5	ई-फाइलिंग मेड इजी	10	454	810.7के
6	11 साल की उपलब्धि	17	307	176.6के
7	कर सहायता	5	185	353.3के
8	आयकर दिवस	19	520	368के
9	आयकर विधेयक, 2025	42	1542	2.1एम
10	विशेष अभियान 5.0 (नेशनल हैंडल से)	4	72	161.4के
	विशेष अभियान 5.0 (रीजनल हैंडल से पोस्ट)	736	1472	3.7 मिलियन

2.8.3 प्रदर्शन मापदंड: संपर्क, जवाबदेही और विकास

आयकर विभाग के आधिकारिक X हैंडल (@IncomeTaxIndia) के वर्तमान में 16.18 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं। दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 26 नवंबर, 2025 के खच, इस हैंडल पर 46,743 ट्वीट और प्रतिक्रियाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें करदाताओं को शिक्षित करने वाले पोस्ट और जनता के प्रश्नों के उत्तर भी शामिल हैं। यह विभाग के डिजिटल आउटरीच प्रयासों के बढ़ते पैमाने और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

2.8.4 अनुपालन-सहायता तंत्र के रूप में सोशल मीडिया

सितंबर 2025 में ई-फाइलिंग के चरम चक्र के दौरान, विभाग ने वास्तविक समय में अनुपालन सहायता के लिए एक्स का व्यापक उपयोग किया। इस हैंडल पर 68,039 कार्रवाई योग्य पोस्ट प्राप्त हुए, जिनका तुरंत समाधान किया गया। दिनांक 1 अप्रैल, 2025 से 16 सितंबर, 2025 (गैर-ऑडिट मामलों में आयकर दाखिल करने की विस्तारित नियत तिथि) की महत्वपूर्ण अनुपालन अवधि के दौरान, 40,023 ट्वीट का जवाब दिया गया, जिनमें से 28,109 उपयोगकर्ताओं/करदाताओं ने गपीग ई-फाइलिंग और आयकर संबंधी मुद्दों के लिए बैकएंड सहायता हेतु ओआरएम सिस्टम/समर्पित ईमेल चैनल के माध्यम से प्रश्न उठाए। उक्त 28,109 प्रश्नों में से 27,725 प्रश्नों का (98.63%) सफलतापूर्वक समाधान कर दिया गया।

यह उच्च समाधान दर महत्वपूर्ण अनुपालन अवधियों के दौरान सोशल मीडिया-आधारित शिकायत निवारण की प्रभावशीलता को दर्शाती करती है।

2.8.5 लक्षित अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना

विभाग की प्रमुख पहलों, जैसे कि स्पेशल कैपेन 5.0, "ई-फाइलिंग मेड इजी", "लेट्स लर्न टैक्स" और अन्य को बढ़ावा देने के लिए लक्षित डिजिटल अभियान चलाए गए।

अन्य विविध विषयों पर पोस्ट सहित, इस अवधि के दौरान नेशनल हैंडल से कुल 157 रचनात्मक पोस्ट/पोस्ट प्रकाशित किए गए, जिन्हें कुल मिलाकर 19.67 मिलियन इंप्रेशन (मूल पोस्ट + रीपोस्ट) प्राप्त हुए।

2.8.6 आयकर अधिनियम, 2025 के संबंध में जागरूकता अभियान:

आयकर कार्यालय (एम एंड टीपी) ने आयकर अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों और निहितार्थों को प्रिंट और सोशल मीडिया, दोनों प्लेटफॉर्मों पर प्रसारित करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। इसका उद्देश्य करदाताओं, कर पेशेवरों और आम जनता तक समय पर, सटीक और सुलभ जानकारी पहुंचाना था।

2.8.6.1 आयकर अधिनियम, 2025 पर प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार

विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति के अलावा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिखे गए विशेषज्ञ लेख प्रमुख समाचार पत्रों और व्यावसायिक प्रकाशनों में प्रकाशित किए गए ताकि सरलीकरण प्रक्रिया और नीति के उद्देश्य स्पष्ट किया जा सके और देने वाली सूचना की रिपोर्टिंग को सुगम बनाया जा सके। अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर संक्षिप्त, आसानी से समझ में आने वाली और आकर्षक पोस्ट प्रसारित करने के लिए विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (ट्विटर/एक्स) का सक्रिय रूप से उपयोग किया गया। करदाताओं को अधिनियम के बारे में जानकारी देने के लिए इन्फोग्राफिक्स, लघु व्याख्यात्मक वीडियो और कैरोसेल की एक श्रृंखला प्रकाशित की गई।

आयकर अधिनियम, 2025 के माध्यम से किए गए संरचनात्मक और शाब्दिक सरलीकरण के प्रमुख तत्वों को लक्षित अभियानों के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रचारित किया गया, जिसमें आयकर अधिनियम, 2025 से संबंधित हैशटैग का उपयोग किया गया। आयकर निदेशालय (पीआर, पी एंड पी) के संवाद सत्रों का आयोजन एक्स/ट्विटर पर किया गया ताकि इनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सके। डीआईटी (पीआर, पी एंड पी) के साथ पुनः पोस्ट करने और सहयोग करने से अभियानों की पहुंच और सहभागिता बढ़ाने में मदद मिली।

नेशनल एक्स/ट्विटर हैंडल से प्रकाशित मूल पोस्ट को कुल 1.26 मिलियन इंप्रेशन मिले। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय स्तर पर प्रसार के लिए 19 अन्य क्षेत्रीय हैंडलों द्वारा भी इस सामग्री को पुनः पोस्ट किया गया। इन सभी हैंडलों पर संयुक्त रूप से प्राप्त उपस्थिति (विजिबिलिटी) के परिणामस्वरूप अनुमानित कुल पहुँच लगभग 2.1 मिलियन तक पहुँच गई।

2.8.6.2 मीडिया/सोशल मीडिया कवरेज और प्रतिक्रिया की निगरानी

प्रिंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया कवरेज की बारीकी से निगरानी की गई ताकि जनता की समझ का आकलन किया जा सके और किसी भी गलत सूचना को तुरंत दूर किया जा सके। सोशल मीडिया पर प्राप्त प्रश्नों और टिप्पणियों का जवाब दिया गया और जहां आवश्यक था वहां स्पष्टीकरण जारी किए गए।

इस प्रकार, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से समन्वित प्रचार-प्रसार के द्वारा आयकर विभाग ने सुनिश्चित किया कि आयकर अधिनियम,

2025 से संबंधित जानकारी व्यापक रूप से, सटीक रूप से और सुलभ तरीके से संप्रेषित हो। बहु-चैनल दृष्टिकोण ने करदाताओं की जागरूकता बढ़ाने और गलत सूचना के प्रयासों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

2.8.7 आयकर विभाग के आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ

आयकर कार्यालय (एम एंड टीपी) ने 19 अगस्त, 2025 को आयकर विभाग का आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। यह सत्यापित चैनल नागरिकों के फोन पर कर संबंधी अपडेट सीधे पहुंचाने के लिए एकतरफा प्रसारण मंच के रूप में कार्य करता है। यह चैनल आधिकारिक जानकारी तक प्रत्यक्ष और सरल पहुंच प्रदान करता है, जिससे अविश्वसनीय स्रोतों पर निर्भरता कम होती है। करदाता इस चैनल के माध्यम से नवीनतम अपडेट, महत्वपूर्ण अलर्ट, जागरूकता अभियान संदेश और प्रमुख पहलों को आसानी से देख सकते हैं।

चैनल के लॉन्च के समय, विभाग के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से इसका प्रचार किया गया था। इस लॉन्च को रिपब्लिक वर्ल्ड जैसे समाचार पोर्टलों ने भी कवर किया था।

प्रमुख उपलब्धियों में निम्न शामिल हैं:

- दो महीनों के भीतर (अक्टूबर 2025 तक) 100,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा पार हो गया, जिससे यह भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले आधिकारिक सरकारी व्हाट्सएप चैनलों में से एक बन गया।
- लॉन्च के समय X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसका व्यापक प्रचार किया गया और प्रमुख समाचार प्लेटफॉर्मों द्वारा इसे कवर किया गया।
- 31 अक्टूबर 2025 तक 106 पोस्ट प्रकाशित हो चुके थे—औसतन प्रतिदिन दो से अधिक पोस्ट।
- चैनल पर फॉलोअर्स की औसत मासिक वृद्धि 50,000 से अधिक दर्ज की जा रही है, साथ ही जुड़ाव का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है।

चैनल की विषयवस्तु की प्रासंगिकता इस बात से पुष्ट होती है कि इसके फॉलोअर्स की संख्या में औसतन हर महीने 50,000 से अधिक की वृद्धि हो रही है। लॉन्च के बाद से चैनल की सहभागिता दर में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तीव्र लोकप्रियता से विभाग के सत्यापित संचार चैनलों पर जनता का मजबूत विश्वास प्रदर्शित होता है।

2.8.8 प्रक्रिया नवाचार और तात्कालिक समय में शिकायत निवारण सहायता

कनेक्ट इनसाइट (केआई) जैसे उन्नत उपकरणों को अपनाने से डेटा संकलन और निगरानी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। गूगल शीट्स के एकीकरण से समस्या समाधान का टर्नअराउंड टाइम (टीएटी) 72 घंटे से घटकर 2-3 घंटे हो गया है, और कई मामलों का समाधान उसी समय पर तुरंत हो गया है।

ई-फाइलिंग के चरम सत्र के दौरान, करदाताओं की शिकायतों के समयबद्ध समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए सिस्टम निदेशालय के समन्वय से एक समर्पित **वॉर रूम** स्थापित किया गया था।

2.8.9 सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत बनाना

संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्तों (एनएडीटी सहित) की देखरेख में संचालित उन्नीस क्षेत्रीय ट्विटर हैंडल, अति-स्थानीय स्तर पर जागरूकता और प्रचार कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। सभी क्षेत्रीय हैंडलों को **ग्रे वेरिफिकेशन टिक** प्राप्त हो चुका है, जो विश्वसनीयता को मजबूत करता है और विभाग के आधिकारिक पत्राचार में हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

2.9 आईटीए प्रभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर कर विभाग को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की निर्दिष्ट धाराओं संबंधित प्रशासन और व्याख्या का दायित्व सौंपा गया है। इनमें प्रमुख हैं परिभाषाएँ, अधिनियम की धारा 10 के तहत छूट, वेतन, अध्याय VIए के तहत मकान संपत्ति कटौती, व्यवसाय या पेशे के लाभ और पूंजीगत लाभ। इसे विभिन्न आयकर प्राधिकरणों को क्षेत्राधिकार सौंपने और अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इस संदर्भ में, वर्ष 2025-26 (01.04.2025 से 30.11.2025) के निम्नलिखित आँकड़ों पर प्रकाश डाला गया है:

क्र. सं.	अनुभाग	विषय	सूचनाएं/आदेश/ अनुमोदन/ निपटान
1.	119(2)(ख)/2(ग)	विलंब की माफी से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया गया	308
2.	2(22ककक)	चुनावी ट्रस्टों के मामले में स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश	5
3.	2(48)	शून्य कूपन बांड	4
4.	10(46)	केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित या गठित किंग निकाय या प्राधिकरण, आदि को होने वाली निर्दिष्ट आय के संबंध में छूट दी जाती है, जो वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं हैं।	28
5.	10(46क)	केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या गठित किसी निकाय या प्राधिकरण, आदि को आवास, योजना, विकास या शहरों/कस्बों/गांवों के सुधार या आम जनता के लाभ के लिए किसी गतिविधि के विनियमन/विकास के उद्देश्य से प्राप्त होने वाली किसी भी आय के संबंध में दी गई छूट।	24
6.	11(1)(ग)	भारत के बाहर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अर्जित आय पर छूट लागू होती है, जिसका उद्देश्य उन अंतरराष्ट्रीय कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना है जिनमें भारत की रुचि है।	3
7.	118	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सीबीडीटी के दिनांक 14.11.2014 के आदेश संख्या 187/45/2014-आईटीए-1 में संशोधन के लिए दिनांक 11.06.2025 का आदेश।	1
8.	120	प्रधान आयकर आयुक्त (प्रधान सीआईटी)/प्रधान आयकर निदेशक (प्रधान डीआईटी)/आयकर आयुक्त (सीआईटी)/आयकर निदेशक (डीआईटी) के पद में अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था के लिए कार्यालय आदेश।	2
		दिनांक 27.10.2025 की अधिसूचना, धारा 120(1)(2) के अंतर्गत - आयकर आयुक्त (सीपीसी), बंगलुरु का क्षेत्राधिकार	1
9.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत	दिनांक 25.06.2025 को जारी परिपत्र संख्या 7/2025 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए वैध आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की समय सीमा में छूट दी गई है।	1
		वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पूर्ण जांच के लिए रिटर्न के अनिवार्य चयन हेतु दिशानिर्देश - ऐसे मामलों के अनिवार्य चयन की प्रक्रिया	1
		दिनांक 28.07.2025 के आयकर आयोग (सीपीसी) क्रमांक 10/2025 द्वारा गलत तरीके से अमान्य घोषित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के प्रसंस्करण की समय सीमा में छूट।	1
		वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर दाखिल करने की नियत तिथि बढ़ाने के संबंध में दिनांक 15.09.2025 को परिपत्र संख्या 12/2025 जारी किया गया।	1
		लेखापरीक्षा योग्य निर्धारितियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (मूल्यांकन वर्ष 2025-26 से संबंधित) के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में दिनांक 25.09.2025 को परिपत्र संख्या 14/2025 जारी किया गया।	1
		लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में दिनांक 29.10.2025 को परिपत्र संख्या 15/2025 जारी किया गया।	1

10.	35(1)(ii)/(ii) आयकर अधिनियम, 1961	अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करने के लिए पात्र संस्थाओं के संबंध में सूचनाएं/निपटान आदेश	4
11.	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 के तहत	अन्य विभागों/एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने से संबंधित मामले	2

2.10 आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ)

प्रधान आयकर महानिदेशालय (प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय का एक संबद्ध निदेशालय है। निदेशालय की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

2.10.1 आयकर निदेशालय (टीपीएस-1, टीडीएस और बीआईएफआर)

2.10.1.1 ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली ई-निवारण

- 'ई-निवारण' एक इलेक्ट्रॉनिक शिकायत निवारण प्रणाली है जो विभाग की आंतरिक ऑनलाइन कार्य प्रणाली, आईटीसीए एप्लिकेशन के साथ एकीकृत है। एएसके केंद्रों के माध्यम से प्राप्त कागजी शिकायतों को भी डिजिटाइज़ करके ई-निवारण मॉड्यूल में एकीकृत किया जाता है। सीबीडीटी प्रधानमंत्री/वित्त मंत्री/राज्य मंत्री/अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यालयों में मैन्युअल रूप से या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को भी डिजिटलीकरण के लिए इस निदेशालय को भेजता है। इन्हें पैन क्षेत्राधिकार के अनुसार

ई-निवारण मॉड्यूल पर अपलोड किया जाता है। निदेशालय पूरे देश में ई-निवारण शिकायतों की लंबितता और निवारण की निगरानी करता है।

- ई-निवारण मॉड्यूल की शुरुआत से लेकर दिनांक 20.11.2025 तक आईटीबीए पर कुल 995730 ई-निवारण शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 98.82% अर्थात् 983942 करदाताओं की शिकायतों का समाधान हो चुका है।

2.10.1.2 शिकायत निवारण अभियान

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए दिनांक 02.10.2025 से 31.10.2025 तक "विशेष अभियान 5.0" चलाया गया। इस संबंध में, ई-निवारण शिकायतों के निपटान की दैनिक प्रगति रिपोर्ट डीओएमएस को दी गई। दिनांक 01.10.2025 से 31.10.2025 तक की अवधि के लिए डीओएमएस के साथ साझा किए गए संचयी आंकड़े इस प्रकार हैं:

ई-निवारण के विशेष अभियान से संबंधित डेटा (दिनांक 01.10.2025 से 31.10.2025 की अवधि के लिए)				
दिनांक 01.10.2025 तक लंबित मामले	इस अवधि के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें (क+ख)	दिनांक 31.10.2025 तक निपटान किया गया।	दिनांक 31.10.2025 तक लंबित मामले
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
16316	12062	28378	16244	12134

- जून 2025 से, ई-निवारण संबंधी शिकायतों की प्रभावी निगरानी और निपटान दर में तेजी लाने के लिए इस निदेशालय द्वारा साप्ताहिक वेबएक्स बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

2.10.2 करदाता सेवा निदेशालय-II एवं वसूली

2.10.2.1 केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को चौबिसों घंटे सातों दिन उपलब्ध है, जिसके माध्यम से वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह पोर्टल नागरिकों से ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकारों तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल शिकायतों के समाधान के विरुद्ध प्रतिक्रिया और अपील का प्रावधान भी करता है। भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) सीपीग्राम पोर्टल का प्रबंधन करने वाला एक निकाय है। डीएआरपीजी से लगभग 90 मंत्रालय/विभाग संबद्ध हैं, जिनमें से सीबीडीटी भी एक है।

2.10.2.2 आयकर विभाग में, नई दिल्ली में एक आयुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में करदाता सेवा निदेशालय-II के तहत करदाताओं की सीपीग्राम

शिकायतों की निगरानी की जाती है और डीएआरपीजी के साथ समन्वय किया जाता है।

2.10.2.3 चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 01.04.2025 से 09.11.2025 तक) 37,690 सीपीग्राम शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 41,985 (111%) का निपटारा किया गया। निपटारे का औसत समय 57 दिन है। डीएआरपीजी रिपोर्ट के अनुसार, शिकायतों के समाधान और संतुष्टि की स्थिति के मामले में सीबीडीटी शीर्ष दस मंत्रालयों और विभागों में शामिल है।

2.10.2.4 सीपीग्राम से संबंधित शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ नियमित रूप से वेबएक्स बैठकें आयोजित की जाती हैं। शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायतों की कार्यवाही की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहती है और उनके द्वारा भेजे गए किसी भी अनुस्मारक/ईमेल का तुरंत जवाब दिया जाता है। लोक शिकायत निदेशालय और पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाई की जाती है।

2.10.3 जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार निदेशालय

2.10.3.1 नए आयकर अधिनियम, 2025 में किए गए परिवर्तनों के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने व्यापक करदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई एहतियाती उपाय किए हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों को करदाताओं के एक व्यापक वर्ग द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सके।

2.10.3.2 जागरूकता अभियान के तहत, निदेशालय ने द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में करदाता केंद्र आयोजित किए और करदाताओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने और नागरिकों के साथ सीधे के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और पूर्वी हिमालयी व्यापार मेले में करदाता लाउंज स्थापित किए।

2.10.3.3 सिलीगुड़ी, रांची, चंडीगढ़, वडोदरा, वाराणसी, प्रयागराज और जबलपुर जैसे शहरों में नए अधिनियम पर केंद्रित विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जहां नए कानून की प्रमुख विशेषताओं को समझाया गया और करदाताओं के प्रश्नों का समाधान किया गया।

2.10.3.4 इसके अतिरिक्त, वडोदरा में आयोजित करदाता केंद्र के दौरान, निदेशालय ने "नए आयकर अधिनियम, 2025 की मुख्य विशेषताएं" शीर्षक

से एक ब्रोशर जारी किया, जिसमें नए कानून के तहत प्रमुख परिवर्तनों और लाभों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान किया गया है।

2.10.3.5 व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, 11 'संवाद सत्र' रिकॉर्ड किए गए और विभाग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किए गए। इन सत्रों में विभागीय अधिकारियों ने संवादात्मक शैली में नए प्रावधानों पर चर्चा की, जिससे आम जनता के लिए सामग्री अधिक सुलभ और समझने में आसान हो गई।

2.10.3.6 दिनांक 01.12.2025 से 31.03.2026 तक भौतिक संपर्क गतिविधियों के लिए रणनीति।

2.10.3.7 भारत सरकार ने मौजूदा आयकर अधिनियम को व्यापक रूप से सरल बनाने का कार्य शुरू किया है, जिसके स्थान पर 1 अप्रैल, 2026 से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा। बेहतर पठनीयता और अनुपालन में आसानी के लिए मौजूदा नियमों और प्रपत्रों में भी अधिनियम में हुए परिवर्तनों के अनुरूप महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। तदनुसार, नए आयकर अधिनियम पर 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक मीडिया और जागरूकता अभियान प्रस्तावित हैं।

2.10.3.8 व्यक्तियों, व्यवसायों, एमएसएमई, कारपोरेट, आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के करदाताओं के लिए नियोजित भौतिक संपर्क गतिविधियाँ सभी 18 प्रधान करदाता आयकर क्षेत्रों में निम्नानुसार की जाएगी:-

जिम्मेदार ऊर्ध्वाधर	ऊर्ध्वाधर में इकाइयों की संख्या	प्रति इकाई आउटरीच गतिविधियों की संख्या
प्रधान आयकर आयुक्त (जेएओ)	84	12 (अधिमानत: प्रत्येक माह 4)
एडीजी (पीआर, पी एंड पी)	18	प्रत्येक 18 पीआर.सीसीएसआईटी (सीसीए) के साथ 02 (मेगा इवेंट)
सीआईटी (टीडीएस)	26	18 (अधिमानत: प्रत्येक माह 6)
डीआईटी (आई एंड सीआई)	18	12 (अधिमानत: प्रत्येक माह 4)
सीआईटी (छूट)	14	12 (अधिमानत: प्रत्येक माह 4)

गतिविधियों की कुल संख्या – 1,896

2.11 आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास)

आयकर निदेशालय (मानव संसाधन विकास) आयकर विभाग के अंतर्गत आयकर विभाग (आईआरएस) और गैर-आईआरएस (आईआरएस) दोनों ही पदों के लिए समग्र प्रशासन, कार्मिक प्रबंधन और नीतिगत ढांचे के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्यों में सेवा पुष्टिकरण, पदोन्नति, पैल में शामिल करना, प्रतिनियुक्ति, अधिकारियों की करियर प्रगति, साथ ही ई-ऑफिस, स्पैरो और एपीएआर का प्रबंधन, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली और पुरस्कार नीतियां शामिल हैं। यह समूह-ख और ग कर्मचारियों की भर्ती की देखरेख करता है। मानव संसाधन विकास निदेशालय आयकर विभाग के केंद्र पुनर्गठन के लिए भी उत्तरदायी है। निदेशालय द्वारा की जाने वाली संक्षिप्त गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

2.11.1 इस वर्ष के दौरान, एसीआईटी से लेकर प्रधान सीआईटी तक विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों की पदोन्नति के लिए फाइलें तैयार की गईं और डीपीसी/स्क्रीनिंग समितियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं।

2.11.2 आयकर निदेशालय (एचआरडी), सीबीडीटी, आयकर विभाग में स्पैरो (SPARROW) के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी समूह-क अधिकारियों और आयकर अधिकारियों को अपने एपीएआर और आईपीआर को स्पैरो पर दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया था। लगभग 11,000 उपयोगकर्ता खाते बनाए गए। हालांकि, विभाग के शेष समूह-ख और समूह-ग कर्मचारी अभी भी एपीएआर को कागजी रूप में दाखिल कर रहे थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, समूह-ख और समूह-ग कर्मचारियों को भी स्पैरो पर शामिल कर लिया गया। इस विस्तार के परिणामस्वरूप, आयकर विभाग में 44,000 से अधिक स्पैरो उपयोगकर्ता हैं। एपीएआर के डिजिटलीकरण से कुशल और प्रभावी केंद्र प्रबंधन और समय पर पदोन्नति सुनिश्चित होगी, जिससे कर्मचारियों का मनोबल और प्रेरणा बढ़ेगी। स्पैरो के विस्तार से संबंधित कुछ आंकड़े नीचे सारणीबद्ध किए गए हैं:

स्पैरो एक्सटेंशन पर सांख्यिकी	2023-24	2024-25
स्पैरो उपयोगकर्ता	11,000	44,000
एपीएआर जो डाले गए	26,185	91,000

2.11.3 इस वर्ष के दौरान, माननीय वित्त मंत्री द्वारा आयकर दिवस के अवसर पर दिनांक 24.07.2025 को "विश्लेषण" नामक एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया। यह पोर्टल जेएओ और अपील इकाइयों द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी में सहायता करता है।

2.11.4 आईआरएस अधिकारियों की अद्यतन नागरिक सूची मई 2025 में जारी की गई थी।

2.11.5 इस वर्ष के दौरान, निरीक्षक, कर सहायक, आशुलिपिक आदि विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए कुल 4655 आवेदन विभिन्न क्षेत्रों को भेजे गए। आईआरएस प्रोबेशनर्स और आईटीओ एवं निरीक्षक, पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षाएं आयोजित की गईं।

3. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

3.1 परिचय

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड या सीबीआईसी (पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड) वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राजस्व विभाग का एक भाग है। यह अप्रत्यक्ष कर प्रशासन के लिए शीर्षस्थ निकाय है। यह सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और अंतर-राज्य माल और सेवा कर (आईजीएसटी) लगाने और संग्रहण, तस्करी की रोकथाम और सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीजीएसटी, आईजीएसटी और नारकोटिक्स से संबंधित मामलों के प्रशासन से संबंधित नीति निर्माण में शामिल है, जो सीबीआईसी के अधिकार क्षेत्र में है। सीबीआईसी जीएसटी परिषद की बैठकों और विधि समिति, जो जीएसटी परिषद के समक्ष लाए गए सभी मामलों पर विचार-विमर्श करती है, की सम्बद्ध गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। केंद्रीय राजस्व बोर्ड की संबंधित गतिविधियों में भी अधिनियम, 1963 के तहत गठित सीबीआईसी में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं जो भारत सरकार के विशेष सचिव होते

हैं। सीबीआईसी के कार्मिक अधीनस्थ कार्यालय के कामकाज की निगरानी करते हैं, जिनमें सीमा शुल्क निदेशालय और इकाइयों, जीएसटी आयुक्तालय और अफीम कारखानों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला जैसे स्वापक नियंत्रण कार्यालय शामिल हैं।

क्षेत्रीय कार्यालय मुख्य रूप से राजस्व संग्रह का कार्य करते हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। सीबीआईसी की ये क्षेत्रीय इकाइयाँ द्वारा करदाताओं की शिकायतों का दैनिक आधार पर समाधान किया जाता है।

बोर्ड को 19 निदेशालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो सहायक कार्यालयों के रूप में कार्य करते हैं और नीति निर्माण में बोर्ड की सहायता करते हैं। प्रत्येक निदेशालय को एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) प्रमुख आसूचना और जांच एजेंसी है जो सीमा शुल्क संबंधी धोखाधड़ी और तस्करी से संबंधित आसूचना जानकारी एकत्र करती है और उसका मिलान करती है। इसी तरह, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय को जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर मामलों की जांच का काम सौंपा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण निदेशालय मानव संसाधन विकास निदेशालय (डीजीएचआरडी) है जो सीबीआईसी के सभी मानव संसाधन मामलों को देखता है।

वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन निदेशालय (डीजीएआरएम) बनाया गया। डीजीएआरएम डेटा विश्लेषिकी और डेटा माइनिंग में संलग्न है। डेटा विश्लेषिकी के परिणामों ने बड़ी संख्या में नकली चालान मामलों का पता लगाने और जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद की है।

सीबीआईसी का आदर्श वाक्य "देश सेवार्थ कर संचय" है।

सीबीआईसी के अंतर्गत कार्यरत विभिन्न अनुभागों/स्कंधों और निदेशालयों के कार्यकलापों और कार्य निष्पादन का सारांश दिया गया है

3.2 राजस्व

राशि करोड़ रुपये में

कर शीर्ष	बजट अनुमान 2025-26	अप्रैल-दिसंबर[अनंतिम]			हासिल किए गए 2025- 26 के बजट अनुमान का हासिल हुआ %
		2024-25	2025-26 [अनंतिम]	% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	
सीमा शुल्क (नकद + स्क्रिप)	2,40,000	1,72,294	2,00,533	16.4%	83.6%
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,17,000	2,25,412	2,47,715	9.9%	78.1%
सेवा कर	100	36	-1,186	-3418.1%	
उप-योग (गैर-जीएसटी)	5,57,100	3,97,742	4,47,061	12.4%	80.2%
सीजीएसटी	10,10,890	6,73,256	7,10,615	5.5%	70.3%
आईजीएसटी	-	-31,590	15,641	149.5%	
जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर	1,67,110	1,11,556	89,777	-19.5%	53.7%
उप-जोड़ (जीएसटी)	11,78,000	7,53,222	8,16,034	8.3%	69.3%
कुल निवल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर [जीएसटी + गैर-जीएसटी]	17,35,100	11,50,964	12,63,095	9.7%	72.8%

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सीबीआईसी), ईएमसी एचआरडी; [पी]=अनंतिम; राउंड ऑफ करने के कारण कुल जोड़ में अंतर हो सकता है।

3.3 माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

3.3.1 प्रक्रियात्मक सुधार

- लघु एवं कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना: जीएसटी परिषद ने अपनी 26वीं बैठक में एक सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण स्कीम की सिफारिश की है, जिसके तहत कम जोखिम वाले आवेदकों और उन आवेदकों को, जो अपने आकलन के आधार पर यह निर्धारित करते हैं कि पंजीकृत व्यक्तियों को आपूर्ति पर उनकी उत्पादन कर देयता 2.5 लाख रुपये प्रति माह (सीजीएसटी, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और आईजीएसटी सहित) से अधिक नहीं होगी, आवेदन जमा करने की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर स्वचालित रूप से पंजीकरण प्रदान किया जाएगा यह व्यवस्था दिनांक 1 नवंबर, 2025 से लागू हो चुकी है और सुचारु रूप से कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि एफओआरआईयू पंजीकरण-01 (पंजीकरण दस्तावेज) में संशोधन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इसे उचित समय पर जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से आपूर्ति करने वाले छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण योजना का परिचय: परिषद ने कई राज्यों में ई-कॉमर्स ऑपरेटरों (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाले लघु आपूर्तिकर्ताओं के लिए सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण तंत्र की अवधारणा को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है, जिन्हें जीएसटी ढांचे के तहत वर्तमान में आवश्यक प्रत्येक राज्य में व्यवसाय का मुख्य स्थान बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उक्त योजना को लागू करने के विस्तृत तौर-तरीके जीएसटी परिषद के समक्ष रखे जाएंगे। इससे ऐसे आपूर्तिकर्ताओं के लिए अनुपालन आसान होगा और उन्हें राज्यों में ई-कॉमर्स में भाग लेने में सुविधा मिलेगी।
- शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति (अर्थात् माल या सेवाओं या दोनों का निर्यात या अधिकृत संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर/इकाई को आपूर्ति) के कारण धनवापसी दावों को सुविधाजनक बनाने के लिए जोखिम-आधारित अनंतिम धनवापसी की स्वीकृति: सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 91 2)) में संशोधन किया गया है ताकि रिफंड अधिकारी द्वारा सिस्टम द्वारा जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के आधार पर अनंतिम धनवापसी के रूप में दावा की गई धनवापसी के 90% की स्वीकृति प्रदान की जा सके।
- विलोमित शुल्क संरचना (आईडीएस) से उत्पन्न धनवापसी की जोखिम-आधारित अनंतिम स्वीकृति का प्रस्ताव: परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54(6) में संशोधन करने की भी सिफारिश की है, ताकि विलोमित शुल्क संरचना से उत्पन्न मामलों में अनंतिम आधार पर दावा की गई धनवापसी के

90% की स्वीकृति प्रदान की जा सके, उसी तर्ज पर जैसे वर्तमान में शून्य-रेटेड आपूर्ति के संबंध में धनवापसी के लिए उपलब्ध है।

- कम मूल्य के निर्यात खेपों पर जीएसटी वापसी के लिए सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन: परिषद ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 14(54) में संशोधन की सिफारिश की है ताकि कर भुगतान के साथ किए गए निर्यातों पर लगने वाली सीमा को हटाया जा सके। इससे कूरियर, डाक आदि के माध्यम से निर्यात करने वाले छोटे निर्यातकों को विशेष रूप से सहायता मिलेगी।
- आईजीएसटी अधिनियम की धारा 8) 13) के अंतर्गत मध्यस्थ सेवाओं के लिए आपूर्ति स्थान संबंधी प्रावधानों में संशोधन: परिषद ने आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 8) 13) के खंड (ख) को हटाने की सिफारिश की। तदनुसार, उक्त कानून संशोधन के बाद, "मध्यस्थ सेवाओं" के लिए आपूर्ति स्थान आईजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 2)13) के अंतर्गत डिफॉल्ट प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान। इससे ऐसी सेवाओं के भारतीय निर्यातकों को निर्यात का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

3.3.2 दर युक्तिकरण 56वीं जीएसटी परिषद)

वस्तुएं:

- जीएसटी परिषद ने दिनांक 3 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी 56वीं बैठक में व्यापक दर युक्तिकरण और चार स्तरीय कर दर संरचना के संरचनात्मक सरलीकरण करने की सिफारिश की है। ताकि इसे नागरिक हितैषी 'सरल कर' में परिवर्तित किया जा सके एक दर संरचना जिसमें मानक दर 18% और मेरिट दर 5% है; कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष डीमेरिट दर है। जीएसटी दर युक्तिकरण में मुख्य रूप से आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योग, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जीएसटी स्लैब में वस्तुओं का नया वितरण इस प्रकार है:
- शून्य दर: इसका दायरा काफी बढ़ाया गया है ताकि इसमें सभी व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा, आवश्यक खाद्य पदार्थ (यूएचटी दूध, पनीर, सभी भारतीय ब्रेड जैसे चपाती/रोटी/पराठा), अभ्यास पुस्तिकाएं/नोटबुक, इरेजर, पेंसिल शार्पनर, मानचित्र और 36 जीवन रक्षक दवाएं शामिल हों।
- 5% दर (मेरिट दर): इसमें आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं (बालों का तेल, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल), अधिकांश खाद्य पदार्थों (पैकेज्ड नमकीन, पास्ता, नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, मक्खन, घी), कृषि उत्पादों (ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी), नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों, सभी दवाओं (12% से घटाकर), वस्त्रों, हस्तशिल्प, ₹2,500 तक के जूते-चप्पलों और सौंदर्य स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करने के लिए इसके दायर में व्यापक विस्तार किया गया है।

- 18% (मानक दर): अब इसमें 350 सीसी से कम क्षमता वाली छोटी कारें और मोटरसाइकिलें, टीवी, एसी, डिशवॉशर, सीमेंट, बसें, ट्रक, एम्बुलेंस, ऑटो पार्ट्स, बीड़ी और अधिकांश अन्य सामान और सेवाएं शामिल हैं।
- 40% (डीमेरिट दर): यह चुनिंदो वस्तुओं तक सीमित है, जिनमें लक्जरी कारें, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, बड़ी नौकाएं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए विमान, तंबाकू उत्पाद (बीड़ी को छोड़कर), पान मसाला, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ, कैसीनो/जुआ सेवाएं और इसी तरह की डीमेरिट वाली वस्तुएं शामिल हैं।

यह एक महत्वपूर्ण सरलीकरण को दर्शाता है, जिसमें अधिकांश वस्तुएं अब 5% या 18% के अंतर्गत आती हैं, जबकि 12% की सीमा को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है और 28% की सीमा को केवल सबसे अधिक डीमेरिट वाली वस्तुओं के लिए 40% में पुनर्गठित किया गया है।

सेवाएं:

(1) बीमा सेवाएं

टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडोमेंट पॉलिसी सहित सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से पूर्ण छूट।

सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों (पारिवारिक फ्लोटर और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों सहित) और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी से पूर्ण छूट।

यह कदम आम आदमी के लिए बीमा सेवाओं को अधिक किफायती बनाने और देश में बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

(ii) आम आदमी/ दैनिक उपयोग की सेवाएं

मध्यम वर्ग के लिए बजट यात्रा को बढ़ावा देने हेतु प्रतिदिन ₹7,500 तक की होटल आवास सेवाओं पर आईटीसी सहित 12% से घटाकर आईटीसी सहित 5% कर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सहित आम आदमी द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जीएसटी को आईटीसी सहित 12% से घटाकर आईटीसी सहित 5% कर दिया गया है।

100 रुपये या उससे कम कीमत वाले सिनेमा टिकटों पर जीएसटी (12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

(iii) श्रम प्रधान सेवाएं

फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा और ईंट आदि से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर जीएसटी को कम करके और उन्हें संबंधित वस्तुओं पर लागू दर के साथ संरेखित करके जॉब वर्क सेवाओं पर जीएसटी को सुव्यवस्थित करना।

(iv) पर्यावरण सेवाएँ

- सतत विकास को बढ़ावा देने और उन लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए, जिनके पास अपने स्वयं के उपचार संयंत्र नहीं हो सकते, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की सेवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर आईटीसी सहित 5% कर दिया गया है।

(v) परिवहन क्षेत्र

- हवाई परिवहन को छोड़कर सभी यात्री परिवहन सेवाओं को सीमित आईटीसी सहित 5% की उचित दर पर या पूर्ण आईटीसी सहित 18% की मानक दर पर जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।
- इसी प्रकार, संपूर्ण माल परिवहन क्षेत्र को भी दो दरों का विकल्प दिया गया है: आईटीसी के बिना 5% की मेरिट दर: जीटीए जैसे छोटे ऑपरेटरों के लिए उपयोगी।
- पूर्ण आईटीसी के साथ 18% की मानक दर: बड़े ऑपरेटरों, कंटेनर परिवहन ऑपरेटरों और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्टर्स के लिए उपयोगी।
- माल ढुलाई के तृतीय पक्ष बीमा के लिए आईटीसी सहित 12% से घटाकर आईटीसी सहित 5% तक जीएसटी दर में कमी।

(vi) डीमेरिट/विलासिता सेवाएं 40% की विशेष दर

- कुछ विलासितापूर्ण सेवाओं पर जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% करना, जिनमें शामिल हैं:
- कैसीनो, रेस क्लब, कैसीनो या रेस क्लब वाले किसी भी स्थान, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश के माध्यम से से दी जाने वाली सेवाएं (मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों को छोड़कर)।
- किसी रेस क्लब द्वारा क्लब में सट्टेबाजों के लाइसेंस के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएं
- निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावे (सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग)

(vii) सेवाओं से संबंधित अन्य परिवर्तन

- रेस्तरां सेवाएं निर्दिष्ट परिसर' स्पष्टीकरण: परिषद ने «निर्दिष्ट परिसर» की परिभाषा में स्पष्टीकरण जोड़ने की सिफारिश की है (रेस्तरां सेवाओं की कराधानता के संदर्भ में), यह स्पष्ट करते हुए कि एक स्वतंत्र रेस्तरां स्वयं को «निर्दिष्ट परिसर» घोषित नहीं कर सकता है और इसलिए आईटीसी के साथ 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुन सकता है।
- स्थानीय वितरण सेवाएं: स्थानीय वितरण सेवाओं (एसएसी 9968) के लिए: ईसीओ के माध्यम से (धारा 9(5))

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर (ईसीओ) के माध्यम से स्थानीय वितरण सेवाओं की आपूर्ति को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(5) के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिस पर 18% की लागू जीएसटी दर लागू होगी, और ईसीओ द्वारा और उसके माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी स्थानीय वितरण सेवाओं को जीटीए सेवाओं के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

जीएसटी - अन्वेषण

(क) (सरकार ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए कई प्रभावी उपाय किए हैं, जिसमें माल और या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान के आधार पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की (आईटीसी) समस्या शामिल है। जीएसटी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के अलावा, इससे आयकर संग्रह, बैंक वित्त और मनीलाइटिंग अपराधों को पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। सरकार ने समय समय पर कई उपाय किए हैं, जिसमें जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने और उन पर नज़र रखने तथा कर चोरी का पता लगाने के लिए मजबूत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना और अधिक लक्षित हस्तक्षेपों के लिए साझेदार कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ डेटा साझा करना शामिल है।

इसके अलावा, वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के दौरान जीएसटी चोरी वाले लिए कुल 20,236 आईटीसी धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कुल 37,732.08 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इसी अवधि के दौरान क्रमशः 1202.37 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्ति, इस अवधि के दौरान 146 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

(ख) पारदर्शिता सुनिश्चित करने और प्रवर्तन कार्रवाई को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी प्रवर्तन संबंधी गतिविधियों की निरंतर निगरानी।

(ग) डीजीजीआई मुख्यालय के अपर/संयुक्त निदेशक (आसूचना) को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मध्यस्थों को विदेशी ऑनलाइन जुआ/कैसीनो सेवा प्रदाताओं को ब्लॉक करने के लिए आदेश जारी करने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया था, जो सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अब सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2025 के लागू होने के साथ, ऐसे आदेश जारी करने के लिए अधिकारी के स्तर को अद्यतन करने का मुद्दा राजस्व विभाग के समक्ष उठाया गया है।

(घ) जीएसटीएएम-2019 में उन करदाताओं से निपटने के लिए संशोधन किए गए जो लेखापरीक्षा अनुरोधों का जवाब नहीं देते हैं। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट (आरईए) और कीमती धातुओं और कीमती पत्थरों के डीलर (डीपीएमएस) के ऑन-साइट निरीक्षण के लिए मानक परिचालन (एसओपी) जारी किए गए और कर अधिकारियों द्वारा समन्वित

लेखापरीक्षा के लिए, महानिदेशक लेखा परीक्षा(डीजी ऑडिट) के समन्वय से सीजीएसटी के तहत बहु-स्थानिक इकाइयों की समन्वित लेखापरीक्षा के लिए एक विस्तृत ढांचा जारी किया गया।

(ड) विभिन्न अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली प्रवर्तन कार्रवाई में कर अधिकारियों की समझ को सुगम बनाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए राजस्व विभाग द्वारा राज्य और केंद्रीय जीएसटी संरचनाओं के प्रवर्तन प्रमुखों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारियों के बीच सहयोग को मजबूत करने के अलावा खामियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने, मजबूत डेटा विश्लेषण के महत्व और करदाताओं के अधिकारों के साथ प्रवर्तन को संतुलित करने पर जोर दिया गया।

(घ) पारदर्शिता लाने से संबंधित सरकारी नीतियों के अनुरूप, जीएसटी पोर्टल से जारी किए गए पत्राचार पर उत्पन्न संदर्भ संख्या (आरएफएन) और सीबीआईसी के ई-ऑफिस के लिए जारी किए गए संचार पर उत्पन्न जारी संख्या को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने योग्य बना दिया गया है।

3.5 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (सीएक्स-1)

जीएसटी के तहत बजटीय सहायता योजना को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था और इसे सीबीआईसी में सीएक्स विंग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें हिमालयी राज्य (जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा) शामिल हैं। यह पूर्ववर्ती क्षेत्र-आधारित छूट योजना के तहत पात्र इकाइयों को बजटीय सहायता प्रदान करता है और वे पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क कराधान व्यवस्था में संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना के तहत लाभ उठा रहा था।

दिनांक 2 अक्टूबर से दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 की अवधि के दौरान स्वच्छता के लिए विशेष अभियान-3 के दौरान सीएक्स और एसटी विंग की लगभग 5731 फाइलों को स्कैन किया गया है और सीएसएमओपी के दिशानिर्देशों के तहत जल्द ही छंटाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके अलावा सफाई अभियान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैप और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को पहले ही हटा दिया गया है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर विभाग (सीबीआईसी) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मामलों के लंबित पुराने न्यायनिर्णय मामलों की निरंतर समीक्षा कर रहा है। इस विभाग द्वारा सभी जोनों के प्रदर्शन पर कड़ी

निगरानी रखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.12.2025 तक) में 11,000 से अधिक पुराने न्यायनिर्णय वाले मामलों का निपटारा किया गया है।

मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान, स्कंधों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ/परिपत्र/निर्देश निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या एवं तिथि	विषय
1	02/2025 - केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक - 8 अप्रैल 2025	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31ए के तहत निपटान हेतु अंतरिम बोर्ड का गठन
क्रम संख्या	आदेश संख्या	विषय
1.	आदेश संख्या 02/2025 दिनांक: 7 अप्रैल 2025	कोलकाता जोन में लंबित अपीलों का पुनः आवंटन
2.	आदेश संख्या 03/2025 दिनांक: 8 अप्रैल 2025	अंतरिम निपटान बोर्डों को लागू करने के लिए कार्यालय की स्थापना
3.	आदेश संख्या 04/2025 दिनांक: 28 अप्रैल 2025	कोलकाता जोन में लंबित अपीलों का पुनः आवंटन
4.	आदेश संख्या 05/2025 दिनांक: 9 सितंबर 2025	नागपुर जोन में लंबित अपीलों का पुनः आवंटन
5.	आदेश संख्या 06/2025 दिनांक: 28 नवंबर 2025	बेंगलुरु जोन में लंबित अपीलों का पुनः आवंटन

3.6 सीमा शुल्क

- अनंतिम मूल्यांकन विनियम 2025 (अधिसूचना 55/2025-सीमा शुल्क (एनटी) 12.09.2025): सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन का फाइनल करना) विनियम, 2025 को पेश किया गया और यह दिनांक 12 सितंबर, 2025 से प्रभावी हो गया। इन विनियमों ने पूर्ववर्ती सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन का फाइनल करना) विनियम, 2018 का स्थान ले लिया। इन विनियमों का उद्देश्य अनंतिम आकलन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूर्वानुमानशीलता और दक्षता लाना है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से लंबी देरी होती रही है।
- मंजूरी के बाद प्रविष्टियों का संशोधन: - सीबीआईसी ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 के परिपत्र संख्या 26/2025 सीमा शुल्क के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18क के तहत मंजूरी के बाद प्रविष्टियों के संशोधन के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। धारा 18क के प्रावधान, जो वित्त अधिनियम, 2025 की धारा 93 के माध्यम से जोड़े गए हैं, सीमा शुल्क मंजूरी मिलने के बाद वस्तुओं से संबंधित पहले से की गई प्रविष्टियों के संशोधन की सुविधा प्रदान करते हैं। सीमा शुल्क (निकासी के बाद प्रविष्टियों का स्वैच्छिक संशोधन) विनियम, 2025 भी इस संबंध में दिनांक 30.10.2025 के अधिसूचना 70/2025-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से जारी किए गए हैं।
- आईएफएससी कोड पंजीकरण के लिए सिस्टम आधारित स्वचालित अनुमोदन (परिपत्र संख्या 24/2025) - व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सीबीआईसी ने आईएफएससी कोड पंजीकरण के लिए सिस्टम आधारित स्वचालित अनुमोदन शुरू किया है। इस

नई पहल के अनुसार, सिस्टम एक ही आयात-निर्यातक कोड (आईईसी) के लिए एक ही प्रोत्साहन बैंक खाते और आईएफएससी कोड के पंजीकरण के अनुरोधों को कई सीमा शुल्क स्थानों पर स्वचालित रूप से अनुमोदित करेगा, बशर्ते कि यही संयोजन पहले से ही किसी एक स्थान पर अनुमोदित हो चुका हो। इस प्रकार, बंदरगाह अधिकारी के मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और सिस्टम सीधे ऐसे अनुरोधों को मंजूरी दे देगा।

- आईसीईटीएबी के उपयोग को लागू करना: - देश भर में आयात जांच के लिए आईसीईटीएबी के सफल उपयोग को देखते हुए, सीबीआईसी ने दिनांक 19.06.2025 से निर्यात जांच और मंजूरी में भी आईसीईटीएबी के उपयोग का विस्तार किया है। इस संबंध में, सीबीआईसी ने दिनांक 19.06.2025 को परिपत्र संख्या 17/25 सीमा शुल्क जारी किया है।
- संस्थागत परामर्श तंत्रों के माध्यम से व्यापार सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए, बोर्ड ने दिनांक 12 सितंबर, 2025 को परिपत्र संख्या 21/2025-सीमा शुल्क जारी किया। परिपत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं - व्यापार सुविधा को बढ़ाना; सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति (सीसीएफसी) और स्थायी व्यापार सुविधा समिति (पीटीएफसी) के माध्यम से सीमा शुल्क निकासी कार्य संभालने वाले सभी हितधारकों की बढ़ी हुई भागीदारी को सुनिश्चित करना; और व्यापारिक शिकायतों का समयबद्ध और कुशल तरीके से समाधान करना। परिपत्र में तुरंत सुविधा केंद्रों (टीएसके) और राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रों (एनएसी) के संपर्क विवरण भी दिए गए हैं, जो ईओडीबी की दिशा में एक और कदम है।
- सीबीआईसी ने दिनांक 26-11-2025 को "व्यापार सुविधा और

लैंगिक समानता" पर एक टीम का पुनर्गठन किया। इस टीम में सीबीआईसी के वे अधिकारी शामिल हैं जिनके पास इस प्रमुख क्षेत्र में विशेषज्ञता है और जिन्हें परिचालन स्तर पर लैंगिक समानता को मुख्यधारा में लाने की पहलों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सीबीआईसी ने दिनांक 26-11-2025 को अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जागरूक किया ताकि देर रात तक काम करने वाली या दूरदराज के स्थानों पर काम करने वाली महिलाओं के लिए सुविधाजनक कार्य घंटे और सुरक्षित परिवहन विकल्प सुनिश्चित किए जा सकें।
- प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और एक ही सी.टी.एच. के तहत एक ही वस्तु/आइटम के आयात के लिए विभिन्न बिल ऑफ एंट्री के साथ एक समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी) को जोखिम उपचार प्रक्रिया की समीक्षा करने और आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करने का कार्य सौंपा गया है।
- जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण में गेट स्वचालन - जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) में, केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा (सीपीपी) में स्व-सीलबंद निर्यात कंटेनरों के लिए गेट स्वचालन को आंशिक रूप से लागू किया गया है। प्रमुख उपलब्धि सीपीपी प्रवेश द्वारों पर यूनिवर्सल ई-सील रीडर्स की सफल तैनाती है, जो एपीआई के माध्यम से आईसीगेट के साथ एकीकृत हैं। यह सिस्टम कंटेनरों पर लगे आरएफआईडी टैग को पढ़ता है और उसी समय डेटा को मान्य करता है, जिससे मैनुअल स्कैनिंग और प्रवेश द्वार पर सीमा शुल्क अधिकारी के हस्तक्षेप की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- सहभागी सरकारी एजेंसियों द्वारा सुगम्यीकरण - सहभागी सरकारी एजेंसियों द्वारा सुगम्यीकरण में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) ने अधिकृत आर्थिक संचालकों (ईओ) को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है, और बेहतर सुगम्यीकरण के लिए विश्वसनीय और अनुपालनशील खाद्य आयातकों की पहचान करने का कार्य जारी है। इसी प्रकार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने आरएमएस में नए चयनात्मक मानदंड विकसित किए हैं। इससे सुगमता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सीडीएससीओ और एफएसएसआई के मामले में सुगमता के स्तर में सुधार देखा गया है। यह सकारात्मक रुझान पीजीए द्वारा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विश्वसनीय हितधारकों को प्राथमिकता देने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे विलंब कम होता है और समग्र व्यापार दक्षता में सुधार होता है।
- स्विफ्ट 2.0 एकीकरण – वर्ष 2024-2027 के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफपी 3.0) के कार्यान्वयन के भाग

के रूप में, व्यापार सुविधा के लिए उन्नत सिंगल विंडो इंटरफेस (स्विफ्ट 2.0) के साथ सहभागी सरकारी एजेंसियों (पीजीए) का एकीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में पहचाना गया है। स्विफ्ट 2.0 को माल की निकासी के लिए आवश्यक लाइसेंस, परमिट, प्रमाणपत्र और अन्य प्राधिकरणों की संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप कम होता है और दक्षता में सुधार होता है। इस प्लेटफॉर्म ने पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली है, जिसमें कई पीजीए को पायलट कार्यान्वयन के लिए शामिल किया गया है और चुनिंदा एजेंसियों के लिए सिंगल साइन-ऑन, यूनिफाइड डैशबोर्ड और एनओसी जारी करने के लिए यूनिफाइड एप्लिकेशन जैसी मुख्य कार्यक्षमताएं अब चालू हो गई हैं। ये प्रगति व्यापार को सुगम बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने, देरी कम करने और व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने के लिए एक सहज, प्रौद्योगिकी-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। स्विफ्ट 2.0 का पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन वर्ष 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है।

- ईएक्सआईएम (एकिजम) ट्रेड- द्वारा अनुपालन में सुगमता - केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने गैर-टैरिफ उपायों (एनटीएम) को संकलित किया है और सत्यापन के लिए उन्हें पीजीए के साथ साझा किया है, जिससे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11(3) के तहत अधिसूचना जारी करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन कदमों का सामूहिक उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, देरी को कम करना और व्यापार सुविधा को मजबूत करना है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के अधिसूचना संख्या 21/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.) के माध्यम से निर्यात प्रविष्टि (इंस्ट्रूमेंट आधारित योजना के संबंध में निर्यात पश्चात रूपांतरण) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया है, और इसके साथ ही पूर्ववर्ती निर्यात पश्चात (शिपिंग बिल (इंस्ट्रूमेंट आधारित योजना के संबंध में निर्यात पश्चात रूपांतरण विनियम, 2022) को निरस्त कर दिया है, जिसे अधिसूचना संख्या 11/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.) द्वारा जारी किया गया था। ये विनियम शिपिंग बिल/निर्यात प्रविष्टियों के निर्यात पश्चात या निकासी पश्चात संशोधन के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिससे शिपिंग बिलों को अन्य पात्र इंस्ट्रूमेंट-आधारित योजनाओं में परिवर्तित किया जा सके और निर्यात संबंधी लाभ प्राप्त किए जा सकें। यह उपाय भारत सरकार की व्यापार सुगमता और व्यापार करने में आसानी की पहल के तहत शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को उचित लाभ पहुंचाना है।
- केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के परिपत्र संख्या 11/2025-सीमा शुल्क के माध्यम से अधिसूचना संख्या 21/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.)

- दिनांक 3 अप्रैल, 2025 के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें निर्यात प्रविष्टि (लिखित आधारित स्कीम के संबंध में निर्यात पश्चात रूपांतरण) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है। उक्त परिपत्र का उद्देश्य उपरोक्त विनियमों के दायरे और उद्देश्य को स्पष्ट करना और सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों तथा व्यापार जगत को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे सरकार के व्यापार सुगमीकरण उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एकसमान समझ और प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके।
- डाक आयात विनियम 2025 को दिनांक 28.03.2025 की अधिसूचना संख्या 18/2025 - सीमा शुल्क (एन.टी.) के माध्यम से डाक आयात के संबंध में तैयार/जारी किया गया है, जिससे सभी डाक आयातों के लिए समान विनियम बनाए गए हैं।
 - दिनांक 15.11.2025 के परिपत्र संख्या 28/2025-सीमा शुल्क के माध्यम से, सीबीआईसी ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 58/58ए के तहत लाइसेंस प्राप्त गोदामों के लिए धारा 65 (एमओओडब्ल्यूआर, 2019 और एमओओएसडब्ल्यूआर, 2020) के तहत अनुमतियों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित/सरल बनाने हेतु आईसीईजीएटीई 2.0 पर एक समर्पित ऑनलाइन मॉड्यूल को चालू किया है।
 - सीबीआईसी ने दिनांक 18.03.2025 की अधिसूचना संख्या 14/2025-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 में संशोधन किया और "उत्पत्ति प्रमाण पत्र" शब्द को "उत्पत्ति का प्रमाण" से प्रतिस्थापित किया। उक्त संशोधनों की व्याख्या करते हुए दिनांक 21.04.2025 का परिपत्र संख्या 14/2025-सीमा शुल्क भी जारी किया गया है।
 - भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और ईरान के इस्लामी गणराज्य सीमा शुल्क प्रशासन (आईआरआईसीए) के बीच सीमा शुल्क सहयोग पर द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 08.05.2025 को भारत गणराज्य की ओर से सीबीआईआईसी के अध्यक्ष श्री संजय कुमार अग्रवाल और ईरान के इस्लामी गणराज्य सीमा शुल्क प्रशासन के उप मंत्री और एच.ई. श्री फरौद असगरी ने हस्ताक्षर किए।
 - भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के मूल नियमों (अनुलग्नक 2.ए) और इसके परिशिष्टों को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 29.09.2025 की अधिसूचना संख्या 59/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.) जारी की गई। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 5 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (भारत और ईएफटीए राज्यों के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत वस्तु की उत्पत्ति का निर्धारण) नियम, 2025 बनाया गया है।
 - भारत गणराज्य के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) और रूस गणराज्य की संघीय सीमा शुल्क सेवा के बीच माल एवं वाहनों के आवागमन से संबंधित पूर्व-आगमन सूचना के आदान-प्रदान में सहयोग हेतु प्रोटोकॉल पर दिनांक 04.12.2025 को भारत गणराज्य की ओर से सीबीआईआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी और रूस की संघीय सीमा शुल्क सेवा की उप प्रमुख सुश्री तातियाना मर्कुशोवा ने हस्ताक्षर किए।
 - सीमा शुल्क मामलों में सहयोग एवं पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर भारत गणराज्य और इथियोपिया गणराज्य के बीच समझौते पर दिनांक 16.12.2025 को भारत गणराज्य की ओर से विदेश मंत्रालय के सचिव (आर्थिक संबंध) श्री सुधाकर दलेला और इथियोपिया के विदेश मामलों के राज्य मंत्री श्री हदेरा अबेरा ने हस्ताक्षर किए।
 - भारत की ओर से सीबीआईसी द्वारा टीआईआर कार्यकारी बोर्ड (टीआईआरएक्सबी) में चुनाव प्रक्रिया में संशोधन करने का प्रस्ताव, जिसमें 'मतों का खुलासा' अनिवार्य किया जाना था, यूएनईसीई के तत्वावधान में 5 और 6 फरवरी 2025 को जिनेवा में आयोजित टीआईआर प्रशासनिक समिति के 85वें सत्र के दौरान उपस्थित और मतदान करने वाले सभी 64 देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मतों के खुलासे का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और टीआईआर कार्नेट के अंतर्गत माल के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पर सीमा शुल्क सम्मेलन (टीआईआर सम्मेलन), 1972 के सदस्य देशों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। भारत के प्रस्ताव की सर्वसम्मति से स्वीकृति एक कूटनीतिक जीत है और अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों में भारत के प्रभाव और बहुपक्षीय समझौतों में पारदर्शिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुशासन, पारदर्शिता और दक्षता के लिए सीबीआईसी के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है, जो वैश्विक व्यापार और परिवहन सुविधा में भारत की नेतृत्व भूमिका को मजबूत करता है।
 - सीमा शुल्क सहयोग पर 21वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता भारत और नेपाल के बीच 10-11 अप्रैल, 2025 को काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सीमा शुल्क सहयोग बढ़ाने के लिए कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सक्रिय भागीदारी और आसूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सीमा पार तस्करी को रोकने में सहयोग की उम्मीद जताई और अनधिकृत व्यापार को नियंत्रित करने और मिलकर काम करने के लिए आवश्यक उपाय करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के एजेंडे में तस्करी पर रोक लगाने के उपाय; सीमा शुल्क डेटा के पूर्व-आगमन आदान-प्रदान और इलेक्ट्रॉनिक मूल डेटा विनियम प्रणाली (ईओडीईएस) पर समझौता ज्ञापन की प्रगति की समीक्षा; सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौते (सीएमए) को अंतिम रूप देना; इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) के

तहत पारगमन कार्गो की आवाजाही को सुगम बनाना; पारगमन प्रक्रियाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण; सीमा अवसंरचना का उन्नयन; ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम और क्षमता विकास के लिए समर्थन आदि अन्य उपाय शामिल थे। सीमा पार आपराधिक गतिविधियों और सोने, नशीले पदार्थों की तस्करी से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नकली करेंसी नोट (एफसीएन), प्रतिबंधित/सीमित श्रेणी की वस्तुएं जैसे ई-सिगरेट, ई-लाइटर, लहसुन की कुछ किस्में और संवेदनशील वस्तुओं सहित वाणिज्यिक धोखाधड़ी के अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। नेपाल ने ज्ञान साझा करने और क्षमता संवर्धन कार्यक्रमों के लिए भारत/सीबीआईसी के प्रति आभार व्यक्त किया।

- भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क के संयुक्त समूह (जेजीसी) की छठी बैठक 24-25 अप्रैल, 2025 को भूटान के थिम्फू में आयोजित की गई। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार और पारगमन को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पारगमन प्रक्रियाओं का स्वचालन और डिजिटलीकरण, समन्वित सीमा प्रबंधन (सीबीएम), आगमन से पहले सीमा शुल्क डेटा का आदान-प्रदान, सीमा शुल्क पारस्परिक सहायता समझौता (सीएमएए) और इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रेकिंग सिस्टम (ईसीटीएस) के तहत पारगमन कार्गो की आवाजाही आदि पर चर्चा की गई। भूटानी पक्ष ने सीबीआईसी को उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया, विशेष रूप से 29 जुलाई से 1 अगस्त, 2024 तक आयोजित 'भारत-भूटान व्यापार और आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ाना' शीर्षक वाली क्षमता-निर्माण कार्यशाला को मान्यता दी, जिसने निर्यात प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और व्यापार संबंधी चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- ईसीटीएस कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग और लाइव जीपीएस ट्रेकिंग के साथ कार्गो आवागमन की निगरानी की सुविधा देता है। यह सील की अखंडता की उसी समय निगरानी और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तत्काल हस्तक्षेप को भी सक्षम बनाता है। इसमें पूर्व निर्धारित अंतरालों पर स्थिति, गति और सील की अखंडता के बारे में उसी समय जानकारी प्रदान करने की कार्यक्षमता है, साथ ही पूर्व निर्धारित जोखिम मापदंडों जैसे छेड़छाड़ का प्रयास, विशिष्ट मार्गों से विचलन आदि के आधार पर अलर्ट उत्पन्न करने का प्रावधान भी है। यह न केवल सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करता है बल्कि लॉजिस्टिक्स दक्षता पर मूल्यवान डेटा भी प्रदान करता है।
- जयगांव लैंड कस्टम्स स्टेशन ने एनटीआरएस (नेशनल टाइम रिलीज स्टडी), 2025 में भूमि सीमा चौकियों के बीच एक राष्ट्रीय मानक स्थापित किया है। जयगांव एलसीएस ने आयात और निर्यात दोनों प्रकार के कार्गो के लिए असाधारण रूप से कम औसत वाला रिलीज टाइम (एआरटी) हासिल किया है। यह एकीकृत चेक पोस्टों पर देखे गए आयात और निर्यात कार्गो के लिए उच्च प्रतीक्षा समय

के बिल्कुल विपरीत है। इसका श्रेय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन पर भारतीय सीमा शुल्क द्वारा उच्च सुविधा दर, स्वचालन और आधुनिक प्रक्रियाओं को अपनाने को जाता है।

- दिनांक 04.11.2025 की अधिसूचना संख्या 73/2025-सीमा शुल्क (एन.टी.) के माध्यम से भारत में कोलकाता, हल्दिया और विशाखापत्तनम बंदरगाहों से माल की दुलाई को रेल द्वारा भारत में भारतीय सीमा शुल्क यार्ड, जोगबानी तक और भारतीय सीमा शुल्क यार्ड, जोगबानी से नेपाल में बीरतनगर तक सड़क मार्ग से अधिसूचित करने के लिए जारी किया गया है।

3.7 आयुक्त (अन्वेषण) (सीमा शुल्क), सीबीआईसी

सीबीआईसी के आयुक्त (अन्वेषण) (सीमा शुल्क) का कार्यालय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, अभियोजन और अपराधों के शमन से संबंधित नीतिगत मामलों से संबंधित मामलों को देखता है (सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय XIII, XIV और XVI से संबंधित सभी विधायी मामले)। यह कार्यालय सोना और स्वापक सहित विभिन्न जब्त और जब्त किए गए सामानों के निपटान, एमएलएटी अनुरोध, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिकारियों के अभियोजन, राष्ट्रपति पुरस्कार, अधिकारियों और मुखबिरों को पुरस्कार, एनसीओआरडी, चुनाव मामलों और सीबीआईसी में एफएटीएफ सेल से संबंधित मामलों को भी देखता है।

निम्नलिखित निर्देश/परिपत्र जारी किए गए:

निर्देश संख्या 10/2025-सीमा शुल्क:- इस कार्यालय ने दिनांक 13.05.2025 को निर्देश संख्या 10/2025 सीमा शुल्क जारी किया, जिसमें गिरफ्तारी रिपोर्ट और घटना रिपोर्ट (उन मामलों में जहां कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है) के लिए संशोधित प्रारूपों में डिजिट प्रविष्टि विवरण (सीमा शुल्क अपराध डेटाबेस) निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके साथ-साथ सीमा शुल्क क्षेत्रों से प्राप्त मासिक मिलान रिपोर्ट ने आगे के रुझान विश्लेषण के लिए एक प्रभावी डिजिटल अपराध डेटाबेस सुनिश्चित किया है।

निर्देश संख्या 12/2025-सीमा शुल्क:- इस कार्यालय ने राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और सीमा शुल्क क्षेत्र इकाइयों द्वारा लाल चंदन के निपटान की प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 22.05.2025 को निर्देश संख्या 12/2025-सीमा शुल्क जारी किया ताकि लाल चंदन के निपटान में तेजी लाई जा सके।

परिपत्र संख्या 13/2025-सीमा शुल्क:- इस कार्यालय ने दिनांक 23.09.2025 को परिपत्र संख्या 23/2025-सीमा शुल्क जारी किया, जिसमें विभाग के कामकाज को सुचारु बनाने के लिए ई-ऑफिस के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए संचार की विशिष्ट संख्या को दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) माना गया।

निर्देश संख्या 30/2025-सीमा शुल्क:- इस कार्यालय ने निर्देश संख्या 30/2025 दिनांक 13.10.2025 जारी किया, जिसमें डीआरआई,

डीजीजीआई और सीमा शुल्क एवं जीएसटी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संबंधित नोडल अधिकारियों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने के लिए दिशा-निर्देशों की रूपरेखा दी गई है।

विशेष अनुमति याचिका

3.8 सीएक्स-8क/विधिक प्रकोष्ठ, सीबीआईसी

वर्ष 2025-26 के दौरान संपन्न किए गए कार्यों की महत्वपूर्ण

मदें:

प्रस्ताव प्राप्त हुआ	दायर की गई विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी)	कोई एसएलपी नहीं	वापस की गई	स्थानांतरित
238	128	41	4	0

वरिष्ठ/कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता/एसपीपी/विशेष अधिवक्ता/विशेष शुल्क अधिवक्ताओं की नियुक्ति

अधिवक्ताओं की श्रेणी	कुल प्रस्ताव (अधिवक्ताओं की संख्या)	संसाधित प्रस्ताव (अधिवक्ताओं की संख्या)	नियुक्त
वरिष्ठ/कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ता	2 (39)	2 (39)	487
विशेष लोक अभियोजक	9 (94)	9 (93)	77
विशेष अधिवक्ता	-	-	-
विशेष शुल्क अधिवक्ता	3 (3)	3 (3)	3

प्राधिकार

प्राधिकार-पत्र के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या	प्रक्रियान्वित प्राधिकारों की संख्या	जारी किए गए प्रधिकार-पत्रों की संख्या
3210	3210	3204

3.9 मानव संसाधन विकास महानिदेशालय (डीजीएचआरडी)

से दिनांक 25.11.2025 तक 308.83 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

3.9.1 डीजीएचआरडी – अवसंरचना प्रभाग

1. सीबीआईसी में अवसंरचना विकास मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजीगत शीर्षों (4059 और 4216) के अंतर्गत 773.25 करोड़ रुपये के कुल बजटीय अनुमान में

2. दिनांक 25.11.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत/जारी/पूर्ण की गई प्रमुख अवसंरचना प्रस्तावा

क्र.सं.	क्षेत्र/निदेशालय	संक्षेप में प्रस्ताव	कुल लागत (करोड़ रुपए में)
1	मुंबई जोन-1 सीमा शुल्क	कस्टम्स एन्क्लेव प्लॉट, वडाला, मुंबई में कार्यालय परिसर और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	975.72
2	नासिन	हिंदूपुर, पलासमुंद्रम (आंध्र प्रदेश) में नए नासिन कॉम्प्लेक्स का निर्माण * दिनांक 16.01.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। परियोजना पूरी होने की संभावित तिथि दिसम्बर, 2025 थी।	840.86
3	हैदराबाद सीजीएसटी	खाजागुडा गांव, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद में कार्यालय भवन (भूतल+28 मंजिला) एवं आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	644.63
4	गुवाहाटी सीजीएसटी	सीजीएसटी शिलांग, सीमा शुल्क (एनईआर) शिलांग, सीजीएसटी लेखा परीक्षा समिति और नासिन शिलांग के लिए कार्यालय भवन और आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	256.63
5	मेरठ सीजीएसटी	गाजियाबाद में सीजीएसटी गाजियाबाद और ऑडिट-II के लिए कार्यालय भवन का निर्माण परियोजना का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 24.10.2025 को किया गया।	116.42
6	डीआरआई	वसंत कुंज, दिल्ली में डीआरआई (मुख्यालय) कार्यालय भवन का निर्माण परियोजना का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 03.06.2025 को किया गया।	99.39
7	चेन्नई सीमा शुल्क	चेन्नई सीमा शुल्क लेखा परीक्षा और आयात समिति तथा साझेदार सरकारी एजेंसियों के लिए जाफर सियारंग स्ट्रीट, चेन्नई में कार्यालय आवास भवन का निर्माण।	91.64

8	मुंबई -II सीमा शुल्क	जेएनसीएच, न्हावा शेवा, जिला रायगढ़, मुंबई में अतिरिक्त कार्यालय भवन (भूतल+7 मंजिल) का निर्माण	80.60
9	चेन्नई सीमा शुल्क	नुंगमबक्कम, चेन्नई में 36 आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	65.42
10	डीआरआई	कोलकाता में डीआरआई कार्यालय भवन का निर्माण परियोजना का उद्घाटन सदस्य (सीबीआईसी) द्वारा दिनांक 12.02.2025 को किया गया।	64.50
11	नासिन हैदराबाद	हैदराबाद के अट्टापुर में आरटीआई, नासिन का निर्माण (एनबीसीसी परियोजना)	46.71
12	पुणे सीजीएसटी	कोल्हापुर के ताराबाई पार्क में सीजीएसटी आयुक्तालय कोल्हापुर के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	42.44
13	हैदराबाद सीजीएसटी	हैदराबाद के ममीडिपल्ली में हैदराबाद कस्टम कमिश्नरेट के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।	44.62
14	डीआरआई अहमदाबाद	राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण	39.86
15	डीआरआई	प्लॉट नंबर 07/13-बी-2, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ में डीआरआई लखनऊ जोनल यूनिट कार्यालय का निर्माण	36.68
16	विशाखापत्तनम सीजीएसटी	तिरुपति में कार्यालय भवन का निर्माण	36.11
17	डीआरआई	ट्रस्टपुरम कोडाम्बक्कम, चेन्नई में डीआरआई जोनल यूनिट के कार्यालय भवन का निर्माण	31.38
18	सीजीएसटी गुवाहाटी	इम्फाल के लाम्फेल में कार्यालय भवन और चारदीवारी का निर्माण	30.08
19	डीआरआई	हैदराबाद में जुबली हिल्स में डीआरआई हैदराबाद जोनल यूनिट के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	24.14
20	सीमा शुल्क अहमदाबाद	जामनगर में स्टाफ क्वार्टर का निर्माण दिनांक 28.03.2025 को प्रस्ताव का उद्घाटन किया गया।	19.42
21	सीजीएसटी लखनऊ	अलीगढ़ में सीजीएसटी प्रभाग के लिए नए कार्यालय भवन का निर्माण।	13.08
22	सीमा शुल्क (निवारक) दिल्ली	कस्टम स्टाफ, लेह, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लिए कार्यालय सह आवासीय भवन का निर्माण	12.83

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि

वर्ष के दौरान कल्याण प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य/प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य निष्पादन और उपलब्धियां:

सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि के तत्वावधान में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का संपूर्ण संशोधन कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद न केवल योजनाओं को समय के साथ अद्यतन और युक्तिसंगत बनाया गया है, बल्कि योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि में भी व्यक्तियों के लाभ के लिए लक्षित योजनाओं और साथ ही आम सुविधाओं की स्थापना के लिए ऊर्जा कुशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी गैजेट/वस्तुओं की अधिप्राप्ति के मामले में पर्याप्त वृद्धि की गई है। प्रमुख योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:-

• चिकित्सा सहायता:

विभागीय अधिकारियों द्वारा स्वयं तथा आश्रित परिवार पर किए गए चिकित्सा व्यय के उस भाग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

की जाती है, जिसकी प्रतिपूर्ति सीजीएस/सीएस (एमए) नियमों के अंतर्गत नहीं की जा सकती।

स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2025 तक 179 विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल 1,39,15,900/- रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

• मृतक अधिकारियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता:

सेवा के दौरान विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके शोक संतप्त परिवारों को अनुग्रह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

दिशानिर्देशों में संशोधन के बाद दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता 7.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.0 लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें ड्यूटी के दौरान कोविड-19 के कारण विभागीय

अधिकारियों की मृत्यु के मामलों में 7 लाख रुपये का विशेष प्रावधान भी शामिल है।

इस स्कीम के तहत दिनांक 25.11.2025 तक विभागीय अधिकारियों के 42 शोक संतप्त परिवारों को 2,07,00,000/- रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।

- **विभागीय कैंटीनों/रसोई घरों की स्थापना/नवीनीकरण:**

सीबीआईसी के तहत विभागीय कैंटीन/रसोईघरों की स्थापना/नवीनीकरण के लिए कल्याण कोष से सहायता प्रदान की जाती है।

- **विभागीय अतिथि गृहों की स्थापना/नवीनीकरण:**

सीबीआईसी के तहत विभागीय अतिथि गृहों की स्थापना/नवीनीकरण के लिए कल्याण निधि से सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 25.11.2025 तक 54,77,223/- रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए 4 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

- **साहसिक खेलों को बढ़ावा:**

विभिन्न आउटडोर साहसिक खेलों/गतिविधियों जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, साहसिक शिविर/गतिविधि/पाठ्यक्रम, वाटर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, हॉट एयर बैलूनरिंग, व्हाइट वाटर राफ्टिंग आदि में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

- **खेलों में पदक/नागरिक पुरस्कार जीतने पर नकद पुरस्कार और खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए सहायता:**

खेलों में पदक/नागरिक पुरस्कार जीतने पर नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, साथ ही कल्याण निधि से खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

दिशा-निर्देशों में संशोधन के बाद अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों/प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर दी जाने वाली राशि में कई गुना वृद्धि की गई है और अब यह खेल एवं युवा मामले मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली राशि के बराबर है।

- **विभागीय व्यायामशाला(जिम)/मनोरंजन/खेल केन्द्रों की स्थापना/नवीनीकरण:**

सीबीआईसी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा विभागीय व्यायामशाला/मनोरंजन/खेल केन्द्रों की स्थापना/नवीनीकरण के लिए कल्याण निधि से सहायता प्रदान की जाती है।

6 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए दिनांक 25.11.2025 की स्थिति के अनुसार 48,16,812/- रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- **शिशुगृह सुविधाओं की स्थापना/नवीनीकरण:**

सीबीआईसी के तहत आने वाले संस्थानों द्वारा शिशुगृहों सुविधाओं की स्थापना/नवीनीकरण के लिए कल्याण निधि से सहायता प्रदान की जाती है।

दिनांक 25.11.2025 तक 19,76,619/- रुपये की कुल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 4 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

- **कोविड-19 से लड़ने के लिए निवारक और कल्याणकारी उपाय:**

कोविड-19 से लड़ने के लिए निवारक और कल्याणकारी उपाय करने हेतु सीबीआईसी के तहत संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

- **समूह 'ख' और समूह 'ग' अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच:**

कल्याण कोष से 40 वर्ष या उससे अधिक आयु के समूह 'ख' और समूह 'ग' अधिकारियों के लिए वार्षिक चिकित्सा जांच के वित्तपोषण की योजना शुरू की गई है।

दिनांक 25.11.2025 तक 234 प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए कुल 4,70,008/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

- **जेएनसीएच, न्हावा शेवा, रायगढ़ में तैनात कर्मचारियों के लिए रियायती परिवहन सुविधा के लिए वित्तीय सहायता**

इस योजना के अंतर्गत, जेएनसीएच, न्हावा शेवा, रायगढ़ में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए सब्सिडीयुक्त परिवहन सुविधा के आंशिक वित्तपोषण के लिए दिनांक 25.11.2025 तक कुल 6,17,836/- रुपये की राशि सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि के शासी निकाय द्वारा स्वीकृत की गई है।

- **जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सहायता:**

विभागीय अधिकारियों के जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) या उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सीबीआईसी द्वारा सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि के माध्यम से एक कल्याणकारी योजना शुरू की गई है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ईएमसी का प्रदर्शन:

- बजट अनुमान 2025-26 में सीबीआईसी को 12054.08 करोड़

रुपये का बजट आवंटित किया गया था, (स्क्रिप-बेस्ड स्कीमों को छोड़कर) और दिनांक 25.11.2025 तक 7758.77 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो निधि के 64.37% उपयोग को दर्शाता है।

(करोड़ रु. में) विवरण	कुल बजट (बजट अनुमान)	दिनांक 25.11.2025 तक व्यय	% उपयोग	शेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय
	1	2	3	4
कुल बजट और व्यय (स्क्रिप-आधारित स्कीमों सहित)	42889.33	22969.72	53.56 %	18526.39
कुल उपलब्ध बजट और 68 बजटीय प्राधिकरण का व्यय (स्क्रिप-आधारित स्कीमों को छोड़कर)	12054.08	7758.77	64.37 %	5034.84

- क्षेत्रीय कार्यालयों और मंत्रालय के अलग-अलग मंजूरी आदेशों के अनुरोध के अनुसार दिनांक 25.11.2025 को 774.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि जारी किया गया, ताकि क्षेत्रीय कार्यालय इन निधियों का इस्तेमाल अपनी तत्काल आवश्यकता के लिए कर सकें।
- आरबीई 2025-26 और बीई 2026-27 के प्रस्ताव को क्षेत्रीय कार्यालयों की आवश्यकताओं के आधार पर अंतिम रूप दिया गया और इसे आईएफयू/मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।
- बजट अनुमान 2025-26 में स्क्रिप-आधारित योजनाओं के लिए 30835.25 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था और दिनांक 25.11.2025 तक 15210.95 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो निधियों के 49.33% उपयोग को दर्शाता है।
- स्क्रिप-आधारित योजनाओं के संबंध में 15210.95 करोड़ रुपये के 29 मंजूरी आदेश जारी किए गए हैं।
- पुनर्विनियोजन आदेश, यदि आवश्यक हो, आरबीई 2025-26 के संबंध में तैयार किया जाना है।
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी फाइनल आवश्यकता 2025-26 के लिए जारी किए जाने वाले पत्र।
- अंतिम आवश्यकता 2025-26 के अनुसार धन का आवंटन।

सीआरबी (लागत वसूली आधार) / वाहन

लक्ष्य और उपलब्धियां: 01 अप्रैल 2025 से 30 नवंबर 2025 तक सीआरबी

मंत्रालय/व्यय विभाग से निम्नलिखित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं:-

- 08 सीमा शुल्क सुविधा केंद्रों के संबंध में 253 अस्थायी पदों का सृजन।
- 19 सीमा शुल्क सुविधा केंद्रों के संबंध में 78 अस्थायी पदों को आगे जारी रखना।
- 07 सीमा शुल्क सुविधा केंद्रों के संबंध में लागत वसूली शुल्क की छूट

वाहन

सीबीआईसी के तहत अतिरिक्त परिचालन वाहनों की स्वीकृति/अनुमोदन मंत्रालय/आईएफयू से प्राप्त किया गया है।

मार्च, 2026 तक शेष अवधि के लिए अनुमान और अनुमान

- विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) 2026-27 तैयार की जानी है, संकलित की जानी है और मंत्रालय/आईएफयू को भेजी जानी है।
- बजट प्रभाग द्वारा प्रदान की गई सीमा के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को आरबीआई 2025-26 आवंटित किया जाना है।

क्र. सं.	मंत्रालय/निदेशालय/विंग/सीबीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय	स्वीकृत वाहन
1	ऑडिट सर्कल, सीजीएसटी के मुख्य आयुक्त और केंद्रीय उत्पाद शुल्क तमिलनाडु और पुडुचेरी जोन	3
2	महानिदेशक सिस्टम, नई दिल्ली	5

3.9.2 निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय)

(i) क्षेत्रीय इकाइयों को निरीक्षण का कार्य सौंपा गया है और इसे यह सुनिश्चित करना है कि क्षेत्रीय कार्यालय सी.बी.आई.सी. के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय विभिन्न आयुक्तालयों / निदेशालयों के निरीक्षण करने और निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा समेकित वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने हेतु निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय के क्षेत्रीय इकाइयों के प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त / सीमा शुल्क / जीएसटी और एडीजी को निरीक्षण कार्य आवंटित करता है। यह कार्य आयुक्तालय के अभिलेखों की आवधिक समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, यह गठन के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और निरीक्षण नोट जारी किया जाता है, जिसमें देखी गई प्रवृत्तियों के साथ विशिष्ट कमियों को रेखांकित किया जाता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय (मुख्यालय) द्वारा सभी क्षेत्रीय इकाइयों सहित, कुल 43 निरीक्षण 30.11.2025 तक पूर्ण किए जा चुके हैं तथा शेष 15 निरीक्षण जनवरी, 2026 के अंत तक पूर्ण किए जाने हैं।

(ii) उपरोक्त कार्य के अलावा, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय को «ऑपरेशनल सिस्टम परफॉर्मेंस रिव्यू» (ओएसपीआर) के तहत आयुक्तालयों / निदेशालयों की परिचालन प्रणालियों की विषय-आधारित प्रदर्शन समीक्षा करने का भी कार्य सौंपा गया था। ओएसपीआर की नियमावली को बोर्ड द्वारा विधिवत अंतिम रूप दे दिया गया है। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (आज तक) के लिए ओएसपीआर के विषयों को अंतिम रूप दिया गया है और उन्हें प्रदर्शन समीक्षा करने और संबंधित परिचालन प्रणाली के लिए संशोधित नीति तैयार करने के लिए बोर्ड के साथ इसे उठाए जाने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आवंटित किया गया है। विषय-आधारित ओएसपीआर रिपोर्ट की स्थिति अनुलग्नक-ख के रूप में संलग्न है।

(iii) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के लिए सी.बी.आई.सी. की नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है और मंत्रालय / बोर्ड और सी.बी.आई.सी. के सभी संलग्न / अधीनस्थ कार्यालयों के मध्य समन्वय कर रहा है। निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेजी जा रही है। इसके अलावा, राजभाषा के कार्यान्वयन / प्रचार के लिए 01 / 04 / 2025 से 30 / 11 / 2025 की अवधि में निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए हैं:

- माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत 18 कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया, जिसमें कार्य निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय ने नोडल कार्यालय के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लिए प्रश्रवली तैयार करने और इसे समिति के

समक्ष प्रस्तुत करने से लेकर, मुख्यालय ने प्रश्रवली तैयार करने और मंत्रालय के साथ सामंजस्य स्थापित करने में पूर्ण सहायता प्रदान की। निरीक्षण बैठक के दौरान मुख्यालय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया और निरीक्षण बैठक के पश्चात्त संदर्भित कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की गई।

- निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से अपने अधीन 100 कार्यालयों का निरीक्षण कर रहा है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। इनमें से 50 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है।
- मुख्यालय की अप्रैल से जून 2025 और जुलाई से सितंबर 2025 तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्टें संकलित और समीक्षा की गईं और रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई के लिए मंत्रालय को भेजी गईं।
- महानिदेशालय में 03 हिंदी कार्यशालाओं (दिनांक 11.07.2025, 21.11.2025 और 24.11.2025 को) का आयोजन किया गया ताकि अधिकारियों / कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी से संबंधित राजभाषा नीतियों के बारे में जागरूक किया जा सके, साथ ही उन्हें 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया।
- महानिदेशालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें (दिनांक 25.06.2025, 26.08.2025 और 11.11.2025 को आयोजित की गईं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुख्यालय और 04 अन्य क्षेत्रीय इकाइयों में राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा की गई और राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशानिर्देश भी जारी किए गए।
- राजभाषा की बैठकें
- अभियंता निदेशालय में दिनांक 15.09.2025 से 30.09.2025 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया जिसमें 06 विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिभा को उजागर किया गया और उन्हें अपना 100% कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- दिनांक 14.10.2025 को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी में "अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, अधीनस्थ कार्यालयों में प्रकाशित विभागीय पत्रिकाओं का मूल्यांकन किया गया और संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त को अखिल भारतीय स्तर पर सम्मानित किया गया। मुख्य आयुक्त को राजभाषा शील्ड और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष थे और बोर्ड और मुख्यालय के साथ-साथ अन्य कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

- विभागीय हिंदी पत्रिका "इंद्रप्रस्थ" का प्रकाशन सुनिश्चित किया गया और इसे माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 14.10.2025 को "अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन" के दौरान जारी किया गया।
- गृह मंत्रालय / वित्त मंत्रालय से प्राप्त राजभाषा से संबंधित दिशानिर्देशों और पत्रों का समय-समय पर परिपत्र जारी कर तथा पत्राचार के माध्यम से निस्तारण किया गया।
- राजभाषा के लिए नोडल कार्यालय होने के रूप में, प्रत्येक तिमाही में, अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट और राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और राजभाषा के कार्यान्वयन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए।
- नोड होना
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया और हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी में अधिकतम कार्य करने के लिए 10 अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

(iv) निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय सभी आयुक्तालयों / निदेशालयों से "SAADHIT" पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्राप्त करता है और उसकी एक समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार कर बोर्ड कार्यालय को प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय द्वारा आकलन डैशबोर्ड का विकास तथा मासिक आकलन रिपोर्ट का संकलन भी किया जाता है।

(v) सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकरण नियुक्त किए गए हैं और आरटीआई आवेदनों के उत्तर निर्धारित समय सीमा में दिए जा रहे हैं। दिनांक 01.04.2024 से 30.11.2025 तक 143 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिनका समय पर निपटान कर दिया गया है। इसी प्रकार सभी अपीलों पर समय सीमा के भीतर कार्रवाई कर उनका निपटान किया जा रहा है। आवश्यक मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट समय पर भेजी जा रही है।

3.9.3 करदाता सेवा महानिदेशालय (डीजीटीएस)

प्रचार-प्रसार

नीचे दिए गए पैरा में करदाता सेवा महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वित 'विज्ञापन और प्रचार' के तहत 31 दिसंबर 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) तक हुए काम-काज पर प्रकाश डाला गया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान हुई प्रचार गतिविधियाँ

अगले-पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के संबंध में प्रचार और आउटरीच अभियान

- जैसा माननीय प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण 2025 में घोषणा किया था कि नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधारों के बारे में

जानकारी प्रसारित करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी, केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी मल्टीमीडिया प्रचार अभियान की योजना बनाई गई और उसे क्रियान्वित किया गया। यह अभियान मंत्रालय और बोर्ड से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलाया गया था। भारत सरकार की नोडल एजेंसी, केंद्रीय संचार ब्यूरो ने देश भर में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक (टीवी और रेडियो), आउटडोर, डिजिटल और विविध मीडिया के माध्यम से व्यापक 360-डिग्री प्रचार अभियान चलाया।

- सुधारों का जीएसटी परिषद द्वारा दिनांक 03.09.2025 को किए गए अनुमोदन के पश्चात, निदेशालय ने दिनांक 22.09.2025 को इनके कार्यान्वयन से पहले व्यापक जन संपर्क सुनिश्चित किया था। सुधारों की प्रमुख विशेषताओं और लाभों के बारे में आम जनता के साथ-साथ व्यापारिक समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान को आगे बढ़ाया गया।

सीबीआईसी सोशल मीडिया हैंडल्स का प्रबंधन

- फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर), व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर सी.बी.आई.सी. की आधिकारिक सोशल मीडिया उपस्थिति की देखरेख और प्रबंधन करना, सुसंगत संदेश, सटीकता और विभागीय संचार प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना।
- जीएसटी और सीमा शुल्क पहलों, जन-हितैषी सुधारों और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल सामग्री की योजना बनाना, संकलन करना एवं प्रकाशन करना, जिससे नागरिकों तक पहुंच एवं सहभागिता में वृद्धि हो सके।
- प्लेटफॉर्म एनालिटिक्स, सार्वजनिक प्रतिक्रिया और रुझानों की निगरानी करना, समय पर सूचना के प्रसार और प्रभावी शिकायत-संवेदनशील संचार को सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों (बोर्ड और फील्ड-फॉर्मेशन) के साथ समन्वय करना।

इवेंट और शिविर प्रबंधन

- प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2025 में भाग लिया और "नेक्स्ट-जेन जीएसटी: सरल कर, खुशहाल राष्ट्र" विषय के साथ 'जीएसटी और सीमा शुल्क शिविर' का सफलतापूर्वक आयोजन और प्रबंधन किया, जिसमें नवीनतम अप्रत्यक्ष कर सुधारों, सी.बी.आई.सी. की पहलों और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया।
- सामग्री विकास, प्रदर्शन डिजाइन, आगंतुक सहभागिता रणनीतियों और मंडप के निर्बाध निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए कई विभागों और भागीदार एजेंसियों के साथ समन्वय सहित, शुरु-से-अंत तक योजना का नेतृत्व किया।
- शिविर में सभी आयु वर्ग, व्यवसायों और क्षेत्रों के आगंतुकों की भारी भीड़ और उत्साहपरक भागीदारी देखने को मिली, जो

हाल के जीएसटी सुधारों में मजबूत सार्वजनिक रुचि और विश्वास को दर्शाती है।

- विभाग के प्रयासों को स्वीकार करते हुए आईटीएफ2025- में 'पब्लिक आउटरीच एवं कम्युनिकेशन' श्रेणी में पवेलियन को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।

मीडिया निगरानी एवं रिपोर्टिंग

- प्रिंट, डिजिटल एवं सोशल मीडिया में सीबीआईसी से संबंधित कवरेज को सम्मिलित करते हुए दैनिक मीडिया मॉनीटरिंग रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई।
- वरिष्ठ अधिकारियों को सारगर्भित और क्रियान्वयन योग्य प्रेरणाएं दी गई जिससे कि सूचित निर्णय-निर्माण एवं समयबद्ध संचार प्रतिक्रियाओं में सहायता मिल सके।

विविध कार्य

प्रमुख संचार सामग्री के उत्पादन की देखरेख की, जिसमें शामिल हैं:

- निम्न पर टेलीविजन कमर्शियल (टीवीसी) पर:**
 - एसएमएस के ज़रिए जीएसटी रिटर्न की शून्य -फाइलिंग।
 - जीएसटी एमआरपी के ऊपर एक अतिरिक्त कर - भ्रम
 - जीएसटी सीधे व्यवसायी की जेब में जाता है और अगर व्यवसायी चाहें तो लगाए गए जीएसटी को बदल सकते हैं – एक गलत अवधारणा
 - कंपोजिशन डीलर्स द्वारा आपूर्ति बिल
 - घर की खरीद पर जीएसटी
 - अतिथि ऐप पर 07 टीवीसी
- इस पर लघु एजुकेशनल वीडियो:**
 - यात्रियों के लिए 'ग्रीन चैनल और रेड चैनल' प्रक्रियाएं।
 - डीजीजीआई 'डिजिट एप्लिकेशन' का अपडेटेड वर्जन
 - निर्यात में जांच के लिए 'आईसटैब'
 - जीएसटी दिवस, 2025 के अवसर पर जीएसटी की यात्रा और सीबीआईसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों को रेखांकित करने वाले 02 ऑडियो-विजुअल।
 - जीएसटी और सीमा शुल्क के विभिन्न विषयों पर 08 लघु वीडियो जो सीबीआईसी की उपलब्धियों को उजागर करते हैं।

- जीएसटी और सीमा शुल्क के निम्नलिखित विषयों पर बहुभाषी ट्यूटोरियल श्रृंखला:**

- जीएसटी के तहत विभिन्न रिटर्न
- जीएसटी से बाहर निकलने (आउट आउट) की प्रक्रिया
- जीएसटी के तहत कैजुअल टैक्सेबल व्यक्ति
- अतिथि ऐप

- सीबीसी के माध्यम से देश भर के अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा के अखबारों में निम्नलिखित विषयों पर प्रकाशित प्रिंट विज्ञापन:**

- तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान योजना - 02 विज्ञापन
- रोजगार मेला, 2025 (अप्रैल, 2025) - 01 विज्ञापन
- जीएसटी पखवाड़ा - 01 विज्ञापन
- नेक्स्ट-जेन जीएसटी सुधार - 39 विज्ञापन
- जीएसटी वार्षिक रिटर्न - 02 विज्ञापन
- पाउचबंद तंबाकू और गुटखा पर मशीन आधारित लेवी - 01 विज्ञापन
- स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा (एचएसएनएस) उपकर अधिनियम, 2025 - 01 विज्ञापन
- कंपोजिशन स्कीम - 02 विज्ञापन

शुल्क (टैरिफ) एवं समन्वय

निम्नलिखित कार्य संबंधी टैरिफ और समन्वय

- सभी क्षेत्रीय इकाइयों के साथ समन्वय
- बोर्ड समन्वय रिपोर्ट
- ई-हेल्पलाइन करदाता रिपोर्ट (मासिक)
- त्रैमासिक सैधित रिपोर्ट संकलन
- वेबिनार रिपोर्ट संकलन
- मासिक निरीक्षण रिपोर्ट संकलन (डिजिटल अभिलेखागार, नागरिक कोना, कारोबार करने में आसानी में परिवर्तन सहित)
- पिछले 8 महीनों में 55 वेबिनार/सेमिनार आयोजित किए गए।
- सीसीएफसी / पीटीएफसी / आरएसी / ओपन हाउस मीटिंग।

सीपीजीआरएएमएस

इस निदेशालय द्वारा सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त सभी सार्वजनिक शिकायतों को संसाधित किया गया और आवश्यक कार्रवाई के

लिए संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को भेज दिया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कुल 11,467 सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 99% का निपटारा कर दिया गया। इसके अलावा, 1,364 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनमें से 96% का निपटारा कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, माननीय राजस्व सचिव की अध्यक्षता में तीन करदाता सेवा और सार्वजनिक शिकायत समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इसके अलावा, सी.बी.आई.सी. के माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में सार्वजनिक शिकायतों पर मासिक समीक्षा बैठकें नियमित रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गईं।

सूचना का अधिकार

यह निदेशालय सी.बी.आई.सी. के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सी.बी.आई.सी. की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 25(2) के तहत अपेक्षित त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रगति की निगरानी के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) के तहत नोडल एजेंसी है। यह सुनिश्चित किया गया कि सी.बी.आई.सी. के तहत सभी क्षेत्रिय संरचनाओं ने सी.आई.सी. वेबसाइट पर अपना आरटीआई त्रैमासिक रिटर्न अपलोड किया। इस अवधि के दौरान, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों को कुशलतापूर्वक संभाला गया। निदेशालय द्वारा प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए उचित संरचनाओं को संसाधित / अग्रेषित किया गया था।

प्राप्त आरटीआई की कुल सं. -732

निपटारा की गई आरटीआई की कुल सं. -721

प्राप्त की गई कुल अपीलें -10

निपटारा की गई कुल अपीलें-101

करदाता सेवा केंद्र

डीजीटीएस के आदेशों में से एक सभी आयुक्तालयों में करदाता सेवा केंद्र स्थापित करना है। जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई से केंद्रीय कर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तालयों में करदाता सेवा केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित हुई है।

प्रकाशन

दिनांक 31.12.2025 तक

निदेशालय ने सी.बी.आई.सी. और अन्य कार्यालयों के आग्रह पर निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए:

- 1) राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना पुस्तिका।
- 2) डीजीटीआई त्रैमासिक बुलेटिन (04 संख्या)।
- 3) 32 विषयों पर महाकुंभ विवरणिका (द्विभाषी)।
- 4) सीमा शुल्क मैनुअल- 2025

5) सिविल सूची 2025

6) 53 विषयों पर आईआईटीएफ- 2025 की विवरणिका (द्विभाषी)।

7) एलसीएस पुस्तिका

8) 12 विषयों पर हिंदी मैनुअल

9) डीजीटीएस हिंदी पत्रिका

दिनांक 31.03.2025 तक अनुमान:

संपर्क 2026; ई-संपर्क, ड्यूटी ड्रॉबैक शेड्यूल; सीमा शुल्क दिवस प्रकाशन आदि

3.10 नासिन, पालसमुद्रम

नासिन क्षमता निर्माण पहल

3.10.1 अधिकारी प्रशिक्षण प्रशिक्षण और विशेष फाउंडेशन कोर्स

- 2025-26 के दौरान, एनएसीआईएन ने प्रत्येक बैच में भूटान की रॉयल सरकार के दस अधिकारी प्रशिक्षुओं सहित 75वें (35 अधिकारी), 76वें (74 अधिकारी) और 77वें बैच (83 अधिकारी) के आईआरएस (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए प्रेरण प्रशिक्षण आयोजित किया। 75वां बैच 16 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अप्रैल 2025 में पास हुआ और अब जनवरी 2026 में उनका फबिशर आयोजित किया जा रहा है। 76वें बैच ने लगभग 13 महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अप्रैल 2026 तक पास होने की संभावना है। हाल ही में, 77वें बैच ने दिसंबर 2025 से अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया है।
- आईआरएस अधिकारी प्रशिक्षुओं को एससी / एसटी और महिला संवेदीकरण, विशाखा दिशानिर्देश, सूचना का अधिकार अधिनियम, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, डिजिटल फोरेंसिक आदि पर विशेष प्रशिक्षण के अलावा अप्रत्यक्ष कर ढांचे और संबद्ध अधिनियमों पर व्यापक प्रशिक्षण मिला। सीमा शुल्क आयुक्तालयों और जीएसटी आयुक्तालयों और निदेशालयों के साथ संलग्नक के माध्यम से दिया गया इमर्सिव फील्ड ट्रेनिंग परिचालन चुनौतियों के लिए हाथों-हाथ एक्सपोजर प्रदान करता है।
- पहली बार, एनएसीआईएन ने 8 सितंबर, 2025 से 5 दिसंबर, 2025 तक 14 सप्ताह के लिए एलबीएसएनए के सहयोगी संस्थान के रूप में विशेष फाउंडेशन कोर्स (एसएफसी) आयोजित किया। 11 विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण ने अनुशासन, अखंडता, नागरिक-केंद्रित शासन और राष्ट्र की सेवा में एक नींव को आत्मसात किया, जिसमें विशेषज्ञों के साथ संवादात्मक सत्र, फील्ड दौरे और सामाजिक सेवा पहल शामिल थीं। यह पहल

सी.बी.आई.सी. के तहत एक प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी के रूप में एन.ए.सी.आई.एन. की भूमिका का हिस्सा है।

- 2025-26 प्रशिक्षण वर्ष में भारत के बेहतरीन विचारकों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों के साथ सम्पर्क देखा गया, जिन्होंने अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ अपना दृष्टिकोण और अनुभव साझा किया।

3.10.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेषीकृत प्रशिक्षण केंद्र (आईसीएससीटी) पहल

- आईसीएससीटी विंग सीमा शुल्क और प्रवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान, आईसीएससीटी ने 14 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिससे दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व को मजबूती मिली।
- **प्रमुख कार्यक्रम:** एचसीएफसी पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (जयपुर में 21 सी.बी.आई.सी. अधिकारी); आई.एम.एफ.-एसएआरटीटीएसी के साथ राजस्व प्रशासन अंतर विश्लेषण (45 अधिकारी); सार्वजनिक सेवा में आईटीईसी नेतृत्व (20 देशों के 34 प्रतिभागी); अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने में आईटीईसी (160 अधिकारी: मुंबई 47, एनसीटीसी मुंबई 21, विशाखापत्तनम 12, बेंगलुरु 80); चार स्थानों पर ओडीएस / एचएफसी नियंत्रण को मजबूत करना (160 अधिकारी: मुंबई 47, एनसीटीसी मुंबई 21, विशाखापत्तनम 12, बेंगलुरु 80); ईओ-एमआरए पर एसएसईसी क्षमता निर्माण (19 सी.बी.आई.सी. अधिकारी और एसएसईसी प्रतिनिधि)।
- आईसीएससीटी ने अफ्रीका, एशिया और ओशिनिया के 20 भागीदार देशों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को आकर्षित किया, जिसमें अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान 450 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- रणनीतिक साझेदारी में डब्ल्यूसीओ, एडीबी-एसएसईसी, यूनोडो, यूएस शामिल हैं। राज्य विभाग, आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी, ओजोन सेल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आते हैं।

3.10.3 इन-सर्विस ट्रेनिंग विंग की गतिविधियाँ

- संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारियों के लिए **मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम (एमसीटीपी)** ने 107 अधिकारियों को एनएसीआईएन

पालामुद्रम में एक सप्ताह और आईएसबी हैदराबाद में तीन सप्ताह के दौरान परिचालन दक्षताओं, नेतृत्व, रणनीतिक सोच, साइबर और डिजिटल फोरेंसिक और व्यवहार कौशल पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया।

- **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों** (49 न्यायिक सदस्यों और 40 तकनीकी सदस्यों) के लिए **विशेष प्रशिक्षण** नवंबर-दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया; इसमें जीएसटी कानून, न्यायनिर्णयन, जीएसटीएन ई-ट्रिब्यूनल सिस्टम, प्राकृतिक न्याय और न्यायिक शासन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शामिल थी।
- सप्ताह का ओरियंटेशन प्रशिक्षण 160 अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था जिन्हें समूह-क अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था।
- जीएसटीएन प्रवर्तन पर मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम (अगस्त 2025 में 30 डीजीआई और 36 सीजीएसटी अधिकारी)।

एनएसीआईएन ने “एनएसीआईएन द्वारा शुक्रवार अंतर्दृष्टि” (एफआईएन) लॉन्च किया, जिसमें विशिष्ट वक्ताओं की एक साप्ताहिक वेबिनार श्रृंखला शामिल है।

3.10.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (जेडटीआई)

- जेडटीआई नेटवर्क देश भर में 18 रणनीतिक स्थानों पर ने विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए यथा- (क) सभी जेडटीआई स्थानों पर नए भर्ती कॉडरों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग; (ख) करियर प्रगति चाहने वाले अधिकारियों के लिए अनिवार्य पदोन्नति –पूर्व प्रशिक्षण; (ग) जीएसटी प्रवर्तन, न्यायनिर्णयन, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं, सीमा शुल्क नियमों, जांच तकनीकों और डिजिटल फोरेंसिक पर डोमेन क्षमता प्रशिक्षण; (घ) नेतृत्व विकास, स्वास्थ्य और कल्याण और योग / ध्यान कार्यक्रमों के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) सहित कार्यात्मक और व्यवहारिक क्षमताएं; (ङ) भारतीय रेलवे, सीएजी अधिकारियों, भारतीय तटरक्षक बल और राज्य पुलिस के लिए हितधारकों के लिए प्रशिक्षण; (च) आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल शौचालय नवीनीकरण, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता और वन्यजीव संरक्षण पहलों सहित सामुदायिक सेवा।
- **एनएसीआईएन मुख्यालय और सभी जेडटीआई में आयोजित प्रशिक्षणों** (अप्रैल से दिसंबर, 2025) की कुल संख्या 1488 है और प्रतिभागियों की कुल संख्या (अप्रैल से दिसंबर, 2025) 1,09,111 है।

4. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

4.1 प्रशासन

राजस्व मुख्यालय, विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों, दोनों बोर्डों (सीबीआईसी और सीबीडीटी) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (संघ के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सीमा तक), केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956, माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (एनडीपीएस), तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेरकर्ता (संपत्ति जब्ती) अधिनियम 1976 (एसएफईएमए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (फेमा), विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कारी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (सीओएफईपीओएसए), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) और विभाग के निम्नलिखित **संबद्ध/अधीनस्थ** कार्यालयों से संबंधित मामलों का प्रशासन करता है:

- (क) प्रवर्तन निदेशालय
- (ख) केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो [सीईआईबी]
- (ग) एसएफईएमए और एनडीपीएस के तहत नियुक्त सक्षम अधिकारी
- (घ) कारखानों के मुख्य नियंत्रक
- (ङ) केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
- (च) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण [सीईएसटीएटी]
- (छ) माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीईएसटीएटी)
- (ज) एसएफईएमए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण
- (झ) वित्तीय आसूचना एकक, भारत [एफआईयू-भारत]
- (ञ) धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत निर्णायक प्राधिकरण
- (ट) राष्ट्रीय लोक वित्त

मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं:

निम्नलिखित की नियुक्ति –

- ✓ सीबीआईसी और सीबीडीटी के अध्यक्ष और सदस्य
- ✓ सीईएसटीएटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य
- ✓ माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीईएसटीएटी) के अध्यक्ष एवं सदस्य
- ✓ सीईआईबी के महानिदेशक
- ✓ प्रवर्तन निदेशक
- ✓ सक्षम प्राधिकारी [एसएफईएमए और एनडीपीएस]

- ✓ निदेशक [एफआईयू-भारत]
- ✓ पीएमएलए के तहत स्थापित निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य
- ✓ एसएफईएमए, 1976 के तहत स्थापित “अपीलीय अधिकरण” के अध्यक्ष और सदस्य
- ✓ सीवीओ, सीबीडीटी/ सीबीआईसी/ प्रवर्तन निदेशालय

4.2 प्रवर्तन निदेशालय

4.2.1 प्रस्तावना

4.2.1.1 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत सरकार की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जिसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के प्रशासन और प्रवर्तन का काम सौंपा गया है। प्रवर्तन निदेशालय आसूचना जानकारी एकत्र करने, अनुसंधान और विश्लेषण करने और धन शोधन, बैंक धोखाधड़ी, वित्तीय घोटाले, विदेशी मुद्रा उल्लंघन आदि से जुड़े मामलों की वित्तीय जांच करने के लिए नोडल एजेंसी है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) के अधिकारी धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाते हैं, आपराधिक की आय को कुर्क करते हैं और विदेशों में जमा संपत्तियों की वसूली और भगोड़ों के प्रत्यर्पण सहित विदेशी अधिकार क्षेत्र में सक्षम अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग करते हैं।

4.2.1.2 हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय का काम गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही दृष्टि से काफी बढ़ गया है। बैंक धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और मानव तस्कारी तथा आतंकवाद के वित्तपोषण आदि से संबंधित आपराधिक आय की कुर्की और जब्ती के मामले में कई हाई-प्रोफाइल मामलों और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव वाले मामलों में जांच शुरू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

4.2.2 निदेशालय की कार्यप्रणाली

4.2.2.1 प्रवर्तन निदेशालय का प्राथमिक कार्य धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) का प्रशासन और प्रवर्तन है, जिसमें धन शोधन के अपराध की जांच, आरोपी के खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज करना, धन शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की और जब्ती, विदेशी क्षेत्राधिकार में सक्षम अधिकारियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपी व्यक्ति आपराधिक की आय का आनंद नहीं ले पाएं। धन शोधन (एमएल) अपराधों की जानकारी एकत्र करने और जांच करने के लिए, पूरे देश में विभिन्न शहरों में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय निम्नलिखित स्रोतों से धन शोधन (एमएल) के अपराध से संबंधित अपराध के बारे में जानकारी एकत्र करता है:

- क) एमएल-1 और एमएल-11 रिपोर्ट:** ये कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट हैं जो एमएल गतिविधियों और उससे संबंधित अपराधों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं।
- ख) अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस):** यह राष्ट्रीय डेटाबेस कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपराधों और अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने और उन तक पहुँचने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर ट्रैकिंग और जाँच की सुविधा मिलती है।
- ग) इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस):** सीसीटीएनएस के समान, यह सिस्टम विभिन्न आपराधिक न्याय हितधारकों के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान-प्रदान की अनुमति देता है, जिससे जाँच प्रक्रिया में सुधार होता है।
- घ) सीबीआई पोर्टल:** सीबीआई नियमित रूप से अपनी सार्वजनिक वेबसाइट पर एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की शाखावार प्रति अपलोड करती है।
- ड) एलईए से अन्य जानकारी:** इसमें कोई भी अतिरिक्त आसूचना जानकारी या डेटा शामिल हो सकता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा स्वप्रेरणा से या निदेशालय के अनुरोध पर प्रदान की गई जांच में सहायता कर सकता है।
- च) संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और परिचालन विश्लेषण (ओए) रिपोर्ट:** एसटीआर वित्तीय संस्थानों द्वारा एफआईयू को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट हैं जो संदिग्ध लेनदेन के अधिकारियों को सूचित करती हैं जो धन शोधन (एमएल) का संकेत दे सकती हैं, जबकि परिचालन विश्लेषण रिपोर्ट कई एसटीआर हैं जिनमें समान कार्यप्रणाली होती है जिन्हें एफआईयू द्वारा विश्लेषण के बाद एक ही एसटीआर में शामिल किया जाता है और इस प्रकार, ओए गहन विश्लेषण प्रदान करता है।
- छ) एमॉट सिक्योर वेब (ईएसडब्ल्यू):** ईएसडब्ल्यू से एकत्रित जानकारी एमएल जांच शुरू करने या चल रही एमएल जांच में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान कर सकती है।
- ज) निजी व्यक्तियों से आसूचना इनपुट या शिकायतें:** जनता से प्राप्त सुझाव या शिकायतें संभावित एमएल गतिविधियों की पहचान करने में मूल्यवान हो सकती हैं।
- झ) ओपन-सोर्स सूचना:** इसमें मीडिया रिपोर्ट, ऑनलाइन लेख और अन्य सार्वजनिक रूप से सुलभ स्रोतों से उपलब्ध डेटा शामिल है जो संभावित धन शोधन (एमएल) गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।
- ञ) किसी अन्य स्रोत से जानकारी:** इसमें कोई भी अतिरिक्त डेटा शामिल है जो प्रासंगिक हो सकता है, चाहे उसका स्रोत कोई भी हो।

उपर्युक्त किसी भी स्रोतों से संदर्भ या सूचना प्राप्त होने और कुछ प्रारंभिक सत्यापन करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय एक मामला दर्ज करता है और अपराध की भौतिकता, अपराध की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति, मामले की जटिलता, व्यापक सार्वजनिक हित और संसाधनों की उपलब्धता जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए जोखिम आधारित दृष्टिकोण के बाद जांच (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट या ईसीआईआर) शुरू करता है। अपराध की आय की पहचान और मात्रा का निर्धारण और आपराधिक की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्ति/संस्थाओं की भागीदारी, धन शोधन के अपराध को साबित करने के साथ-साथ धन शोधन अपराध की सजा के लिए मुख्य आवश्यकताएँ हैं।

4.2.2.2 प्रवर्तन निदेशालय को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के कार्यान्वयन का कार्य भी सौंपा गया है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना है, ताकि बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके और विदेशी मुद्रा संसाधनों के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा दिया जा सके। संभावित फेमा उल्लंघनों के बारे में सूचना मानव आसूचना संसाधनों और विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई है जैसे (i) भारतीय रिजर्व बैंक से निर्यात बकाया विवरण (एक्सओएस विवरण), विदेशी मुद्रा की गैर-प्रत्यावर्तन, लंबित प्रविष्टियों के बिल, एफडीआई से संबंधित उल्लंघन, प्राधिकृत डीलर- I और II (एडी- I और एडी- II) की सूची जो फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं; (ii) बैंकों से विदेशी मुद्रा के गलत उपयोग/आयात के लिए अग्रिम भुगतान, निर्यात आय की वसूली न होना और एनआरई/एनआरओ/एफसीएनआर खातों के मानदंडों का उल्लंघन सहित फेमा के उल्लंघन के संबंध में; (iii) सीमा शुल्क अधिकारियों और आयकर अधिकारियों से निर्यात/आयात के अधिक/कम चालान, विदेशी मुद्रा की तस्करी, अवैध सोने का आयात, सामान नियमों का उल्लंघन इत्यादि के संबंध में; (iv) विदेशी निवेशकों आदि द्वारा फेमा से संबंधित एफ.डी.आई. मानदंडों के उल्लंघन के संबंध में सेबी; (v) विदेशियों द्वारा कृषि भूमि की खरीद आदि के संबंध में राज्य प्राधिकरण और (vi) काला धन अधिनियम के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में आयकर प्राधिकरण या अन्यथा जो फेमा की धारा 37क के तहत कार्रवाई की जानी है। इसके अलावा, इस निदेशालय द्वारा फेमा के तहत मामलों की निम्नलिखित श्रेणियों की जांच की जाती है:

- क) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मार्ग का दुरुपयोग,
- ख) धोखाधड़ी वाले ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करना,
- ग) व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल),
- घ) प्रेषित धन प्राप्त करने और भेजने के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग,
- ड) ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग/क्रिप्टो के लिए विदेशी वॉलेट में धनराशि का अंतरण,
- च) एलआरएस मार्ग का दुरुपयोग,

- छ) जाली सीए सर्टिफिकेट (फॉर्म 15सीबी) द्वारा विदेश में धनराशि का प्रेषण,
- ज) विदेशी संस्था द्वारा भारत स्थित कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी) जारी करना,
- झ) बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के प्रावधानों का उल्लंघन,
- ञ) एनआरआई द्वारा भारत में कृषि भूमि की खरीद,
- ट) मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) का दुरुपयोग,
- ठ) अघोषित विदेशी संपत्तियों का स्वामित्व,
- ड) ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ओडीआई) को बड़े खाते में डालना
- ढ) निर्धारित सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा का कब्जा और
- ण) एनआरआई/एनआरओ/ईईएफसी खातों का दुरुपयोग।

तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय उन मामलों की जांच करता है और कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करता है, जहां फेमा के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप पाए जाते हैं। इन कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाता है और साथ ही संबंधित मुद्रा/संपत्ति को जब्त किया जाता है।

4.2.2.3 प्रवर्तन निदेशालय को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के कार्यन्वयन का भी दायित्व सौंपा गया है। एफईओए में भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से

बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने तथा भारत में कानून के शासन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उपाय बताए गए हैं। उक्त अधिनियम के तहत उन आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़कर चले गए हैं या जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करते हैं तथा जहां आर्थिक अपराध में शामिल कुल राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक है।

4.2.3 संगठनात्मक संरचना

4.2.3.1 प्रवर्तन निदेशालय का नेतृत्व निदेशक करते हैं, जो भारत सरकार के अपर सचिव के पद से निम्न स्तर के नहीं होते हैं। मुख्यालय में उनके काम में सभी रैंक के अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय की सहायता के लिए मुख्यालय में 03 विशेष निदेशक, 11 अपर/संयुक्त निदेशक और कई अन्य अधिकारी/कर्मचारी की स्वीकृत शक्ति उपलब्ध है। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रवर्तन निदेशालय की कार्यात्मक स्थापना चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिणी क्षेत्र), दिल्ली (मध्य क्षेत्र), कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र) और मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र) में स्थित 05 क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक क्षेत्र का नेतृत्व एक विशेष निदेशक करता है। उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा, मुख्यालय जांच इकाइयों (एचआईयू) और विशेष निदेशक की अध्यक्षता में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) नामक विशेष इकाइयां भी मुख्यालय में काम कर रही हैं। क्षेत्रों का गठन अंचल द्वारा किया जाता है, जिनकी अध्यक्षता अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक करते हैं और उप-अंचल का नेतृत्व उप निदेशक करते हैं। उप-अंचल संबंधित अंचल द्वारा नियंत्रित होते हैं।

4.2.3.2 मुख्यालय में निष्पादित कार्यों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	अनुभाग	सौंपे गए कार्य
01.	स्थापना अनुभाग	- यह अनुभाग भर्ती, स्थानांतरण और तैनाती आदि के कार्य को देखता है। - अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना स्थिति बनाए रखने सहित सभी मानव संसाधन संबंधी कार्य; रिक्त पदों को रिक्ति परिपत्र जारी करके भरना/यूपीएससी, एसएससी आदि के साथ पत्राचार करना। - अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि का विस्तार; डीपीसी, विभागीय परीक्षा, कानूनी सलाहकारों का चयन आदि। - भर्ती नियमों का निर्माण और संशोधन। - स्थापना संबंधी क्रेट मामले/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के मामले।
02.	प्रशासन और लेखा अनुभाग	- कार्यालय बजट तैयार करने और क्षेत्रीय संरचनाओं को धन आबंटित करने सहित सभी प्रशासन और लेखा संबंधी कार्य; - कार्यालय व्यय का प्रबंधन जैसे वेतन, जीपीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, एसएसएफ आदि; - लंबित प्रस्तावों के लिए राजस्व विभाग के साथ संपर्क करना - वाहनों, कार्यालय उपकरणों आदि की खरीद/लीज/अनुबंध; - व्यावसायिक और कानूनी बिलों पर कार्रवाई करना और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना। - भौतिक अवसंरचना (कार्यालय और आवास) की व्यवस्था करना। - सीसीटीवी कैमरा लगाना और मुख्यालय परिसर आदि की सुरक्षा करना। - अन्य विविध कार्य

क्र. सं.	अनुभाग	सौंपे गए कार्य
03.	सतर्कता अनुभाग	- अधिकारियों और कर्मचारियों की अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित सतर्कता से संबंधित सभी कार्य। - निदेशालय के सभी अधिकारियों के अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) और एपीएआर। - सतर्कता मंजूरी, सतर्कता शिकायतें, सहमत सूची और ओडीआई सूची तैयार करना आदि कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जा रहा है। - सीसीएस आचरण नियमों के नियम 18 के तहत सूचनाओं का प्रबंधन करना। - विदेश यात्राओं और उच्च अध्ययन के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करना।
04.	समन्वय अनुभाग	- समन्वय अनुभाग में 03 कार्य हैं- समन्वय, पीएमएलए अनुभाग और आरटीआई। - विभिन्न रिपोर्टों के संग्रह और संकलन के लिए मुख्यालय और क्षेत्र संरचनाओं के विभिन्न अनुभागों के साथ समन्वय करना। - राजस्व विभाग (गैर-कर राजस्व और महत्वपूर्ण घटना पर मासिक रिपोर्ट, मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर), मसौदा कैबिनेट नोट, मसौदा विधेयक और एफडीआई प्रस्तावों आदि पर टिप्पणियां भेजना और अन्य मंत्रालयों (जैसे पूर्ववर्ती सत्यापन)/विभागों के साथ विभिन्न रिपोर्ट भेजने के लिए समन्वय करना। - क्षेत्रीय एसडीई / एसडीई (एचआईयू / एसटीएफ) से प्राप्त मासिक डीओ रिपोर्ट का विश्लेषण। - जीईपी आवेदनों पर कार्रवाई करना, आरबीआई द्वारा लघु वित्त बैंक और भुगतान गेटवे बैंक लाइसेंस आदि के लिए संदर्भित संस्थाओं का सत्यापन। - क्षेत्रों / क्षेत्रों और पूर्ववर्ती एजेंसियों के समन्वय में ईसीआईआर की रिकॉर्डिंग की निगरानी; एमएल -1 और एमएल -2 रिपोर्टों का संकलन और प्रसार; आरएएमसी बैठकें आदि आयोजित करना। - संसद प्रश्न और आश्वासन। - आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई करना। - वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट का संकलन कर तैयार करना। - वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कार्य योजना लक्ष्य निर्धारित करना। - क्षेत्रीय अधिकारियों (क्यूसीजेडओ) का त्रैमासिक सम्मेलन और अन्य समीक्षा बैठकें आयोजित करना। - तकनीकी परिपत्र/दिशानिर्देश जारी करना।
05.	आसूचना अनुभाग	- विभिन्न संगठनों जैसे कि एफआईयू, सीबीआई, रॉ, डीआरआई, आईबी, सीईआईबी, सीवीसी, एनटीआरओ, एमएसी, आदि से प्राप्त या एकत्रित सभी आसूचना सूचनाओं पर कार्रवाई करना, साथ ही अनौपचारिक स्रोतों जैसे कि निजी व्यक्तियों, खुले स्रोतों आदि से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करना। - पीएमएलए/फेमा आदि से संबंधित विभिन्न एलईए और निजी व्यक्तियों से प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई करना और कोफेपोसा के मामलों पर कार्य करना, - एफआईयू के कार्य को देखना; फाइनेक्स 2.0 पोर्टल के माध्यम से एसटीआर पर कार्रवाई करना और ईएसडब्ल्यू (ईजीमोंट सिक्योर वेब) के माध्यम से आसूचना एकत्र करना और इसे संबंधित अधिकार क्षेत्र (क्षेत्रों/जोनों) में प्रसारित करना और उस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना। - क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त ईजीमोंट अनुरोधों और पैन आधारित पूछताछ पर कार्रवाई करना और इसे एफआईयू-आईएनडी को अग्रेषित करना। - गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) और कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर), कानूनी अवरोधन प्राप्त करना। - सभी आईसीआईजे लीक मामलों - पनामा, पैराडाइज, पेंडोरा, मॉरीशस, एचएसबीसी, आदि के साथ-साथ जीडीआर, ईसीबी, आतंकवाद वित्तपोषण, वामपंथी उग्रवाद और अन्य ऐसे मामलों में क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई पर डेटाबेस बनाए रखना और अनुवर्ती कार्रवाई करना; नैटग्रिड। - सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरनेट/इंट्रानेट, एन.आई.सी. के साथ समन्वय, आई.टी. से संबंधित सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर की स्थापना और प्रबंधन, साइबर लैब का संचालन और प्रबंधन आदि से संबंधित सभी मामलों।

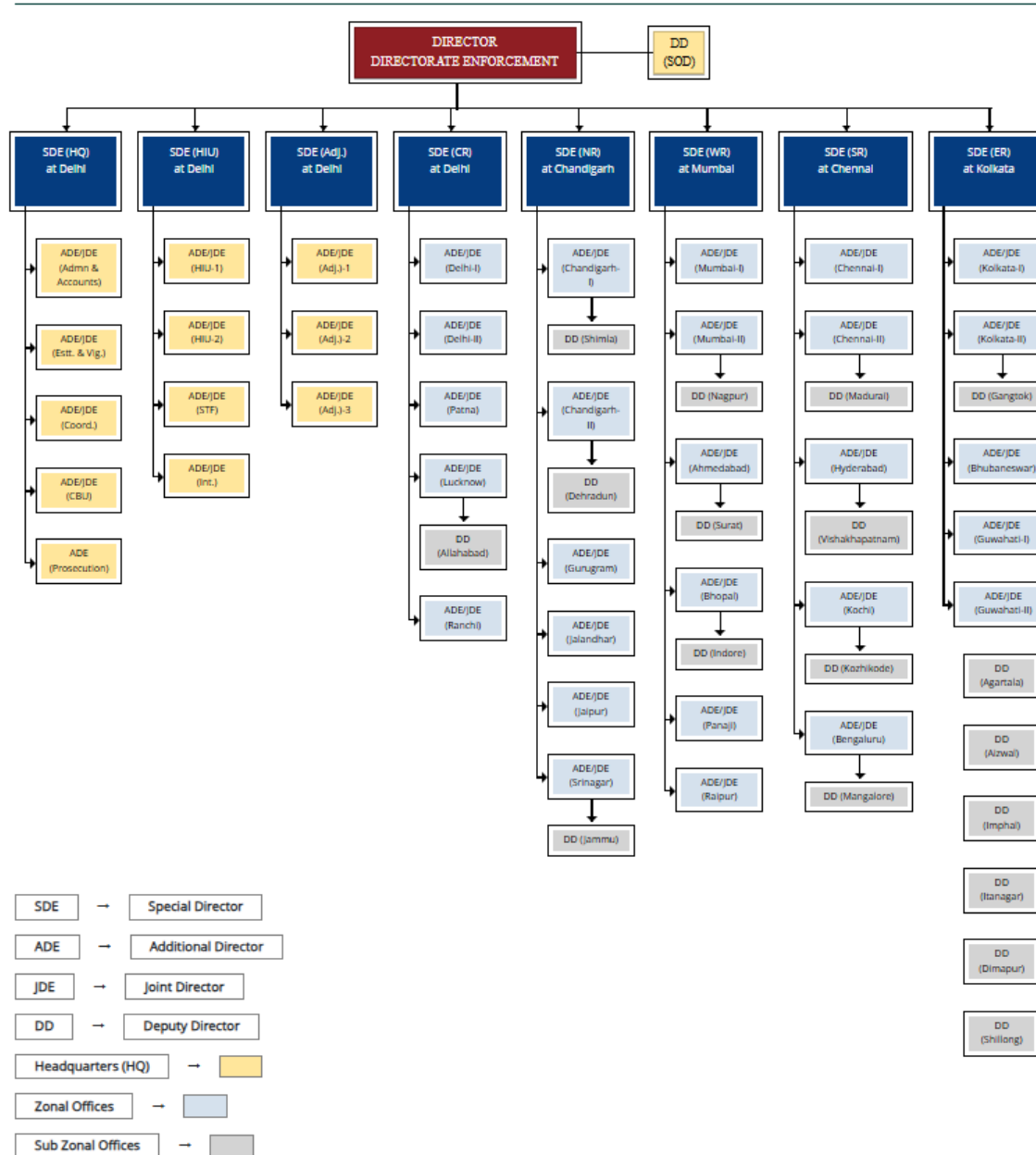
क्र. सं.	अनुभाग	सौंपे गए कार्य
06.	जांच अनुभाग	- पीएमएलए, 2002 और फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच से संबंधित मामलों पर कार्य करना। - जांच अनुभाग, जांच और विश्लेषण के लिए कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), स्थिति रिपोर्ट और कार्य योजना मांगता है। - दिनांक 19.12.2024 के तकनीकी परिपत्र संख्या 07/2024 का अनुपालन सुनिश्चित करना, जिसके तहत क्षेत्रीय संरचनाओं को जांच के विभिन्न चरणों में समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। - मासिक और त्रैमासिक तलाशी और गिरफ्तारी रिपोर्ट की प्राप्ति और संकलन। - आयकर विभाग, सीबीआई, एसएफआईओ आदि जैसे विभिन्न एलईए के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान। - काले धन पर एसआईटी से संबंधित कार्य करना।
07.	न्यायिक निर्णय अनुभाग	- इस अनुभाग को फेरा के तहत सभी लंबित एस.सी.एन. के न्यायनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है। - फेमा के तहत ए.डी.ई./जे.डी. के स्तर तक के एस.सी.एन. के न्यायनिर्णयन का कार्य भी इस अनुभाग को सौंपा गया है। - विभिन्न न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों के स्तर पर फेमा, 1999 के तहत न्यायनिर्णयन की लंबितता की निगरानी। - फेरा और फेमा के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली की निगरानी।
08.	विधिक अनुभाग	- विधि अनुभाग, मुख्यालय निदेशालय से संबंधित सभी विधिक कार्य करता है। - माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के निर्णयों/आदेशों की समीक्षा। - सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका/अपील/रिट याचिका मामले; विदेशी मुद्रा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीएफई) के समक्ष अपील दायर करना। - निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए), एटीएफई और एटी (पीएमएलए) के समक्ष वकील का नामांकन। - पीएओ, पीसी, हलफनामों, अपीलों, एलआर, प्रत्यर्पण अनुरोध आदि की जांच सहित कुछ मामलों में विधिक राय। - फेमा, पीएमएलए और एफईओए से संबंधित या उन पर प्रभाव डालने वाले विधिक मुद्दों/प्रस्तावित कानून पर मंत्रालयों से प्राप्त संदर्भों से निपटना। - न्यायालयों में अभियोजकों/अधिवक्ताओं के कार्य पर नज़र रखना, अधिवक्ताओं का पैनल बनाना, निदेशालय की ओर से निर्णायक प्राधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना। - अखिल भारतीय स्तर पर न्यायालयीन मामलों और कानूनी मुद्दों की निगरानी करना आदि।

क्र. सं.	अनुभाग	सौंपे गए कार्य
09	विदेशी जांच इकाई (ओआईयू)	- ओआईयू के कार्य प्रोफाइल में अंतरराष्ट्रीय बैठकों/प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं के सभी रूपों पर कार्य करना और जी20-एसीडब्ल्यूजी, यूएनओडीसी, एआरआईएन-एपी, विश्व बैंक, स्टार पहल, एफएटीएफ, संपत्ति वसूली आदि से संबंधित मामलों में टिप्पणियाँ प्रस्तुत करना शामिल है। - पीएमएलए/फेमा एलआर और एमएलए अनुरोध, एलओसी आदि जैसे मुद्दों पर तकनीकी परिपत्रों का मसौदा तैयार करना। - अनौपचारिक सहयोग के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करना। - धन शोधन (धन शोधन) और ड्रग तस्करी से संबंधित एफएटीएफ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए आंकड़े/टिप्पणियां प्रदान करना। - देवास मल्टीमीडिया जैसे विदेशी विवादों/मध्यस्थता से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लेना और डीईए, एमईए, डीओएस, सीबीडीटी, सीबीआईसी, डीओटी, आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ आवश्यक जानकारी साझा करना।
10.	क्षमता निर्माण इकाई	- निदेशालय का प्रशिक्षण अनुभाग, जो पहले सिस्टम्स एंड ट्रेनिंग वर्टिकल का हिस्सा था, को जून 2025 में क्षमता निर्माण इकाई के रूप में पुनः नामित किया गया। - इस इकाई का प्राथमिक कार्य इस निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके व्यावसायिक कौशल को निखारना है, जिससे उनके कार्यक्षमता में वृद्धि हो। - यह इकाई निदेशालय के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करती है। - भारत में प्रशिक्षण के लिए निदेशालय के अधिकारियों का नामांकन।
11.	राजभाषा (हिंदी) अनुभाग	- राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों के साथ समन्वय करना तथा उसे गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए समेकित करना। - सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी मापदंडों पर मौजूदा निर्देशों का अनुपालन करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों की निगरानी करना तथा उन्हें जागरूक करना। - वार्षिक आधार पर अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करना। - अधिकारियों के कौशल में सुधार के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना। - प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारियों को राजभाषा में काम करने के लिए पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिता आयोजित करना।
12.	मुख्यालय जांच इकाइयाँ (एचआईयू):	संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए निदेशालय के मुख्यालय में वर्ष 2012 में एचआईयू की स्थापना की गई थी। प्रत्येक एचआईयू में 03 कार्यात्मक इकाइयां हैं।
13.	विशेष कार्य बल (एसटीएफ)	विशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन मार्च, 2019 में मुख्यालय में विशेष रूप से ड्रग तस्करी, आतंकवादी वित्तपोषण और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए किया गया था। एसटीएफ में 3 कार्यात्मक इकाइयां हैं।

4.2.3.3 क्षेत्रीय, आंचलिक और उप-आंचलिक कार्यालयों में संगठनात्मक संरचना:

निदेशालय के सभी क्षेत्रीय, आंचलिक और उप-आंचलिक कार्यालयों की वर्तमान संरचना को नीचे दर्शाया गया है:

Organizational Structure



सूचना एकत्र करने और धन शोधन (धन शोधन) अपराधों तथा फेमा के प्रावधानों से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए संगठन की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पांच (05) क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) अधिकारियों के पास सूचना एकत्र करने और धन शोधन (एमएल)/फेमा के अपराध से संबंधित जांच करने के लिए पूरे देश के लिए अधिकार क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय जांच इकाइयाँ (एचआईयू) और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें सौंपे गए किसी भी मामले की जांच कर सकते हैं। 05 क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत कार्यालय नीचे दिए गए हैं:

- (क) **पश्चिमी क्षेत्र:** इस क्षेत्र का कार्यालय मुंबई में है। इस क्षेत्र में 06 अंचल हैं, अर्थात् मुंबई-I, मुंबई-II, अहमदाबाद, भोपाल, पणजी(गोवा) रायपुर तथा 03 उप-अंचल हैं, अर्थात् मुंबई-II के अंतर्गत नागपुर, अहमदाबाद के अंतर्गत सूरत और भोपाल के अंतर्गत इंदौर।
- (ख) **उत्तरी क्षेत्र :** इस क्षेत्र का कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है। इस क्षेत्र में 06 अंचल हैं, अर्थात् चंडीगढ़-I, चंडीगढ़-II, गुडगांव (गुरुग्राम), जालंधर, जयपुर और श्रीनगर तथा 03 उप-अंचल हैं, अर्थात् चंडीगढ़-I के अंतर्गत शिमला, चंडीगढ़-II के अंतर्गत देहरादून तथा श्रीनगर के अंतर्गत जम्मू।

(ग) **दक्षिणी क्षेत्र:** इस क्षेत्र का कार्यालय चेन्नई में है। इसमें 05 अंचल शामिल हैं, अर्थात् चेन्नई-I, चेन्नई-II, बेंगलुरु, कोच्चि और हैदराबाद तथा 04 उप-जोन, अर्थात् चेन्नई जोन-II के अंतर्गत मदुरै, बेंगलुरु के अंतर्गत मंगलोर, कोच्चि के अंतर्गत कोसीकोड और हैदराबाद के अंतर्गत विशाखापत्तनम।

(घ) **मध्य क्षेत्र:** मध्य क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसमें 05 अंचल शामिल हैं, अर्थात् दिल्ली-I, दिल्ली-II, लखनऊ, पटना और रांची तथा 01 उप-अंचल अर्थात् इलाहाबाद (प्रयागराज) उप-अंचल जो लखनऊ अंचल के अंतर्गत आता है।

(ङ) **पूर्वी क्षेत्र:** इस क्षेत्र का कार्यालय कोलकाता में है। इसमें 05 अंचल शामिल हैं, अर्थात् कोलकाता-I, कोलकाता-II, भुवनेश्वर, गुवाहाटी-I और गुवाहाटी-II और 07 उप-अंचल अर्थात् कोलकाता-II के अंतर्गत गंगटोक और अन्य छह उप-अंचल अर्थात् अगरतला, आइजोल, इम्फाल, ईटानगर, दिमापुर और शिलांग, सभी गुवाहाटी-II के अंतर्गत आते हैं।

4.2.3.4 क्षेत्रीय विशेष निदेशकों को क्षेत्र के विभिन्न शहरों में स्थित निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के समग्र कामकाज और कार्यप्रणाली तथा अन्य प्रशासनिक/सतर्कता मामलों की देखरेख और निगरानी की भूमिका सौंपी गई है। इसी तरह, क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उप-क्षेत्रों सहित अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एफ.यू. के समग्र पर्यवेक्षण और कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं। उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व उप निदेशक करते हैं और वे क्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशकों को रिपोर्ट करते हैं।

4.2.3.5 वर्ष 2021 में, कार्य के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्यात्मक इकाई की अवधारणा शुरू की गई थी। ऐसी प्रत्येक इकाई एक आत्मनिर्भर इकाई है जिसका नेतृत्व उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसके पास जांच, प्रशासन, आसूचना आदि सहित स्पष्ट रूप से सीमांकित संसाधन और जिम्मेदारियाँ होती हैं। कार्यात्मक इकाइयों का नेतृत्व एक उप निदेशक द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता के लिए औसतन 02 सहायक निदेशक, 02 प्रवर्तन अधिकारी, 03 सहायक प्रवर्तन अधिकारी और 2 सिपाही होते हैं। कार्यात्मक इकाई का गठन इस प्रकार है:

क्र. सं.	पदनाम	अधिकारियों की संख्या
1.	उप निदेशक (डीडी)	1
2.	सहायक निदेशक (एडी)	2
3.	प्रवर्तन अधिकारी (ईओ)	2
4.	सहायक प्रवर्तन अधिकारी (ईईओ)	3
5.	सिपाही	2
कुल		10

4.2.3.6 पूरे भारत में स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय यह सुनिश्चित करते हैं कि धन शोधन अपराधों की जांच प्रभावी तरीके से की जाए और यह संभावित अपराधियों के लिए निवारक के रूप में भी कार्य करता है।

4.2.3.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है तथा सीमा पार वित्तीय अपराधों, अंतरराष्ट्रीय हवाला, आतंकवाद के वित्तपोषण और मादक पदार्थों की तस्करी सहित धन शोधन विरोधी गतिविधियों को तेज किया है। निदेशालय ने पूर्वोत्तर की सभी सेवन सिस्टम्स (पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत 07 राज्य) में कार्यालय स्थापित किए हैं।

4.2.4 धन शोधन का अपराध

4.2.4.1 धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3, पीएमएलए की अनुसूची में सूचीबद्ध कई प्रकार के आपराधिक मामले को धन शोधन के गुनाह को आपराधिक बनाती है। इन अपराधों में संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी और रैकेटियरिंग, आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी, अवैध मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी, चोरी के सामान की अवैध तस्करी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, उत्पादों की जालसाजी और चोरी, पर्यावरण संबंधी अपराध, अपहरण, डकैती, तस्करी, जबरन वसूली, जालसाजी, चोरी और अंदरूनी व्यापार और बाजार में हेरफेर शामिल हैं। अनुसूची में सूचीबद्ध इन अपराधों को "पूर्वानुमानित अपराध" कहा जाता है और पीएमएलए की धारा 3 में कहा गया है कि जो इन आपराधिक गतिविधियों से संबंधित "अपराध की आय" से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा और पीएमएलए की धारा 4 के तहत तीन से दस साल के कठोर कारावास से दंडित किया जा सकता है।

4.2.4.2 यह आवश्यक नहीं है कि धन शोधन का अपराध करने के लिए संबंधित व्यक्ति अपराध की आय को बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करे या दावा करे, यह पर्याप्त है कि वह अपराध की आय से जुड़ी किसी भी गतिविधि की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जिसमें इसे छिपाना, कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना शामिल है। इस प्रकार, धन शोधन के अपराध की परिभाषा वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 3(1)(बी) और 3(1)(सी) और पलेर्मो कन्वेंशन के अनुच्छेद 6(1) के पूर्ण अनुपालन में है।

4.2.5 कुर्की और जब्ती

4.2.5.1 धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 5 में यह प्रावधान है कि जहां निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, या उनके द्वारा प्राधिकृत उप निदेशक के पद से नीचे का कोई अन्य अधिकारी, अपने कब्जे में मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण रखता है (ऐसे विश्वास का कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए), कि (क) किसी व्यक्ति के पास अपराध की कोई आय है और (ख) अपराध की ऐसी आय को छुपाया, स्थानांतरित किया या किसी भी तरीके से निपटारा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है, वह लिखित आदेश द्वारा, आदेश की तारीख से 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकता है।

4.2.5.2 धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, जो उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, तलाशी और जब्ती कार्रवाई करने और तलाशी के दौरान मिले किसी भी रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देती है। यदि ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को जब्त करना व्यावहारिक नहीं है, तो संबंधित अधिकारी इसके हस्तांतरण पर रोक लगाते हुए संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है। पीएमएलए की धारा 18 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने और किसी भी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति देती है। पीएमएलए की धारा 17 और 18 के तहत जब्ती/फ्रीजिंग के मामले में, संबंधित अधिकारियों द्वारा ऐसे रिकॉर्ड या संपत्ति को अपने पास रखने या फ्रीजिंग के आदेश को जारी रखने के लिए निर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना आवश्यक है।

4.2.5.3 निर्णायक प्राधिकरण एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं। पीएमएलए की धारा 5 या 17 या 18 के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, निर्णायक प्राधिकरण सभी पक्षों को सुनने के बाद यह तय करता है कि संपत्ति धन शोधन में शामिल है या नहीं। कुर्की/फ्रीजिंग आदेश जांच के दौरान 365 दिनों से अधिक की अवधि के लिए या निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने पर विदेशी न्यायालयों सहित किसी भी न्यायालय में पीएमएलए के तहत किसी भी अपराध से संबंधित कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान लागू रहता है। इस प्रकार, निर्णायक प्राधिकरण के आदेश के बाद, जांच के दौरान कुर्की/फ्रीजिंग जारी रहती है और अभियोजन पक्ष की शिकायत दर्ज होने के बाद भी तब तक लागू रहेगी जब तक कि मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता।

4.2.5.4 धन शोधन के अपराध के लिए मुकदमे के समापन के बाद पीएमएलए की धारा 8(5) के तहत विशेष न्यायालय द्वारा जब्ती का आदेश पारित किया जाता है और संपत्ति में सभी अधिकार और हक सभी ऋणभार से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होते हैं। यद्यपि, निर्णायक प्राधिकरण, अर्ध-न्यायिक निकाय द्वारा कुर्की/जब्ती की पुष्टि के बाद, पीएमएलए की धारा 8(4) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कुर्क की गई संपत्ति को अपने कब्जे में ले लेंगे और तदनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपराधी "अपराध की आय" का लाभ न लें। इस प्रकार, निर्णायक प्राधिकरण द्वारा कुर्की/जब्ती की पुष्टि के बाद, यह अब केवल एक "अंतिम उपाय" नहीं रह जाता है क्योंकि संपत्ति अपराधियों के लिए उपलब्ध नहीं होती है।

4.2.5.5 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों सहित निर्णायक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, पीएमएलए की धारा 26 के तहत अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण अपीलीय न्यायाधिकरण, के समक्ष 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है और अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, जैसा वह उचित समझे आदेश पारित कर सकता है, अपील किए गए आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे रद्द करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून या तथ्य के किसी भी मुद्दे पर 60 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है।

4.2.6 जांच, अभियोजन और दोषसिद्धि

4.2.6.1 पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को धन शोधन के अपराध की जांच करने और अपराध की आय को कुर्क/फ्रीज करने और जब्त करने के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इनमें समन, सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती, व्यक्तियों की तलाशी, गिरफ्तारी आदि की शक्तियां शामिल हैं। सीबीआईसी, सीबीडीटी, पुलिस, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए आदि जैसे विभिन्न अन्य विभागों के अधिकारियों को पीएमएलए के कार्यान्वयन में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की सहायता करने का अधिकार है और उनसे यह अपेक्षित है।

4.2.6.2 शिकायत दर्ज करने के बाद, सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी "अपराध की आय" की पहचान और मात्रा का पता लगाते हैं। वे अपराध की शुरुआत से संबंधित साक्ष्य भी एकत्र करते हैं, जिसमें समानांतर वित्तीय जांच, अभियुक्तों, अपराध से जुड़े अन्य व्यक्तियों और तीसरे पक्ष की जांच, उनके लिखित बयान को कम करना, सर्वेक्षण और तलाशी आदि पर पूर्ववर्ती एजेंसी से प्राप्त जानकारी शामिल हो सकती है। वे "अपराध की आय" के रूप में पहचानी गई संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करते हैं और निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करते हैं। उचित मामलों में, संबंधित एजेंसी के सहयोग से संयुक्त जांच भी की जाती है।

4.2.6.3 आवश्यक जांच करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय पीएमएलए की धारा 43 के तहत गठित विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर करता है, जो पीएमएलए की धारा 3 के तहत किए गए धन शोधन के अपराध का संज्ञान लेता है। विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद, अभियुक्त को पीएमएलए की धारा 4 के अनुसार दोषी ठहराया जाता है और दंडित किया जाता है।

4.2.7 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

4.2.7.1 जब भारत में किए गए अपराध से संबंधित अपराध की आय विदेशी अधिकार क्षेत्रों में स्थानांतरित हो जाती है, या जब आरोपी व्यक्ति धन शोधन या उसके किसी भाग को अंजाम देने के बाद भारत से भाग जाता है या अपराध देश के बाहर किया गया है या गवाह और अन्य भौतिक साक्ष्य किसी अन्य देश में उपलब्ध हैं, तो विदेश में जानकारी एकत्र करना या औपचारिक जांच करना आवश्यक हो सकता है।

4.2.7.2 आम तौर पर, किसी अनुबंधकारी राज्य से पारस्परिक कानूनी सहायता मांगने का आधार आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) है। अब तक, भारत ने 45 देशों के साथ एमएलएटी पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुपक्षीय संधियों, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) या अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी) के आधार पर भी पारस्परिक कानूनी सहायता मांगी जा सकती है। जहां ऐसी कोई संधि नहीं है, वहां आपस में पारस्परिक आश्वासन के आधार पर अनुरोध किया जा सकता है। ये अनुरोध सामान्यतः पीएमएलए की धारा 57 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के माध्यम से किए जाते हैं, हालांकि एमएलएटी या बहुपक्षीय संधियों के अंतर्गत, अनुरोधों को न्यायालयों के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं होती है।

4.2.7.3 यदि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा कुर्की/फ्रीजिंग/जब्त का आदेश पारित किया गया है और उक्त संपत्ति के विदेशी क्षेत्राधिकार में होने का संदेह है, तो विशेष न्यायालय ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी न्यायालय या प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है।

4.2.7.4 प्रवर्तन निदेशालय विदेशी क्षेत्राधिकारों को सहायता भी प्रदान करता है और यदि उक्त विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी न्यायालय या प्राधिकरण

से अनुरोध प्राप्त होता है, तो आवश्यक पूछताछ करके धन शोधन के अपराध की जांच करता है। यदि उक्त विदेशी क्षेत्राधिकार में किसी न्यायालय या प्राधिकरण से अनुरोध प्राप्त होता है, तो यह किसी व्यक्ति द्वारा विदेशी क्षेत्राधिकार में संबंधित कानून के तहत किए गए अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त संपत्ति जो भारत में है, को कुर्क, जब्त, फ्रीज या अधिहरण भी कर सकता है।

केस स्टडी

प्रवर्तन निदेशालय को डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, मैनेजर एसेट्स रिकवरी/धन शोधन, फाइनेंशियल क्राइम ग्रुप, न्यूजीलैंड पुलिस नेशनल हेड क्वार्टर से एक पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध प्राप्त हुआ। इस संचार में जानकारी है कि न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय ने श्रीमती ए (नी बी), श्री सी और अन्य के खिलाफ एक वैश्विक निरोधक आदेश जारी किया है। इसके आधार पर न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने आरोपी श्रीमती ए और श्री सी द्वारा भारत में सात बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए धन को जब्त करने के लिए समुचित आदेश का अनुरोध किया है।

न्यूजीलैंड में किए गए अपराध न्यूजीलैंड के अपराध अधिनियम, 1961, न्यूजीलैंड के गुप्त आयोग अधिनियम, 1910 और न्यूजीलैंड के सीपीआरए के तहत थे। न्यूजीलैंड में किए गए अपराध और मामले में लगाई गई धाराएँ आईपीसी की धारा 120बी और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के बराबर हैं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के परिशिष्ट भाग ए के तहत अनुसूचित अपराध हैं, और अपराध से आय उत्पन्न हुई थी। चूंकि प्रथम दृष्टया पीएमएलए अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध और धारा 4 के तहत दंडनीय प्रतीत होता है।

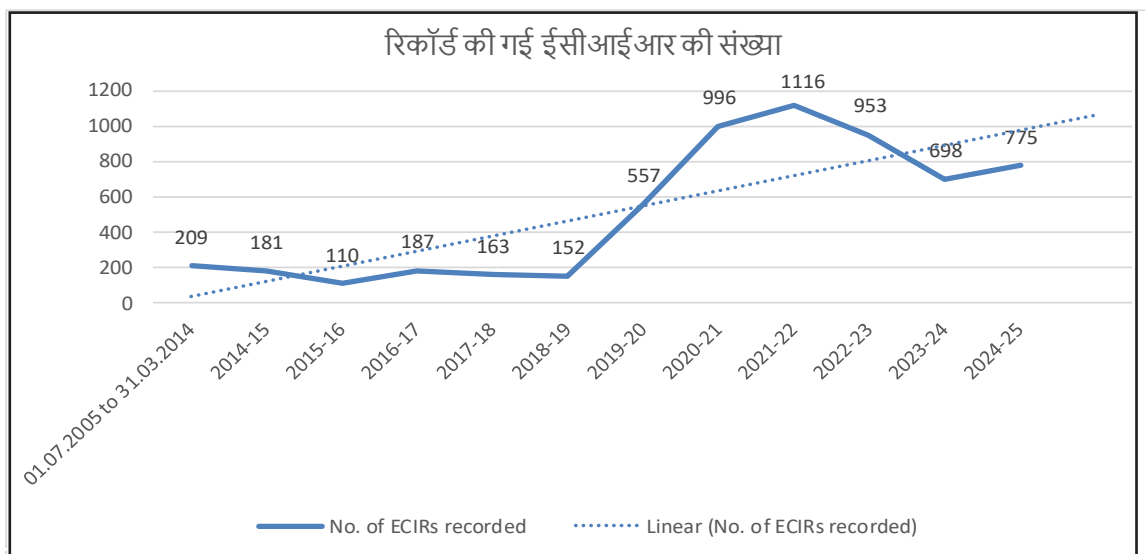
इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तीन अलग-अलग बैंकों में बैंक खातों की तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः खातों के संबंध में धारा 17(1)(ए) के तहत फ्रीजिंग आदेश जारी किए गए। माननीय निर्णायक प्राधिकारी ने अपने दिनांक 23.10.2023 के आदेश के माध्यम से उक्त खातों के फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की है। इस बीच, न्यूजीलैंड के अधिकारियों को अपने देश में अपराध से प्राप्त कुछ और आय मिली, जिसे उन्होंने संलग्न कर दिया और भारत में समतुल्य राशि जारी करने का अनुरोध किया। तदनुसार, बैंकों को सामान्य बैंकिंग कार्यों के लिए अनुरोधित बैंक खातों को जारी करने के लिए निर्देशित किया गया था। मामले में जांच न्यूजीलैंड में चल रही है और पीएमएलए के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई, यानी न्यूजीलैंड या संबंधित व्यक्तियों को फ्रीज की गई अपराध की आय की वापसी या रिलीज, तदनुसार की जाएगी।

4.2.8 पीएमएलए के क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय का प्रदर्शन

4.2.8.1 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, निदेशालय ने 556 मामलों में पीएमएलए के उपबंधों के तहत जांच की है। दिनांक 30.11.2025 के अनुसार कुल 8327 ईसीआईआर दर्ज किए गए हैं। इसका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	दर्ज की गई ईसीआईआरएस की संख्या
01.07.2005 से 31.03.2014 तक	1883 (209 औसत प्रति वर्ष)
2014-15	181
2015-16	110
2016-17	187

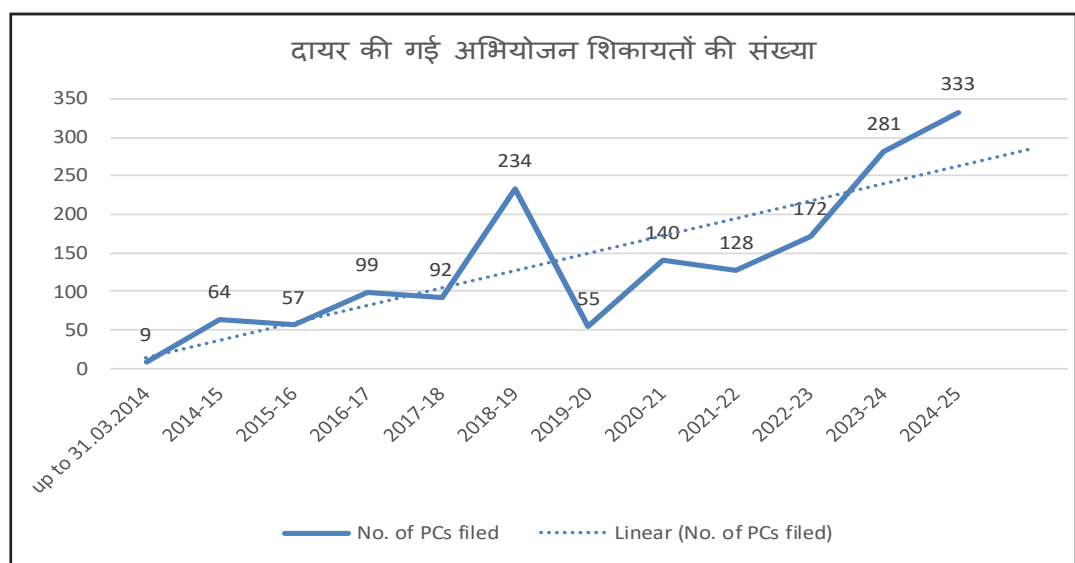
वर्ष	दर्ज की गई ईसीआईआरएस की संख्या
2017-18	163
2018-19	152
2019-20	557
2020-21	996
2021-22	1116
2022-23	953
2023-24	698
2024-25	775
2025-26 (30.11.2025 तक)	556
कुल	8327



4.2.8.2 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, निदेशालय ने 261 अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके 31,275.88 करोड़ रुपये (लगभग) के कुल मूल्य के अपराध की आय को कुर्क किया है, जिससे 30.11.2025 तक 3050 अनंतिम कुर्की आदेश जारी करके अपराध की आय की कुल कुर्की 1,85,869.86 करोड़ रुपये हो गई है। निर्णायक प्राधिकरण ने दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक की अवधि के दौरान 16531.75 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि की है। इस प्रकार, 30.11.2025 के अनुसार कुल पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियों की राशि लगभग 1,23,261.38 करोड़ रुपये है।

4.2.8.3 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक की अवधि के दौरान, पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 188 अभियोजन शिकायतें दायर की गई हैं। दिनांक 30.11.2025 तक पीएमएलए के तहत दायर अभियोजन शिकायतों की कुल संख्या 1927 है। इसका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	दायर की गई अभियोजन शिकायतों (पीसीएस) की संख्या
01.07.2005 से 31.03.2014 तक	84 (09 औसत प्रति वर्ष)
2014-15	64
2015-16	57
2016-17	99
2017-18	92
2018-19	234
2019-20	55
2020-21	140
2021-22	128
2022-23	172
2023-24	281
2024-25	333
2025-26 (30.11.2025 तक)	188
कुल	1927



4.2.8.4 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने 4.26 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है और आरोपियों पर 1.43 करोड़ रुपये (लगभग) का संचयी जुर्माना लगाया है। आज की तारीख में पीएमएलए के तहत कुल जब्त राशि 15,735.74 करोड़ रुपये (लगभग) है।

4.2.8.5 दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, निदेशालय ने 06 दोषसिद्धि आदेश प्राप्त किए हैं, जिनमें से 16 अभियुक्तों को विशेष न्यायालय पीएमएलए द्वारा दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, 06.12.2025 को निदेशालय ने एक और दोषसिद्धि आदेश प्राप्त किया है। इस प्रकार, आज की तारीख तक, इस निदेशालय ने 54 दोषसिद्धि आदेश प्राप्त किए हैं, जिनमें से 122 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है।

4.2.9 आतंकवाद के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान

4.2.9.1 प्रवर्तन निदेशालय, आतंकवाद के वित्तपोषण के मामलों की जांच पर विशेष ध्यान देता है। यूएपीए के तहत आतंकवाद के मामलों की जांच और अभियोजन एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा किया जाता है। यद्यपि, राज्य पुलिस अधिकारी यूएपीए के तहत और भारतीय दण्ड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत भी आतंकवाद के मामलों की जांच करते हैं।

4.2.9.2 पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच का ध्यान आम तौर पर आपराधिक जांच पर होता है जैसे कि हथियार कहाँ से प्राप्त हुए हैं, साजिश कैसे रची गई, मास्टरमाइंड कौन था, साजिश क्या थी, मकसद क्या था, इसमें कौन शामिल थे आदि।

4.2.9.3 प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस अधिकारियों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद, वित्तीय जांच करता है, जिसमें धन कहाँ से प्राप्त हुआ है, बैंकिंग चैनलों में धन कैसे डाला गया और यदि बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नहीं, तो क्या यह हवाला या वस्तु विनिमय व्यापार या व्यापार आधारित धन शोधन से था आदि की जांच शामिल है। यह इस बात की जांच भी करता है कि धन कैसे और किसे वितरित किया गया और यदि धन किसी संपत्ति में निवेश किया गया है, तो क्या संपत्ति अभी भी मौजूद है या समाप्त हो गई है। एक बार संपत्ति की पहचान हो जाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय अस्थायी रूप से संपत्ति को कुर्क कर लेता है और फिर निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के बाद उसे अपने कब्जे में ले लेता है। यदि संपत्ति का परिसमापन किया जाता है, तो भारत या विदेश में समतुल्य राशि की संपत्ति कुर्क की जाती है।

4.2.9.4 प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया है कि आतंकवादी वित्तपोषण के लिए कई तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विदेशी धन प्राप्त करके बैंकिंग चैनल
- वेस्टर्न यूनियन जैसी अधिकृत धन अंतरण सेवाएँ
- हवाला भुगतान

- एनपीओ/सामाजिक कल्याण संगठनों को दान
- वस्तु विनिमय व्यापार
- नकली भारतीय मुद्रा नोट

4.2.9.5 आतंकवादी वित्तपोषण के मामलों में, अपराध की आय का पता लगाने और आतंकवादियों द्वारा इसके शोधन में प्रवर्तन निदेशालय की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रवर्तन निदेशालय न केवल अपराध की आय को संलग्न करता है और उसी पर कब्जा कर लेता है, बल्कि पीएमएलए के तहत आतंक के आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज करता है।

4.2.9.6 प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्र-विरोधी तत्वों के खिलाफ आतंकी वित्तपोषण से संबंधित कई मामले दर्ज करके आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और आतंकी फंडिंग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए धनशोधन की तीव्र जांच की है, जिससे 1506.42 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक आपराधिक आय का पता चला है। पहचान की गई पीओसी में से, इस निदेशालय द्वारा 1239.07 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में भारत में 1036.07 करोड़ रुपये (लगभग) और विदेश में 203 करोड़ (लगभग) की चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं (30.11.2025 के अनुसार)। एक मामले में, आरोपी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018(एफईओए) के प्रावधानों के तहत 97.99 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 21 अनुपूरक अभियोजन शिकायतें सहित कुल 59 अभियोजन शिकायतें (आरोप-पत्र) दायर की गई हैं तथा पीएमएलए विशेष न्यायालय द्वारा 04 मामलों में 09 अभियुक्तों को विशेष न्यायालय द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। इसके अलावा, विशेष न्यायालयों द्वारा 14 अभियुक्तों को उद्धोषित अपराधी तथा 03 अभियुक्तों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है।

4.2.9.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी समूहों के विरुद्ध कार्रवाई: पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए निदेशालय ने एनएससीएन (आईएम) एनएससीएन (के.) दीमा हलाम दाओगाह (ज्वेल गरोलसा फैक्सन) जैसे कुछ प्रमुख उग्रवादी समूहों के विरुद्ध पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत कई जांच की हैं।

4.2.9.8 बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नक्सली फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई: बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में सक्रिय वामपंथी उग्रवादियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत सख्त कार्रवाई की गई है, जिसके चलते कई मामलों में संपत्तियों को कुर्क किया गया है और अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं। इन मामलों में नक्सली/वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों में 24.88 करोड़ रुपये (लगभग) की पीओसी की पहचान की गई है, जिसमें से 16 विभिन्न पीओ में 10.71 करोड़ रुपये की पीओसी कुर्क की गई है। इसके अलावा, 30.11.2025 तक नक्सली/वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मामलों में 01 पूरक पीसी सहित 16 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

4.2.10 धनशोधन के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम इस प्रकार हैं:

(i) **साइबर धोखाधड़ी:** प्रौद्योगिकी के आगमन और इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता ने नवाचारों और आर्थिक विकास को जन्म दिया है,

लेकिन साथ ही अपराधियों द्वारा अपराध करने के लिए इसकी कमजोरियों का भी पता लगाया गया है। इस प्रकार, भारत सहित पूरे विश्व में साइबर धोखाधड़ी में तेज वृद्धि हुई है। सरकारी एजेंसियों की नजर में आए बिना अपराधिक आय को विदेशी अधिकार क्षेत्र में अंतरित करने के लिए अपराधियों द्वारा आभासी मुद्रा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। साइबर धोखेबाजों ने न केवल साधन संपन्न लोगों को बल्कि आम और

गरीब लोगों को भी अपना निशाना बनाया है। निदेशालय ने साइबर अपराध और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित मामलों में अपराधिक आय का पता लगाकर और उसे कुर्क/जब्त/फ्रीज करके धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए सतर्क कदम उठाए हैं। प्रवर्तन निदेशालय (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा जांच हेतु लिए गए ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मामले पर केस स्टडी नीचे बॉक्स में दी गई है।

केस स्टडी

एम/एस एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक जटिल धन शोधन योजना का संचालन किया, जिसे सोशल मीडिया पर रेफरल प्रोत्साहन का उपयोग करके आक्रामक रूप से प्रचारित किया गया था। कंपनी ने यूपीआई और बैंक अंतरण के माध्यम से भारतीय उपयोगकर्ताओं से धन एकत्र किया, और उन्हें ई-कॉमर्स संस्थाओं के रूप में झूठे पंजीकृत शेल कंपनियों के माध्यम से भेजा। इन संस्थाओं ने वैध विदेशी मुद्रा व्यापार का अनुकरण करने के लिए भुगतान गेटवे तक पहुंच प्राप्त की और एबीसी ऐप पर कई भारतीय बैंक खातों को प्रदर्शित किया। धन को मूल खातों के माध्यम से लेयर किया गया था, भुगतान गेटवे के माध्यम से रूट किया गया था, और वैधता उधार देने के लिए आंशिक रूप से सेबी-पंजीकृत एआईएफ में निवेश किया गया था। पूरे ऑपरेशन को श्री ए द्वारा नियंत्रित किया गया था, जिन्होंने निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशों में भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया और 4.2 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि विदेश भेजने के लिए जाली चालान का उपयोग किया। धन शोधित राशि का एक हिस्सा मैसर्स एबीसी इंडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से फिर से निवेश किया गया था, जिसे आईपीएल के दौरान हाई-प्रोफाइल ब्रांड प्रचार और सेलिब्रिटी समर्थन द्वारा और छिपाया गया था।

इस मामले में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए और 84 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया। भारत में 35.07 करोड़ रुपये की संपत्ति और स्पेन में स्थित श्री ए और उनकी संस्थाओं के स्वामित्व वाली 41.73 करोड़ रुपये मूल्य की 19 अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए।

इसके अलावा, 2025 में, श्री ए और उनकी संस्थाओं की विदेश में स्थित 131.45 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई और उसे कुर्क कर दिया गया। दिनांक 19.09.2025 के एक अन्य पीएओ के अनुसार, भारत के बाहर स्थित लगभग 2,385 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न क्रिप्टोकॉरेसी के रूप में चल संपत्ति को भी कुर्क किया गया है।

मैसर्स एबीसी और अन्य के खिलाफ 01.10.2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और 20.12.2024 को एक पूरक पीसी दायर की गई। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मामले का संज्ञान लिया है और अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही जारी की है।

(ii) **मानव तस्करी:** भारत में मानव तस्करी और प्रवासी तस्करी सबसे महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में से एक है। पीड़ित आमतौर पर वे लोग होते हैं जिन्हें अवैध रूप से काम करने वाले तस्करी एजेंटों द्वारा गलत जानकारी दी जाती है और गुमराह किया जाता है, या लड़कियों को जबरन यौन शोषण रैकेट में डाल दिया जाता है या मनुष्यों को बेहतर अवसरों के लालच में विदेशी देशों में तस्करी कर दी जाती है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भारत और विदेशों में काम करने वाले ऐसे संगठित अपराधिक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्रिय रहा है।

(iii) **भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार भारत की सबसे पुरानी समस्याओं में से एक है जो भारत की सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और विकास संबंधी आकांक्षाओं को खतरे में डालता है। प्रवर्तन निदेशालय भ्रष्टाचार के कई मामलों में कार्रवाई कर रहा है और इसका उद्देश्य धन शोधन करने वालों को अपराधिक आय का आनंद लेने से रोककर प्रभावी धन शोधन जांच के साथ इसे कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच हेतु लिए गए ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मामले पर केस स्टडी नीचे बॉक्स में दी गई है।

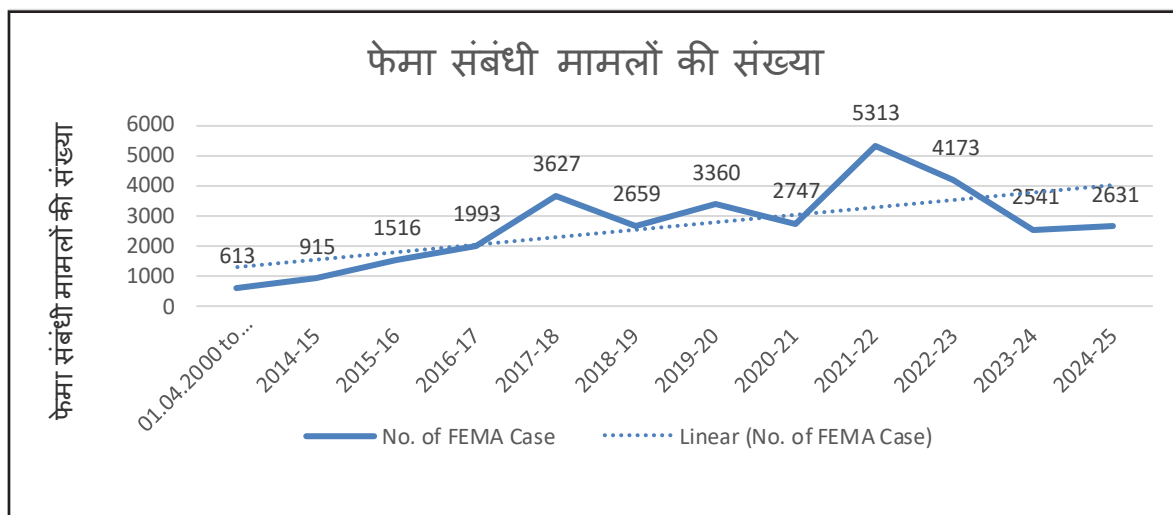
केस स्टडी

इस निदेशालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच शुरू की, जिसमें आरोप है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री श्री ए, अन्य व्यक्तियों के साथ भूमि हड़पने की गतिविधियों में शामिल थे। प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप है कि मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए अपनी पत्नी श्रीमती बी के नाम पर 14 साइटों के लिए मुआवजा प्राप्त किया, जिसके बदले में एक्सवाईजेड शहरी विकास प्राधिकरण (एक्सवाईजेड) द्वारा अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंते जमीन दी गई, जिससे एक्सवाईजेड और राज्य सरकार को नुकसान हुआ। जांच के दौरान, श्री ए और सहयोगियों के विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, यह पता चला कि श्रीमती बी को आबंटित 14 साइटों के अलावा, बड़ी संख्या में साइटें एक्सवाईजेड द्वारा रियल एस्टेट कारोबारियों को मुआवजे के रूप में "अवैध रूप से" आबंटित की गई हैं, जिन्होंने बदले में इन साइटों को "भारी" मुनाफे पर बेचा और भारी मात्रा में "अधोषित" नकदी उत्पन्न की। पीएमएलए जांच के दौरान, ईडी द्वारा ₹ 140.53 करोड़ (जिसका बाजार मूल्य ₹ 450 करोड़ है) की संपत्ति कुर्क की गई। साइटों के अवैध आबंटन में बड़े पैमाने पर घोटाले की जानकारी पीएमएलए, 2002 की धारा 66 (2) के तहत 30.11.2024 और 24.01.2025 को लोकायुक्त पुलिस के साथ साझा की गई। जांच से पता चला कि अपराध से प्राप्त भारी आय अवैध रूप से आबंटित एक्सवाईजेड के रूप में प्राप्त की गई थी। जांच से यह भी पता चला है कि एक्सवाईजेड के तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अनुचित संतुष्टि/घूस लिया गया था। एक्सवाईजेड के तत्कालीन आयुक्त श्री सी ने अपने रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर एक्सवाईजेड साइटों के अवैध आबंटन के बदले में अचल संपत्ति और नकदी/धन और बैंक अंतरण के रूप में अपराध से प्राप्त आय अर्जित की थी। श्री सी को 16.09.2025 को गिरफ्तार किया गया था।

4.2.11 फेमा के क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय का निष्पादन

दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, निदेशालय ने विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत कुल 2242 मामलों में जांच शुरू की है। इस अवधि के दौरान कुल 119 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और कुल 49 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा, 66.84 करोड़ रुपये (लगभग) का जुर्माना भी लगाया गया है और इस अवधि के दौरान 70 लाख रुपये (लगभग) का जुर्माना वसूल किया गया है। इसके अतिरिक्त, फेरा के अवशिष्ट कार्य सहित फेमा के तहत, विशेष रूप से वरिष्ठ स्तर पर न्यायनिर्णयन के लिए लंबित कारण बताओ नोटिस के बैकलॉग पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय में एक समर्पित न्यायनिर्णयन अनुभाग बनाया गया है। फेमा के तहत एडीई/जेडी के स्तर तक कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन का कार्य भी इस अनुभाग को सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न न्यायनिर्णयन प्राधिकरणों के स्तर पर फेमा, 1999 के तहत न्यायनिर्णयन की लंबितता की निगरानी करने का कार्य भी सौंपा गया है। फेरा और फेमा के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली और शुरू की गई फेमा जांच का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	फेमा के मामलों की संख्या
01.04.2000 से 31.03.2014	8586 (613 औसतन प्रतिवर्ष)
2014-15	915
2015-16	1516
2016-17	1993
2017-18	3627
2018-19	2659
2019-20	3360
2020-21	2747
2021-22	5313
2022-23	4173
2023-24	2541
2024-25	2631
2025-26(30.11.2025 तक)	2242
कुल	42303



4.2.12 एफईओ के क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय का निष्पादन

दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, इस निदेशालय ने सक्षम न्यायालय में 05 व्यक्तियों के विरुद्ध एफईओ के तहत आवेदन दायर किए हैं। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान सक्षम न्यायालय द्वारा श्री राषिद नसीन नामक एक व्यक्ति को एफईओ घोषित किया गया है। दिनांक 30.11.2025 तक, प्रवर्तन निदेशालय ने 31 व्यक्तियों के विरुद्ध एफईओ के तहत आवेदन दायर किए हैं, जिनमें से 15 व्यक्तियों को सक्षम न्यायालयों द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माननीय विशेष न्यायालय ने एफईओ से संबंधित 930.758 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अन्य घोषित एफईओ के संबंध में संपत्तियों को जब्त करने के लिए सक्षम न्यायालयों में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा, 03.12.2025 को एक मामले में, माननीय विशेष न्यायालय ने 127.98 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। इस प्रकार, आज की तारीख तक, भारत सरकार को 1058.738 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अन्य

घोषित एफईओ के संबंध में संपत्ति की जब्ती के लिए सक्षम न्यायालयों में सुनवाई चल रही है।

इसके अलावा, निदेशालय द्वारा हाई प्रोफाइल भगोड़े आर्थिक अपराधियों के मामले में प्रत्यर्पण कार्यवाही भी नियमित रूप से की जा रही है।

4.2.13 प्रत्यर्पण और रेड नोटिस के क्षेत्र में प्रवर्तन निदेशालय का निष्पादन

दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 की अवधि के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने 12 व्यक्तियों के संबंध में रेड नोटिस और 10 व्यक्तियों के संबंध में ब्लू नोटिस प्रकाशित करने का अनुरोध किया है। साथ ही, इस अवधि के दौरान 03 रेड नोटिस, 03 ब्लू नोटिस, 04 सिल्वर नोटिस और 01 परपल नोटिस प्रकाशित किए गए हैं। आज तक, प्रवर्तन निदेशालय ने 61 व्यक्तियों के संबंध में रेड नोटिस प्रकाशित करने का अनुरोध किया है, जिनमें से 41 व्यक्तियों के संबंध में रेड नोटिस प्रकाशित किया गया है। इसके

अलावा, इस अवधि के दौरान एक प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया है। कुल 37 व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न देशों को कुल 45 प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों और अन्य आरोपियों को प्रत्यर्पित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है, जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचते रहे हैं। निदेशालय के प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न भगोड़े आर्थिक अपराधियों और अन्य आरोपियों के प्रत्यर्पण के लिए विदेश में सक्षम न्यायालय के समक्ष सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व किया गया है। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उचित है कि यूके कोर्ट ने अन्य एलईए और विदेश में भारतीय मिशन के समन्वय से निदेशालय के प्रभावी प्रतिनिधित्व के बाद कुछ हाई प्रोफाइल आरोपियों के भारत में प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है।

4.2.14 धनशोधन के पीड़ितों/वैध दावेदारों को संपत्ति वापस दिलाना

प्रवर्तन निदेशालय न केवल धनशोधन का पर्दाफाश करने के लिए आर्थिक अपराधियों का सक्रिय रूप से पीछा कर रहा है, बल्कि अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी किए गए बैंकों और अन्य लोगों की संपत्ति वापस दिलाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पीड़ितों या वैध दावेदारों को लगभग 46,061.15 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिलाई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई वापसी/पुनर्स्थापना का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	वापस की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ ₹ में)
01.07.2005 से 31.03.2019 तक	0
2019-20	1,613.30
2020-21	0
2021-22	13,517.18
2022-23	0
2023-24	71.16
2024-25	15,263.03
2025-26 (दिनांक 30.11.2025 तक)	15,596.48
कुल	46,061.15

4.2.15 ई-गवर्नेंस के लिए पहल

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ई-गवर्नेंस और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में ई.डी. द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) ईडी की नई, नवीनीकृत आधिकारिक वेबसाइट का विकास:

निदेशालय ने ईडी की डिजिटल उपस्थिति और सेवा प्रदान करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट को नया रूप देने की एक बड़ी पहल की है। पुरानी तकनीक पर बनी पिछली साइट में सुरक्षा, स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और उपयोगकर्ता अनुभव सीमित

थे। इन कमियों को दूर करने और विकसित हो रहे ई-गवर्नेंस मानकों को पूरा करने के लिए, प्लेटफॉर्म को अलग-अलग एप्लिकेशन और डेटाबेस परतों के साथ एक आधुनिक आर्किटेक्चर का उपयोग करके पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया गया है।

नई वेबसाइट जीआईडीडब्ल्यू 3.0, डब्ल्यूसीएजी 2.1 और एसटीक्यूसी आवश्यकताओं का अनुपालन करती है और इसमें वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल, सीईआरटी-आईएन-संरक्षित सुरक्षा उपाय, स्वचालित बैकअप और बेहतर लॉगिंग जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं। उपयोगकर्ता-उन्मुख उन्नयन में सहज नेविगेशन, सुव्यवस्थित और अपडेट की गई सामग्री (महत्वपूर्ण निर्णय, समाचार सुर्खियों में ईडी, नया क्या है), द्विभाषी समर्थन, गतिशील राष्ट्रीय-घटना विषय और पूरी तरह से प्रतिक्रियात्मक डिजाइन शामिल हैं। वेबसाइट ईडी के इंटरनेट पर लाइव है, और आवश्यक एनआईसी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के आर्बटन पर सार्वजनिक रोलआउट की योजना है।

(ii) कुशल तकनीकी जनशक्ति की तैनाती:

अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और ईडी की डिजिटल पहलों का समर्थन करने के लिए, ईडी ने सभी क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों के लिए संविदात्मक आधार पर 07 सिस्टम एनालिस्ट और 36 वैज्ञानिक तकनीकी सहायकों के पदों के लिए विज्ञापन दिया है। इन भूमिकाओं के लिए आईटी, कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेष योग्यताएं, सॉफ्टवेयर विकास और डेटाबेस प्रबंधन में अनुभव आवश्यक है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, नेटवर्क और सर्वर अवसंरचना को बनाए रखने, इन-हाउस अनुप्रयोगों का समर्थन करने, डेटाबेस का प्रबंधन करने और ईमेल, एनआईसी-वीसी और अन्य डिजिटल सेवाओं के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए इस तकनीकी कार्यबल की नियुक्ति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, 2 एसए और 14 एसटीए तैनात हैं और शेष कर्मियों का चयन प्रक्रियाधीन है।

(iii) अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल पहल:

(क) ई-ऑफिस कार्यान्वयन - ई-ऑफिस प्रशासनिक कार्यों के लिए ईडी में पूरी तरह से संचालन में है, जिससे भौतिक फाइलें समाप्त हो गई हैं और दस्तावेजों की पहुंच, कार्यप्रवाह दक्षता और प्रसंस्करण समय-सीमा में सुधार हुआ है। इस डिजिटल बदलाव ने फाइल मूवमेंट में पारदर्शिता भी बढ़ाई है और निदेशालय के कागजरहित और सुव्यवस्थित प्रशासनिक वातावरण की ओर बढ़ने को मजबूत किया है।

(ख) ई-एचआरएमएस 2.0 ऑन-बोर्डिंग - सभी ईडी कर्मचारियों को डीओपीटी के ई-एचआरएमएस 2.0 प्लेटफॉर्म पर शामिल किया गया है, जिससे सेवा रिकॉर्ड का केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित डिजिटल प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है। इससे कर्मचारियों को अपनी सेवा संबंधी जानकारी तक आसानी से पहुंचने में मदद मिली है, साथ ही निदेशालय को सटीक, कागजरहित और आसानी से पुनर्प्राप्त करने योग्य एचआर डेटा बनाए रखने में सहायता मिली है।

(ग) एजीटी स्थानांतरण के लिए प्रवर्तन निदेशालय कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली (ईडीईएमएस) - इन-हाउस विकसित ईडीईएमएस एप्लिकेशन निदेशालय में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण की पारदर्शी, स्वचालित और नियम-आधारित प्रसंस्करण को सक्षम बनाता है। इसने स्थापना प्रभाग को मैनुअल सबमिशन के बजाय डिजिटल रूप से स्थानांतरण अनुरोध प्राप्त करने में मदद की है, जिससे बेहतर सटीकता, बेहतर रिकॉर्ड-के रखरखाव और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ सुचारु समन्वय सुनिश्चित हुआ है।

(घ) इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आईआईएमएस) - आईआईएमएस आसूचना के भंडारण, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें शिकायतों की तेजी से पुनर्प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए उन्नत खोज सुविधाएँ हैं। यह सूचना के व्यवस्थित संगठन को सक्षम बनाता है और आसूचना मूल्यांकन के दौरान अधिकारियों को समय पर और सूचित निर्णय लेने में सहायता करता है।

(ङ) प्रवर्तन निदेशालय अपराधी ट्रैकिंग सिस्टम (ईडीओटीएस) - ईडीओटीएस को शुरू में पीएमएलए/फेमा के तहत जांच के अंतर्गत व्यक्तियों और संस्थाओं के एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार के रूप में विकसित किया गया था (वार्षिक रिपोर्ट)। प्रवर्तन निदेशालय के भीतर जांच के तहत सभी मामलों के डेटा को केंद्रीकृत करने के लिए ईडीओटीएस को लागू किया गया है। यह केंद्रीकृत प्रणाली मामले की ट्रैकिंग को सुव्यवस्थित करेगी, समन्वय बढ़ाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कुशल निर्णय लेने और जांच प्रक्रिया के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रासंगिक डेटा वास्तविक समय में उपलब्ध है। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) अब सीधे ईडीओटीएस से जनरेट की जाती हैं और क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यक अतिरिक्त मासिक और त्रैमासिक रिपोर्टों के स्वचालित उत्पादन को सक्षम करने के लिए आगे कार्रवाई की जा रही है।

(च) सम्मन्स मॉड्यूल (ईडीओटीएस उप-मॉड्यूल) - डिजिटल सम्मन्स मॉड्यूल क्यूआर-सक्षम सम्मन्स जारी करता है, जिससे प्राप्तकर्ता ईडी की वेबसाइट के माध्यम से प्रामाणिकता सत्यापित कर सकते हैं, जिससे दुरुपयोग को रोका जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। यह पहल फर्जी या धोखाधड़ी वाले सम्मन्स के परिचालन को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है कि व्यक्ति निदेशालय द्वारा जारी किए गए वास्तविक सम्मन्स को आसानी से पहचान सकें, जिससे पारदर्शिता और जन जागरूकता में काफी वृद्धि हो सके। ईडी ने हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है जिसमें व्यक्तियों को प्राप्त सम्मन्स की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इसे दिनांक 08.10.2025 को प्रेस विज्ञप्ति अनुभाग द्वारा इस निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।

उसी का वेब लिंक नीचे दिया गया है: - उक्त प्रेस विज्ञप्ति के लिए वेब लिंक-

https://enforcementdirectorate.gov.in/sites/default/files/latestnews/Press_release_fake%20summons-08.10.2025%201.pdf

(छ) स्वागतम पोर्टल - स्वागतम पोर्टल डिजिटल सत्यापन के माध्यम से ईडी मुख्यालय में सभी आगंतुक प्रविष्टियों का प्रबंधन करता है, जिससे एक्सेस कंट्रोल और सुरक्षा मजबूत होती है। पोर्टल ने आगंतुक प्रबंधन की पारदर्शिता में सुधार किया है और मैनुअल हस्तक्षेप को कम किया है, जिससे एक अधिक कुशल और जवाबदेह प्रवेश प्रणाली सुनिश्चित होती है।

(ज) एपीएआर प्रोसेसिंग के लिए स्पैरो - स्पैरो ऑनलाइन एपीएआर जनरेशन और प्रोसेसिंग के लिए पूरी तरह से कार्यात्मक है, जिससे ईडी कैंडर के कर्मचारी अपने पिछले एपीएआर रिकॉर्ड को आसानी से और सुरक्षित रूप से एक्सेस कर सकते हैं। निदेशालय के लिए, इसने प्रदर्शन रिपोर्टों को बनाए रखने और प्रबंधित करने, रिकॉर्ड रखने और संस्थागत दक्षता को मजबूत करने के लिए एक कागजरहित, पारदर्शी और डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित प्रणाली को सुगम बनाया है।

(झ) साइबर फोरेंसिक के लिए एनएफएसयू के साथ सहयोग - एनएफएसयू के साथ अपने एमओए के माध्यम से, ईडी अपनी 7 साइबर लैब्स (1 ईडी मुख्यालय में, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में और 1 एनएफएसयू-गांधीनगर में) का संचालन करता है और डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन और फोरेंसिक संचालन के लिए प्रशिक्षित तकनीकी सहायता प्राप्त करता है। यह निदेशालय अपनी चल रही डिजिटल उन्नयन पहलों के हिस्से के रूप में अपने मुख्यालय और क्षेत्रीय साइबर लैब्स के लिए नए अत्याधुनिक उन्नत फोरेंसिक उपकरण खरीदने की प्रक्रिया में है। साथ ही ईडी में फील्ड कार्यालयों को प्रदान किए गए फील्ड किट (मात्रा में 32) को अपडेट किया जा रहा है। ये उन्नत उपकरण जांच के दौरान साइबर फोरेंसिक, साक्ष्य निष्कर्षण और विश्लेषण में ईडी की तकनीकी क्षमता को और मजबूत करेंगे।

(ञ) प्रवर्तन निदेशालय में आईगोट प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन - प्रवर्तन निदेशालय ने इस निदेशालय के 1311 कर्मचारियों/अधिकारियों/कार्मिकों को आईगोट प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक शामिल किया है। इसके अलावा, 908 कर्मचारियों/अधिकारियों/कार्मिकों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह बनाने के हिस्से के रूप में आईगोट प्लेटफॉर्म पर इस निदेशालय द्वारा पहचाने गए 10 पाठ्यक्रमों में से प्रत्येक को 6 से अधिक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

4.3 वित्तीय आसूचना एकक - भारत (एफआईयू-भारत):

4.3.1 वित्तीय आसूचना इकाई, भारत (एफआईयू-भारत) वह केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी है जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, उसका प्रसंस्करण करने, उसका विश्लेषण करने और प्रवर्तन एजेंसियों तथा विदेशी एफआईयू को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। एफआईयू-भारत धन-शोधन तथा आतंकवाद और प्रसार के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आसूचना, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों

के समन्वय और सुदृढीकरण के लिए भी जिम्मेदार है। इस वर्ष एफआईयू-भारत ने डीएनएफपीबी (रियल एस्टेट, रत्न और आभूषण, वीएएसपी और टीसीएसपी) को शामिल करके आरई डोमेन का विस्तार किया है।

एफआईयू-भारत विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं अर्थात् सीमा-आधारित रिपोर्ट और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट से आसूचना जानकारी प्राप्त करने और उसका प्रसंस्करण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन स्रोतों से परे, एफआईयू-भारत खुले स्रोत की आसूचना जानकारी से संभावित अपराधों और धन-शोधन से संबंधित आसूचना जानकारी को सक्रिय रूप से एकत्रित करता है। इसमें प्रतिकूल मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिनका अक्सर कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जिससे वे साइबर अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों में फंस जाते हैं।

4.3.2 एगमोंट समूह में सहयोग और बड़ी हुई वैश्विक मान्यता और सहभागिता

4.3.2.1 सर्वश्रेष्ठ एगमोंट केस अवार्ड (बीईसीए) 2025

एफआईयू-इंडिया को धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक उत्कृष्ट मामले के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ एगमोंट केस अवार्ड (बीईसीए) 2025 से सम्मानित किया गया। यह मामला एफआईयू-इंडिया द्वारा लकजमबर्ग में एगमोंट समूह की पूर्ण बैठक के दौरान आयोजित बीईसीए कार्यशाला के दौरान प्रस्तुत किया गया था और इसे दुनिया भर के एफआईयू से व्यापक सराहना मिली।

4.3.2.2 एगमोंट गवर्नेंस में नेतृत्व की भूमिका:

सुश्री एम. शनमुगा प्रिया, संयुक्त निदेशक, एफआईयू-इंडिया को एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय समूह (एपीआरजी) के क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया, जो एक महत्वपूर्ण नेतृत्व पद है और क्षेत्रीय समूह के सदस्यों से संबंधित निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस नियुक्ति ने एगमोंट समिति में भारत की स्थिति को सुरक्षित किया, जो एगमोंट समूह का मूल शासी निकाय है, जिससे वैश्विक एएमएल/सीएफटी नीति-निर्माण में भारत की भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री मनीष कुमार हैरत, निदेशक एफआईयू-इंडिया (प्रभारी), जो सूचना विनिमय कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, ने पूर्ण सत्र के दौरान कई सत्रों की सफलतापूर्वक अध्यक्षता की। अधिकारी ने आईटी बिजनेस स्ट्रेटेजी - एफआईयू-इंडिया पर्सपेक्टिव्स एंड लेटैस्ट टेक्नोलॉजिकल एन्हांसमेंट्स पर प्रस्तुति भी दी, जिसमें आसूचना जुटाने में एफआईयू-इंडिया के नवाचारों को प्रदर्शित किया गया।

आईडब्ल्यूजी, पीपीडब्ल्यूजी, टीएटीडब्ल्यूजी, एमएससीडब्ल्यूजी और एपीआरजी जैसे कार्य समूहों में एफआईयू-इंडिया की सक्रिय भागीदारी की अत्यधिक सराहना की गई। इकाई के योगदान ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय आसूचना समुदाय में एक विचार नेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।

4.3.2.3 विषयगत कार्यशाला प्रस्तुतियाँ: एफआईयू-इंडिया ने दो प्रमुख विषयगत कार्यशालाओं में सक्रिय रूप से योगदान दिया:

जोखिम प्राथमिकता - एएमएल/सीएफटी जोखिम पहचान को बढ़ाने के लिए एफआईयू-इंडिया के तकनीक-संचालित दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। परिचालन सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) - एफआईयू और रिपोर्टिंग

संस्थाओं के बीच रणनीतिक सहयोग के लिए एफपीएसी (एएमएल/सीएफटी सहयोग के लिए एफआईयू-आईएनडी भागीदारी) पहल को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।

4.3.2.4 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर:

एफआईयू-इंडिया ने एफआईयू-कुवैत और एफआईयू-तिमोर लेस्ते के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य धन शोधन, संबंधित अपराधों और आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित आसूचना के आदान-प्रदान में सहयोग को मजबूत करना है। ये समझौते प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ एफआईयू-इंडिया की द्विपक्षीय भागीदारी और परिचालन समन्वय को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

4.3.3 फिननेट 2.0

फिननेट 2.0 को एफआईयू- इंडिया में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह अपनी तरह की अग्रणी आईटी प्रणालियों में से एक है जो एफआईयू- इंडिया की सभी सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के लिए एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करती है, जिसमें सूचना प्राप्त करना, उसका विश्लेषण करना और उसका प्रसार करना शामिल है, और एक तरफ एफआईयू- इंडिया और रिपोर्टिंग संस्थाओं (फिंगेट 2.0) और दूसरी तरफ एफआईयू- इंडिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच एक सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से दो-तरफा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली प्रदान करती है।

फिननेट 2.0 एक अत्याधुनिक आईटी प्रणाली है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों का लाभ उठाती है। फिननेट 2.0 सटीकता में सुधार के लिए बाहरी डेटा स्रोतों का उपयोग कर रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा का सत्यापन और संवर्धन करता है। यह प्रणाली व्यक्तियों, व्यवसायों, रिपोर्टों, नेटवर्क और मामलों के लिए जोखिम स्कोर उत्पन्न करती है, जो एलईए को तुरंत प्रसारित करने के लिए उच्च जोखिम वाली संस्थाओं या रिपोर्टों की पहचान और प्राथमिकता में सहायता करती है। इसके अतिरिक्त, फिननेट 2.0 प्राथमिकता वाले संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) को अन्य कम जोखिम वाले एसटीआर से अलग करने के लिए जोखिम विश्लेषण लागू करता है।

4.3.4 रणनीतिक विश्लेषण प्रयोगशाला: - तेजी से जटिल होते वित्तीय अपराधों और वित्तीय अपराधों के अन्य संगठित अपराधों के साथ एकीकरण के साथ, नए धन शोधन/आतंकवाद वित्तपोषण प्रकारों को समझने में फुर्तीला होना आवश्यक है ताकि उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। इसी दृष्टिकोण के साथ, रणनीतिक विश्लेषण प्रयोगशाला (एसएएल) की स्थापना फिननेट 2.0 परियोजना के भाग के रूप में आसूचना जनरेट करने में सुधार के लिए लगातार अनुसंधान और डेटा का विश्लेषण करने के लिए की गई थी।

रणनीतिक विश्लेषण प्रयोगशाला (एसएएल) की स्थापना वर्ष 2021 में पूरी हुई थी, और तब से, 100 से अधिक अध्ययन पूरे हो चुके हैं। एसएएल के पास नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच रखने वाले अपने स्वयं के विशेष मानव संसाधन हैं। यह एक "उत्कृष्टता केंद्र" के रूप में कार्य करता है और एफआईयू-इंडिया की आसूचना जनरेट

करने की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए डेटा का खनन करता है। प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों के तहत एसएलएल द्वारा किए गए कुछ अध्ययन इस प्रकार हैं:

- यहाँ भौगोलिक रूप से संवेदनशील देशों से संबंधित एसटीआर, सीबीडब्ल्यूटीआर और अन्य रिपोर्टों का रणनीतिक विश्लेषण किया गया, जो एसटीआर में पाए गए ऐसे पैर से जुड़े थे। यह रिपोर्ट एफआईयू-इंडिया के अधिकारियों के साथ साझा की गई है और इसका उपयोग ऑपरेशनल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट विकसित करने के लिए किया जाता है।
- संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित एसटीआर और आतंक वित्तपोषण के संदेह वाले एसटीआर का रणनीतिक विश्लेषण। एसटीआर का सेट विभिन्न एलईए के साथ साझा किया गया।
- उन मामलों और संस्थाओं की पहचान के लिए सीबीडब्ल्यूटीआर डेटा का विश्लेषण जिनमें गैर-सरकारी संगठनों (एनपीओ) को एफसीआरए लाइसेंस या पूर्व अनुमति के बिना विदेशी धन प्राप्त हुआ है। उपरोक्त अध्ययन संबंधित एलईए के साथ साझा किया गया।
- राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन कार्य के भाग के रूप में मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित एसटीआर का विश्लेषण। मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित एसटीआर का एसटीआर प्रवृत्ति विश्लेषण स्रोत, राज्य, रेड फ्लैग इंडिकेटर, वर्ष के अनुसार और रिपोर्टिंग इकाई के अनुसार प्रवृत्ति और संबंधित कीवर्ड निष्कर्षों के आधार पर मादक पदार्थों की तस्करी के उपप्रकारों की पहचान पर किया गया।
- विभिन्न भुगतान माध्यमों, रिपोर्टिंग इकाई भिन्नता, प्रमुख स्रोत की पहचान, लिंक किए गए विधेय अपराध और गेमिंग/जुआ गतिविधि में शामिल लोगों की आर्थिक प्रोफाइल के लिए संदिग्ध लेनदेन मात्रा हिस्सेदारी से संबंधित भुगतान जोखिम विश्लेषण के लिए गेमिंग/जुआ एसटीआर का अध्ययन। इस अध्ययन में क्षेत्रीय हिस्सेदारी और भिन्नता, लिंग और आयु वर्ग पैटर्न पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- बैंकिंग क्षेत्र के जोखिम मूल्यांकन का विश्लेषण 4 विभिन्न विषयों में - भुगतान प्रणालियाँ, एमटीएसएस, म्यूल खाते और सहकारी बैंक। इस अध्ययन में लेनदेन की मात्रा और प्रकार में भिन्नता, आरई श्रेणी के अनुसार उपयोग किए गए लेनदेन के तरीके,

भौगोलिक और जनसांख्यिकीय प्रसार और अपराधों के आधार पर संबंध शामिल थे।

- एस टी आर डेटाबेस से व्यक्तियों की जोखिम प्राथमिकता - इस अध्ययन का उद्देश्य व्यक्तियों की जोखिम प्राथमिकता को उन विशिष्ट एस टी आर की संख्या के आधार पर निर्धारित करना है जिनसे वे जुड़े हुए हैं, उन विशिष्ट आर ई की संख्या जिन्होंने उन एस टी आर को दाखिल किया है, अलर्ट का स्रोत, लिंक किए गए एस टी आर में रिपोर्ट किए गए अपराधों की प्रकृति, और लिंक किए गए सी टी आर, सी बी डब्ल्यू टी आर, एन टी आर की संख्या और मात्रा।

4.3.5 एफ.आई.यू.-इंडिया द्वारा अनुपालन कार्रवाई

वर्तमान वर्ष के दौरान, एफ.आई.यू.-इंडिया ने कई रिपोर्टिंग संस्थाओं पर अनुपालन कार्रवाई की, जिसमें एक आर.ई. यानी यूनिन बैंक ऑफ इंडिया पर रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में अपने दायित्व का अनुपालन न करने के लिए 37 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया गया।

4.3.6 प्रभाव का आकलन: एफआईयू-इंडिया द्वारा साझा की गई आसूचना के आधार पर एलईए की कार्रवाई

एलईए ने एफआईयू-इंडिया द्वारा साझा की गई कार्रवाई योग्य आसूचना के आधार पर कई कार्रवाइयाँ की हैं और विभिन्न मामले दर्ज किए हैं, जिसमें ऑपरेशनल एनालिसिस, टैक्टिकल एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस और एसटीआर शामिल हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस के साइबर-क्राइम विंग ने प्रतिबंधित पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों के माध्यम से कथित तौर पर वयस्क सामग्री बनाने और प्रसारित करने के आरोप में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। केरल में एक एलईए द्वारा वन ट्रस्ट और उसके एनआरआई चेरमैन पर एफसीआरए पंजीकरण के बिना 220 करोड़ रुपये का विदेशी योगदान प्राप्त करने और फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कृषि संपत्तियों में निवेश करने के मामले में तलाशी ली गई।

भारत-चीन सीमा के माध्यम से तस्करी किए गए 108 किलोग्राम एफओ सोने की छड़ें जब्त करने के संबंध में चल रही जाँच में शामिल भारतीय व्यक्तियों और क्रिप्टो करेंसी/वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) लेनदेन में शामिल व्यक्तियों के संबंध में एक एलईए द्वारा कार्रवाई की गई।

4.3.7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, 01/04/2025 से 30/11/2025 की अवधि के दौरान प्राप्त, निपटाए गए और अस्वीकृत आरटीआई आवेदनों की संख्या।

प्राप्त	निपटाए गए		टिप्पणियाँ
	हस्तांतरित	अस्वीकृत	
131	04	0	प्राप्त 119 आर.टी.आई. अनुरोधों और 08 आवेदनों के लिए प्रदान की गई जानकारी क्रमशः निपटान के लिए लंबित है।

नोट: एफआईयू-आईएनडी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 28.09.2005 की अधिसूचना के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(1) के तहत, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप से संबंधित जानकारी को छोड़कर, इस अधिनियम के संचालन से मुक्त है।

4.4 आर्थिक सुरक्षा (ई.एस.)

4.4.1 आर्थिक सुरक्षा प्रकोष्ठ जांच और प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित समन्वय कार्य करता है, यह आर्थिक सुरक्षा मामलों, एशिया/प्रशांत धन-शोधन समूह, ईजीमॉट समूह आदि जैसे विदेशी संगठनों से संबंधित मामलों के संबंध में मंत्रिसमूह/विभिन्न समितियों आदि द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन

का कार्य करना है। यह धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रशासन/संशोधन से भी संबंधित है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा प्रकोष्ठ नीचे दिए गए संगठनों को प्रशासनिक रूप से नियंत्रित करता है:

(i) धन-शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण

(ii) वित्तीय आसूचना एकक-भारत

4.4.2 धन-शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 17 जनवरी, 2003 को अधिनियमित किया गया था और 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य धन-शोधन को रोकना और धन-शोधन से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति को जब्त करने और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना है। अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

- धन-शोधन को अपराध घोषित करना तथा धन-शोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, जब्ती और जब्ती का प्रावधान करना [प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्यान्वित]; तथा
- बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बिचौलियों पर केवाईसी, रिकॉर्ड रखने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने से संबंधित दायित्व निर्धारित करना [वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफआईयू-इंडिया) द्वारा कार्यान्वित]।

4.5 वित्तीय कार्रवाई कार्य बल

- वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) 39 सदस्यों (37 अधिकार क्षेत्र और 2 संगठन) वाला एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है, जो विश्व भर के देशों में धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, वित्तपोषण का मुकाबला करने या सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए कानूनी, नियामक और कार्यान्वयन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अपने सदस्य अधिकार क्षेत्रों द्वारा स्थापित किया गया है। भारत वर्ष 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना। भारत दो एफएटीएफ शैली के क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) - एशिया प्रशांत समूह (एपीजी) और यूरेशियन समूह (ईएजी) का भी सदस्य है जो धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करते हैं।
- एफएटीएफ का मुख्य कार्य अपने सदस्यों का पारस्परिक मूल्यांकन करना और एफएसआरबी को उनके संबंधित सदस्य अधिकार क्षेत्रों का पारस्परिक मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता करना है। एफएटीएफ के संशोधित मानकों (40 सिफारिशें और 11 तत्काल परिणाम) के आधार पर भारत के पारस्परिक मूल्यांकन का अंतिम दौर मई, 2023 में शुरू हुआ और यह जून, 2024 में पूरा हो गया है। अपने पिछले पारस्परिक मूल्यांकन में, भारत ने एफएटीएफ सिफारिशों में उच्च स्तर की तकनीकी अनुपालन हासिल की है और अवैध वित्त से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे 26 जून से 28 जून, 2024 के बीच सिंगापुर

में आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी में अपनाया गया था, भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखती है, यह एक ऐसा अंतर है जो केवल चार अन्य जी20 देशों द्वारा साझा किया जाता है। यह धन-शोधन (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) से निपटने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धी है।

- पास्परिक मूल्यांकन अत्यंत व्यापक और गहन कार्य है जिसमें किसी राष्ट्र के वित्तीय क्षेत्र की धन-शोधन रोधी और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है।
- दिनांक 9 नवंबर, 2017 के भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के तहत एफएटीएफ प्रकोष्ठ का गठन वर्ष 2017 में राजस्व विभाग में किया गया था।
- एफएटीएफ सचिवालय से संबंधित समन्वय या कार्य एफएटीएफ प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है। इसके भाग के रूप में, एफएटीएफ अन्य प्रमुख एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय, एफआईयू-भारत, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, एमएचए, एनआईए, एमईए, एमसीए आदि के साथ समन्वय करता है।
- यह देश के सभी संबंधित हितधारकों के साथ एफएटीएफ, एपीजी, ईएजी से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों/प्रस्तावों को प्राप्त करता है, प्रसारित करता है और उन पर विचार-विमर्श करता है तथा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इन मुद्दों पर भारत की टिप्पणियां भेजी जाती हैं।
- एफएटीएफ प्रकोष्ठ एफएटीएफ, एपीजी और ईएजी के पूर्ण अधिवेशनों और अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नामांकन को भी संभालता है। एफएटीएफ प्रकोष्ठ के अधिकारियों सहित प्रमुख एजेंसियों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं और यह प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मामलों पर बहुपक्षीय चर्चाओं में भाग लेते हैं।
- वर्तमान में, एफएटीएफ सेल कई देशों को एफएटीएफ फ्रेमवर्क के तहत पारस्परिक मूल्यांकन के लिए उनकी तैयारियों का समर्थन करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस संदर्भ में, श्रीलंका को उसके आगामी एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी।
- एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन करना है जहां बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, नामित गैर-वित्तीय व्यापार और व्यवसाय क्षेत्रों आदि जैसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के जोखिम का समय-समय पर आकलन किया जाता है। राजस्व विभाग का एफएटीएफ प्रकोष्ठ, भारत/टीएफ एनआरए के संचालन के लिए समन्वयक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, एफएटीएफ प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन 2025 से संबंधित कार्यों का समन्वय कर रहा है।

- x. एमएल/सीएफटी मामलों पर स्थूल-स्तरीय नीति का निर्णय करने में, सरकार का कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय आसूचना एकक-भारत और नियामक या पर्यवेक्षक के साथ कार्यान्वयन संबंधी सहयोग और राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन (एनआरए) का पर्यवेक्षण के उद्देश्य से पीएमएलए की धारा 72क के तहत राजस्व सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति का गठन किया गया है एफएटीएफ प्रकोष्ठ आईएमसीसी के सचिवालय के रूप में काम करता है।
- xi. सभी हितधारकों के बीच परिचालन समन्वय बढ़ाने के लिए अपर सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में एक एमएल/सीएफटी संयुक्त कार्य समूह बनाया गया है।
- xii. एफएटीएफ प्रकोष्ठ जी20 भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) पर काम करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा गठित मुख्य गुप का भी हिस्सा है और 2022-24 के लिए कार्य योजना पर सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें वर्ष 2023 शामिल है। जब भारत जी20 के अध्यक्ष पद को अलंकृत करेगा। एफएटीएफ प्रकोष्ठ डीईए द्वारा समन्वित जी20 के वित्त ट्रैक, ब्रिक्स एमएल/सीएफटी बैठकों, आरआईसी बैठकों, आतंकवाद की रोकथाम पर वार्ता, आतंकवादी वित्तपोषण से संबंधित लक्षित वित्तीय प्रतिबंध पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय आर्थिक निकायों की बैठकों के लिए नियमित इनपुट प्रदान करता है।
- xiii. वर्ष 2025 के दौरान, राजस्व विभाग के एफएटीएफ प्रकोष्ठ ने मौजूदा एमएल/सीएफटी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के पर्यवेक्षकों और नियामकों के साथ मिलकर काम किया, और एफएटीएफ मानकों के अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। एफएटीएफ प्रकोष्ठ का काम वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएसपी), कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर्स को एमएल/सीएफटी पर्यवेक्षण के दायरे में लाने में सहायता करना और उन्हें एफआईयू-भारत के लिए रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करना था। राष्ट्रीय एमएल/सीएफटी नीति को विकसित करने और जारी करने के लिए एफएटीएफ सेल ने सभी संबंधित संगठनों के साथ समन्वय किया। आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) के साथ-साथ सीटी संवाद पर समन्वय के लिए एफएटीएफ सेल के अधिकारी एफसीओआरडी की बैठकों में भाग लेते हैं।
- xiv. एफएटीएफ, ईएजी, एपीजी की पूर्ण और कार्यकारी समूह की बैठकें अब भौतिक प्रारूप में आयोजित की जा रही हैं और भारतीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहा है। फरवरी 2025 एफएटीएफ पूर्ण सत्र पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था और इसमें भारत से ग्यारह (11) सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था, जबकि

जून, 2025 पूर्ण सत्र सिंगापुर में आयोजित किया गया था और भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट पर अंतिम विचार-विमर्श के कारण इसमें 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था। अक्टूबर 2025 एफएटीएफ पूर्ण सत्र पेरिस में आयोजित किया गया था और इसमें भारत के 8 (आठ) सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था।

- xv. एफएटीएफ सेल, राजस्व विभाग ने नई दिल्ली में संयुक्त निर्धारकों का प्रशिक्षण, 2025 (7-11 अप्रैल) आयोजित किया और इसमें एफएटीएफ/ईएजी/एपीजी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

एफएटीएफ सेल ने नई दिल्ली में मध्य एशियाई देशों के लिए 2-दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (21-22 अप्रैल) भी आयोजित किया।

4.6 स्वापक नियंत्रण (एनसी)

4.6.1 स्वापक नियंत्रण प्रभाग द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) को कार्यान्वित किया जाता है, जो चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के निर्माण, उत्पादन, कब्जे, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण को प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार सरकार की नीति चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना है, जबकि वैध स्रोतों से उनके विचलन को रोकना तथा अवैध तस्करी और दुरुपयोग को रोकना है। स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम वैध गतिविधियों के विनियमन की शक्तियों और जिम्मेदारी को विभाजित करता है। अधिनियम की धारा 9 में ऐसी विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार नियमों द्वारा विनियमित कर सकती है जबकि धारा 10 में ऐसी विभिन्न गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें राज्य सरकारें नियमों द्वारा विनियमित कर सकती हैं। तदनुसार, केंद्र सरकार द्वारा स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 बनाए गए हैं, जो अफीम की खेती, स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के निर्माण, आयात/निर्यात को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा, व्यापक औद्योगिक उपयोग के अग्रगामी रसायनों को स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण से रोकने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 9ए के तहत स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (नियंत्रित पदार्थों के विनियमन) आदेश, 2013 तैयार किया गया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के उपरोक्त प्रावधानों को अन्य बातों के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् (i) केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) और (ii) मुख्य कारखाना नियंत्रक, सरकारी अफीम और आल्कलॉइड कारखाने (जीओएएफ) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

4.6.2 केंद्रीय स्वापक ब्यूरो के कार्य/कार्यप्रणाली

स्वापक आयुक्त ग्वालियर स्थित केंद्रीय स्वापक ब्यूरो (सीबीएन) मुख्यालय का प्रमुख होता है। स्वापक आयुक्त पोस्ट की खेती पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है, जो वर्तमान में तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और

राजस्थान के चयनित अधिसूचित क्षेत्रों में किया जाता है। अफीम पोस्ट की खेती के लाइसेंस, खेतों की माप और परीक्षण माप और अफीम और पोस्ट के भूसे, जिसमें से कोई रस नहीं निकाला जाता है, की खरीद से संबंधित कार्य के अलावा सीबीएन अफीम को अवैध चैनलों में जाने से रोकने के लिए निवारक जाँच और सतर्कता भी करता है और साथ ही स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 को लागू करता है।

- पूरे देश में अफीम की अवैध खेती का सर्वेक्षण, पता लगाना और उन्मूलन।
- मादक पदार्थों, मनःप्रभावी पदार्थों और नियंत्रित पदार्थों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों को लागू करना, जिसमें नशीली दवाओं के अपराधियों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, जांच और अभियोजन, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार से प्राप्त नशीली दवाओं के तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों का पता लगाना और उन्हें जब्त करना शामिल है।
- एनडीपीएस अधिनियम 1985 के तहत अधिसूचित सिंथेटिक स्वापक औषधि के निर्माण के लिए घरेलू निर्माताओं को लाइसेंस जारी करना।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के निर्यात/आयात के लिए निर्यात अधिकार पत्र और आयात प्रमाणपत्र जारी करना और 1961, 1971 और 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों के तहत अग्रगामी रसायनों के आयात/

निर्यात के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करना, सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण (सीएनए) के कार्य हैं। जो इन दवाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थों रसायनों/पदार्थों की व्यवस्था करना।

- वर्ष 1988 कन्वेंशन के तहत देशों के सीएनए को आईएनसीबी और संबंधित देशों के सक्षम अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले अग्रदूत रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से विचलन को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने की आवश्यकता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी), यूनाइटेड नेशनल ऑफिस आन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) के साथ-साथ अन्य देशों के सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों के साथ स्वापक दवाओं, मनःप्रभावी पदार्थों और अग्रदूत रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दों पर संपर्क बनाए रखना।
- अन्य औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों जैसे राजस्व आसूचना निदेशालय, सीमा शुल्क, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, राज्य पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क, राज्य एफडीए और विभिन्न अन्य औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय।

4.6.2.1 निष्पादन और उपलब्धियां: - वर्ष 2024-25 के दौरान अग्रदूत रसायनों के निर्यात/आयात के लिए केंद्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी एनओसी के संबंध में निष्पादन/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

जारी किए गए एनओसी की संख्या	दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक	दिनांक 01.12.2025 से 31.03.2026 तक (अनुमानित)
नियंत्रित पदार्थ के निर्यात के लिए	1551	750
नियंत्रित पदार्थ के आयात के लिए	1041	390
कुल	2592	1140
सीएनए को भेजे गए पूर्व-निर्यात अधिसूचना (पीईएन) की संख्या	1363	1140
रोकी गई /निलंबित शिपमेंट की संख्या (निर्यात)	40	लागू नहीं

इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी) ने सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए ऑनलाइन पूर्व-निर्यात अधिसूचना (पीईएन) प्रणाली प्रदान की है। सीबीएन ने लेन-देन की वैधता की पुष्टि करने के लिए विभिन्न आयातक देशों के सक्षम प्राधिकारी को (दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक की अवधि के दौरान) 1363 पीईएन जारी किए थे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन पेन प्रणाली के माध्यम से की गई पहल पर, सी.बी.एन. ने रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान वैध

माध्यमों से हटाए जाने के संदेह में अग्रदूत रसायनों के संदिग्ध लेन-देन की पहचान की है और उन्हें रोक दिया है।

वर्ष (दिनांक 01.04.2025 से 31.10.2025 तक) के दौरान स्वापक औषधि/ मनःप्रभावी पदार्थों के निर्यात/आयात के लिए केंद्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा जारी निर्यात अधिकार पत्र और आयात प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में निष्पादन/ उपलब्धि निम्नानुसार है:-

	मनःप्रभावी पदार्थ		स्वापक औषधि	
	दिनांक 01.04.2025 से 30.10.2025 तक	दिनांक 01.12.2025 से 31.03.2026 तक (अनुमानित)	दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक	दिनांक 01.12.2025 से 31.03.2026 तक (अनुमानित)
जारी किए गए निर्यात अधिकार पत्र की संख्या	4521	2179	325	115
जारी किए गए आयात प्रमाणपत्र की संख्या	662	331	124	30
कुल	5183	2510	449	145

वर्ष 01.04.2025 से 30.11.2025 के दौरान प्राकृतिक स्वापक औषधियों द्वारा विभिन्न फार्मास्युटिकल्स कंपनियों को स्वापक औषधियों के कोटा (एनडी)/सिंथेटिक स्वापक औषधियों (एसडी) के लिए केंद्रीय स्वापक ब्यूरो आबंटन के संबंध में निष्पादन/उपलब्धि निम्नानुसार है:-

कोटा आबंटन का विवरण	वर्ष 2025 (दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक)	अनुमानित (01.12.2025 से 31.03.2026 तक)
प्राकृतिक स्वापक औषधि (एनडी) के कोटा आबंटन का प्रमाण पत्र जारी किया गया	266	201
सिंथेटिक स्वापक औषधि (एसडी) के कोटा आबंटन का प्रमाण पत्र जारी किया गया	59	37
कुल	325	238

4.6.2.2 एनडीपीएस अधिनियम, 1985 का प्रवर्तन-

केंद्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों की औषधि तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई करता है। यह औषधि से संबंधित अपराधों की जांच और अभियोजन, अवैध औषधि की तस्करी से प्राप्त औषधि तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का पता लगाना और उसे जब्त करने का कार्य भी करता है। अप्रैल 2025 और नवंबर 2025 में अवैध अफीम पोस्ट की खेती और गांजे को नष्ट किए जाने का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	राज्य	नष्ट किया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)
2025-26	हिमाचल प्रदेश	1763 (गांजा)
2025-26	उत्तराखंड	1383 (अफीम पोस्ट)
कुल		3146

अप्रैल 2025 और नवंबर 2025 के दौरान सीबीएन द्वारा की गई जब्ती

क्रम संख्या	स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रीकर्सर	मामलों की संख्या	मात्रा
1	पौपी स्ट्रॉ	93	176865.97 कि.ग्रा.
2	हेरोइन	05	0.922 कि.ग्रा.
3	गांजा	12	577.311 कि.ग्रा.
4	चरस	01	2.574 कि.ग्रा.
5	ट्रामाडोल टैब/कैप/इंजेक्शन	07	1291558 कैप
6	अफीम	44	2304.023 कि.ग्रा.
7	अल्प्रजोलम टैब/पाउडर	10	2722169 टैब
8	क्लोरडियाज़ेपॉक्साइड टैब	*	290 टैब
9	क्लोनाज़ेपैम टैब	01	1835 टैब
10	लोराज़ेपैम	*	136800 टैब
11	नाइट्रोजेपैम टैब	01	268 टैब
12	केटामाइन	01	81800 एम्प्यूल्स
13	ब्यूप्रैनॉर्फिन	01	16675 एम्प्यूल्स
14	कोडीन फॉस्फेट सिरप/टैब	01	103336 बोटल
15	पेंटाज़ोसीन इंजे.	*	74398 इंजेक्शन
16	एमडीएमए पिल्स/क्रिस्टल	04	2.800 कि.ग्रा.
17	सस्पेंडेड साइकोट्रोपिक पाउडर	01	10.078 कि.ग्रा.
18	एम.डी. पाउडर साइकोट्रोपिक दवाएं ज़ोलपिडेम टैब मेथाम्फेटामाइन मेफेड्रोन टैपेन्टाडोल टैब	04	0.949 कि.ग्रा.

क्रम संख्या	स्वापक औषधि/मनःप्रभावी पदार्थ/प्रीकर्सर	मामलों की संख्या	मात्रा
19	साइकोट्रोपिक दवाएं	*	230720 टैब
20	ज़ोलपिडेम टैब मेथाम्फेटामाइन मेफेड्रोन टैपेन्टाडोल टैब	*	120 टैब
21	मेथाम्फेटामाइन	01	0.200 कि.ग्रा.
22	मेफेड्रोन	11	5.098 कि.ग्रा.
23	टैपेन्टाडोल टैब	*	12000 टैब

वर्ष 2025 (30.11.2025 तक) के दौरान सीबीएन द्वारा जब्त की गई औषधि का निपटान

अफीम	169.974 कि.ग्रा.
हेरोइन	0.712 कि.ग्रा.
खसखस भूसी	44624.86 कि.ग्रा.
मेफेड्रोन	3.32 कि.ग्रा.
एसिटिक एनहाइड्राइड	0.800 कि.ग्रा.
नाइट्रोजेपाम	89 टैब
खसखस का पौधा	2045
ट्रामाडोल	46912 टैब + 400 इंजेक्शन
अल्प्रजोलम	9.9 कि.ग्रा.
मॉर्फिन टैबलेट	0.690 कि.ग्रा.
मेथाम्फेटामाइन	1.064 कि.ग्रा.
गांजा/कैनबिस	1227.69 कि.ग्रा.
चरस	2.527 कि.ग्रा.

4.6.2.3 जेंडर इशू/महिलाओं का सशक्तिकरण

कार्यस्थल पर महिलाओं के "यौन उत्पीड़न" के संबंध में शिकायत समिति का गठन किया गया और यह मुख्यालय, ग्वालियर और इकाई कार्यालयों में कार्यरत है। कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न (निवारक, निषेध और निवारण अधिनियम, 2013) के तहत शिकायतों पर की गई कार्रवाई पर डीजीएचआरडी को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

4.6.2.4 ई-गवर्नेंस गतिविधियाँ

भारत को डिजिटल इंडिया में बदलने की दिशा में एक और कदम के रूप में सी.बी.एन. का यूनिफाइड वेब पोर्टल यू.आर.एल. (<http://www.cbnonline.gov.in>) के साथ लॉन्च किया गया था। यूनिफाइड पोर्टल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ सभी लाइसेंस से संबंधित कार्यों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम कर रहा है।

4.6.2.5 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरटीआई धारा के तहत प्राप्त आवेदनों को आरटीआई अधिनियम के तहत निश्चित समय सीमा में निपटाया जाता है। विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विस्तृत कार्य और विभिन्न पहलू सीबीएन वेबसाइट <http://www.cbn.nic.in> पर भी उपलब्ध हैं।

4.6.2.6 वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 55472 कृषकों को गम अफीम के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया। फसल वर्ष 2024-25 के दौरान 54344 कृषकों ने गम अफीम की निविदा की और अफीम कृषकों से 70 सार्द्रता (अनंतिम आंकड़ा) पर 346 मीट्रिक टन अफीम का उत्पादन किया गया। फसल वर्ष 2024-25 के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इकाइयों से प्राप्त परिणामों के आधार पर 70 सार्द्रता पर औसत उपज (किलोग्राम/हेक्टेयर) 64.70 किलोग्राम/हेक्टेयर(अनंतिम) है।

अनलांस्ड पोस्ता स्ट्रॉ (यूपीएस) का उत्पादन :- फसल वर्ष 2024-25 में बिना बीज वाले पोस्ता भूसे की खेती के लिए कुल 42830 कृषकों को लाइसेंस जारी किया गया और 41788 कृषकों ने फसल वर्ष 2024-25 में कुल 3838 एम.टी. यू.पी.एस. की मात्रा उपलब्ध की।

4.6.2.7 वर्ष 2025-26 के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों की अन्य विशेषताएं

i. जेम खरीद:-

कार्यालयी उद्देश्य के लिए वस्तुओं की खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती है। जड़ वस्तुओं और खराब होने वाली

वस्तुओं को जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीदा जाता है। सामग्री की आगामी खरीद/सेवा ज्यादातर जेईएम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

ii. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा विश्व औषधि दिवस, 26 जून, 2025 का आयोजन:

समाज में नशीली दवाओं की हानि के प्रति जागरूकता लाने तथा इस समस्या को सुलझाने के लिए लोगों की भागीदारी के लिए प्रति वर्ष 26 जून को "नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय स्वापक औषधि ब्यूरो ने कई कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर बैनर लगाना, जागरूकता फैलाने के लिए बाइक रैली, एफएम रेडियो के माध्यम से जागरूकता अभियान के रूप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग, लेख तथा नारे लिखना, कार्यालय के कैपस में वृक्षारोपण का आयोजन किया है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

iii. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के हिंदी अनुभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम

वर्ष 2025-26 के दौरान हिंदी अनुभाग में दिनांक - 14.09.2025 से 30.09.2025 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। जिसमें विजयी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन हेतु दिनांक- 30.06.2025 को पुरस्कृत किया गया था।

4.6.3 सरकारी अफीम और अल्कलॉइड्स वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) के कार्य/कार्यप्रणाली

सरकारी अफीम और अल्कलॉइड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) अपने दो कारखानों अर्थात गाजीपुर (यूपी) और नीमच (एमपी) में सरकारी अफीम

और अल्कलॉइड वर्क्स (जीओएडब्ल्यू) के माध्यम से निर्यात और अफीम अल्कलॉइड के निर्माण के लिए कच्ची अफीम के प्रसंस्करण में लगी हुई है। जीओएडब्ल्यू में निर्मित उत्पाद मुख्य रूप से भारत के औषधी उद्योग द्वारा खांसी की दवाई, दर्द निवारक, नशामुक्ति दवाओं और घातक कैंसर और एचआईवी के गंभीर रोगियों के लिए दवा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जीओएडब्ल्यू को 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित "प्रबंधन समिति" नामक एक उच्चस्तरीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया गया है। अपर सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। आयुक्त/संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी मुख्य कारखाना नियंत्रक होता है जो कारखाना को नियंत्रित करते हैं तथा गाजीपुर और नीमच में स्थित प्रत्येक फैक्ट्री में दो इकाइयां हैं जिसे महाप्रबंधक जो अपर आयुक्त/निदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं, के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मुख्य कारखाना नियंत्रक का कार्यालय दिल्ली में स्थित है। गाजीपुर और नीमच में स्थित प्रत्येक फैक्ट्री में दो इकाइयाँ हैं - अफीम फैक्ट्री और अल्कलॉइड वर्क्स। अफीम फैक्ट्रियां खेतों से अफीम प्राप्त करने, उसके भंडारण और निर्यात तथा घरेलू खपत के लिए प्रसंस्करण का काम करती हैं। अल्कलॉइड वर्क्स दवा उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कच्ची अफीम को फार्माकोपियल ग्रेड के अल्कलॉइड में संसाधित करने में लगी हुई हैं।

जीओएडब्ल्यू के अफीम और अल्कलॉइड के अपने दो प्लांटों में कुल 420 व्यक्ति नौकरी करते हैं। इस कार्यबल में संघ लोक सेवा आयोग से सीधे चयनित अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय अग्रयत्क कर और सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय स्वापक औषधि ब्यूरो, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला से अधिकारी एवं कर्मचारी लिए जाते हैं। इन फैक्ट्रियों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) जो गृह मंत्रालय का एक अर्द्ध सैनिक बल है, द्वारा देखी जाती है।

4.6.3.1 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीओएफ का कार्य निष्पादन

क्रम सं.	विवरण	इकाई	वास्तविक उत्पादन अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक	अनुमानित उत्पादन दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक
क	उत्पादन			
1	क) मॉर्फिन सल्फेट	कि.ग्रा.	1363.200	1000
	ख) कोडीन फॉस्फेट (सीपी)	कि.ग्रा.	7778.000	17250
	ग) शुद्ध थेबाइन	कि.ग्रा.	1193.500	661
	घ) नोस्केपाइन बीपी	कि.ग्रा.	13406.000	9000
	ङ) पापावरिन एसआर	कि.ग्रा.	3494.200	1660
	च) आईएमओ पाउडर	कि.ग्रा.	12100.000	6050
	छ) आईएमओ केक	कि.ग्रा.	2586.000	1293
	कुल (1) (क से छ)	कि.ग्रा.	41920.900	36914

*09 अधीक्षक को सहायक आयुक्त (इन-सीटू आधार) के रूप में पदोन्नत किया गया

01 प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य लेखा अधिकारी (इन-सीटू आधार) के रूप में पदोन्नत किया गया

क्रम सं.	विवरण	वास्तविक बिक्री अप्रैल 2025 से नवंबर, 2025 तक मात्रा (किलोग्राम में)	अनुमानित बिक्री दिसंबर, 2025 से मार्च, 2026 तक मात्रा (किलोग्राम में)
ख	बिक्री		
1	क) मॉर्फिन सल्फेट	685.016	1600
	ख) कोडीन फॉस्फेट (स्वदेशी उत्पादन और आयातित)	17588.446	16228
	ग) शुद्ध थेबाइन	1250.030	723
	घ) नोस्केपाइन बीपी	12882.000	7250
	ड) पापावरिन एसआर	3725.000	3725
	च)आईएमओ पाउडर (घरेलू बिक्री + निर्यात)	12661.705	12461
	छ) आईएमओ केक (घरेलू बिक्री+निर्यात)	3686.715	3686
	ज) आरआईओ (निर्यात)	428.000	10120

ग. (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर, 2025 तक) के लिए 90°C पर अफीम का देश-वार निर्यात (आईएमओ पाउडर और केक की घरेलू बिक्री को छोड़कर)
(मात्रा किलोग्राम में)

क्र.सं.	इकाई	यूएसए	फ्रांस	स्विट्जरलैंड	कुल
1	जीओएएफ	428.086	4000.000	380.000	4808.086

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर 2025 से मार्च 2026 तक) के लिए 90°C पर अफीम का देशवार निर्यात (आईएमओ पाउडर और केक की घरेलू बिक्री को छोड़कर)
(मात्रा किलोग्राम में)

क्र.सं.	इकाई	फ्रांस	कुल
1	जीओएएफ	4000	4000

घ. (क) वित्तीय वर्ष 2025-26 (नवंबर 2025 तक) के लिए राजस्व प्राप्ति (वसूली के आधार पर)
(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	इकाई	अफीम फैक्ट्री	अल्कलॉइड कारखाने	कुल
1	जीओएएफ	0.53	147.22	147.76

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 तक) के लिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान (वसूली के आधार पर)
(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	इकाई	अफीम फैक्ट्री	अल्कलॉइड कार्य	कुल
1	जीओएएफ	6.94	104.44	111.38

II. नवंबर 2025 तक सीसीएफ संगठन की उपलब्धियां पिछले वर्ष अर्थात् 2024 की इसी अवधि के तुलनात्मक आंकड़ों के साथ

क्रम सं.	विवरण	इकाई	वास्तविक उत्पादन अप्रैल से नवंबर	
			2024-25	2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क.	उत्पादन			
1.	औषधियों का विनिर्माण:			
	क) मॉर्फिन सल्फेट	कि.ग्रा.	266.800	1363.200
	ख) कोडीन फॉस्फेट	कि.ग्रा.	22393.500	7778.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

ग) शुद्ध थेबाइन	कि.ग्रा.	856.850	1193.500
घ) नोस्केपाइन बीपी	कि.ग्रा.	633	13406.000
ड) पापावरिन एसआर	कि.ग्रा.	1923.870	3494.200
च) आईएमओ पाउडर	कि.ग्रा.	9800.000	12100.000
छ) आईएमओ केक	कि.ग्रा.	0	2586.000
कुल (1)(क+छ)	कि.ग्रा.	35874.020	41920.900

ख.	बिक्री		
क्रम सं.	विवरण	2024-2 अप्रैल से नवंबर	2025-26 अप्रैल से नवंबर
		मात्रा (किलोग्राम)	मात्रा (किलोग्राम)
(1)	(2)	(4)	(6)
1	औषधियों की घरेलू बिक्री: (वास्तविक आधार पर)		
	क) मोर्फिन सल्फेट	300.010	685.016
	ख) कोडीन फॉस्फेट	18755.751	17588.446
	(स्वदेशी एवं आयातित)		
	ग) शुद्ध थेबाइन	770	1250.030
	घ) नोस्केपाइन बीपी	2878.500	12882.000
	ड) पापावरिन एसआर	1800	3725.000
	च) आईएमओ पाउडर (घरेलू बिक्री + निर्यात)	7503.500	12661.705
	छ) आईएमओ केक (घरेलू बिक्री + निर्यात)	3484.721	3686.715

ग. 90°C पर अफीम का तुलनात्मक देशवार निर्यात (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नवंबर तक)
(90°C पर मात्रा किलोग्राम में)

इकाई	यूएसए	फ्रांस	स्विट्ज़रलैंड	श्रीलंका	कुल
2024-25					
जीओएफ	68.17	2000	668	130	2866.17
2025-26					
जीओएफ	428.086	4000	380	0	4808.086

- अफीम प्राप्ति, नमूनाकरण और परीक्षण में डिजिटलीकरण: -ओसीटीए (अफीम कंटेनर ट्रैकिंग एप्लिकेशन) क्यूआर कोड आधारित, ब्लॉकचेन द्वारा सुरक्षित एप्लिकेशन है, जिसे इस संगठन द्वारा अफीम गम की प्राप्ति, सैंपलिंग और परीक्षण में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया है। इस वर्ष इस एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए, 53,349 किसानों से प्राप्त नमूनों की रिपोर्ट 20 दिनों से भी कम समय में प्रस्तुत की गई।
- शट डाउन के माध्यम से निर्धारित रखरखाव पूरा हो गया है और अफीम चार्जिंग क्षमता बढ़कर 300 एमटी प्रति वर्ष (25 एमटी प्रति माह) हो गई है, जो पिछली क्षमता 150 एमटी प्रति वर्ष से दोगुनी है। यह विस्तार हमारी समग्र उत्पादन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।
- सीपीएस नीति का कार्यान्वयन पीपीपी मॉडल के माध्यम से मेसर्स सनलाइट एल्कलॉइड्स प्राइवेट लिमिटेड, नीमच, मध्य प्रदेश के साथ किया जा रहा है।
- मेसर्स बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात, प्रति वर्ष कम से कम 500 मीट्रिक टन अफीम पोस्ता कैप्सूल के साथ

भूसे को कॉन्सन्ट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ (सीपीएस) विधि के माध्यम से संसाधित करेगा।

- जीओएडब्ल्यू, नीमच ने 17.03.2025 से प्रभावी डब्ल्यूएचओ-जीएमपी प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

4.6.3.2 सीसीएफ संगठन सार्वजनिक सेवाओं के लिए किसी भी योजना को लागू और संचालित नहीं करता है।

4.6.3.3 प्रबंधन द्वारा अनुभाग प्रभारियों के साथ साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से कार्य की नियमित निगरानी की जाती है और दक्षता बढ़ाने के लिए मुख्यालय के साथ नियमित बैठकें की जाती हैं।

4.6.3.4 दिव्यांगजन क्षेत्र और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए की जाने वाली क्रिया कलाप : इस संगठन में विकलांग व्यक्तियों को तैनात किया गया है और उन्हें सभी कल्याणकारी उपाय प्रदान किए जाते हैं। समाज के कमजोर वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शामिल हैं, को सरकारी मानदंडों के अनुसार अवसर और समय पर लाभ दिए जा रहे हैं।

4.6.3.5 जेंडर बजटिंग/महिला सशक्तिकरण: कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और यह सुचारु रूप से काम कर रही है।

4.6.3.6 ई-गवर्नेंस गतिविधियाँ :

- खरीद और निविदा देने का काम ई-टेंडरिंग और जीईएम के माध्यम से किया जा रहा है, केवल उन वस्तुओं को छोड़कर जो अत्यावश्यक हैं और जीईएम पर उपलब्ध नहीं हैं।
- ओसीटीए इस कार्यालय द्वारा की गई एक ई-गवर्नेंस पहल है, जिसमें अपीम गम की प्राप्ति, नमूनाकरण और परीक्षण प्रक्रिया क्यूआर कोड और ब्लॉकचेन आधारित एप्लिकेशन द्वारा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।

4.6.3.7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन: सी.पी.आई.ओ., ए.पी.आई.ओ. और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और वे आर.टी.आई. आवेदन के समय पर निपटान की सुविधा के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

4.6.3.8 दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निर्धारित सभी नियमों और नीतियों का पालन किया जा रहा है। सीसीएफ संगठन किसी भी योजना को संचालित और क्रियान्वित नहीं करता है।

4.7 केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी)

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो आर्थिक आसूचना की एक नोडल एजेंसी है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1985 में इसका गठन आर्थिक आसूचना तथा प्रवर्तन कार्रवाइयों के समन्वय और सुदृढीकरण के लिए किया गया था।

ब्यूरो के अध्यक्ष महानिदेशक हैं जिनकी सहायता दो अपर-महानिदेशक (संयुक्त सचिव के समकक्ष), संयुक्त सचिव (कोफेपोसा), अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक (उप सचिव/निदेशक के समकक्ष), अवर सचिव, उप निदेशक (अवर सचिव के समकक्ष) और अन्य स्टाफ करता है। ब्यूरो में अधिकारियों तथा स्टाफ की स्वीकृत संख्या 116 है।

4.7.2 सीईआईबी के मुख्य कार्य

4.7.2.1 अपने मौजूदा चार्टर के अनुसार सीईआईबी निम्नानुसार कार्य करता है:

- आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) के लिए सचिवालय के रूप में;
- आर्थिक आसूचना कोष (इकोइंट) के समन्वय कार्य के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वयन तथा
- केंद्र सरकार स्तर पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 लागू करता है।

4.7.2.2 अपने पहले जनादेश के हिस्से के रूप में, सीईआईबी निम्नानुसार कार्य करता है:

- आर्थिक अपराधियों और अपराधों पर डेटाबेस का रखरखाव;
- बृहत स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण;

(ग) क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी), कार्य संचालन का पर्यवेक्षण और मॉनीटरिंग जो क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय निकाय हैं जिसमें आर्थिक अपराधों से निपटने वाली केंद्र एवं राज्य के विभिन्न प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं;

(घ) राजस्व विभाग/आरईआईसी की सदस्य एजेंसियों के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

4.7.2.3 राजस्व विभाग (मुख्यालय) द्वारा जारी इसके मौजूदा संशोधित चार्टर तारीख 12.12.2003 के अनुसार सीईआईबी निम्नलिखित कार्य करता है –

- आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) के लिए सचिवालय;
- समन्वित कार्रवाई के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वयन;
- आर्थिक आसूचना के लिए कोष (ईसीओआईएनटी) ;
- केंद्र सरकार के स्तर पर कोफेपोसा अधिनियम, 1974 लागू करने का कार्य;
- एनएससीएस, आईबी तथा आर एंड ए डब्ल्यू के बीच सुरक्षा निहितार्थ वाले आसूचना का त्वरित प्रसार सुनिश्चित करना;
- क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) के कार्यों का समन्वयन करना;
- मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) के साथ समन्वय;
- निर्धारित अंतराल पर राजस्व के सचिव की बैठकें आयोजित करना और प्रत्येक बैठक के बाद ईआईसी के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा
- राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में आर्थिक अपराधों से जुड़े सभी मुद्दों पर 'थिंक टैंक' (विशेषज्ञ समूह) के रूप में कार्य करना तथा बृहत स्तर की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और विश्लेषण करना।

4.7.2.4 राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड (एनईओआर):

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड (एनईओआर) एप्लिकेशन को आर्थिक अपराधों की रोकथाम और शमन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के बीच सूचना साझा करने और बहु-एजेंसी समन्वय को सक्षम करने के लिए एक सुरक्षित वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) में आर्थिक अपराधियों के वास्तविक समय के डेटा साझा करने, पूर्ववर्ती सत्यापन और 360 डिग्री प्रोफाइलिंग को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एप्लिकेशन को बाहरी डेटाबेस से एपीआई-आधारित डेटा निष्कर्षण का लाभ उठाकर उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं के साथ आर्थिक अपराध डेटा के एक व्यापक भंडार में विकसित करने के लिए डिज़ाइन और विकसित

किया गया है, जिससे डेटा पुनर्प्राप्ति को सुव्यवस्थित किया जा सके, मैन्युअल डेटा प्रविष्टि को कम किया जा सके और समग्र सिस्टम दक्षता बढ़ाई जा सके। एलईए के साथ एपीआई एकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वर्तमान में यह कार्य किया जा रहा है।

एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक एलएनडीसी, दिल्ली में एचसीआई अवसंरचना पर उपलब्ध किया गया है, और सॉफ्टवेयर सुरक्षा ऑडिट, डीएनएस पंजीकरण, और पहचानी गई कमजोरियों के निवारण के पूरा होने के बाद एनआईसी-नेट पर इसे एक्सेस किया जा सकता है।

ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, एप्लिकेशन पर एक दिवसीय मास्टर ट्रेनर्स और एडमिनिस्ट्रेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम सीईआईबी में आयोजित किया गया, जिसमें केस मैनेजमेंट, एडवांस्ड सर्च, एनालिटिक्स, एमआईएस और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन जैसे प्रमुख मॉड्यूल शामिल थे। सीबीडीटी, सीबीआईसी, ईडी, सेबी, एसएफआईओ, एनआईए, डीजीएफटी और अन्य सहित कई एलईए के अधिकारियों ने इसमें भाग लिया, जिससे गो-लाइव के लिए परिचालन तत्परता सुनिश्चित हुई।

4.7.2.5 विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (कोफेपोसा) अधिनियम, 1974 का कार्यान्वयन

किसी राष्ट्र की आर्थिक सुस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन और तस्करी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लिंक को इन कार्यों से जुड़े व्यक्तियों को हिरासत में लेकर निष्क्रिय किया जाना आवश्यक है क्योंकि तस्करी, विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी और संबंधित गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार राज्य की सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

पद स्थिति

केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो: दिनांक 14.1.2026 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या

क्रम सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पद संख्या	वर्तमान पदस्थिति	रिक्ति
1	महानिदेशक (ग्रुप-क)	लेवल-15-17	1	1	-
2	संयुक्त सचिव (कोफेपोसा)(ग्रुप-क)	स्तर-14	1	-	1
3	अपर महानिदेशक (ग्रुप-क)	स्तर-14	2	2	-
4	अपर निदेशक/ संयुक्त निदेशक (ग्रुप-क)	लेवल-13/12	5	5	-
5.	निदेशक/उपसचिव (सीएसएस) (ग्रुप-क)	लेवल-13/12	3	3	-
6.	अवर सचिव (ग्रुप-क)	लेवल-11	4	2	2
7.	उप निदेशक (ग्रुप-क)	लेवल-11	8	1*	7 ^{\$}
8.	सीनियर स्टेट ग्रेड- II (ग्रुप-क)	लेवल-09	1	0	1
9.	एसओ (ग्रुप-ख राजपत्रित)	स्तर-8/10	2	2+2=4	-
10.	एसओ (ग्रुप-ख)+ यूडीसी	स्तर-7 और स्तर-6	4+4=8	5	1
11.	सहायक निदेशक (ग्रुप-ख)	स्तर -7	20	17	3
12.	पीएसओ/सीनियर पीपीएस (ग्रुप-क)	लेवल-12	1	-	1
13.	पीपीएस (ग्रुप-क)	लेवल-11	4	2	2
14.	पीएस(ग्रुप-ख राजपत्रित)	स्तर-8/10	6	2	4
15.	स्टेनो ग्रेड-सी (ग्रुप-ख)	स्तर -7	4	1	3
16.	स्टेनो ग्रेड-डी (ग्रुप-ग)	स्तर -6	3	0	3
17.	अन्वेषक(समूह-ग)	स्तर -6	2	0	2

इस खतरे से निपटने के लिए, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा अधिनियम, 1974) को अधिनियमित किया गया है, ताकि तस्करो और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों को इन पूर्वाग्रही गतिविधियों में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून का प्रावधान किया जा सके।

राजस्व विभाग के कोफेपोसा विंग को कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के प्रभावी कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। यह विंग केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य कर रहा है।

वर्ष 2025-26 के दौरान, कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत 29 व्यक्तियों (दिनांक 01.04.2025 से 30.11.2025 तक) के विरुद्ध निवारक निरोधादेश पारित किए गए, जबकि दिनांक 30.11.2025 से पहले 19 निरोधादेश (पिछले वर्षों के आदेशों सहित) को निष्पादित किया गया। इसके अलावा, कोफेपोसा अधिनियम, 1974 के तहत गठित विभिन्न सलाहकार बोर्डों द्वारा 03 निरोधादेश की पुष्टि की गई।

4.7.2.6 सीईआईबी में प्रशासन

प्रशासन स्कंध कार्मिक और कार्यालय/सामान्य प्रशासन, बजट अनुमान (बीई)/संशोधन अनुमान (आरई) की तैयारी, आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन, सार्वजनिक शिकायतों के निवारण आदि के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन स्कंध (विंग) का नेतृत्व अपर महानिदेशक (प्रशासन) करते हैं जिनकी सहायता एक अपर निदेशक और दो अवर सचिव द्वारा की जाती है। अपर महानिदेशक (प्रशासन), ब्यूरो के मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और महानिदेशक, सीईआईबी के निर्देशन और मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्यूरो में अधिकारियों/ कर्मचारियों की स्वीकृत कार्यबल और मौजूदा पद स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

क्रम सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पद संख्या	वर्तमान पदस्थिति	रिक्ति
18.	अवर श्रेणी लिपिक (ग्रुप-ग)	लेवल 2	6	0	6
19.	स्टाफ कार चालक (ग्रुप-ग)	स्तर-4	5	0	5
20.	एमटीएस (ग्रुप-ग)	स्तर-3	30	09	21
कुल:-			116	54	62

\$डीडी के 6 पदों को समाप्त कर दिया गया है।

*एक डीडी को डीओआर/सीबीआईसी द्वारा ऋण के आधार पर तैनात किया गया है।

4.7.3 वर्ष 2025-26 के दौरान सीईआईबी की उपलब्धियाँ

4.7.3.1 सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल

आज तक 28803 मामलों को संसाधित किया गया है और एनईओआर डेटाबेस में दर्ज किया गया है। साथ ही, सूचना साझाकरण प्रोटोकॉल के तहत बहु-एजेंसी निहितार्थ वाले 7937 मामलों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया गया है।

4.7.3.2 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषद (आरईआईसी)

सीईआईबी 30 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों (आरईआईसी) के लिए समन्वय एजेंसी है, जो विभिन्न राज्यों में स्थापित हैं। प्रत्येक आरईआईसी हर वित्तीय वर्ष में द्वि-मासिक बैठकें आयोजित करता है। आरईआईसी के नामित सदस्य विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो राजस्व-आधारित अपराधों जैसे डीआरआई, ईडी, डीजीजीआई, ईओडब्ल्यू, सीबीआई, आयकर, लोकायुक्त, सेबी, राज्य विकास प्राधिकरण आदि पर कार्रवाई करते हैं। एलईए के लिए राजस्व-आधारित अपराधों को साझा करने के लिए, आरईआईसी एक महत्वपूर्ण मंच है, जिनमें अंतर-एजेंसी निहितार्थ होते हैं।

अप्रैल, 2025 से अब तक 62 आरईआईसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें आरईआईसी संरचना और संचालन को और सुदृढ़ करने के लिए सीईआईबी के अधिकारियों ने भी भाग लिया। साथ ही, आरईआईसी बैठकों में एफआईयू-आईएनडी, टेलीकॉम अथॉरिटी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसे विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया।

जून, 2025 में, एक अखिल भारतीय आरईआईसी ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई जिसमें 30 आरईआईसी के 200 से अधिक अधिकारियों ने आरईआईसी संचालन और एनईओआर एप्लीकेशन पर चर्चा करने के लिए भाग लिया। इसके अलावा, नवंबर, 2025 में, एनईओआर में आरईआईसी मॉड्यूल का व्यावहारिक प्रशिक्षण सीईआईबी में आयोजित किया गया, जिसमें 30 आरईआईसी के अधिकारियों और कार्मिकों ने प्रस्तुति और प्रशिक्षण के लिए सीईआईबी का दौरा किया।

4.7.3.3 प्रशिक्षण और विकास

सीईआईबी अध्ययन, विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आयोजित करता है। कुल 10 पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। ये पाठ्यक्रम विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली; राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर; राष्ट्रीय आसूचना अकादमी, नई दिल्ली; भारतीय सेना, पुणे; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिविलियन मार्केट्स, नवी मुंबई; स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ़ कंज्यूमर बैंकिंग, हैदराबाद; मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशिक्षण अकादमी गुडगांव के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं। सीईआईबी ने परिवीक्षा अधीन सहायक अनुभाग अधिकारियों के लिए नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी सुविधा प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, एनसीएफएल द्वारा, नई दिल्ली में "इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर" (आई4सी) द्वारा 'डिजिटल इन्वेस्टिगेशन एंड साइबर फोरेंसिक्स' में बेसिक इंटेसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम पर एक नया पाठ्यक्रम वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान शुरू किया गया है। कुल 10 बैच आयोजित किए गए हैं।

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 200 अधिकारियों को नामांकित किया गया है।

4.7.3.4 आर.ई.आई.सी. द्वारा तैयार किए गए अध्ययन रिपोर्टों के संकलन पर पुस्तक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर.ई.आई.सी. की अध्ययन रिपोर्टों का संकलन करने वाली पुस्तक तैयार की गई।

4.7.3.5 वैश्विक प्रवेश कार्यक्रम (जी.ई.पी.)

सीईआईबी को वित्त मंत्रालय के अधीन नोडल एजेंसी के रूप में जीईपी आवेदनों को मंजूरी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) कार्यक्रम है, जो अमेरिकी हवाई अड्डों पर कम जोखिम वाले यात्रियों के लिए त्वरित निकासी की सुविधा प्रदान करता है। सीईआईबी इन भाग लेने वाली एजेंसियों से प्रतिक्रिया/इनपुट प्राप्त करने के लिए नौ कानून प्रवर्तन एजेंसियों, अर्थात् ईडी, डीआरआई, एनआईए, सेबी, डीजीजीएसटीआई, एसएफआईओ, सीबीडीटी, सीबीआई और एनसीबी के साथ समन्वय करता है। सीईआईबी अपने स्वयं के डेटाबेस से प्रत्येक आवेदक के लिए पूर्ववर्ती जांच भी करता है। वित्त वर्ष 2025-26

(30.01.2026 तक) के दौरान, कुल 11,381 जीईपी आवेदनों को संसाधित किया गया।

4.8 राज्य कर

जीएसटी संग्रह में जीएसटी के लागू होने के बाद साल-दर-साल वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर, 2025 तक) **15.64 लाख करोड़ रुपये** के कुल सकल जीएसटी संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि के संग्रह से 7.39% अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 (नवंबर, 2025 तक) के लिए औसत मासिक सकल संग्रह **1.96 लाख करोड़ रुपये** है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में एकत्र **1.82 लाख करोड़ रुपये** से अधिक है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए नवंबर, 2025 तक रिफंड का जीएसटी राजस्व निवल **13.64 लाख करोड़ रुपये** है, जिसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.66% की वृद्धि है। कुल मिलाकर, जीएसटी राजस्व के आंकड़े, निरंतर विकास गति और सकारात्मक प्रदर्शन दर्शाते हैं।

इसके अलावा, 03 सितंबर 2025 को आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में की गई सिफारिशों के अनुसार, तंबाकू उत्पादों के अलावा अन्य वस्तुओं पर उपकर 22 सितंबर, 2025 से बंद कर दिया गया है। निर्दिष्ट वस्तुओं, अर्थात् पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू उत्पाद जैसे जर्दा, अप्रसंस्कृत तंबाकू और बीड़ी पर उपकर लागू रहेगा और क्षतिपूर्ति उपकर के कारण संपूर्ण ऋण और ब्याज देनदारियों के निर्वहन के आधार पर नई दरों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

4.9 कर नीति अनुसंधान एकक (टीपीआरयू)

4.9.1 परिचय

कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) ने अपनी पहली रिपोर्ट में कर नीति और संबंधित कानूनों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया है जिसमें संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि कर नीति का काम दो बोर्डों, यथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के द्वारा अलग-अलग किया जा रहा है। इस काम उनके अपने संबंधित कर अनुसंधान एकक (टीआरयू) और कर नीति और विधान (टीपीएल) विंग के माध्यम से देखा जा रहा था। परिणामस्वरूप, नीतिगत प्रस्ताव वित्त मंत्री तक अलग-अलग चैनलों के माध्यम से पहुंचे। इस खंडित प्रणाली से कर नीति निर्माण में स्थिरता, सुसंगतता और बहु-विषयक इनपुट के उपयोग में कमी आ गई।

कर नीति और अनुसंधान एकक (टीपीआरयू) की स्थापना टीएआरसी की सिफारिशों के आधार पर, की गई थी। इसका उद्देश्य कर नीति निर्माण में अधिक समन्वय, विश्लेषणात्मक शक्ति और स्थिरता लाना था। इस एकक में कर प्रशासक, अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद, कर कानून विशेषज्ञ, परिचालन अनुसंधान पेशेवर और सामाजिक शोधकर्ता जैसे विशेषज्ञ शामिल हैं।

टीपीआरयू माननीय वित्त मंत्री, राजस्व सचिव और दोनों बोर्डों की सहायता करने वाले एक अनुसंधान और सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है।

टीपीआरयू राजस्व विभाग के अंतर्गत काम करता है और वर्तमान में इसका नेतृत्व एएस (राजस्व) के पास है। इसका कार्य विश्लेषण का होता जोकि बहुत कठिन कार्य साथ ही यह रणनीतिक नीति पत्र तैयार करता है। आईआरएस, आईईएस और आईएसएस के अधिकारियों के साथ-साथ फील्ड अधिकारियों और रिसर्च फेलो को एक साथ लाकर, यह एकक सीबीडीटी और सीबीआईसी के बीच संस्थागत अंतराल को भरती है। यह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कर परिप्रेक्ष्य को संरेखित करने के लिए राज्य वाणिज्यिक कर विभागों के साथ मिलकर काम करता है।

इतने सारे वर्षों में, टीपीआरयू ने कुछ प्रमुख अध्ययन पूरे किए हैं जिसमें प्रमुख नीतिगत और विधायी सुधारों के बारे में बताया गया है। टीडीएस सरलीकरण पर इसके कार्य में एक भूगतान आधारित प्रणाली पर विचार किया गया है जिसके तीन स्लैब रेट्स होंगे। जिसमें माइक्रोसिमुलेशन मॉडलिंग का उपयोग किया जाएगा। ट्रांसफर प्राइसिंग लिटिगेशन और वैश्विक पद्धतियों पर किए गए इसके विश्लेषण का 2024-25 के सुधारों पर प्रभाव पड़ा है जिसमें विस्तारित सुरक्षित बंदरगाह नियम और ब्लॉक आकलन भी शामिल है। विवादों के समाधान में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए टीपीआरयू ने एक लिटिगेशन मैनेजमेंट संरचना तैयार की है। जिसमें कॉल बुक तंत्र और संरचित अपील वर्गीकरण की व्यवस्था है।

4.9.2 अघिदेश और उद्देश्य

उद्देश्य

टीपीआरयू और सीबीडीटी और सीबीआईसी द्वारा संदर्भित राजकोषीय और कर नीति के मुद्दों का गहन अध्ययन करता है इस पर अपना स्वतंत्र विश्लेषण प्रदान करता है। यह उभरती कर नीति की चुनौतियों पर नीति पत्र, पृष्ठभूमि नोट्स और तुलनात्मक अध्ययन तैयार और प्रसारित करता है। यह एकक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली कर नीति परिषद को सूचित और दूरदेशी कर नीति निर्माण में सहायता करता है, और अंतर-सरकारी संरेखण की आवश्यकता वाले मुद्दों पर राज्य वाणिज्यिक कर विभागों के साथ समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

अतिरिक्त जिम्मेदारियां

टीपीआरयू भारत के बिजनेस रेडी (बी-रेडी)/ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) प्रयासों के बीच का समन्वय का काम करता है, जिसमें डीपीआईआईटी, सीबीडीटी, सीबीआईसी और विश्व बैंक के साथ सम्पर्क भी शामिल है, और विश्लेषण और आउटरीच के माध्यम से कर-संबंधित ईओडीवी सुधारों का में सहायता भी करता है। यह आईजीएसटी निपटान समिति और मंत्रियों के मुआवजा उपकर समूह (जीओएम) के सचिवालय के

रूप में भी कार्य करता है। यह एकक परियोजना प्रबंधन, समीक्षक समन्वय और बहु-हितधारक जुड़ाव के माध्यम से भारत की एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया में भी सहायता करता है। इसके अलावा, टीपीआरयू उन्नत कर राजस्व पूर्वानुमान और नाउकास्टिंग टूल विकसित करता है, जिसमें जीएसटी के लिए एक उच्च सटीकता डायनेमिक फैक्टर मॉडल भी आते हैं।

4.9.3. प्रमुख कार्यधाराएँ (वर्क स्ट्रीम)

4.9.3.1 माल और सेवा कर (जीएसटी)

टीपीआरयू जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने, जीएसटी नेक्स्ट-जेनरेशन सुधारों के तहत इन्वर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर और जोखिम-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से अधिक व्यापार-अनुकूल ई-वे बिल प्रणाली के डिजाइन पर विश्लेषणात्मक कार्य करता है। इसके अध्ययनों में अवरुद्ध क्रेडिट और वैट श्रृंखला पर उनका प्रभाव, संरचना और रिवर्स चार्ज तंत्र जैसे विशेष वितरण और एमएसएमई और स्टार्ट-अप पर जीएसटी 2.0 के निहितार्थ शामिल हैं। एकक केंद्र-राज्य राजस्व संतुलन का आकलन करने, क्षेत्रवार अनुपालन और राजस्व रिपोर्ट तैयार करने और जीएसटी मुआवजे और राज्य राजस्व रुझानों का मूल्यांकन करने के लिए जीएसटी इक्विटी डैशबोर्ड विकसित करने का विचार कर रहा है।

4.9.3.2 प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों में काम करने में कॉर्पोरेट कर मॉडल का मूल्यांकन, लाभ स्थानान्तरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था कराधान का विश्लेषण और डीईए-डीपीआईआईटी टास्क फोर्स के तहत विदेशी निवेश पर डीटीए का प्रभाव मूल्यांकन शामिल है। यह एकक नीति आयोग के समन्वय में कर प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की पड़ताल करती है, आयकर विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जांच करती है, और भारतीय कर कानूनों के अर्थमितीय विश्लेषण पर यूएनयू-वाइडर के साथ सहयोग करती है। यह सहभागी बजट पर पहल का भी समर्थन करता है और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण और सीमा शुल्क मूल्यांकन के लिए एक अभिसरण ढांचा विकसित करता है।

4.9.3.3 सीमा शुल्क और व्यापार

टीपीआरयू औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता का सहायता करने के लिए टैरिफ संरचनाओं का विश्लेषण करता है, सीमा शुल्क और व्यापार नीतियों को संरेखित करता है, और कर के दृष्टिकोण से उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं का मूल्यांकन भी करता है।

4.9.3.4 उभरते क्षेत्र

कार्य के उभरते क्षेत्रों में हरित कराधान और कार्बन मूल्य निर्धारण, कानूनी विश्लेषण, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों सहित डिजिटल और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था का कराधान, और कर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी-सक्षम

उपकरण जैसे एआई/एमएल-आधारित अनुपालन समर्थन और जोखिम इंजन शामिल हैं।

4.9.4 वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए कार्य

वर्ष 2025-26 के दौरान, कर नीति और अनुसंधान एकक (टीपीआरयू) ने साक्ष्य-आधारित कर नीति निर्माण को मजबूत करने, अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बढ़ाने और कराधान और नियामक सुधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव में सहायता करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। इस वर्ष ने टीपीआरयू के विश्लेषणात्मक, समन्वय और आउटरीच कार्यों का एक महत्वपूर्ण विस्तार किया गया है, विशेष रूप से वैश्विक बैंचमार्किंग प्रेक्टिस सुधारों और संस्थागत क्षमता निर्माण के संदर्भ में।

इस वर्ष के दौरान एक प्रमुख फोकस रहा है- क्षेत्र विश्व बैंक के बिजनेस रेडी (बी-रेडी) प्रेक्टिस के साथ भारत की भागीदारी पर। टीपीआरयू ने बी-रेडी ढांचे के तहत विशेष रूप से कराधान से संबंधित संकेतकों पर भारत की स्थिति के समन्वय और इसे आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। डीपीआईआईटी के सचिव की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समिति में एकक के योगदान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। पूरे वर्ष के दौरान, टीपीआरयू ने सीबीआईसी, सीबीडीटी, जीएसटीएन, श्रम और रोजगार मंत्रालय और डीपीआईआईटी सहित प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के साथ नियमित रूप से संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठकें आयोजित कीं, जिससे की संस्थानों में लगातार संरेखण सुनिश्चित किया जा सके और तकनीकी और नीतिगत मुद्दों का समय पर समाधान किया जा सके।

स्वदेश समन्वय के अलावा, टीपीआरयू ने अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेने के लिए सिंगापुर, हांगकांग और न्यूजीलैंड के साथ सरकार-से-सरकार विचार-विमर्श की सुविधा प्रदान की। विशेष रूप से, यूनिट ने न्यूजीलैंड में एक बहु-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल की शुरुआत की और समन्वय किया, जो 2024 में जारी पहली बी-रेडी रिपोर्ट में सभी क्षेत्रों में सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में उभरा। टीपीआरयू ने विश्व बैंक मुख्यालय में एक बहु-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल में भी भाग लिया, जहां बी-रेडी कार्यप्रणाली, संकेतक और डेटा सत्यापन प्रक्रियाओं के कराधान से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

जैसा कि अभ्यास के तहत अनिवार्य है बी-रेडी के तहत तकनीकी कार्य को पूरा करते हुए, टीपीआरयू ने एक व्यापक धारणा प्रबंधन और आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम वर्ष के दौरान 20 शहरों में लागू किया गया था और इसमें कर पेशेवरों, उद्योग प्रतिनिधियों और उद्योग संघों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संरचित सम्पर्क शामिल था। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की धारणाओं को समझना, कार्यान्वयन की बाधाओं की पहचान करना और कराधान में व्यापार करने में आसानी पर

वैश्विक बेंचमार्क के साथ प्रशासनिक प्रथाओं को संरेखित करना था। इसके साथ-साथ में, टीपीआरयू ने देश भर में सीबीडीटी और सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ सक्रिय आउटरीच सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में सीमा शुल्क, जीएसटी और आयकर कार्यालयों के अधिकारियों को बी-रेडी ढांचे के प्रति संवेदनशील बनाने और राजस्व अखंडता से समझौता किए बिना करदाताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के व्यापक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान के मोर्चे पर, टीपीआरयू यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रिसर्च (यूएनयू-वाइडर), हेलसिंकी के साथ संलग्न है। सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए श्रृंखलाबद्ध ऑनलाइन बैठकों की आयोजन की गई, जिसमें अनुप्रयुक्त कर नीति अनुसंधान, असमानता, विकास वित्त और नीति मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक डेटा का उपयोग शामिल है। इन कार्यक्रमों से भविष्य की संयुक्त अनुसंधान पहलों के लिए आधार तैयार होने की उम्मीद है।

इस वर्ष के दौरान, टीपीआरयू ने दोहरे कराधान से बचाव समझौतों (डीटीएए) के प्रभाव विश्लेषण में अपनी भागीदारी के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय कराधान की नीति के विश्लेषण में भी योगदान दिया। एकक ने विदेशी निवेश प्रवाह पर डीईए-डीपीआईआईटी टास्क फोर्स के तत्वावधान में किए गए एक अध्ययन के हिस्से के रूप में विश्लेषणात्मक इनपुट तैयार किया, जिसमें डीईए-डीपीआईआईटी टास्क फोर्स के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस काम में संधि संरचनाओं, निवेश पैटर्न और उभरते अंतरराष्ट्रीय कर मानदंडों की जांच करना शामिल था, ताकि भविष्य की संधि वार्ता और कर नीति डिजाइन को सूचित किया जा सके।

अप्रत्यक्ष कराधान और जीएसटी सुधारों में इस एकक का काम इसकी गतिविधियों का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। टीपीआरयू ने जीएसटी अनुपालन में सुधार और संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कई विश्लेषणात्मक अध्ययन किए हैं। ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या पुनर्प्राप्ति (ओआईडीएआर) सेवाओं पर अनुसंधान और सेवाओं के आयात के परिणामस्वरूप परिभाषात्मक स्पष्टता के लिए सिफारिशों की गईं और आयकर डेटा के साथ प्रेषण रिपोर्टिंग को एकीकृत किया गया, जिससे राजस्व आश्वासन को मजबूत किया गया। बी2सी लेनदेन में लगातार अंतराल को दूर करने के लिए टीपीआरयू ने ई-चालान के विस्तारित उपयोग का विचार रखा है और यूपीआई जैसे भुगतान प्लेटफार्मों को जीएसटी रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप कार्य करने की सिफारिश की है।

जीएसटी पूर्वानुमान और संस्थागत समर्थन के संदर्भ में, टीपीआरयू ने उच्च-आवृत्ति संकेतकों को शामिल करते हुए डायनेमिक फैक्टर मॉडल का उपयोग करके अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखा। समानांतर में, एकक ने राजस्व अनुमानों की सटीकता और समयबद्धता में सुधार के लिए मशीन-लर्निंग-आधारित पूर्वानुमान विधियों के विकास को उन्नत किया।

टीपीआरयू ने आईजीएसटी निपटान समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य किया, जो सूचित निर्णय लेने की सुविधा के लिए विश्लेषणात्मक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है।

अपनाए गए अन्य कार्य

ऊपर उल्लिखित प्रमुख पहलों के अलावा, टीपीआरयू ने पूरे वर्ष मंत्रालय को लगातार विश्लेषणात्मक और सलाहकार सहायता देता रहा है। इसमें नीति नोट्स और अवधारणा पत्र तैयार करना, बजट चक्र के दौरान विश्लेषणात्मक समर्थन, अनुसंधान अध्ययन और क्षेत्र-विशिष्ट कराधान आकलन और अंतर-मंत्रालयी समूहों और समितियों के लिए ब्रीफिंग नोट्स शामिल हैं। यूनिट ने डेटा डैशबोर्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट भी विकसित किया है, उभरते कर मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया नोट तैयार किए, और अंतरराष्ट्रीय तुलना और सर्वोत्तम अभ्यास समीक्षा की। सामूहिक रूप से, इन गतिविधियों ने सूचित निर्णय लेने का समर्थन किया, नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यान्वयन के बीच समन्वय को मजबूत किया, और राजस्व विभाग के भीतर एक केंद्रीय ज्ञान और विश्लेषणात्मक केंद्र के रूप में टीपीआरयू की भूमिका को मजबूत किया।

भावी योजनाएं

टीपीआरयू कर नीति पर स्पष्ट और साक्ष्य-आधारित सलाह के साथ सरकार का समर्थन करना जारी रखेगा। यह केंद्रीय बजट में कर प्रस्तावों की गुणवत्ता में सुधार करने और जीएसटी परिषद को डेटा-आधारित इनपुट प्रदान करने में मदद करेगा। यह एकक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्राधिकरणों के बीच समन्वय को बेहतर बनाने के लिए भी काम करेगी। अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम करने और यह सुनिश्चित करने पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा कि कर नीतियां नई तकनीकों और वैश्विक रीतियों के साथ तालमेल बिठाती रहें।

जीएसटी नेक्स्ट-जेनरेशन रिफॉर्म्स के तहत, टीपीआरयू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान करेगा और जोखिम-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों का उपयोग करके एक सरल और अधिक व्यापार-अनुकूल ई-वे बिल प्रणाली की दिशा में काम करेगा। यह अवरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव का अध्ययन करेगा और कंपोजिशन स्कीम जैसी विशेष योजनाओं की समीक्षा करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे में निष्पक्षता को ट्रैक करने के लिए एक नया जीएसटी इक्विटी डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा।

टीपीआरयू जीएसटी के अगले चरण का भी अध्ययन करेगा, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और स्टार्ट-अप पर इसके प्रभाव। इसके अलावा, यह कॉर्पोरेट कर नियमों, अंतराष्ट्रीय कर प्रथाओं और कर संधियों की समीक्षा करेगा। यह एकक नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देगी और पारदर्शी और सहभागी बजट में मदद करेगा।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, वर्ष 2025-26 के दौरान किए गए कार्य राजस्व विभाग के भीतर एक केंद्रीय विश्लेषणात्मक और समन्वय केंद्र के रूप में

टीपीआरयू के निरंतर विकास को दर्शाते हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव, ठोस अनुभवजन्य विश्लेषण और नीति एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सक्रिय समर्थन प्रदान करके, इस एकक ने भारत के कर नीति ढांचे की विश्वसनीयता, सुसंगति और प्रभावशीलता को मजबूत करने में योगदान दिया है। आगे चलकर, टीपीआरयू का ध्यान अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, तकनीकी एकीकरण और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण पर केंद्रित होगा, जिससे विकास को समर्थन देने, अनुपालन में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका और भी बढ़ेगी कि भारत की कर प्रणाली कुशल, न्यायसंगत और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनी रहे।

4.10 सक्षम प्राधिकरण

4.10.1 एसएफईएमए (सफेमा) के तहत अपीलीय अधिकरण

4.10.1.1 यह अपीलीय अधिकरण तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा) के तहत गठित किया गया है। यह 03.01.1977 से कार्य कर रहा है। यह सफेमा/एनडीपीएस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी, पीएमएलए, फेमा और बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दायर अपीलों की भी सुनवाई करता है।

4.10.1.2 अपीलीय अधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। इसमें एक अध्यक्ष (जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या रहे हैं अथवा किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं) और चार सदस्य होते हैं। इन चार सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के उन अधिकारियों में से की जाती है जिन्होंने भारत सरकार के अपर सचिव या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद धारण किया है और तीन वर्षों के लिए न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा न्यायनिर्णयन का कार्य किया है।

4.10.1.3 उपर्युक्त अधिनियमों के तहत अध्यक्ष द्वारा गठित न्याय पीठों के द्वारा अपील और संबद्ध याचिकाओं का निपटान किया गया है। दिनांक **01.04.2025 से 30.11.2025** की अवधि के दौरान, कुल **2861 अपील** (पीएमएलए में 1702, एनडीपीएसए में 288, सफेमा में शून्य, फेमा में 68 और पीबीपीटी में 803) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त की गई। कुल **2642 अपीलों** (पीएमएलए में 1712, एनडीपीएसए में 118, सफेमा में 05, फेमा में 152 और पीबीपीटी में 655) का निपटान उक्त अवधि के दौरान किया गया। अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सबसे पुरानी याचिकाएँ वर्ष 1986, 1991 आदि की थीं। हालाँकि, उचित न्यायनिर्णयन और रोस्टर एवं पीठों के परिवर्तन के साथ, 2012 तक दायर सभी अपीलों का निपटारा कर दिया गया, सिवाय उन अपीलों के जिनमें कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है या उच्च मंचों द्वारा निर्देशों के साथ वापस भेज दी गई है, जिससे अपील की औसत आयु में भारी कमी आई है। वर्तमान वर्ष में अपीलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण की स्थापना के बाद से अब तक सबसे अधिक रहा है।

4.10.1.4 इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ताओं एवं प्रतिवादियों को अधिक सरलता एवं लचीलापन प्रदान करने के लिए ई-फाइलिंग की सुविधा शुरू की गई है।

4.10.2 सफेमा/एनडीपीएसए के तहत सक्षम प्राधिकरण

4.10.2.1 तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा (एफओपीए) में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1974 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियों के समपहरण के लिए प्रावधान किया गया है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) में, इसी अधिनियम के अंतर्गत या किसी दूसरे देश के किसी समनुरूपी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988, जम्मू एवं कश्मीर स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अवैध व्यापार के लिए नजरबंद व्यक्तियों की गैर कानूनी रूप से अभिग्रहीत सम्पत्ति का पता लगाने, खरीद अथवा नष्ट करने पर रोक लगाने, जब्ती और समपहरण के लिए प्रावधान है।

4.10.2.2 गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण का कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति हेतु सफेमा (एफ ओ पी) अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम में प्रावधान है। वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुम्बई में स्थित है और एक यूनिट अहमदाबाद में है। सफेमा (एफओपी) अधिनियम में तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति का समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति अपीलों को सुनने के लिए एक अपीलीय फोरम, नामतः अपील न्यायाधिकरण की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

4.10.2.3 बेनामी संपत्ति लेन-देन निषेध अधिनियम, 1988 में वित्त अधिनियम, 2021 के नवीनतम संशोधनों के अनुसार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी पीबीपीटी अधिनियम, 1988 द्वारा या उसके तहत प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी हैं। पीबीपीटी अधिनियम बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था, जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून के प्रावधानों को निष्फल करने के लिए या वैधानिक बकाया के भुगतान से बचने के लिए या लेनदारों, लाभकारी मालिकों, बेनामीदार और किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने से बचने के लिए बेनामी लेनदेन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है, वह उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।

4.10.2.4 सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त की गई रिपोर्टों की संख्या, जारी किए गए कारण बताओ नोटिस की संख्या और उसमें शामिल संपत्ति का मूल्य, जब्ती के आदेशों की संख्या और उसमें शामिल संपत्ति के मूल्य के बारे में विवरण और वर्ष 2000-01 से 2025-26 [30.11.2025 तक] निस्तारित की गई संपत्ति की बिक्री आय मूल्य नीचे दिया गया है:-

एनडीपीएसए और सफेमा (एफओपी) के तहत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती

वित्तीय वर्ष	प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	जब्ती के लिए जारी किए गए नोटिसों की संख्या और इसमें शामिल संपत्ति का मूल्य		जारी किए गए जब्ती आदेशों की संख्या और इसमें शामिल संपत्ति का मूल्य		निपटवाई गई संपत्ति की बिक्री आय का मूल्य (लाख रुपए में)
		संख्या	मूल्य (लाख रुपए में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपए में)	
1	2	3	4	5	6	7
2000-2001	491	159	2755	103	1662	201
2001-2002	228	89	7223.12	50	3202.39	107
2002-2003	995	72	1269.22	53	2498.60	18
2003-2004	1180	97	1547.75	25	977.01	51.6
2004-2005	1357	162	3251.64	25	650.93	73.67
2005-2006	607	214	10074.59	91	744.60	153.27
2006-2007	514	243	3017.27	112	868.57	2.63
2007-2008	507	210	12784.31	24	551.10	366.97
2008-2009	99	39	2065.88	28	1115.33	121.30
2009-2010	48	21	178.5	20	2153.20	शून्य
2010-2011	128	19	1394.06	22	45.57	1123.49
2011-2012	112	17	690.85	22	391.58	191.27
2012-2013	40	13	3091.48	10	101.10	रु.1294.28 लाख यूएस \$3400
2013-2014	61	5	73.55	3	118.73	608.37
2014-2015	54	24	643.908	18	3253.55	166
2015-2016	92	22	1553.81	12	308.93	11.52
2016-2017	45	22	1232.95	19	2.35	778.44 और \$443783.19
2017-2018	40	7	77.92	3	39.47	1641.45
2018-2019	104	28	1243.69	4	94.26	918.93
2019-2020	105	36	7417.96	52	15,606.82	371.89
2020-2021	38	17	3549.17815	1	22500.00	3.70
2021-2022	50	2	25.66	4	42.58	536.7
2022-2023	36	22	1303.24	21	1170.99	554.21
2023-2024	70	20	550.13	13	975.59	937.95
2024-2025	350	36	3112.46	13	405.32	541.15
2025-2026 (01.04.2025– 30.11.2025)	280	70	1778.19	7	259.57	1084.35

4.11 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी)

4.11.1 संगठन के कार्य/कार्यप्रणाली

4.11.1.1 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण जिसे पहले सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण के रूप में जाना जाता था, एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई करता है। सेवा कर अपील अब वित्त अधिनियम, 1994 के तहत भी अधिकरण के समक्ष दायर की जाती हैं। अधिकरण के पास सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत एंटी-डंपिंग मामलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और इसकी सुनवाई राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली विशेष न्यायपीठ द्वारा की जाती है। सी.ई.एस.टी.ए.टी. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत भी अपीलों सुनता है।

4.11.1.2 न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ दिल्ली में स्थित है और क्षेत्रीय पीठ मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, इलाहाबाद और हैदराबाद में स्थित हैं। न्यायाधिकरण की प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है।

4.11.1.3 न्यायाधिकरण के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। सदस्यों (न्यायिक) के 16 पद और सदस्यों (तकनीकी)

वर्ष	संस्थानों	निपटान	दिनांक 30.11.2025 तक कुल लंबित मामले
अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक	9578	10842	70850

4.11.3 विभाग ने अपील की ऑनलाइन फाइलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें प्रतिवादी और करदाताओं के लिए उनके खिलाफ दायर की गई अपीलों की स्थिति देखने के लिए एक अलग डैशबोर्ड जोड़ा गया है। प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सभी जानकारी ट्रिब्यूनल की वेबसाइट पर सक्रिय रूप से अपलोड की जाती है। ट्रिब्यूनल के दैनिक आदेशों सहित सभी आदेश भी अपलोड किए जाते हैं, इसके अलावा बेंच द्वारा लिए गए आइटम नंबर का वास्तविक समय प्रदर्शन भी वेबसाइट और ट्रिब्यूनल परिसर में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड दोनों पर उपलब्ध है। करदाताओं द्वारा अपील की ऑनलाइन फाइलिंग भी 15.11.2025 से शुरू हो गई है। वर्ष 2026 के मध्य तक ट्रिब्यूनल ई-कोर्ट की स्थापना के साथ कागजरहित बनने के लिए तैयार है। ट्रिब्यूनल की सभी बेंचों में नियमित रूप से वर्चुअल सुनवाई भी हो रही है।

4.11.4 पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र कोलकाता पीठ के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि, पूर्वोत्तर क्षेत्र से अप्रत्यक्ष कर मुकदमेबाजी अपेक्षाकृत कम है।

4.11.5 दिव्यांगों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कमजोर वर्गों के संबंध में सरकार द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाओं का सख्ती से पालन किया जाता है और पात्र अभ्यर्थियों/कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

के 16 पद हैं। वर्तमान में सदस्यों के सभी 32 पद भरे हुए हैं।

4.11.1.4 किसी न्यायपीठ में सदस्यों के बीच मतभेद का समाधान तीसरे सदस्य को नामित करके और बहुमत के निर्णय से किया जाता है। जब भी अधिकरण की समन्वय न्यायपीठ द्वारा किसी एक मुद्दे पर भिन्न निर्णय पारित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा गठित बड़ी न्यायपीठ द्वारा मुद्दे का समाधान किया जाता है तथा बड़ी न्यायपीठ द्वारा लिया गया निर्णय सभी खंडपीठों तथा अधीनस्थ अधिकरणों पर लागू होता है।

4.11.1.5 छोटे मामलों जिनकी वित्तीय स्थिति 50,00,000/- (पचास लाख रुपये) तक होती है, जिसमें शुल्क की दर या मूल्यांकन का कोई प्रश्न शामिल नहीं है, के शीघ्र निपटान के लिए एकल सदस्यीय पीठ का गठन किया जाता है। अधिकरण आयुक्त (अपील) के आदेशों से अपीलों की सुनवाई करने वाला अंतिम अपीलीय प्राधिकारी भी है। वर्गीकरण और मूल्यांकन के मुद्दों पर अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती हैं क्योंकि इनका प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर होता है।

4.11.2 वर्ष के दौरान निष्पादन और उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं

अधीनस्थ कर्मचारियों की कई रक्तियों सहित विभिन्न बाधाओं के बावजूद, अपीलों का निपटान निरंतर शीघ्र गति से किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में संस्थानों और अपीलों के निपटान को दर्शाने वाला एक नमूना विवरण नीचे दिया गया है:

4.11.6 इस न्यायाधिकरण की महिला कर्मचारियों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/07/2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/4/2009-स्था.(एल) के अनुसार सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए, माननीय रचना गुप्ता, सदस्य (जे), सीईएसटीएटी की अध्यक्षता में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। अभी तक समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

4.11.7 जनवरी 2017 में शुरू की गई न्यायाधिकरण की गतिशील वेबसाइट को इसकी भेद्यता के कारण बंद कर दिया गया है। एनआईसी द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं का उपयोग करते हुए एक नई वेबसाइट विकसित की गई है जो मुकदमेबाज जनता की बढ़ती जरूरतों को पूरा कर रही है। वाद सूची साप्ताहिक आधार पर अपलोड की जाती है और दैनिक आदेश दैनिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं। सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद अंतिम आदेश अपलोड कर दिए जाते हैं। न्यायाधिकरण से संबंधित सभी जानकारी डीओपीटी के दिनांक 15/04/2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/6/2011 के अनुसार उपलब्ध है। एनआईसी द्वारा निर्धारित द्वारा ऑनलाइन अपील दाखिल करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

4.11.8 न्यायाधिकरण एफआरबीएम अधिनियम (वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का

प्रयास कर रहा है। सभी व्यय न्यायाधिकरण के लिए आबंटित बजट तक सीमित हैं। जब भी किसी सदस्य को दौरे पर भेजा जाता है, तो हालांकि वे बिजनेस क्लास की उड़ानों से यात्रा करने के हकदार होते हैं, लेकिन सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे मितव्ययिता उपायों के तहत इकोनॉमी क्लास से यात्रा करें। विभिन्न वस्तुओं/सेवाओं की कीमतों में वृद्धि और अतिरिक्त बेंचों के कार्य के बावजूद, व्यय को दी गई सीमा तक सीमित रखा गया है। वित्तीय औचित्य और तर्कसंगतता के साथ व्यय को नियंत्रित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

4.11.9 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

अधिकरण की सभी पीठों में लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को लोक प्राधिकरण द्वारा नामित किया गया है, और वे सूचना प्रदान करने में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। सभी आरटीआई आवेदन और अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों सहित आदेश वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं।

4.12 माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण

माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) वस्तु एवं सेवा कर कानूनों के तहत दूसरी अपीलेट अथॉरिटी है और इसमें नई दिल्ली में मौजूद प्रिंसिपल बेंच के साथ-साथ भारत में अलग-अलग जगहों पर 31 स्टेट बेंच शामिल हैं। जीएसटीएटी में अपील फाइल करने के लिए वेब एप्लीकेशन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री ने 24 सितंबर, 2025 को किया था। इस तरह ट्रिब्यूनल चालू हो गया है और इसे 100% वर्चुअल/ई-कोर्ट मोड में लागू किया गया है। पोर्टल पर अपील फाइल करना पहले ही शुरू हो चुका है। इसके अलावा, ऑपरेशन शुरू करने के लिए मेंबर्स और शुरुआती स्टाफ की नियुक्ति भी पूरी हो चुकी है और इसी तरह, ज्यादातर जगहों पर बिलडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनल कर दिया गया है। मामलों की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है और यह उन टेम्पररी जगहों से की जा रही है जहाँ फाइनल की गई जगहें पूरी तरह से चालू नहीं हैं।

4.12.2 अध्यक्ष (लेवल-18), 50 न्यायिक सदस्य (लेवल-17), 29 तकनीकी सदस्य (केंद्र) (लेवल-17) और 12 तकनीकी सदस्य (राज्य) (लेवल-17) ने कार्यभार ग्रहण किया है।

4.12.3 आनुषंगिक कर्मचारियों में, उच्च श्रेणी लिपिक (लेवल-4) से लेकर रजिस्ट्रार (लेवल-13) के स्तर तक 192 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है। इनके अलावा, 9 समूह 'ग' के पद अन्य माध्यमों से भरे गए हैं। अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।

4.12.4 बुनियादी अवसंरचना में, प्रधान पीठ, जीस्टेट वर्ष 2024 से कार्यरत है। दिनांक 21 जनवरी, 2026 से राज्य पीठों को अस्थायी स्थानों पर स्थापित किये गये हैं। निम्नलिखित पीठें पूरी तरह से कार्यरत हैं, अर्थात् ठाणे, गुवाहाटी, कोलकाता और विजयवाड़ा, अन्य पीठें अस्थायी स्थानों से संचालित हो रही हैं। संपूर्ण रूप से कार्यशील कार्यालय जून, 2026 तक तैयार हो जाएंगे।

4.13 राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्था (एनआईपीएफपी)

4.13.1 राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) सार्वजनिक वित्त एवं लोक नीति के क्षेत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान, नीति समर्थन और क्षमता निर्माण के लिए समर्पित एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। 1976 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित, संस्थान ने भारत सरकार के सभी स्तरों पर नीति सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने अनुसंधान, समर्थन और प्रशिक्षण पहलों के माध्यम से, एनआईपीएफपी साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना और सार्वजनिक वित्त प्रणालियों को मजबूत करना जारी रखता है।

4.13.2 संस्थान के शासी निकाय की अध्यक्षता एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री करते हैं और वर्तमान में इसका नेतृत्व भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल कर रहे हैं। शासी निकाय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सचिव (राजस्व), सचिव (आर्थिक कार्य) और मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

4.13.3 इसके अलावा, शासी निकाय में निम्नलिखित शामिल हैं: नीति आयोग से एक नामांकित व्यक्ति, भारतीय रिजर्व बैंक से एक नामांकित व्यक्ति, प्रायोजक राज्य सरकारों से तीन नामांकित व्यक्ति, आईसीआईसीआई बैंक से एक नामांकित व्यक्ति, फिक्की और एसोचैम से एक-एक नामांकित व्यक्ति, तीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, सहयोगी अनुसंधान संस्थानों के तीन प्रमुख, शासी निकाय द्वारा सहयोजित दो सदस्य, संस्थान के निदेशक (पदेन) और संस्थान के एक प्रोफेसर, जिन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए बारी-बारी से (रोटेशन) द्वारा नामित किया जाता है।

सीबीडीटी के अध्यक्ष और सीबीआईसी के अध्यक्ष शासी निकाय में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।

4.13.4 निदेशक को सलाह देने के लिए एक अकादमिक समिति है। अकादमिक समिति में निदेशक अध्यक्ष के रूप में, सभी प्रोफेसर सदस्य के रूप में, शासी निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रोफेसर (बारी-बारी से) संयोजक के रूप में, और एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर (वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से) एक वर्ष की अवधि के लिए शामिल होते हैं।

4.13.5 एनआईपीएफपी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं:

सिक्किम सरकार:

एनआईपीएफपी वर्ष 2024-25 से 2026-27 की अवधि के लिए मध्यम अवधि की वित्तीय योजना (एमटीएफपी) की तैयारी और वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए सिक्किम एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की मूल्यांकन रिपोर्ट पर एक अध्ययन कर रहा है।

त्रिपुरा सरकार:

एनआईपीएफपी त्रिपुरा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने और त्रिपुरा में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के पुनर्गठन के लिए संभावित उपायों पर एक अध्ययन कर रहा है।

असम सरकार:

एनआईपीएफपी असम राज्य के लिए राजस्व सृजन बढ़ाने के संभावित तरीकों पर एक अध्ययन कर रहा है।

4.13.6 दिव्यांग लोगों और अनु.जा./अमु.जनजा के साथ-साथ समाज के दूसरे कमजोर तबकों की भलाई के लिए शुरू किए गए कदम

अनु.जा./अमु.जनजा/ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व पोस्ट भरने के लिए एक्शन लिया गया है, और पोस्ट उसी हिसाब से भर दी गई हैं। दिव्यांग लोगों के लिए, हमारी बिल्डिंग में रैंप और आसानी से मिलने वाले टॉयलेट जैसी सही व्यवस्था की गई है।

4.13.7 जेंडर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहल

एनआईपीएफपी ने इस विषय पर अनुसंधान किया है तथा संयुक्त राष्ट्र संगठनों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नीतिगत संवाद आयोजित किया है।

4.14 संशोधन आवेदन इकाई**4.14.1 संशोधन आवेदन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**

4.14.1.1 दिनांक 10.10.1982 तक लागू योजना के तहत, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तों (तब कलेक्टर कहलाते थे) के आदेशों के खिलाफ अपील केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (अब सीबीआईसी) के पास होती थी। जहां तक कलेक्टरों (अब आयुक्त कहलाते हैं) से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील का सवाल है, उन्हें सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपीलीय कलेक्टरों के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक था।

4.14.1.2 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की पूर्ववर्ती धारा 131 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 36 ने केंद्र सरकार को सीबीआईसी और अपीलीय कलेक्टरों द्वारा उनके अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित आदेशों को संशोधित करने का अधिकार दिया है। सरकारी स्तर पर, सचिव (राजस्व) या विशेष सचिव ने सीबीआईसी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध संशोधन आवेदनों पर निर्णय लिया, और अपर सचिव या संयुक्त सचिव ने सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अपीलीय कलेक्टरों और सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यकारी कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध आवेदनों पर विचार किया है।

4.14.1.3 वित्त (सं.2) अधिनियम, 1980 ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करके एक नई प्रणाली शुरू की है। सीबीआईसी के अपीलीय क्षेत्राधिकार और केंद्र सरकार के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को 11.10.1982 से समाप्त कर दिया गया, सिवाय कुछ अवशिष्ट संक्रमणकालीन प्रावधानों के और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण अपीलीय न्यायाधिकरण (जिसे तब सीईजीएटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आम तौर पर सीईएसटीएटी के नाम से जाना जाता है) की स्थापना 11.10.1982 से की गई।

4.14.1.4 वित्त अधिनियम, 1984 से विशिष्ट प्रकार के मामलों में केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियों को पुनर्जीवित किया गया। सीमा शुल्क पक्ष

पर, अधिनियम की धारा 129घघ के साथ धारा 129(क) के प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को संशोधित करने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क पक्ष पर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ख की उप-धारा (ii) के प्रथम प्रावधान के साथ धारा 35डड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेशों को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार को समीक्षा और पुनरीक्षण शक्तियां दी हैं।

4.14.1.5

क. आरंभ से ही केवल एक संशोधन आवेदन इकाई थी जिसका कार्यालय दिल्ली में था, जिसका नेतृत्व संयुक्त सचिव (संशोधन आवेदन), राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा किया जाता था। जुलाई, 2017 तक केंद्र सरकार की संशोधन शक्तियों का प्रयोग राजस्व विभाग, मुख्यालय (आईआरएस (आईआरएस के तहत एक तकनीकी पद होने के नाते) में एक संयुक्त सचिव द्वारा किया जा रहा था।

ख. मार्च, 2016 में, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एनवीआर फोर्जिंस बनाम भारत संघ {2016 (335) ईएलटी 679} के मामले में माना कि संयुक्त सचिव द्वारा पारित संशोधन आदेश, जो आयुक्त (अपील) के समान रैंक पर है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के इस आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 (348) ईएलटी ए-82 में रिपोर्ट के अनुसार बरकरार रखा है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय और माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने भी मामले में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है। इसलिए, संशोधन प्राधिकरण के पद को अपग्रेड किया गया।

ग. माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, संयुक्त सचिव के एक मौजूदा पद और संशोधन आवेदन इकाई में निदेशक के नव निर्मित पद को तकनीकी पदों के रूप में अपर सचिव के स्तर पर अस्थायी रूप से अपग्रेड करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी दी गई थी, और, परिणामस्वरूप, राजस्व विभाग के स्वीकृति आदेश संख्या 160/2017 दिनांक 19.07.2017 के तहत आईआरएस (सीएंडसीई) के कैडर की संख्या से प्रधान आयुक्त के दो पद कम कर दिए गए थे। इसके अनुसरण में, राजस्व विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 202/2017 दिनांक 20.07.2017 के तहत नई दिल्ली और मुंबई में एस (आरए) का एक-एक पद बनाया गया था।

घ. हाल-फिलाल तक, दिल्ली और मुंबई में दो संशोधन आवेदन इकाइयाँ थी जो विनिर्दिष्ट भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार उपरोक्त विनिर्दिष्ट मामलों में केंद्र सरकार के समक्ष दायर संशोधन आवेदनों से निपटती हैं। इन संशोधन आवेदन इकाइयों का नेतृत्व वर्तमान में प्रधान आयुक्त (संशोधन आवेदन) और भारत सरकार के पदेन अपर सचिव करते हैं जो कानून की उचित प्रक्रिया का

पालन करने के बाद संशोधन आवेदनों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। भौगोलिक आधार पर दो संशोधन प्राधिकरणों के बीच वितरित किया गया है, अर्थात् उत्तर, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों से संबंधित कार्य आरए-यूनिट, नई दिल्ली में संभाले जाते हैं जबकि पश्चिम से संबंधित कार्य आरए यूनिट, मुंबई में संभाले जाते हैं। वर्ष 2022 में आदेश संख्या 191/2022, दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से व्यवस्था को संशोधित किया गया था, दक्षिण क्षेत्र से संबंधित मामलों को आरए यूनिट नई दिल्ली को पुनः आबंटित किया गया था, जिसका उद्देश्य लंबित आवेदनों को तेजी से निपटान के लिए समान रूप से वितरित करना था। वर्ष 2025 में कार्यालय आदेश संख्या 164/2025 दिनांक 13.10.2025 के अनुसार व्यवस्था में अधिक संशोधन किया गया, अपर सचिव (आर.ए.), मुंबई का अधिकार क्षेत्र अतिरिक्त सचिव (आर.ए.), दिल्ली को सौंपा गया है।

4.14.2 संशोधन आवेदन इकाई का गठन, कार्य और कार्यप्रणाली

परिचय

4.14.2.1 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की पुनरीक्षण आवेदन इकाई, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 डब और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 घघ के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मामलों में केन्द्र सरकार के समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदनों पर विचार करती है। सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर (अपील) के आयुक्तों के आदेशों के विरुद्ध पक्षों या विभाग द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदनों पर, विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अपर सचिव (आरए) द्वारा विचार किया जाता है और निर्णय दिया जाता है।

4.14.2.2 सामान्यतः आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील न्यायाधिकरण अर्थात् सीईएसटीएटी के समक्ष की जाती है, लेकिन निम्नलिखित श्रेणी के मामलों में आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन अपर सचिव (संशोधन आवेदन) (जिन्हें आगे एएस (आरए) भी कहा जाएगा) के समक्ष दायर किया जाता है:-

क. सीमा शुल्क संबंधी मामले:-

(सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129क की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक में विनिर्दिष्ट)

4.14.2.3 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घघ के साथ धारा 129क(1) के प्रावधान के तहत केंद्र सरकार को सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को संशोधित या समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है, यदि ऐसा आदेश निम्नलिखित से संबंधित हो:-

- सामान के रूप में आयातित या निर्यातित कोई भी माल;
- भारत में आयात के लिए किसी वाहन में लदा हुआ कोई माल, किन्तु जो भारत में अपने गंतव्य स्थान पर नहीं उतारा जाता है, अथवा ऐसे माल की उतनी मात्रा, जो किसी ऐसे गंतव्य पर नहीं उतारी गई है, यदि ऐसे गंतव्य पर उतारे गए माल, उस गंतव्य पर उतारे जाने के लिए अपेक्षित मात्रा से कम हैं।

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय X तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार प्रतिअदायगी का भुगतान करना।

ख. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी मामले:-

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ख की उपधारा (1) के प्रावधान में विनिर्दिष्ट)

4.14.2.4 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डब को धारा 35ख(1) के परंतुक के साथ पठित धारा 35डब केन्द्र सरकार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है, यदि ऐसे आदेश निम्नलिखित से संबंधित हों:-

- माल की हानि का मामला, जहां हानि किसी कारखाने से गोदाम या किसी अन्य कारखाने तक, या एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक, या किसी गोदाम में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान होती है, चाहे वह कारखाने में हो या गोदाम में;
- भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र को निर्यात किए गए माल पर या भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र को निर्यात किए गए माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क में छूट;
- शुल्क का भुगतान किए बिना भारत से बाहर निर्यातित माल (नेपाल या भूटान को छोड़कर);
- * केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत अंतिम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने हेतु अनुमत किसी शुल्क का क्रेडिट और ऐसा आदेश वित्त (सं.2) अधिनियम, 1998 की धारा 109 के अंतर्गत नियत तिथि को या उसके पश्चात आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया जाता है।

नोट: *यह इंगित करता है कि यह खंड अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि यह वित्त अधिनियम, 1998 की धारा 109 के अंतर्गत नियुक्त की जाने वाली तारीख को या उसके पश्चात प्रभावी होना है तथा ऐसी कोई तारीख अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है।

ग. सेवा कर संबंधी मामले:-

4.14.2.5 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डब के प्रावधान, जो केन्द्र सरकार द्वारा संशोधन से संबंधित हैं, को सेवा कर से संबंधित वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय V के लिए उपयुक्त बनाया गया है। वित्त अधिनियम, 2015 में, धारा 86 को संशोधित किया गया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सेवा कर में छूट से संबंधित मामले में आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध समाधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डब के अनुसार होगा। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि सेवा कर में छूट से संबंधित सभी अपीलों और

वित्त अधिनियम, 2012 के प्रभावी होने की तिथि के बाद न्यायाधिकरण में दायर की गई और राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक, 2015 को मंजूरी दिए जाने की तिथि (अर्थात् 14.05.2015) को लंबित रहने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35डड के अनुसार स्थानांतरित की जाएंगी और उनका निपटारा किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में, आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध, संशोधन आवेदन अपर आयुक्त (आरए) के समक्ष दायर किया जाना आवश्यक है।

4.14.2.6 वित्त अधिनियम, 2015 की धारा 117 द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धारा (1) में सम्मिलित दो प्रावधानों का मूलपाठ (14.05.2015 से प्रभावी) निम्नानुसार है:

“परंतु जहां निर्यात की जाने वाली किसी सेवा से संबंधित कोई आदेश धारा 85 के अधीन पारित किया गया है और मामला इनपुट सेवाओं पर सेवा कर की छूट देने या ऐसी सेवा प्रदान करने में प्रयुक्त इनपुट पर भुगतान किए गए शुल्क की छूट से संबंधित है, ऐसे आदेश पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी; आगे यह भी प्रावधान है कि वित्त अधिनियम, 2012 के लागू होने के पश्चात् प्रथम परंतुक के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर सभी अपीलें, और वित्त विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख तक उसके समक्ष लंबित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड के प्रावधानों के अनुसार स्थानांतरित की जाएंगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी।”

4.14.3.1. संशोधन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

(क) पीड़ित पक्ष आयुक्त (अपील) के आदेशों को रद्द करने या संशोधित करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घघ की उपधारा (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड के तहत पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकता है।

(ख) “यदि सीमा शुल्क आयुक्त या प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त की राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश कानूनी और उचित नहीं है, तो वह उचित अधिकारी को ऐसे आदेश में संशोधन के लिए केंद्र सरकार को अपनी ओर से आवेदन करने का निर्देश दे सकता है। इस प्रकार, विभाग सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घघ की उपधारा (1क) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड के तहत संशोधन प्राधिकरण को आवेदन दायर करता है।”

(ग) आयुक्त या प्रधान आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन का कोई मामला दायर नहीं किया जा सकता, भले ही ऐसा आदेश ऊपर बताए गए विषय पर ही क्यों न हो। ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील सेस्टेट के समक्ष की जा सकती है, प्रधान आयुक्त (आरए) और भारत सरकार के पदेन अतिरिक्त सचिव के समक्ष नहीं। पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन केवल आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध किया जा सकता है, जिसमें ऊपर बताए गए विषय शामिल हों।

(घ) पुनरीक्षण प्राधिकारी को आदेश के संबंध में आवेदन स्वीकार करने से इंकार करने का विवेकाधिकार है, यदि ऐसे आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क या जुर्माना या दंड की राशि पांच हजार रुपये से अधिक नहीं है।

4.14.3.2 संशोधन आवेदन दाखिल करने की समय सीमा:-

(क) आयुक्त (अपील) के आदेश की सूचना मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक को पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जाना चाहिए, जिसके विरुद्ध आवेदन किया जा रहा है।

(ख) यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक को तीन महीने की पूर्वोक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो वह इसे तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है। अतः पुनरीक्षण प्राधिकरण को योग्य मामलों में तीन महीने तक की देरी को माफ करने का अधिकार है।

4.14.3.3. संशोधन आवेदन दाखिल करना:-

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घघ की उपधारा (3) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड में यह प्रावधान है कि संशोधन आवेदन (पक्षकारों द्वारा) ऐसे प्रारूप में होगा और हम रीति से सत्यापित किया जायेगा जो इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो और इसके साथ दो सौ रुपये का शुल्क होगा, जहां आवेदन से संबंधित मामले में मांगा गया शुल्क और ब्याज तथा जुर्माना या दंड एक लाख रुपये है या एक हजार रुपये का शुल्क होगा, जहां आवेदन से संबंधित मामले में मांगा गया शुल्क और ब्याज तथा जुर्माना या दंड एक लाख रुपये से अधिक है। विभाग द्वारा दायर आवेदन के मामले में ऐसा कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(ख) पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने का प्रारूप और तरीका सीमाशुल्क (अपील) नियम, 1982 (अधिसूचना संख्या 212-सीमाशुल्क दिनांक 10 सितम्बर 1982)/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियम, 2001 (अधिसूचना संख्या 32-गड दिनांक 21.06.2001) में प्रदान किया गया है। सीमा शुल्क (अपील) नियम 1982 के नियम 8क और 8ख के अनुसार, पुनरीक्षण आवेदन निर्धारित प्रपत्र घक-8 में दायर किया जाना चाहिए और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) नियम, 2001 के नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार पुनरीक्षण आवेदन निर्धारित प्रपत्र डक-8 में दो प्रतियों में दायर किया जाना चाहिए, साथ ही सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश और सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा पारित प्रासंगिक निर्णय या आदेश की समान संख्या में प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए और इसे अवर सचिव पुनरीक्षण आवेदन इकाई, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए या ऐसे अधिकारी को संबोधित पंजीकृत डाक से भेजा जाना चाहिए।

(ग) अपील नियमों के अनुसार, आवेदन पत्र में अपील का आधार और सत्यापन का प्रारूप आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(घ) केन्द्र सरकार अपने प्रस्ताव पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129घघ की उपधारा (1) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35डड में विनिर्दिष्ट किसी आदेश को रद्द या संशोधित कर सकती है।

ड) किसी भी मामले में संशोधन प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना या दंड बढ़ाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जिसमें आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश ने जब्ती के बदले में कोई जुर्माना या दंड बढ़ाया हो। अन्य मामले में, संशोधन प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना या दंड बढ़ाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को रद्द या संशोधित किए जाने वाले आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर इसके खिलाफ कारण बताने के लिए नोटिस न दे दिया गया हो।

(च) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर का कोई शुल्क नहीं लगाया गया है या कम लगाया गया है, वहां इस धारा के अंतर्गत शुल्क लगाने या बढ़ाने संबंधी कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि प्रस्तावित आदेश से प्रभावित व्यक्ति को धारा 28/धारा 11क में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसके विरुद्ध कारण बताने के लिए नोटिस न दे दिया जाए।

4.14.4 अपर सचिव (आरए) के समक्ष संशोधन आवेदन दाखिल करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें:

संयुक्त सचिव (आरए) के समक्ष अपील दायर करने से पहले निम्नलिखित आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए:-

- जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है, वह आयुक्त (अपील) द्वारा पारित होना चाहिए तथा ऊपर उल्लिखित मुद्दे/मुद्दों से संबंधित होना चाहिए।
- यदि ऊपर विनिर्दिष्ट विषय पर, सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, तो ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील एस(आरए) के समक्ष न की जाकर सीईएसटीएटी के समक्ष की जाएगी।
- सरकार अर्थात् अपर सचिव (आरए) किसी आदेश के संबंध में आवेदन स्वीकार करने से इंकार कर सकती है, जहां ऐसे आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क या जुर्माना या दंड की राशि पांच हजार रुपये तक है।

4.14.5 आरए यूनिट में संशोधन आवेदन की प्रक्रिया के लिए अपनाई गई प्रक्रिया:

संशोधन आवेदन इकाई, विभाग तथा पक्षकारों द्वारा निर्धारित प्रारूप ईए-8/सीए-8 में दायर संशोधन आवेदन प्राप्त करती है।

ऐसे आवेदन दाखिल करने के लिए निर्धारित समय संचार या अपील आदेश की तारीख से तीन महीने हैं। योग्य मामलों में केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने तक की देरी को माफ किया जा सकता है।

पुनरीक्षण आवेदन इकाई, पुनरीक्षण आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को पावती जारी करती है, साथ ही दस्तावेजों में कमी, यदि कोई हो, का ज्ञापन भी देती है।

प्रतिवादी पक्ष को प्रतिउत्तर दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। तत्पश्चात, वरिष्ठता के क्रम में, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मामलों में व्यक्तिगत सुनवाई तय/आयोजित की जाती है।

केवल उन योग्य मामलों में बारी-बारी से सुनवाई की अनुमति दी जाती है जिनमें पर्याप्त राजस्व शामिल हो, बार-बार होने वाले मुद्दे के कारण मामलों की बहुलता हो, ब्याज देयता हो, मुद्दा अब एकीकृत न हो, यात्री विदेश जा रहा हो और वित्तीय कठिनाई के मामले हों।

सुनवाई पूरी होने के बाद, एस (आरए) द्वारा अंतिम पुनरीक्षण आदेश जारी किया जाता है।

4.14.6 अपर सचिव (आरए) द्वारा पारित संशोधन आदेश के विरुद्ध अपील:

केंद्र सरकार की ओर से संशोधन आदेश पारित करते समय संशोधन प्राधिकरण विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करता है। संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकरण का कोई प्रावधान नहीं है।

इन संशोधन आवेदनों में केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राधिकारी है, और इसलिए केंद्र सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम हैं। हालांकि, संशोधन प्राधिकरण के आदेशों से असंतुष्ट आवेदकों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करने का ही विकल्प है।

अंतिम संशोधन आदेश पारित करने के बाद संशोधन प्राधिकरण पदेन हो जाता है। यह क्षेत्राधिकार आयुक्त होता है जो उच्च न्यायालय में रिट याचिकाओं का विरोध करता है या उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करता है।

4.14.7 संशोधन आवेदन इकाई सीधे राजस्व सचिव के प्रति उत्तरदायी है।

4.14.8 निष्पादन

अप्रैल, 2025 से नवंबर, 2025 तक आरए दिल्ली इकाई द्वारा 24 संशोधन आवेदनों का निपटारा किया गया है।

4.15 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

4.15.1 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजस्व विभाग के तहत एक पूर्ण राजभाषा प्रभाग है जिसे भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। इस प्रभाग में निदेशक (राजभाषा) का एक स्वीकृत पद है और यह प्रभाग वर्तमान में तीन हिंदी अनुभागों के माध्यम से कार्य कर रहा है। प्रत्येक अनुभाग का नेतृत्व

एक सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा किया जाता है और इसका पर्यवेक्षण उप निदेशक (राजभाषा) के दो पदों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में निदेशक (राजभाषा) का पद, सहायक निदेशक (राजभाषा) का एक पद, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पांच पद और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी का एक पद रिक्त है।

यह प्रभाग संघ की राजभाषा नीति को लागू करने के कार्य और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों और अनुदेशों पर समय पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का कार्य करता है। विभाग से संबंधित सभी अनुवाद कार्य अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी भी राजभाषा प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

राजस्व विभाग, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत एक अधिसूचित कार्यालय है। तथा वर्ष 2025 के दौरान, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के क्रमशः 1085 और 27 कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है।

4.15.2 वर्ष 2025 के दौरान राजभाषा प्रभाग का कार्यनिष्पादन

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और राजस्व मुख्यालय से संबंधित सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के तहत द्विभाषी रूप में जारी किए गए;

भारत के राजपत्र में प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, संसदीय प्रश्नों के उत्तर डिग्लॉट रूप में उपलब्ध कराए गए;

मंत्रिमंडल को नोट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट का हिंदी में अनुवाद किया गया और द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया;

दोहरे कराधान को रोकने के लिए कई देशों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का भी हिंदी में अनुवाद किया गया;

राजभाषा विभाग से राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सभी आदेशों और परिपत्रों को राजस्व विभाग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों और दोनों बोर्डों के नियंत्रण वाले कार्यालयों को समय पर परिचालित किया गया;

कोफेपोसा अनुभाग द्वारा जारी निरुद्धि आदेश और उनके कारणों का हिंदी में अनुवाद किया गया;

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त पत्रों को द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराया गया इत्यादि।

4.15.3 हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर सलाह देने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों का नेतृत्व संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री द्वारा किया जाता है और इसका गठन भारत के माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय हिंदी समिति की सिफारिश पर बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

इस प्रयोजन के लिए, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग, व्यय विभाग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। और इसका संकल्प 27 जून, 2025 को प्रकाशित किया गया है। पुनर्गठित संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक शीघ्र आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

4.15.4 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

राजभाषा संबंधी संसदीय समिति ने इस वर्ष राजस्व विभाग के 40 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया। राजभाषा प्रभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अनुवाद अधिकारियों ने इन कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया।

4.15.5 राजभाषा से संबंधित विभागीय निरीक्षण

रिपोर्ट की अवधि के दौरान कार्यालयों में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति का जायजा लेने के लिए राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग मुख्यालय के नियंत्रण में 04 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने के सुझाव भी दिए गए।

4.15.6 हिंदी पखवाड़े का आयोजन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, 14-15 सितंबर, 2025 को माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह की अध्यक्षता में गांधी नगर, गुजरात में इस वर्ष का हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया था। राजस्व विभाग के राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों/कार्मिकों और विभाग के अन्य कार्मिकों ने भी इस समारोह में भाग लिया।

विभाग में 14 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक हिंदी पखवाड़े 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस अवधि के दौरान, नियमित सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से कुल 05 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पखवाड़े के दौरान, निबंध लेखन, हिंदी में आशुभाषण, वर्ग-पहेली प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद और राजभाषा प्रश्नोत्तरी (लिखित) और हिंदी डिक्टेशन तथा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता (केवल एमटीएस के लिए) जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रत्येक प्रतियोगिता में 5000/- रुपये (प्रथम पुरस्कार), 3000/- रुपये (द्वितीय पुरस्कार), 2000/- रुपये (तृतीय पुरस्कार) और 1000/- रुपये के सात प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

4.15.7 हिंदी में मूल टिप्पण/प्रारूपण और डिक्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए नकद प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हिंदी में सरकारी कामकाज (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) करने और अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाएं (पूर्णकालिक) लागू की गईं।

इस योजना के तहत, राजस्व विभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्मिकों से प्राप्त आठ प्रविष्टियों को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा विभाग के एक अधिकारी को हिंदी में डिक्टेशन देने संबंधी प्रोत्साहन योजना में पुरस्कृत किया गया।

4.15.8 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और राजभाषा नीति को लागू करने में अनुभागों/अधीनस्थ कार्यालयों की बाधाओं को दूर करने के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, विभाग में तीन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। संयुक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में राजस्व मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की जाती है, जबकि संयुक्त सचिव (सीबीडीटी) और संयुक्त सचिव (सीबीआईसी) की अध्यक्षता वाली समितियां क्रमशः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती हैं। इन समितियों की बैठकें गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष आयोजित विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का विवरण निम्नलिखित है:-

(क) संयुक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में समिति की 11.06.2025, 27.08.2025 और 11.12.2025 को बैठकें आयोजित की गईं

(ख) संयुक्त सचिव (सीबीडीटी) की अध्यक्षता में समिति की 02.05.2025, 16.9.2025 और 13.11.2025 को बैठकें आयोजित की गईं

(ग) संयुक्त सचिव (सीबीआईसी) की अध्यक्षता में समिति की 24.06.2025 और 18.09.2025 को बैठकें आयोजित की गईं

उक्त बैठकों के कार्यवृत्त सभी अनुभागों को अनुपालन के लिए जारी किए गए।

4.15.9 राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित कार्यशालाएं

इस अवधि के दौरान देश की राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विभाग के मुख्यालय, सीबीआईसी और सीबीडीटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10.09.2025 और 09.12.2025 को 2 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 10 जून 2025 को एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई।

4.15.10 प्रशिक्षण

हिंदीतर भाषी अधिकारियों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत भाषा प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाता है। इसके अलावा उन आशुलिपिकों/सचिवालयीन

कार्मिकों को हिंदी टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिनके लिए हिंदी टाइपिंग का ज्ञान अनिवार्य है। तीन कार्मिकों ने जुलाई 2025 को समाप्त हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और जनवरी 2026 में समाप्त होने वाले प्रशिक्षण सत्र में छह कार्मिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। भाषा और टाइपिंग प्रशिक्षण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित पत्राचार और टिप्पणियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

4.15.11 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का परिचालन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 की प्रतियां राजस्व विभाग मुख्यालय के सभी कार्यालयों और अनुभागों को परिचालित की गईं। प्रत्येक वर्ष में जारी वार्षिक कार्यक्रम हिंदी के प्रचार और प्रगामी प्रयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है।

4.16 स्वच्छ भारत अभियान

वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ-साथ उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय आगामी विशेष अभियान 5.0 में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक भारत सरकार के विभागों में आयोजित किया जा रहा है। अभियान का नेतृत्व प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा स्वच्छता को और संस्थागत बनाने और लंबित संदर्भों के समय पर और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

दिनांक 15 सितंबर 2025 से शुरू होने वाले प्रारंभिक चरण के भाग के रूप में, राजस्व विभाग के अंतर्गत सभी संगठनों - जिनमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय आसूचना एकक - इंडिया और अन्य शामिल हैं - ने लंबित सांसद/राज्य सरकार के संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियानों, डिजिटलीकरण और वीडिंग आउट के लिए अभिलेखों और स्कैप और अप्रचलित वस्तुओं के निपटान की पहचान करने के लिए गहन समीक्षा की है। प्रत्येक संगठन ने कार्यान्वयन चरण के दौरान समर्पित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को नामित किया है। कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने और सभी स्तरों पर उत्साही भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग भौतिक

अभिलेखों को कम करने, कागज रहित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर भी जोर दे रहा है।

राजस्व विभाग ने विशेष अभियान 4.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया और लंबितता को कम करने और स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिसंबर 2024 से अगस्त, 2025 की अवधि के दौरान, राजस्व विभाग ने कुल 38 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ (मंत्रिमंडल टिप्पणी, सीओएस नोट, ईएफसी मेमो आदि), 28 वीआईपी संदर्भ, 7043 सार्वजनिक शिकायतें, 8 सार्वजनिक शिकायत अपील का निपटान किया। इसके अलावा, कुल 9603 भौतिक फाइलों की समीक्षा के बाद उन्हें हटा दिया गया। इसके अलावा, स्क्रेप निपटान के साथ, 1,05,000/- रुपये का राजस्व भी उत्पन्न हुआ।

विशेष अभियान 5.0 सभी स्तरों पर प्रशासनिक दक्षता और स्वच्छता को और बढ़ाने के लिए **स्वच्छता, पारदर्शिता और जवाबदेही** के प्रति राजस्व विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

4.17 सूचना का अधिकार कक्ष

राजस्व मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना के प्रसार को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- आरटीआई आवेदन/अपील को संपर्क रहित और कागज रहित तरीके से दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आरटीआई

ऑनलाइन पोर्टल (www.rtionline.gov.in) इस संबंध में बहुत सुविधाजनक रहा है। आरटीआई आवेदन और अपील के जवाब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं, जिन्हें आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा विशेष रूप से देखा जा सकता है। ऑफलाइन आरटीआई आवेदन को अन्य सार्वजनिक प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने की व्यवस्था बनाने के लिए आरटीआई अनुरोध और अपील प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दर्ज किया जाता है ताकि इसे तुरंत संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सके।

- विभाग ने पारदर्शिता और प्रभावी शासन करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं हमने सूचना को सक्रिय प्रकटीकरण के आधार पर इसे सार्वजनिक डोमेन में रखा है जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1) के तहत यथा अपेक्षित विभाग की वेबसाइट (<https://dor.gov.in/rti/revenue-headquarters>) पर उपलब्ध है।
- प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले पारदर्शिता ऑडिट के संबंध में प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन प्रपत्र का राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा ऑडिट किया गया है।
- निम्नलिखित तालिका वित्तीय वर्ष 2025 में दिनांक 01.04.2025 से 31.12.2025 तक प्राप्त ऑनलाइन आरटीआई आवेदनों और अपीलों की संख्या को दर्शाती है:

प्रकार	वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या, जिसमें अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित मामले भी शामिल हैं	धारा 6(3) के तहत अन्य जनप्राधिकारियों को हस्तांतरित + आवेदक को वापस किए गए मामलों की संख्या	अनुरोध अस्वीकृत	अनुरोध/अपील स्वीकार किए गए।
ऑफलाइन आरटीआई आवेदन	697	580	-	117
ऑनलाइन आरटीआई आवेदन	8605	7449	313	843
ऑफलाइन अपील	39	0	0	39
ऑनलाइन अपील	164	89	0	75
धारा 7(1) के तहत प्राप्त कुल शुल्क 5175/- है।				
धारा 7(3) के अंतर्गत ऑफलाइन प्राप्त अतिरिक्त शुल्क 770/- रु. है।				

5. एकीकृत वित्तीय एकक (आईएफयू)

राजस्व विभाग का एकीकृत वित्त प्रभाग **अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर** से संबंधित अनुदानों के संबंध में बजट, वित्त और व्यय प्रबंधन के निपटान हेतु तीन इकाइयाँ हैं। निदेशक (वित्त), राजस्व विभाग/सीबीआईसी और निदेशक (वित्त), प्रत्यक्ष कर अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) की सहायता करते हैं।

5.1 एकीकृत वित्तीय एकक द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ:

राजस्व विभाग के अंतर्गत सभी कार्यालय, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व मुख्यालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न निदेशालयों सहित, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न निदेशालयों, स्वापक नियंत्रण प्रभाग, केंद्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य कारखाना नियंत्रक, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी), माल एवं सेवा कर परिषद सचिवालय, कर नीति अनुसंधान इकाई, प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), समझौता आयोग (आईटी/डब्ल्यूटी), अग्रिम विनियम प्राधिकरण, सम्पत्ति अपील अधिकरण, पीएमएलए के तहत न्याय निर्णय प्राधिकरण, आयकर लोकपाल आदि को बजट निर्माण, निधि आबंटन, व्यय निगरानी एवं नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को लागू करने, क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रत्यायोजित शक्तियों से परे व्यय प्रस्तावों की जांच और मंजूरी के संदर्भ में एकीकृत वित्त प्रभाग की तीन इकाइयों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

5.2 व्यय और वित्तीय प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन का विवरण:

- (क) पदों का सृजन और निरंतरता, कार्यालयों का निर्माण/खरीद/किराए पर लेना, साथ ही केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग और इसके संबद्ध कार्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए आवास की व्यवस्था करना।
- (ख) तस्करी रोधी उपकरणों जैसे स्कैनर और समुद्री जहाजों की खरीद सहित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।
- (ग) विभाग, सीबीडीटी, सीबीआईसी और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/दौरा/प्रशिक्षण के प्रस्ताव।
- (घ) पुनर्गठन प्रस्ताव, क्षेत्रीय कार्यालयों और घटक इकाइयों में कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति।

- (ड) राजस्व विभाग, सीमा शुल्क और जीएसटी कार्यालयों सहित इनके क्षेत्रीय कार्यालयों तथा आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों का व्यापक कम्प्यूटरीकरण।
- (च) राजस्व विभाग की प्रबंधन समिति (सीओएम) के प्रस्ताव जो सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना (जीओएडब्ल्यू) के कामकाज की देखरेख करती है।
- (छ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान तथा केंद्रीय राजस्व खेल एवं सांस्कृतिक बोर्ड को अनुदान सहायता।
- (ज) सीबीडीटी/सीबीआईसी की व्यापक कम्प्यूटरीकरण योजना, तीनों विभागों के कार्यालय/आवासीय परिसरों और रेडीमेड कार्यालय/आवासीय भवनों के निर्माण से जुड़े पूंजीगत व्यय से संबंधित प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी), सार्वजनिक निवेश बोर्ड और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के लिए प्रस्ताव।
- (झ) सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि तथा विशेष उपकरण निधि से वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्राप्त। मनोरंजन/खेल क्लब, व्यायामशाला, विभागीय कैंटीन, विभागीय अधिकारियों के बच्चों के लिए क्रेच, अतिथि गृह तथा बालिकाओं और समूह 'घ' कर्मचारियों के बच्चों पर विशेष जोर देते हुए मेधावी बच्चों के लिए नकद पुरस्कार योजना की स्थापना/नवीनीकरण के संबंध में मानदंडों में संशोधन को अंतिम रूप दिया गया।
- (ञ) वित्तीय नियमों में छूट/व्याख्या से संबंधित प्रस्ताव और व्यय विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता संबंधी सभी प्रस्ताव।
- (ट) एकीकृत वित्त प्रभाग को प्रारंभिक चरण से ही महत्वपूर्ण व्यय प्रस्तावों की योजनाएं तैयार करने का कार्य भी सौंपा गया है।

5.3 प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर राजस्व विभाग के व्यय बजट/गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान 2025-26 के लिए तैयार की गई हैं। बजट प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अनुमानित संशोधित अनुमान 2025-26 और बजट अनुमान 2026-27 की अधिकतम सीमा की जानकारी दे दी गई है। तीनों अनुदानों के संबंध में संशोधित अनुमान 2025-26 और दिनांक 30.11.2025 तक वास्तविक व्यय और बजट अनुमान 2026-27 का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

अनुदान	अनुदान सं.	2025-26 बजट अनुमान	30 नवंबर, 2025 तक वास्तविक व्यय	2025-26 संशोधित अनुमान	2026-27 बजट अनुमान
राजस्व विभाग	35	133880.26	1534.46	15042.54	3126.42
प्रत्यक्ष कर	36	10900.45	7006.49	12732.08	15306.57
अप्रत्यक्ष कर	37	42889.33	23267.45*	41496.11#	27682.63#

* ई-लेखा पोर्टल में दिए गए विवरण के अनुसार, नवंबर, 2025 तक का वास्तविक व्यय डीजीएचआरडी से लिया गया है।

बजट प्रभाग द्वारा संशोधित अनुमान 2025-26 और बजट अनुमान 2026-27 के आंकड़े अभी तय किए जाने हैं।

5.4 एकीकृत वित्त प्रभाग ने वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित कदम/पहल उठाई हैं:

- अनुदान संख्या 35 (राजस्व विभाग), अनुदान संख्या 36 (प्रत्यक्ष कर) और अनुदान संख्या 37 (अप्रत्यक्ष कर) के संबंध में बीई/आरई और डीडीजी की तैयारी और प्रस्तुति।
- लेखापरीक्षा आपत्तियों, निरीक्षण रिपोर्टों, मसौदा लेखापरीक्षा पैरा और लोक लेखा समिति / स्थायी समिति की रिपोर्टों के निपटारे तथा लेखापरीक्षा पैरा, वित्तीय स्थायी समिति, आवधिक रिपोर्टों आदि के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए विभाग/बोर्डों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- अग्रिमों से संबंधित बजट जैसे गृह निर्माण अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम आदि का आबंटन और निगरानी।
- विभिन्न स्क्रिप-आधारित योजनाओं के बजटीय तंत्र का समग्र

पर्यवेक्षण तथा इन योजनाओं के संचालन/प्रावधान के लिए राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग और वस्त्र विभाग के साथ समन्वय करना।

- वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा परिकल्पित मासिक व्यय योजना (एमईपी) और त्रैमासिक व्यय आबंटन (क्यूईए) के अनुसार नकदी प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन।
- सख्त वित्तीय अनुशासन के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन में बजटीय आबंटन और एमईपी/क्यूईए के संबंध में मासिक और त्रैमासिक व्यय की समीक्षा और राजस्व सचिव और व्यय सचिव को रिपोर्ट करना।
- राजस्व विभाग की विशिष्ट गतिविधियों/विकास की समीक्षा और मासिक आधार पर सचिव (व्यय) को रिपोर्ट करना।
- व्यय विभाग द्वारा जारी मितव्ययता अनुदेशों के अनुरूप व्यय की आवधिक समीक्षा करना तथा व्यय नियंत्रण के लिए व्यय प्राधिकारियों को परामर्श द्वारा व्यय में मितव्ययता संबंधी अनुदेशों को लागू करना।
- जीएसटी के लागू होने पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति की तैयारी और बजटीय आबंटन; सरकारी अफीम और क्षारोद कारखाना; आवासीय और कार्यालय आवास का अधिग्रहण; सीबीआईसी, सीबीडीटी और राजस्व विभाग के ई-गवर्नेंस के लिए आईटी क्षमता को मजबूत करना; समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए जहाजों और बेड़ों का अधिग्रहण और तस्करी रोधी उपकरणों का अधिग्रहण।

संगठन : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)^					कैलेंडर वर्ष 2025(अर्थात 01.01.2025 से 30.11.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा**					अन्य माध्यमों द्वारा				
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह 'क'	4347	780	395	680	11	180*	27	13	49	18	-	-	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समूह 'ख'	26584	4327	1820	4227	376	344	86	51	83	58	2252	345	155	269	4	1	1	0	0	0
समूह 'ग'	18859	3371	1426	5557	951	2859	545	264	1021	419	602	95	47	170	8	118	32	9	27	0
कुल	49790	8478	3641	10464	1338	3383	658	328	1153	495	2854	440	202	439	12	119	33	9	27	-

* दिनांक 19.11.2025 तक सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2024 के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को सीबीडीटी द्वारा 180 'नियुक्ति प्रस्ताव' जारी किए गए हैं। ये संख्या ऊपर कॉलम 2 से 6 में शामिल नहीं हैं।

** रिक्ति वर्ष 2024 और 2025 के लिए अपर आयकर आयुक्त ग्रेड में 251 रिक्तियों (अ.ज.: 11; अ.ज.जा.: 10 सहित) को भरने के लिए यूपीएससी में दिनांक 12.09.2025 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। डीपीसी की तारीख का इंतजार है। हालाँकि, कार्यालय आदेश संख्या 89/2025 दिनांक 04.04.2025 के अनुसार रिक्ति वर्ष 2024 के विरुद्ध 29 आयकर अधिकारियों को तदर्थ आधार पर अपर आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया है।

^ कार्यालय आदेश संख्या 350/2024 दिनांक 31.12.2024 के अनुसार 313 आयकर अधिकारियों (अ.जा. और अ.ज.जा सहित) को रिक्ति वर्ष 2022 और 2023 के विरुद्ध नियमित आधार पर अपर आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, कार्यालय आदेश संख्या 354/2024 दिनांक 31.12.2024 के अनुसार 168 आयकर अधिकारियों (अ.जा. और अ.ज.जा सहित) को रिक्ति वर्ष 2024 के आधार पर तदर्थ आधार पर अपर आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था।

संगठन : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)

दिनांक 01.01.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 01.01.2025 तक)					कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा					अन्य माध्यमों द्वारा				
	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	4197	791	428	526	9	डेटा डी.जी.एच.आर.डी. के पास उपलब्ध नहीं है और इसे प्रशासन-II से मांगा जा सकता है।					14	1	1	0	0	सी.बी.आई.सी. में समूह क अधिकारियों की पूर्व-संवर्ग प्रतिनियुक्ति नहीं है।				
समूह-ख	36902	5921	3682	7504	1157	2525	468	231	742	335	1014	218	93	0	0	65	0	0	0	0
समूह-ग (पूर्ववर्ती समूह-घ पदों सहित)	10149	2089	899	2651	412	909	149	72	318	94	225	49	19	0	0	0	0	0	0	0
कुल	51248	8801	5009	10681	1578	3434	617	303	1060	429	1253	268	113	0	0	65	0	0	0	0

संगठन : राजस्व मुख्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य माध्यमों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	232	43	15	23	-	-	-	-	-	-	-	17	1	1	1
समूह ख	416	77	60	111	-	-	-	-	8	4	-	-	-	-	-
समूह ग	274	68	18	57	6	3	-	3	13	03	01	03	-	-	-
कुल	922	188	93	191	6	3	-	3	21	7	1	20	1	1	1

संगठन : वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू-भारत)

समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)				पिछले कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (अर्थात् दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक)											
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य माध्यमों द्वारा (प्रतिनियुक्ति पर)			
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
समूह क	25	09	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	02	01	-	-
समूह ख	05	02	-	-	02	01	-	-	-	-	-	-	01	01	-	-
समूह ग	06	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
कुल	36	13	-	05	02	01	-	-	-	-	-	-	05	02	00	00

टिप्पणी: 02 सहायक अनुभाग अधिकारी एवं 05 एमटीएस (समूह 'ग') के पदों को छोड़कर नियुक्ति का तरीका केवल प्रतिनियुक्ति है।

संगठन : सफेमा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण

[illegible]

संगठन : अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य माध्यमों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	9	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
समूह ख	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
समूह ग	31	5	-	10	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1
कुल	52	7	-	12	1	-	-	1	-	-	-	7	1	-	1

संगठन : सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी)

समूह	कर्मचारियों की संख्या					कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			अन्य माध्यमों द्वारा			
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.
समूह क	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह ख	40	13	3	23	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	46	15	3	27	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	51	20	6	24	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
					1		1									-	2
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)											-	-	-	-	-	-	
कुल	141	50	12	76	3	3	1		2		-	2	1	-	-	-	2

संगठन : स्वापक नियंत्रण प्रभाग

(I) केंद्रीय स्वापक ब्यूरो

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात् दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा					अन्य माध्यमों द्वारा				
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह क	10	4	1	2	0	0	0	0	0	0	10	1	0	3	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समूह ख	203	32	22	35	5	13	2	1	5	3	19	7	0	2	0	0	0	0	0	0
समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	474	74	41	148	52	280	53	22	105	41	19	3	1	10	1	0	0	0	0	0
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	687	110	64	185	57	293	55	23	110	44	48	11	1	15	1	0	0	0	0	0

*09 अधीक्षक को सहायक आयुक्त (इन-सीटू आधार) के रूप में पदोन्नत किया गया

01 प्रशासनिक अधिकारी को मुख्य लेखा अधिकारी (इन-सीटू आधार) के रूप में पदोन्नत किया गया

ii. मुख्य कारखाना नियंत्रक

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																					
कार्यालय	समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात् दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या														
							सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा					अन्य माध्यमों द्वारा				
		कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ई.डब्ल्यू.एस.
सी सी ए फ संगठन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	समूह क	06	01	01	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ख	10	06	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ग (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	325	86	50	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (सफाई कर्मचारी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	341	93	51	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संगठन : प्रवर्तन निदेशालय

दिनांक 30.11.2025 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़े वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																				
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात् दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.11.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों /पदोन्नतियों की संख्या														
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति					अन्य माध्यमों द्वारा (प्रतिनियुक्ति पर)				
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	ई. डब्ल्यू. एस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह क	421	32	16	40	1	-	-	-	-	-	60	2	1	22	0	55	-	-	-	-
समूह ख	731	86	34	182	32	93	17	6	24	16	66	10	5	21	0	28	-	-	-	-
समूह ग	482	28	12	48	5	23	4	2	7	7	6	0	0	0	0	17	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1634	146	62	270	38	116	21	8	31	23	132	12	6	43	0	100	-	-	-	-

संगठन : राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान

समूह	कर्मचारियों की संख्या 30.11.2025 तक				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या (01-04-2025 से 30-11-2025 तक)										
					सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा				अन्य माध्यमों द्वारा		
	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.	अ.पि. व.	कुल	अ.जा.	अ. ज.जा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
समूह क	35	2	1	3	02	-	-	-	00	-	-	-	00	-	-
समूह ख	13	1	-	3	03	01	-	01	00	-	-	-	00	-	-
समूह ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	18	6	-	4	04	02	-	-	00	-	-	-	00	-	-
समूह घ (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	00	-	-	-	00	-	-	-	00	-	-
कुल	66	9	1	10	09	03	-	01	00	-	-	-	00	-	-

संगठन : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

दिनांक 30.11.2025 तक दिव्यांगजनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																									
समूह	कर्मचारियों की संख्या (30.11.2025 तक)^					कैलेंडर वर्ष 2025(अर्थात 01-04-2025 से 30-11-2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति**									
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एचएच	ओएच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओएच	आई डी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
समूह क	4347	8	31	86	-	2	1	2	-	180*	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
समूह ख	26584	98	92	580	1	62	33	34	23	135	31	1	3	3	59	47	59	19	559	18	15	42	0		
समूह ग	18859	203	139	325	14	1181	43	41	22	879	571	25	25	12	31	317	25	13	80	7	5	8	0		
कुल	49790	309	262	991	15	1245	77	77	45	1194	604	27	30	24	90	364	84	32	639	25	20	50	0		

* 180 परीक्षार्थियों को दिनांक 19.11.2025 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सिविल परीक्षाओं (सीएसई) 2024 के माध्यम से चयनित नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए हैं। ये संख्याएँ ऊपर कॉलम 2 से 5 में शामिल नहीं हैं।

** रिक्ति वर्ष 2024 के लिए एसीआईटी के ग्रेड में 251 रिक्तियों (वीएच: 1; एचएच: 2; ओएच: 2 सहित) को भरने के लिए यूपीएससी में 12.09.2025 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। डीपीसी की तिथि का इंतजार है।

^ 313 आयकर अधिकारियों. (वी.एच.; एच.एच.; ओ.एच. सहित) को रिक्ति वर्ष 2022 और 2023 के लिए कार्यालय आदेश संख्या 350/2024 दिनांक 31.12.2024 के अनुसार नियमित आधार पर अपर आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, 168 आयकर अधिकारियों को रिक्ति वर्ष 2024 के लिए कार्यालय आदेश संख्या 354/2024 दिनांक 31.12.2024 के अनुसार तदर्थ आधार पर अपर आयकर आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया था।
टिप्पणी:-

- वी.एच. का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)।
- एच.एच. का अर्थ है श्रवण विकलांग (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति)।
- ओ.एच. का अर्थ है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (गतिशीलता विकलांगता से पीड़ित व्यक्ति) या
- आई.डी. का अर्थ है बौद्धिक अक्षमता।

संगठन : राजस्व मुख्यालय

[illegible]

संगठन : सफेमा के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती								पदोन्नति							
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
'क'	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ख'	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
'ग'	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
कुल	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

संगठन : अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी

[illegible]

संगठन : सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीस्टैट)

1	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)				कैलेंडर वर्ष 2025(अर्थात 01-04-2025 से 30-11-2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या													
					सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
'क'	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
'ख'	40	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
'ग'	97	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	141	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

संगठन : स्वापक नियंत्रण प्रभाग

i. केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो

दिनांक 30.11.2025 तक दिव्यांगजनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																									
समूह	कर्मचारियों की संख्या					कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात 01-04-2025 से 30-11-2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
						सीधी भर्ती										पदोन्नति									
						आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या						आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या					
	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एचएच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी		
क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ख	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ग	7	3	1	3	0	0	3	2	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		
कुल	9	3	1	5	0	0	3	2	0	3	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0		

ii. मुख्य कारखाना नियंत्रक

दिनांक 30.11.2025 तक दिव्यांगजनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																								
							कैलेंडर वर्ष 2025(अर्थात 01-01-2025 से 30-11-2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
कार्यालय	समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
							आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्तियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				
		कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एचएच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी	कुल	वी एच	एच एच	ओ एच	आई डी
सीसीएफ संगठन	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	समूह क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह ग	08	03	01	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	02	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	समूह घ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	10	03	02	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

संगठन : प्रवर्तन निदेशालय

दिनांक 30.11.2025 तक दिव्यांगजनों का समूह-वार प्रतिनिधित्व																							
समूह	कर्मचारियों की संख्या (दिनांक 31.12.2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2025(अर्थात 01-01-2025 से 30-11-2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																	
						सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति									पदोन्नति द्वारा नियुक्ति								
						आरक्षित रिक्रियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या				की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	आईडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
समूह क	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
समूह ख	731	0	0	1	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0
समूह ग	482	1	0	5	0	0	0	0	0	23	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
समूह घ	लागू नहीं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1634	1	0	6	0	0	0	0	0	116	0	0	1	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0

संसद में प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश:

1. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

क्र. सं.	वर्ष	उन पैरा / लोक लेखा रिपोर्ट की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा से जांच के बाद की गई कार्रवाई विषयक नोट लोक लेखा समिति को जमा किए गए हैं	उन पैरा/पब्लिक अकाउंट्स रिपोर्ट की जानकारी जिन पर एक्शन टेकन नोट्स लंबित हैं		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।	एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण किया गया है लेकिन मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
1.	2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 9	0	1	0	0
2.	2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 13	283	145	11	15
3.	2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 14	0	1	0	0
4.	2025 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 14	114	154	8	58
	कुल	397	301	19	73

2. केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश

क्र. सं.	वर्ष	उन पैरा/पीए रिपोर्ट की संख्या जिन पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद लोक लेखा समिति को एटीएन प्रस्तुत किए गए हैं	पैरा/पीए रिपोर्ट का विवरण जिन पर एटीएन लंबित हैं		
			मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटाए गए एटीएन की संख्या और लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है	एटीएन की संख्या जिनका लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण किया गया है लेकिन मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया है
पीएसी-जीएसटी खंड					
1	2025 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 12	0*	0	0	0*
पीएसी-सीमा शुल्क खंड					
1.	2025 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 11	0*	27	21	18*
2.	2024 की ऑडिट रिपोर्ट संख्या 17	0*	0	0	0*
	कुल	0*	27	21	18*

* लोक लेखा समिति सेल, सीबीआईसी, लोक लेखा समिति को एटीएन जमा नहीं करता है। सभी स्टेज पर पैरा के एटीएन की अपलोडिंग एएमपीएस पोर्टल पर की जाती है, जिसे सीजीए मैनेज करता है, जो व्यय विभाग के तहत आता है और सीएजी तक इसकी पहुँच है।

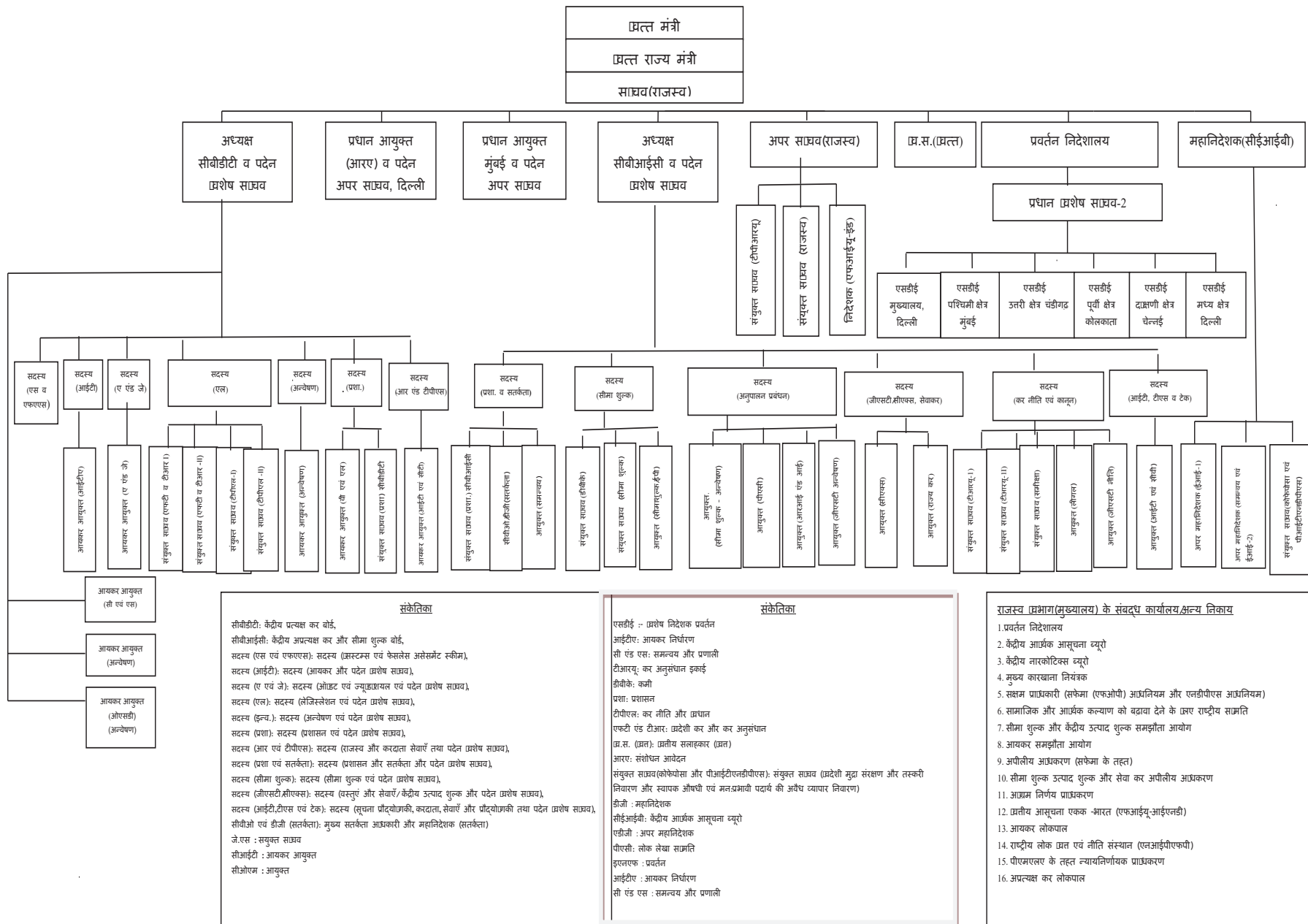
3. राज्य कर (एसटी)

सीएजी लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	रिपोर्ट सं.	अध्याय सं.	पैरा सं.	लेखापरीक्षा पैरा का सार	दिनांक 17.11.2025 तक की स्थिति
1.	2021	7	2	पैरा 2.3.3 - वित्त वर्ष 18 से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आई.जी.एस.टी. के अल्प हस्तांतरण का लेखा-जोखा	वित्त वर्ष 18 से संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आई.जी.एस.टी. के अल्प हस्तांतरण का लेखा-जोखा	ए.टी.एन. को दिनांक 17.07.2025 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
2.	2021	7	2	पैरा 2.7.2 - अविभाजित आईजीएसटी	अविभाजित आईजीएसटी	ए.टी.एन. को दिनांक 17.07.2025 को एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया है। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
3.	2021	1	3	संपूर्ण अध्याय - जीएसटीएन का सूचना प्रौद्योगिकी ऑडिट (चरण-II)	यह पैरा रिफंड मॉड्यूल, रिटर्न मॉड्यूल, ईडब्ल्यूबी की अस्वीकृति और जीएसटीएन के इन्फ्रा/नेटवर्क के अन्य मुद्दों के आईटी ऑडिट से संबंधित है।	सीएजी के कार्यालय ने दिनांक 30.06.2025 को लेखापरीक्षा टिप्पणियों को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है। आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 30.10.2025 को अपलोड किया गया। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
4.	2022	5	4	संपूर्ण अध्याय - जीएसटीएन द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता	यह पैरा (1) कर योग्य मूल्यों और घोषित कर देयता के बीच असंगतता से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप अविश्वसनीय डेटा प्राप्त होता है और (2) जीएसटी के सीजीएसटी और एसजीएसटी घटकों में असंगतता।	सीएजी के कार्यालय ने दिनांक 30.05.2025 को लेखापरीक्षा टिप्पणियों को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है। आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 31.10.2025 को अपलोड किया गया। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
5.	2024	7	अध्याय VII	(कंपोजिशन लेवी) सम्मिश्रण उद्ग्रहण योजना डेटा का डेटा विश्लेषण	कंपोजिशन लेवी योजना डेटा का डेटा विश्लेषण	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 04.04.2025 को अपलोड किया गया। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।(एटीएन प्रस्तुत) कर दिए गए हैं।
6.	2024	7	अध्याय VI	माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता	माल एवं सेवा कर नेटवर्क द्वारा बनाए गए जीएसटी डेटा की विश्वसनीयता	सीएजी के कार्यालय ने दिनांक 28.04.2025 को लेखापरीक्षा टिप्पणियों को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है। आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 22.10.2025 को अपलोड किया गया। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
7.	2024	7	अध्याय 1	पैरा 1.3.2 - अप्रत्यक्ष करों के विभिन्न घटकों की तुलनात्मक वृद्धि	भारत की समेकित निधि में आईजीएसटी का प्रतिधारण	आगे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर एपीएमएस पोर्टल पर दिनांक 30.07.2025 को अपलोड किया गया। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।
8.	2025	12	संपूर्ण रिपोर्ट	जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट	दिनांक 30.10.2025 को एपीएमएस पोर्टल पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर प्रस्तुत किया गया है। सीएजी कार्यालय द्वारा उक्त की समीक्षा अभी तक नहीं की गई है।

राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट

अनुबंध-IV



अध्याय - IV

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

I. कार्य

मौजूदा कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार, विभाग हेतु शासनादेश इस प्रकार हैं :

1. (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी नियोजन या किसी अन्य पद्धति के माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित सभी मामलों।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में रणनीतिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर, जहां आवश्यक हो, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।

2. रणनीतिक विनिवेश सहित विनिवेश के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

3. विनिवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर(रों) से संबंधित सभी मामलों।

4. (क) इक्विटी में सरकारी निवेश के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निर्णय लेना जैसे कि पूंजी पुनर्संरचना, बोनस, लाभांश, सरकारी इक्विटी का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दे।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय पुनर्संरचना के मामलों में तथा पूंजी बाजार के माध्यम से उक्त उद्यमों में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना।

5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) से संबंधित विषय।

II. दृष्टिकोण

(i) विनिवेश के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की समृद्धि में हिस्सेदारी के लिए उनमें जनस्वामित्व को बढ़ावा देना।

(ii) आर्थिक विकास में तेजी लाने और उच्चतर व्यय हेतु सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सीपीएसई में सरकारी निवेश का दक्ष प्रबंधन।

III. लक्ष्य

(i) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध करना ताकि सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से जन-स्वामित्व को बढ़ावा

मिल सके और अपने शेयरधारकों के प्रति जवाबदेही के माध्यम से सीपीएसई की दक्षता में सुधार हो सके।

(ii) रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से सीपीएसई में संचालनात्मक दक्षता लाना ताकि अर्थव्यवस्था में उनका अधिक योगदान सुनिश्चित हो सके।

(iii) राष्ट्रीय हित में सीपीएसई के वित्तीय प्रबंधन और सीपीएसई के स्वामित्व में सार्वजनिक भागीदारी में विस्तार पर लक्षित विनिवेश हेतु एक पेशेवर दृष्टिकोण अपनाना।

IV. संगठनात्मक ढांचा

इस समय निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के मुखिया सचिव, डॉ. अरुणीश चावला हैं। उनकी सहायता दो अपर सचिव, दो संयुक्त सचिवों, एक आर्थिक सलाहकार और एक सलाहकार (लागत) द्वारा की जाती है। विभाग डेस्क अधिकारी पद्धति पर कार्य करता है और सौंपा गया कार्य संयुक्त सचिव, निदेशक/उप सचिव और अवर सचिव स्तरों पर किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-II में दिया गया है।

V. सीपीएसई के विनिवेश से संबंधित मौजूदा नीति

सरकार सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश नीति को लागू करती है।

(i) अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री

कुछ सीपीएसई में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना सेबी द्वारा अनुमोदित पद्धतियों जैसे कि आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ), बिक्री की पेशकश (ओएफएस), शेयरों की वापस खरीद आदि के माध्यम से मूल्य को निर्मुक्त करने, जन स्वामित्व को बढ़ावा देने, सेबी की न्यूनतम जन शेयरधारिता की शर्त को पूरा करने और उच्च स्तर की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। ये पद्धतियां (i) अच्छा प्रदर्शन करने वाले सीपीएसई की खरीद-फरोक्त में वृद्धि (ii) शेयरों और बॉण्डों के विस्तारित दायरे में भागीदारी के लिए फुटकर निवेशकों को अवसर प्रदान करने और (iii) बाजार की तरलता और गहनता में वृद्धि के माध्यम से पूंजी बाजार को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

(ii) रणनीतिक विनिवेश

"रणनीतिक विनिवेश" का आशय प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ किसी सीपीएसई में सरकारी शेयरधारिता के संपूर्ण या पर्याप्त हिस्से की बिक्री से है। **निजीकरण** के मामले में, जो रणनीतिक विनिवेश का एक उप-समूह है, सीपीएसई में सरकारी इक्विटी और इसका प्रबंधन नियंत्रण एक निजी रणनीतिक खरीदार(रों) को हस्तांतरित कर दिया जाता है और रणनीतिक विनिवेश के अन्य मामलों में, सरकारी इक्विटी को नियंत्रण के साथ दूसरे सीपीएसई को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

रणनीतिक विनिवेश पर नीति इस मूल आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों में नहीं बने रहना चाहिए जिनमें प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बहुत पहले से आए हुए हैं और ऐसी कंपनियों की आर्थिक संभावना विभिन्न घटकों जैसे कि पूंजी लगाने, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा दक्ष प्रबंधन परिपाटियों के कारण रणनीतिक निवेशक के हाथों में संभवतः बेहतर अन्वेषित होगी।

नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश हेतु सीपीएसई की पहचान करने के लिए अधिदेशित किया गया था। फरवरी, 2021 तक नीति आयोग ने रणनीतिक विनिवेश हेतु सीपीएसई की पहचान (i) राष्ट्रीय सुरक्षा; (ii) अप्रत्यक्ष तौर पर शासकीय कार्य; और (iii) बाजार का अभाव तथा सार्वजनिक उद्देश्य के मापदंडों के आधार पर की है।

निजीकरण/रणनीतिक विनिवेश हेतु खुली, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया

प्रक्रिया को परिणामोन्मुखी और तीव्र बनाने के लिए रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया को संशोधित भी किया गया है। नई क्रियाविधि में समग्र प्रक्रिया को चलाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की व्यवस्था है जिसके अध्यक्ष सचिव, दीपम एवं सचिव, प्रशासनिक मंत्रालय हैं, जो सीपीएसई के प्रदर्शन और बोलीदाताओं के रुझान को कम होने से रोकने के लिए अतिरिक्त और अनुमोदन की बहुलता को कम करते हुए पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। समग्र प्रक्रिया का निरीक्षण स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) द्वारा भी किया जाता है।

नई पीएसई नीति

आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ("पीएसई") संबंधी नई नीति मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2021 को अनुमोदित की गई थी और दिनांक 04 फरवरी, 2021 को अधिसूचित की गई थी। नीति का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यापारिक उद्यमों में सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को पुनः परिभाषित करना और सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ("पीएसई") संबंधी नई नीति के तहत, सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना, वित्तीय सेवाओं के प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मापदंडों के आधार पर मोटे तौर पर निम्नलिखित चार रणनीतिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है :

- ✓ परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा;
- ✓ परिवहन और दूरसंचार;
- ✓ विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज; और
- ✓ बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएँ।

रणनीतिक क्षेत्रों में, नियंत्रित कंपनी के स्तर पर मौजूदा सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की केवल न्यूनतम उपस्थिति सरकारी नियंत्रण में

बनाए रखी जाएगी। रणनीतिक क्षेत्र के शेष उद्यमों, के निजीकरण या किसी अन्य पीएसई के साथ विलय/ उसकी सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाएगा।

गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में, जहां व्यवहार्य हो, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण पर विचार किया जाएगा, अन्यथा ऐसे उद्यम को बंद करने के लिए विचार किया जाएगा।

किसी विशिष्ट पीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार का अनुमोदन समय-समय पर, मामला-दर-मामला आधार पर प्राप्त किया जाएगा। विशिष्ट सौदों का समय, हालांकि अन्य बातों के साथ, उपयुक्त अनुक्रमण, क्षेत्रीय प्रवृत्तियों, प्रशासनिक व्यवहार्यता, निवेशकों के रुझान आदि पर निर्भर करेगा।

यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के कुछ वर्गों पर लागू नहीं होती है, जैसे गैर-लाभकारी कंपनियाँ, या सीपीएसई जो कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करते हैं या विकासात्मक/संवर्धन संबंधी भूमिकाएँ निभाते हैं, इत्यादि।

नई नीति की पहल

रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया को समय-समय पर संशोधित किया जाता है ताकि इसे अधिक परिणामोन्मुखी बनाया जा सके और नई चुनौतियों का सामना किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए, मंत्रिमंडल ने वर्ष 2022-23 के दौरान वैकल्पिक तंत्र को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की। इसी तरह, मंत्रिमंडल ने दिनांक 18.05.2022 को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) के निदेशक मंडल को विनिवेश (रणनीतिक विनिवेश और अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री दोनों) करने या उनकी कुछ सहायक कंपनियों या इकाइयों के बंदीकरण या संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री की अनुशंसा करने के लिए शक्ति-संपन्न बनाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया। यह भी अनुमोदित किया गया कि सीपीएसई के बोर्ड और प्रशासनिक मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर, दीपम वैकल्पिक तंत्र का "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसके बाद, सीपीएसई का बोर्ड दीपम या लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के आधार पर सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के विनिवेश या बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

दीपम द्वारा दिनांक 14.09.2022 को नियंत्रित/मूल पीएसई द्वारा रणनीतिक विनिवेश/सहायक कंपनियों/इकाइयों की अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए दिशानिर्देशों सिद्धांत जारी किए गए थे। डीपीई द्वारा दिनांक 31.10.2022 को नियंत्रित/मूल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने के लिए दिशानिर्देश सिद्धांत जारी किए गए थे। इसके अलावा, दीपम ने नीति आयोग के परामर्श से दिनांक 23.08.2023 को प्रशासनिक मंत्रालयों को सीपीएसई द्वारा संयुक्त उद्यमों, सहायक इकाइयों, एसपीवी आदि बनाने से जुड़े प्रस्तावों की जांच के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

VI. सीपीएसई में मूल्य सृजन

सरकार ने अब सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के संपूर्णतावादी दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है जो मौजूदा नीति (अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री और रणनीतिक विनिवेश) के अनुसार सरकार (और सूचीबद्ध कंपनियों में अल्पांश शेयरधारकों) के लिए प्राप्ति को इष्टतम और सीपीएसई का विनिवेश करने के लिए सीपीएसई में मूल्य सृजन और मूल्य निर्मुक्त करने के उद्देश्यों को संतुलित करता है। इस रणनीति के एक भाग के रूप में, सीपीएसई को स्वयं के लिए, इसके कर्मचारियों, शेयरधारकों और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य सृजन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। निम्नलिखित पहलुओं को महत्व दिया गया है।

(i) **सीपीएसई के प्रदर्शन को बढ़ाना:** सीपीएसई के लिए वार्षिक समझौता ज्ञापन ढांचे में कई प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल किए गए हैं, जिनके आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों में पूंजीगतव्यय, निवल मूल्य पर प्राप्ति या नियोजित पूंजी पर प्राप्ति, राजस्व के % के रूप में निर्यात और आयात, राजस्व के % के रूप में ब्याज, कर, मूल्यहास, और परिशोधन से पहले अर्थागम (EBIDTA) और परिसंपत्ति कुल-कारोबार अनुपात शामिल हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए समझौता ज्ञापन ढांचे में सूचीबद्ध सीपीएसई हेतु शेयरधारकों को कुल प्राप्ति (सीपीएसई की बाजार पूंजी बनाम क्षेत्रीय सूचकांक की बाजार पूंजी, पूंजी प्रबंधन दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश भुगतान आदि के आधार पर) जैसे बाजार से संबंधित मापदंड भी शामिल किए गए हैं। यह बाजार में इन कंपनियों के मूल्य को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

(ii) **पूंजीगतव्यय पर ध्यान:** सीपीएसई को अपने कारोबार में लाभदायक वृद्धि हासिल करने के लिए पूंजीगतव्यय वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए, सीपीएसई, बिना बजटीय सहायता के अपने स्वयं के संसाधनों से सालाना 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश करते हैं। इतना बड़ा पूंजीगतव्यय विकास के अवसर और रोजगार के अवसर का सृजन करता है।

(iii) **पूंजी प्रबंधन दिशानिर्देश:** यह दिशानिर्देश सुसंगत लाभांश नीति और अन्य पूंजी प्रबंधन उपाय जैसे कि वापस खरीद, बोनस, स्टॉक स्प्लिट आदि सुनिश्चित करते हैं। बाजार वास्तविकताओं और सीपीएसई की अपेक्षितताओं के साथ नीति को अनुरूप बनाने हेतु सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्संरचना पर संशोधित दिशानिर्देशों को दिनांक 18.11.2024 को जारी किया गया है।

(iv) **सीपीएसई की संपर्क रणनीति पर ध्यान:** सीपीएसई को अन्य पूंजी बाजार प्रतिभागियों के साथ व्यापक और बारंबार बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बाजार प्रतिभागियों के साथ व्यवसाय के बारे में बेहतर संसूचना सीपीएसई को अपने भविष्य के विकास और रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए धन जुटाने में सहायता करता है।

(v) **अंशशोधित (कैलिब्रेटेड) विनिवेश रणनीति:** कंपनियों के सूचीकरण/आरंभिक सार्वजनिक पेशकश और अल्पांश शेयरधारकों के हितों

के अनुरूप शेयर बाजार के माध्यम से अल्पांश हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करके अंशशोधित (कैलिब्रेटेड) विनिवेश रणनीति का पालन किया जा रहा है। इस अंशशोधित (कैलिब्रेटेड) रणनीति ने सीपीएसई को अपनी दक्षता और विकास में सुधार करने और पूंजी बाजार में महत्वपूर्ण सहभागी बनने में सक्षम बनाया है। अंशशोधित विनिवेश नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि जब भी सौदे किए जाएं, तो बाजार में विघटन पैदा न हो और समग्र बाजार दिशा के अनुरूप बना रहे। इससे सीपीएसई के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिससे शेयरधारकों की प्राप्ति बढ़ी है।

ऊपर उद्धृत उपायों के माध्यम से मूल्य-सृजन और मूल्य निर्मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करने से पिछले कुछ वर्षों में बाजार पूंजी और सीपीएसई शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे इन शेयरों के धारक निवेशकों की प्राप्ति में वृद्धि हुई है। सूचीबद्ध सीपीएसई की कुल बाजार पूंजी पिछले तीन वर्षों में लगभग 3.3x बढ़कर 12.10 लाख करोड़ रुपये (31.03.2021) से 40.07 लाख करोड़ रुपये (23.12.2025) हो गई है। सूचीबद्ध सीपीएसई में भारत सरकार की इक्विटी की बाजार पूंजी भी पिछले चार वर्षों में 6.91 लाख करोड़ रुपये (31.03.2021) से 3.6x बढ़कर 25.11 लाख करोड़ रुपये (23.12.2025) हो गई है। इसी प्रकार, पिछले 4 वर्षों के दौरान, सीपीएसई सूचकांक ने स्टॉक मार्केट में बेन्चमार्क सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन (प्रतिशत वृद्धि के संदर्भ में) किया है।

वर्ष	सेनसेक्स	बीएसई सीपीएसई	निफ्टी-50	निफ्टी सीपीएसई
पिछले 2 वर्ष	15.24%	24.04%	17.53%	30.45%
पिछले 3 वर्ष	38.78%	120.19%	43.30%	133.40%
पिछले 4 वर्ष	36.57%	137.24%	40.94%	165.70%

दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार

VII. विनिवेश कार्य निष्पादन

अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री

i. आरंभिक/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश आईपीओ/एफपीओ

(क) **आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ):** जब कोई असूचीबद्ध कंपनी पहली बार आम जनता को शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम या बिक्री के लिए अपने मौजूदा शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की पेशकश या दोनों करती है तो यह आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहलाती है। इससे निर्गमकर्ता के शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और खरीद-फरोख्त का रास्ता साफ हो जाता है।

(ख) **अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ):** जब पहले से ही सूचीबद्ध कोई कंपनी आम जनता को शेयरों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का नया निर्गम या आम जनता को बिक्री की पेशकश करती है तो यह अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश कहलाती है।

उपलब्धियां: वर्ष 2014-15 से, 18 केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (भारतीय जीवन बीमा निगम सहित) को सूचीबद्ध किया गया है जिनसे 51,244.10 करोड़ रु. की प्राप्ति हुई। इस अवधि के दौरान 75.91 लाख खुदरा निवेशकों ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के आईपीओ में 16,564.36 करोड़ रु. की राशि निवेश की। नए सूचीकरण के माध्यम से 7.47 लाख करोड़ रु. (सूचीकरण मूल्य के आधार पर परिकलित बाजार पूंजीकरण) की अतिरिक्त बाजार पूंजी प्राप्त की गई। वर्तमान में, दिनांक 13.01.2026 की स्थिति के अनुसार 40.64 लाख करोड़ रु. की कुल बाजार पूंजी के साथ 67 सीपीएसई सूचीबद्ध हैं (इनमें सरकारी क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनियां शामिल नहीं हैं)। दिनांक 13.01.2026 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 16 बैंकों और बीमा कंपनियों की कुल बाजार पूंजी 25.87 लाख करोड़ रु. है।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक इकाई है, सूचीबद्ध हो चुकी है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक अन्य सहायक इकाई नामतः केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) के सूचीबद्ध होने की संभावना है।

ii. शेयरों की वापसखरीद

वापसखरीद किसी कंपनी द्वारा मौजूदा शेयरधारकों से अपने शेयरों की पुनः खरीद होती है जिससे खुले बाजार में उसके शेयरों की संख्या में कमी आ जाती है।

कंपनियां अपने शेयरों की वापसखरीद करती हैं :

- (क) प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए।
- (ख) उन अल्पांश शेयरधारकों की ओर से किसी खतरे को कम करने के लिए, जो नियंत्रक हिस्सेदारी की प्रत्याशा करते हैं।
- (ग) सीपीएसई के लिए, वापसखरीद भारत सरकार के लिए सीपीएसई में भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी का विनिवेश करने और सीपीएसई के पास पड़ी बेकार धनराशि का उपयुक्त उपयोग करने का एक साधन है।

दीपम द्वारा दिनांक 18.11.2024 को सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्संरचना के लिए जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीएसई, जिनके शेयर का बाजार मूल्य पिछले छह महीनों से लगातार बही मूल्य से कम है, और कम से कम 3000 करोड़ रुपए का निवल मूल्य और 1500 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और बैंक शेष है, वे अपने शेयरों को वापस-खरीदने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि अतिरिक्त नकदी वाले, लेकिन कोई प्रतिबद्ध व्यय न करने वाले सीपीएसई के लिए वापसखरीद वाछनीय नहीं मानी जाती है, तो कंपनी शेयरधारकों को उच्चतर या विशेष लाभ देने पर विचार कर सकती है।

उपलब्धियां: सीपीएसई के पास बेकार पड़ी नकद धनराशि का उपयोग करने और प्रति शेयर अर्जन में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने वापसखरीद

पद्धति का प्रभावी रूप से उपयोग किया है। पिछले आठ वर्षों के दौरान, 45 सीपीएसई द्वारा शेयरों की वापसखरीद से 45,104 करोड़ रुपये का विनिवेश अर्थागम प्राप्त किया गया।

iii. बिक्री की पेशकश (ओएफएस)

बिक्री की पेशकश (ओएफएस) सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफार्म के माध्यम से शेयरों की बिक्री की एक सरल पद्धति है। इस तंत्र को सेबी द्वारा वर्ष 2012 में पहली बार लागू किया गया ताकि सार्वजनिक तौर पर खरीद-फरोख्त करने वाली कंपनियों के प्रवर्तकों को अपनी धारिता कम करने और जून, 2013 तक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मापदंडों का अनुपालन करने में आसानी हो। इस पद्धति को सूचीबद्ध कंपनियों, राष्ट्र संचालित और निजी, दोनों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया गया ताकि सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के मापदंडों का अनुपालन किया जा सके। सरकार ने सीपीएसई में अपनी शेयरधारिता के विनिवेश के लिए प्रायः इस माध्यम का उपयोग किया।

ओएफएस की मुख्य विशेषताएं :

- ✓ निष्पादन में सरल
- ✓ बाजार संचालित
- ✓ प्रबंधन नियंत्रण सरकार के पास बने रहना
- ✓ लागत प्रभावी
- ✓ समयबद्ध (2 व्यापारिक दिवसों में संपन्न)
- ✓ मूल्य-समता आधार पर पारदर्शी आबंटन

उपलब्धियां : पिछले 10+ वर्षों में (दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार) ओएफएस पद्धति द्वारा विनिवेश से विभिन्न सौदों के माध्यम से 1,42,488 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसमें जनवरी, 2015 में कोल इंडिया लिमिटेड के मामले में 22,000 करोड़ रुपये से अधिक का सबसे बड़ा ओएफएस शामिल था।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निम्न ओएफएस सौदे किए गए थे (दिनांक 17.02.2026 की स्थिति के अनुसार) :

(i) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल):

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर, वैकल्पिक तंत्र ने दिनांक 03.04.2025 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में सरकार की मौजूदा 84.83% शेयरधारिता में से प्रदत्त इक्विटी के 4.83% के बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश को अनुमोदन प्रदान किया। बिक्री की पेशकश दिनांक 04.04.2025 और 07.04.2025 को की गई थी। भारत सरकार ने बिक्री की पेशकश के ज़रिए कुल शेयरधारिता के 3.61% के विनिवेश से 3673.42 करोड़ रुपये अर्जित किए। विनिवेश के बाद, एमडीएल में भारत सरकार की शेयरधारिता 81.22% हो गई है।

(ii) बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (बीओएम):

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर, वैकल्पिक तंत्र ने दिनांक 01.12.2025 को बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र (बीओएम) में सरकार

की मौजूदा 79.6% शेयरधारिता में से प्रदत्त इक्विटी के 6% के बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश को अनुमोदन प्रदान किया। बिक्री की पेशकश दिनांक 02.12.2025 और 03.12.2025 को की गई थी। भारत सरकार को इस लेनदेन से 2624.24 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। विनिवेश के बाद, भारत सरकार की शेयरधारिता 73.6% है और बीओएम अब न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालक बन गया है।

(iii) इंडियन ओवरसीज बैंक

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर, वैकल्पिक तंत्र ने दिनांक 16.12.2025 को इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकार की मौजूदा 94.61% शेयरधारिता में से प्रदत्त इक्विटी के 3% (2% बेस और 1% ग्रीन शू विकल्प) के बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश को अनुमोदन प्रदान किया। बिक्री की पेशकश दिनांक 17.12.2025 और 18.12.2025 को की गई थी। भारत सरकार ने इस लेनदेन से 1419.36 करोड़ रुपये अर्जित किए। 2.17% के विनिवेश के बाद आईओबी में भारत सरकार की कुल शेयरधारिता 92.44% है।

iv. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर, वैकल्पिक तंत्र ने भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में सरकार की मौजूदा 63.17% शेयरधारिता में से प्रदत्त इक्विटी के बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से विनिवेश को अनुमोदन प्रदान किया। बिक्री की पेशकश दिनांक 11.02.2026-12.02.2026 को की गई थी। भारत सरकार ने इस लेनदेन से 4,464.91 करोड़ रुपये अर्जित किए। विनिवेश के बाद बीएचईएल में भारत सरकार की शेयरधारिता 58.17% है।

अन्य लेनदेन (2025-26) (दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार) एसयूयूटीआई से धनप्रेषण के रूप में 1,051.00 करोड़ रुपयों की प्राप्ति हुई।

दूरसंचार सुधार और सहायता पैकेज के तहत योग्य स्पेक्ट्रम किस्त को इक्विटी में बदलने के परिणामस्वरूप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) में भारत सरकार की इक्विटी धारिता बढ़कर 48.99% हो गई।

आईटीडीसी के इन होटलों/इकाइयों के लिए वैकल्पिक तंत्र (एएम) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है :

क) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएबीएचसीएल) – वैकल्पिक तंत्र ने जून, 2025 में आरएबीएचसीएल में आईटीडीसी की 51% शेयरधारिता झारखंड सरकार को ₹3.06 करोड़ के मूल्य अंकन पर बिक्री करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया।

ख) होटल जम्मू अशोक, जम्मू – वैकल्पिक तंत्र ने अगस्त, 2025 में ₹11.09 करोड़ के मूल्य अंकन पर होटल जम्मू अशोक, जम्मू को 'यथास्थिति, यथास्थान' के आधार पर जम्मू और कश्मीर सरकार को अंतरित करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया।

ग) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड (पीएचसीएल) – वैकल्पिक तंत्र ने सितंबर, 2025 में ₹79.39 लाख के मूल्य अंकन पर पीएचसीएल में आईटीडीसी की 51% इक्विटी पंजाब टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

(पीटीडीसी) को अंतरित करने को अनुमोदन प्रदान कर दिया।

वैकल्पिक तंत्र ने दिनांक 28.08.2025 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) की हिस्सेदारी को एक या अधिक खेपों में इसके संयुक्त उद्यम यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) में विनिवेश को दीपम के दिनांक 01.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/17/2021-दीपम-IIB(ई) के अनुसार अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) में अहर्ता प्राप्त संस्थागत नियुक्ति (क्यूआईपी) - वैकल्पिक तंत्र (एएम) ने इरेडा में भारत सरकार की शेयरधारिता को कम करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है, नई इक्विटी का निर्गम क्यूआईपी तरीके से इरेडा की 7% प्रदत्त इक्विटी की सीमा तक किया जाएगा। तदनुसार, इरेडा ने दिनांक 11.06.2025 को क्यूआईपी के माध्यम से 4.32% (नए निर्गम) का लेन-देन किया। क्यूआईपी के माध्यम से 2005.9 करोड़ रुपये जुटाए गए, जिसका इस्तेमाल सीपीएसई को मजबूत करने और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करने के लिए देश की क्षमता को और बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

वर्ष 2016-17 से सीपीएसई-ईटीएफ और भारत-22 ईटीएफ की विभिन्न पेशकशों के माध्यम से सरकार ने 98,949 करोड़ रु. की विनिवेश प्राप्तियां जुटाईं। तथापि, अब मौजूदा ईटीएफ विंडो के माध्यम से विनिवेश की सीमित संभावना है क्योंकि सीपीएसई-ईटीएफ और भारत-22 ईटीएफ में अनेक अंतर्निहित शेयर भारत सरकार की 51% इक्विटी के स्तर पर पहुंच गए हैं या ईटीएफ बास्केट में कुछ शेयर रणनीतिक विनिवेश या अन्य कारणों से विनिवेश हेतु आगे उपलब्ध नहीं हैं। इसके साथ-साथ यह समस्या भी है कि इक्विटी ईटीएफ की बड़ी और बारम्बार खेपों ने मूल्य गिरावट के कारण पीएसयू शेयरों में निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का काम किया है। इसलिए, सरकार ने अब अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के लिए एक साधन के रूप में इक्विटी ईटीएफ के उपयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

ख. रणनीतिक विनिवेश में कार्यनिष्पादन

सरकार ने वर्ष 2016 से, पीएसई और/या पीएसई की सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों/बैंकों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 36 मामलों में 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। इन मामलों में से, 12 सीपीएसई-रणनीतिक विनिवेश किया जा चुका है (लेनदेन संपन्न हो चुका है), 5 सीपीएसई-बंद किए जाने की सिफारिश की गई है, 3 सीपीएसई- लेनदेन सफल नहीं हुआ और रुचि की अभिव्यक्ति रद्द कर दी गई है, 2 सीपीएसई- लेनदेन आगे नहीं बढ़ाया गया (एएम ने अनुमोदन प्रदान नहीं किया), 6 सीपीएसई- दीपम लेनदेन की कार्रवाई कर रहा है, 4 सीपीएसई- लेनदेन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा संसाधित किया जा रहा है और 4 सीपीएसई- लेनदेन विफल हो गया, विलय/बंद करने/सहायक इकाई बनाने के लिए विचार किया जा रहा है। वितरण परिशिष्ट-1 पर दिया गया है।

ग. विनिवेश लक्ष्य और उपलब्धियां

वर्ष 2014-15 से, विभिन्न पद्धतियों/लिखतों का उपयोग करके विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 4,47,055 करोड़ रुपये (दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार) की धनराशि जुटाई गई। इसमें अल्पांश हिस्सेदारी की

बिक्री से प्राप्त 3,37,766 करोड़ रुपये, और 10 सीपीएसई में (एयर इंडिया और एनआईएनएल का निजीकरण कर दिया गया है और शेष 8 सीपीएसई में रणनीतिक विनिवेश सीपीएसई से सीपीएसई क्षेत्र में किया गया था) रणनीतिक विनिवेश सौदों से 69,412 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त धनराशि (69,412 करोड़ रुपये) में एनआईएनएल सौदे के लिए उद्यम मूल्य के रूप में प्राप्त 12,100 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं चूंकि भारत सरकार की केंद्र और राज्य पीएसई के इस संयुक्त उद्यम में कोई प्रत्यक्ष इक्विटी नहीं है। अन्य सौदों से 39,877 करोड़ रुपये का अर्थागम हुआ।

वर्ष 2014-15 से सरकार द्वारा निर्धारित विनिवेश लक्ष्यों/संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक विनिवेश का ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	लक्ष्य (संशोधित अनुमान)	वास्तविक
2014-15	26,353	24,349
2015-16	25,313	23,997
2016-17	45,500	46,247
2017-18	1,00,000	1,00,037
2018-19	80,000	84,972
2019-20	65,000	50,300
2020-21	32,000	32,886
2021-22	78,000	13,534
2022-23	50,000	35,294
2023-24	विनिवेश के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है	16,508
2024-25		10,164
2025-26 (*)		8,768
कुल		4,47,055

(*) दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार

विनिवेश एक सतत प्रक्रिया है, और विशेष सौदों का निष्पादन/संपन्न होना बाजार परिस्थितियों, घरेलू और वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, भू-राजनैतिक कारकों, निवेशक अभिरुचि और प्रशासनिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से विनिवेश के लिए कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है। तथापि, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) चरण में विविध पूंजीगत प्राप्ति के तहत 47,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसमें विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से इक्विटी निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए प्राप्त प्राप्ति शामिल हैं।

VIII. अन्य पहलकदमियां

(i) भारत बॉन्ड ईटीएफ की शुरुआत

एए रेडेड सीपीएसई वाले भारत बॉन्ड ईटीएफ को दिसंबर 2019 में शुरू किया गया था, जो अपनी तरह का पहला उच्च गुणवत्ता आधारित सार्वजनिक क्षेत्र का बॉन्ड था। दिसंबर, 2019 में शुरू किए गए भारत बॉन्ड ईटीएफ की खेप-I से 12,400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। भारत बॉन्ड ईटीएफ की खेप-II जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी जिससे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गए थे। दिसंबर, 2021 में खेप-III शुरू की गई थी जिससे 6,200 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। तीनों खेपों को निवेशकों के सभी वर्गों विशेषकर खुदरा निवेशकों से भारी प्रतिक्रिया मिली।

50000+ करोड़ रुपये के एयूएम के साथ तीन खेपों की सफल शुरुआत के बाद, भारत बॉन्ड ईटीएफ की चौथी खेप बीबीईटीएफ – 2033 जो 10+ वर्षों से अधिक में अप्रैल 2033 में परिपक्व होने वाली है, दिनांक 2 दिसंबर, 2022 को शुरू हुई और दिनांक 8 दिसंबर, 2022 को समाप्त हुई। भारत बॉन्ड ईटीएफ का अप्रैल 2033 का निर्गम 1,000 करोड़ रुपये के मूल निर्गम आकार के मुकाबले 2.8 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ है। 1000 करोड़ रुपए के मूल निर्गम आकार के मुकाबले कुल 2800 करोड़ रुपए जुटाए गए। 8 सीपीएसई नामतः पीएफसीएल, आईआरएफसी, आरईसी, नाबार्ड, हुडको, एनटीपीसी लिमिटेड, एचपीसीएल और एनपीसीआईएल ने इसमें भाग लिया और बॉन्ड जारी किए।

बॉन्ड ईटीएफ बाजार के लिए एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) बढ़कर 62,218 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार) हो गया है, जिसमें से लगभग 90% भारत बॉन्ड ईटीएफ (लगभग 56,064 करोड़ रुपये) के लिए है। इसने सीपीएसई को कम लागत पर ऋण जुटाने में मदद करते हुए खुदरा निवेशकों को कम राशि (1,000 रुपये जैसी न्यून) के साथ बॉन्ड तक पहुंच बनाने का अवसर प्रदान किया गया। इस मॉडल के आधार पर जी-सेक, स्टेट डेवलपमेंट लोन (एसडीएल) और कॉरपोरेट बॉन्ड पर आधारित कई बॉन्ड-ईटीएफ बाजार में आ गए हैं।

(ii) विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष (एसएनआईएफ)

एसआईएल को सूची से हटाने की पेशकश में, विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष (एसएनआईएफ) में रखे गए स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) के 33,61,461 शेयरों को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मार्च, 2024 में वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था, जिसके अनुसरण में दिनांक 8 अप्रैल, 2024 को एसएनआईएफ द्वारा धारित एसआईएल के ऐसे सभी शेयरों की निविदा जारी कर दी गई थी। इस लेन-देन के परिणामस्वरूप, दिनांक 2 मई, 2024 को 10.68 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। वर्ष 2021 में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (एसआईएल) को बंद करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया था और अब 2024 में यह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध कर दी गई है।

(iii) शत्रु शेयरों का मुद्रीकरण

मंत्रिमंडल ने दिनांक 08 नवंबर, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में शत्रु शेयरों का निपटान करने हेतु प्रक्रिया और तंत्र को अनुमोदन प्रदान किया, इसे भी दीपम द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। सीईपीआई गृह

मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए शत्रु शेयरों के अनुसार, 99.4% से अधिक शेयरों की बिक्री कर दी गई है। आज की तारीख में (नवंबर, 2024), कुल 2740.81 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों की बिक्री की जा चुकी है और इससे प्राप्त अर्थागम भारत सरकार को प्राप्त हुआ है।

IX. पूंजी प्रबंधन एवं लाभांश प्राप्ति

सीपीएसई के पूंजी पुनर्गठन के लिए संशोधित दिशानिर्देश

दीपम ने दिनांक 18.11.2024 को माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से सीपीएसई के पूंजी पुनर्संरचना के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी शेयरधारकों के उचित परामर्श के बाद जारी किए गए ये दिशानिर्देश पूंजी बाजार की स्थितियों के विकास, विनियामक एवं क्षेत्रीय परिवर्तन, आदि को दर्शाते हैं। इन दिशानिर्देशों का मुख्य उद्देश्य सीपीएसई एवं शेयरधारकों की प्राप्ति में वृद्धि करना, देश के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए सीपीएसई को प्रचालनगत एवं वित्तीय लचीलापन प्रदान करते हुए उनके प्रदर्शन एवं क्षमता में सुधार करना है। यह व्यापक संशोधित दिशानिर्देश सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई को अनुपालन हेतु परिचालित कर दिए गए हैं।

लाभांश:

सीपीएसई से प्राप्त लाभांश गैर-कर प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है। वित्त वर्ष 2020-21 से लाभांशों से संबंधित कार्य आर्थिक कार्य विभाग से दीपम को अंतरित कर दिया गया था। तदनुसार, सीपीएसई के छूट प्रस्तावों सहित पूंजी प्रबंधन/पुनर्संरचना और लाभांश भुगतान के संबंध में विचार-विमर्श/अनुमोदन प्रदान करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति नामतः सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश निगरानी समिति (सीएमसीडीसी) बनाई गई है। कंपनियों द्वारा लाभांश भुगतान में पूर्वानुमान को सुनिश्चित करने के लिए दीपम ने (नवंबर, 2020 में) एक सुसंगत लाभांश नीति तैयार की है। एक पूर्वानुमानित लाभांश व्यवस्था निवेशकों की रुचि को पुनर्जिवित करने और सीपीएसई के शेयरों के लिए बाजार की धारणा में सुधार लाने में मदद करती है क्योंकि नियमित लाभांश भुगतान में पूर्वानुमान से सीपीएसई के शेयरों के लिए गुणी निवेशक आकर्षित होंगे और भावी लाभांश की आशा में उन्हें बनाए रखेंगे। सरकार को भी आंतरिक लाभांश के रूप में पूर्वानुमानित और आवधिक लाभांश प्राप्त होते रहेंगे। सीपीएससी से इस नीति की अनुपालना बढ़ रही है।

पिछले 3-4 वर्षों में सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के लिए सीपीएसई से लाभांश प्राप्ति का रूप में क्रमशः 59,533 करोड़ रुपये, 64,000 करोड़ रुपये और 74,129 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जबकि संशोधित अनुमान क्रमशः 43,000 करोड़ रुपये, 50,000 करोड़ रुपये और 55,000 करोड़ रुपये था।

चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, सरकार ने (दिनांक 14.01.2026 तक) 69,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (बीई) के मुकाबले 49,580.47 करोड़ रुपये का अर्थागम प्राप्त किया है।

X. दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए की गई पहल:

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के प्रतिनिधित्व के साथ विभाग के कर्मचारियों की संख्या अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

XI. जेण्डर बजटिंग और महिला सशक्तिकरण से संबंधित पहल

जहां तक महिलाओं के सशक्तिकरण का संबंध है, विभाग के आबंटित कार्य की प्रकृति में जेंडर बजटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है।

XII. राजभाषा नीति

राजभाषा नीति को लागू करने के लिए विभाग के पास एक संपूर्ण राजभाषा इकाई है। विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है। हिंदी अनुभाग (राजभाषा)-दीपम, ने वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया:

- अधिकारियों ने माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गांधीनगर में हिंदी दिवस और 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन (दिनांक 14-15 सितंबर 2025) में भाग लिया।
- हिंदी पखवाड़े (दिनांक 18-30 सितंबर 2025) में आशु-भाषण, निबंध लेखन, श्रुतलेख एवं शब्द ज्ञान और चित्र अभिव्यक्ति जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- प्रतियोगिता विजेताओं को नकद पुरस्कार (ई-भुगतान के माध्यम से) और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठक गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार तिमाही आधार पर आयोजित की जाती है।
- विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की बैठकें दिनांक 24 जून 2025 (प्रथम तिमाही) और दिनांक 29 सितंबर 2025 (द्वितीय तिमाही) को आयोजित की गईं।
- हिंदी में काम करने में कर्मचारियों के बीच झिझक को कम करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

XIII. ई-गवर्नेंस

सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सुशासन के भाग रूप में निम्नलिखित पहल की गई हैं:

- (i) विभाग की वेबसाइट (www.dipam.gov.in) को नियमित आधार पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अद्यतित किया जाता है। यह वेबसाइट भारतीय सरकारी वेबसाइट के दिशानिर्देशों (जीआईजीडब्ल्यू) का अनुपालन करती है।
- (ii) पे-रोल पैकेज का रख-रखाव
- (iii) ई-ऑफिस का कार्यान्वयन
- (iv) निम्नलिखित वेब आधारित निगरानी प्रणाली कार्यरत हैं:
 - राज्य सभा प्रश्न, उत्तर निगरानी प्रणाली

- केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस)
- केंद्रीकृत निविदा/प्रकयोरमेंट निगरानी प्रणाली। निविदाएं नियमित आधार पर वेबसाइट पर डाली जाती हैं और ई-प्रकयोरमेंट पोर्टल में ई-प्रकाशन नियमित आधार पर किया जाता है।
- भारत सरकार के पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की निगरानी प्रणाली (आरआरसीपीएस) (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग पोर्टल)
- आईएस अधिकारियों (संयुक्त सचिव स्तर एवं उससे ऊपर), सीएसएस/सीएसएसएस अधिकारियों (सभी स्तरों के) के लिए एपीआर निगरानी प्रणाली।

- (v) संवर्ग प्रबंधन प्रणाली (सीएसएस अधिकारियों के लिए)
- (vi) पेंशन पोर्टल
- (vii) जीईएम पोर्टल का उपयोग
- (viii) त्रै-मासिक रोलिंग प्लान
- (ix) डाटा पोर्टल (Data.gov.in)

XIV. लोक शिकायतों का निवारण

विभाग, केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) का उपयोग कर रहा है। विभाग की वेबसाइट में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने का एक अंतर्निर्मित तंत्र भी है। इस प्रयोजन हेतु एक संयुक्त सचिव को नोडल शिकायत अधिकारी और अपर सचिव को नोडल अपीलीय अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में आन्तरिक शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के संबंध में विशाखा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13 अगस्त, 1997 के निर्णय के अनुपालन में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में, महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में, राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से दिनांक 16 और 17 अक्तूबर 2025 को सभी कर्मचारियों के लिए दीपम में एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

XV. सतर्कता तंत्र

विभाग में एक अपर सचिव को अंश-कालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

XVI. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन सूचना के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं :

- (i) आरटीआई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदन एकत्रित करने, संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकरणों को आवेदन अंतरित करने और आरटीआई आवेदनों/अपीलों की प्राप्ति तथा निपटान का त्रैमासिक विवरण केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत करने के लिए एक आरटीआई कोष्ठ स्थापित किया गया है।
- (ii) सूचना का अधिकार अधिनियम के खण्ड 4(1) (बी) के अनुपालन में, विभाग के कार्यों के साथ-साथ उनके निष्पादकों से संबंधित विवरण विभाग की वेबसाइट (www.dipam.gov.in) पर प्रस्तुत किया गया है और इसको समय-समय पर अद्यतित किया जाता है।
- (iii) अधिनियम की धारा 5(1) के अधीन एक अवर सचिव को नोडल केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और 2 उप निदेशक, 2 सहायक निदेशक तथा 10 अवर सचिवों को, उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले मामलों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया है।
- (iv) 4 निदेशक, 2 संयुक्त निदेशक और 6 उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उनके प्रभाग से संबंधित सभी मामलों के लिए अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

XVII. बेहतर प्रशासन के लिए की गई पहल

भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 द्वारा प्रदान किए गए शासनादेश के अनुसार, विभाग किसी भी प्रकार की लोक सेवाएं प्रदान करने में शामिल नहीं होता और इस प्रकार इसका नागरिकों और बड़े पैमाने पर जनता के साथ सीधा संपर्क नहीं होता है। तथापि, विभाग ने बेहतर प्रशासन के भाग के रूप में निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

विलंब और भ्रष्टाचार की किसी गुंजाइश से बचने के लिए तथा बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए लेन-देन संबंधी बिलों के निपटान के लिए समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

XVIII. लेखापरीक्षा पैराग्राफ/आपत्तियां

छ: लेखा पैरा लंबित हैं। विवरण अनुबंध-III पर दिया गया है।

XIX. एकीकृत वित्त इकाई

एकीकृत वित्त इकाई, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (वित्त) के अधीन कार्य करती है तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की अनुदान संख्या - 34 के अधीन व्यय एवं बजट संबंधी उन प्रस्तावों पर कार्यवाही करती है, जिनमें सचिवालय सामान्य सेवाएं सम्मिलित हैं, जिनमें निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का स्थापना बजट शामिल होता है।

अनुदान संख्या 34 के अधीन बजटीय आबंटन निम्नानुसार हैं :-

(करोड़ रुपये में)

अनुदान संख्या	बजट अनुमान 2025-26		
	पूँजी	राजस्व	कुल
34-निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	1.70	55.43	57.13

एकीकृत वित्त इकाई विभाग के वित्तीय एवं व्यय संबंधी सभी प्रस्तावों, जैसे कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति, अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति/दौरों आदि पर निगरानी रखती है। विभाग की व्यय संबंधी प्रवृत्तियों की एकीकृत वित्त इकाई (आई एफ यू) द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाती है। वित्त संबंधी स्थायी समिति से संबंधित मुद्दों सहित बजट संबंधी सभी मामले इस इकाई के कार्यक्षेत्र में आते हैं।

XX. विशेष अभियान 5.0:

दीपम के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। चिन्हित श्रेणियों में लंबित अभिनिर्देशों के निपटान, फाइलों की समीक्षा करने/छंटाई करने, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष अभियान 5.0 को पूरे उत्साह के साथ चलाया गया।

इस अभियान के दौरान हुई प्रगति को 'एससीडीपीएम' पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड किया गया था एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया और लगभग सभी श्रेणियों में लंबिता न्यूनतम स्तर पर लाई गई।

XXI. न्यायलयी मुकदमों की निगरानी:

दीपम में न्यायलयी मुकदमों की निगरानी अब विधिक सूचना ब्रीफिंग प्रणाली 2.0 (एलआईएमबीएस 2.0) में की जाती है। एलआईएमबीएस पोर्टल में न्यायलयी मुकदमों की प्रविष्टि, अद्यतन करने और मामले अंतरित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रभाग के उप निदेशक/अवर सचिव/ उप सचिव स्तर के अधिकारियों को एलआईएमबीएस प्रयोगकर्ता पदनामित किया गया है। अतः एलआईएमबीएस पोर्टल के माध्यम से विभाग के प्रभागों में प्रयोगकर्ता स्तर पर लंबित न्यायालयी मुकदमों की स्थिति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

रणनीतिक विनिवेश लेनदेन की स्थिति

क. संपन्न लेन-देन

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)
2.	रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी)
3.	हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडिया) लिमिटेड
4.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)
5.	कामराजार पोर्ट लिमिटेड
6.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसी)
7.	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ)
8.	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (सब्सिडियरी) (जिसका नाम बदलकर केपीपीएल कर दिया गया है)
9.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)
10.	एयर इंडिया और उसकी सब्सिडियरी (एआई)
11.	नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)
12.	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

ख. सीपीएसई को बंद करने की सिफारिश की गई

क्र. सं.	पीएसई का नाम
13.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
14.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
15.	भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
16.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
17.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नयागांव यूनिट)

ग. लेनदेन विफल और ईओआई रद्द कर दिया गया:

क्र. सं.	पीएसई का नाम
18.	पवन हंस लिमिटेड
19.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20.	अलॉय स्टील प्लांट, दुर्गापुर; सलेम स्टील प्लांट; भद्रावती इस्पात संयंत्र - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां।

घ. लेनदेन को आगे नहीं बढ़ाया गया (एएम अनुमोदित नहीं हुआ):

क्र. सं.	पीएसई का नाम
21.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
22.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

ङ. दीपम द्वारा किए जा रहे लेन-देन

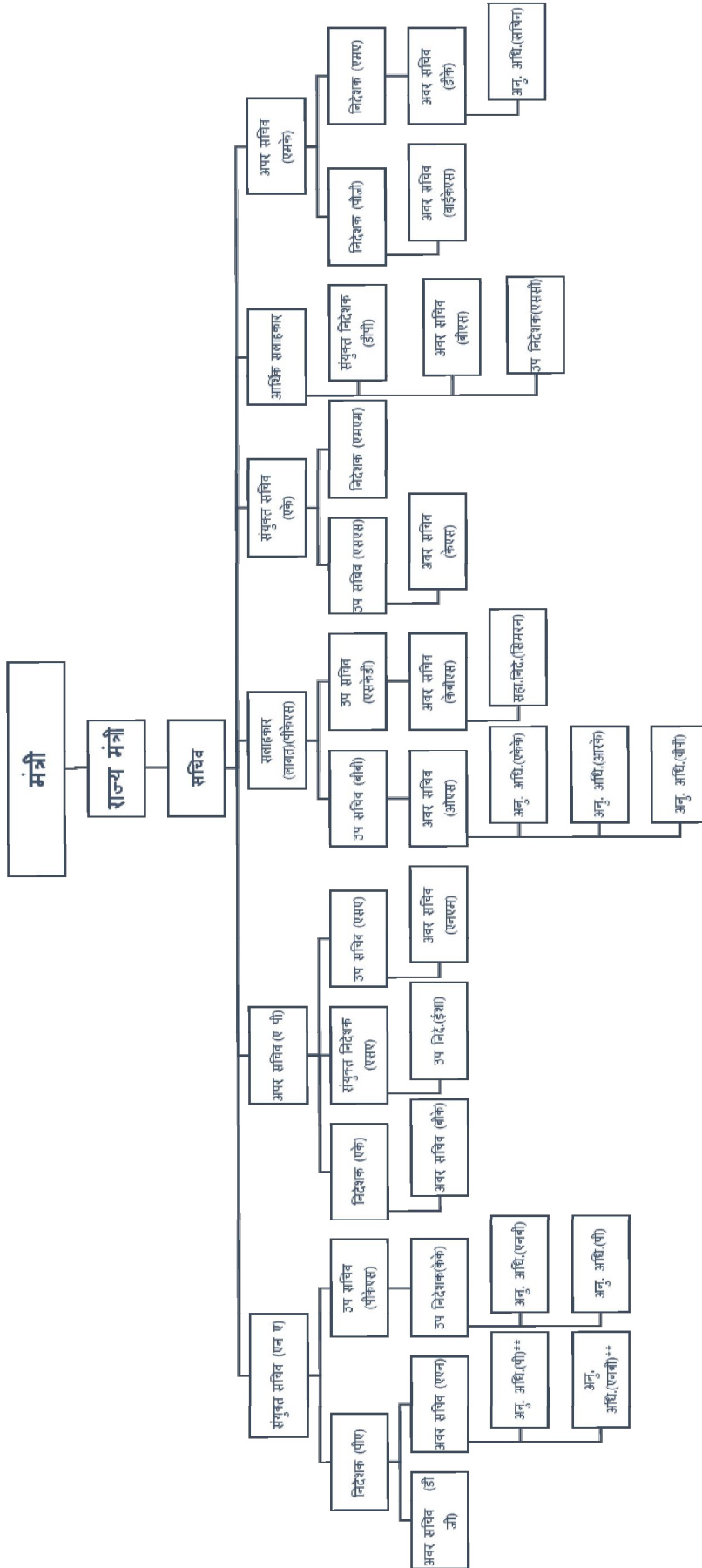
क्र. सं.	पीएसई का नाम
23.	आईडीबीआई बैंक
24.	इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)
25.	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल)
26.	बीईएमएल लिमिटेड
27.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
28.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

च. लेन-देन की प्रक्रिया संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जा रही है

क्र. सं.	पीएसई का नाम
29.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की विभिन्न इकाइयाँ
30.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (राज्य सरकार से विरोध)
31.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां (नकारात्मक निवल मूल्य)
32.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (प्रतिकूल न्यायिक आदेश)

छ. लेन-देन में विफलता होने से विलय/बंद/सहायक कंपनी बनाने हेतु विचाराधीन

क्र. सं.	पीएसई का नाम
33.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड
34.	ब्रिज एंज रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
35.	प्रोजेक्ट एंड डेवलेपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)
36.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)



(*) अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारी

अनुबंध- I

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या									
	(दिनांक 18.12.2025 की स्थिति के अनुसार)				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा		
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	39	8	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख	19	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग	14	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	72	18	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

अनुबंध- II

दीपम में विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती द्वारा								पदोन्नति							
	(दिनांक 18.12.2025 की स्थिति के अनुसार)				की गई आरक्षित नियुक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					रिक्तियों की संख्या आरक्षित नियुक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच		
क	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ख	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ग	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कुल	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल महत्वपूर्ण अवलोकन का सारांश

क्रम संख्या	वर्ष	पैरापीए रिपोर्ट का विवरण जिन पर एटीएन लंबित हैं			
		पैरापीए रिपोर्टों की संख्या, जिनमें लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षण के बाद एटीएन को पीएसी को प्रस्तुत किए गए हैं	मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए एटीएन की संख्या, जिन्हें भेजा गया है लेकिन टिप्पणियों के साथ लौटा दिया गया है और लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पुन प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है	एटीएन की संख्या, जिनकी अंतिम रूप से लेखा परीक्षा द्वारा जांच कर ली गई है लेकिन मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति को प्रस्तुत नहीं की गई है
1	2025		पैरा 4.2.2.3- (अनुबंध 4.6बी, क्रम संख्या 68) - मामूली शीर्ष/उप शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण बचत		
2	2025		पैरा 4.2.2.2 (अनुबंध 4.5, क्रम संख्या 25)- खंड स्तर पर महत्वपूर्ण बचत		
3	2021		पैरा संख्या 2.7.3 दीपम- शत्रु संपत्तियों की बिक्री से रसीद की गलत बुकिंग		
4	2021		पैरा संख्या 2.4.7 दीपम- यूटीआई के निर्दिष्ट उपक्रम की संपत्ति का उपचार		
5	2022		पैरा 3.3.1 (चित्र 3.4)- विभिन्न संस्थाओं में सरकारी निवेश-आंकड़ों का बेमेल		
6	2022		पैरा 3.8.3- यूटीआई (एसयूटीआई) के निर्दिष्ट उपक्रम की आय/प्राप्तियों का उपचार		

अध्याय - V

वित्तीय सेवाएं विभाग

1. वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत संगठन/संस्थान/विनियामक

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के कुल 105 संगठन आते हैं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ता, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान, विनियामक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डीआरटी/डीआरएटी, सरसाई, अभिरक्षक का कार्यालय, विशेष न्यायालय और परिसमापक न्यायालय का कार्यालय हैं। नीचे इन संगठनों का विवरण दिया गया है:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (12)

- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- केनरा बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- इंडियन बैंक
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र
- यूको बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- इण्डियन ओवरसीज बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता (7)

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
- भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)
- दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (यूआईआईसीएल)
- दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल)
- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल)
- एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीआईएल)

सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (7)

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)
- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)
- नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (नैबफीड)
- इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईएफसीआई)
- राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

विनियामक (3)

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (28)

- आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक
- अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
- असम ग्रामीण विकास बैंक
- बिहार ग्रामीण बैंक
- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
- गुजरात ग्रामीण बैंक
- सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक
- हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
- जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक
- झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक
- कर्नाटक ग्रामीण बैंक
- केरल ग्रामीण बैंक
- मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक

- महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
- मणिपुर ग्रामीण बैंक
- मेघालय ग्रामीण बैंक
- मिजोरम ग्रामीण बैंक
- नागालैंड ग्रामीण बैंक
- ओडिशा ग्राम्य बैंक
- पुडुचैर् भरतियार ग्राम बैंक
- पंजाब ग्रामीण बैंक
- राजस्थान ग्रामीण बैंक
- तमिलनाडु ग्राम बैंक
- तेलंगाना ग्रामीण बैंक
- त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक

डीआरटी (39)

- डीआरटी1-, अहमदाबाद
- डीआरटी2-, अहमदाबाद
- डीआरटी, इलाहाबाद
- डीआरटी, औरंगाबाद
- डीआरटी1-, बेंगलुरु
- डीआरटी2-, बेंगलुरु
- डीआरटी1-, चण्डीगढ़
- डीआरटी2-, चण्डीगढ़
- डीआरटी3-, चण्डीगढ़
- डीआरटी1-, चेन्नै
- डीआरटी2-, चेन्नै
- डीआरटी3-, चेन्नै
- डीआरटी, कोयम्बतूर
- डीआरटी, कटक

- डीआरटी1-, दिल्ली
- डीआरटी2-, दिल्ली
- डीआरटी3-, दिल्ली
- डीआरटी, देहरादून
- डीआरटी1-, एर्णाकुलम
- डीआरटी2-, एर्णाकुलम
- डीआरटी, गुवाहाटी
- डीआरटी1-, हैदराबाद
- डीआरटी2-, हैदराबाद
- डीआरटी, जबलपुर
- डीआरटी, जयपुर
- डीआरटी1-, कोलकाता
- डीआरटी2-, कोलकाता
- डीआरटी3-, कोलकाता
- डीआरटी, लखनऊ
- डीआरटी, मदुरै
- डीआरटी1-, मुम्बई
- डीआरटी2-, मुम्बई
- डीआरटी3-, मुम्बई
- डीआरटी, नागपुर
- डीआरटी, पटना
- डीआरटी, पुणे
- डीआरटी, रांची
- डीआरटी, सिलीगुड़ी
- डीआरटी, विशाखापटनम

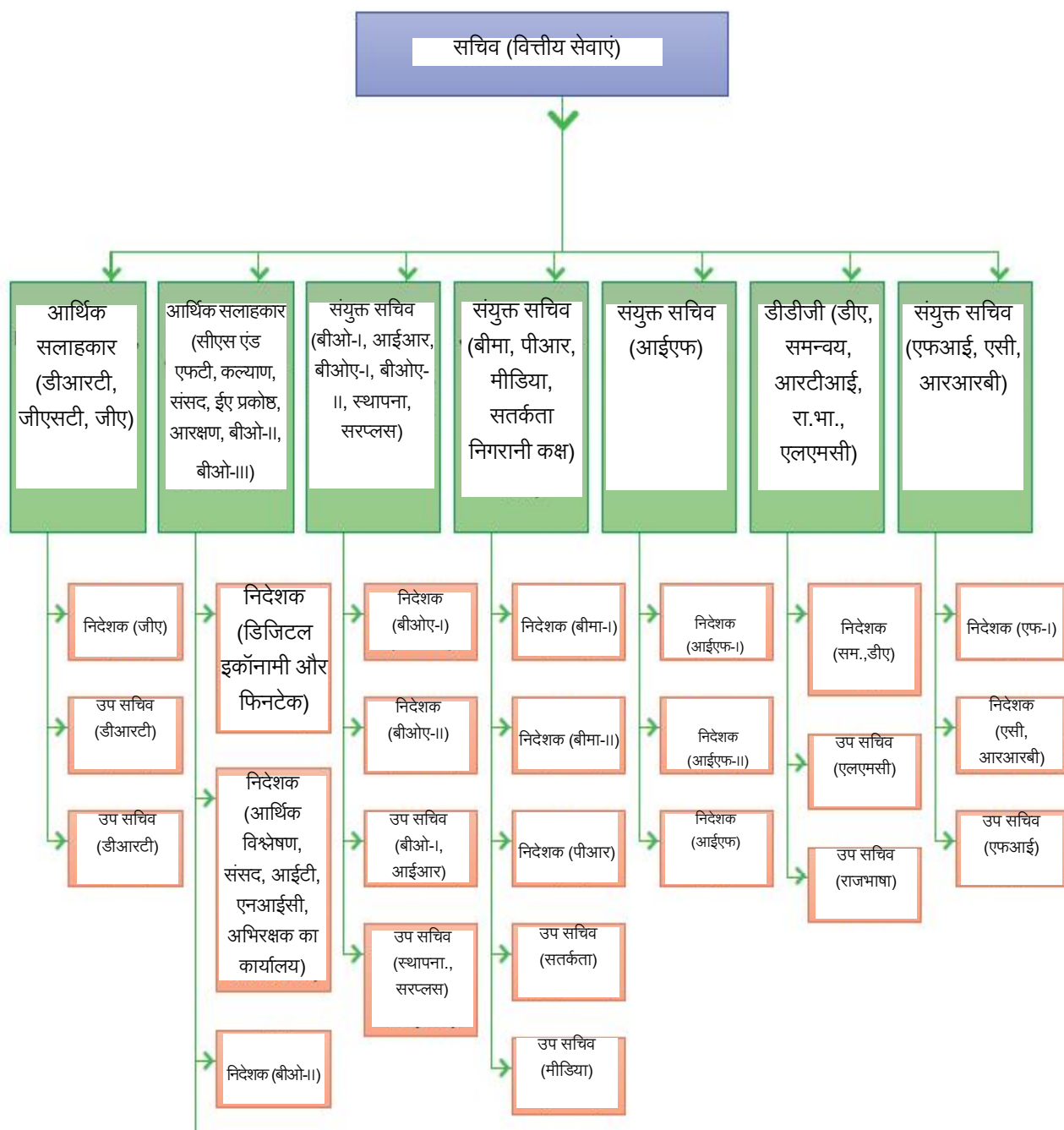
डीआरएटी

- डीआरएटी, इलाहाबाद
- डीआरएटी, चेन्नै
- डीआरएटी, दिल्ली
- डीआरएटी, कोलकाता
- डीआरएटी, मुम्बई

2. संगठनात्मक चार्ट

इस विभाग के प्रमुख सचिव (वित्तीय सेवाएं) हैं जिनकी सहायता

के लिए चार संयुक्त सचिव (जेएस), दो आर्थिक सलाहकार (ईए) और एक उप महानिदेशक (डीडीजी) हैं। विभाग के संगठनात्मक चार्ट को नीचे दर्शाया गया है:-



3. अनुभागों के बीच कार्य आबंटन

इस समय विभाग में निम्नलिखित अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं। उनका कार्य आबंटन निम्नानुसार है:

बैंकिंग परिचालन-I (बीओ-I)

- भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निम्नलिखित पदों की नियुक्ति/नामांकन:
 - भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर/डिप्टी गवर्नर।
 - राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष।
 - भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक।
 - राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यकारी निदेशक।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक।
 - राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक, कर्मकार और गैर-कर्मकार कर्मचारी निदेशक।
 - राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में सीए श्रेणी के निदेशक।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक/निदेशिका।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थानीय बोर्डों के सदस्य।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के मानव संसाधन संबंधी सभी मामले - जैसे वेतन, भत्ते और छुट्टी प्रबंधन, विदेश दौरे, वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का रखरखाव, सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार आदि सहित अन्य निबंधन और शर्तों का निर्धारण।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों की पेंशन नीति और संबंधित मुद्दे।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों/सदस्यों को बैठक संबंधी देय शुल्क।
- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना का अभिशासन, 1970/1980।
- कारपोरेट अभिशासन से संबंधित मामलों के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 का अभिशासन।

बैंकिंग परिचालन-II (बीओ-II)

- वित्तीय प्रणालियों से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों जैसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881, चिट फंड अधिनियम, 1982 तथा इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978, आदि, अविनियमित निक्षेप पाबंदी स्कीम अधिनियम, 2019
- निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961
- आपदा प्रबंधन और संकट प्रबंधन से संबंधित मामलों के कार्य का समन्वय
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- डिजीलॉकर से संबंधित मामलों, जिसमें बैंकों में खाताधारक के पते को अद्यतन किए जाने का प्रस्ताव है
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 9 के तहत प्राप्त अपीलों का निपटान
- फेक्ट्रिंग विनियमन अधिनियम, 2011
- राज्य कानून - जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के संबंध में राज्य सरकारों के अधिनियम
- बहु-स्तरीय विपणन और पोंजी योजनाओं से संबंधित मामले
- आईएफएससी -जीआईएफटी की स्थापना
- अंतर्राष्ट्रीय संबंध (बैंकिंग)/द्विपक्षीय मामले
- डब्ल्यूटीओ, आरसीईपी, जेसीसीआईआई और भारत के सीईपीए/सीईसीए/एफटीए में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद और इसकी उप-समितियों से संबंधित मामले
- केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीआईबी) से संबंधित मामले
- परिसमापक न्यायालय, कोलकाता के कार्यालय से संबंधित मामले
- सरकारी एजेंसी व्यवसाय से संबंधित कार्य
- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ)
- सीमावर्ती जिलों (अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 80 किमी. के भीतर) में बैंकों द्वारा करेंसी चेस्ट की स्थापना
- बैंक के अवकाश का युक्तिकरण/परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत बैंक अवकाशों की घोषणा
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) से संबंधित सभी मामले - एएमएल और सीएफटी मामले

बैंकिंग परिचालन-III (बीओ-III)

- बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों में ग्राहक सेवा
- इन संस्थानों में व्यक्तियों/संघों से उनकी शिकायतों के निवारण के लिए प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतों/अभ्यावेदन जैसे चेकों के भुगतान में देरी, ड्राफ्ट का भुगतान/जारी न किया जाना, डुप्लीकेट ड्राफ्ट जारी न करना/जारी करने में देरी किया जाना, संस्थान के कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार/गलत व्यवहार और परेशान किया जाना, मृतक के खातों का निपटान न किया जाना/निपटान में देरी, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में खातों का अंतरण न किया जाना/देरी किया जाना, नए खातों को न खोलना/खोलने में देरी किया जाना, ग्राहकों के स्थायी अनुदेशों का अनुपालन न किया जाना, परिपक्वता से पूर्व सावधि जमा राशियों का भुगतान न किया जाना, पेंशनभोगियों को भुगतान में देरी सहित क्रेडिट कार्ड, एटीएम आदि से संबंधित शिकायतें।
- सरकारी/निजी क्षेत्र/विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों के संबंध में डीएआरपीजी/डीपीजी से प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें
- सांसदों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों/पीएमओ से निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के विरुद्ध प्राप्त सभी प्रकार की शिकायतें
- बैंकिंग ग्राहक सेवा
- बैंकिंग लोकपाल
- प्रगति बैठकों का समन्वय

बैंकिंग परिचालन एवं लेखा-I (बीओए-I)

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कार्यप्रणाली के संबंध में वार्षिक समेकित समीक्षा तैयार करना तथा संसद के दोनों सदनों के पटल पर इन्हें प्रस्तुत करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा तथा अंतिम लेखा पद्धति
- पीएसबी बैंकों के कार्य परिणामों का अध्ययन तथा विश्लेषण
- पीएसबी/एफआई के कराधान संबंधी मामले
- पीएसबी द्वारा केन्द्रीय सरकार को अदा किया जाने वाला लाभांश
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा की जाने वाली पीएसबी की वार्षिक वित्तीय समीक्षाओं की संवीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई
- पीएसबी की पूंजीगत पुनर्संरचना (सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण बैंकों की पुनर्संरचना सहित) तथा शेयर पूंजी में सरकार का अंशदान, बैंकों का सार्वजनिक निर्गम
- यूएसएआईडी के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक को विदेशी सहायता अनुदान जारी करना

- पीएसबी के बीच एवं पीएसबी तथा अन्य सरकारी विभागों/सार्वजनिक उद्यमों (पीएसई) के बीच विवाद और मध्यस्थता
- पीएसबी में वकीलों की नियुक्ति
- गोवा में पुर्तगाली बैंकों के अवशिष्ट मामले
- बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों को खोला जाना एवं इन कार्यालयों को अन्यत्र स्थापित करना
- बैंकिंग परिचालन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, जैसे लाइसेंस प्रदान करना, समामेलन, पुनर्संरचना, अधिस्थगन निधि तथा निजी क्षेत्र के बैंकों का अधिग्रहण
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कार्यप्रणाली
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की विभिन्न धाराओं से छूट के संबंध में अधिसूचना तथा बीआर अधिनियम और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अंतर्गत अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा राज्य स्तरीय बैंकों से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों का अभिशासन
- पीएसबी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि संसद में प्रस्तुत करना

बैंकिंग परिचालन और लेखा-II (बीओए-II)

- ऋण सूचना कंपनियां (सीआईसी)
- सभी पीएसबी के एनपीए तथा समझौतों और एकबारगी निपटान (ओटीएस) सहित वसूली की निगरानी से संबंधित कार्य
- संसदीय कार्य, वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, उपर्युक्त कार्यों से संबंधित शिकायतें तथा अन्य मामले
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए गए राहत उपायों सहित एनपीए/दबावग्रस्त आस्तियों (क्षेत्र विशिष्ट दबाव से इतर) से संबंधित सभी मामले
- दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएसएफ)
- बैंकों की लेखापरीक्षा, पीएसबी/एफआई के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण
- पीएसबी द्वारा बैंक गारंटियां, साख पत्र तथा वचन/सुविधा पत्र तथा संबंधित शिकायतें
- पीएसबी/आरबीआई का नागरिक घोषणा-पत्र
- परिसरों का अधिग्रहण/पट्टे पर लेना/किराये पर लेना/खाली करना, सरकारी स्थान अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपदा अधिकारी
- भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन (आईडीसी तथा एफडीआई नीतिगत मामलों सहित)
- बैंकिंग क्षेत्र सुधार (ईज इंडेक्स तथा पीएसबी सुधार एजेंडा सहित)
- एनबीएफसी तथा एनबीएफसी के संबंध में अपीलीय प्राधिकरण
- धोखाधड़ियों तथा भगोड़ा अपराधियों सहित परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन (साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल भुगतान सुरक्षा से इतर)

- एनबीएफसी तथा सीआईसी से संबंधित सभी अधिनियमों/विनियमों/नियमों का अभिशासन
- आशय विवरण/पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन संबंधी प्रमुख निष्पादन संसूचकों/कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी)
- भारतीय बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाएँ

औद्योगिक संबंध (आईआर)

- आईडीबीआई/आरबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवा संबंधी मामले
- औद्योगिक विवाद अधिनियम के मामले, पीएसबी और आरबीआई यूनियनों और बैंकिंग उद्योग में संघों से संबंधित मानव संसाधन मामले, बैंकों में स्थानांतरण, पदोन्नति और मानव संसाधन विकास की नीति के द्विपक्षीय समझौते
- बैंक कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में आईबी रिपोर्ट
- विदेशों में स्थित शाखाओं में बैंक कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते
- मानव संसाधन सुधार

कृषि ऋण (एसी)

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण प्रवाह
- कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008
- नाबार्ड से संबंधित मामले (नाबार्ड के पेंशन मामले सहित), कृषि वित्त निगम (सेवा मामलों को छोड़कर), इस विषय पर राज्य विधान, सहकारी बैंक (शहरी सहकारी बैंकों सहित), ग्रामीण/कृषि ऋण से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपील, प्राकृतिक आपदाओं, दंगा उपद्रवों इत्यादि से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। केवीआईसी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बैंक ऋण
- नाबार्ड का नागरिक चार्टर
- नाबार्ड के सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना
- आरबीआई द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने के विरुद्ध शहरी सहकारी बैंकों द्वारा की गई अपील के संबंध में नामोदिष्ट अपीलीय प्राधिकारी को सचिवालय सहायता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 से संबंधित विधायी मामले और इसके अंतर्गत नियम बनाना
- आरआरबी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करना, अध्यक्ष की नियुक्ति, आरआरबी की अनुशंसा, आरआरबी के कार्यनिष्पादन की समीक्षा, वेतन संशोधन, जनशक्ति योजना

- समीक्षा के साथ-साथ सभी आरआरबी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
- आरआरबी के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कर्मचारी सेवा विनियम तथा पदोन्नति नियमावली तैयार करना, आरआरबी के आईआर मामले
- आरआरबी का नागरिक चार्टर
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, सूक्ष्म वित्त तथा इससे संबंधित अन्य मामले, जिनमें अजा/अजजा सहित कमजोर वर्गों को उधार देना शामिल है, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों को ऋण, सचर समिति द्वारा अनुशंसा किए गए कतिपय मापदंडों पर अनुवर्ती कार्रवाई, डीआरआई योजना।

बीमा-I

- कॉरपोरेट अभिशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं तथा एआईसीआईएल, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमांकक संस्थान परिषद, बीमा लोकपाल, बीमा लोकपाल परिषद में नियुक्ति तथा सेवा संबंधी मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों की भर्ती और नियम एवं शर्तें और बैंक बोर्ड ब्यूरो के संबंध में बीमा से संबंधित नियुक्ति के मामले, बीमांकक अधिनियम, 2006 का अभिशासन तथा संबंधित मामले
- सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 से संबंधित सार्वजनिक संस्थाओं के मामले
- संसदीय, लेखापरीक्षा, सूचना का अधिकार, न्यायालय, मध्यस्थता तथा वीआईपी संदर्भ से संबंधित मामले और ऊपर उल्लिखित मदों तथा उनसे संबंधित किसी मामले के संबंध में आवतियों अथवा अन्य रूप में संदर्भित मामले

बीमा-II

- बीमा अधिनियम, 1938; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956; साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 का अभिशासन तथा इनसे संबंधित कॉरपोरेट अभिशासन से इतर अन्य मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों की भर्ती एवं सेवा शर्तों से संबंधित नियुक्ति तथा सेवा संबंधी मामले
- बीमा से संबंधित नीतिगत मामले, और इसके लिए, उक्त अधिनियमों द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित बीमा क्षेत्र और विभिन्न निकायों के रुझानों और प्रगति तथा कार्यनिष्पादन का विश्लेषण
- सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एआईसीआईएल) के संबंध में अभिशासन, नियुक्ति तथा सेवा मामलों से इतर प्रशासनिक मामले

- पूंजी आवश्यकता, लाभांश भुगतान तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों तथा एआईसीआईएल के कार्यनिष्पादन का आकलन
- बीमा सुरक्षा के संबंध में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं तथा सरकार द्वारा प्रायोजित/समर्थित अन्य बीमा योजनाएं
- कॉरपोरेट अभिशासन से इतर बीमा लोकपाल नियम और इसका प्रशासन, बीमा लोकपाल और बीमा लोकपाल परिसर के संबंध में नियुक्ति तथा सेवा संबंधी मामले
- बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश
- बीमा में प्रौद्योगिकी अपनाने सहित (साइबर सुरक्षा और फिनटेक अनुभाग को आवंटित मामलों के अलावा) इस क्षेत्र में तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में सुधार
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बीमा संबंधी पहलु के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कार्य में अनुभाग प्रभारी की सहायता करना
- बीमा क्षेत्र से संबंधित कराधान के मामले
- औद्योगिक निकायों/संघों द्वारा उठाए गए मामलों सहित उद्योग से संबंधित मामले
- विधि आयोग की रिपोर्टों को लागू करना
- बीमा से संबंधित सभी अवशिष्ट मामले जिन्हें बीमा-I अनुभाग और बीमा-II अनुभाग को आवंटित कार्यों की सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो
- संसदीय मामले, लेखापरीक्षा से संबंधित मामले, सूचना का अधिकार, न्यायालय, मध्यस्थता, वीआईपी संदर्भ से संबंधित मामले और ऊपर उल्लिखित मदों तथा उनसे संबंधित किसी मामले के संबंध में आवतियां अथवा अन्य रूप में संदर्भित मामले

वित्तीय समावेशन (एफआई)

- वित्तीय सेवाएं विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की निगरानी सहित इससे संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एनएमएफआई):
- (1) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) (नीति तथा कार्यान्वयन)
- (2) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) (केवल कार्यान्वयन)
- (3) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (केवल कार्यान्वयन)
- (4) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (नीति तथा कार्यान्वयन)

(5) स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई) (नीति तथा कार्यान्वयन)

- वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य, वित्तीय समावेशन के संबंध में अन्य अनुभागों, कार्यालयों, संस्थानों आदि के साथ समन्वय
- बैंकों का शाखा विस्तार
- अग्रणी बैंक योजना और सेवा क्षेत्र पद्धति
- जिला और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)
- बैंकिंग नेटवर्क का क्षेत्रीय असंतुलन, व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधा प्रदाता, मोबाइल बैंकिंग आदि से संबंधित मामले
- बैंकिंग टच प्वाइंट/बीसी/एटीएम लगाना तथा जन-धन दर्शक ऐप (जेडीडी) से संबंधित मामले
- बीसी के कार्यकलापों की निगरानी सहित इनसे संबंधित मामले
- न्यूनतम शेष जमा राशि, नकदी परिचालन और डिजिटल भुगतान प्रभार से संबंधित मामले
- मिशन कार्यालय से संबंधित प्रशासनिक मामले
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के संबंध में बैंकिंग मामले, मिशन कार्यालय
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) तथा अन्य भुगतान बैंक से संबंधित मामले
- अंतर राज्यीय क्षेत्रीय परिषद बैठक
- आकांक्षी जिले सरकार द्वारा एलडब्ल्यूई तथा वित्तीय समावेशन के लिए अन्य पहल
- वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन के संबंध में राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफआई) पर आरबीआई के साथ समन्वय/वित्तीय समावेशन परामर्शदात्री समिति (एफआईसी)/टीजीएफआईएफएल तथा अन्य संबंधित मामले
- 75 ब्लॉकों – पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग कार्यक्रम (संभव), स्वामित्व योजना, अंत्योदय कार्यक्रम, एकेएम 2.0, स्वनिधि पीएम. विश्वकर्मा योजना आदि से संबंधित मामले

औद्योगिक वित्त-I (आईएफ-I)

- “निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981” का प्रशासन और आईआईएफसीएल की अर्थक्षम अवसंरचना परियोजना (एसआईएफटीआई) के वित्तपोषण की योजना, एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईडब्ल्यूआरएफसी और आईआईबीआई लि. से संबंधित परिचालन/नीतिगत/बजटीय मामले
- आईएफसीआई लि., आईडीएफसी लि. से संबंधित मामले और आईआईबीआई लि. से संबंधित मामलों का परिसमापन तथा अन्य संबद्ध मामले

- बोर्ड स्तर की नियुक्तियां – पूर्णकालिक निदेशक - आईआईएफसीएल, एक्जिम, आईएफसीआई लि. और उनके व्यक्तिगत मामले
- सरकार नामित निदेशक - एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल, आईएफसीआई लि. और आईडीएफसी लि.
- एक्जिम बैंक, आईआईएफसीएल तथा आईएफसीआई लि. में गैर-सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति
- क्षेत्र विशेष मामले – जैसे अवसंरचना, विद्युत, वस्त्र, निर्यात; इस्पात, दूरसंचार, सड़क, जहाजरानी (जोड़ा गया) आदि क्षेत्र से संबंधित मामले
- आईआईएफसीएल, एक्जिम बैंक, आईएफसीआई लि. की वार्षिक रिपोर्ट और आईआईबीआई लि. की परिसमापक रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत करना
- रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल) से संबंधित मामले
- एक्जिम बैंक और आईआईएफसीएल का नागरिक चार्टर
- आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) के समाधान और पंजीकरण मुद्दों से संबंधित सभी मामले और एआरसी की गतिविधियों को ट्रैक करना
- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि से संबंधित सभी मामले
- एक्जिम बैंक में सांविधिक लेखाकार की नियुक्ति
- डीएफएस में मीडिया और प्रचार से संबंधित मामले
- परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) की बैठक
- आंशिक ऋण गारंटी योजना (पीसीजीएस)
- संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) (जो प्रतिभूति लेनदेन में अनियमितताओं की जांच कर रही है)
- प्रतिभूति लेनदेन में अनियमितता में संलिप्त बैंक कर्मचारी/कार्यपालकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई
- **अभिरक्षक का कार्यालय**
 - विशेष न्यायालयों/अभिरक्षक के कार्यालय से संबंधित स्थापना मामले
 - अभिरक्षक के कार्यालय तथा अभिरक्षक की नियुक्ति के कार्यकाल को बढ़ाने सहित अभिरक्षक के कार्यालय तथा विशेष न्यायालय के सभी पदों को जारी रखने, इसके बजट संबंधी मामले

औद्योगिक वित्त-II (आईएफ-II)

- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का प्रशासन
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 का प्रशासन
- राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 का प्रशासन
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड

(एनसीजीटीसी) से संबंधित प्रचालनात्मक और नीतिगत मामले

- सिडबी और एनएचबी में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति और सभी कार्मिक मामले
- एनसीजीटीसी के बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति
- सिडबी और एनएचबी की वार्षिक रिपोर्टें संसद के समक्ष रखना
- अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क से संबंधित मामले
- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए अपीलीय प्राधिकरण (एआईएफआर) के बंद होने के बाद से संबंधित मामले
- शैक्षिक ऋण से संबंधित मामले
- एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस), कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस), सूक्ष्मवित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई) और फैक्ट्रिंग के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएसएमएफआई)
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), आवास, सूक्ष्मवित्त संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), व्यापार प्राप्य इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली (टीआरडीईएस), एमएसएमई के लिए ऋण मूल्यांकन मॉडल, माइक्रो क्रेडिट कार्ड और पीएसबीलोन इन 59 मिनट पोर्टल से संबंधित मामले
- वीआईपी/पीएमओ संदर्भ, लेखापरीक्षा पैरा, बजट घोषणाएं, संसद के प्रश्न, आश्वासन, आरटीआई अनुरोध/अपील, न्यायालय के मामले, उपर्युक्त मामलों पर सामान्य शिकायतें

सतर्कता और निगरानी प्रकोष्ठ

- सीवीसी/सीटीई से परामर्श
- पीएसबी/वित्तीय संस्थाओं(एफआई)/सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को नामित करना
- सीबीआई के साथ पत्राचार
- भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के संबंध में वार्षिक कार्य योजना
- सीबीआई और आरबीआई द्वारा धोखाधड़ी के मामलों की जांच
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामले
- निवारक सतर्कता
- आरबीआई/पीएसबी/एफआई तथा बीमा कंपनियों, पीएफआरडीए तथा इरडाई/आरबीआई में सतर्कता प्रणालियां तथा प्रक्रिया
- पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी/पीएफआरडीए तथा इरडाई/आरबीआई के महाप्रबंधकों/कार्यपालक निदेशकों तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा उन पर सतर्कता निगरानी
- पीएसबी (भारत और विदेशों में) में बड़ी धोखाधड़ी

- भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय का संदर्भ
- बैंक सुरक्षा, बैंकों में डकैतियों और हानि पर रोक लगना
- कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के मामले में अभियोजन की स्वीकृति
- वॉर बुक संबंधी मामले
- सीवीसी की वार्षिक रिपोर्ट
- पीएसबी/एफआई में आचरण विनियम, पीएसबी में सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार विनियम
- डीआरटी/डीआरएटी से संबंधित सीवीसी/सीबीआई संदर्भ
- पीएसबी, एफआई, पीएसआईसी, पीएफआरडीए, इरडाई और आरबीआई के बोर्ड स्तरीय अधिकारियों के संबंध में सतर्कता अनापत्ति, अभियोजन की स्वीकृति तथा कोई अन्य मामला
- वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों, अभिरक्षक कार्यालय के अधिकारियों तथा डीआरटी/डीआरएटी में सरकारी कामों के सतर्कता मामले

साइबर सुरक्षा और फिनटेक (आईटी)

- वित्तीय सेवाएं क्षेत्र और विभाग के संबंध में समग्र साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले
- फिनटेक और डीपटेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ब्लॉक चेन आदि) के बीच समन्वयन, वित्तीय सेवाएं क्षेत्र और विभाग से संबंधित मामले (बैंकिंग प्रणाली में ई-भुगतान से संबंधित मामलों सहित)
- सभी एफआई में ई-गवर्नेंस से संबंधित मामले तथा बैंकिंग प्रणाली में ई-भुगतान एवं पीएसबी का कंप्यूटरीकरण
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की योजना, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) सहित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), डिजिटल भुगतान अवसंरचना (डीपीआई), एनपीसीआई तथा इसकी संस्थाओं से संबंधित मामले
- भुगतान विनियामक बोर्ड (पीआरबी) के गठन तथा पीआरबी से संबंधित मामले
- रुपये डेबिट कार्ड तथा कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेनदेन (व्यक्ति से व्यापारी) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों का स्कोर कार्ड
- डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों को शामिल करना
- यूपीआई, भीम – क्यूआर, रुपये डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, यूएसएसडी, पीओएस आदि सहित डिजिटल भुगतान की विभिन्न पद्धतियों से संबंधित मामले
- मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) सहित भुगतान की विभिन्न पद्धतियों के संबंध में लगाए गए प्रभार
- ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित डिजिटल भुगतान की विभिन्न पद्धतियों से संबंधित धोखाधड़ी
- विनियमन से इतर डिजिटल भुगतान तथा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म आधारित ऐप से संबंधित मामले
- डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से संबंधित बैंकिंग मामले
- विभाग के संबंध में एनआईसी से समन्वय

- विभाग की वेबसाइट तथा वेब सेवाओं का प्रबंधन

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)

- बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के अंतर्गत डीआरटी/डीआरएटी की स्थापना ,
- ऋणों की वसूली और शोधन अक्षमता (आरडीबी) अधिनियम का अभिशासन, अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बनाना अथवा इनमें संशोधन करना,
- डीआरटी/डीआरएटी में अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, वसूली अधिकारियों तथा अन्य पदों को भरना
- प्रशासनिक मामलों पर स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश जारी करना/समीक्षा
- डीआरटी/डीआरएटी के द्वारा मामलों पर कार्रवाई तथा उनका निपटान
- डीआरटी/डीआरएटी के संबंध में बजट प्रावधान, निगरानी आदि
- सरफेसी अधिनियम का प्रशासन, रजिस्ट्रार/प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, हालिया संशोधनों से प्राप्त होने वाला ईज आफ डूइंग बिजनेस एजेंडा
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सीकेवाईसी मामले
- भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) से संबंधित नीतिगत मामले, सरफासी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्ट्री सहित एक पीएसयू

पेंशन सुधार (पीआर)

- पेंशन क्षेत्र में सुधार
- एनपीएस, अटल पेंशन योजना और स्वावलम्बन योजना से संबंधित नीतिगत मामले
- पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 का अभिशासन
- पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नियम बनाना
- पीएफआरडीए के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति, पीएफआरडीए में सीवीओ, पीएफआरडीए का बजट और निधियां तथा पीएफआरडीए को विधायी एवं नीति संबंधी निदेश उपलब्ध कराना

संसद

- संसद प्रश्न, नोटिस, स्वीकृत प्रश्न एकत्र करना, अभिचिह्नित करना और उन्हें निर्दिष्ट करना तथा मंत्री महोदय से फाइल अनुमोदित कराना
- मंत्रियों के पैड के लिए तथ्यों और उत्तरों को तैयार करना

- विलंबित आश्वासनों का लेखा-जोखा तथा अभिलेख रखना, 377 के अंतर्गत विशेष उल्लेख और संदर्भ तथा आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य मामले
- संसद के संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण
- अन्य मंत्रालयों/विभागों के संसद प्रश्न के लिए सामग्री का संकलन करना और प्रस्तुत करना
- संसदीय समिति के मामले

कल्याण अनुभाग एवं आरक्षण प्रकोष्ठ

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसबी/एआई/पीएसआईसी) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती/पदोन्नति तथा कल्याण उपायों से संबंधित मामले
- पीएसबी/एफआई/पीएसआईसी में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण नीति से संबंधित मामले, आरआरबी में आरक्षण संबंधी मामले
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/पीएसआईसी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण रोस्टर का निरीक्षण/जांच, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों और दायित्वों के सुचारु कार्यकरण और निर्वहन के लिए संपर्क अधिकारी को सहायता प्रदान करना, इस विभाग के उचित सचिवालय के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के आरक्षण रोस्टर तैयार करना/रखरखाव, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूडी के लिए राष्ट्रीय आयोग संबंधी संसदीय प्रश्नों के उत्तर देना विभाग के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के डेटा का रखरखाव, संबंधित मामलों में अन्य मंत्रालयों/विभागों/संसदीय समितियों आदि को सभी रिपोर्ट/सूचनाएं प्रस्तुत करना।

स्थापना (स्था.)

- भर्ती नियम (आरआर) सहित डीएफएस के अधिकारियों तथा स्टाफ से संबंधित मामले, नियुक्ति, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, प्रतिनियुक्ति (विदेश सहित), प्रशिक्षण, आईडब्ल्यूएसयू एसआईयू, कल्याण, एफआर 56(ज) के अंतर्गत अधिकारियों की समीक्षा, आंतरिक सतर्कता, कर्मचारी शिकायत, पेंशन आदि।
- अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार का अग्रिम प्रदान करना, वकीलों की फीस का भुगतान, चिकित्सा दावों तथा सीजीएचएस मामलों का निपटान, परिवार कल्याण कार्यक्रम

समन्वय

- पीएसबी के सीईओ के साथ वित्त मंत्री की बैठक और क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन

- सचिव (वित्तीय सेवाएं) की स्टाफ बैठक/वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम)
- वीआईपी संदर्भ, प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ के निपटान की निगरानी और समीक्षा, आरबीआई के विलंबित मामलों का समन्वय
- वीआईपी संदर्भ के संबंध में संसदीय प्रश्न
- सचिव (वित्तीय सेवाएं) की ओर से मंत्रिमंडल सचिव को भेजा जाने वाला मासिक अ.शा. पत्र
- डीएफएस की आरंभिक सामग्री का अद्यतन करना; डीएफएस के दो या उससे अधिक प्रभागों से सम्बद्ध वीआईपी, पीएमओ, राष्ट्रपति सचिवालय के संदर्भों इत्यादि का समन्वय

आरटीआई प्रकोष्ठ

- केंद्रीय सूचना आयोग के आवेदन, अपील, शिकायतें और निर्णय प्राप्त करने के लिए एकल संदर्भ बिंदु;
- संबंधित अनुभाग/सीपीआईओ के माध्यम से सभी आरटीआई आवेदनों /अपीलों के उत्तर;
- सीआईसी की सभी शिकायतों और निर्णयों को कम्प्यूटरीकृत डायरी प्रणाली पर अपलोड करना;
- जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित आरटीआई आवेदनों/अपीलों को अलग-अलग करना और उन्हें बिना किसी विलंब के संबंधित सीपीआईओ को अग्रेषित करना ताकि अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर कार्रवाई/प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके;
- आरटीआई आवेदन जो इस विभाग से संबंधित नहीं हैं उसका संबंधित लोक प्राधिकारी को हस्तांतरण।
- निम्नलिखित के संबंध में इस विभाग का समन्वय :-
- आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय प्रकटीकरण;
- ऐसे व्यवस्थागत परिवर्तन जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रश्नों की संख्या को कम करने के लिए किए जा सकते हों;
- विभाग से प्राप्त की जा सकने वाली सूचना पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का निरूपण;
- पहचाने गए साधनों के माध्यम से सूचना प्रसार;
- सीपीआईओ, एफए और संपर्क अधिकारियों की सूची बनाए रखना;
- सीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट;
- समय-समय पर अधिसूचित आरटीआई अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक कोई अन्य कार्यकलाप या अतिरिक्त कार्य करना
- आरटीआई अनुरोध/अपील के निपटान और सीआईसी के अनुदेशों के अनुपालन के संबंध में आवधिक निगरानी रिपोर्ट तैयार करना।

सामान्य प्रशासन (जीए)

- हाउसकीपिंग/सुरक्षा मामले, सफाई, स्टोर, कैंटीन, प्राप्ति एवं प्रेषण, पुस्तकालय
- स्टाफ कार चालक, वित्तीय सेवाएं विभाग के अधिकारियों को वाहन
- कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद और कंप्यूटरों, प्रिंटरों और अन्य उपकरणों का रख-रखाव
- फर्नीचर तथा विद्युत उपकरणों का रखरखाव
- डीएफएस के कर्मचारियों की विदाई समारोह की व्यवस्था के लिए लॉजिस्टिक सहायता
- डीएफएस के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों आदि के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों/कार्यकारी निदेशकों/जन सम्पर्क अधिकारी आदि को पहचान-पत्र उपलब्ध कराना

राजभाषा

- सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन
- संसद प्रश्न से संबंधित अनुवाद कार्य
- स्थायी समिति, बैठकों के कार्यवृत्त
- हिंदी शिक्षण योजना तथा डीएफएस की आरंभिक सामग्री में यथा उल्लिखित अन्य विविध कार्य

आरक्षण प्रकोष्ठ

- सम्पर्क अधिकारी को सुचारु रूप से कार्य करने और एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी के सम्पर्क अधिकारी के रूप में कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करने में सम्पर्क अधिकारी की सहायता करना, इस विभाग के समुचित सचिवालयीय कार्य हेतु एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी का आरक्षण रोस्टर तैयार करना/इनका रख-रखाव करना, विभाग के एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी कर्मचारी के संबंध में संसद प्रश्न/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी आयोग के प्रश्नों का जवाब देना, विभाग के एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी स्टाफ के आंकड़ों का रखरखाव, संबद्ध मामले में अन्य मंत्रालयों/विभागों/संसदीय समितियों को सभी रिपोर्ट/सूचना प्रस्तुत करना।

आंकड़ा विश्लेषण (डीए)

- भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण नीति- व्यस्त सत्र – कम कारोबार का समय और चयनात्मक ऋण नियंत्रण
- वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन तथा क्षेत्रीय ऋण विश्लेषण
- बैंक जमा तथा अग्रिमों के संबंध में बैंकिंग आंकड़े
- बैंकों के जमा तथा अग्रिम
- बैंक जमाओं तथा अग्रिमों के संबंध में ब्याज दरें
- आरबीआई, आईबीए, बैंकिंग सुधारों संबंधी अध्ययनों से संबंधित प्रतिफल तथा महत्वपूर्ण सूचना प्रदर्शित करना

- भारत में बैंकिंग क्षेत्र से संबद्ध अन्य अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों का विश्लेषण
- वित्तीय क्षेत्र सुधार समिति की रिपोर्टों का विश्लेषण आदि
- प्रबंधन सूचना प्रणाली – बैंकिंग उद्योग से संबंधित आंकड़ों का संग्रह तथा मिलान
- परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी), विभिन्न अवसरों पर वित्त मंत्री/राज्य मंत्री के भाषण
- लेखापरीक्षा पैरा
- यूएन-ई-गवर्नमेंट सूचकांक और डिजिटल सेवाएं
- वित्तीय क्षेत्र सांख्यिकी समिति से संबंधित कार्य
- डीएफएस के बजट प्रस्तावों का समन्वय बजट घोषणाओं से संबंधित मामले, आउटपुट- आउटकम निगरानी संरचना
- डीएफएस से संबंधित संपोषणीय विकास लक्ष्य – संकेतक

जीएसटी प्रकोष्ठ

- जीएसटी के संदर्भ में “बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा” क्षेत्र के समूहों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं में जीएसटी को लागू करने की तैयारी की निगरानी करना
- वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण वाली संस्थाओं के संबंध में जीएसटी आरंभ करने तथा लागू करने, समन्वय से संबंधित अन्य मामले आदि

सरप्लस प्रकोष्ठ

- एएआईएफआर और बीआईएफआर के सरप्लस स्टाफ को पुनः तैनात करने सहित सेवा संबंधी सभी मामले और दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक मामले
- डीओपीटी से परामर्श, सरप्लस स्टाफ के कोर्ट केस के संबंध में कार्रवाई, आरटीआई और सरप्लस स्टाफ से संबंधित व्यक्तिगत मामले जैसे अवकाश, पुनःविचारण लाभ, अनुलाभ और भत्ते इत्यादि

विधिक निगरानी प्रकोष्ठ

- न्यायालयगत मामलों की मानीटरिंग तथा समय-सीमा का प्रभावी अनुपालन करने के लिए संबंधित अनुभागों के साथ मामले को उठाना
- एलआईएमबीएस पोर्टल पर विभाग के न्यायालयगत मामलों का प्रबंधन करना तथा उन्हें अद्यतन करना, माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय/माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की वेबसाइटों पर विभाग के न्यायालयगत मामलों की स्थिति का पता लगाना
- न्यायालयगत मामलों को प्राप्त करना/न्यायालयगत मामलों के संबंध में पत्राचार एवं उन्हें संबंधित अनुभागों के लिए अभिविह्वित/वितरित करना
- केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउंसिल के विधिक बिलों के भुगतान तथा उनकी नियुक्ति से संबंधित मामले

बैंकिंग क्षेत्र में विकास

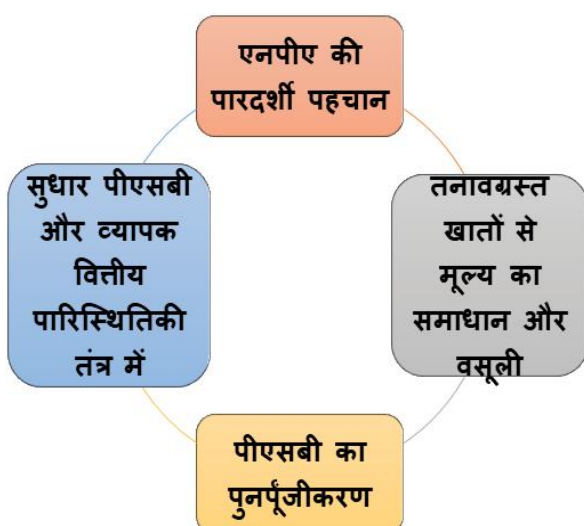
4.1 बैंकिंग क्षेत्र की समग्र स्थिति

भारत में बैंकिंग प्रणाली, जो कई दशकों में विकसित हुई है, सुदृढ़ है और अर्थव्यवस्था की क्रेडिट और बैंकिंग जरूरतों को पूरा कर रही है। बैंकिंग इकोसिस्टम देश के आर्थिक विकास और विकास को गति प्रदान कर रहा है और विभिन्न ग्राहकों और उधारकर्ताओं की विशिष्ट और विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा 2015 में आयोजित "ज्ञान संगम" नामक "रिट्रीट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस" में की गई थी। बाद में अगस्त-2015 में, सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2018-19 तक चार वर्षों में पूंजी निवेश योजना सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार और सुधार के लिए व्यापक ढांचे के लिए "इंद्रधनुष" योजना शुरू की।

वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा 2015 में आयोजित "ज्ञान संगम" नामक "बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए रिट्रीट" में की गई थी। बाद में अगस्त-2015 में, सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2018-19 तक चार वर्षों में पूंजी निवेश योजना सहित पीएसबी की वित्तीय स्थिति में सुधार और सुधार के लिए व्यापक ढांचे के लिए "इंद्रधनुष" योजना शुरू की।

सरकार ने पीएसबी के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एनपीए को पारदर्शी रूप से पहचानने, समाधान और वसूली, पीएसबी के पुनर्पूजीकरण और वित्तीय प्रणाली में सुधारों की एक व्यापक 4आर रणनीति लागू की।



पिछले दशक में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को मजबूत करने के लिए कई क्षेत्रों में मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार करके, कई विधायिकाओं को अधिनियमित और संशोधित करके और सार्वजनिक क्षेत्र

के बैंकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए व्यापक ढांचे की स्थापना करके कई पहल की हैं।

सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

4.1.1 क्रेडिट अनुशासन:

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का अधिनियमन, 2016

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) ने देश में दिवालियापन के समाधान के लिए सभी हितधारकों के लिए नाजुक संतुलन बनाए रखते हुए संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करने और समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक सामूहिक तंत्र निर्धारित किया है। यह है:

- कॉर्पोरेट देनदार के सशक्त लेनदार;
- 'कब्जे में देनदार' से 'नियंत्रण में लेनदार' शासन पर ध्यान केंद्रित करके देनदार-लेनदार संबंधों में व्यवहार परिवर्तन का नेतृत्व किया।

- सितंबर 2025 तक, एनसीएलटी में 8,659 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) भर्ती की गई हैं, जिनमें से 3,865 मामलों में सीडी को बचाया गया था। इसमें से 1,300 मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें लेनदारों ने कुल 3.99 लाख करोड़ रुपये की राशि प्राप्त की है। इन सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने पर उनके पास उपलब्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य क्रमशः 3.58 लाख करोड़ रुपये और 2.35 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि लेनदारों के कुल दावों के 12.31 लाख करोड़ रुपये थे। लेनदारों ने परिसमापन मूल्य का 170.09% और उचित मूल्य का 93.79% प्राप्त किया है (1177 मामलों के आधार पर जहां उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है)। समाधान की गई सीडी के परिणामस्वरूप स्वीकृत दावों की तुलना में 32.44 प्रतिशत से अधिक की वसूली हुई। संपत्ति के उचित मूल्य के सापेक्ष लेनदारों के लिए हेयर कटिंग लगभग 6% थे, जबकि उनके स्वीकृत दावों के सापेक्ष लगभग 67% है।



- इसके अलावा, इस वसूली में सीआईआरपी लागत शामिल नहीं है, और भविष्य की कई संभावित प्राप्तियां जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत गारंटी से वसूली, समाधान आवेदकों द्वारा पूंजीगत व्यय सहित सीडी में डाली गई निधियां और समाधान संबंधी आवेदनों से वसूली।

[स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड]

4.1.2. दबाव की पहचान और समाधान

क. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) में संशोधन किया गया है और जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को यह प्रावधान किया गया था कि वे आवेदन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उधारदाताओं द्वारा प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने के प्रयोजन के लिए आदेश पारित करें;

ख. ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993

ऋण वसूली एवं शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 में संशोधन किया गया है और इसमें तीन माह के कारावास का प्रावधान किया

गया है यदि उधारकर्ता डीआरटी को आवेदन करते समय ऋणदाता द्वारा विनिर्दिष्ट संपत्तियों/आस्तियों के अलावा अन्य संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है;

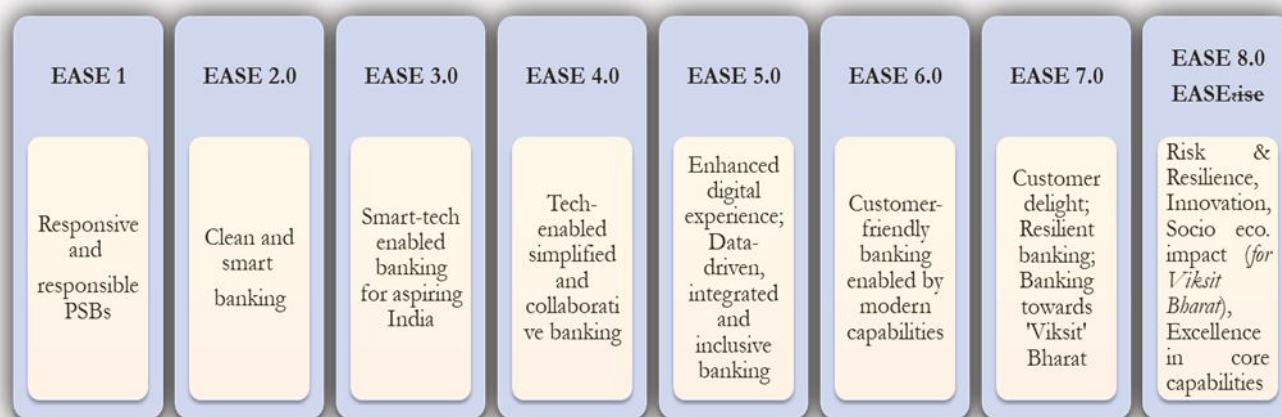
(ग) ऋण वसूली अधिकरण

ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) का क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया ताकि डीआरटी उच्च मूल्य के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें;

4.1.3 उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (ईज)

वर्ष 2018 से ईज सुधार एजेंडा यात्रा ने पीएसबी को पारंपरिक, प्रक्रिया-प्रधान संस्थानों से डिजिटल रूप से सशक्त, ग्राहक-केंद्रित और आघात सहनीय बैंकों में रूपांतरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईज के प्रत्येक चरण ने अपने पूर्ववर्ती चरण पर आधारित होकर भारतीय बैंकिंग को अभिशासन, प्रौद्योगिकी और धारणीयता के वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया है।

ईज ढांचे के माध्यम से, विकसित इकोसिस्टम के साथ तालमेल में वृद्धिशील सुधारों की एक उद्देश्य प्रक्रिया को पीएसबी में संस्थागत बनाया गया है। ईज सुधार एजेंडा, जो पीएसबी में गहराई से शामिल है और बैंक नेतृत्व के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है, सभी बैंकों की आवश्यकताओं के लिए एक सामान्य एजेंडा प्रदान करता है और लघु एवं दीर्घकालिक दृष्टिकोण से उद्योग की प्राथमिकताओं को दर्शाता है।



वर्तमान ईज 8.0 (वित्तीय वर्ष 26) संस्करण ईज पीएसबी के लिए जोखिम आघात सहनीयता, डिजिटल और एआई अपनाने, समावेशी बैंकिंग, स्थिरता, ग्राहक अनुभव और परिचालनीय उत्कृष्टता को शामिल करने वाला एक व्यापक सुधार ढांचा है। इसका उद्देश्य पीएसबी को भारत सरकार के दृष्टिकोण के साथ भविष्य के लिए तैयार, आघात सहनीय, ग्राहक-केंद्रित संस्थानों के रूप में तैयार करना है।

ईज 8.0 व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्चना और ग्राहक उत्कृष्टता के लिए नवाचार को बढ़ावा देते हुए, आर.आई.एस.ई. के संक्षिप्त रूप के अंतर्गत चार सुधार विषयों पर आधारित है- जोखिम और आघात सहनीयता, नवाचार, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव (विकसित भारत) और उत्कृष्टता जिसमें 16 सुधार संकेतक शामिल हैं। चूंकि

पीएसबी ईज 8.0 के अंतर्गत जारी हैं, इसलिए विकसित भारत 2047 तक के विजन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

4.1.4 पीएसबी में अभिशासन

पीएसबी में अभिशासन को निम्नलिखित के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है:-

- एफएसआईबी के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन का निष्पक्ष चयन;
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की शुरुआत;
- टैलेंट पूल को बढ़ाना और एमडी के लिए कार्यनिष्पादन-आधारित विस्तार लागू करना;

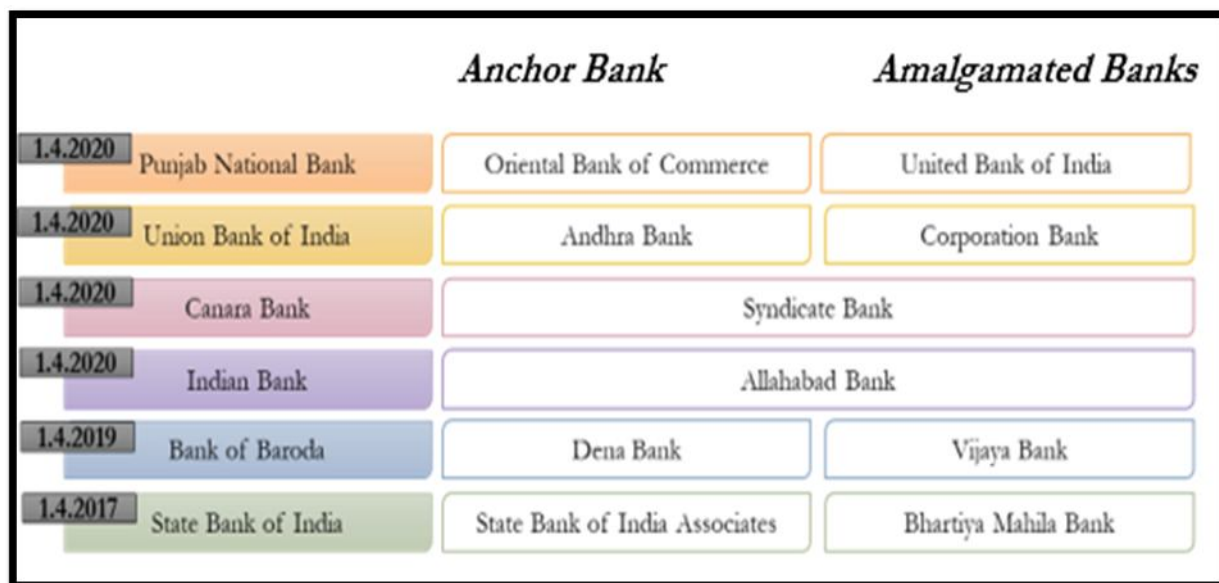
- शीर्ष प्रबंधन और एनओडी के बोर्ड द्वारा मूल्यांकन लागू करना;
- टैलेंट पूल को व्यापक बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधन नियुक्तियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने की दृष्टि से, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) का पद, भारतीय स्टेट बैंक में एक प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद और बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक कार्यकारी निदेशक (ईडी) का पद निजी

क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खोले गए हैं; तथा

- सीएक्सओ की भर्ती अर्थात् मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, बाजार से मुख्य अर्थशास्त्री।

4.1.5 पीएसबी का समेकन

पिछले एक दशक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समेकन के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने की किफ़ायत और तालमेल का लाभ उठाकर बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि हुई है।



समेकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप इन बैंकों में वित्तीय स्थिति और अभिशासन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पीएसबी का लाभ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और वे देश के कोने-कोने में अपनी पहुंच का विस्तार करना जारी रखते हैं। उनका पूंजी आधार सुदृढ़ हुआ है और उनकी

आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बैंक अब पुनर्पूँजीकरण के लिए सरकार पर निर्भर रहने के स्थान पर बाजार से पूंजी जुटा रहे हैं।

4.1.6 राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड

- आस्तियों के अधिग्रहण के संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(राशि करोड़ रुपए में)

चरण	खाते की संख्या	शामिल राशि	खरीद राशि	जारी की गई सरकारी गारंटी
अधिगृहित *	30	1,63,289	31,379	21,922
दिया गया प्रस्ताव	4	7,530	-	-
मूल्यांकनाधीन (सम्यक तत्परता)	3	32,259	-	-
कुल	37	2,03,078	31,379	21,922.74

* समाधान आवेदक के रूप में 5,555 करोड़ रुपये की अधिग्रहण राशि पर 32,815 करोड़ रुपये के कुल एक्सपोजर वाले 2 खातों का अधिग्रहण किया गया।

- दिनांक 03.12.2025 की स्थिति के अनुसार, एनएआरसीएल ने पहले ही 1,63,289 करोड़ रुपये के कुल ऋण जोखिम के साथ 30 उधारकर्ता संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया है। (30 नए खातों में से, एनएआरसीएल 32,815 करोड़ रुपये के कुल ऋण जोखिम के साथ 2 मामलों में समाधान आवेदक के रूप में कार्य कर रहा है)। यह सूचित किया है कि उन्होंने 20 खातों में 4,570 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें से 2,588 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 में वसूल किए गए हैं।

4.1.7 वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान की गई पहल:

4.1.7.1 बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अभिशासन मानकों को बढ़ाने, जमाकर्ताओं और निवेशकों के लिए सुरक्षा को सुदृढ़ करने, पीएसबी में लेखा गुणवत्ता में सुधार करने, बैंकों द्वारा वैधानिक रिपोर्टिंग को आरबीआई को स्थानांतरित करने तथा ग्राहकों की सुविधा के लिए नामांकन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।



4.1.7.2 पीएसबी मंथन

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने दो दिवसीय कार्यक्रम पीएसबी मंथन 2025 का आयोजन 12-13 सितंबर 2025 को किया जिसमें विनियामकों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, प्रौद्योगिकीविदों और बैंकिंग व्यवसायियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ नेतृत्व ने भाग लिया।



कार्यक्रम में एक अनौपचारिक बातचीत और ओपन हाउस सत्र शामिल थे, जिसमें ग्राहक अनुभव, अभिशासन, उद्देश्यपूर्ण नवाचार, ऋण वृद्धि, जोखिम प्रबंधन, कार्यबल तत्परता, प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे विषयों को शामिल किया गया था। विचारविमर्श में डिजिटल युग में ग्राहक यात्राओं की पुनर्कल्पना करने, अभिशासन और परिचालनीय उत्कृष्टता को समाहित करने, उद्देश्यपूर्ण नवाचार को बढ़ावा देने, सतत ऋण वृद्धि सुनिश्चित करने, जोखिम प्रबंधन ढांचे को सुदृढ़ करने और एक समावेशी तथा भविष्य के लिए तैयार कार्यबल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

पीएसबी मंथन 2025 का एक महत्वपूर्ण परिणाम दिशा की एक साझा भावना थी जो दो दिनों के विचारविमर्श में उभर कर सामने आई। चर्चाओं में अभिशासन, ग्राहक सेवा, प्रौद्योगिकी और ऋण वितरण के आसपास निकट अवधि की प्राथमिकताएं निर्धारित की गईं, साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सतत विकास के साथ संरेखित करने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी संस्थानों के रूप में विकसित होने के लिए एक दीर्घकालिक मार्ग की रूपरेखा भी तैयार की गई।

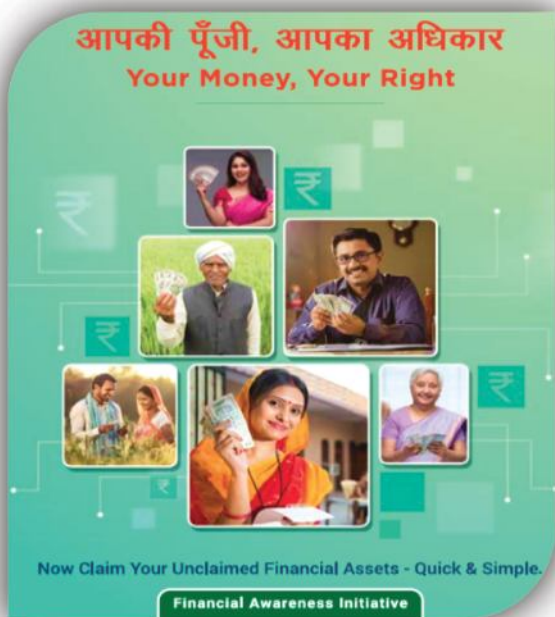
पीएसबी मंथन 2025 ने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय बैंकिंग का भविष्य साहसिक महत्वाकांक्षाओं और परिवर्तनकारी उद्देश्य से आकार लेगा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाएंगे और वैश्विक स्तर के संस्थानों के रूप में उभरने की आकांक्षा रखेंगे।

पीएसबी ने आधिकारिक तौर पर 12 नवंबर 2025 को पीएसबी मंथन 2025 की रिपोर्ट जारी की जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सामूहिक दृष्टिकोण और विकसित भारत 2047 तक की दिशा में रोडमैप को रेखांकित किया गया है।

4.1.7.3. आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान:

भारत सरकार ने बैंक जमा, बीमा, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित अदावी वित्तीय आस्तियों के निपटान की सुविधा के लिए “आपकी पूंजी, आपका अधिकार - योर मनी, योर राइट” शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है।

4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया यह अभियान 3एं ढांचे - जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई पर निर्मित है। यह तीन माह का अभियान (अक्टूबर-दिसंबर 2025) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में लागू किया गया है। अभियान के दौरान पहुंच को अधिकतम करने के लिए, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी), अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता सामग्री के साथ-साथ लघु वीडियो संदेशों का व्यापक रूप से प्रसार किया गया है। दावा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर डिजिटल प्रदर्शनों, हेल्पडेस्क और निर्देशित सहायता के साथ जिला स्तरीय शिविर आयोजित किए जाते हैं।



इस अभियान में वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रमुख निधि विनियामकों- आरबीआई, सेबी, इरडाई, पीएफआरडीए और आईईपीएफए की सहयोगात्मक भागीदारी शामिल है। आरबीआई के उदगम (अदावी जमा राशि के लिए), इरडाई के बीमा भरोसा (अदावी बीमा आय के लिए) और सेबी के मित्रा (अदावी म्यूचुअल फंड के लिए) जैसे मौजूदा प्लेटफार्मों ने नागरिकों को अपनी अदावी आस्तियों का अधिक कुशलता से पता लगाने का अधिकार दिया है।

4.1.7.4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देशों का समेकन:

मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित और समेकित करने हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्ष 2011 से समय-समय पर जारी किए गए पूर्व दिशानिर्देश लगभग 13 निर्देशों के समूह में विभाजित थे और उनमें एक एकीकृत संरचना का अभाव था, जिसके कारण नियुक्ति प्रस्तावों को संसाधित करने में अक्सर व्याख्यात्मक कठिनाइयाँ और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ उत्पन्न होती थीं। संशोधित समेकित दिशानिर्देश उभरते बैंकिंग और अभिशासन परिदृश्य के साथ निरंतरता, पारदर्शिता और संरेखण सुनिश्चित करने के लिए एक समान और व्यापक ढांचा स्थापित करते हैं।

यह दिशानिर्देश प्रत्येक डब्ल्यूटीडी पद पर लागू मूल्यांकन मानदंडों का एक मानकीकृत समूह पेश करते हैं, जिससे नियुक्तियों में स्पष्टता, निष्पक्षता और प्रक्रियात्मक दक्षता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त, टैलेंट पूल को व्यापक बनाने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सभी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) के पद, भारतीय स्टेट बैंक में एक प्रबंध निदेशक (एमडी) का पद

और बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में एक कार्यपालक निदेशक (ईडी) का पद निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खोले गए हैं। संशोधित समेकित दिशानिर्देशों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- **आयु और अवशिष्ट सेवा:** यह दिशानिर्देश नियुक्ति, कार्यकाल के विस्तार और बहाली के लिए न्यूनतम आयु मानदंड और अवशिष्ट सेवा आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं।
- **पात्रता की गणना की तिथि:** कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त सभी पदों के लिए, यह दिशानिर्देश प्रदान करते हैं कि पात्रता का मूल्यांकन रिक्ति उत्पन्न होने की तारीख के आधार पर किया जाएगा। कार्यपालक निदेशकों के लिए पात्रता का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन के रूप में किया जाएगा।
- **शैक्षिक योग्यता:** यह दिशानिर्देश सभी पदों के लिए स्नातक की एक समान न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करते हैं।
- **अनुभव और सेवा आवश्यकताएँ:** यह दिशानिर्देश न्यूनतम अनुभव अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उम्मीदवारों और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पात्रता मानदंड निर्धारित करते हैं।
- **चयन प्रक्रिया:** यह दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया का पालन करते हैं।
- **सतर्कता और विनियामकीय अनापत्तियाँ:** इन दिशा-निर्देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उम्मीदवारों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त करना और निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के संबंध में आसूचना ब्यूरो से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। इन दिशानिर्देशों में सभी नियुक्तियों के

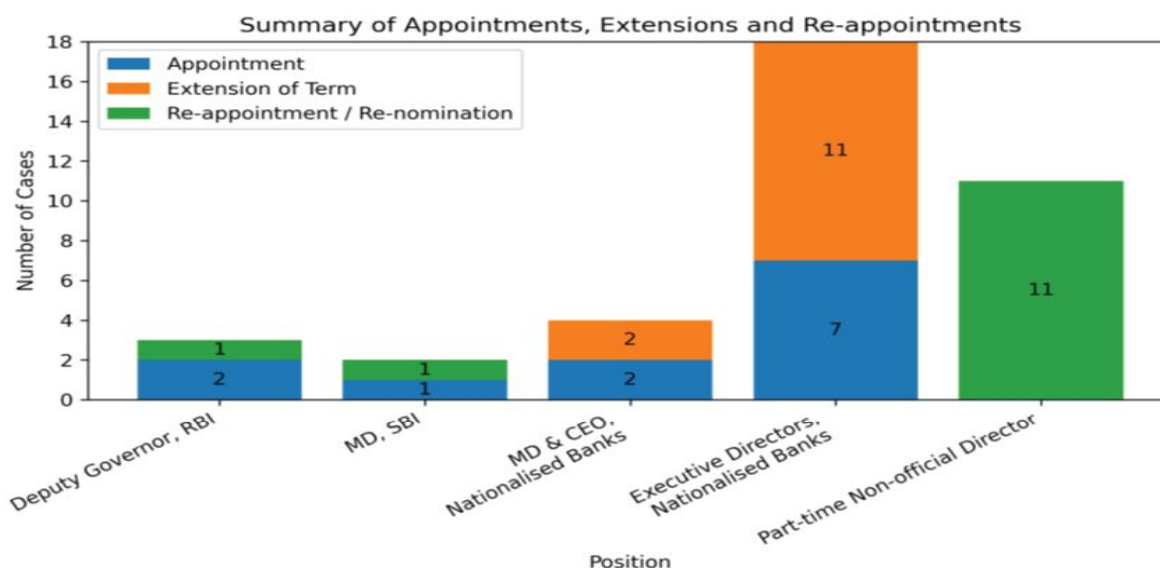
लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ अनिवार्य परामर्श की भी आवश्यकता होती है।

- **पदावधि:** इन दिशा-निर्देशों में मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप सभी पदों के लिए पदावधि का प्रावधान है।
- **वेतन और सेवा की शर्तें:** इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि वेतन और सेवा की अन्य शर्तें समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
- **पैनलों की वैधता:** यह दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से पैनल के आकार को निर्धारित करते हैं, जिसमें वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवारों की संख्या के साथ-साथ ऐसे पैनलों की वैधता अवधि भी शामिल है।

- **अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था:** ये दिशा-निर्देश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यकारी प्रमुख के पद पर रिक्ति की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार सौंपने के लिए एक विशिष्ट तंत्र का प्रावधान करते हैं ताकि अंतरिम अवधि के दौरान नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। यह प्रावधान पहले के दिशा-निर्देशों में मौजूद नहीं था।
- **दंड और अखंडता प्रावधान:** इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार को दो या दो से अधिक प्रमुख दंड दिए जाने की स्थिति में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रावधान का उद्देश्य सत्यनिष्ठा और नैतिक मानकों को बनाए रखना है।

4.1.7.5. भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नरों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड स्तर के निदेशकों की नियुक्ति/विस्तार:-

(i) उप गवर्नर , आरबीआई		
नियुक्ति	-	02
बहाली	-	01
(ii) प्रबंध निदेशक , एसबीआई		
नियुक्ति	-	01
बहाली	-	01
(iii) एमडी एवं सीईओ, राष्ट्रीयकृत बैंक		
नियुक्ति	-	02
कार्यकाल का विस्तार	-	02
(iv) कार्यपालक निदेशक , राष्ट्रीयकृत बैंक		
नियुक्ति	-	07
कार्यकाल का विस्तार:	-	11
(v) अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक-		
पुनर्नामांकन	-	11



4.1.7.6. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों के बैठक शुल्क में संशोधन:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में निदेशकों की कुछ श्रेणियां बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र हैं। बैठक शुल्क के भुगतान को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देशों को आखिरी बार वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। वर्ष 2019 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख करोड़ रुपये से कम के सम्मिश्र व्यवसाय वाले बैंकों को प्रति बोर्ड बैठक 40,000 रुपये और प्रति बोर्ड समिति की बैठक 20,000 रुपये तक की बैठक में बैठक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, जो कुल 15,00,000 रुपये की वार्षिक सीमा के अधीन थी। बड़े बैंकों (10 लाख करोड़ रुपये या उससे अधिक के सम्मिश्र व्यवसाय) के लिए, बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक शुल्क कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या विनियमों के आधार पर निर्धारित सीमा तक सीमित था, जबकि बोर्ड समिति की बैठकों के लिए बैठक शुल्क बोर्ड की बैठक के शुल्क के आधे तक सीमित था, जो कि 25,00,000 रुपये की कुल वार्षिक सीमा के अधीन था।

उक्त दिशा-निर्देश कई वर्षों से अपरिवर्तित रहे थे। समय के साथ, मुद्रास्फीति के प्रभाव और विनियामकीय ढांचे के विकास ने निर्धारित सीमाओं को उत्तरोत्तर अपर्याप्त और कम प्रासंगिक बना दिया। तदनुसार, अक्टूबर 2025 में दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत अधिनियमित नियमों या विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों में बैठक शुल्क को युक्तिसंगत और एक समान बनाया गया। तदनुसार निम्नलिखित परिवर्तन लागू किए गए हैं:-

- सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए बैठक शुल्क के भुगतान पर समग्र वार्षिक सीमा को हटा दिया गया है।
- संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत अधिनियमित विनियमों के आधार पर निर्धारित सीमाओं के अधीन प्रति-बैठक शुल्क निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

4.1.7.7. आईबीसी का कार्य निष्पादन

सितंबर 2025 तक, एनसीएलटी में 8,659 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) स्वीकार की जा चुकी हैं, जिनमें से 3,865 मामलों में सीडी का बचाव किया गया था। इसमें से 1,300 मामलों में समाधान योजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया था जिसमें लेनदारों को कुल 3.99 लाख करोड़

रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इन सीडी के सीआईआरपी में प्रवेश करने पर उनके पास उपलब्ध आस्तियों का उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य क्रमशः 3.58 लाख करोड़ रुपये और 2.35 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था, जबकि लेनदारों के कुल दावे 12.31 लाख करोड़ रुपये के थे। लेनदारों ने परिसमापन मूल्य का 170.09% और उचित मूल्य (1177 मामलों के आधार पर जहां उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है) का 93.79% प्राप्त किया है। समाधान की गई सीडी के परिणामस्वरूप स्वीकृत दावों की तुलना में 32.44 प्रतिशत से अधिक की वसूली हुई। आस्तियों के उचित मूल्य के सापेक्ष लेनदारों के लिए मार्जिन लगभग 6% था, जबकि उनके स्वीकृत दावों के सापेक्ष यह लगभग 67% था। इसके अतिरिक्त, इस वसूली में सीआईआरपी लागत और भविष्य की कई संभावित प्राप्ति जैसे इक्विटी, कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत गारंटी से वसूली, समाधान आवेदकों द्वारा पूंजीगत व्यय सहित सीडी में निवेशित निधि और परिहार आवेदनों से वसूली शामिल नहीं है। [स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड]

लोकसभा में दिनांक 12.08.2025 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया था, जिसमें इस विभाग (डीएफएस) ने प्रवेश, समाधान और परिसमापन में विलंब को दूर करने, लेनदारों के लिए मूल्य अधिकतम करने और दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार करने के लिए कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। उक्त विधेयक को जांच के लिए लोकसभा की चयन समिति के पास भेजा गया था और समिति ने दिनांक 17.12.2025 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

डीएफएस तिमाही आधार पर 500 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले पीएसबी के शीर्ष बीस मामलों की समीक्षा करता है जो एनसीएलटी में प्रवेश के लिए लंबित हैं। समाधान के लिए लंबित शीर्ष दस मामलों की भी निगरानी की जा रही है। परिणामस्वरूप, आईबीसी, 2016 के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये से अधिक के एक्सपोजर वाले 13 मामलों का प्रवेश-पूर्व चरण में ही स्वीकार/निपटान किया गया है।

4.1.7.8. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की संगोष्ठी

एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) की भूमिका पर सहयोगात्मक संवाद की सुविधा के लिए, डीएफएस ने जुलाई 2025 में 'एनबीएफसी संगोष्ठी 2025' की मेजबानी की। वित्तीय इकोसिस्टम में एनबीएफसी की सुदृढ़ भूमिका को ध्यान में रखते हुए, यह परिकल्पना की गई है कि-

NBFC credit as percentage to SCB's credit increases to 50% by 2047 from 25% currently

50% of NBFC-credit is extended to sunrise sectors

100% adoption of tech-driven process across all domains

इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए, सभी क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए साझा प्लेटफार्मों सहित सुदृढ़ सह-उधार तंत्र, वित्तीय रूप से वंचित वर्गों में पैठ बनाकर वित्तीय समावेशन में बढ़ी हुई भूमिका, बेहतर वित्तीय स्थिति, बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन और आघात सहनीयता एवं फिनटेक, एग्रीटेक, वाणिज्यिक बैंकों आदि के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर एकीकृत सहयोग को अपनाना शामिल है।

4.1.7.9. बैंकिंग क्षेत्र की समग्र स्थिति

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली का विकास चक्र सभी मापदंडों पर ऊपर की ओर अग्रसर है। अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों

में ऋण प्रवाह अच्छी गति से बढ़ रहा है। सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में गिरावट के साथ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर) में लगातार वृद्धि हुई है। बैंकों को कम गिरावट अनुपात, बाजार से पूंजी जुटाने और लाभ के माध्यम से निवल पूंजी वृद्धि के साथ अपनी पूंजी पर्याप्तता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है।

- एससीबी/पीएसबी की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति इस प्रकार है:-

मापदंड	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक						सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक					
	मार्च-15	मार्च-18	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25	*सितम्बर-25	मार्च-15	मार्च-18	मार्च-23	मार्च-24	मार्च-25	*सितम्बर-25
सकल एनपीए (लाख करोड़ रु. में)	3.23	10.36	5.71	4.81	4.32	4.18	2.79	8.96	4.28	3.40	2.84	2.65
सकल एनपीए (%)	4.28	11.18	3.87	2.75	2.22	2.05	4.97	14.58	4.97	3.47	2.58	2.30
निवल एनपीए (लाख करोड़ रु. में)	2.31	5.20	1.35	1.07	0.95	0.94	2.15	4.54	1.02	0.73	0.55	0.51
निवल एनपीए (%)	3.13	5.94	0.95	0.62	0.50	0.48	3.92	7.97	1.24	0.76	0.52	0.45
पीसीआर (%)	49.31	62.96	90.94	92.50	93.14	93.24	46.04	62.71	90.73	93.00	94.31	94.63
सीआरएआर (%)	12.94	13.85	17.24	16.84	17.36	17.24	11.45	11.66	15.53	15.55	16.10	15.96

स्रोत: *सितंबर 2025 के लिए आरबीआई के अनंतिम आंकड़े

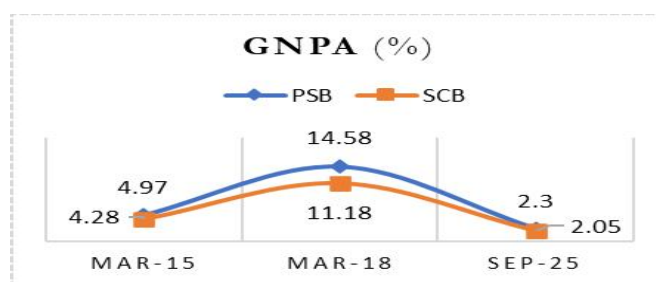
- (क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, एससीबी ने 4.01 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वोच्च निवल लाभ दर्ज किया है। पीएसबी ने भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.78 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वोच्च निवल लाभ दर्ज किया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान पीएसबी का निवल लाभ 0.94 लाख करोड़ रुपये था।



- (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वैश्विक जमा और वैश्विक अग्रिम मार्च 2015 के 71.95 लाख करोड़ रुपये और 56.16 लाख करोड़

रुपये से बढ़कर सितंबर, 2025 में क्रमशः 146.27 लाख करोड़ रुपये और 114.85 लाख करोड़ रुपये हो गया।

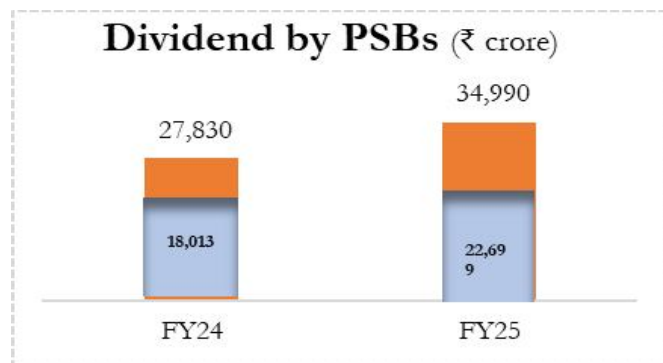
- (ग) जीएनपीए और एनएनपीए अनुपात के साथ पीएसबी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जो मार्च 2015 में क्रमशः 4.97% और 3.92% से घटकर सितंबर 2025 में 2.30% और 0.45% हो गए।



- (घ) पीसीआर के मार्च 2015 में 46.04 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2025 में 94.62 प्रतिशत होने से पीएसबी की आघात सहनीयता में वृद्धि हुई।

(ड.) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी पर्याप्तता में सुधार हुआ है, सितंबर 2025 में उनका सीआरएआर बढ़कर 15.96% हो गया, जो मार्च 2015 में 11.45% था।

(च) पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में शेयरधारकों को 27,830 करोड़ रुपये के कुल लाभांश (भारत सरकार का 18,013 करोड़ रुपये का शेयर) की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेयरधारकों को 34,990 करोड़ रुपये (भारत सरकार का 22,699 करोड़ रुपये का शेयर) का लाभांश घोषित किया।



(छ) व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन से सक्षम, पीएसबी की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जिससे बाजार से पूंजी (इक्विटी और बॉन्ड दोनों के रूप में) जुटाने की उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है। पीएसबी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.9.2025 की स्थिति के अनुसार) तक बाजार से 5.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी जुटाई है।

4.2 लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय/पहल

4.2.1. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल किया है जैसे कि भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिरूपण और कदाचार को रोकने हेतु कदम उठाना जिससे बैंकिंग उद्योग में भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़े। इस प्रकार की पहल का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:-

(क) परीक्षाओं में उम्मीदवार सत्यापन के लिए आईबीपीएस द्वारा आधार प्रमाणीकरण का उपयोग:

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन [सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत एक लोक परीक्षा प्राधिकरण] को अपनी परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान पहचान सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार

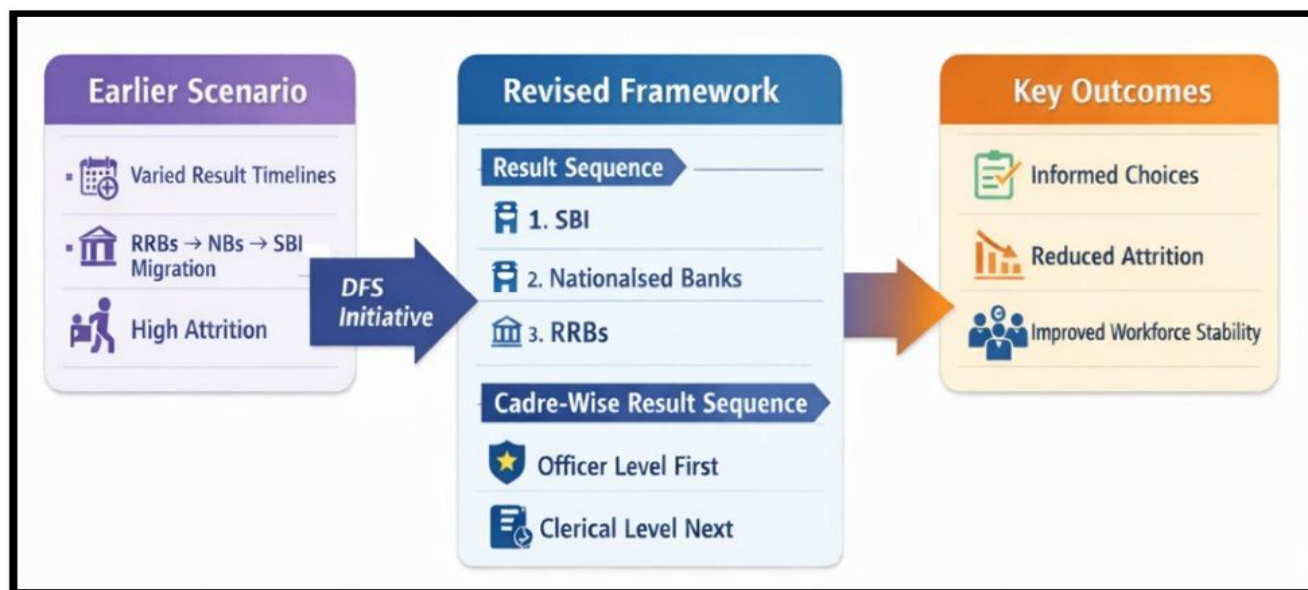
प्रमाणीकरण (हां/नहीं और/अथवा ई-केवाईसी) का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन नियमावली, 2020 के नियम 5 के अंतर्गत यूआईडीआईआई के परामर्श से मिटी द्वारा अधिकृत किए जाने के पश्चात् प्रकाशित की गई है। इस पहल का उद्देश्य सुशासन को बढ़ाना, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, प्रतिरूपण और कदाचार को रोकना, पहचान सत्यापन को सरल बनाना और बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं एवं बीमा क्षेत्र की भर्ती प्रणाली में विश्वास को सुदृढ़ करना है।

(ख) बैंकिंग भर्तियों में परिणामों की घोषणा को सुव्यवस्थित करना:

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने भर्ती परीक्षाओं की समयसीमा को सुव्यवस्थित करने और उनके परिणामों की घोषणा करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), राष्ट्रीयकृत बैंकों (एनबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में भर्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त, इन पहलों का उद्देश्य इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाना है।

एसबीआई, एनबी और आरआरबी में भर्ती संबंधित बैंकों के अधिदेशों के अनुसार आईबीपीएस प्रक्रिया के माध्यम से आयोजित की जाती है। आमतौर पर, आरआरबी के लिए परीक्षाएं एनबी और एसबीआई से पहले आयोजित की जाती हैं। इसी क्रम में बाद में परिणाम घोषित किए जाते हैं। तथापि, एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति सामने आई है जिसमें नए भर्ती किए गए उम्मीदवार अक्सर आरआरबी से एनबी और बाद में एसबीआई में चले जाते हैं। इस स्थानांतरण (माइग्रेशन) के परिणामस्वरूप बैंकों में महत्वपूर्ण कमी आई है और परिचालन संबंधी चुनौतियां सामने आई हैं।

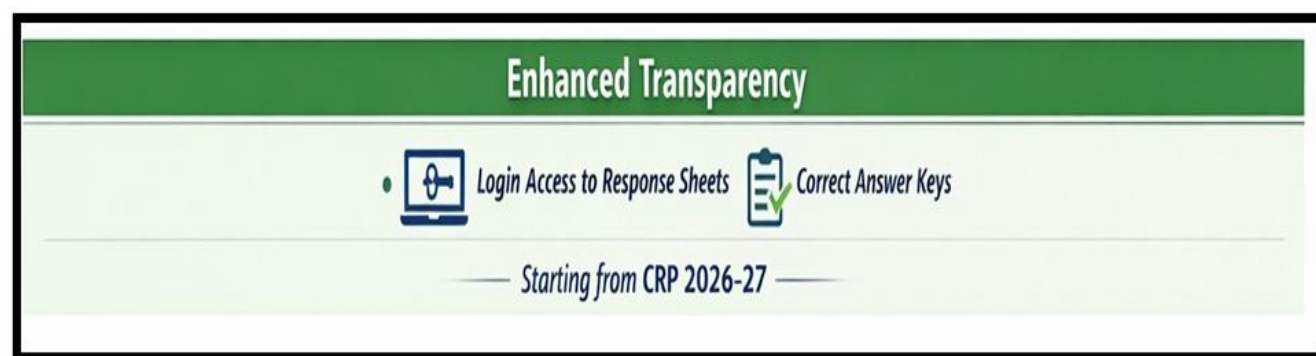
उपर्युक्त मुद्दे का संज्ञान लेते हुए, डीएफएस ने भर्ती परीक्षाओं की व्यापक प्रक्रिया और परिणाम घोषणा के पद्धति की समीक्षा की, जिसमें भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को बैंकों की सभी तीन श्रेणियों में भर्ती परिणामों की घोषणा के लिए एक मानकीकृत और तार्किक अनुक्रम लागू करने की सलाह दी गई। परिणामस्वरूप, एक संशोधित ढांचा स्थापित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि अब पहले एसबीआई के लिए, उसके बाद एनबी के लिए और बाद में आरआरबी के लिए परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इन श्रेणियों में सभी अधिकारी स्तर की परीक्षाओं के परिणाम शुरू में घोषित किए जाएंगे, लिपिक-स्तर के परीक्षा परिणाम बाद में उसी क्रम में घोषित किए जाएंगे।



यह व्यवस्थित अनुक्रमण उम्मीदवारों को उनकी प्राथमिकताओं को शीघ्रता से व्यक्त करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। यह दृष्टिकोण उम्मीदवारों के लिए पूर्वानुमान में वृद्धि करेगा, भर्ती स्थिरता में सुधार करेगा, उद्योग के पलायन को काफी हद तक कम करेगा और बैंकिंग क्षेत्र में अधिक प्रभावी कार्यबल योजना को सक्षम करेगा।

(ग) बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं में बढ़ी हुई पारदर्शिता:

इस विभाग ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2026-27 के सामान्य भर्ती प्रक्रिया चक्र से, आईबीपीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिकाओं और सही उत्तर कुंजी तक लॉगिन-आधारित पहुंच प्रदान की जाएगी।



यह पहल बैंकिंग सेक्टर में भर्ती के तरीकों को दूसरी बड़ी सरकारी भर्ती एजेंसियों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के साथ जोड़ती है और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करती है। इससे बैंकिंग भर्ती प्रणाली में लोगों का भरोसा बढ़ेगा।

4.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा अपनाई जाने वाली पदोन्नति प्रक्रिया की समीक्षा की गई और पाया कि सभी बैंकों में समय-सीमा अलग-अलग हैं, क्योंकि कुछ पीएसबी तीसरी तिमाही में प्रक्रिया शुरू करते हैं और प्रत्येक

वर्ष मार्च तक इसे पूरा कर लेते हैं, जबकि कुछ पीएसबी में पदोन्नति प्रक्रिया विलंब से शुरू होने के कारण इसे मई-जून (वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही) में पूरा कर पाते हैं।

इसलिए, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कम से कम रुकावट हो, प्रक्रिया तय समय सीमा से आगे न बढ़े, और सभी बैंकों में एकरूपता बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए, इस विभाग ने सभी पीएसबी को सलाह दी है कि वे अपनी-अपनी पदोन्नति प्रक्रिया और अंतिम परिणाम की घोषणा प्रत्येक वर्ष के मार्च माह या उससे पहले घोषित करें, और यह भी सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष जून से पहले पूरी हो जाए। सभी बैंकों ने भी इसका पालन करने की पुष्टि की है।

4.2.3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विनियमों का समय पर अद्यतनीकरण

(क) हर द्विपक्षीय समझौते/संयुक्त नोट पर साइन होने के बाद, सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभों के संबंध में सहमत प्रावधानों को शामिल करने के लिए संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी पेंशन विनियमों (बीईपीआर) में ज़रूरी संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के संबंधित बैंक के बीईपीआर में किए गए संशोधनों को संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

पूर्व में, संबंधित बैंकों के बीईपीआर में संशोधन करने और उन्हें संसद के समक्ष रखने की प्रक्रिया में आम तौर पर 6-8 वर्ष का समय लगता था। हालांकि, 08.03.2024 को हुए हालिया द्विपक्षीय समझौते के संबंध में, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच के बाद, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के परामर्श से, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी इन बैंकों को 24.09.2025 के पत्रों के माध्यम से दी गई थी। इन संशोधनों को बाद में अक्टूबर/नवंबर, 2025 के दौरान आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया और उसके बाद दिसंबर, 2025 (शीतकालीन सत्र) में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया, जिससे प्रक्रिया समय पर और कुशलता से पूरी हुई।

परिणामस्वरूप, बीपीएस/संयुक्त टिप्पणी के समापन से लेकर आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन और बाद में संसद के समक्ष राजपत्र अधिसूचनाएं रखने की प्रक्रिया 18 महीने की अभूतपूर्व अवधि के भीतर पूरी की गई।

(ख) इस विभाग ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) स्तर के पदों को अनुमोदित किया था। इसके अलावा, 12वें द्विपक्षीय समझौते का समापन और 9वें संयुक्त टिप्पणी पर हस्ताक्षर 8.3.2024 को हुए हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए बैंक अधिकारी सेवा विनियमों (ओएसआर) को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संशोधित किया जाना था, जिसे इस विभाग द्वारा 2 चरणों में लिया गया है, जो निम्नानुसार है:

चरण I – चूंकि सीजीएम स्तर के पद पहली बार पांच बैंकों अर्थात् बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक में शुरू किए जा रहे थे, इसलिए इस विभाग ने पहले इन बैंकों के साथ आवश्यक संशोधन किए हैं। इसके अलावा, द्विपक्षीय समझौते के समापन और 9वें

संयुक्त टिप्पणी पर हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप, बैंकों के सभी अधिकारियों के संशोधित वेतनमानों के साथ-साथ अन्य सहमत प्रावधानों को एनबीई के ओएसआर में शामिल किया जाना है।

तदनुसार, इस विभाग द्वारा उपर्युक्त संशोधनों के समेकित प्रस्तावों पर विचार किया गया था। इन प्रस्तावों की विधायी विभाग (एलडी), विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से जांच की गई थी। इन बैंकों को दिनांक 16.5.2025 के पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत करा दिया गया था। इन संशोधनों को बाद में मई, 2025 में आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया और आगे अगस्त, 2025 (मानसून सत्र) में संसद के दोनों सदनों में समय पर और प्रभावी तरीके से रखा गया।

इस वर्ष बीपीएस/संयुक्त टिप्पणी के समापन की तारीख से लेकर संसद में राजपत्र अधिसूचनाएं जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया 17 महीने की रिकॉर्ड समय अवधि में पूरी की गई है। इससे पहले, 11वें बीपीएस/8वें संयुक्त टिप्पणी के दौरान इसी प्रक्रिया में 48 महीने लगते थे।

चरण II - शेष छह बैंकों, जहां सीजीएम स्तर के पद पहले से मौजूद हैं, में संशोधन चरण II के तहत किया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त प्रस्तावों की वर्तमान में एलडी के परामर्श से विभाग में जांच की जा रही है। इसके बाद, माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी शीघ्र ही मांगी जाएगी।

4.3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, लघु उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास के लिए छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, आबादी के सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ऋण वितरण के लिए एक वैकल्पिक चैनल बनाने के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संयुक्त स्वामित्व केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के पास है जिनकी शेयरधारिता क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में है।

वर्तमान में, 28 आरआरबी देश के लगभग 700 जिलों को कवर करते हुए 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) में 22,158 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रचालन कर रहे हैं।



यह वर्ष 2025 आरआरबी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वे वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में 50 साल पूरे कर रहे हैं।

4.3.1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की भूमिका:

आरआरबी के पास ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का अधिदेश है। वर्तमान में समग्र रूप से आरआरबी द्वारा किए जा रहे योगदान संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

- 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआरबी द्वारा दिए गए कुल ऋण में से 85% से अधिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाते हैं और लगभग 66% कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है। कुल ऋण में से लगभग 61% समाज के कमजोर वर्गों को दिया गया है।
- आरआरबी सूक्ष्म ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका हिस्सा एसएचजी ऋण खातों का 31% हैं और ऋण राशि का 25% एसएचजी को है। कुल केसीसी का लगभग 19% आरआरबी द्वारा जारी किया गया है।
- सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे पीएमजेडीवाई, पीएमजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, एपीवाई आदि के तहत कुल खातों/नामांकनों में आरआरबी का हिस्सा 15% से 20% के बीच है।
- आरआरबी की 92% शाखाएं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या में आरआरबी की हिस्सेदारी 29% है। आकांक्षी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग नेटवर्क में आरआरबी की लगभग 40% शाखाएं हैं। इसके अलावा, कई आरआरबी की

दूरस्थ क्षेत्रों में शाखाएं हैं और वे कमजोर वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

- ग्रामीण क्षेत्रों में, आरआरबी के जमा खातों की हिस्सेदारी 25% है और सभी श्रेणियों के बैंकों में से आरआरबी में पीएमजेडीवाई खातों में औसत शेष राशि सबसे अधिक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, आरआरबी लगभग 38% ग्रामीणों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करते हैं। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, सभी बैंकों के लिए 70% के समग्र ग्रामीण ऋण-जमा (सीडी) अनुपात की तुलना में आरआरबी का ग्रामीण ऋण-जमा (सीडी) अनुपात 81% है।

4.3.2. पुनर्पूजीकरण योजना:

भारत सरकार आरआरबी के अन्य हितधारकों अर्थात संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंकों के साथ मिलकर आरआरबी को 9% सीआरएआर (जोखिम भारित आस्ति अनुपात के लिए पूंजी) की विनियामक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए उनका पुनर्पूजीकरण करती है। आरआरबी में पूंजी का निवेश पर्याप्त विकास पूंजी के साथ आरआरबी को फिर से जीवंत और पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि वे खुद को स्थायी रूप से व्यवहार्य और आत्मनिर्भर वित्तीय संस्थानों के रूप में फिर से स्थापित कर सकें और विकास प्रक्रिया तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन का नेतृत्व कर सकें। पूंजी निवेश आरआरबी को प्रौद्योगिकी अपनाने में मदद करने और ग्रामीण आबादी की वित्तीय समावेशन आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए है।

इसके अलावा, पुनर्पूजीकरण योजना के साथ-साथ ऋण विस्तार, कारोबार विविधीकरण, एनपीए में कमी, लागत युक्तिकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने, कारपोरेट अभिशासन में सुधार आदि के उद्देश्य से सुस्पष्ट कार्यान्वयन तंत्र के साथ सतत व्यवहार्यता योजना (एसवीपी) के व्यापक दायरे के तहत परिचालन और अभिशासन सुधार किए गए हैं।

4.3.3. प्रगति और परिणाम:

- i) पिछली पुनर्पूजीकरण सहायता आरआरबी को भारत सरकार के शेयर के रूप में 5,445 करोड़ रुपये के एकमुश्त अग्रिम पुनर्पूजीकरण के रूप में प्रदान की गई थी, जिसे व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 11.10.2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया था, जिसमें से 75% अर्थात् 4,084 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आरआरबी में डाले गए थे। व्यवहार्यता योजना के अनुसार परिचालन और अभिशासन सुधारों में उल्लेखनीय सुधार होने पर भारत सरकार के हिस्से के रूप में 1,361 करोड़ रुपये के पुनर्पूजीकरण समर्थन का शेष 25% वर्ष 2022-23 के दौरान डाला जाना था।
- ii) तदनुसार, प्रत्येक आरआरबी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिचालन और शासन सुधारों को शामिल करते हुए 3 साल की बोर्ड अनुमोदित व्यवहार्यता योजना तैयार की। आरआरबी ने व्यवहार्यता योजना के तहत प्रमुख वित्तीय संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार का प्रदर्शन किया। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान आरआरबी में 1,361 करोड़ रुपये की शेष राशि डाली गई।
- iii) इस पृष्ठभूमि में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आरआरबी के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है। आरआरबी अपने वित्तीय प्रदर्शन में लगातार सुधार दिखा रहे हैं। आरआरबी ने अपना निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3,219 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7571 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6,820 करोड़ रुपये कर दिया है। सकल अनर्जक आस्तियाँ वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9.1 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5.4 प्रतिशत हो गया। सीआरएआर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 12.7% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 14.4% पर पहुंच गया। ऋण विस्तार से समेकित ऋण-जमा अनुपात में 73.1% की वृद्धि हुई, जो 35 वर्षों में सबसे अधिक थी। प्रौद्योगिकी अपनाने की गति बढ़ गई है क्योंकि अधिक आरआरबी ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल सेवाएं शुरू कर दी हैं।

4.3.4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरआरबी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रगति:

4.3.4.1 सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा आरआरबी की समीक्षा:

सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने 05 मई, 2025 को मुंबई में आरआरबी के प्रदर्शन और चौथे चरण के सम्मेलन प्रक्रिया के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की।

4.3.4.2 आरआरबी के चरण-IV सम्मेलन के लिए प्रक्रिया की कार्यान्वयन:

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क के अनुसार, केन्द्र सरकार, नाबार्ड, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक

के परामर्श के पश्चात् जनहित में एक राज्य में दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्मेलन कर सकती है।

आरआरबी को अपने ओवरहेड खर्चों को कम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को अनुकूलित करने, पूंजी आधार और संचालन के क्षेत्र को बढ़ाने तथा उनके जोखिम को बढ़ाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में आरआरबी के संरचनात्मक समेकन की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप सम्मेलन के 3 चरणों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक आरआरबी की संख्या 196 से घटकर 43 हो गई है।

आरआरबी की यूएसपी अर्थात् ग्रामीण समुदायों से निकटता को बनाए रखने और पैमाने की दक्षता और लागत युक्तिरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए, भारत सरकार ने 'एक राज्य-एक आरआरबी' के लक्ष्य की दिशा में 01.05.2025 से 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 26 आरआरबी का सम्मेलन किया है, जिससे आरआरबी की संख्या 43 से घटकर 28 हो गई है।

चौथे चरण के सम्मेलन को वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार द्वारा गठित एक मजबूत संस्थागत ढांचे के माध्यम से निष्पादित किया गया था, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राष्ट्रीय स्तर की परियोजना निगरानी इकाई (एनएलपीएमयू): उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), नाबार्ड की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसमें वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार, नाबार्ड और प्रायोजक बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एसएलएमसी): नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों (सीजीएम) की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिसमें प्रायोजक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सीबीएस/आईटी विक्रेताओं के सदस्य होते हैं।

एनएलपीएमयू और एसएलएमसी ने साथ में प्रगति की निगरानी करने, चुनौतियों का समाधान करने और सम्मेलन प्रक्रिया के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 100 से अधिक बैठकें आयोजित कीं। 13 अक्टूबर, 2025 तक सभी 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हस्तांतरणकर्ता आरआरबी के कोर बैंकिंग सिस्टम (सीबीएस) और एनपीसीआई भुगतान चैनलों का एकीकरण पूरा कर लिया गया था।

4.3.4.3 आरआरबी के लिए एकसमान ब्रांडिंग और लोगो संरचना

जनता के बीच दृश्यता, ब्रांडिंग और स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए, सरकार ने सभी आरआरबी के लिए एक समान लोगो को मंजूरी दी है, जिससे देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।



FINANCE & TRUST



LIFE & GROWTH

ऊपर की ओर तीर (प्रगति का प्रतीक): ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि, विकास और उन्नति का प्रतीक है।

हाथ (पोषण का प्रतीक): ग्रामीण समुदायों के देखभाल, समर्थन और मदद का प्रतीक है।

लौ (आत्मज्ञान का प्रतीक): गर्मजोशी, ज्ञान और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने का प्रतीक है।

इसके अलावा, आरआरबी के लिए एक एकीकृत पहचान स्थापित करने के लिए, उन्हें सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित करके जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 23.10.2025 की अधिसूचना के माध्यम से 6 आरआरबी के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में सभी आरआरबी अब एक समान नामकरण परंपरा का पालन करते हैं:

<राज्य का नाम><स्थानीय भाषा में ग्रामीण/ग्रामीण><बैंक>

ये सुधार एक मजबूत ब्रांड बनाने का प्रयास करते हैं जो ग्रामीण समावेशन, वित्तीय स्थिरता और पारदर्शिता को दर्शाता है। मानकीकृत ब्रांडिंग से परिचालन दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है, सामेलन के बाद सामंजस्य का समर्थन करता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।

4.3.4.4 एपीजीवीबी की संपत्ति और देनदारियों का विभाजन

आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक (एपीजीवीबी) तेलंगाना के 21 जिलों और आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में प्रचालन कर रहा था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, डीएफएस, भारत सरकार ने दोनों राज्यों के बीच एपीजीवीबी की संपत्ति और देनदारियों के विभाजन के लिए एक योजना को मंजूरी दी। इस अनुमोदन के अनुसार, विभाजन 01 जनवरी 2025 से प्रभावी हुआ। परिणामस्वरूप, तेलंगाना में स्थित एपीजीवीबी की शाखाओं को तेलंगाना ग्रामीण बैंक के साथ विलय कर दिया गया, जबकि विभाजित एपीजीवीबी ने आंध्र प्रदेश के 7 जिलों में अपना परिचालन जारी रखा।

4.3.4.5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए स्थायी सलाहकार समिति (एससीसी) का गठन

डीएफएस, भारत सरकार ने 18 सितंबर, 2025 के पत्र के माध्यम से आरआरबी के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति (एससीसी) का गठन किया है, जो मानव संसाधन, सेवा शर्तों, भर्ती और पदोन्नति से संबंधित मुद्दों, वैधानिक प्रावधानों की समीक्षा, मसौदा नीतियों, नियमों, विनियमों, निर्देशों, दिशानिर्देशों आदि में नीतिगत मामलों के विचार-विमर्श और समाधान के लिए एक संरचित मंच के रूप में कार्य करेगी।

एससीसी का गठन डीएमडी, नाबार्ड की अध्यक्षता में डीएफएस, भारत सरकार, प्रायोजक बैंकों और आरआरबी के प्रतिनिधियों के साथ किया गया है। समिति डीएफएस, भारत सरकार/नाबार्ड द्वारा डीएफएस के पूर्व परामर्श से संदर्भित मुद्दों की जांच करेगी।

4.3.4.6 आरआरबी में स्थानांतरण नीति

अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने और आरआरबी में एक समान और गैर-विवेकाधीन स्थानांतरण व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार के डीएफएस ने आरआरबी में स्थानांतरण नीति तैयार करने के लिए आरआरबी को 20 फरवरी, 2025 के पत्र के माध्यम से संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

4.3.4.7 सरकार द्वारा नामित निदेशक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन संरचना में सुधार के लिए सरकार ने सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सरकार द्वारा नामित निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

4.3.4.8 आरआरबी के लिए व्यवहार्यता योजना

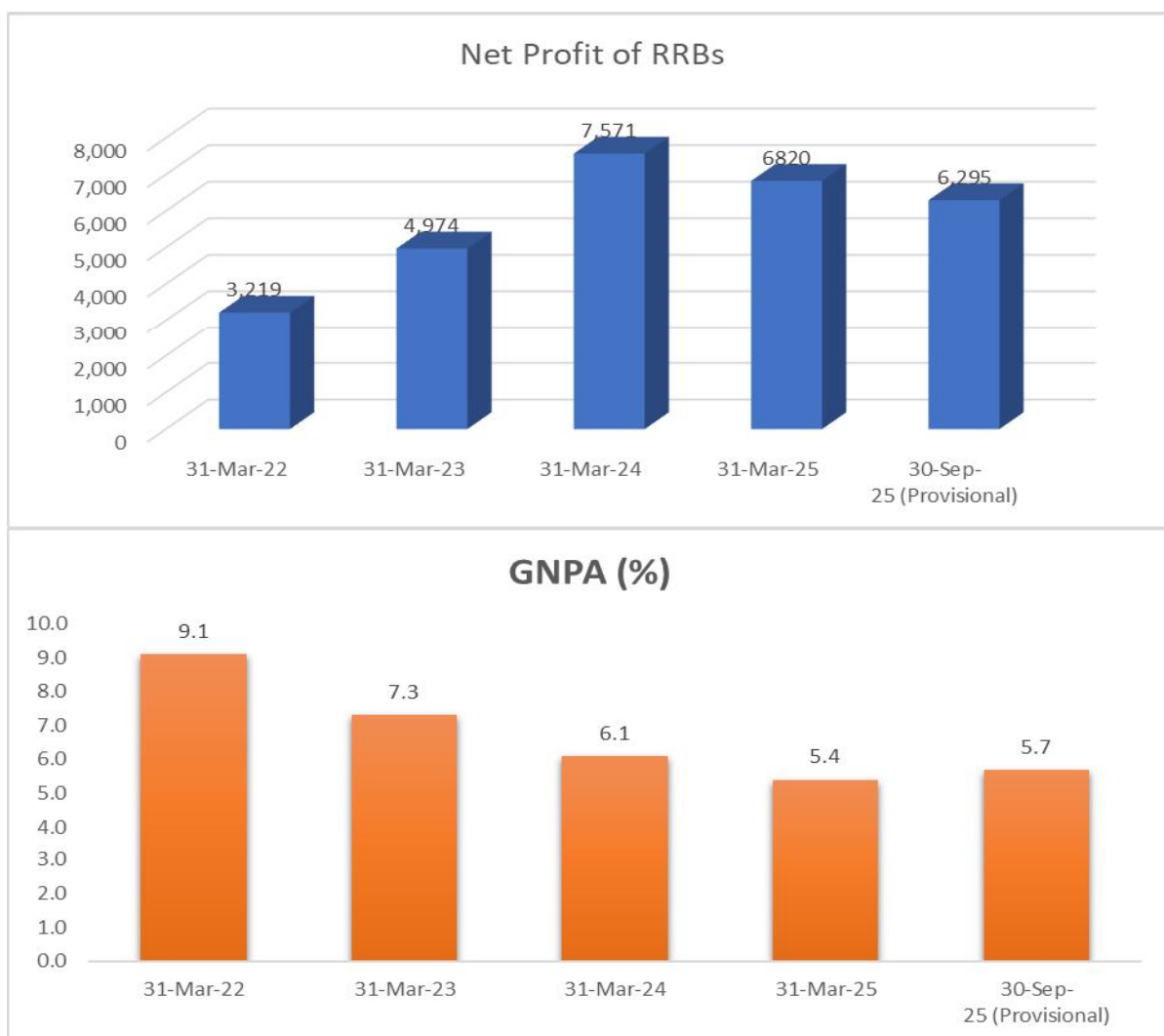
आरआरबी में प्रदर्शन निगरानी को संस्थागत बनाने और शासन सुधारों को मजबूत करने के लिए, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2024-25 को कवर करते हुए 3 साल की व्यवहार्यता योजना शुरू की है। उभरते वित्तीय दबावों और निरंतर निगरानी की निरंतर आवश्यकता को देखते हुए, योजना को अब वित्तीय वर्ष 2027-28 तक तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा रहा है।

विस्तार का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि आरआरबी ग्रामीण ऋण, डिजिटल समावेशन और वित्तीय पहुंच में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जुड़े रहें।

4.3.5 मुख्य वित्तीय पैरामीटर:

(राशि करोड़ रु. में)

विवरण	31-मार्च-22	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-25	30-सितंबर-25 (अंतरिम)
आरआरबी की संख्या (संख्या)	43	43	43	43	28
ब्रांच नेटवर्क (संख्या)	21,892	21,995	22,069	22,158	22,179
शेयर पूंजी	14,880	17,232	19,042	19,303	19,303
रिज़र्व	34,359	40,123	46,659	53,060	57,962
जमा	5,62,538	6,08,509	6,59,815	7,13,800	7,20,000
उधार	73,881	84,712	92,444	92,268	81,155
निवेश	2,95,665	3,13,401	3,19,099	3,21,213	3,00,281
सकल ऋण और अग्रिम बकाया	3,62,838	4,10,738	4,70,109	5,21,913	5,50,509
लाभ कमाने वाले आरआरबी की संख्या	34	37	40	38	25
लाभ की राशि (क)	4,116	6,178	7,796	8,018	6,546
नुकसान उठाने वाले आरआरबी की संख्या	9	6	3	5	3
नुकसान की राशि (ख)	897	1,205	225	1,193	251
आरआरबी का शुद्ध लाभ (क-ख)	3,219	4,974	7,571	6,820	6,295
जीएनपीए (राशि)	33,190	29,894	28,913	28,169	31,782
जीएनपीए (%)	9.1	7.3	6.1	5.4	5.7



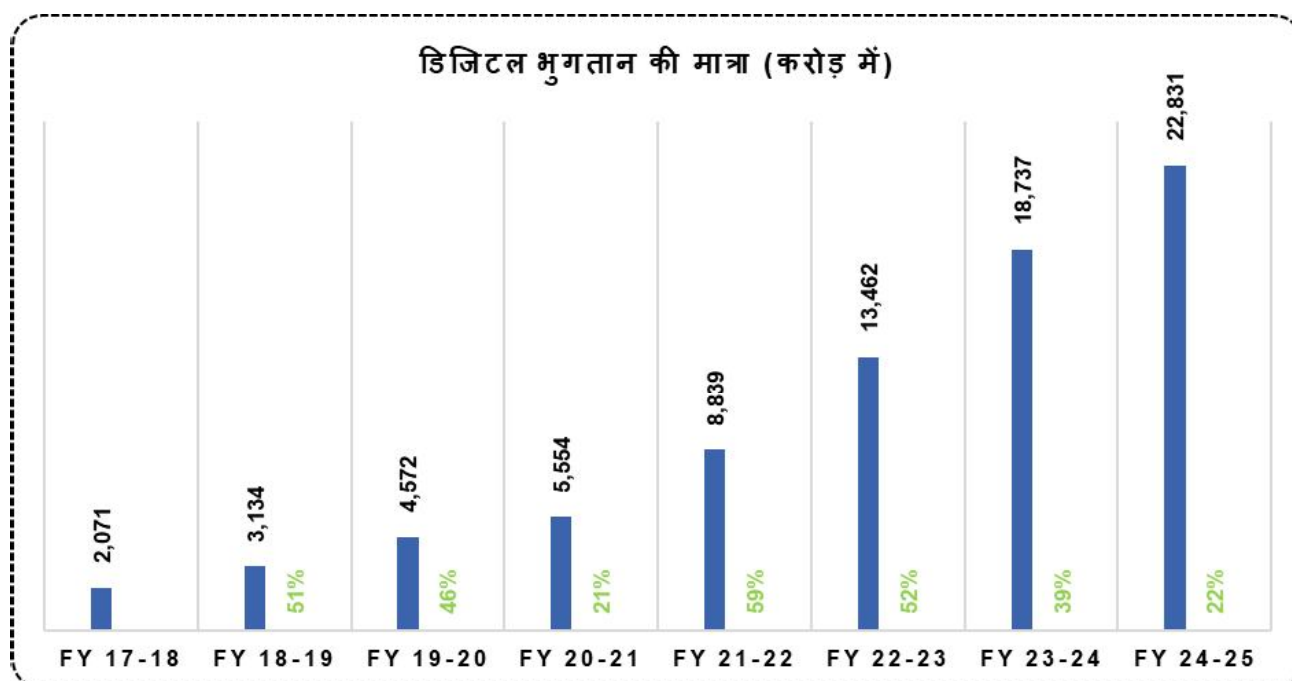
5. डिजिटल भुगतान

सरकार देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल कर रही है, विशेष रूप से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (आधार, यूपीआई, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, डिजी लॉकर, सीबीडीसी, ओएनडीसी आदि) के निर्माण के लिए। देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है, खासकर वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद। एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वैश्विक रियलटाइम भुगतान लेनदेन का लगभग 49% भारत में हो रहा है। डिजिटल भुगतान लेनदेन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,831 करोड़ हो गया है। इसी अवधि के दौरान, डिजिटल भुगतान लेनदेन का मूल्य 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,509 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 14 दिसंबर 2025 तक, डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या 19,040 करोड़ है और इसका मूल्य 2,181 लाख करोड़ रुपये है।

जुलाई 2023 में, 17 जुलाई 2023 के कैबिनेट अधिसूचना संख्या 1/21/6/2023-सीएबी के माध्यम से डिजिटल भुगतान का प्रचार एमईआईटीवाई से वित्तीय सेवाएं विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। वित्तीय सेवाएं विभाग देश में डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के प्रसार के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

5.1 डिजिटल भुगतान लेनदेन में प्रगति:

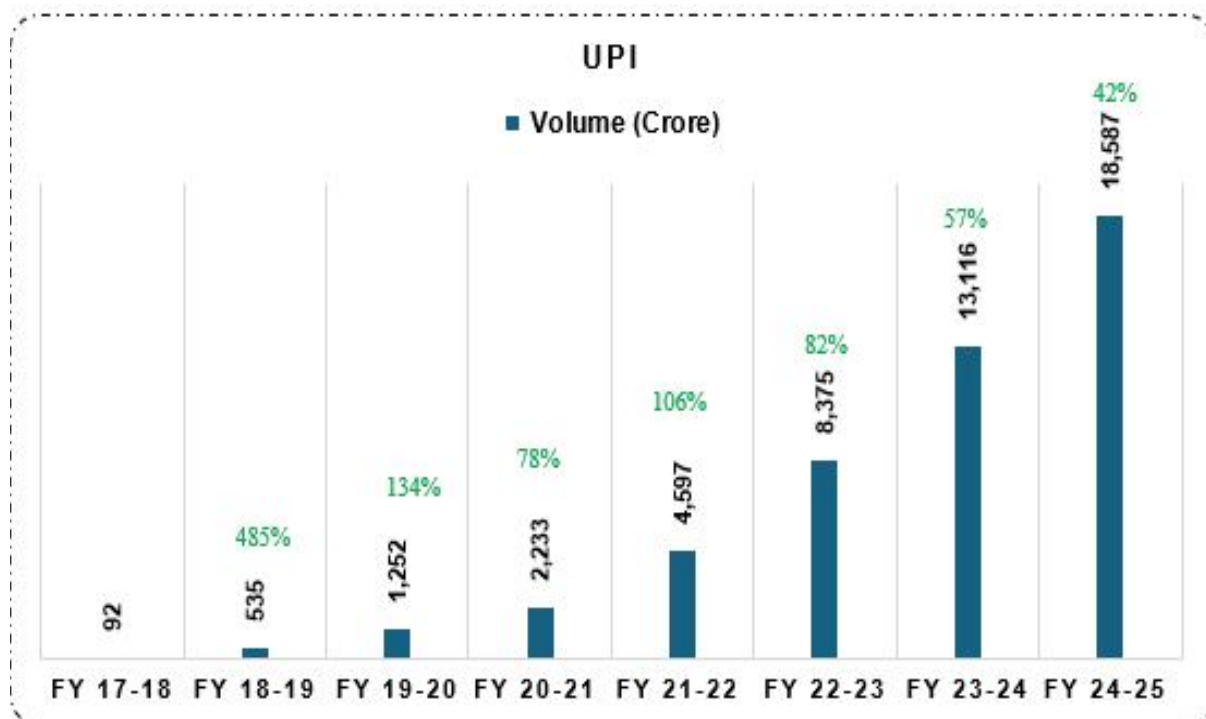
सभी हितधारकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में काफी वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान लेनदेन वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2,071 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 22,831 करोड़ हो गया है। इसी अवधि के दौरान, डिजिटल भुगतान लेनदेन का मूल्य 1,962 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 3,509 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 14 दिसंबर 2025 तक, डिजिटल भुगतान लेनदेन की संख्या 19,040 करोड़ है और इसका मूल्य 2,181 लाख करोड़ रुपये है।



- **एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)** स्वदेशी डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों से त्वरित और आसान भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान में क्रांति ला दी है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में यूपीआई लेनदेन 92 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18,587 करोड़ हो गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 14 दिसंबर 2025 तक यूपीआई लेनदेन की संख्या 16,518 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 में यूपीआई के आरंभ होने से भारत को रियल टाइम भुगतान प्रणाली और डिजिटल लेनदेन की समग्र प्रगति में ग्लोबल लीडर के रूप में अपने आप को

स्थापित करने में सहायता मिली है। एसीआई वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वैश्विक रियल-टाइम भुगतान लेनदेन का 49% भारत में हो रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में 81% डिजिटल भुगतान लेनदेन के साथ यूपीआई देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन की समग्र प्रगति में प्रमुख कारक बना है। (31 दिसंबर, 2024 तक)
- यूपीआई लेनदेन दिसंबर 2019 में प्रति माह 1.31 बिलियन (130.84 करोड़) लेनदेन से बढ़कर नवंबर 2025 में प्रति माह 20.46 बिलियन (2,046 करोड़) लेनदेन हो गया।



➤ डिजिटल भुगतान का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

- भारत में तैयार किए गए स्वदेशी यूपीआई और रुपये कार्ड डिजिटल भुगतान के लिए विश्वस्तरीय प्लेटफॉर्म हैं। सरकार इन उत्पादों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।
- वर्तमान में यूपीआई 8 देशों में अर्थात् यूएई, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर और कतर में पूरी तरह से कार्य कर रहा है।
- रुपये कार्ड को 6 देशों में अर्थात् नेपाल, भूटान, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव में स्वीकार किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में एक टास्क फोर्स तैयार की गई है ताकि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में भारत की जी20 अध्यक्षता के लक्ष्यों का पर्यवेक्षण कर सके और उसे पूरा कर सके और अभिशासन ढांचों के साथ यूपीआई जैसे नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके।

5.2 डिजिटल भुगतान अवसंरचना:

इकोसिस्टम में शामिल भागीदारों के समन्वित प्रयासों से देश में डिजिटल भुगतान स्वीकार्यता अवसंरचना में भारी वृद्धि हुई है, जो मार्च 2018 के 0.31 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2025 तक 73.59 करोड़ हो गई है।

➤ भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना:

आरबीआई ने 5 जनवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना को 1 जनवरी, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए परिचालित किया है। 29 दिसंबर, 2023 को इस योजना को आगे 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर राज्यों एवं जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए टियर-3 और टियर-6 केंद्रों में अंतर-परिचालनीय भुगतान स्वीकार्यता अवसंरचना के लिए सब्सिडी देकर अधिग्रहणकर्ताओं (बैंकों और गैर-बैंकों) तथा व्यापारियों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना में हर साल डिजिटल भुगतान के लिए 30 लाख नए टच प्वाइंट बनाने की परिकल्पना की गई है। अगस्त 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) के पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को पीआईडीएफ योजना के लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, अब योजना के विस्तार के साथ, देश भर में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को पीआईडीएफ योजना की शुरुआत के बाद से ही तैनाती के लिए व्यापारियों के रूप में शामिल किया गया है। 31 अक्टूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, पीआईडीएफ के माध्यम से लगभग 5.45 करोड़ डिजिटल टच प्वाइंट का परिनियोजन किए गए हैं।

परिनियोजन की स्थिति (30.11.2025 की स्थिति के अनुसार):

स्थान	वास्तविक उपकरण	डिजिटल उपकरण	साउंड बॉक्स उपकरण	आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपकरण
टियर 3 एवं 4 केंद्र	7,50,463	1,50,38,223	32,34,410	8,493
टियर 5 एवं 6 केंद्र	8,41,018	2,31,84,394	63,76,871	47,346
पूर्वोत्तर राज्य	1,49,853	25,79,758	4,92,089	5,112
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र	62,912	13,66,171	2,88,611	283
टियर 1 एवं 2 केंद्र (पीएम स्वनिधि योजना)	2,461	17,04,345	53,804	-
टियर 1 एवं 2 केंद्र (पीएम विश्वकर्मा योजना)	38	12,836	23,761	-
कुल	18,06,745	4,38,85,727	1,04,69,546	61,234
कुल टचप्वाइंट			5,62,23,252	

5.3 रुपये और यूपीआई के लिए प्रोत्साहन योजना:

- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना अर्थव्यवस्था को स्वच्छ और औपचारिक बनाने, निवेश को सक्रिय करने, ऋण तक पहुंच में सुधार करने और आम आदमी को व्यापक लाभ प्रदान करने के लिए बैंकों में बचत को मुख्यधारा में लाने की सरकार की रणनीति का एक अभिन्न अंग है।
- इस नीति पर जोर देने के लिए, दिनांक 01.01.2020 से, रुपये डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई का उपयोग करके किए गए भुगतान पर कोई शुल्क [मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) सहित] देय नहीं है। इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपने बजट भाषण में डिजिटल भुगतान माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के सरकार के इरादे की घोषणा की। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22, वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए “रुपये डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना” अधिसूचित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंकों और अन्य भुगतान प्रणाली संचालकों और ऐप प्रदाताओं को रुपये डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (2,000 रुपये तक) (व्यक्ति से व्यापारी) के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, “कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम)” के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना अवधि के लिए, अनुमानित परिव्यय 1,300 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 1,450 करोड़ रुपये कर दिया गया था। योजना के अंतर्गत सभी प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान पर वास्तविक व्यय के साथ योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय 1,389 करोड़ रुपये था। एक वर्षीय योजना दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई।
- योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित परिव्यय 2,600 करोड़ रुपये था, जिसमें इसके अंतर्गत सभी प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान पर वास्तविक व्यय 2,210 करोड़ रुपये था। एक वर्षीय योजना दिनांक 31.03.2023 को समाप्त हो गई।
- योजना अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित परिव्यय

3,500 करोड़ रुपये था, जिसे बढ़ाकर 3,637 करोड़ रुपये कर दिया गया था। योजना के अंतर्गत सभी प्रतिबद्ध देनदारियों के भुगतान पर वास्तविक व्यय के साथ योजना के अंतर्गत कुल व्यय 3,631 करोड़ रुपये था। एक वर्षीय योजना दिनांक 31.03.2024 को समाप्त हो गई।

- यह योजना डिजिटल भुगतान में वृद्धि लाने में सफल रही। भीम-यूपीआई लेनदेन की मात्रा 70 प्रतिशत की सीएजीआर अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 18,587 करोड़ हो गई। इसी प्रकार, मूल्य के संदर्भ में यूपीआई लेनदेन 59 प्रतिशत की सीएजीआर अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 में 41.03 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 260.57 लाख करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, रुपये डेबिट कार्ड (पीओएस और ईकॉम) लेनदेन की मात्रा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 137 करोड़ थी उसमें 24 % गिरावट से घटकर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 59 करोड़ हो गई। इसे भीम-यूपीआई से तीव्र प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिसके कारण पिछले वर्ष की तुलना में डेबिट कार्ड लेनदेन में समग्र गिरावट आई। इसी अवधि के दौरान डेबिट कार्ड का उपयोग करने वाले लेनदेन में समग्र डेबिट कार्ड उद्योग के लिए 26% की गिरावट आई है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए “कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 01 अप्रैल, 2024 से 1,500 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया गया था। दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार कुल वास्तविक व्यय 1,046 करोड़ रुपए था।

5.4 अकाउंट एग्रीगेटर

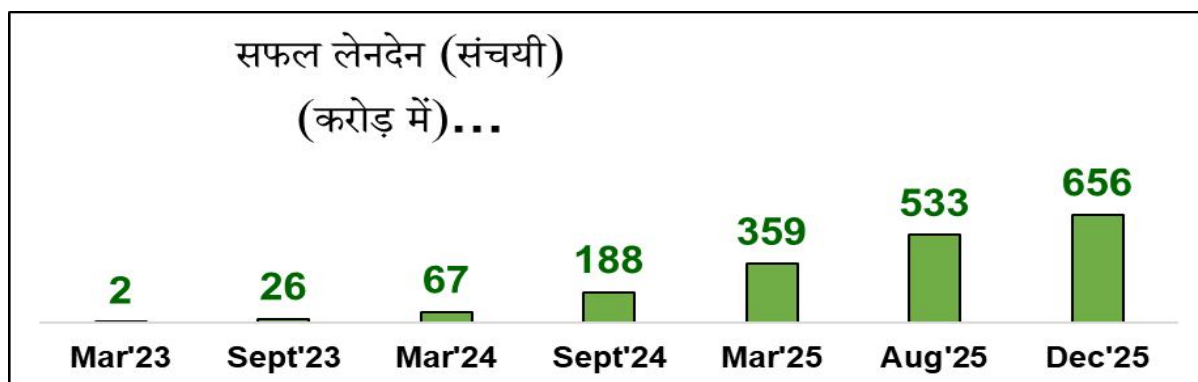
अकाउंट एग्रीगेटर एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जो ग्राहक से संबंधित वित्तीय सूचना को प्राप्त या एकत्र करने की सेवा प्रदान करने का व्यवसाय करती है। ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना एए ढांचे द्वारा ग्राहक की कोई वित्तीय सूचना प्राप्त, साझा या स्थानान्तरित नहीं की जाती है। किसी व्यक्ति के अनुदेश और सहमति के आधार पर ही एए एक वित्तीय संस्थान से दूसरे को डाटा स्थानान्तरित करता है। इस संबंध में, भारतीय

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 02 सितंबर, 2016 को मास्टर निदेश अर्थात् गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) – अकाउंट एग्रीगेटर (रिजर्व बैंक) निदेश जारी किए हैं।

संस्थाएं अर्थात् बैंक, बैंकिंग कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी), आस्ति प्रबंधन कंपनी, निक्षेपागार, निक्षेपागार सहभागी, बीमा कंपनी, बीमा कोष, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जीएसटीएन, दि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसे वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) और ऐसी अन्य संस्थाएं जैसाकि इन निदेशों के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और वित्तीय सूचना

उपयोगकर्ता (एफआईयू), जो एक पंजीकृत संस्था है और किसी वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित होती है, के रूप में एए फ्रेमवर्क में शामिल हो सकते हैं। वर्तमान में, आरबीआई ने सत्रह कंपनियों को एए का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में पंजीकरण की प्रक्रिया, सहमति की रूपरेखा, डाटा सुरक्षा, तकनीकी विनिर्देश, वित्तीय सूचना प्रदाताओं द्वारा वित्तीय सूचना साझा करने और अकाउंट एग्रीगेटर व वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता द्वारा सूचना का उपयोग करने के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश दिए गए हैं। उपयोग के संदर्भ में, एए फ्रेमवर्क ने अपने शुभारंभ के बाद से अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है।



हालांकि इकोसिस्टम की शुरुआत एंकर उपयोग के मामले के रूप में ऋण देने के साथ हुई है, व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन, एफएंडओ खाता खोलने के लिए आय सत्यापन और जीवन बीमा के लिए वित्तीय हामीदारी प्रमुख अनुप्रयोग बन गए हैं।

6. वित्तीय समावेशन

6.1 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

बैंकिंग पैठ बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश भर में प्रति परिवार कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध कराने की दृष्टि से 15 अगस्त, 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) नामक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (एफआई) की घोषणा की गई थी। इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक रूप से किया गया था। 14 अगस्त, 2018 तक 2 चरणों में वंचित वर्गों का व्यापक वित्तीय समावेशन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित था :-

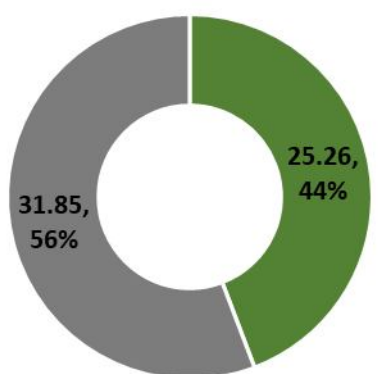
- पहला चरण (15 अगस्त, 2014 - 14 अगस्त, 2015) :- अवसरानुसार और कनेक्टिविटी की बाधाओं वाले क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच और 1 लाख रुपये के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ मूल बैंकिंग खाते और रुपये डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन करना।

- दूसरा चरण (15 अगस्त, 2015 - 14 अगस्त, 2018) :- छह महीने के संतोषजनक परिचालन/पूर्व विवरण के पश्चात 5,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट (ओडी) की सुविधा दी जाएगी। ओवरड्राफ्ट खातों और स्वावलंबन जैसे असंगठित क्षेत्र की पेंशन योजनाओं में चूक के कवरेज के लिए ऋण गारंटी निधि का सृजन किया जाएगा।
- पीएमजेडीवाई का विस्तार - पीएमजेडीवाई योजना को दिनांक 14.08.2018 के बाद भी खोलने पर ध्यान केंद्रित करना का तरीका "प्रत्येक परिवार" से बदलकर "प्रत्येक बैंक रहित वयस्क" कर दिया गया है साथ ही योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित में वृद्धि की गई है :-
 - क) ओडी सीमा को 5,000 रुपये से 10,000 रुपये;
 - ख) रुपये कार्ड धारकों का दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये;
 - ग) ओडी सुविधा का लाभ उठाने की आयु सीमा को 18-60 वर्ष से बढ़ाकर 18-65 वर्ष करना; और
 - घ) 2000 रुपये तक ओडी के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है।

6.1.1. पीएमजेडीवाई का कार्य-निष्पादन

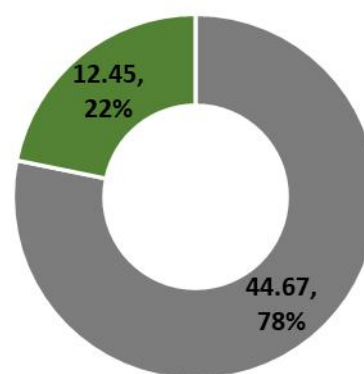
पीएमजेडीवाई की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं (संख्या करोड़ में) :						
निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	पीएमजेडीवाई खाते (करोड़ में)	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (पुरुष)	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (महिला)	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (ग्रामीण/अर्धशहरी)	पीएमजेडीवाई खातों की संख्या (शहरी/मेट्रो)	पीएमजेडीवाई खातों में जमा (करोड़ रुपए में)
मार्च '15	14.72	7.15	7.39	8.68	5.86	14,641
मार्च '16	21.43	10.37	11.05	13.17	8.26	35,672
मार्च '17	28.17	13.67	14.49	16.87	11.30	62,972
मार्च '18	31.44	14.85	16.60	18.52	12.92	78,494
मार्च '19	35.27	16.53	18.74	20.90	14.37	96,107
मार्च 20	38.33	17.85	20.48	22.63	15.70	1,18,434
मार्च 21	42.20	18.82	23.38	27.85	14.35	1,45,551
मार्च '22	45.06	19.98	25.08	30.07	14.99	1,66,459
मार्च '23	48.65	21.60	27.05	32.45	16.20	1,98,844
मार्च '24	51.95	23.05	28.90	34.58	17.36	2,32,502
मार्च 25	55.18	24.43	30.75	36.74	18.44	2,60,387
नवंबर '25	57.11	25.26	31.85	44.67	12.45	2,74,033

पीएमजेडीवाई खातों का लिंग-वार विभाजन (करोड़ में)



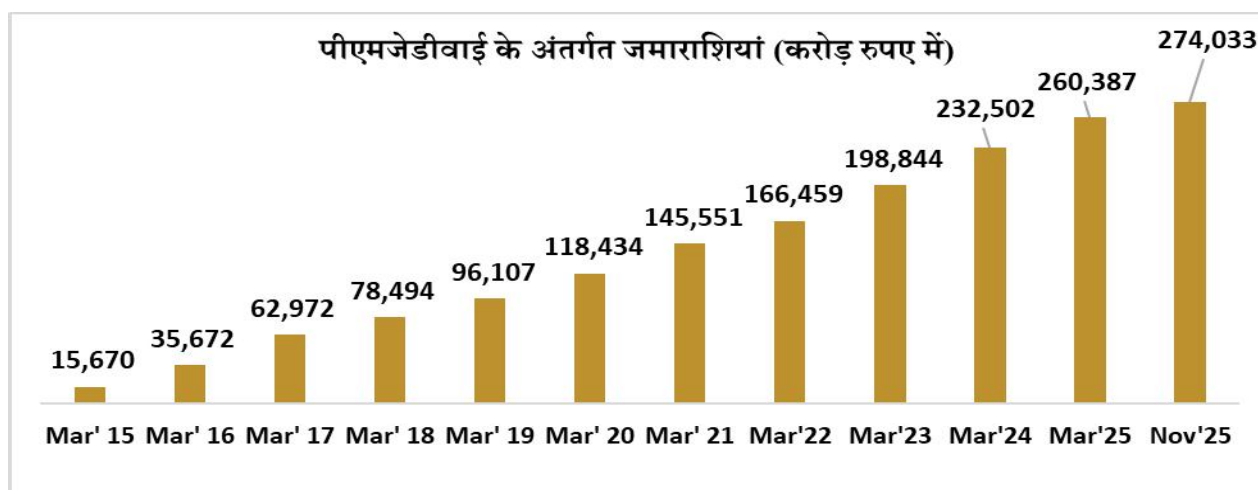
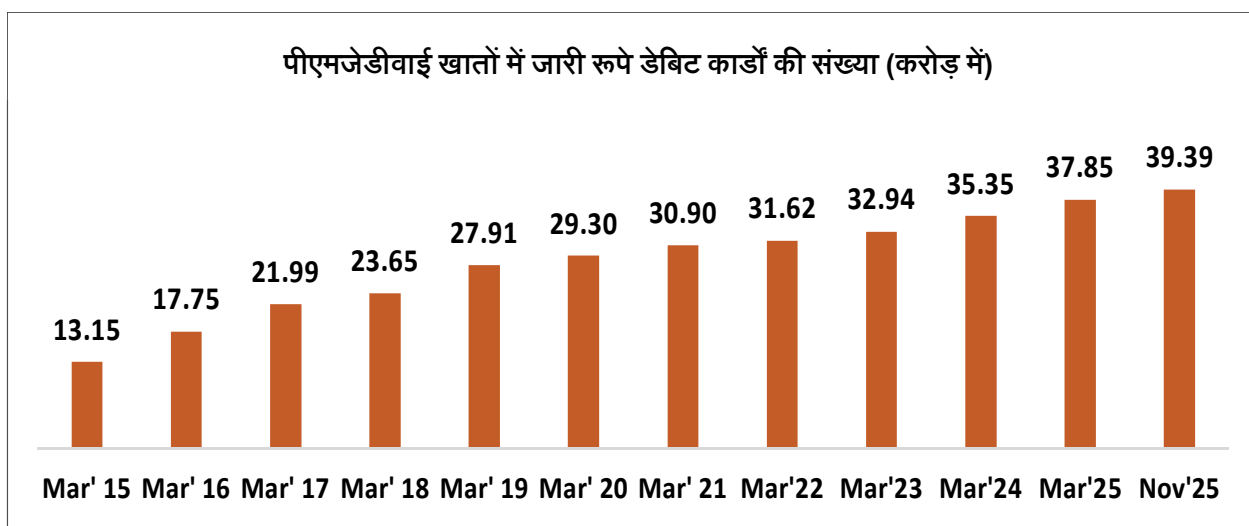
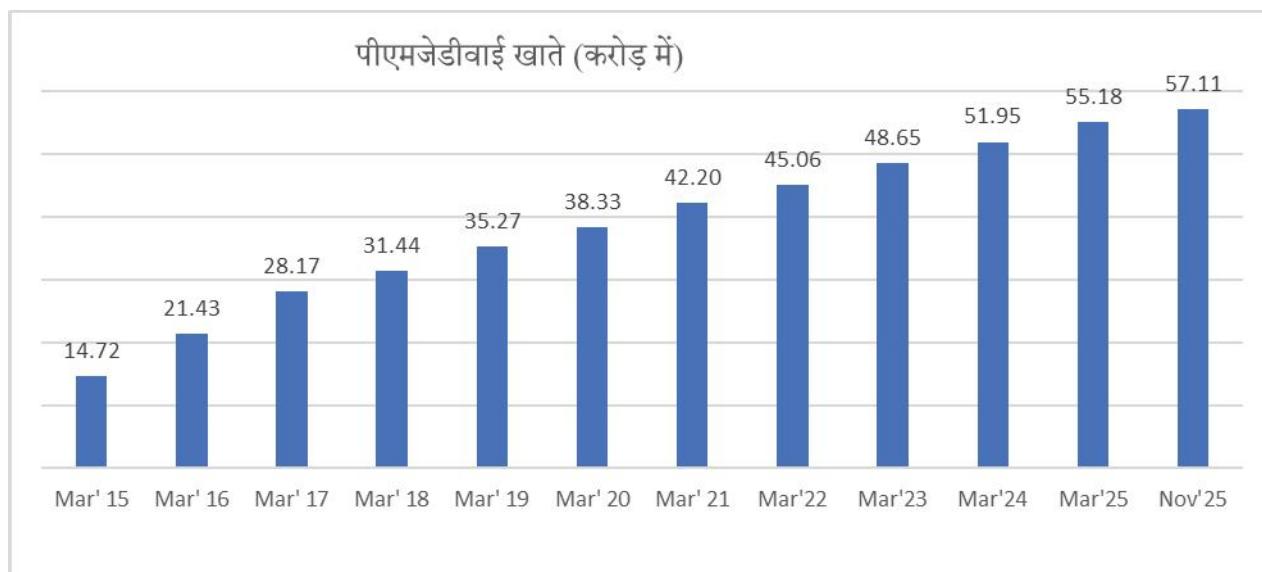
■ No of PMJDY accounts (Male)
■ No of PMJDY accounts (Female)

पीएमजेडीवाई खातों का क्षेत्र-वार विभाजन (करोड़ में)

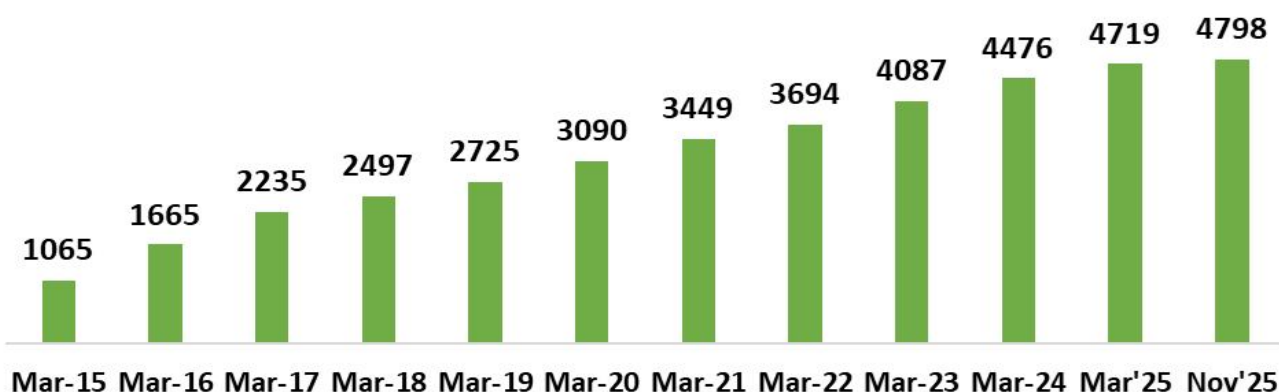


■ No of PMJDY accounts (Rural/Semi-urban)
■ No of PMJDY accounts (Urban/Metro)

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत प्रमुख रुझान



प्रति खाता जमाराशियां रुपए में



पीएमजेडीवाई के अंतर्गत नवंबर 2025 तक 2,74,033 करोड़ रुपए की शेष जमाराशि के साथ कुल 57.11 करोड़ जन-धन खाते खोले गए। पीएमजेडीवाई खाते में प्रति खाता औसत शेष जमा राशि लगभग 4,798 रुपए है।

31.85 करोड़ (55.8%) महिला जन-धन खाताधारक हैं जिनमें से लगभग 44.67 करोड़ (78.2%) खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं।

पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 2 लाख रुपए (दिनांक 28.8.2018 के पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपए) की अन्तर्निहित दुर्घटना बीमा

कवरेज के साथ लगभग 39.39 करोड़ रुपये कार्ड भी प्रदान किए गए हैं।

पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए कुल सक्रिय खातों में से 88.6% को खाताधारक की सहमति के आधार पर उसके आधार नंबर से जोड़ा जा चुका है, जिससे अंतर-परिचालनीय और त्वरित आधार संख्या पर आधारित लेनदेन संभव हुआ है, जिसमें आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शामिल है।

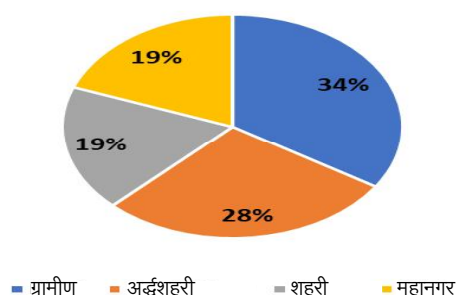
6.2 बैंकिंग टच प्वाइंट: पिछले कुछ वर्षों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या में वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

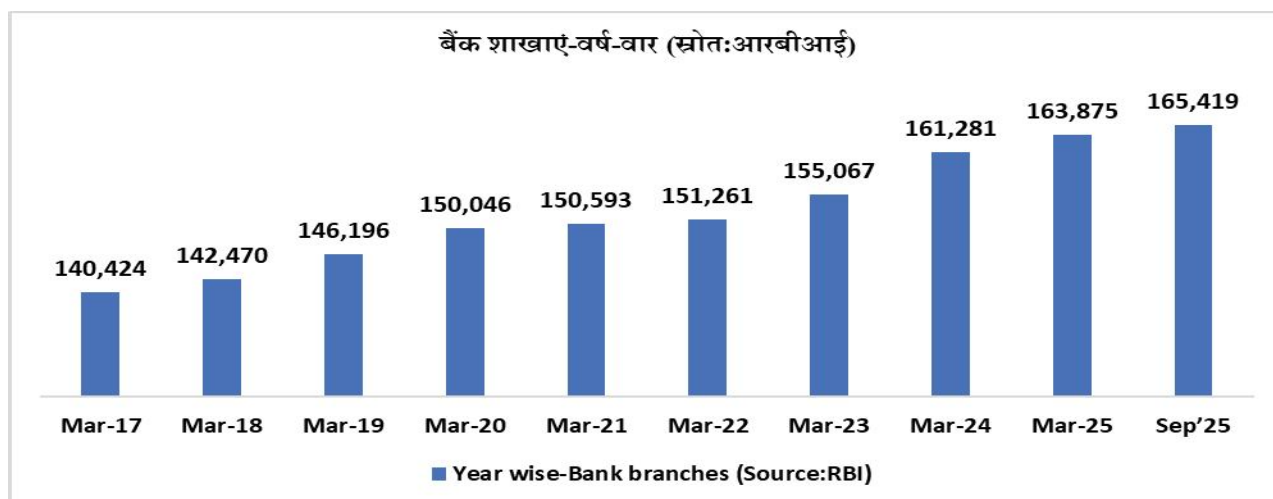
तालिका 1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की संख्या :

	ग्रामीण	अर्द्धशहरी	शहरी	महानगर	कुल
मार्च-17	49,860	38,931	25,103	26,530	1,40,424
मार्च-18	50,860	39,616	25,458	26,536	1,42,470
मार्च-19	51,609	41,031	26,399	27,157	1,46,196
मार्च-20	52,382	42,213	27,318	28,133	1,50,046
मार्च-21	52,651	42,441	27,446	28,055	1,50,593
मार्च-22	53,204	42,443	27,433	28,181	1,51,261
मार्च-23	54,244	43,745	28,021	29,057	1,55,067
मार्च-24	55,213	45,101	29,083	30,319	1,59,716
मार्च-25	56,080	46,405	30,047	31,343	1,63,875
सितंबर-25	56,406	46,875	30,356	31,782	1,65,419

स्रोत: आरबीआई

बैंक शाखाओं का क्षेत्र-वार विभाजन (सितंबर '25 की स्थिति के अनुसार)



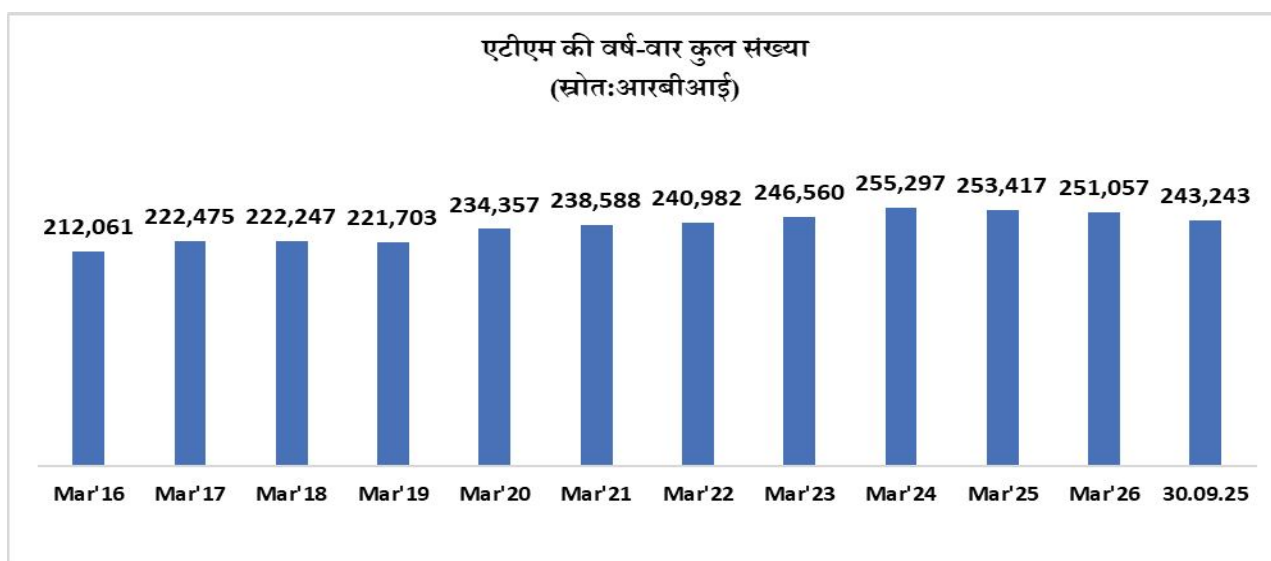


तालिका 2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), पेमेंट बैंकों (पीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों के एटीएम की संख्या

निम्नलिखित की स्थिति के अनुसार	ऑफसाइट एटीएम- *	ऑनसाइट एटीएम-	कुल एटीएम *
31.03.2016	1,10,111	1,01,950	2,12,061
31.03.2017	1,12,666	1,09,809	2,22,475
31.03.2018	1,15,471	1,06,776	2,22,247
31.03.2019	1,15,323	1,06,380	2,21,703
31.03.2020	1,21,086	1,13,271	2,34,357
31.03.2021	1,22,983	1,15,605	2,38,588
31.03.2022	1,29,766	1,16,794	2,46,560
31.03.2023	1,31,684	1,23,613	2,55,297
31.03.2024	1,27,301	1,26,116	2,53,417
31.03.2025	1,19,734	1,31,323	2,51,057
30.09.2025	1,11,579	1,31,664	2,43,243

स्रोत: आरबीआई

* इसमें व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों द्वारा लगाए गए एटीएम शामिल हैं।

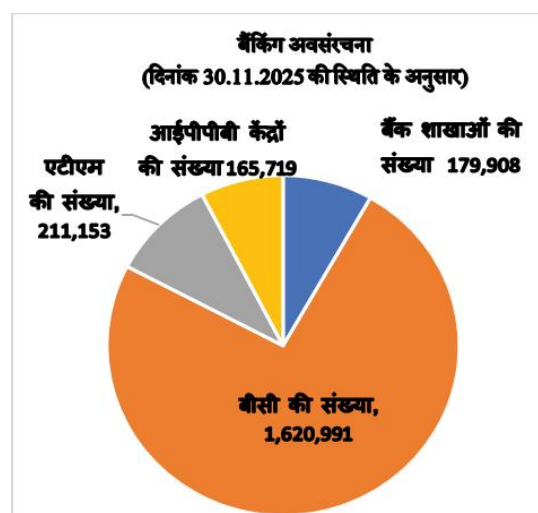
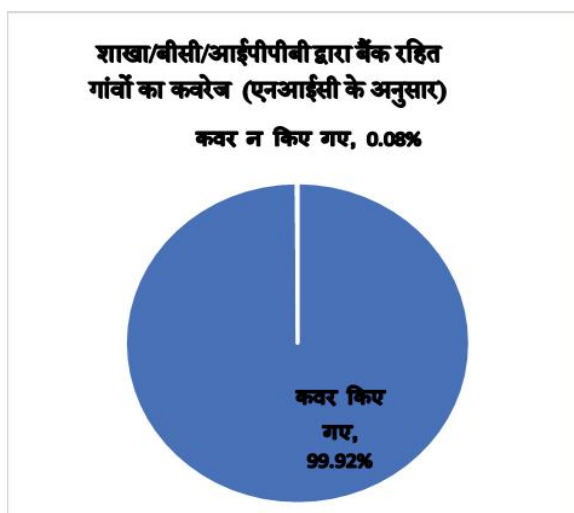


प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के कार्ड स्वीकृति उपकरणों की संख्या मार्च 2020 में 51.86 लाख थी जो अक्टूबर 2025 में बढ़कर 123.17 लाख हो गई है।

6.3 जन धन दर्शक एप

एक मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है, जो कि देश में बैंक शाखाओं, एटीएम, बैंक मित्र, डाकघर इत्यादि जैसे बैंकिंग सेवा सम्पर्क

स्थलों का पता लगाने के लिए एक नागरिक केंद्रित प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। इस एप्लीकेशन का वेब संस्करण <http://findmybank.gov.in> लिंक पर उपलब्ध है। बैंक/आईपीपीबी को ऐप पर अपनी शाखाओं, व्यवसाय प्रतिनिधि और एटीएम की जीआईएस स्थिति अपलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेन्शियल्स (लॉगिन के लिए विवरण) प्रदान किए गए हैं।



जेडीडी ऐप के अनुसार, 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, बैंकों द्वारा 1.80 लाख शाखाएं, 17.87 लाख बीसी (1.66 लाख आईपीपीबी-बीसी सहित) और 2.11 लाख एटीएम अभिचिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा, बैंकों द्वारा जेडीडी ऐप पर अपलोड किए गए डाटा के अनुसार ऐप पर अभिचिह्नित किए गए 6.01 लाख (6,01,328) गांवों में से 6.00 लाख (6,00,821) (99.92%) गांवों में 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर शाखा या बीसी की सुविधा उपलब्ध है।

6.4 जन-धन आधार मोबाइल (जेएएम)

जन-धन खाते को मोबाइल नंबर तथा आधार से जोड़ने के लिए एक जन-धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) पाइपलाइन तैयार की गई है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के प्रवाहों, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन योजनाओं को अपनाने, ऋण प्रवाहों को सुकर बनाने, डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने आदि के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान कर रही है। इसने डिजिटलीकृत, वित्तीय रूप से समावेशी और बीमित समाज बनाने की गति को तेज करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की है। विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभों का तत्काल अंतरण जेएएम पाइपलाइन के माध्यम से संभव हो सका है।

6.5 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 16.10.2022 को देश की आजादी के 75 वर्ष (आजादी का अमृत महोत्सव) मनाने के लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) समर्पित की। सार्वजनिक, निजी क्षेत्र और लघु वित्त बैंक सहित 24 बैंकों द्वारा स्थापित ये डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करती

हैं। डीबीयू उन लोगों की सहायता करने के लिए हैं जो डिजिटल बैंकिंग को अपनाने हेतु तकनीकी रूप से सक्षम (टेक सेवी) नहीं हैं और जिसमें ग्राहकों को दो तरीके से उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी: सेल्फ सर्विस के माध्यम और डिजिटल सहायता के माध्यम से।

डीबीयू के माध्यम से दी जा रही सेवाओं में बचत खाता खोलना, शेष राशि की जांच, पासबुक-प्रिंटिंग, निधियों का अंतरण, सावधि जमा में निवेश, ऋण आवेदन, जारी किए गए चेक के लिए भुगतान रोकने संबंधी अनुदेश, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन, खाता विवरण देखना, कर भुगतान, बिल भुगतान, नामांकन करना आदि जैसी बैंकिंग सुविधाएं शामिल हैं। डीबीयू जन समर्थ पोर्टल और कम मूल्य वाले एमएसएमई/खुदरा ऋणों के एंड-टू-एंड डिजिटल प्रोसेसिंग के माध्यम से सरकारी ऋण संबद्ध योजनाओं में ऑन बोर्डिंग के लिए सुविधा भी प्रदान कर रहा है।

एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 16.10.2022 से दिनांक 30.11.2025 की अवधि के दौरान निर्धारित सभी 116 डीबीयू में 2.97 करोड़ से अधिक हस्तक्षेप (प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में) हुए हैं।

6.6 क्षेत्रीय असंतुलन: ध्यान केंद्रित करना

आकांक्षी जिलों के बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए वित्तीय समावेशन (एफआई) पैरामीटर के अधीन 112 आकांक्षी जिलों (एडी) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें लक्षित वित्तीय समावेशन पहल कार्यक्रम (टीएफआईआईपी) नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। डीएफएस वित्तीय समावेशन पैरामीटर में पीछे चल रहे 10 चयनित जिलों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए 'मिशन उत्कर्ष' पर भी काम कर रहा है।

6.7 मुख्य योजनाएं

6.7.1 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) — यह योजना किसी बैंक/डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष के आयु-वर्ग के उन लोगों के लिए उपलब्ध है, जो इसमें शामिल होने/स्वतः डेबिट (ऑटो-डेबिट) के लिए अपनी सहमति देते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज है, जो 436/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर है, जिसे अभिदाता के बैंक / डाकघर खाते से स्वतः डेबिट किया जाना है।

6.7.2. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) — यह योजना 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास बैंक / डाकघर खाता है जो उसमें स्वतः आहरण में शामिल होने के लिए अनुमति देते हैं। इस योजना के अंतर्गत 20 रुपये प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के मामले में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये है; जिसकी 'स्वतः आहरण' के माध्यम से खाताधारक के बैंक / डाकघर खाते से कटौती की जाती है।

पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई के कार्यान्वयन में मुख्य सुधार:

- दावे के लंबित मामले की अवधि को कम करने और सही दावेदारों को लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीएमजेजीबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए नामांकन और दावा संबंधी फॉर्मों में

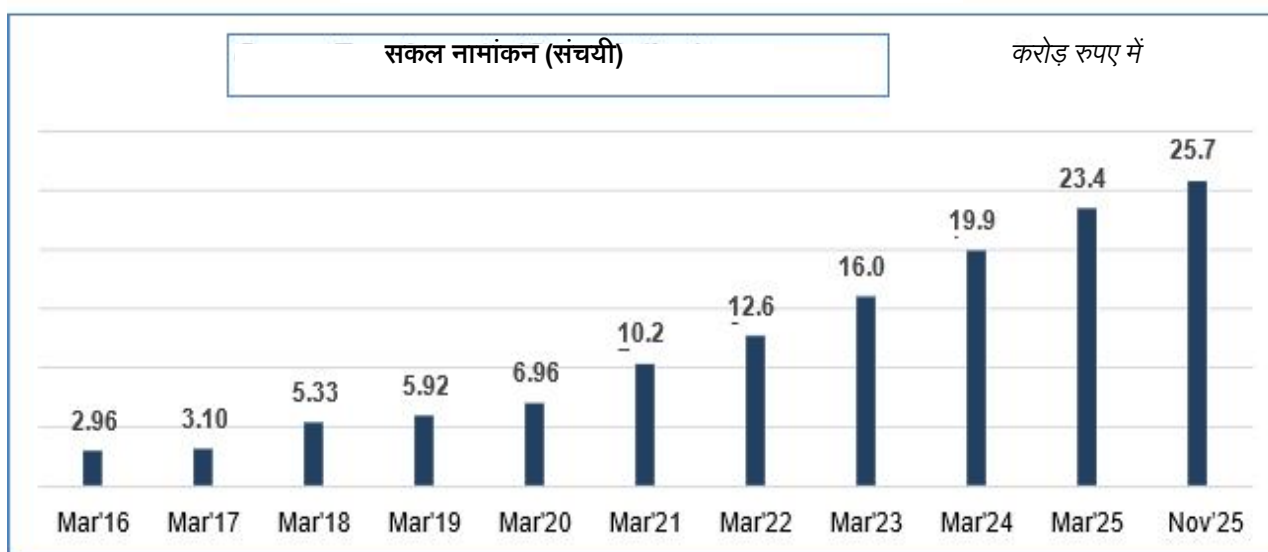
संशोधन किया गया है।

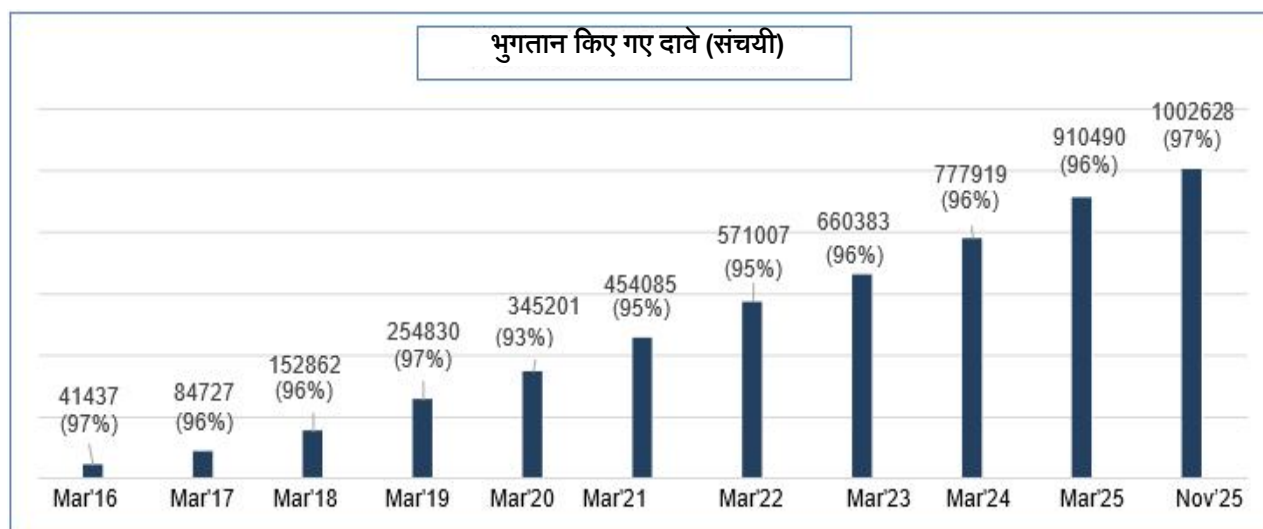
- नामिती (या नाबालिग नामिति के लिए नियुक्त व्यक्ति) का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आयु अब दर्ज की जाती है और किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में नामितियों को उपलब्ध लाभ और दावा प्रक्रिया के बारे में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में तत्परतापूर्वक सूचित किया जाता है।
- दुर्घटनावश मृत्यु, जिसके लिए दावा इस योजना में शामिल होने की तारीख से स्वीकार्य है, को छोड़कर पीएमजेजीबीवाई के अंतर्गत मृत्यु के मामले के दावे की स्थिति में प्रतीक्षा अवधि को 1 जून 2021 से 45 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।
- बैंकों ने अपने कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) से उन मौजूदा अभिदाताओं की पहचान करने का अनुरोध किया है जिसके खाते में दिनांक 31.5.2022 की स्थिति के अनुसार पर्याप्त शेष राशि नहीं है ताकि उनके खाते से प्रीमियम की राशि ऑटोडेबिट किया जा सके और प्रीमियम दरों में संशोधन के संबंध में एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जा सके।
- बैंक/डाकघर दावा प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर अपने सहभागी बीमाकर्ता की नामोदिष्ट ऐप/ईमेल आईडी पर दावा दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से अग्रेषित करें और बीमाकर्ता दावा प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर दावों का निपटान करें।

नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार प्रगति निम्नानुसार है :

योजना	पात्रता (वर्ष)	प्रीमियम (वार्षिक)	संचयी नामांकन (करोड़)	भुगतान किए गए दावे	दावों की राशि (करोड़)	निपटान अनुपात (%)
पीएमजेजीबीवाई	18 से 50	436 रुपए	25.79	10,02,628	Rs.20,052.56	99.94%
पीएमएसबीवाई	18 से 70	20 रुपए	55.32	1,70,608	Rs. 3,388.40	97.05%

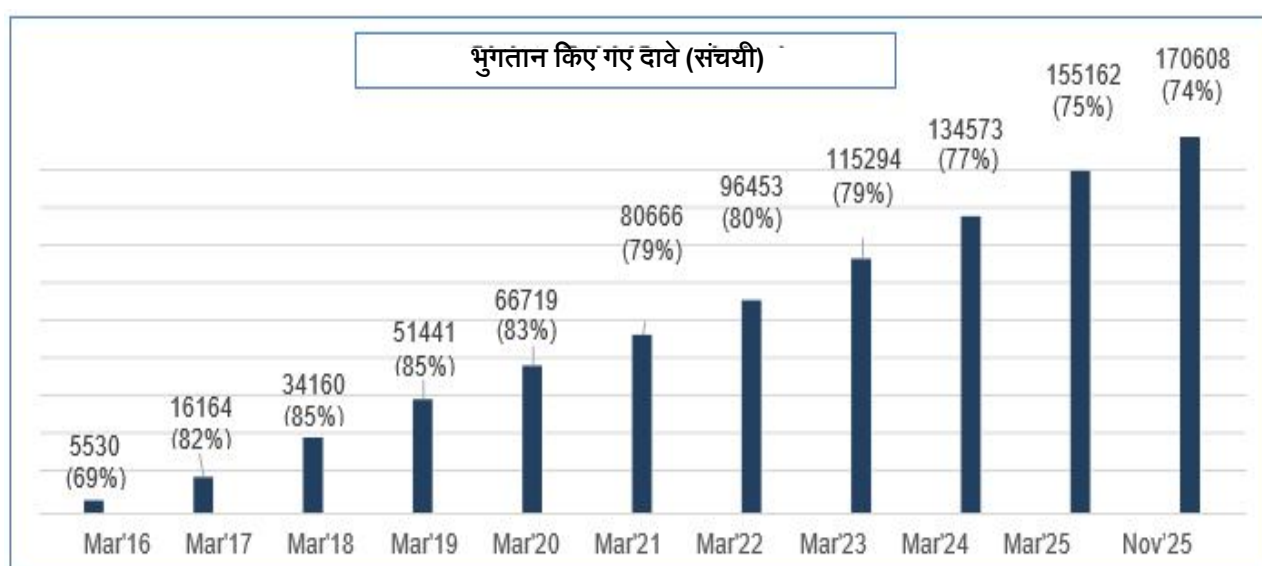
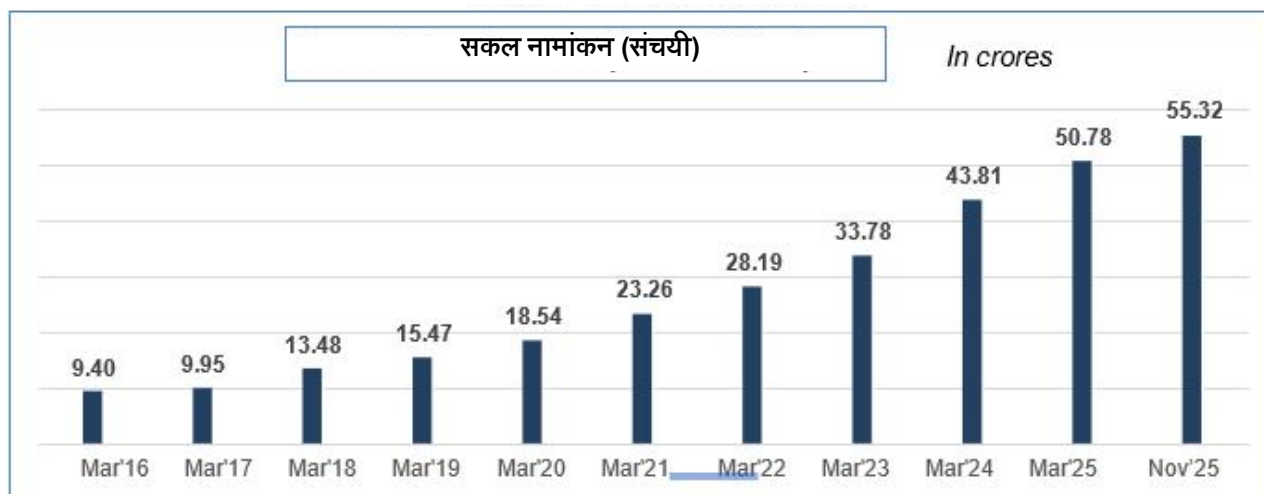
नवंबर 25 की स्थिति के अनुसार पीएमजेजीबीवाई रुझान





प्रतिशत भुगतान किये गए संचयी दावों बनाम सूचित किए गए संचयी दावों को दर्शाता है

नवंबर' 25 की स्थिति के अनुसार पीएमएसबीवाई का रुझान



प्रतिशत भुगतान किये गए संचयी दावों बनाम सूचित किए गए संचयी दावों को दर्शाता है

6.7.3 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) - यह योजना 8 अप्रैल 2015 को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय-सृजित करने वाले छोटे व्यवसाय उद्यमों के वित्तपोषण के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मुर्गी पालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, आदि जैसी कृषि से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों तरह की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। पीएमएमवाई के अंतर्गत ऋण सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) जैसे; बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के माध्यम से दिए जाते हैं।

- श्रेणियाँ: शिशु - 50,000/- रु. तक, किशोर- 50,000 रु. से 5 लाख रु. तक, तरुण - 5.00 लाख रु. से 10.00 लाख रु. तक, तरुण प्लस – 10 लाख रु. से 20 लाख रु. तक (उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 से 'तरुण' श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है)।
- पीएमएमवाई के अंतर्गत मुद्रा ऋण की सीमा मौजूदा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। विशेष रूप से उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है, के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋण की एक नई श्रेणी, तरुण प्लस आरंभ की गई है। दिनांक 24.10.2024 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत 20 लाख रुपये तक के पीएमएमवाई ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है।
- 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण।
- सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋणों और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत स्वीकृत ओवरड्राफ्ट ऋण राशि को गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म इकाइयों के लिए एक ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पश्चात, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के स्वीकृत ऋण भी सीजीएफएमयू के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगे। कंपनी अधिनियम, 1956 (2013) के अंतर्गत गठित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी), इस निधि की ट्रस्टी है।
- दिनांक 31.12. 2025 की स्थिति के अनुसार, लाइव गारंटी के अंतर्गत कवर की गई स्वीकृत राशि 5.60 लाख करोड़ रुपये है।

दिनांक 10.01.2025 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत उपलब्धियाँ

- इस योजना के आरम्भ से, 37.57 लाख करोड़ रुपये की राशि के 55.85 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं। नए

उद्यमियों को कुल ऋण का लगभग 21% स्वीकृत किया गया है।

- ऋणों की कुल संख्या में से महिला उद्यमियों को लगभग 68% ऋण स्वीकृत किए गए हैं और एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के उधारकर्ताओं को 50% ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

- श्रेणीवार विवरण: -

श्रेणी	ऋणों की संख्या (%)	स्वीकृत राशि (%)
शिशु	76%	33%
किशोर	22%	42%
तरुण	2%	25%
तरुण प्लस	-	-
कुल	100%	100%

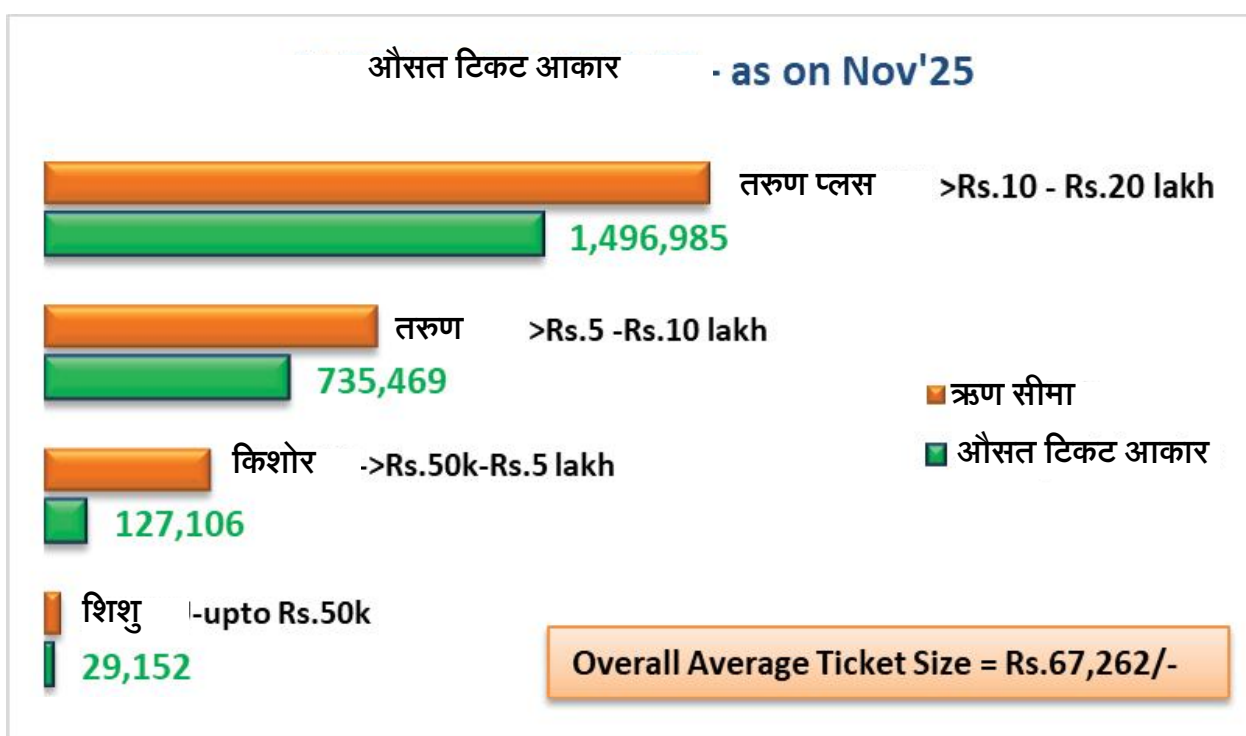
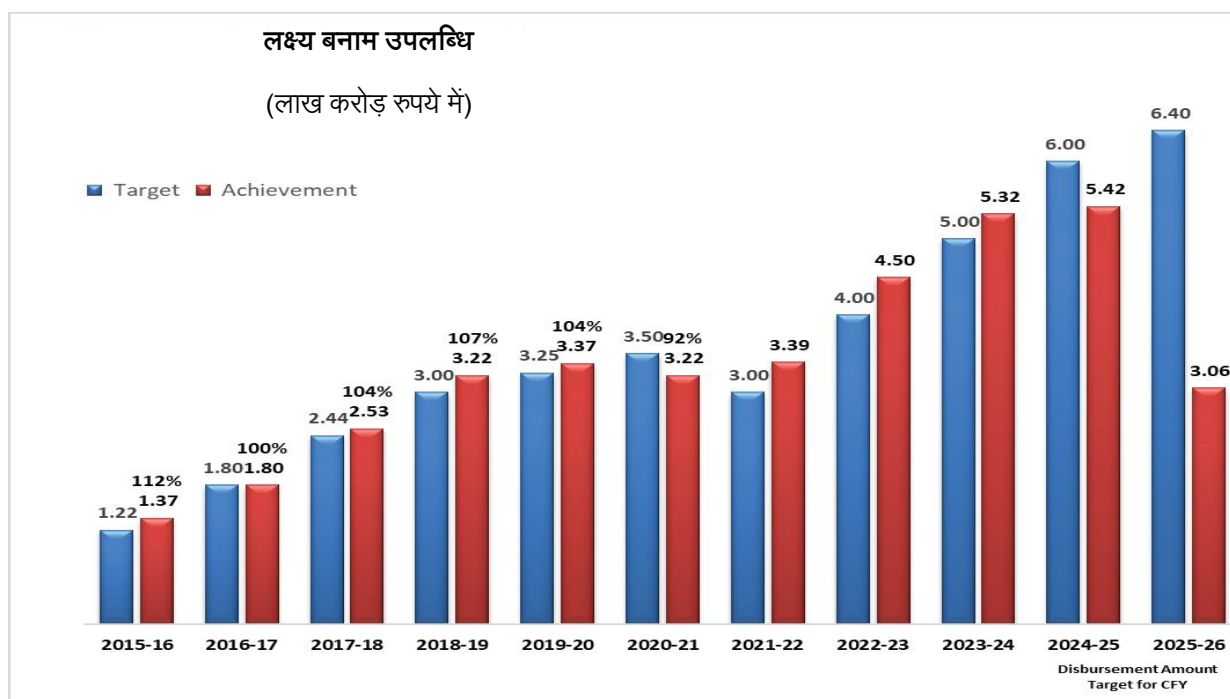
- इस योजना के आरम्भ से कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 को छोड़कर लक्ष्यों को लगातार पूरा किया गया है।

- वर्ष-वार स्वीकृति राशि इस प्रकार है: -

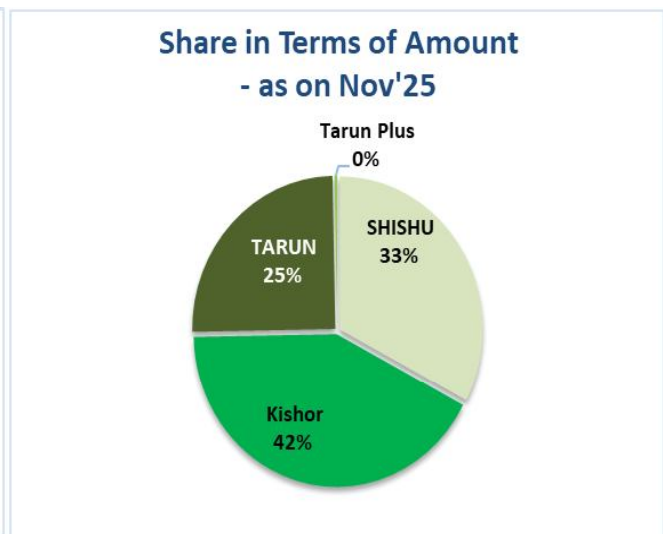
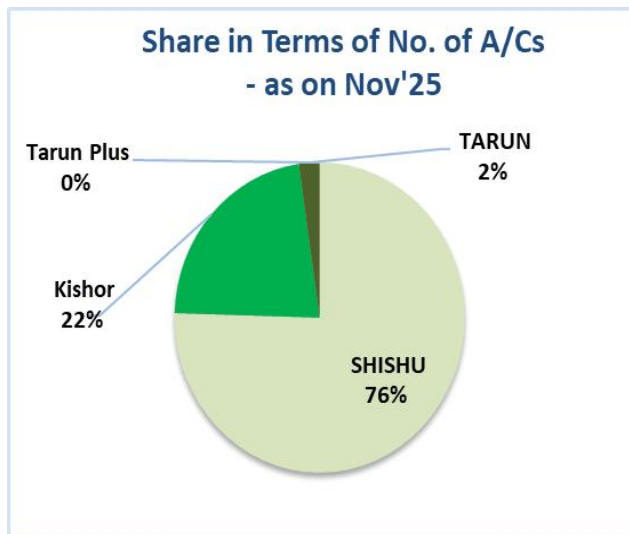
वर्ष	स्वीकृत ऋणों की संख्या (करोड़ में)	स्वीकृत राशि (लाख करोड़ रुपए)
2015-16	3.49	1.37
2016-17	3.97	1.80
2017-18	4.81	2.54
2018-19	5.98	3.22
2019-20	6.22	3.37
2020-21	5.07	3.22
2021-22	5.38	3.39
2022-23	6.23	4.56
2023-24	6.67	5.41
2024-25	5.46	5.52
2025-26 (नवंबर 25 तक)	2.54	3.15
कुल	55.85	37.57

समेकित उपलब्धियां (नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार)

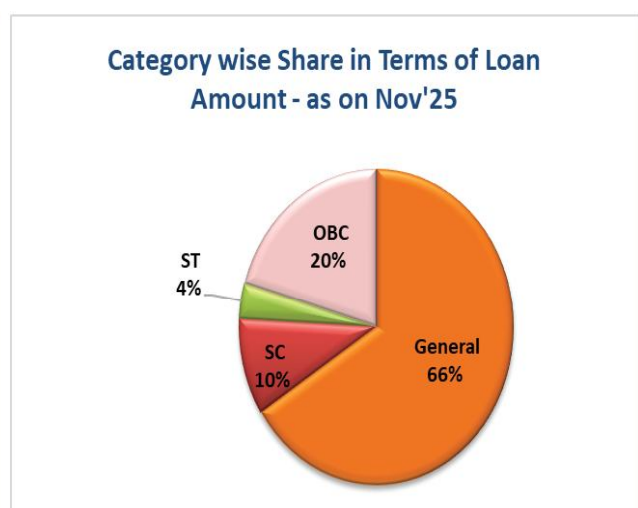
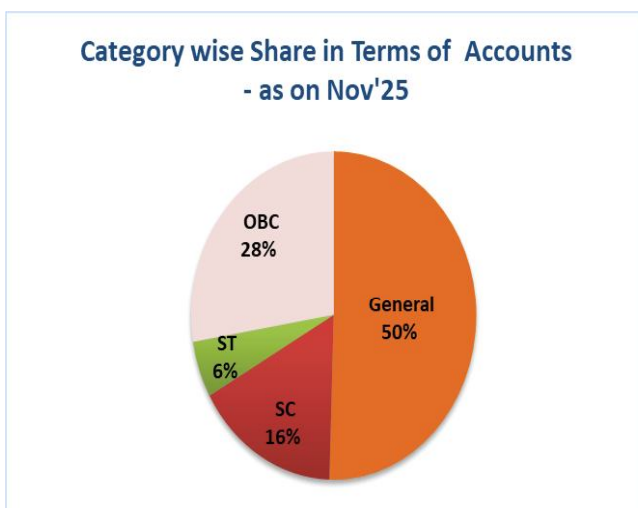
लक्ष्य प्राप्त करना, उत्कृष्टता प्राप्त करना :



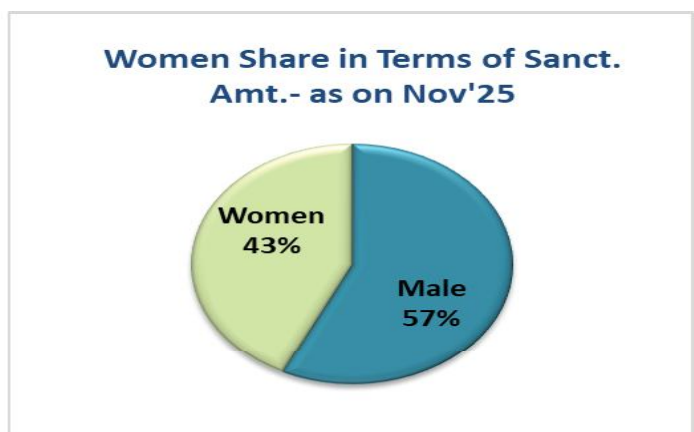
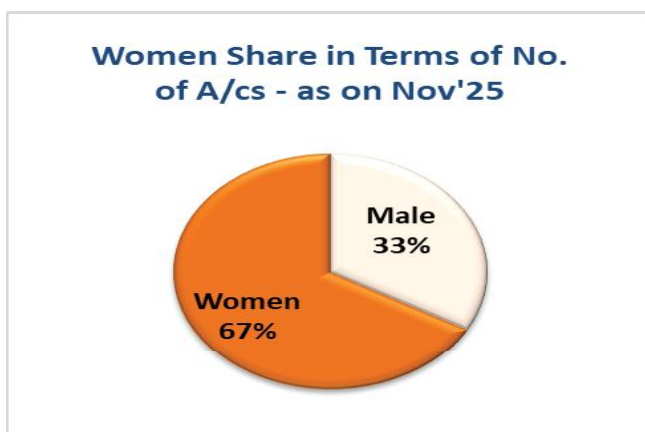
श्रेणी-वार शेयर (संचयी आंकड़ों के आधार पर)



श्रेणीवार शेयर (संचयी आंकड़ों के आधार पर)



उद्यमी महिलाओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सुदृढ़ करना
(संचयी आंकड़ों के आधार पर)



6.7.4 स्टैंड अप इंडिया योजना (एसयूपीआई) - 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ऋणदाता और एक महिला ऋणदाता को व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।

वर्ष 2019-20 में, स्टैंड-अप इंडिया योजना को 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल वर्ष 2020-25 तक की पूरी अवधि के लिए विस्तारित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, स्टैंड-अप इंडिया योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं।

- उधारकर्ता द्वारा लाई जाने वाली मार्जिन राशि को परियोजना लागत के '25% तक' से घटाकर '15% तक' कर दिया गया है।

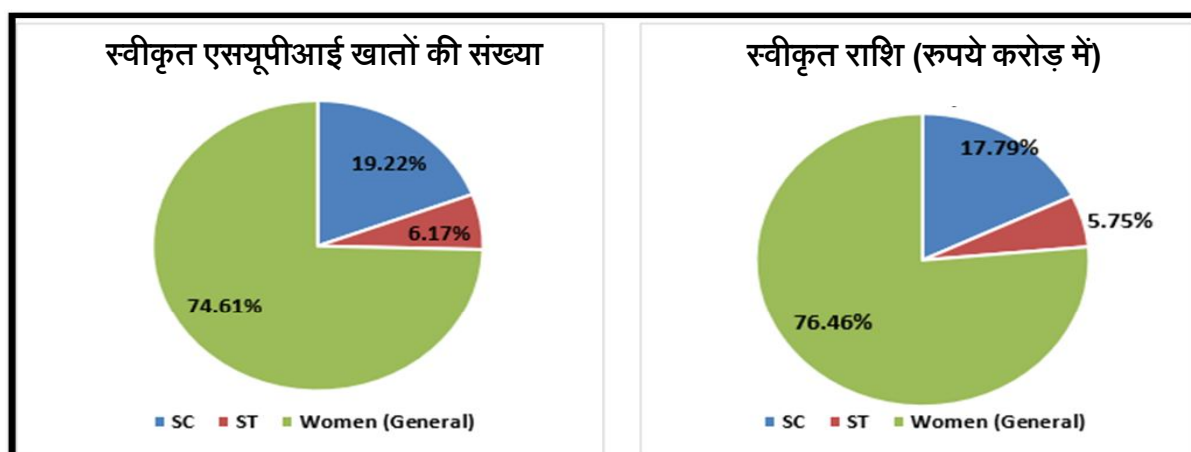
इस योजना में '15% तक' मार्जिन राशि का प्रावधान है, जिसे पात्र केंद्रीय/राज्य योजनाओं के साथ समन्वय में प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, उधारकर्ता स्वयं के योगदान के रूप में परियोजना लागत का कम से कम 10% योगदान करना जारी रखेगा।

- 'कृषि से संबद्ध गतिविधियों' जैसे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, पशुधन, पालन, ग्रेडिंग, छंटाई, एकत्रीकरण कृषि उद्योग, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र, खाद्य और कृषि-प्रसंस्करण, आदि (फसल ऋण, भूमि सुधार जैसे नहर, सिंचाई, कुओं को छोड़कर) और इन्हें समर्थन देने वाली सेवाओं के लिए ऋण योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पात्र होंगे। यह योजना मार्च 25 तक वैध/प्रचालनरत थी।

दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार, स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं की कुल संख्या निम्नानुसार है।

(करोड़ रुपये में)

अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		महिला (सामान्य)		कुल	
खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	खातों की संख्या	स्वीकृत राशि
52,901	11,168.36	16,991	3,612.84	2,05,399	48,010.73	2,75,291	62,791.93



6.7.5 पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएमस्वनिधि)

केंद्रीय क्षेत्र की योजना, पीएम स्वनिधि योजना, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचए) द्वारा दिनांक 01.06.2020 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट

वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में मदद करना था। यह योजना मूल रूप से दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए शुरू की गई थी जिसे बाद में दिनांक 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.12.2024 से आगे ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को मंजूरी दी और ऋण अवधि को 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दिया गया है।

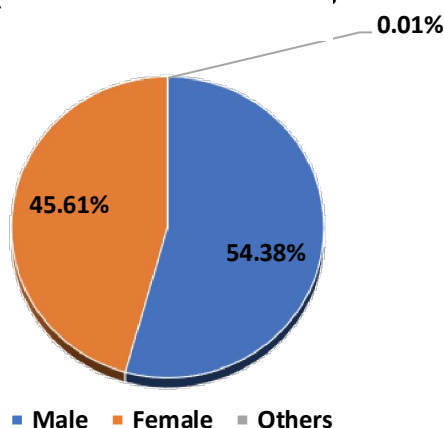
इस योजना को अब आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा, जिसमें डीएफएस बैंकों/ वित्तीय संस्थानों और उनके बुनियादी स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से ऋण/क्रेडिट कार्ड तक पहुंच की सुविधा के लिए जिम्मेदार होगा।

पुनर्गठित योजना की मुख्य विशेषताएं:

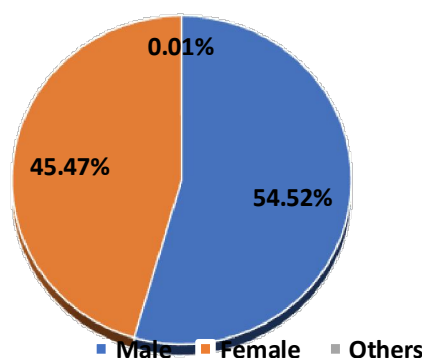
- पहले चरण के ऋण की राशि 12 महीनों के लिए 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है और दूसरे चरण के ऋण की राशि 18 महीनों के लिए 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। तीसरे चरण के ऋण की राशि 36 महीनों के लिए 50,000 रुपये ही रहेगी।
- पीएम स्वनिधि योजना के उन लाभार्थियों को यूपीआई से जुड़ा रुपये क्रेडिट कार्ड प्रदान करना, जिनकी सीमा 30,000 रुपये है और जिन्होंने अपना दूसरा ऋण चुका दिया है।
- पहले ऋण, दूसरे ऋण और तीसरे ऋण ऋण के लिए मौजूदा ऋण गारंटी कवरेज क्रमशः 31.87 प्रतिशत, 8.25 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है। कार्ड में आंशिक ऋण गारंटी होगी, जिसमें 75% जोखिम साझा करने के साथ 20% एनपीए स्तर तक होगा।
- ब्याज सब्सिडी 7% पर यथावत रहेगी।
- प्रत्येक डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये का कैशबैक, अधिकतम 100 रुपये प्रति माह, 12 महीनों के लिए (ऋण की प्रत्येक किश्त पर अधिकतम 1200 रुपये प्रति वर्ष का डिजिटल प्रोत्साहन)।
- कम से कम 2,000 रुपये की थोक खरीदारी पर डिजिटल लेनदेन करने पर, चार तिमाहियों तक प्रति तिमाही अधिकतम 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

संचयी							
स्वीकृत किये गए आवेदन	पुरुष	महिला	अन्य	संवितरित आवेदन	पुरुष	महिला	अन्य
	स्वीकृत किये गए आवेदन	स्वीकृत किये गए आवेदन	स्वीकृत किये गए आवेदन		संवितरित आवेदन	संवितरित आवेदन	संवितरित आवेदन
1,03,73,266	56,41,407	47,30,945	914	1,00,42,368	54,74,768	45,66,720	880

स्वीकृत खातों की लिंगवार संख्या;



संवितरित खातों की लिंगवार संख्या



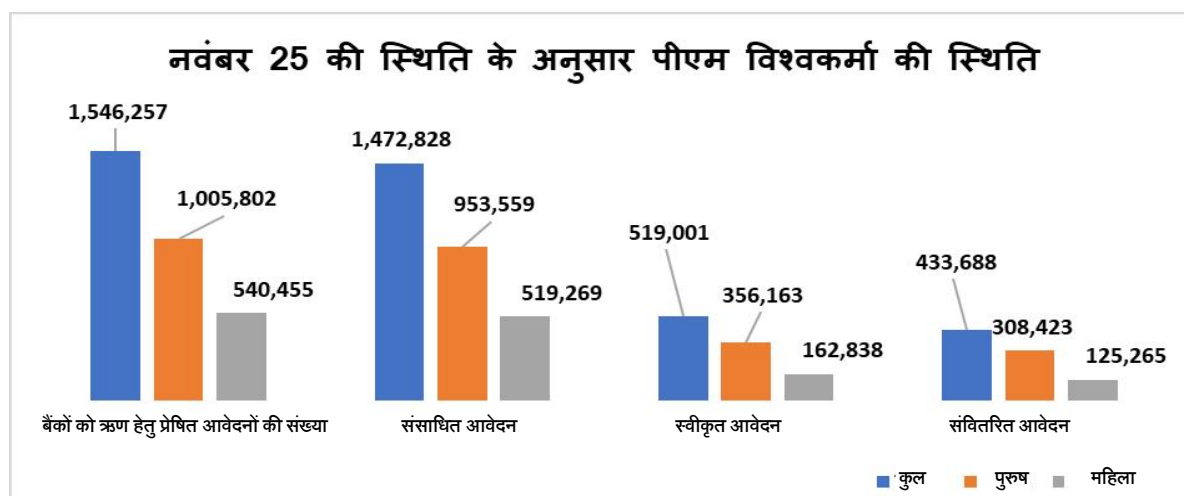
6.7.6 पीएम विश्वकर्मा योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा कार्यान्वित पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर, 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) के बीच सहयोग शामिल है, जिसका उद्देश्य 18 चिन्हित व्यवसायों में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, बिना गारंटी के

ऋण, आधुनिक उपकरण, बाजार संपर्क सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करना है।

डीएफएस ऋण आवेदन और संवितरण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करता है कि कारीगर और शिल्पकार आसानी से संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकें। डीएफएस ऋण आवेदनों और संवितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को भी बढ़ावा देता है।

नवंबर 2025 तक, बैंकों द्वारा 14.73 लाख आवेदनों पर कार्रवाई की गई है, जिनमें से 5.19 लाख ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं।

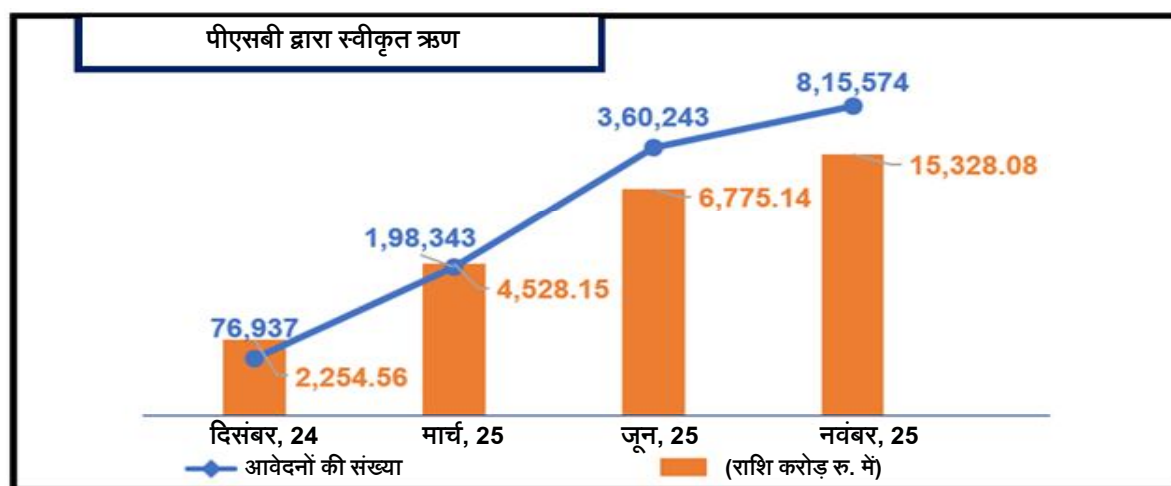


6.7.7 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना:

- प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके एक करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से संचालित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत, 3 किलोवाट तक के आरटीएस प्रणाली की स्थापना करने वाले लाभार्थियों को 78,000 रुपये तक की

सब्सिडी प्रदान की जाती है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता वाली प्रणाली को 78,000 रुपये की अधिकतम सब्सिडी के साथ स्थापित किया जा सकता है।

- ऋण आवेदन जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप में भेजे जाते हैं और इसे एमएनआरई के राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत हुई नवीनतम प्रगति इस प्रकार है:

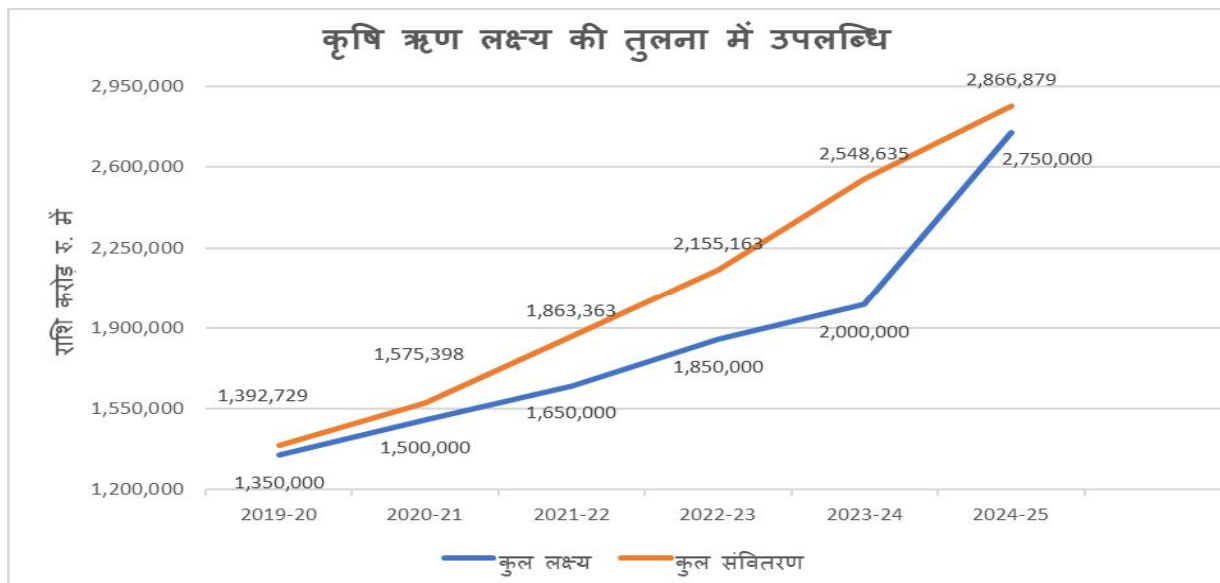


7. कृषि ऋण

कृषि क्षेत्र को प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से बढ़ावा देने के लिए, सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले मूल स्तर के कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है। वर्ष 2019-25 की अवधि के लिए कृषि ऋण प्रवाह के अंतर्गत वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि के विश्लेषण से वास्तविक वितरण की निरंतर प्रवृत्ति का पता चलता है, जो वर्ष दर वर्ष वार्षिक लक्ष्यों से अधिक हो रही है। वर्ष 2024-25 के लिए 27.50

लाख करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में, कृषि ऋण वितरण 28.67 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 104 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, पिछले छह वर्षों में, संवितरण ने 12.79% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की है। वर्ष 2025-26 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन करने वाले किसानों के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के उपलक्ष्य के साथ कृषि ऋण लक्ष्य 32.50 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। 30 सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 32.50 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में 14.94 लाख करोड़ रुपये संवितरित (अंतिम) किए

गए, जिसमें 46% उपलब्धि दर्ज की गई। पिछले छह वर्षों में उपलब्धि की तुलना में कृषि ऋण लक्ष्य की वृद्धि की प्रवृत्ति निम्न ग्राफ में दर्शाई गई है:-



स्रोत: नाबार्ड का ईएनएसयूआरई पोर्टल

7.1. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

केसीसी योजना वर्ष 1998-99 में एक नवीन ऋण वितरण तंत्र के रूप में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य लचीले, सुविधाजनक और लागत प्रभावी तरीके से इनपुट की खरीद सहित किसानों को उनकी खेती की जरूरतों के लिए बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। बैंकों को सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की सलाह दी गई है। केसीसी योजना को सरल बनाया गया है और इसमें एक बार की दस्तावेजीकरण प्रक्रिया, सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि और एटीएम-सक्षम डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। केसीसी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत, सीमा 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की जाती है, और लाभार्थियों को निकासी और पुनर्भुगतान में आसानी और लचीलापन प्राप्त होता है।

केसीसी योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋणों पर @1.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को मंजूरी दी है, जो 3 लाख रुपये प्रति वर्ष की समग्र सीमा पर उपलब्ध है और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में शामिल प्रति किसान 2 लाख रुपये की अधिकतम उप-सीमा के अधीन है। ऋणों की शीघ्र अदायगी पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है, जो प्रभावी रूप से ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत कर देता है।

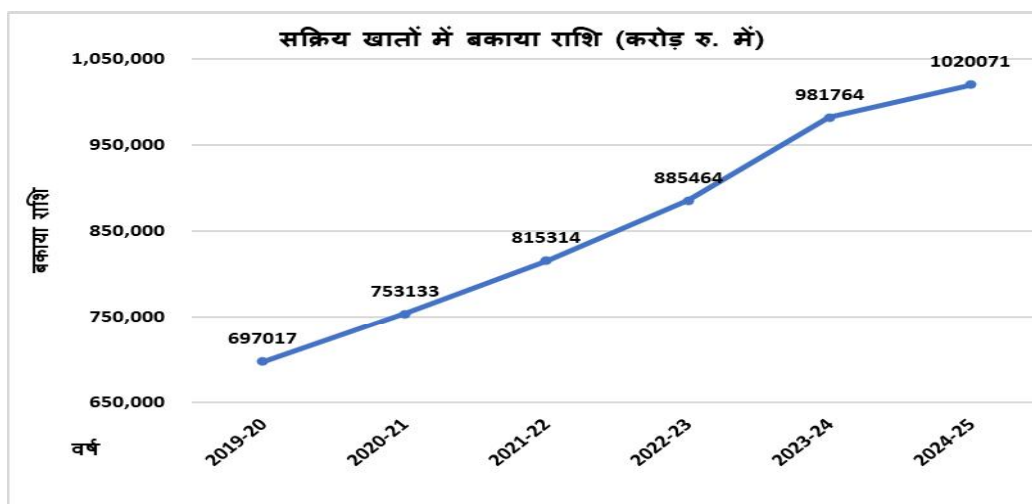
रियायती संस्थागत ऋण की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने फरवरी 2020 से मिशन मोड में एक अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थियों को

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उपलब्ध कराना था। किसानों को सुविधाजनक और किफायती ऋण वितरण सुनिश्चित करते हुए, इस अभियान ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादन एवं संबद्ध गतिविधियों को गति देने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2019 में, पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करने के लिए केसीसी की सुविधा का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, केसीसी के अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को शामिल करने के लिए, किसानों को सुविधाजनक और किफायती ऋण वितरण सुनिश्चित करने और कृषि उत्पादन में तेजी लाने के उद्देश्य से 15 नवंबर, 2021 से साप्ताहिक "जिला स्तरीय शिविर" के रूप में एक विशेष संतृप्ति अभियान शुरू किया गया।

राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान को समय-समय पर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन किसानों को कुल 47,80,225 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

वर्तमान में (दिनांक 30.09.2025 की स्थिति के अनुसार), किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 7.81 करोड़ चालू खाते हैं, जिन पर कुल 10.39 लाख करोड़ रुपये का बकाया ऋण है। पिछले 5 वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत चालू खातों में बकाया राशि में लगातार वृद्धि हुई है, जो इस प्रकार है:-



7.2. ग्रामीण वित्त पोषण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की भूमिका

नाबार्ड, एक शीर्ष विकासात्मक वित्तीय संस्था है, जिसकी स्थापना 1982 में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के संवर्धन और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमित करने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित की जा सके। नाबार्ड के प्रमुख कार्य वित्तीय, विकासात्मक और पर्यवेक्षण हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ), सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), अल्पावधि सहकारी ग्रामीण ऋण (पुनर्वित्त) निधि, अल्पावधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (पुनर्वित्त) निधि, दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) आदि जैसी अनेक निधियां ग्रामीण अवसंरचना के सृजन और कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड के पास उपलब्ध हैं।

7.3. ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ)

कृषि और ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश में गिरावट के मद्देनजर, वर्ष 1995-96 में नाबार्ड में आरआईडीएफ (आरआईडीएफ) की स्थापना की गई थी, जिसकी प्रारंभिक निधि 2,000 करोड़ रुपये थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों को चालू ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। इस निधि में वाणिज्यिक बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित अनुपात में योगदान करते हैं, जो बैंकों की प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कमी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। यह निधि, जो वर्ष 1995-96 के दौरान चल रही सिंचाई, बाढ़ संरक्षण और जलसंभर प्रबंधन परियोजनाओं को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के लिए "अद्योपांत दृष्टिकोण (लास्ट माइल अप्रोच)" के रूप में शुरू हुई थी, आज 39 कार्यकलापों को शामिल करती है, जिन्हें प्रमुख तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) कृषि और संबंधित क्षेत्र (ii) सामाजिक क्षेत्र और (iii) ग्रामीण संपर्क। आरआईडीएफ के लिए निधि का वार्षिक आवंटन वर्ष 1995-96 में 2,000 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 35,000 करोड़ रुपये हो गया है।

31 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संचयी वित्त पोषण प्रतिबद्धता 6,02,711 करोड़ रुपये (भारत निर्माण सहित) थी, जिसके अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 4,92,385 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में, आरआईडीएफ प्रभावशाली ग्रामीण परियोजनाओं के सार्वजनिक वित्त पोषण के एक भरोसेमंद स्रोत के रूप में उभरा है। वर्ष 1995-96 से विभिन्न किस्तों के अंतर्गत राज्य सरकारों को स्वीकृत कुल आरआईडीएफ ऋणों में से 26 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों, 30 प्रतिशत सिंचाई के लिए, 21 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र के लिए, 13 प्रतिशत कृषि क्षेत्र (सिंचाई के अलावा) और 10 प्रतिशत ग्रामीण पुलों के लिए है।

7.4. दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)

जल संसाधन विभाग, नदी विकास तथा गंगा पुनरुद्धार विभाग, जल-शक्ति मंत्रालय (पूर्व में जल संसाधन मंत्रालय) के माध्यम से भारत सरकार ने देश में रुकी हुई कई सिंचाई परियोजनाओं जिनके लिए नाबार्ड में दीर्घावधि सिंचाई निधि (एलटीआईएफ) की स्थापना की गई थी, को पूरा करने के लिए बड़ी पहल की है। 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 99 चिह्नित परियोजनाओं हेतु नाबार्ड द्वारा एलटीआईएफ के अंतर्गत 71,883 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा, पोल्लावरम सिंचाई परियोजना हेतु 11,218 करोड़ रुपये, नार्थ कोयल जलाशय परियोजना के लिए 1,379 करोड़ रुपये, शाहपुर कंडी बांध परियोजना के लिए 485 करोड़ रुपये तथा सरहिंद एवं राजस्थान फीडर के पुनरुद्धार के लिए 826 करोड़ रुपये की राशि एलटीआईएफ के अंतर्गत स्वीकृत की गई है जिससे एलटीआईएफ के तहत संचयी स्वीकृतियां कुल मिलाकर 85,791 करोड़ रुपये हो गयीं। 99 अभिचिन्हित परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति के बदले जारी की गई संचयी राशि 51,213 करोड़ रुपये थी। इसी प्रकार, पोल्लावरम परियोजना, नार्थ कोयल जलाशय परियोजना तथा शाहपुरकंडी बांध परियोजना के लिए जारी की गई संचयी राशि क्रमशः 10,650 करोड़ रुपये, 721 करोड़ रुपये और 207 करोड़ रुपये थी जिससे एलटीआईएफ के तहत संचयी निर्गम कुल मिलाकर 62,791 करोड़ रुपये हो गयीं हैं।

7.5. सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ)

राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड में वर्ष 2019-20 से 5,000 करोड़ रुपये के कार्पस से सूक्ष्म सिंचाई निधि की शुरुआत की गई है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत इसकी कवरेज का विस्तार करने और पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के प्रावधानों से बाहर इसको अपनाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2022-23 से, पीडीएमसी योजना प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही है। 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) को जारी रखने और इसमें अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपये की वृद्धि करने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया। 31 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार, एमआईएफ के अंतर्गत कुल संस्वीकृत राशि और जारी की गई राशि क्रमशः 4854 करोड़ रुपए तथा 4074 करोड़ रुपए हैं। इससे 16 लाख किसानों को शामिल करते हुए 24 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा का विस्तार हो पाएगा।

7.6. लघु अवधि सहकारी ग्रामीण ऋण एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) निधि

सहकारी बैंकों को लघुकालिक पुनर्वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से, किसानों को रियायती ब्याज दरों पर निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, नाबार्ड में एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) निधि की स्थापना वर्ष 2008-09 में 5,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक निधि के साथ की गई थी। नाबार्ड सहकारी बैंकों को 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋणों के लिए 4.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है, जिन्हें सहकारी बैंक अंतिम उधारकर्ताओं को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर संवितरित करते हैं। एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) निधि के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान 35,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दिनांक 18.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एसटीसीआरसी (पुनर्वित्त) निधि से वर्ष 2025-26 के दौरान 25,939.29 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

चालू वर्ष के दौरान, नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों को संवितरित कुल पुनर्वित्त राशि 67,166.74 करोड़ रुपये (दिनांक 18.11.2025 की स्थिति के अनुसार) है, जिसमें अतिरिक्त एसएओ और एसटी (अन्य) के अंतर्गत गैर-रियायती एसटी पुनर्वित्त शामिल है। साथ ही, सहकारी बैंकों द्वारा जारी किए गए केसीसी की कुल संख्या 3.49 करोड़ है, जिसकी कुल बकाया राशि दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार 2,28,488.73 करोड़ रुपये है।

7.7. लघु अवधि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एसटीआरआरबी (पुनर्वित्त) निधि

एसटीआरबी (पुनर्वित्त) निधि की स्थापना वर्ष 2012-13 में 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ की गई थी, ताकि नाबार्ड आरआरबी को उनके फसल ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए लघु अवधि पुनर्वित्त प्रदान कर सके। नाबार्ड आरआरबी को 3.00 लाख रुपये तक के फसल ऋणों के लिए 4.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर पुनर्वित्त प्रदान करता है, जबकि आरआरबी द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं को 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं। एसटीआरबी निधि के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान 7,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। दिनांक 18.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एसटीआरबी (पुनर्वित्त) निधि से वर्ष 2025-26 के दौरान 5,517.01 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।

चालू वर्ष के दौरान नाबार्ड द्वारा आरआरबी को दिनांक 18.11.2025 की स्थिति के अनुसार कुल 21,508.51 करोड़ रुपये का पुनर्वित्त संवितरित किया गया, जिसमें अतिरिक्त एसएओ और एसटी (अन्य) के अंतर्गत गैर-रियायती एसटी पुनर्वित्त शामिल है। वहीं, दिनांक 31.10.2025 की स्थिति के अनुसार आरआरबी द्वारा जारी केसीसी की कुल संख्या 1.50 करोड़ है, जिसमें कुल बकाया राशि 2,08,794.93 करोड़ रुपये है।

7.8. दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ)

दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) की स्थापना कृषि में निवेश क्रियाकलापों के लिए उधार देने हेतु सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दीर्घावधि पुनर्वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि इस क्षेत्र में पूंजी निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एलटीआरसीएफ के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए की निधि का आवंटन किया गया है। तथापि दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार इस विभाग को अंशदायी बैंकों से जमा के रूप में 3,996.76 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 30.11.2024 तक) के दौरान एलटीआरसीएफ के अंतर्गत सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को संवितरित किया गया है। उपर्युक्त के अलावा, नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 30.11.2024 तक) के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,342.17 करोड़ रुपये का गैर-रियायती एलटी पुनर्वित्त भी प्रदान किया।

8. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के कमजोर वर्गों को ऋण तक पहुंच प्राप्त हो और अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह बनाए रखा जाए जिनमें रोजगार की अधिक संभावना है जो गरीबी उन्मूलन पर प्रभाव डालने में मदद करेगा। इस प्रकार, वैसे क्षेत्र जो जनसंख्या के बड़े वर्गों अर्थात्, कमजोर वर्गों और कृषि और सूक्ष्म और लघु उद्यमों जैसे रोजगार पर जोर देने वाले क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का हिस्सा हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से इन क्षेत्रों को ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋणों में आठ पात्र श्रेणियों - कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य को दिए जाने वाले ऋण शामिल हैं।

पीएसएल पर संशोधित दिशानिर्देश हितधारकों से प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए मौजूदा प्रावधानों की व्यापक समीक्षा के बाद 24 मार्च, 2025 को जारी किए गए थे और इसमें निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन शामिल थे:

- (1) पीएसएल कवरेज बढ़ाने के लिए आवास, शिक्षा ऋण सहित कई ऋण सीमाओं में वृद्धि;
- (2) उन उद्देश्यों का विस्तार जिनके आधार पर ऋणों को 'नवीकरणीय ऊर्जा' के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है;
- (3) कमजोर वर्गों की श्रेणी के अंतर्गत पात्र उधारकर्ताओं की सूची का विस्तार करने के साथ-साथ यूसीबी द्वारा व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को ऋण पर मौजूदा सीमा को हटाना।

दिशा-निर्देशों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा पीएसएल को ऋण देने के लिए 40 प्रतिशत के लक्ष्य और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा पीएसएल को ऋण देने के लिए 75 प्रतिशत के लक्ष्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 20 जून, 2025 को, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए पीएसएल लक्ष्य को संशोधित कर 60% उच्चतर कर दिया गया था। समग्र पीएसएल के अंतर्गत, बैंकों के लिए निम्नलिखित उप-लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के ऋण समतुल्य (सीईओबीई) के प्रतिशत के रूप में हैं, इनमें से जो भी अधिक हो, बैंकों द्वारा प्राप्त किए जाने हैं:

उप-लक्ष्य:	
कृषि	18%; जिसमें से 14 प्रतिशत का लक्ष्य गैर-कारपोरेट किसानों (एनसीएफ) के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए 10 प्रतिशत शामिल है
लघु उद्यम	7.5 %
कमजोर वर्गों को अग्रिम	एससीबी के लिए 12 प्रतिशत और आरआरबी के लिए 15 प्रतिशत

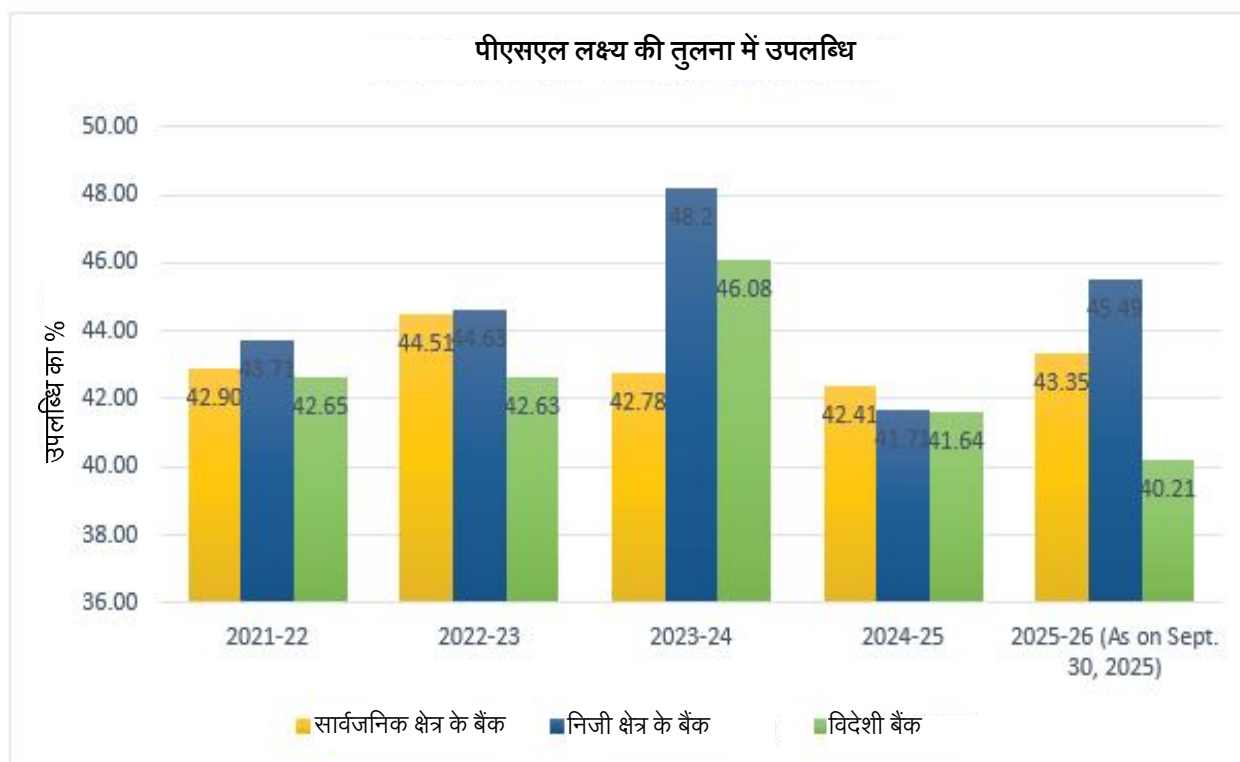
विगत पांच वर्ष में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)

का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2021-22	26,49,180 (42.90)	16,85,806 (43.71)	2,08,107 (42.65)	2,45,481 (89.76)
2022-23	30,36,062 (44.51)	21,01,827 (44.63)	2,19,622 (42.63)	2,69,835 (95.72)
2023-24	34,01,407 (42.78)	26,09,386 (48.20)	2,78,694 (46.08)	2,89,336 (89.86)
2024-25	38,12,376 (42.41)	27,01,993 (41.71)	2,86,060 (41.64)	3,08,892 (88.44)
2025-26 (30 सितंबर, 2025 तक)	40,57,579 (43.35)	31,70,746 (45.49)	2,84,617 (40.21)	3,23,261 (95.90)

नोट: कोष्ठक में आंकड़े एनबीसी या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण का (ईबीओईसी) प्रतिशत, जो भी अधिक हो। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए पीएसएल लक्ष्य 40% है जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लक्ष्य 75% है।

स्रोत: आरबीआई



हाल के वर्षों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का कार्यनिष्पादन सभी बैंकों द्वारा ऋण में पूर्ण रूप से ऋण में सतत वृद्धि को दर्शाता है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष

2025-26 में, बैंकों की सभी श्रेणियां, अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और आरआरबी वास्तव में अपने पीएसएल लक्ष्यों से अधिक हो गए हैं।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए एक नई प्रोत्साहन प्रणाली आरंभ किया गया है जिसमें जिलों की रैंकिंग प्रति व्यक्ति ऋण प्रवाह के आधार पर की जाएगी जिसमें कम ऋण प्रवाह वाले क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन दिए जाएंगे तथा उच्चतर प्रवाह वाले क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन नहीं दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024-25 से, प्रति व्यक्ति कम पीएसएल 9,000 रुपये से कम वाले जिलों को अधिक वृद्धिशील ऋण 125% प्राप्त होगा, जबकि प्रति व्यक्ति उच्च पीएसएल 42,000 रुपये से अधिक वाले लोगों को कम 90% प्राप्त होगा।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, पीएसएल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों के अनुपालन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तिमाही आधार पर की जा रही है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में किसी प्रकार की कमी वाले बैंकों को नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड के पास अन्य निधियों में अंशदान की राशि आबंटित की जाएगी, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग के परामर्श से समय-समय पर निर्णय लिया गया है।

8.1. शिक्षा ऋण

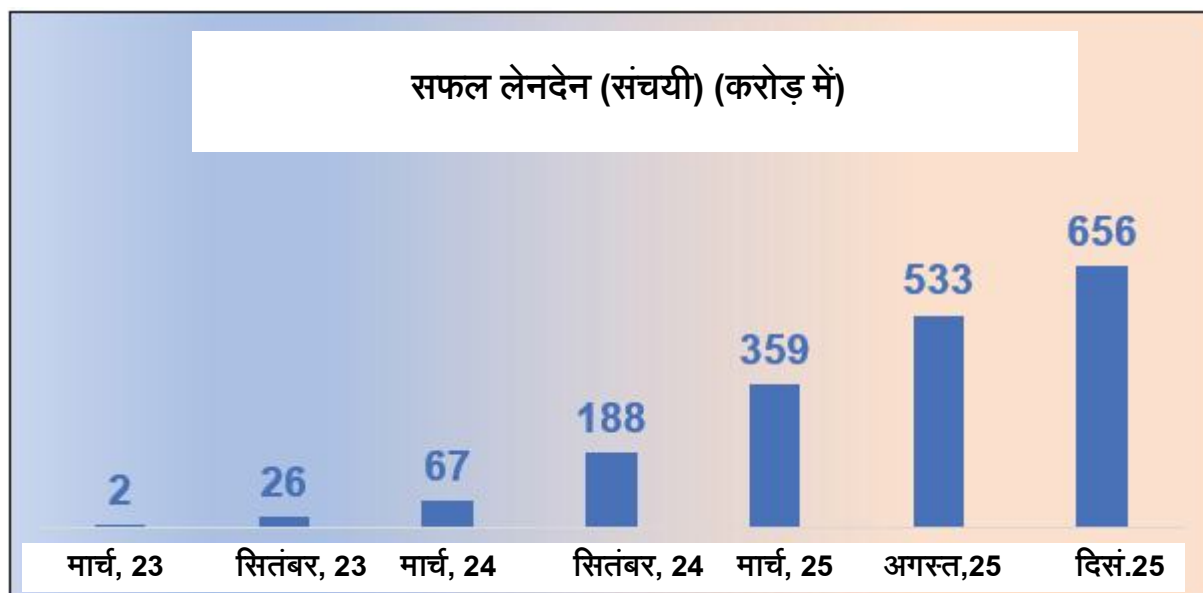
प्रत्येक मेधावी छात्र को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक ऋण तक पहुंच होनी चाहिए, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने मॉडल शैक्षिक ऋण योजना तैयार की थी और इसे वर्ष 2001 में बैंकों के बीच परिचालित किया था। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए है। भारतीय नागरिक इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक ऋण के लिए पात्र हैं जिन्होंने प्रवेश परीक्षा/योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भारत या विदेश में किसी

मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया है, इसके कार्यान्वयन के दौरान वर्षों से प्राप्त अनुभव और फीडबैक के आधार पर योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया है। इस योजना का अंतिम संशोधन जून 2025 के दौरान किया गया था। संशोधित मॉडल शैक्षिक ऋण योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

- यह योजना आवश्यकता आधारित शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती है।
- 7.50 लाख रुपये तक के ऋण राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्रतिभूति/तृतीय-पक्ष गारंटी की आवश्यकता नहीं है (उन ऋणों के मामले में जो सीएसआईएस के लिए पात्र है और/या 'शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना' (सीजीएफएसईएल) के अन्तर्गत विस्तारित क्रेडिट गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं।
- 4 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं।
- सभी मामलों में अध्ययन अवधि और एक वर्ष तक की अधिस्थगन अवधि की अनुमति है।
- सभी ऋणों के लिए चुकोती अवधि (अधिस्थगन के बाद) 15 वर्ष तक उपलब्ध है।

8.1.1 शिक्षा ऋण का कार्य निष्पादन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल बकाया शिक्षा ऋण 72,726 करोड़ रुपये था और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार 1,16,786 करोड़ रुपये था।



ग्राफ 1: शैक्षिक ऋण का प्रदर्शन

8.1.2 प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी (पीएम-विद्यालक्ष्मी) योजना

मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.11.2024 को उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी

दी है, जो मेधावी छात्रों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराएगी ताकि भारत के किसी भी छात्र की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा में वित्तीय बाधाएं रुकावट न बनें। मिशन मोड तंत्र मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करेगा और सक्षम बनाएगा जो देश के शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च

शिक्षण संस्थानों (क्यूएचआई) में प्रवेश प्राप्त करते हैं, अर्थात् प्रत्येक वर्ष लगभग 22 लाख छात्रों को कवरेज मिलेगा। यह योजना इन क्यूएचआई के मेधावी छात्रों को एक सरल, पारदर्शी, छात्र के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाती है। योजना के समग्र कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:-

- एक एकीकृत पोर्टल जो छात्रों को डिजिटल रूप से शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
- पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल, छात्रों को ऋण की मंजूरी के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति देता है।
- शिक्षा ऋण आवेदन करने के लिए एक सरल 2-पृष्ठ का आवेदन प्रारूप
- शिक्षा ऋण के लिए साधारण आवेदन के माध्यम से छात्रों के लिए कई बैंकों में आवेदन करने की सुविधा;
- छात्रों के लिए जमा किए गए आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा;
- योजना की प्रभावी निगरानी के लिए बैंकों के लिए विभिन्न रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा।

इस योजना में एक वर्ष में अधिकतम एक लाख जरूरतमंद छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट का भी प्रावधान है, जहां परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। इसका तात्पर्य यह है कि, जो छात्र सीएसआईएस या किसी अन्य केंद्र/राज्य सरकार की छात्रवृत्ति या किसी अन्य ब्याज सहायता (सबवेंशन) योजना या शुल्क प्रतिपूर्ति के अंतर्गत लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 3 प्रतिशत ब्याज सहायता (सबवेंशन) का लाभ उठाने के पात्र होंगे।

9. बीमा क्षेत्र

9.1 संक्षिप्त विवरण

बीमा क्षेत्र नागरिकों और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है जो व्यक्तियों को मृत्यु, स्वास्थ्य संबंधी संकट या संपत्ति के नुकसान जैसे अप्रत्याशित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति को बढ़ावा मिलता है। यह स्थिरता उद्यमिता और निवेश को प्रोत्साहित करती है जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। बीमा तंत्र व्यापक वित्तीय संकट की संभावना को कम करते हुए और समाज की समग्र भलाई का समर्थन करते हुए प्रणालीगत जोखिमों को कम करता है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक निधि प्रदान करता है और निरंतर आर्थिक परिवर्तन में सहायता करता है।

9.2 सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता

बीमा क्षेत्र में परिचालनरत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां निम्नानुसार हैं:

- भारतीय जीवन बीमा निगम

- भारतीय साधारण बीमा निगम - जीआईसी सी (पुनः बीमाकर्ता)
- दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- एग्रिकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड— विशेषज्ञता प्राप्त बीमाकर्ता (नाबार्ड के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा आरंभ की गई कंपनी)
- ईसीजीसी ऑफ इंडिया लिमिटेड – विशेषज्ञता प्राप्त बीमाकर्ता (निर्यात ऋण गारंटी के लिए भारत सरकार का उद्यम)

9.3 बीमा क्षेत्र को अभिशासित करने वाला विधायी ढांचा

देश में बीमा क्षेत्र के विकास में निम्नलिखित अधिनियमों का नीति निर्धारण और प्रशासन शामिल है:

- बीमा अधिनियम, 1938
- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956
- साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972
- इरडा अधिनियम, 1999
- बीमांकक अधिनियम, 2006

राज्य सभा की चयन समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008 के अनुसार बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करने के लिए 26 दिसंबर, 2014 को बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2014 नामक एक अध्यादेश प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश को बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के लागू होने के साथ ही, भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की सुरक्षा के साथ किसी भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश की सीमा 26 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है।

25 मार्च, 2021 को अधिनियमित बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 को प्रख्यापित करके बीमा अधिनियम, 1938 में अतिरिक्त संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा सरकार ने भारतीय स्वामित्व और नियंत्रण की शर्तों में कुछ शर्तों के साथ एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया है। सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि का संशोधन) विधेयक 2025 ने एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया है।

9.4 बीमा उद्योग में नए प्रवेशकर्ता

वर्ष 2000 में निजी और विदेशी निवेश के लिए इस क्षेत्र को खोले जाने के बाद से बीमा उद्योग में प्रतिभागियों की संख्या सात (7) बीमाकर्ताओं

(भारतीय जीवन बीमा निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं, एक विशेष बीमाकर्ता और राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में साधारण बीमा निगम सहित) से बढ़कर 31 मार्च, 2025 तक चौहत्तर (47) बीमाकर्ता हो गए हैं, जो जीवन, साधारण और पुनर्बीमा खंडों (विशेषज्ञ बीमा कंपनियों नामतः एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड और एग्रीकल्चर इश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित) में कार्य कर रहे हैं।

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, 26 जीवन बीमाकर्ता हैं, जिनमें एक सार्वजनिक क्षेत्र में, 52 साधारण बीमाकर्ता हैं, जिनमें से चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में दो विशेष बीमाकर्ता, आठ स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एसएचआई) और सार्वजनिक क्षेत्र में एक सहित 13 पुनर्बीमाकर्ता हैं।

पंजीकृत बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

बीमाकर्ता के प्रकार	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन बीमाकर्ता	1	25	26
साधारण	6	21	27
स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य	0	8	8
पुनर्बीमाकर्ता	1	12	13
कुल	8	66	74

स्रोत : इरडाई

9.5 बीमा संबंधी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:-

दो प्राथमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), के अतिरिक्त, एक बीमा योजना अर्थात् प्रधान मंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवाई) 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

9.5.1. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना:

- प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवाई) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा पेश की जाती है और भारत सरकार द्वारा समर्थित है, ताकि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल की अवधि के लिए सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान की जा सके, इसे उस मूल्य से संबद्ध किया गया जिस पर वे पेंशन पॉलिसी खरीदते हैं।

- भारत सरकार विभेदी प्रतिलाभ अर्थात् एलआईसी द्वारा सृजित प्रतिलाभ (रिटर्न) और वार्षिक आधार पर ब्याज-अंतर सब्सिडी के रूप में योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध सुनिश्चित प्रतिलाभ के मध्य के अंतर का वहन करती है।
- 15,00,000 रुपये की अधिकतम निवेश की अनुमति है।
- इस योजना के अंतर्गत, तीन पॉलिसी वर्ष के पूरा होने के बाद, खरीद मूल्य के 75% तक के ऋण की अनुमति है।
- एलआईसी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, पीएमवीवाई योजना के अन्तर्गत कुल 8.36 लाख अभिदाता (पॉलिसी की संख्या 10.9) लाभान्वित हो रहे हैं।
- यह योजना 31 मार्च 2023 तक वैध थी।
- पीएमवीवाई के पहले, भारत सरकार द्वारा समर्थित एलआईसी की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) - प्लान 161 और प्लान 828 में वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान की जाती थी। एलआईसी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक वीपीबीवाई योजना के अन्तर्गत 3.58 लाख अभिदाताओं (4.16 लाख पॉलिसियों) को लाभ हुआ है।

9.6 बीमा उद्योग संबंधी आंकड़े

बीमा कवरेज

बीमा कवरेज से तात्पर्य जीवन, स्वास्थ्य और अन्य बीमा श्रेणियों के लिए बीमा के अंतर्गत शामिल किए गए जीवन की संख्या से है। इरडाई की रिपोर्ट के अनुसार, 2024-25 के दौरान, जीवन बीमाकर्ताओं ने व्यक्तिगत व्यवसाय के अन्तर्गत 270.22 लाख नई पॉलिसियां जारी की हैं और साधारण, स्वास्थ्य और विशेष बीमा कंपनियों ने 3913.53 लाख पॉलिसियां जारी की हैं।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के अन्तर्गत दिनांक 29.10.2025 की स्थिति के अनुसार संचयी नामांकन 25.46 करोड़ और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अन्तर्गत 54.73 करोड़ है।

बीमा की पहुंच और बीमा का घनत्व

बीमा की पहुंच और घनत्व का माप किसी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को दर्शाता है। जबकि बीमा की पहुंच को जीडीपी के लिए बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है, बीमा घनत्व की गणना प्रीमियम से जनसंख्या के अनुपात के रूप में की जाती है (अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना की सुविधा के लिए यूएस \$ में मापा जाता है)।

	भारत (2001-02)	भारत (2024-25)	मलेशिया (2024-25)	थाईलैंड (2024-25)	चीन (2024-25)
बीमा की पहुंच (%)	2.7	3.7 (जीवन: 2.7 % गैर जीवन: 1%)	5.3	5.1	4.2
बीमा घनत्व (यूएस\$)	11.5	97 (जीवन: 72 एवं गैर जीवन: 25)	623	371	558

स्रोत: स्विस् री, सिग्मा रिपोर्ट विश्व बीमा रिपोर्ट (सं 2/2025)

वर्ष 2024-25 में वैश्विक स्तर पर बीमा की पहुंच और घनत्व जीवन क्षेत्र के लिए क्रमशः 3.0 प्रतिशत और 388 यूएसडी और गैर जीवन क्षेत्र के लिए 4.3 प्रतिशत और 555 यूएसडी था। वर्ष 2024-25 में, भारत में बीमा घनत्व वर्ष 2023-24 में 95 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 97 हो गया।

भारत में जीवन बीमा क्षेत्र की बीमा की पहुंच वर्ष 2023-24 में 2.8 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2024-25 में 2.7 प्रतिशत हो गई है और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र के लिए इन दोनों वर्षों में यह 1 प्रतिशत पर बनी हुई है। इस प्रकार, भारत की समग्र बीमा की पहुंच वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 3.7 प्रतिशत तक समान रहा है।

9.7 जीवन बीमा उद्योग

उदारीकरण के बाद बीमा उद्योग, विशेष रूप से जीवन क्षेत्र में तीव्र वृद्धि देखी गई है। जीवन बीमा उद्योग ने वर्ष 2024-25 के दौरान 886. लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय दर्ज की, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 8.3 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें 73.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम में 07.21 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम में 2.75 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एकमात्र जीवन बीमाकर्ता है जो भारत के बाहर व्यवसाय की हामीदारी दे रहा है और वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 398.15 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया है।

जीवन बीमा उद्योग वर्ष 2024-25 के लिए हामीदारी किया गया नया प्रीमियम

	बाजार हिस्सेदारी	नया कारोबार प्रीमियम	नवीनीकरण प्रीमियम	कुल प्रीमियम
एलआईसी	57.02%	2.27 लाख करोड़ रुपए	2.62 लाख करोड़ रुपए	4.89 लाख करोड़ रुपए
निजी बीमाकर्ता	42.98%	1.71 लाख करोड़ रुपए	2.26 लाख करोड़ रुपए	3.97 लाख करोड़ रुपए
उद्योग का कुल	100%	4.89 लाख करोड़ रुपए	3.97 लाख करोड़ रुपए	8.86 लाख करोड़ रुपए

स्रोत: इरडाई

स्वास्थ्य बीमा कारोबार सहित साधारण बीमा उद्योग

साधारण बीमा उद्योग (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में 3.08 लाख करोड़ रुपये के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम की हामीदारी थी, जबकि 2023-24 में यह 2.90 लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष में दर्ज 12.76 प्रतिशत की तुलना में 6.19 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं (विशेष बीमाकर्ताओं सहित) ने मिलकर बाजार हिस्सेदारी का 34.57% योगदान दिया, जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने शेष 65.43% में योगदान दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन बीमा कंपनियों (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को छोड़कर) और निजी क्षेत्र की दो बीमा कंपनियों (केयर हेल्थ और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड) द्वारा देश के बाहर कुल प्रीमियम 2024-25 में क्रमशः 3,973 करोड़ रुपये और 82.28 करोड़ रुपये था।

क्षेत्र	वर्ष 2024-25 के लिए प्रीमियम (करोड़ रुपए)	वर्ष 2023-24 से वृद्धि
पीएसयू	95,252	5.54%
निजी साधारण बीमा कर्ता	1,62,837	5.00%
निजी स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एसएएचआई)	38,414	15.99%
विशिष्ट बीमाकर्ता	11,108	-0.92%
उद्योग का कुल	3,07,611	6.19%

स्रोत: इरडाई वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

बीमा क्षेत्र को खोलने का एक लाभ यह भी हुआ है कि स्वास्थ्य बीमा कवर का समाज के व्यापक वर्गों तक विस्तार किया गया है। स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय 2024-25 में कुल प्रीमियम के 41.42% (2023-24 में 40.29% योगदान) के अंशदान के साथ सबसे बड़ा क्षेत्र है। स्वास्थ्य बीमा खंड ने 2024-25 में 9.19% की वृद्धि (2023-24 में 19.50% वृद्धि) की सूचना दी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2023-24 10,119 करोड़ रुपये के निवल लाभ की तुलना में 13,154 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कर पश्चात लाभ 2023-24 में 157 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 798 करोड़ रुपये था, निजी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को 2023-24 में 5,983 करोड़ रुपये की तुलना में 8,150 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ हुआ। विशेष बीमाकर्ताओं का निवल लाभ 2023-24 में 3,063 करोड़ रुपये के मुकाबले 3,444 करोड़ रुपये था और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए निवल लाभ 2023-24 में 915 करोड़ रुपये की तुलना में 2024-25 में 762 करोड़ रुपये था।

9.8 बीमा क्षेत्र का निवेश:

बीमाकर्ताओं को इरडाई (निवेश) विनियम, 2016 के अन्तर्गत आवश्यक निवेश के स्वरूप का अनुपालन करना अनिवार्य किया गया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार 74.44 लाख रुपए की तुलना में दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 67.57 लाख करोड़ रुपए का निवेश बीमा उद्योग द्वारा किया गया था जो 10.14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जीवन बीमा कंपनियों, साधारण बीमा कंपनियों और पुनर्बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमशः 91.07 प्रतिशत, 7.04 प्रतिशत और 1.89 प्रतिशत रही। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान 68.4% था, जबकि निजी क्षेत्र का 31.6% था।

	बीमा क्षेत्र (2022-23)	बीमा क्षेत्र (2023-24)	जीवन बीमाकर्ता (2023-24)	सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता (2023-24)
कुल निवेश	67.57 लाख करोड़ रु.	74.44 लाख करोड़ रु.	कुल निवेश का 91.07%	कुल निवेश का 68.40%

9.9 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के कारोबार

इरडाई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 और इरडाई (मोटर तृतीय पक्ष के बीमा कारोबार के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015 की समीक्षा की गई है और इरडाई (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर तृतीय पक्ष दायित्व) विनियम, 2024 के रूप में अधिसूचित किया गया है जिसे 1 अप्रैल, 2024 से लागू किया गया।

संशोधित नियमों में वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण, सामाजिक और मोटर तृतीय-पक्ष कारोबार दायित्वों को निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था:

क) ग्रामीण क्षेत्र के दायित्व: सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) सामूहिक रूप से न्यूनतम 25000 ग्राम पंचायतों में आग और मोटर बीमा के अंतर्गत न्यूनतम 10 प्रतिशत आवासों, दुकानों और वाहनों को कवर करेंगे

ख) सामाजिक क्षेत्र के दायित्व: सभी बीमाकर्ता-जीवन, साधारण और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एआईसी और ईसीजीसी को छोड़कर) - यह सुनिश्चित करेंगे कि कवर किए गए कुल जीवन के अनुपात के रूप में 10 प्रतिशत जीवन सामाजिक क्षेत्र के तहत कवर किए जाएंगे।

ग) मोटर तृतीय पक्ष दायित्व: प्रत्येक साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, एआईसी और ईसीजीसी के अलावा) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग सामान ले जाने, यात्री ले जाने वाले वाहनों और ट्रैक्टरों (विविध खंड) की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि सुनिश्चित करेंगे।

ग्रामीण दायित्व के अन्तर्गत, यह बताया गया है कि सभी साधारण बीमाकर्ताओं ने सामूहिक रूप से आवंटित ग्राम पंचायतों के लिए 1,61,525 आवास और दुकानों और 11,82,073 वाहनों का बीमा किया है। 11 साधारण बीमाकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों को पूरा नहीं किया है। यात्री वाहक वाहन और ट्रैक्टर श्रेणी के अन्तर्गत, 18 बीमाकर्ताओं ने कमी की सूचना दी है और माल ढोने वाले वाहन श्रेणी के अन्तर्गत, 17 बीमाकर्ताओं ने कमी की सूचना दी है।

एसएचआई बीमाकर्ताओं ने सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का अनुपालन करते हुए 166.60 लाख जीवन को कवर किया जो वर्ष के दौरान कवर किए कुल जीवन का 20 प्रतिशत कवर किया जिससे सामाजिक क्षेत्र के दायित्वों का अनुपालन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के संबंध में, एसएचआई बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य में 17.76 लाख लोगों के जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना के तहत 12.21 लाख लोगों के जीवन को कवर किया।

सूक्ष्म बीमा

सूक्ष्म बीमा कम कीमत-उच्च मात्रा वाला कारोबार होने के नाते, इसकी सफलता और स्थिरता मुख्य रूप से लेनदेन लागत को कम रखने पर निर्भर करती है। सूक्ष्म बीमा-जीवन में, 9.32 लाख नई पॉलिसियों के माध्यम से वर्ष 2024-25 के लिए व्यक्तिगत नया व्यवसाय प्रीमियम 359.05 करोड़ रुपये था और समूह का नया व्यवसाय प्रीमियम 9,242.85 करोड़ रुपये था, जो 1,364.48 लाख लोगों को कवर करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में जीवन बीमाकर्ताओं से 1,01,630 सूक्ष्म बीमा एजेंट जुड़े हुए थे। साधारण बीमा कंपनियों से 706 सूक्ष्म बीमा एजेंट जुड़े हुए थे और 31.96 करोड़ रुपये के सकल घरेलू प्रीमियम के साथ पॉलिसियों की संख्या 26,097 थी।

9.1 डीएफएस द्वारा की गई पहल/ उठाए गए कदम:

- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) अधिनियम, 2025 ने बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाना, बीमा की पहुंच को अधिक बढ़ाना, बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास में तेजी लाना और व्यापार करने में आसानी को बढ़ाना है। संशोधन ने भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया। यह स्थिर और टिकाऊ निवेश को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने, बीमा की पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने और '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
- संशोधन में पॉलिसीधारकों के लिए शिक्षा और संरक्षण कोष बनाने का भी प्रावधान है। पॉलिसीधारकों की अधिक सुरक्षा के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) को बीमाकर्ता या मध्यस्थ द्वारा लिए गए अनुचित लाभ को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की जा रही है। यह बीमा क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के लिए एक कानूनी आधार तैयार करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पॉलिसीधारकों की जानकारी विधिवत सुरक्षित और संरक्षित है।
- पॉलिसीधारकों को निर्बाध सेवा और सहायता सुनिश्चित करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संशोधन में बीमा मध्यस्थों के एकमुश्त पंजीकरण का प्रस्ताव है। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के लिए चुकता इक्विटी पूंजी के शेयरों के हस्तांतरण के लिए इरडाई की मंजूरी लेने की सीमा को मौजूदा 1% से

बढ़ाकर 5% किया जा रहा है। विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए निवल स्वामित्व निधि की आवश्यकता को 5,000 करोड़ रुपये से घटाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रवेश की सुविधा मिल सके, जिससे देश में अधिक पुनर्बीमा क्षमताओं का निर्माण हो सके

- यह विभाग पीएसजीआईसी के कार्य निष्पादन की लगातार समीक्षा कर रहा है। ठोस प्रयासों से, चार पीएसजीआईसी का कर पश्चात लाभ 2023-24 में 157 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 798 करोड़ रुपये हो गया है।
- डीएफएस ने दीपम के साथ समन्वय से 4 और 5 सितंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से इक्विटी शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव द्वारा भारतीय साधारण बीमा निगम में 3.39 प्रतिशत की सीमा तक अपनी इक्विटी हिस्सेदारी का विनिवेश किया है। कुल 594,32,385 इक्विटी शेयर (कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 3.39%) लगभग 2345.55 करोड़ रुपये जुटाकर बेचे गए।
- यह विभाग क्षेत्र के विनियामक ईरडाई के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों की निगरानी के लिए उपाय कर रहा है। डीएफएस ने ईरडाई से खतरों की रोकथाम और निगरानी के लिए नवीनतम सुरक्षा तंत्र के साथ संरेखित करने के लिए बीमा कंपनियों और मध्यस्थों की साइबर सुरक्षा की नियमित समीक्षा करने का अनुरोध किया।
- बीमा क्षेत्र से संबंधित सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में दिव्यांगजनों की पहुंच संबंधी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं विभाग ने अगस्त 2024 में «बीमा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश» तैयार किए हैं।
- यह विभाग गोल्डन ऑवर के अंतर्गत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना को लागू करने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का समर्थन कर रहा है, जो सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए एक कल्याणकारी उपाय है। इसके अतिरिक्त, डीएफएस मोटर वाहन दुर्घटना कोष में समय पर योगदान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और बीमा कंपनियों के बीच समन्वय कर रहा है। दिसंबर 2025 तक बीमा कंपनियों द्वारा "बीमित वाहनों के खाते" में कुल 504 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया।
- बीमा प्रतिभूति बांडों (आईएसबी) को बैंक गारंटी (बीजी) के लिए एक व्यवहार्य विकल्प/पूरक के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। इस संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया है कि वे अपने मंत्रालयों से संबंधित परियोजनाओं में प्रतिभूति बांड के उपयोग का पता लगाएं, अपनाएं और उसे बढ़ावा दें।

10. पेंशन क्षेत्र

मुख्य/पलैगशिप कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य-निष्पादन और उपलब्धियां (तालिका अनुलग्नक 1 में)

10.1 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी। यह भारत के 18-40 वर्ष की आयु के बीच के सभी नागरिकों के लिए है, जिनका बैंक या डाकघर में बचत बैंक खाता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को गारंटीकृत पेंशन के बेहतर लक्ष्य के लिए कोई भी आयकर दाता 1 अक्टूबर, 2022 से एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। एपीवाई के अंतर्गत अभिदाता को चुनी गई पेंशन की राशि और योजना में शामिल होने की उम्र द्वारा निर्धारित राशि का मासिक/त्रैमासिक/छमाही योगदान करना आवश्यक है। अभिदाता को चुने गए योगदान के आधार पर, 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक, सरकार द्वारा गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी दी जाएगी। अभिदाता की मृत्यु के बाद अभिदाता के पति/पत्नी अभिदाता की पेंशन राशि के समान पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। अभिदाता और पति/पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नामिती अभिदाता की 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

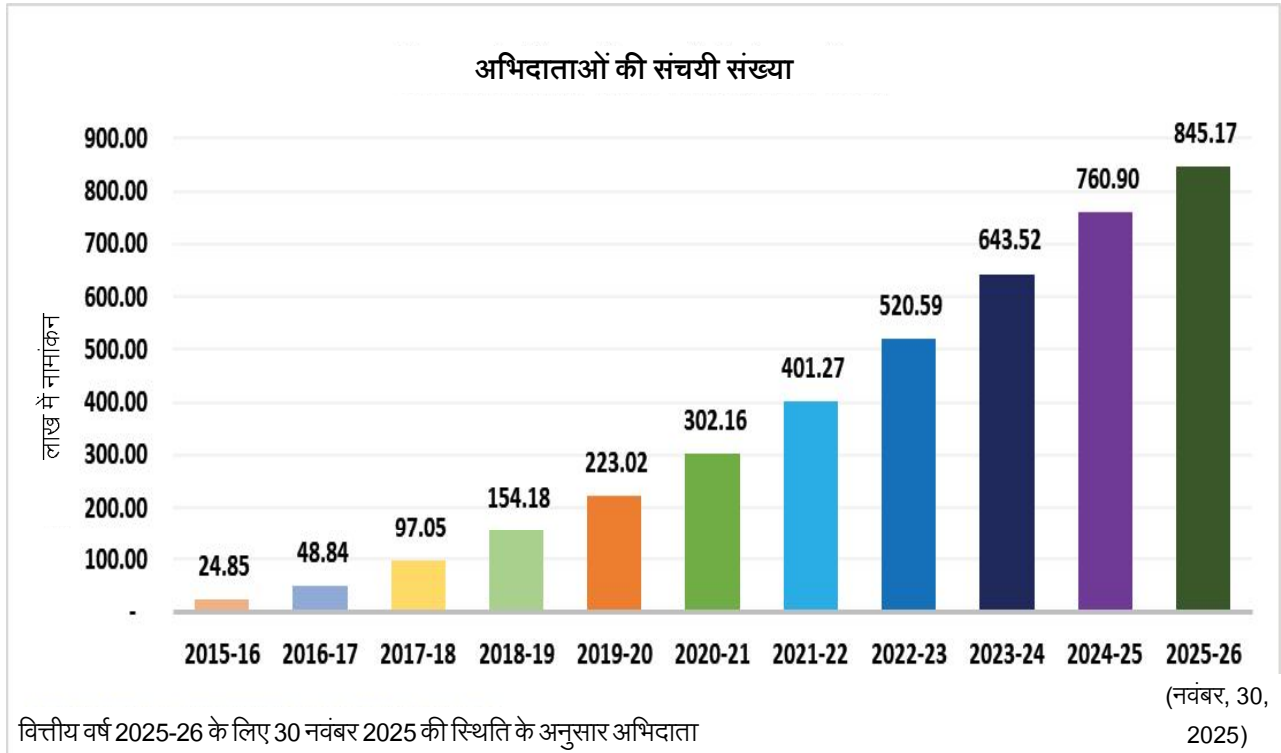
एपीवाई को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा अभिशासित किया जा रहा है। 30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, एपीवाई के अंतर्गत सकल नामांकन की संख्या 52,419.63 करोड़ रुपये (भारत सरकार से अंतर निधियन सहित) के एयूएम के साथ 8.45 करोड़ से अधिक है।

- नामांकन के आंकड़े: 30 नवंबर, 2025 तक एपीवाई के अन्तर्गत कुल सकल नामांकन 8.45 करोड़ को पार कर गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 नवंबर, 2025 तक 84 लाख से अधिक एपीवाई अभिदाताओं को नामांकित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के कुल नामांकन में से 5.89 करोड़ खाते हैं, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के 1.73 करोड़ खाते हैं।
- लिंग और आयु वितरण (30 नवंबर 2025 तक): महिला अभिदाताओं के लिए सकल नामांकन का 4,10,44,015 (48.54%) हिस्सा है। नामांकित सबसे बड़ा आयु वर्ग 21 से 25 वर्ष (27.60%, या 2,33,30,498 नामांकन) के मध्य है, इसके बाद 26 से 30 वर्ष (24.14%) है।
- पेंशन स्लैब प्राथमिकता: अधिकांश अभिदाताओं (86.91%) ने 1,000 रु. पेंशन स्लैब का विकल्प चुना, जबकि 8.15% अभिदाताओं ने उच्चतम 5,000 रु. पेंशन स्लैब का विकल्प चुना।

- प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) और रिटर्न: एपीवाई के अन्तर्गत कुल एयूएम 30, नवंबर 2025 तक ₹52,419.63 करोड़ तक

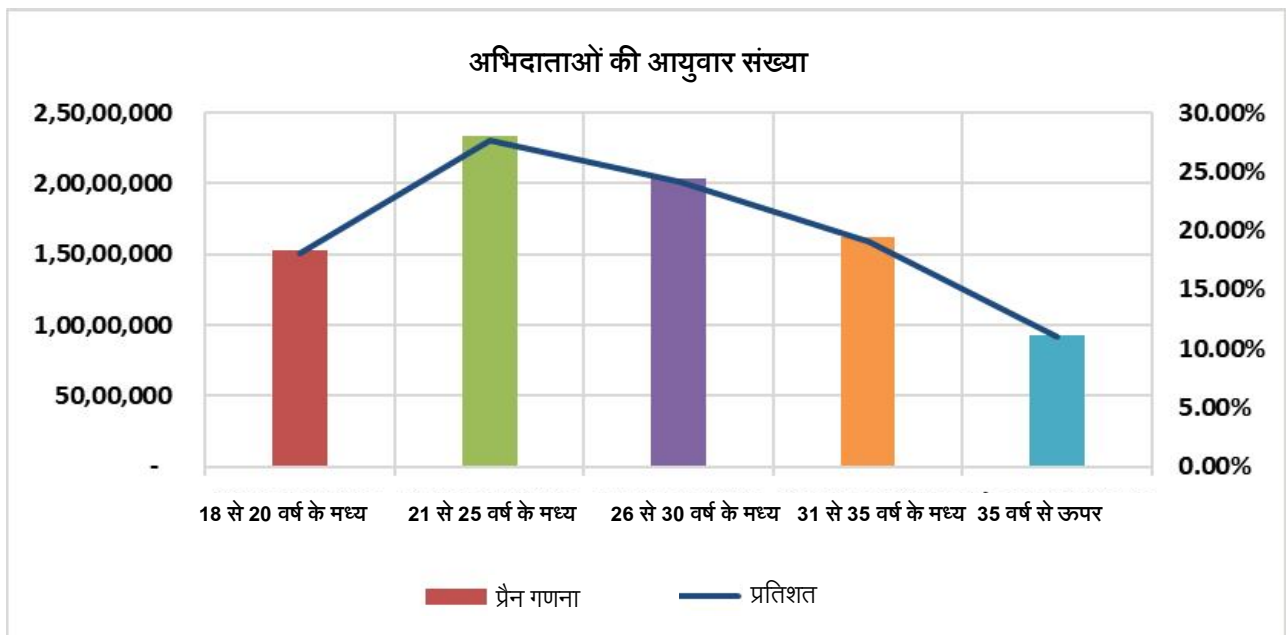
पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹44,780.49 करोड़ से अधिक था। 28 नवंबर, 2025 तक स्थापना के बाद से एपीवाई योजना रिटर्न 9.00% था।

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अन्तर्गत सकल संचयी नामांकन



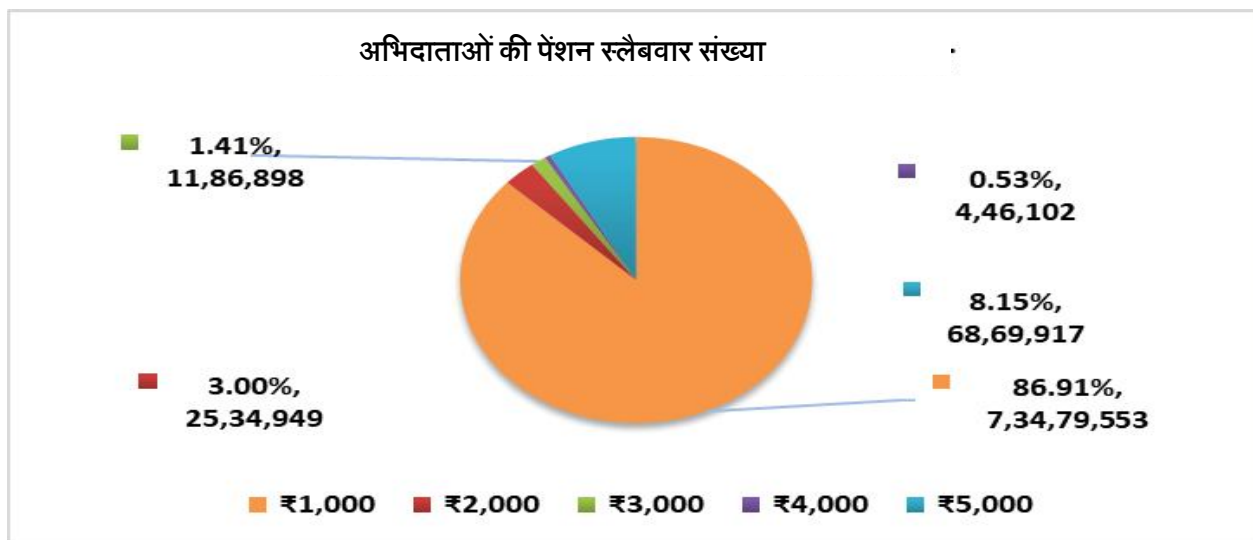
स्रोत: :प्रोटीन सीआरए

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अन्तर्गत आयु-वार सकल अभिदाता

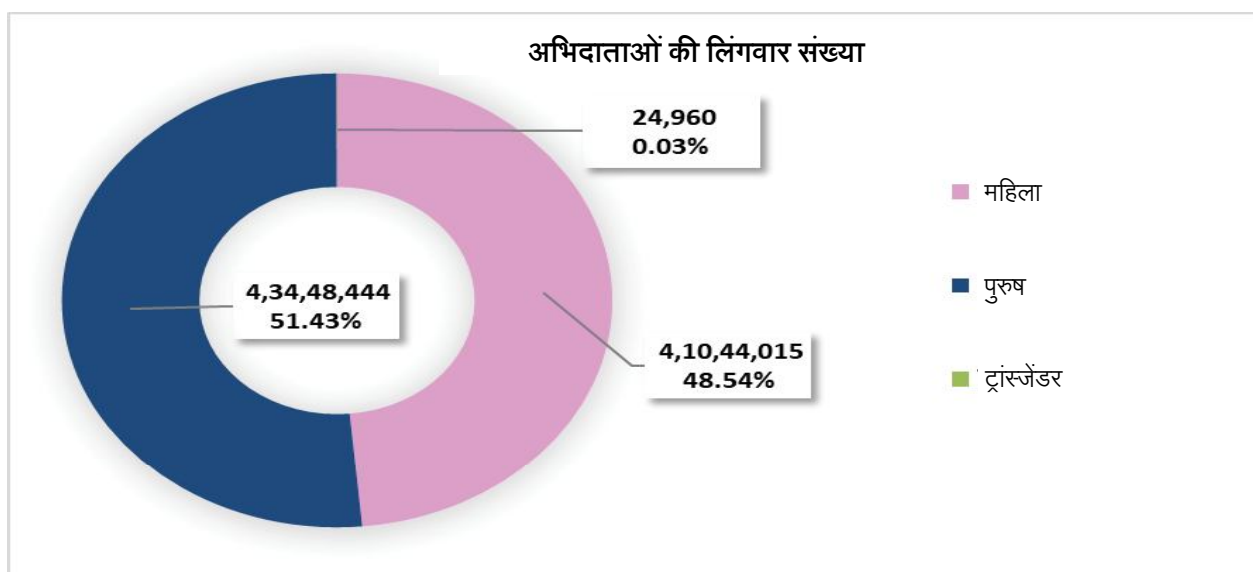


स्रोत: :प्रोटीन सीआरए

दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अन्तर्गत सकल अभिदाताओं की पेंशन स्लैब-

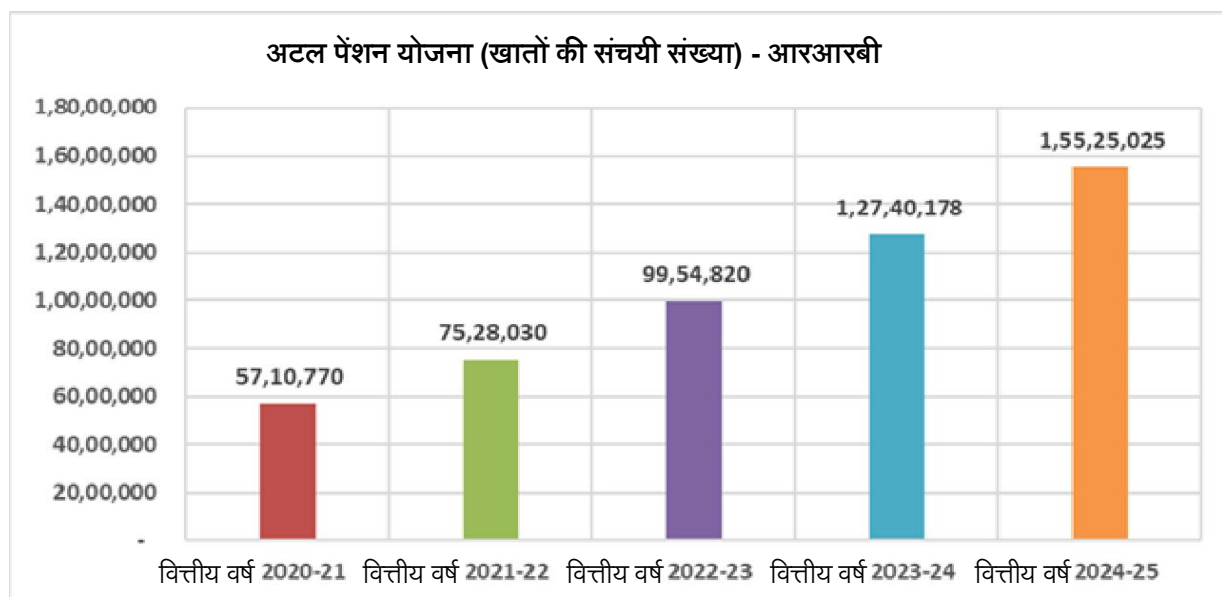


दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अन्तर्गत सकल अभिदाताओं की लिंग-वार संख्या



तालिका I: वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत कार्यनिष्पादन - संचयी खाते / नामांकन करोड़ में

क्रम सं.	सरकारी योजना	31-मार्च-24			31-मार्च-25			वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)	
		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सभी बैंक	आरआरबी का हिस्सा (%)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सभी बैंक	आरआरबी का हिस्सा (%)	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सभी बैंक
1	अटल पेंशन योजना	1.27	6.44	19.72	1.55	7.60	20.39	22.04	18.01



10.2 एकीकृत पेंशन योजना (सएपीयू)

यूपीएस को 24 जनवरी, 2025 की एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जिसे मौजूदा एनपीएस ढांचे के भीतर सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-अनुक्रमित और पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए बनाया गया था। व्यापक आउटरीच और प्रचार पहलों के परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के 1.22 लाख से अधिक कर्मचारियों ने 30 नवंबर, 2025 तक यूपीएस का विकल्प का चुनाव किया।

10.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (सएपीनए)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को भारत सरकार द्वारा 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना के माध्यम से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली को परिभाषित योगदान पेंशन योजना द्वारा बदलने के लिए आरंभ किया गया था, ताकि वृद्धावस्था आय सुरक्षा को वित्तीय रूप से स्थायी तरीके से प्रदान किया जा सके और विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में छोटी बचत को चैनलाइज किया जा सके। इसे 01 जनवरी, 2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और इसे स्वैच्छिक आधार पर 01 मई, 2009 से सभी नागरिकों के लिए भी लागू कर दिया गया है। एनपीएस को अधिकांश राज्य सरकारों और अधिकांश केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों द्वारा अपनाया गया है। इसके पश्चात, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) अधिनियम, 2013 पारित किया गया। यह योजना दो प्रकार के खाते प्रदान करती है, अर्थात् टियर-I, जो पेंशन खाता है, और टियर-II खाता, जो एक सक्रिय टियर-I खाते के साथ अनुमति प्राप्त स्वैच्छिक निकासी खाता है। एनपीएस की कुछ विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं:

10.3.1 एनपीएस की संरचना

एनपीएस की संरचना में संग्रह और वितरण शाखाओं के रूप में पाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), एक केंद्रीय अभिलेखापाल अधिकरण (सीआरए) जो डेटा और रिकॉर्ड का रखरखाव करती है, ट्रस्टी बैंक बैंकिंग संचालन का प्रबंधन करता है, ग्राहकों के निवेश पर अधिकतम प्रतिलाभ का सृजन करने और उसे अधिकतम करने के लिए पेंशन निधि (पीएफ) द्वारा खरीदी गई संपत्ति की देखभाल करने के लिए संरक्षक और एनपीएस ट्रस्ट जो ग्राहकों की संपत्ति को उनके लाभ के लिए रखता है और निवेश संचालन की देखरेख करता है, शामिल है।

10.3.2 एनपीएस के अंतर्गत निकासी

ग्राहक अपने स्वयं के योगदान का 25% तक चार साल के अंतराल के साथ और 60 वर्ष की आयु से पहले चार बार और 60 वर्ष की आयु के बाद तीन साल तक निकाल सकते हैं।

10.4 एनपीएस के तहत कर लाभ:

10.4.1 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लाभ (पुरानी व्यवस्था)

- क. धारा 80ककघ (1): कटौती के लिए पात्र कर्मचारी योगदान
 - वेतन के 10% तक (मूल राशि+ डीए)
 - स्व-नियोजित के लिए सकल आय का 20% (धारा 80सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा)
- ख. धारा 80सीसीडी (1ख): 50,000 रुपये की अतिरिक्त कर कटौती।
- ग. धारा 80सीसीडी (2): कटौती योग्य नियोजित योगदान
 - पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए वेतन के 10% तक

- नई कर व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के लिए वेतन का 14%

10.4.2 कॉर्पोरेट कर लाभ

- एनपीएस में नियोक्ता का योगदान (वेतन का 14% तक, अर्थात्, मूल राशि+ डीए) एक व्यावसायिक व्यय के रूप में माना जाता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (iv) (a) के तहत कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है।

10.4.3 स्वीकृत अधिवर्षिता निधि से एनपीएस में अंतरण पर कर लाभ

एक अनुमोदित अधिवर्षिता निधि से एनपीएस को निधि अंतरण की सुविधा के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (13) के तहत उपखंड (v) इस तरह के अंतरण को संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए कर्मचारी की आय के रूप में नहीं मानते हुए कर छूट प्रदान करता है।

10.4.4 एनपीएस से बाहर निकलने पर कर लाभ

- बाहर निकलने पर वार्षिकी की खरीद के लिए उपयोग की गई राशि (न्यूनतम 40% अनिवार्य) को आय के रूप में नहीं माना जाता है।
- वार्षिक खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर (वर्तमान में 1.8 प्रतिशत) लागू नहीं है।

- बाहर निकलने के समय कुल कोष का अधिकतम 60% आय के रूप में नहीं माना जाता है।

- आंशिक निकासी कर-मुक्त है

30 नवंबर, 2025 तक, सभी एनपीएस क्षेत्रों में कुल एयूएम 15,94,909.57 करोड़ रुपये हैं, जिसमें कुल ग्राहकों की संख्या 210.30 लाख थी। चालू वित्त वर्ष में 3,138 नए कॉर्पोरेट्स के शामिल होने के साथ कॉर्पोरेट क्षेत्र का पंजीकरण 22,957 से अधिक हो गया, जिससे औपचारिक क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति कवरेज मिली।

10.5 एनपीएस वात्सल्य

18 सितंबर, 2024 को आरंभ की गई एनपीएस वात्सल्य, नाबालिगों के लिए एक योगदान-आधारित बचत-सह-पेंशन योजना है जिसका उद्देश्य उनके भविष्य को सुरक्षित करना और बचत की संस्कृति को पोषित करना है।

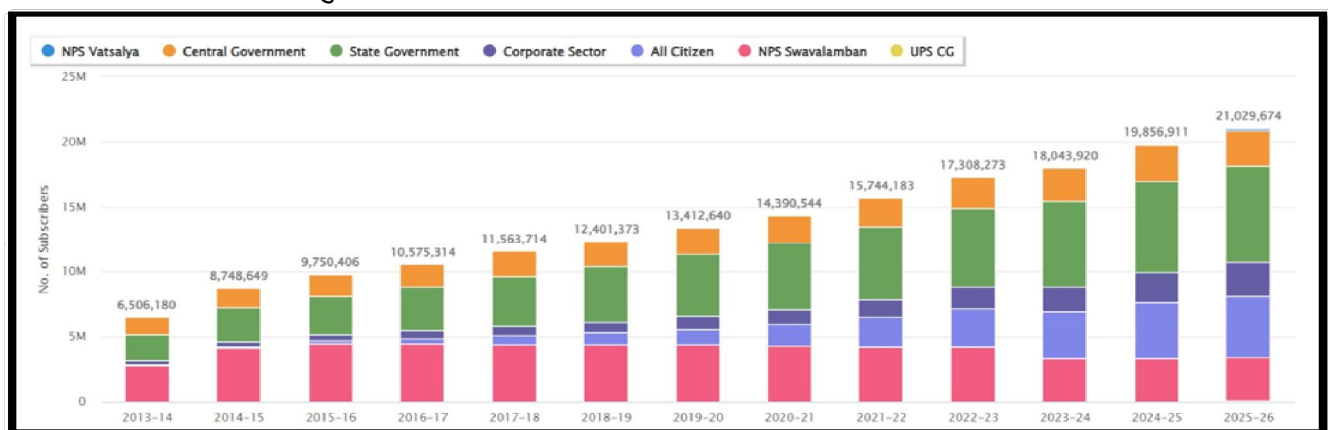
कार्य निष्पादन (30 नवंबर, 2025 तक): इस योजना में 1,59,205 ग्राहक और 215.95 करोड़ रुपये का एयूएम दर्ज किया गया। ग्राहकों की संख्या में 70,599 महिलाएं और 88,558 पुरुष शामिल हैं। सबसे बड़ा नामांकित आयु समूह 0-5 वर्ष (66,686 ग्राहक) है।

10.6 30 नवंबर, 2025 तक एनपीएस की स्थिति निम्नानुसार है:

क्षेत्र	सब्सक्राइबर की संख्या (लाखों में)	प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (करोड़ रुपये में)
केंद्र सरकार	28.01	4,31,005.49
राज्य सरकार	74.58	8,14,339.54
गैर-सरकारी क्षेत्र	निगमित	25.97
	सभी नागरिक मॉडल	46.65
	वात्सल्य	1.59
एनपीएस लाइट* (बंद)	33.50	6,387.97
कुल	210.30	15,94,909.57

*(1 अप्रैल, 2025 से कोई नया पंजीकरण अनुमति नहीं है)

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार एनपीएस सब्सक्राइबर आधार



10.7 समावेशी विकास/सार्वजनिक सेवा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और पहल

10.7.1 नीतिगत निर्णय और रूपरेखा:

1. **पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में संशोधन:** पीएफआरडीए ने हितधारकों के परामर्श के बाद 12 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के माध्यम से पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में संशोधनों को अधिसूचित किया। संशोधनों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति आय सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अभिदाता के लचीलेपन और विकल्प को बढ़ाना है।

संशोधनों में अधिकतम प्रवेश और निकास आयु 85 वर्ष, निहित अवधि को संशोधित करने और सभी नागरिक मॉडल ग्राहकों के लिए न्यूनतम सदस्यता अवधि को हटाने का प्रावधान है। सिस्टेमेटिक लम्प विडड्रॉल (एसएलडब्ल्यू) और सिस्टेमेटिक यूनिट विडड्रॉल (एसयूआर) सहित संरचित भुगतान विकल्प प्रदान करने वाले निकास प्रावधानों की पुनः जांच की गई है कम कार्पस राशि (12 लाख रुपये तक) के लिए अभिदाता पूर्ण निकासी और/या एस. यू. आर. या वार्षिकी का विकल्प चुन सकते हैं, जबकि उच्च कार्पस के लिए, 100% का लाभ उठाने के विकल्प के साथ एस. एल. डब्ल्यू. या एस. यू. आर. के रूप में ली गई एकमुश्त राशि के साथ वार्षिकी अनिवार्य है क्योंकि किसी भी कार्पस आकार के लिए वार्षिकी उपलब्ध रहती है। सेवानिवृत्ति से बाहर निकलने/60 वर्ष/15 वर्ष की अवधि प्राप्त करने के लिए, जैसा लागू हो, सरकारी ग्राहकों के लिए एकमुश्त और वार्षिकी अनुपात 60:40 पर यथावत रखा गया है, जबकि गैर-सरकारी ग्राहकों के लिए इसे संशोधित कर 80:20 कर दिया गया है। समय से पहले बाहर निकलने के लिए पूर्ण निकासी सीमा 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है और 60 वर्ष की आयु के बाद शामिल होने वाले ग्राहक निहित अवधि की आवश्यकता के बिना बाहर निकलने के लिए पात्र हैं।

यह संशोधन विनियमित वित्तीय संस्थानों को आंशिक निकासी पर लागू सीमा के भीतर व्यक्तिगत पेंशन खातों पर ग्रहणाधिकार अंकन के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी अनुमति देता है। आंशिक निकासी की अनुमति चार साल के अंतराल के साथ और 60 वर्ष की आयु से पहले चार बार और 60 वर्ष की आयु के तीन साल बाद दी जाती है। समग्र सेवानिवृत्ति आय उद्देश्यों को बनाए रखते हुए एनपीएस के तहत विशिष्ट प्रयोजन योजनाओं की शुरुआत के लिए सक्षम प्रावधान भी शामिल किए गए हैं

2. **मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ):** 1 अक्टूबर, 2025 (एनपीएस दिवस) को संचालित प्रत्येक केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) में प्रान के माध्यम से एनपीएस में कई योजनाओं को आयोजित करने और प्रबंधित करने के लिए पैन के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाने जाने वाले ग्राहक को अनुमति देता है। यह

नई संरचना पेंशन फंड (पीएफ) को विशिष्ट ग्राहक प्रोफाइल के अनुरूप योजनाओं को डिजाइन करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि स्व-नियोजित व्यवसायिक या डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकर्ता, पेंशन में समावेशिता को बढ़ावा देते हैं। इस फ्रेमवर्क के तहत 25 योजनाएं आरंभ की गई हैं। 30 नवंबर, 2025 तक कुल 15,720 अभिदाताओं ने कुल ए. यू. एम. के साथ शुरू की गई विभिन्न एमएसएफ योजनाओं में 20 करोड़ रुपये निवेश किया।

3. **निवेश विकल्पों का विस्तार और तर्कसंगत बनाना:** एनपीएस के तहत केंद्र सरकार (सीजी) के कर्मचारियों के लिए निवेश विकल्पों की सीमा को चार से बढ़ाकर छह अलग-अलग विकल्प कर दिया गया था। दो नए ऑटो चॉइस विकल्प पेश किए गए: लाइफ साइकिल 75 (एल. सी. 75) जो उच्च इक्विटी एक्सपोजर की पेशकश करता है, और बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड (बी. एल. सी.) जो जीवन में बाद में अपेक्षाकृत उच्च इक्विटी बनाए रखता है। इसके अलावा, पीएफआरडीए ने जीवन चक्र निधियों के नामकरण को तर्कसंगत बनाया ताकि उनके इक्विटी जोखिम और जोखिम प्रोफाइल को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जा सके, पारदर्शिता और चयन में आसानी को बढ़ावा दिया जा सके।
4. **एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लचीलापन:** भारत सरकार ने 'वन-टाइम वन-वे स्विच सुविधा' आरंभ किया, जिससे यूपीएस ग्राहकों को सेवा के दौरान किसी भी समय (सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति से पहले की समय सीमा के अधीन) एनपीएस में वापस जाने की अनुमति मिलती है। महत्वपूर्ण रूप से, यूपीएस के तहत अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान को पूरी तरह से कर-मुक्त कर दिया गया है।
5. **सीआरए चयन विकल्प:** पीएफआरडीए ने 15 सितंबर, 2025 को एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें एनपीएस के तहत स्वेच्छा से नामांकन करने वाले ग्राहकों को अपने पसंदीदा सीआरए का चयन करने का विकल्प दिया गया। एपीवाई और एनपीएस-लाइट के लिए, विकल्प प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) में रहता है, लेकिन यदि पीओपी कई सीआरए के साथ एकीकृत होता है, तो मौजूदा और नए दोनों ग्राहक अपने पसंदीदा सीआरए का चयन कर सकते हैं।
6. **एनपीएस निकास नीति संशोधन:** 21 अप्रैल, 2025 का एक परिपत्र, उन ग्राहकों के लिए एनपीएस खातों को बंद करने और पूर्ण निकासी (वार्षिकी के बिना) की अनुमति देता है, जिन्होंने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है और जिनके पास ओसीआई कार्ड नहीं है।
7. **सीआरए शुल्क निर्धारण:** मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (हर पांच साल में एक बार की जाने वाली) के बाद पीएफआरडीए ने 15 सितंबर, 2025 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सीआरए के लिए संशोधित शुल्क संरचना निर्धारित की गई।

8. **पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015 में संशोधन:** पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और निकासी) विनियम, 2015, जिसे पिछली बार 2021 में संशोधित किया गया था, वर्तमान में गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (एमएसएफ) के आरंभ सहित एनपीएस संरचना में हाल के विकास को दर्शाने के लिए समीक्षा की जा रही है। अधिक लचीलेपन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए हितधारकों की प्रतिक्रिया को भी संशोधन अभ्यास में शामिल किया जा रहा है।

10.7.2 समावेशी विकास और पहुंच के लिए पहल

1. अनौपचारिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत हेतु, पीएफआरडीए ने गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए एनपीएस आरंभ किया है। इस पहल की शुरुआत जोमेटो और गोवा माइल्स से जुड़े श्रमिकों को शामिल करने के साथ हुई, जो इस उभरते कार्यबल वर्ग को पेंशन लाभ देने की दिशा में एक उपाय है।
2. एमएसएमई में शामिल कार्यबल के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, परामर्श फर्मों के समन्वय में एनपीएस जागरूकता के लिए 50 से अधिक आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, व्यापार निकायों के सहयोग से एनपीएस पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं।
3. एनपीएस की दृश्यता और आम जनता के बीच पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, विभाग ने कई मीडिया भागीदारों के साथ शामिल होने के माध्यम से बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इस तरह के 50 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें इन सभी शहरों में मीडिया पार्टनर के माध्यम से कार्यक्रम से पहले और बाद में स्थानीय कवरेज शामिल है।
4. प्वाइंट ऑफ प्रेजेस (पीओपी) के कर्मचारियों का प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किया जा रहा है।
5. एनरिच एलिवेट एन्रोल-ट्रिपल «ई» और एनपीएस दिवस, एनपीएस गेम चेंजर्स अभियान पीओपी अधिकारियों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और सम्मानित करने के लिए आयोजित किए गए थे जो एनपीएस विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
6. ग्रामीण और एफपीओ आउटरीच: पीएफआरडीए ने 45,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) तक एनपीएस पहुंच का विस्तार करने के लिए एनपीएस दिवस 2025 के दौरान नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। टियर II शहरों और मफस्सिल कस्बों में भी आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, और पीएफआरडीए ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के साथ कार्य कर रहा है।
7. एनपीएस वात्सल्य जागरूकता: कम उम्र से ही जागरूकता और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 11 से 16 नवंबर, 2025 तक «बाल वित्तीय सुरक्षा सप्ताह: एनपीएस वात्सल्य के साथ जागरूकता और बचत को बढ़ावा देना» शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया गया था।

8. केवाईसी/एमएल/सीएफटी ढांचे को मजबूत करना: पीएफआरडीए ने उद्योग में प्रचलित जोखिम-आधारित केवाईसी दृष्टिकोण की ओर संक्रमण की दिशा में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जो केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित पिछले «वन-साइज-फिट-ऑल» मॉडल से अवगत। यह सुव्यवस्थित ढांचा सी. के. वाई. सी. आर., बैंक द्वारा जारी के. वाई. सी. और सी. बी. एस. आधारित सत्यापन से पहचानकर्ताओं का लाभ उठाता है ताकि न्यूनतम भौतिक दस्तावेजों के साथ तेजी से अभिदाता को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में, परिपत्र केवाईसी प्रक्रिया को विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है।
9. वितरण चैनल को मजबूत करना-एनपीएस के वितरण चैनल को मजबूत करने के लिए, पीएफआरडीए ऑनलाइन मोड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिनटेक के साथ कार्य कर रहा है। इसके अलावा, पीएफआरडीए ने एफपीओ के लिए पेंशन एजेंट विकल्पों का विस्तार किया है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन वितरण चैनलों दोनों का विस्तार करेगा, जिससे एनपीएस ईकोसिस्टम में अतिरिक्त चैनलों की व्यापक पहुंच और ऑनबोर्डिंग को सक्षम बनाया जा सकेगा और एनपीएस के तहत पीओपी के माध्यम से एफपीओ के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा जारी किया गया है।
10. अभिदाता ऑनबोर्डिंग पर संशोधित दिशानिर्देश: एनपीएस के लिए पूरी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल और मानकीकृत करने के मुख्य उद्देश्यों के साथ, एसआरएफ को अधिक समावेशी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और सभी उपलब्ध चैनलों में निर्बाध डिजिटल ग्राहक पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, पीएफआरडीए ने अक्टूबर, 2025 में अभिदाता ऑनबोर्डिंग के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश और एक संशोधित अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (एसआरएफ) जारी किया।
11. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) आउटरीच-पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2025-26 में 32 एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, जिसमें एसएलबीसी और एलडीएम के साथ समन्वय में 30 नवंबर, 2025 तक ऐसे 24 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित क्षेत्रीय कार्यनीति समीक्षा बैठकों में भी प्रचार के लिए इन कार्यनीतियों पर चर्चा की जाती है। क्षेत्रीय पहुंच बढ़ाने के लिए, हिंदी, अंग्रेजी और 21 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक-पेजर वाला एकल एपीवाई फ्लायर बनाया गया था।
12. परामर्श पत्र और भविष्य की कार्यनीति: पीएफआरडीए ने 2025 के अंत में भविष्य की कार्यनीति को संबोधित करते हुए दो परामर्श पत्र जारी किए। पहले पेपर में एनपीएस ढांचे के तहत तीन अलग-अलग योजनाओं का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें पेंशन

योजना-2, एक आश्वस्त लाभ योजना शामिल है, जिसे आवधिक मुद्रास्फीति समायोजन के साथ लक्षित पेंशन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पी. एफ. आर. डी. ए. ने 28 अक्टूबर 2025 को मुंबई में भारतीय बीमा संस्थान में परामर्श पत्र पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। सेमिनार ने एनपीएस के लिए भविष्य की रूपरेखा और परामर्श में उल्लिखित प्रस्तावों के व्यावहारिक कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिभागियों के बीच समृद्ध चर्चा उत्पन्न की। दूसरे पेपर में एनपीएस/एपीवाई में लंबे समय तक चलने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के लिए दोहरे मूल्यांकन ढांचे ('संचय' और 'उचित बाजार') को अपनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थिर पेंशन धन संचय को दर्शाना और अल्पकालिक ब्याज दर की अस्थिरता के प्रभाव को कम करना है।

10.7.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम आधारित पहल (अनुबंध I में तालिका)

पूर्वोत्तर में एपीवाई की पहुंच बढ़ाने के लिए, पीएफआरडीए ने क्षेत्रीय हितधारकों के सहयोग से आउटरीच कार्यक्रम आरंभ किए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दो प्रमुख कार्यक्रम एक एलडीएम ईटानगर के साथ समन्वय में ईटानगर में और दूसरा एसएलबीसी असम के साथ समन्वय में गुवाहाटी में आयोजित किए गए, इन कार्यक्रमों में पेंशन की आवश्यकता, इसके तीन लाभों सहित एपीवाई की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया और इसमें राज्यवार प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ संबंधित राज्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एलडीएम और राज्य समन्वयकों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल था। सत्रों में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीएफआरडीए, आरबीआई, नाबार्ड, एसआरएलएम, बैंकों, बीसी, एसएचजी, ग्राहकों और एफएलसी सदस्यों के अधिकारियों ने भाग लिया।

स्थानीय संचार को मजबूत करने के लिए, अनुसूची 22 के तहत सूचीबद्ध प्रमुख पूर्वोत्तर भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, नेपाली, खासी, मिज़ो और गारो और अंग्रेजी में भी, में एक पृष्ठ का समर्पित एपीवाई फ़्लायर विकसित किया गया है। जो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक स्वीकृति और समझ की सुविधा प्रदान करते हैं।

पीएफआरडीए की सूचीबद्ध प्रशिक्षण एजेंसी के माध्यम से पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

पीएफआरडीए और विभिन्न हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से, पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में एपीवाई सकल नामांकन 30 नवंबर 2025 तक 26.77 लाख तक पहुंच गया। इनमें से 15.10 लाख महिला नामांकन

हैं, जो इस क्षेत्र में कुल नामांकन का 56.40 प्रतिशत है। यह मजबूत महिला भागीदारी एपीवाई के तहत अधिक योग्य महिलाओं को लाने में पीएफआरडीए के केंद्रित प्रयासों को दर्शाती है।

10.7.4 ई-अभिशासन संबंधी गतिविधियाँ

10.7.4.1 डिजिटल एकीकरण और अभिदाता पहुंच

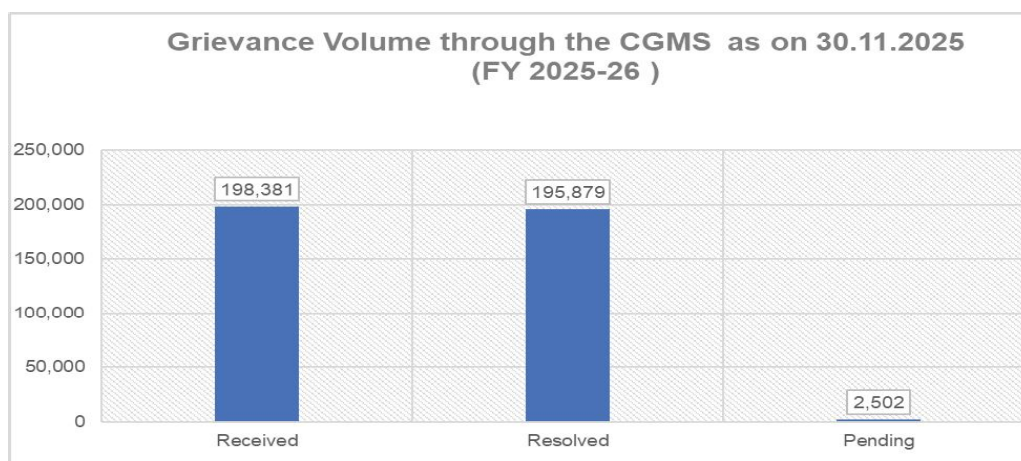
1. **भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म:** एनपीएस खाते भीम, फोनपे, मोबिक्विक और कोटक महिंद्रा बैंक (नेट बैंकिंग) सहित भारत कनेक्ट-सक्षम प्लेटफॉर्मों के माध्यम से व्यक्तिगत निवेशकों से योगदान स्वीकार कर सकते हैं।
2. **अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क इंटीग्रेशन:** एनपीएस एए फ्रेमवर्क के साथ एकीकृत हो रहा है, जो विनियमित संस्थाओं के बीच वास्तविक समय और डेटा ब्लाइंड तरीके से वित्तीय और अन्य जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। यह तकनीक एनपीएस ग्राहकों को अपनी एनपीएस जानकारी तक निर्बाध और सुरक्षित पहुंच प्रदान करती है और एन्क्रिप्टेड रूप में इसकी पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाती है।
3. **एपीवाई ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग:** बैंकों को एपीवाई ऑनबोर्डिंग के लिए ऑनलाइन वितरण चैनलों विशेष रूप से आधार-प्रमाणीकरण का उपयोग करके ई-एपीवाई पोर्टल और एपीवाई ऐप के माध्यम से, और बैंकों के नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टलों के माध्यम से मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है,

10.7.4.2 शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम)

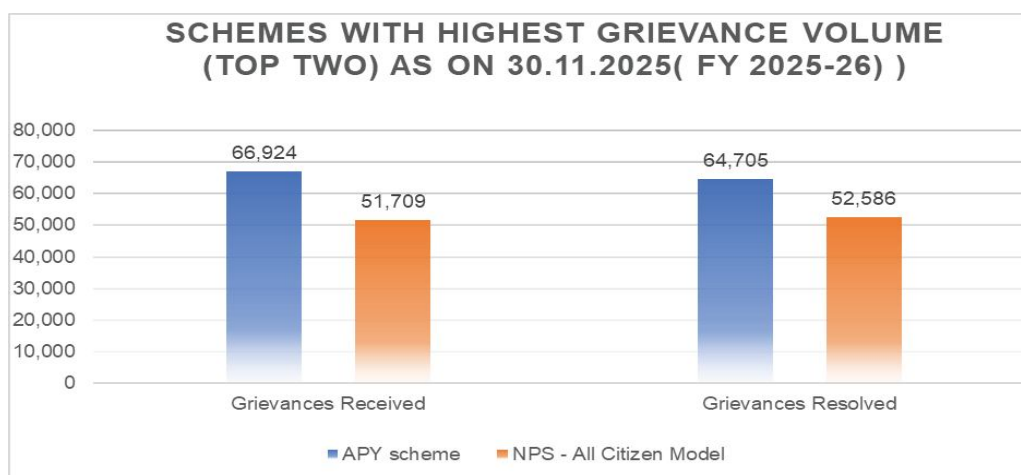
केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (सीआरए) द्वारा प्रबंधित केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीजीएमएस) एनपीएस, एपीवाई और यूपीएस के तहत ग्राहकों के लिए एक प्रणाली संचालित शिकायत निवारण तंत्र की सुविधा प्रदान करती है।

1. शिकायतों की संख्या (30.11.2025 तक वित्त वर्ष 2025-26) वित्त वर्ष 2025-26 में सीजीएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 198,381 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 195,879 का समाधान किया गया। एपीवाई योजना के तहत सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं (66,924 प्राप्त हुईं, 64,705 का समाधान किया गया) इसके बाद एनपीएस-ऑल सिटीजन मॉडल (एसीएम) (51,709 प्राप्त हुईं, 52,586 का समाधान किया गया) है
2. शीर्ष शिकायत श्रेणियां: प्राप्त होने वाली शीर्ष शिकायत श्रेणियां निकासी से संबंधित (47,098) पीआरएएन कार्ड से संबंधित (41,542) और सामान्य पूछताछ (35,732) थीं।

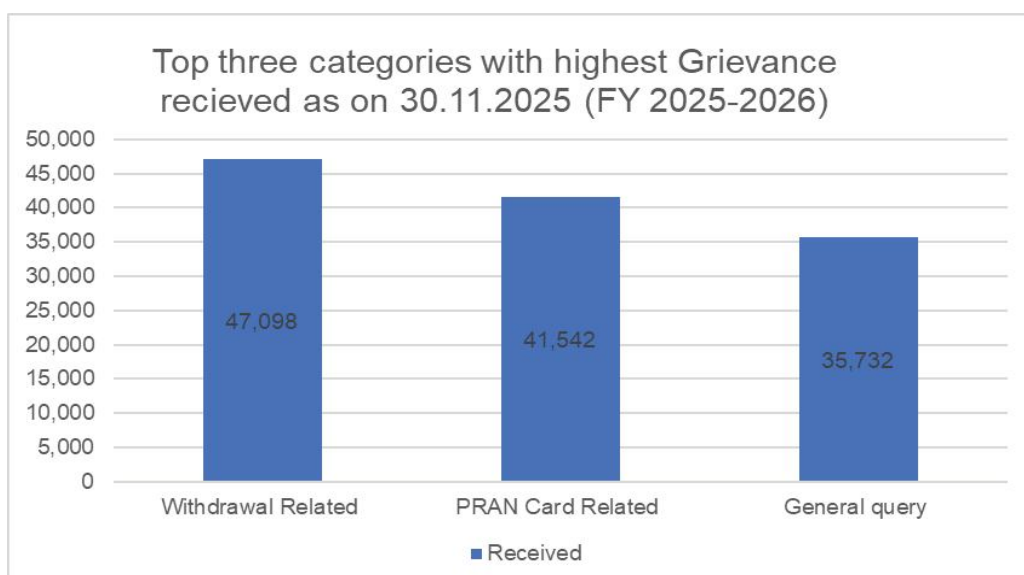
क. 30.11.2025 (वितीय वर्ष 2025-26) तक सीजीएमएस के माध्यम से प्राप्त



ख. 30.11.2025 तक सबसे ज़्यादा शिकायतों वाली योजनाएँ (शीर्ष दो) (वितीय वर्ष 2025-26)



ग. 30.11.2025 (वितीय वर्ष 2025-2026) तक सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त करने वाली शीर्ष तीन श्रेणियां



वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा 'शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने के उपाय' पर एक कार्यशाला 4.8.2025 को पीएफआरडीए में आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के तहत शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, विशेष रूप से एनपीएस, एपीवाई और यूपीएस से संबंधित पेंशन-सम्बंधित शिकायतों पर बल दिया गया। कार्यशाला में व्यवस्थित डेटा संग्रह और संकेतक-आधारित मूल कारण विश्लेषण के महत्व को उजागर किया गया ताकि बार-बार सामने आने वाली शिकायत श्रेणियों और ग्राहक की समस्याओं की पहचान की जा सके। सेवा वितरण में अंतर, प्रक्रियात्मक विलंब, प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ और मध्यस्थ स्तर पर जागरूकता की कमी जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श का उद्देश्य निगरानी में सुधार, हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और अधिक प्रभावी, समय पर और नागरिक-केंद्रित शिकायत समाधान को सक्षम बनाना था।

11. वित्तीय संस्थान

11.1 राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एक विकास वित्त संस्थान है, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 53) के अंतर्गत 1988 में स्थापित किया गया था। एनएचबी आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देने और ऐसे संस्थानों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एनएचबी के तीन व्यापक कार्य आवास वित्तीय कंपनियों (एचएफसी) का पर्यवेक्षण, वित्तपोषण और संवर्धन और विकास हैं। एनएचबी दो विकल्पों नामतः पुनर्वित्त और परियोजना वित्त के माध्यम से आवासन क्षेत्र को वित्त उपलब्ध कराता है।

एनएचबी के कारोबार में आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघु वित्त बैंकों (एसएचबी) के व्यक्तिगत आवास ऋणों का पुनर्वित्त पोषण करना और उनकी आवास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक एजेंसियों और सार्वजनिक निजी भागीदारी का वित्तपोषण करना शामिल है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने में कमी का उपयोग करते हुए की गई थी। दिनांक 30.11.2025 तक, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा प्रबंधित यूआईडीएफ के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यूआईडीएफ का प्राथमिक उद्देश्य वित्तपोषण के विश्वसनीय स्रोतों की पेशकश करके टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की शहरी अवसंरचना विकास की पहल को कार्यान्वित करना है। एनएचबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियामक आवंटन दिशानिर्देश स्थापित किए हैं और कुशल योजना निष्पादन के लिए एक स्वचालित प्रणाली लागू की है। दिनांक 30.11.2025 तक, बैंक ने यूआईडीएफ के अंतर्गत 13842.54 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और 1868.37 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

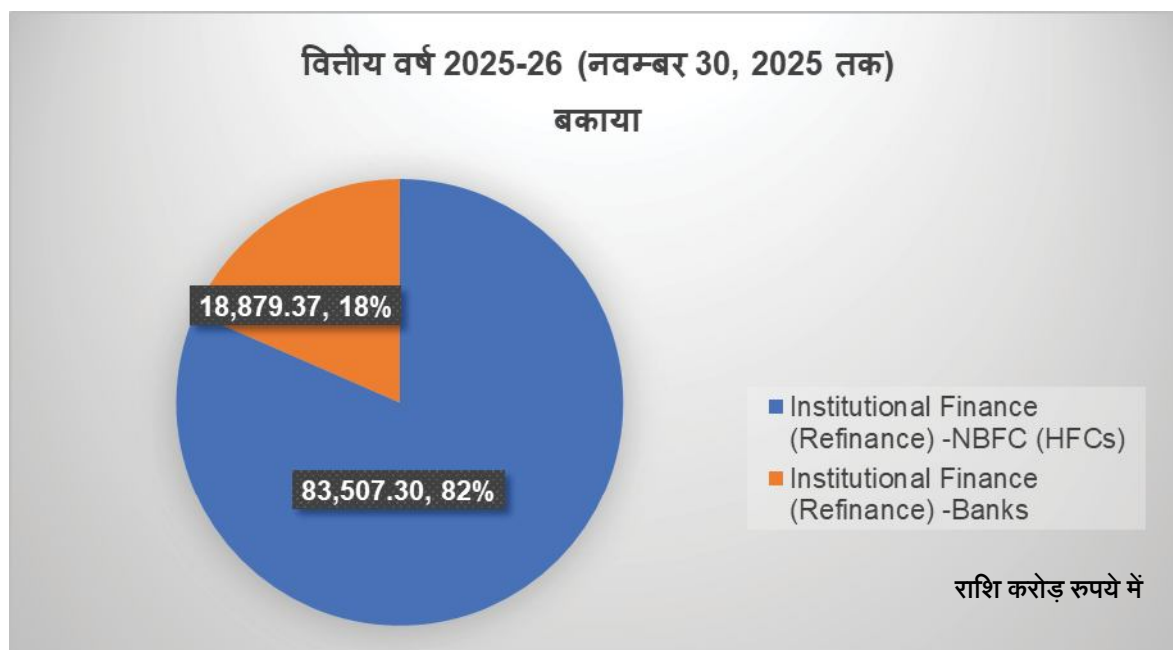
11.1.1 पुनर्वित्तपोषण

दिनांक 30.11.2025 तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने 4.33 लाख करोड़ रुपये का संयोजी पुनर्वित्त संवितरित किया है, जिसमें से 59,368 करोड़ रुपये किफायती आवास निधि के अंतर्गत संवितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 30.11.2025 तक) के दौरान एनएचबी द्वारा की गई पुनर्वित्त की गतिविधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

व्यापार समूह	वित्तीय वर्ष 2024-25 (1.7.2024 – 30.6.2025)			वित्तीय वर्ष 2025-26 (1.7.2024 – 31.11.2025 तक)		
	मंजूरी	संवितरण	दिनांक 30-06-2025 को बकाया	मंजूरी	संवितरण	दिनांक 30-11-2025 को बकाया
संस्थागत वित्त - (पुनर्वित्त) (एचएफसी) एनबीएफसी	28,168	27,266.40	86,440.55	23,618	9,387.85	83,507.30
संस्थागत वित्त बैंक - (पुनर्वित्त)	8,366	5,042	21,472.89	4,250	509.00	18,879.37
कुल	36,534	32,308.40	1,07,913.44	27,868	9,896.85	1,02,386.67

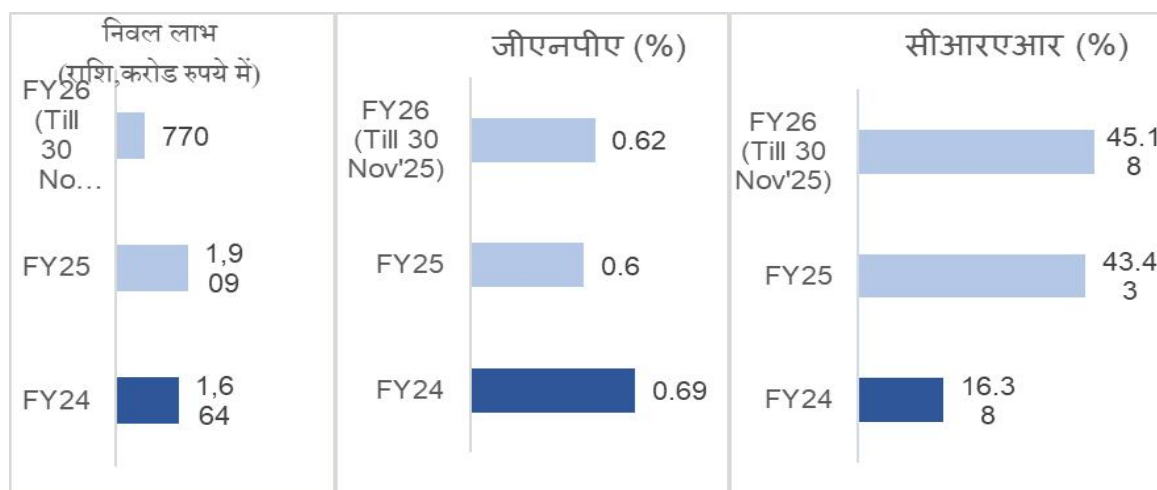
* इन आंकड़ों में पिछले वित्तीय वर्ष की अग्रेषित सीमा से संवितरण शामिल है।



11.1.2 वित्तीय विशेषताएं

- बैंक ने 30 नवंबर, 2025 (जुलाई-नवंबर) को समाप्त अवधि के लिए 1.59% के आरओए, 11.66% के एनओएफ पर रिटर्न और 30.11.2025 को 45.18% के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) के साथ 770 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया।

- 30.11.2025 को बैंक का सकल एनपीए अनुपात 0.62% था।
- बैंक ने चालू वित्त वर्ष (जुलाई, 2025 – जून, 2026) के दौरान 30.11.2025 तक 9,897/- करोड़ रुपये की संचयी राशि संवितरित की है।



11.2 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

सिडबी की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान है और यह इसी तरह की गतिविधियों में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों के समन्वय का भी कार्य करता है। सिडबी, एमएसएमई को निम्नलिखित माध्यमों से वित्तीय सहायता प्रदान करता है-

- (क) अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम के साथ ही अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रत्यक्ष वित्त
- (ख) यह बैंकों (एसएफबी सहित), एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य संस्थानों के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्त/पुनर्वित्त प्रदान करता है और ऐसे संस्थाओं के सूक्ष्म और लघु (एमएसई) ऋण पोर्टफोलियो के लिए पुनर्वित्त/संसाधन समर्थित सहायता प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

सिडबी भारत में एमएसएमई क्षेत्र के लिए विभिन्न विकासात्मक और इकोसिस्टम निर्माण पहलों जैसे क्लस्टर स्तर के हस्तक्षेप, प्रचार और विकास पहल, सरकारी योजना प्रबंधन, डिजिटल नवाचार, उद्यम पूंजी सहायता आदि में भी कार्यरत है।

11.2.1 वित्तीय विशेषताएं

समग्र पोर्टफोलियो के बढ़ने की उम्मीद है जैसा कि नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

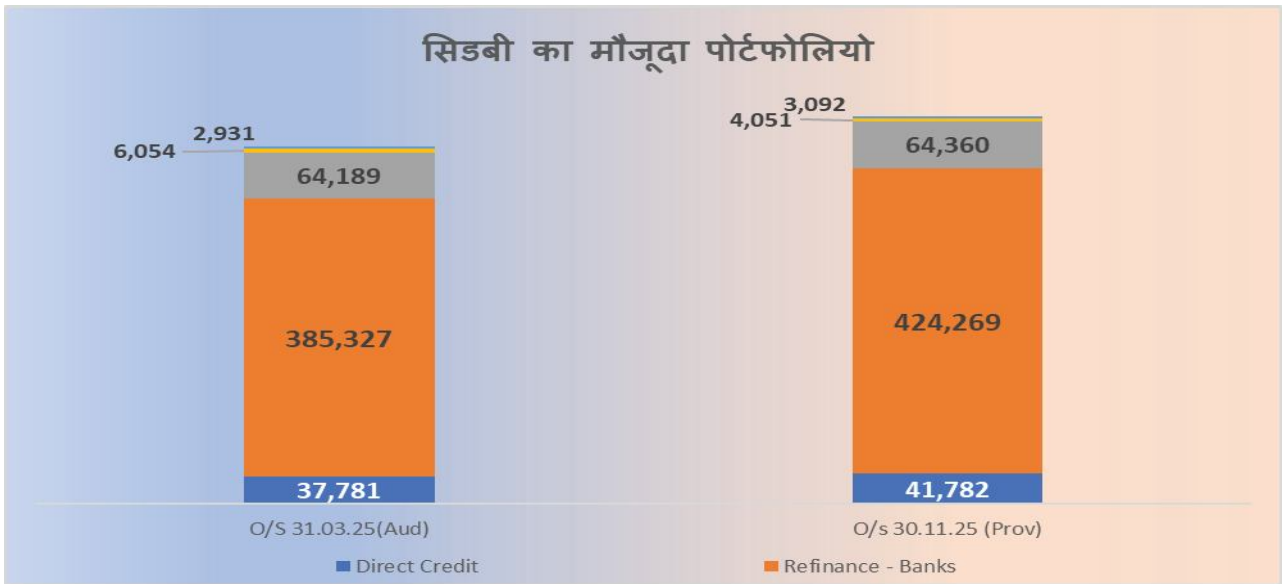
व्यापार समूह (सिडबी)	ओ/एस 31.03.25 (लेखापरीक्षित)	ओ/एस 30.11.25 (प्रावधान)
कुल	4,96,282	5,37,554

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर पश्चात लाभ और 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार सिडबी का सकल एनपीए क्रमशः 4,811 करोड़ रुपये और 0.04 प्रतिशत रहा।

11.2.2 पहलें

बैंक ने एमएसएमई की उभरती आवश्यकताओं को लक्षित करते हुए नए उत्पाद लॉन्च किए हैं, जिनमें रक्षा से संबंधित व्यवसायों के लिए नकदी प्रवाह-आधारित समर्थन, डीजी सेट खरीदने के लिए प्रोत्साहन, आतिथ्य उद्यमों के लिए आधुनिकीकरण सहायता और कृषि-आधारित उद्योगों के लिए निवेश सहायता शामिल है।

सिडबी ने पूरे भारत में औद्योगिक समूहों में उद्योग संघों का विकास (डीआईए) कार्यक्रम भी शुरू किया है। सिडबी डिजिटल पहलों के माध्यम से ऋण पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एमएसएमई के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना जारी रखता है।



वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर पश्चात लाभ और 31 मार्च, 2025 तक सिडबी का सकल एनपीए क्रमशः 4,811 करोड़ रुपये और 0.04 प्रतिशत रहा।

11.3 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्विज बैंक)

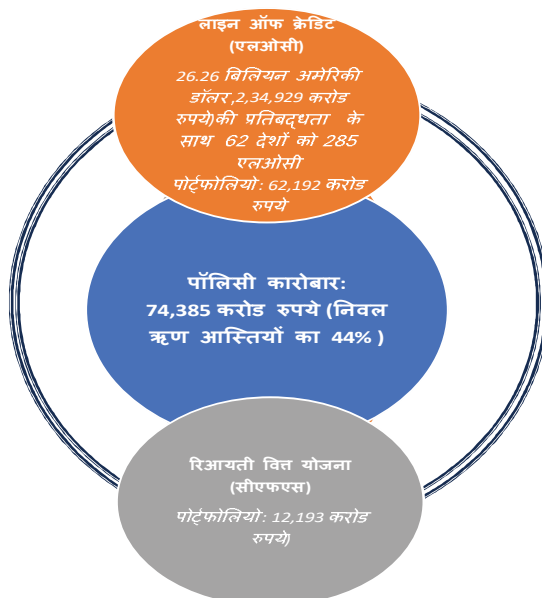
वर्ष 1982 में एक्विज बैंक की स्थापना देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने और भारत सरकार (जीओआई) के एक प्रमुख नीतिगत सूचना प्रदाता के रूप में काम करने के लिए भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के वित्त पोषण, सुविधा प्रदान करने और संवर्धन के लिए की गई थी।

एक्विज बैंक भारतीय कम्पनियों के वैश्विक प्रयासों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उधार और सेवा/परामर्शी कार्यक्रमों की विस्तृत श्रेणी की पेशकश करता है। एक्विज बैंक विशेष रूप से परियोजना निर्यात, ऋण व्यवस्था (एलओसी) और विदेशी निवेश वित्त (ओआईएफ) तथा उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाता है, जो एमएसएमई सहित समस्त विदेशोन्मुख

भारतीय कंपनियों को लाभ पहुंचाता है। बैंक का व्यापार सहायता कार्यक्रम (टीएपी) भागीदार देशों में स्थानीय बैंकों और भारत में बैंकों के बीच एक प्रभावी माध्यम प्रदान करके व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई को व्यापार वित्त अंतर को दूर करने की दिशा में भी काम कर रहा है।

इंडिया एक्विज फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड गिफ्ट सिटी में स्थापित एक्विज बैंक की सहायक कंपनी है। 30 नवंबर, 2025 तक एक्विज फिनसर्व ने 31.10 मिलियन अमरीकी डालर (275 करोड़ रुपये के समतुल्य) के कुल मूल्य के साथ लेनदेन का समर्थन किया है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में निर्यात के लिए 1,726 लेनदेन (इनवाइस) शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और दिल्ली आदि में स्थित एमएसएमई निर्यातकों का समर्थन करते हैं।

क. बैंक का पॉलिसी कारोबार (नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार)



ख. वाणिज्यिक कारोबार: (नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार)



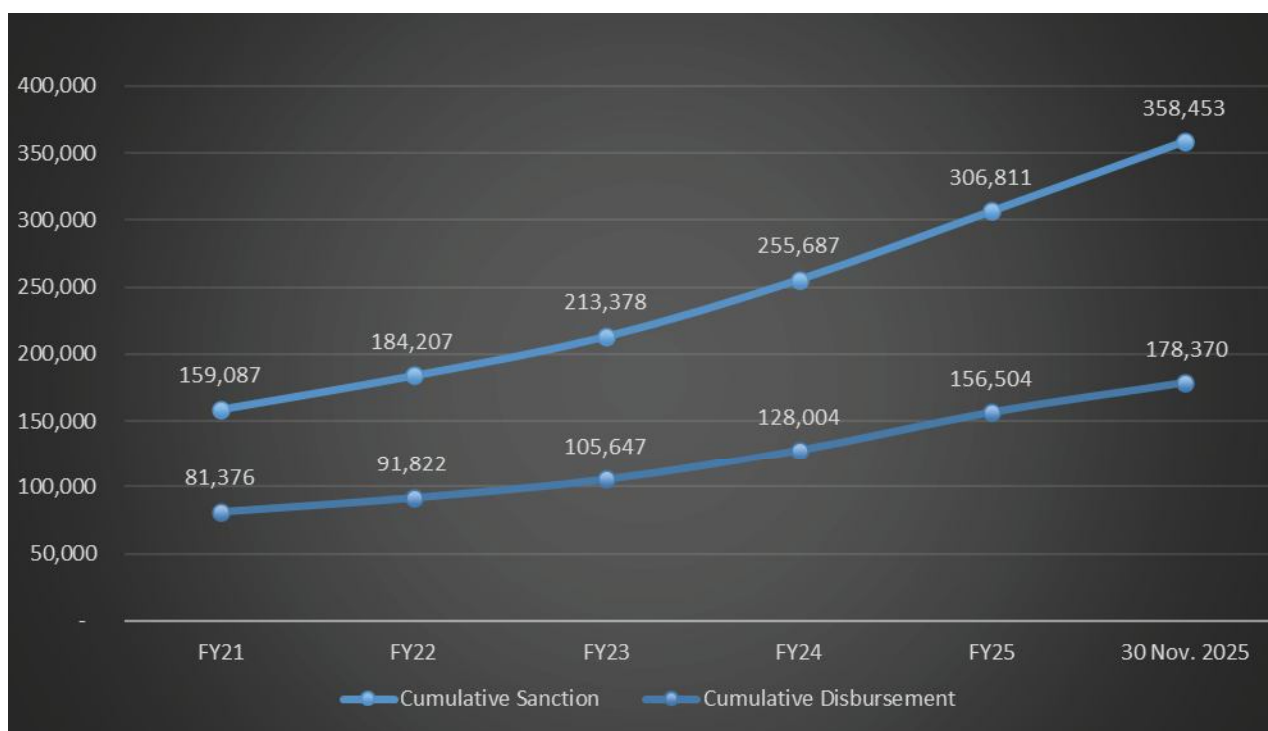
11.4 भारतीय अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

आईआईएफसीएल भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 2006 में व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। आईआईएफसीएल को सितंबर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक में एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी-अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-आईएफसी) के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह पात्र अवसंरचना उप-क्षेत्रों और उत्पाद की पेशकश के मामले में सबसे विविध सार्वजनिक क्षेत्र के अवसंरचना उधारकर्ताओं में से एक है। आईआईएफसीएल भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना का संवर्धन करने और विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न मंचों के माध्यम से सरकार को अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में इनपुट और नीतिगत सहायता प्रदान करने में भी सक्रिय है। आईआईएफसीएल ने निम्नलिखित तीन पूर्ण स्वामित्व

वाली अनुषंगी कंपनियों की स्थापना की है, जो इस प्रकार हैं:

- क) आईआईएफसी (यूके)
- ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (आईपीएल)
- ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएमसीएल)

यह संगठन सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता देता है। आईआईएफसीएल प्रत्यक्ष ऋण (एसआईएफटीआई), टेकआउट वित्त, पुनर्वित्त और ऋण संवर्धन के उत्पाद मिश्रण के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है। अपनी विकासात्मक भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवसंरचना परियोजना बॉन्ड में निवेश किया है और अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट) को ऋण देता है।



आकृति.1 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार स्वीकृतियां और संवितरण

एकल आधार पर, 30 नवंबर, 2025 तक, आईआईएफसीएल ने प्रत्यक्ष ऋण, टेकआउट वित्त, पुनर्वित्त योजनाओं, इनविट और बांड में निवेश के तहत लगभग 880 परियोजनाओं के लिए 3,58,453 करोड़ रुपये की संचयी सकल स्वीकृति दी है। इसमें प्रत्यक्ष ऋण के तहत 1,41,746 करोड़ रुपये की संचयी सकल मंजूरी शामिल है। कंपनी ने 30 नवंबर, 2025 तक 1,78,370 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया है। स्थापना से, आईआईएफसीएल का 60 प्रतिशत कारोबार वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की अवधि के दौरान किया गया है।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,165 करोड़ रुपये का सर्वकालिक उच्च कर पश्चात लाभ (पीएटी) और वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 719 करोड़ रुपये का पीएटी दर्ज किया। इसके अलावा,

आईआईएफसीएल वित्तीय वर्ष 2026 में अपने संवितरण का 20 प्रतिशत हरित और धारणीय वित्तपोषण की दिशा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लक्षित कर रहा है। अगस्त 2024 में, आईआईएफसीएल ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की सुविधा के लिए एक व्यापक सतत और ईएसजी वित्तपोषण ढांचा पेश किया, साथ ही उनकी उचित परिनियोजन के लिए एक ग्रीन वित्त फ्रेमवर्क भी पेश किया।

11.5 राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

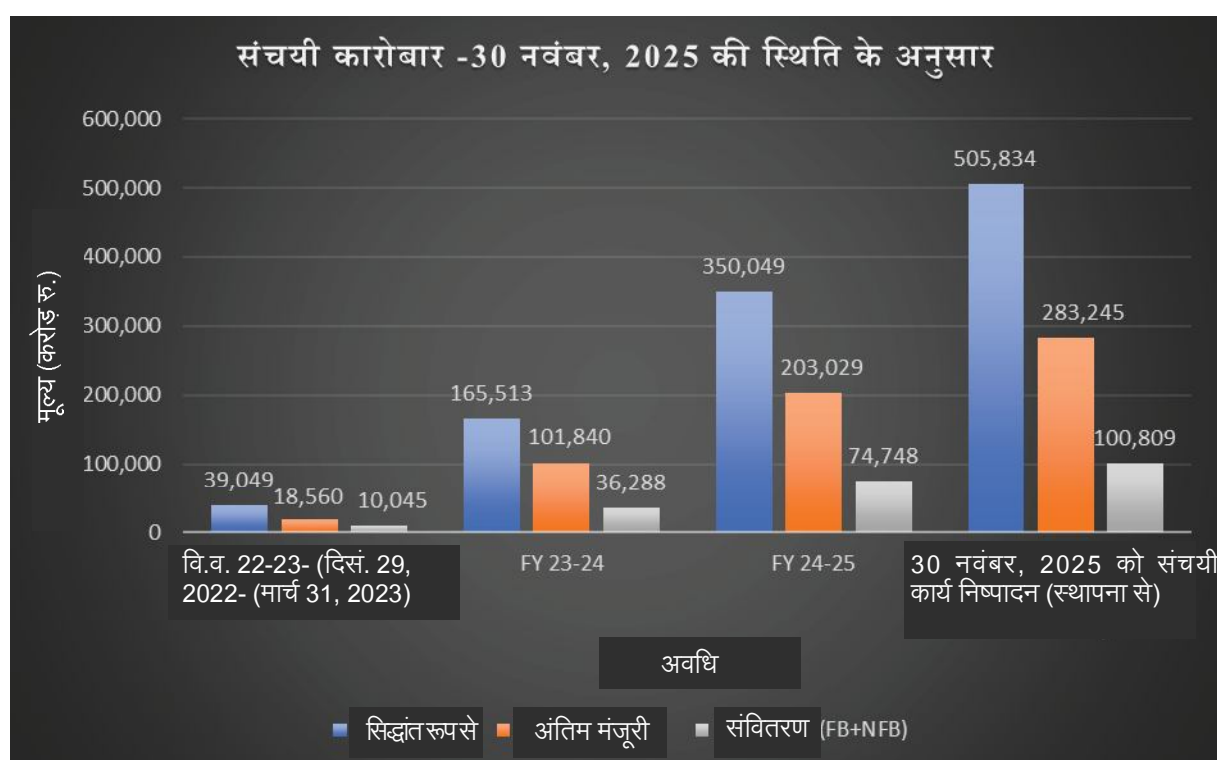
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक ('संस्था') की स्थापना 28 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 के तहत एक अवसंरचना केंद्रित विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई) के रूप में किया गया है, ताकि अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए

आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास सहित भारत में दीर्घकालिक गैर-आलंबन अवसंरचना के वित्तपोषण के विकास का समर्थन किया जा सके। आरबीआई द्वारा संस्थान को 8 मार्च, 2022 को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) का दर्जा दिया गया था।

संस्थान ने 29 दिसंबर, 2022 को अपने पहले ऋण संवितरण के साथ अपना कारोबार संचालन शुरू किया। संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए 1,602 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 2,191 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2026 के प्रथम छह महीनों के लिए 1,486 करोड़ रुपये के कर पश्चात निवल लाभ की सूचना दी। संस्थान को आईसीआरए, क्रिसिल, केयर और इंडिया रेटिंग से उच्चतम एएए (स्थिर) घरेलू रेटिंग प्राप्त हुई। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में, संस्थान ने 16,851 करोड़ रुपये जुटाए

(जिनमें से 3,911 करोड़ रुपये की अवधि 20 वर्ष थी) और सितंबर 2025 को समाप्त छमाही के दौरान, संस्थान ने बांड के माध्यम से सफलतापूर्वक 7,809 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, संस्थान ने सड़क, नवीकरण, पारेषण और वितरण, डेटा केंद्रों, अस्पतालों, शिक्षा और अन्य के मध्य सामाजिक वाणिज्यिक जैसे क्षेत्रों में ~2,83,245 करोड़ रुपये की संचयी मंजूरी (दिसंबर 2022 से) और ~1,00,809 करोड़ रुपये का संचयी संवितरण किया है। दो-तिहाई स्वीकृतियां 15-30 साल के बीच की दीर्घकालिक अवधि में हैं। संस्थान वित्तीय वर्ष 2025-2026 के अंत तक ~3,23,000 करोड़ रुपये की संचयी मंजूरी और ~1,45,000 करोड़ रुपये के संचयी संवितरण की योजना बना रहा है।



विकासात्मक अधिदेश की दिशा में प्रमुख उपलब्धि:

- संस्थान ने 18 सितंबर, 2025 को आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) उत्पाद लॉन्च किया। इसका उद्देश्य अवसंरचना के वित्तपोषण में बीमा और पेंशन फंड की भागीदारी को उत्प्रेरित करना और निवेशक आधार का विस्तार करना है। पीसीई सुविधा संबंधी जोखिम साझा करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों से बैकस्टॉप गारंटी सुविधा का कार्य प्रगति पर है।
- यह संस्थान सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लेन-देन परामर्शी सेवाएं (टीएस) प्रदान कर रहा है, जो बैंक योग्य परियोजना पाइपलाइन के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। अमरावती शहर के विकास के लिए शहरी

अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए 12 नवंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) द्वारा संस्थान को लेनदेन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। संस्थान ने 24 अक्टूबर, 2025 को डल झील के पास पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण प्राधिकरण (जम्मू एवं कश्मीर एलसीएमए) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए और इस पर काम शुरू हो गया है।

- संस्थान द्वारा दिसंबर 2024 में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/नगर निगमों के लिए अपशिष्ट से बिजली, अपशिष्ट से बायोगैस और अपशिष्ट जल उपचार सहित अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं

के ऋण वित्तपोषण के लिए एक कार्यक्रम आधारित ऋण उत्पाद शुरू किया गया था। 06 फरवरी, 2025 को निर्धारित कार्यक्रम में नगर निगमों/यूएलबी सहित विभिन्न प्रतिभागियों को इस उत्पाद की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

- iv. संस्थान विभिन्न बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ साझेदारी के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रहा है। संस्थान ऐसे ऋणों के लिए जो जलवायु वित्तपोषण के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं, के लिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) के सहयोग से एक आंशिक ऋण गारंटी प्रस्ताव विकसित कर रहा है।
- v. आंशिक ऋण संवर्धन (पीसीई) उत्पाद के विकास के लिए मिश्रित/रियायती वित्त संरचना और विश्व बैंक समूह के साथ जुड़ाव; जलवायु संबंधी लचीलापन को बढ़ावा देने और शहरी और ग्रामीण अवसंरचना के सुधार का समर्थन करने के उद्देश्य से सहयोग हेतु सह-ऋण गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त केंद्र (आईएफसी) के साथ समझौता ज्ञापन, एशियाई विकास बैंक के साथ एलओआई।

11.6 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई)

आईएफसीआई लिमिटेड (आईएफसीआई) की स्थापना 1948 में एक सांविधिक निगम ("भारतीय औद्योगिक वित्त निगम" जिसे अब "आईएफसीआई लिमिटेड" के रूप में नामित किया गया है) के रूप में उद्योग को मध्यम और दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के लिए स्वतंत्र भारत के पहले विकास वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था। वर्ष 1993 में, आईएफसीआई अधिनियम के निरसन के बाद, आईएफसीआई कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बन गई। आईएफसीआई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास पंजीकृत सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा स्वीकार न करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है और यह स्केल आधारित विनियामक (एसबीआर) ढांचे के अनुसार एनबीएफसी-मध्यम लेयर (एनबीएफसी -एमएल) के रूप में वर्गीकृत है। यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अन्तर्गत अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था (पीएफआई) भी है। आईएफसीआई अप्रैल 2015 में एक सरकारी कंपनी बन गई और आज की तारीख (30.11.2025) की स्थिति के अनुसार भारत सरकार की शेरधारिता आईएफसीआई की चुकता पूंजी का 72.57% है। आईएफसीआई बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसकी छह अनुषंगी कंपनियां हैं, और इसके अंतर्गत एक सहयोगी कंपनी भी है।

11.7 आईएफसीआई लिमिटेड सरकारी परामर्शी सेवाएं तथा निगम संबंधी परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है। सरकारी परामर्श में, आईएफसीआई

को भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत" के तत्वावधान में शुरू की गई विभिन्न उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और अभिज्ञात क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। आईएफसीआई विभिन्न पूंजी सब्सिडी योजनाओं के लिए सत्यापन और निगरानी एजेंसी भी है। निगमित सलाहकार के अंतर्गत, आईएफसीआई कारपोरेट और सरकारी क्षेत्रों को वित्तीय सलाहकार, ईएसजी परामर्शी तथा अन्य परियोजना परामर्शी सेवाएं प्रदान कर रहा है। आईएफसीआई 1984 से चीनी विकास निधि (एसडीएफ) के ऋणों की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी भी है।

11.8 नई पहलें

- एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (एमसीजीएस-एमएसएमई)

सरकार ने एमसीजीएस-एमएसएमई नामक एक सरकार समर्थित पहल का आरंभ किया है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु ऋण तक सुगमता में मदद करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह योजना ऋण गारंटी प्रदान करती है, जिससे एमएसएमई के लिए विशेष रूप से आवश्यक लिखत और मशीनरी खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह योजना ऋणदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) को एमएसएमई को 100 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण के लिए ऋण गारंटी कवर प्रदान करती है, जिसमें लिखत/मशीनरी की खरीद शामिल है।

- नया ऋण मूल्यांकन मॉडल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल आरंभ किया गया है। यह ऋण मूल्यांकन मॉडल इकोसिस्टम में उपलब्ध डिजिटल रूप से प्राप्त और सत्यापन योग्य डेटा का लाभ उठाता है और सभी ऋण आवेदनों के लिए वस्तुनिष्ठ निर्णय और दोनों एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए मॉडल-आधारित सीमा मूल्यांकन का उपयोग करके एमएसएमई ऋण मूल्यांकन के लिए स्वचालित माध्यम तैयार करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) के पास एमएसएमई ग्राहकों के लिए मॉडल उपलब्ध है।

पीएसबी में, भारतीय स्टेट बैंक ने एमएसएमई इकाइयों द्वारा बैंकों से उनकी आवश्यकता-आधारित ऋण आवश्यकताओं के लिए ऋण आवेदन के लिए आईटी सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। मुख्य लिखत/विशेषताएं और इसका प्रभाव (विभिन्न पहलुओं में ग्राहक संतुष्टि) निम्नानुसार हैं:

मामले का अध्ययन: भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई इकाइयों द्वारा उनकी आवश्यकता-आधारित ऋण आवश्यकताओं के लिए ऋण आवेदन के लिए एंड टू एंड आईटी समर्थित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था।

प्रमुख लिखत/विशेषताएं

- ग्राहक के डिजिटल फुटप्रिंट (जीएसटी, आईटीआर, बैंक खाता विवरण, सीआईसी रिपोर्ट आदि) के आधार पर एमएसएमई ऋणों के लिए तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी।
- 10 लाख रुपये तक के मुद्रा ऋण के लिए जन समर्थ पोर्टल और 10 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीएलपी पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन सोर्सिंग एक एंड-टू-एंड जर्नी है।
- अधिकांश सम्यक तत्परता विभिन्न एपीआई के माध्यम से डिजिटल रूप से किए जाएंगे।
- 50 लाख रुपये तक के एमएसएमई ऋण के लिए ऋण प्रोसेसिंग में औसतन 45-50 मिनट का समय लगता है।
- बीआरई द्वारा मंजूरी के बाद भौतिक कागजात/दस्तावेजों को न्यूनतम जमा करना।
- यह जीओ/एनओजीओ मॉडल पर एमएसएमई ग्राहकों के अनुरोध के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के साथ एंड-टू-एंड जर्नी है।

प्रभाव

- ऋण आवेदन करने के लिए शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। एमएसएमई प्रमोटरों के पास 24/365 के आधार पर कहीं से भी ऋण के लिए आवेदन करने की सुविधा है।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक है और मंजूरी के लिए हार्ड कॉपी जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- ऋण आवेदन पूरा होने के तुरंत बाद, लिए गए निर्णय से आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिससे प्रक्रियागत समय में सुधार होगा।

• निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई)

- निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) का आरंभ 01.12.2025 को किया गया था ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थानों (सदस्य ऋणदात्री संस्थान - एमएलआई) को भारतीय निर्यातकों को उस अवधि के दौरान अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके जब वे कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और उन्हें अपने बाजारों में विविधता लाने और अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय करने पड़ते हैं।

- इस सक्रिय हस्तक्षेप का उद्देश्य ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए एमएलआई को प्रोत्साहित करना और निर्यातक-उधारकर्ताओं-विशेष रूप से एमएसएमई को समय पर चलनिधि सुनिश्चित करना है, जिससे उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत किया जा सके, नए बाजारों की तलाश की सुविधा मिल सके, आपूर्ति श्रृंखलाओं का स्थिरीकरण हो सके, निर्यात गतिविधियों के विस्तार का समर्थन किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

• योजना की विशेषताएं

- ऋण सहायता: पात्र निर्यातकों को अतिरिक्त संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी में ₹20,000 करोड़ तक
- गारंटी कवरेज: सदस्य ऋणदात्री संस्थानों को एनसीजीटीसी के माध्यम से 100 प्रतिशत कवरेज

- पात्रता: एमएसएमई और गैर-एमएसएमई इकाइयों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातक

- मात्रा: स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा का 20% तक

- अवधि: 4 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की अधिस्थगन भी शामिल है

- गारंटी शुल्क: शून्य

- वैधता: 31 मार्च 2026 तक या ₹20,000 करोड़ तक गारंटी जारी की जाती है।

11.9 जीएसटी सहाय परियोजना-

सिडबी ने ऑनलाइन पीएसबी ऋण लिमिटेड (ओपीएल) और आईएसपीआईआरटी के सहयोग से सूक्ष्म उद्यमों को छोटे मूल्य के ऋण के लिए 'ऑन टैप' इनवॉयस-आधारित वित्तपोषण (नकदी प्रवाह आधारित) प्रदान करने के लिए ओपन क्रेडिट एन्हांसमेंट नेटवर्क (ओसीईएन) और अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क का उपयोग करके एक संदर्भ जीएसटी सहाय ऐप विकसित किया है। ऐप की संकल्पना कागज रहित है और उत्पत्ति से लेकर पुनर्भुगतान तक समग्र ऋण अवधि को कवर करती है। यह कागज रहित प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से व्यापार जानकारी, एए के माध्यम से बैंक की जानकारी, क्रेडिट ब्यूरो की स्थिति, आदि और इंडिया स्टैक के अन्य घटकों जैसे ई-साइन और ई-स्टाम्पिंग, ई-एनएसीएच जनादेश आदि से व्यापार जानकारी का उपयोग करता है। विनियमित संस्थाओं द्वारा जीएसटी सहाय ऐप को अपनाने के लिए आरबीआई की मंजूरी के बाद, सिडबी ने जन औषधि केंद्र और संबंधित हितधारकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए 12.3.2024 को इस ऐप को आरंभ किया।

12. विशेष न्यायालय और अभिरक्षक का कार्यालय

12.1.1 विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 दिनांक 06.06.1992 से प्रभाव में आया। विधायिका ने इस अधिनियम के माध्यम से (क) अपराधों की त्वरित सुनवाई (ख) घोटाले में शामिल होने की आशंका वाले सभी पक्षों की आस्तियों की तत्काल कुर्की एवं जब्ती और (ग) संपत्ति को उचित एवं न्यायसंगत रूप से वितरित करने के लिए विधायिका ने विशेष न्यायालय गठित करने पर विचार किया।

वर्तमान में विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उनके दैनिक कामकाज में सहायता करने के लिए, विशेष न्यायालय का कार्यालय विभिन्न स्तरों पर 26 अधिकारियों के समूह के साथ कार्य करता है।

12.1.2 अभिरक्षक का कार्यालय

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कर्तव्यों के निर्वहन में अभिरक्षक की सहायता करने के लिए वर्तमान में दो कार्यालय, नई दिल्ली और मुंबई में कार्यरत हैं। अभिरक्षक के कार्यालय की वर्तमान स्वीकृत संख्या 19 (अभिरक्षक के पद सहित) है। वर्तमान में अभिरक्षक का प्रभार वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग में उनके प्रभार के अतिरिक्त संभाला जाता है।

शुरु से अब तक, स्पेशल कोर्ट में कुल 13,636 मामले और सुप्रीम कोर्ट में 552 मामले दायर किए गए हैं, जिनमें से स्पेशल कोर्ट में 13,567 मामले और सुप्रीम कोर्ट में 490 मामले निपटा दिए गए हैं, जिससे 30 नवंबर, 2025 तक स्पेशल कोर्ट में 69 मामले और सुप्रीम कोर्ट में 62 मामले निपटाए जाने बाकी हैं। 30 नवंबर, 2025 तक, नोटिफाइड पार्टियों की कुल बकाया देनदारियां 40,905.15 करोड़ रुपये थीं, जबकि रिकवर की जा सकने वाली एसेट्स की वैल्यू 6,342.5 करोड़ रुपये थी। 30 नवंबर, 2025 तक कस्टोडियन द्वारा 13,539.33 करोड़ रुपये (लगभग) रिकवर किए गए हैं और इन संपत्तियों में 7,196.83 करोड़ रुपये से विशेष न्यायालय के अनुदान के अनुसार आयकर विभागों, बैंकों और अन्य को वितरित किया गया है।

13. लोक शिकायतों का निपटान

बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों से संबंधित जनता की शिकायतों का समय पर निवारण, वित्तीय क्षेत्र के इस अत्यंत महत्वपूर्ण खंड में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को उन्नत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने लोक शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन वेब-आधारित प्रणाली, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) की स्थापना की है।

डीएआरपीजी ने दिनांक 23.08.2024 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से शिकायतों के निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया था और अपीलों के निवारण की समय सीमा 30 दिनों पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

वित्तीय सेवाएं विभाग में नागरिकों से सीधे ऑनलाइन और डाक के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों/समस्याओं की एक महत्वपूर्ण संख्या बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों से संबंधित है। डाक संबंधी शिकायतों को भी डिजिटाइज किया जाता है और सीपीग्राम के माध्यम से संसाधित किया जाता है ताकि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसबी/पीएसआईसी) के उप महाप्रबंधक/महाप्रबंधक (डीजीएम/जीएम) को 21 दिनों की अधिकतम समय सीमा के भीतर निवारण हेतु अग्रेषित किया जा सके। इस विभाग के प्रशासनिक दायरे में आने वाले सभी संगठनों को इन निर्देशों का पालन करना होगा। कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट सिस्टम पर अपलोड कर दी जाती हैं और शिकायतकर्ताओं को सीपीग्राम पर जवाब की स्कैन की हुई प्रति उपलब्ध करा दी जाती है, जिसे वे ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग में एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है, जिससे टेलीफोन नंबर 23346785 और ई-मेल पता sobo3-dfs@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

डीएआरपीजी ने मई 2023 से एक व्यापक शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक (जीआरआई) लागू किया है। जीआरआई का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों को उनकी शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा, विश्लेषण और उसे सुव्यवस्थित करने में सहायता करना है, साथ ही उनकी खूबियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना है। जीआरआई को 4 आयामों और 11 संकेतकों के आधार पर तैयार किया गया है, जिनमें संबंधित भारिता निर्धारित हैं। नवंबर 2025 के महीने के लिए, इस विभाग ने अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है, जैसा कि नीचे बताया गया है: -

क्षेत्र	जीआरआई के आधार पर डीएआरपीजी द्वारा रैंकिंग			
	अप्रैल 2025	सितम्बर 2025	अक्टूबर 2025	नवंबर 2025
बैंकिंग	24	13	11	7
बीमा	30	11	9	6

सचिव (वित्त मंत्रालय) व्यक्तिगत रूप से हर महीने यादृच्छिक आधार पर चयनित बीस (20) शिकायतों समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें नागरिकों को संबंधित संगठनों के अध्यक्ष/एमडी और सीईओ/वरिष्ठ प्रबंधन की उपस्थिति में बीएफएसआई क्षेत्र के खिलाफ अपनी चिंताओं को उठाने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार के प्रयास का सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इससे वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। आज तक, सोलह (16) ऐसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं और समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन सौ बीस (320) शिकायतों का विश्लेषण किया गया है। विभाग के संयुक्त सचिवों द्वारा भी इसी प्रकार की बैठकें आयोजित की जाती हैं। इस अनुभव से सीखते हुए, वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष/एमडी एवं सीईओ भी अपने-अपने संगठनों में इसी तरह का अभ्यास कर रहे हैं। इसका उद्देश्य विभाग में शीर्ष स्तर पर 'डिप-स्टिक सर्वेक्षण' के माध्यम से शिकायत समाधान की प्रभावशीलता का आकलन करना है।

वर्ष 2025 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के साथ प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र पर केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) कार्यशालाओं का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। विनियामक संस्थाओं, जैसे कि पीएफआरडीए के साथ कार्यशाला दिनांक 04.08.2025 को, आरबीआई के साथ दिनांक 13.10.2025 को और इरडाई के साथ

दिनांक 19.12.2025 को आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के शिकायत निवारण अधिकारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और लोकपालों ने भाग लिया था। इस तरह के अभ्यास से

संगठनों को शिकायतों के मूल कारणों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिली, जिससे शिकायतों में कमी आई और उनका गुणात्मक समाधान सुनिश्चित हुआ।



आईआरडीएआई और पीएफआरडीए में आयोजित कार्यशाला की झलकियाँ



आरबीआई में आयोजित कार्यशाला की झलकियाँ



शिकायतों की मासिक समीक्षा की झलकियाँ

शिकायत निवारण ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से, इस विभाग ने जून 2025 से शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निवारण के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की रैंकिंग शुरू की, जिससे उनके प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की रैंकिंग भी प्रक्रियाधीन है। इससे बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा त्वरित निपटान समय (टीएटी) पर अधिक ध्यान केंद्रित करने, ग्राहक और संबंधित संगठनों के बीच पारदर्शी संचार और संगठनों में ग्राहक सेवा प्रशिक्षण में वृद्धि के माध्यम से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखा कर्मचारी ग्राहकों और आगंतुकों को उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करें, सभी बैंकों को प्रौद्योगिकी (वॉयस चैट, ईमेल, क्यूआर कोड आदि) की मदद से ग्राहक सेवाओं पर प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की सलाह दी गई थी।

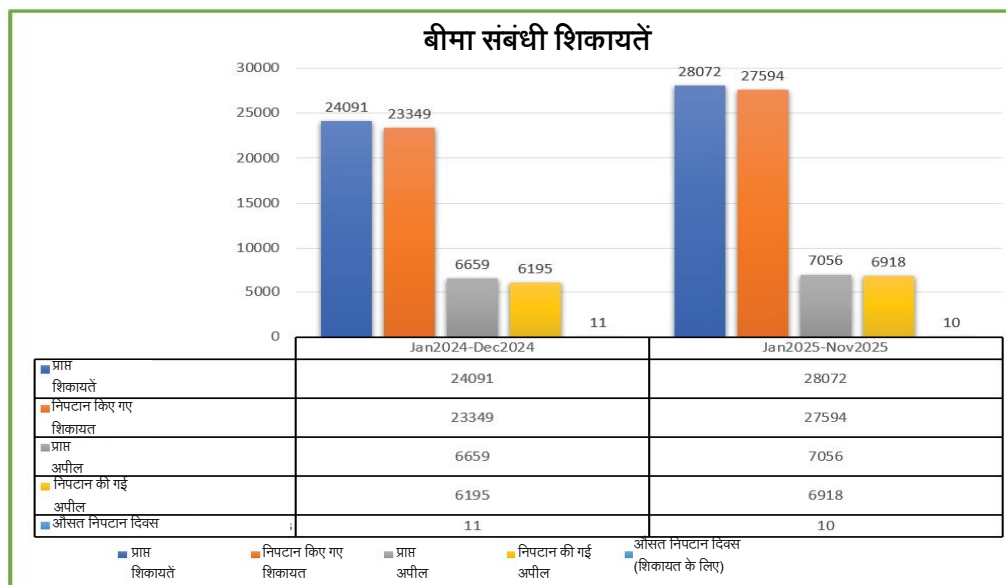
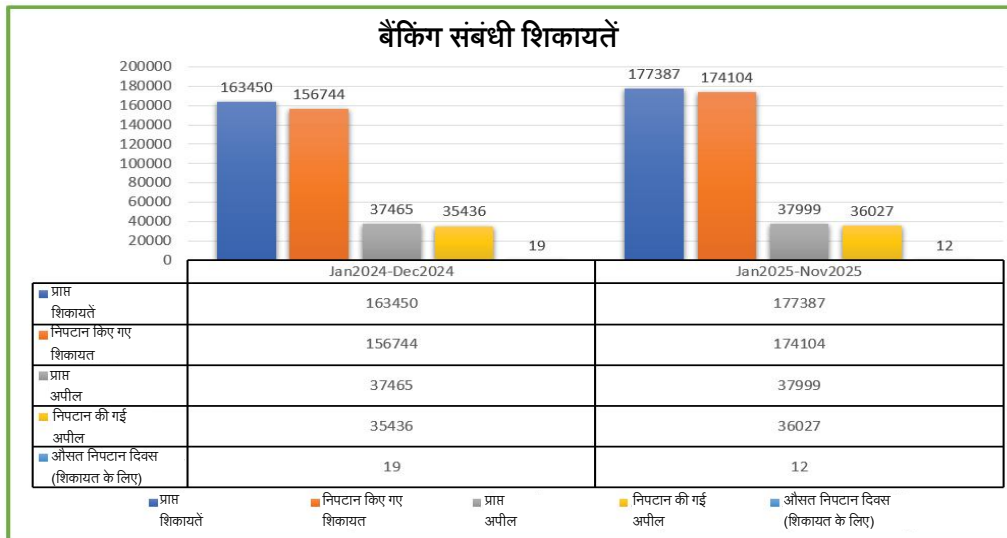
बैंकों और बीमा कंपनियों के पास अपनी शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है और यह उनकी संबंधित वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। शिकायत

निवारण का पहला स्तर बैंकों और बीमा कंपनियों में शाखा प्रबंधक होता है, उसके बाद क्षेत्रीय प्रबंधक और फिर प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक (ग्राहक सेवा) होते हैं। कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित शिकायतों का समाधान क्रमशः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के माध्यम से किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने-अपने बैंकों की शिकायतों के निपटारे के लिए लोकपाल भी स्थापित किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 12.11.2021 को 'रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' का शुभारंभ किया है। यह योजना आरबीआई की मौजूदा तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत करती है, अर्थात् – (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018 और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019। मौजूदा तीन योजनाओं को एकीकृत करने के अलावा, एकीकृत योजना के दायरे में 50.00 करोड़ रुपये और उससे अधिक

की जमा राशि वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक भी शामिल हैं। इस योजना में “एक राष्ट्र एक लोकपाल” तंत्र को अपनाया गया है। बैंकिंग के क्षेत्र में आरबीआई लोकपालों के 24 कार्यालय हैं और बीमा के क्षेत्र में 18 बीमा लोकपाल हैं।

बैंकिंग एवं बीमा विभाग के लिए दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 और दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.11.2025 की अवधि के दौरान शिकायतों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान को दर्शाने वाला बार आरेख नीचे दिया गया है:-



इस विभाग ने दिसंबर 2025 से, वित्तीय संस्थान संवाद कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें सीपीग्राम पोर्टल में प्राप्त शिकायतों के आधार पर चयनित संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। पहले चरण के रूप में, इस प्रक्रिया के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का चयन किया जाता है। डीएफएस वित्तीय सेवाएं क्षेत्र में शिकायत निवारण ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग, तीसरी मंजिल, जीवन

दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को निर्धारित शुल्क सहित उचित लिखित आवेदन देकर सूचना का अधिकार के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकता है और/या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत www.rtiononline.gov.in पर उपलब्ध ऑनलाइन पोर्टल पर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना दर्ज कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 30.11.2025 तक), बैंकिंग, बीमा और पेंशन से संबंधित विभिन्न मामलों पर 6387 आरटीआई आवेदन और 167 प्रथम अपीलें प्राप्त हुईं सभी आवेदनों और अपीलों का उत्तर/निपटान सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के भीतर कर दिया गया था।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण पर अपनी वेबसाइट पर कुछ स्वतःस्फूर्त खुलासे करने का दायित्व डालती है। डीएफएस ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों आदि से संबंधित जानकारी के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए खुलासे भी किए हैं।

15. सतर्कता

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी) और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के लिए प्रशासनिक विभाग है। विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अपने कार्यों के निर्वहन में उन्हें उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

15.1 प्रदर्शन

- विभाग का सतर्कता प्रभाग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान और अनुशासनात्मक/सतर्कता मामलों के लंबित रहने की नियमित रूप से निगरानी करता है और इस विभाग में सीवीओ के साथ उचित अंतराल पर बैठकें आयोजित करता है।
- समय-समय पर, जब भी प्रणाली में कोई खामी देखी जाती है, इन संगठनों में निवारक सतर्कता को मजबूत करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
- सतर्कता अनुभाग ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीवीओ के साथ लंबित धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा करने, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17क और 19 से संबंधित मामलों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सचिव स्तर की बैठकें भी आयोजित कीं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसबी) के लिए सीवीसी की वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक बड़े मूल्य के धोखाधड़ी के मामलों, शिकायतों और जांच की मंजूरीयों और अभियोजन के लिए स्थिति की समीक्षा करने के लिए आयोजित की गई थी।

15.2 सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 27.10.2025 से दिनांक 02.11.2025 तक मनाया गया। विभाग में सतर्कता नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध और स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, डीएफएस के सतर्कता अनुभाग ने अधीनस्थ संगठनों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के सफल समापन की निगरानी भी की।

16. ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी)

16.1 बीएएनकेएनईटी पोर्टल:

वर्ष 2018 में जारी सुधारों के एक भाग के रूप में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने बैंकों के पास गिरवी रखी गई और बैंकों/वित्तीय

संस्थानों आदि द्वारा नीलामी के लिए रखी गई संपत्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए एक एकीकृत ई-नीलामी मंच के विकास का प्रस्ताव रखा। सरकार का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वसूली तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, पारदर्शिता में सुधार करना और ऐसी नीलामी के माध्यम से प्राप्त बिक्री मूल्य को बढ़ाना था। तदनुसार, 2019 में ई-बिक्रय के रूप में एक एकीकृत ई-नीलामी मंच का शुभारंभ किया गया, जिसे इंडियन बैंक द्वारा विकसित किया गया था, और इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एमएसटीसी लिमिटेड को पोर्टल के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित करने के लिए नामित किया गया था।

उपयोगकर्ताओं की बदलती आवश्यकताओं, प्रौद्योगिकी में प्रगति और खरीदारों की भागीदारी को और अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इस प्लेटफॉर्म को समकालीन उद्योग मानकों के अनुरूप व्यापक रूप से अपग्रेड किया गया है। पुनर्गठित पोर्टल, जिसका नाम अब बीएएनकेएनईटी रखा गया है, को औपचारिक रूप से 3 जनवरी, 2025 को वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव द्वारा शुरू किया गया था। बीएएनकेएनईटी गिरवी रखी गई संपत्तियों की निर्बाध सूचीकरण और नीलामी को सक्षम बनाता है, संभावित खरीदारों के समूह को काफी हद तक बढ़ाता है, और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए वसूली परिणामों को काफी हद तक बढ़ाने की उम्मीद है।

नीलामी में बोली लगाने वालों की बढ़ती संख्या से प्रतिस्पर्धा की तीव्रता में उल्लेखनीय सुधार का संकेत मिलता है। बोली की सफलता दर को और बढ़ाने और नीलामी के समग्र परिणामों में सुधार करने के लिए पोर्टल में और अधिक कार्यक्षमताएं जोड़ी जा रही हैं।

16.2 ई-डीआरटी:

वित्तीय सेवाएं विभाग की एक प्रमुख परियोजना, ई-डीआरटी को सरकार की तीव्र गति से सुधार लाने और कारोबार करने में आसानी का माहौल बनाने की पहल के अनुरूप लागू किया गया था। दिनांक 01.10.2018 से कार्यान्वित इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में स्थित 39 डीआरटी और 5 डीआरएटी के कामकाज को डिजिटलाइज करना था। इससे प्रक्रिया प्रवाह में स्वचालन सफलतापूर्वक संभव हो पाया है, जिसके परिणामस्वरूप पारदर्शिता, सुविधा और दस्तावेजों तक आसान पहुंच के साथ-साथ लागत दक्षता भी प्राप्त हुई है। ई-डीआरटी एक सतत परियोजना है और 2018 में इसके लॉन्च के बाद से इसमें कई विशेषताएं जोड़ी गई हैं। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताओं में ई-फाइलिंग मॉड्यूल (स्क्रीन डिजाइन, वर्कफ्लो, उपयोगकर्ता पंजीकरण, ऑनलाइन केस फाइलिंग), भारत कोष भुगतान प्रणाली का एकीकरण (ऑनलाइन कोर्ट फीस भुगतान को सक्षम करना), एसएमएस अलर्ट सुविधा, एमआईएस मॉड्यूल और सीआईएस मॉड्यूल शामिल हैं, जो दस्तावेजों की जांच, मामलों की सुनवाई, फॉर्म तैयार करना, आदेश और निर्णय अपलोड करना, केस सूचियों का सार्वजनिक प्रदर्शन, केस की स्थिति आदि की सुविधा प्रदान करते हैं।

सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी डीआरटी/डीआरएटी में हेल्पडेस्क सहायता और ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, सभी डीआरटी/डीआरएटी में हाइब्रिड मोड या ऑनलाइन मोड के माध्यम से मामलों की सुनवाई शुरू कर दी गई है। इससे उपयोगकर्ताओं/वादियों को अपने मामलों की सुनवाई में दूर से ही शामिल होने की सुविधा मिली है।

16.3 ई-फाइलिंग नियम:

दिनांक 23.6.2025 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.का. नि.403 के अनुसार, ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नियम, 2020 में संशोधन किया गया है, जिससे डीआरटी/डीआरएटी में किसी भी आवेदन की ई-फाइलिंग के बाद किसी भी भौतिक फाइलिंग की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

16.4 सीकेवाईसीआरआर:

सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआरआर) वित्तीय क्षेत्र में ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड का एक केंद्रीकृत भंडार है (वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों जैसे आरबीआई, एसबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के विनियमित संस्थाओं में) जिसमें एक समान केवाईसी मानदंड और वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड की परस्पर उपयोगिता है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी रिकॉर्ड का कुशल आदान-प्रदान हुआ है, जिससे बैंकों सहित विनियमित संस्थाओं के लिए व्यापार करना आसान हो गया है और नागरिकों के लिए जीवन यापन करना आसान हो गया है। समय के साथ-साथ सीकेवाईसीआरआर का उपयोग काफी बढ़ गया है। दिनांक 30.11.2025 तक, लगभग 8,529 रिपोर्टिंग संस्थाओं (आरई) को शामिल किया जा चुका है, जिनके 108 करोड़ से अधिक केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड किए गए हैं और संबंधित केवाईसी पहचानकर्ता उत्पन्न किए गए हैं। डाउनलोड की संख्या 169 करोड़ तक पहुंच गई है, जो ग्राहक ऑनबोर्डिंग के लिए सीकेवाईसीआरआर पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। सीकेवाईसीआरआर के पुनर्गठन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, जिसमें कई सुविधाएं सक्षम की गई हैं जैसे कि वेबसाइट के माध्यम से सीकेवाईसी कार्ड खोजने और डाउनलोड करने की क्षमता, मिस्ड कॉल के माध्यम से सीकेवाईसी कार्ड तक पहुंच और डिजी लॉकर के साथ एकीकरण जिससे ग्राहक अपने केवाईसी कार्ड प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, सीकेवाईसीआरआर अब आरई को पिछले पांच वर्षों में केवाईसी रिकॉर्ड को कितनी बार अपडेट या डाउनलोड किया गया है, इस बारे में डेटा प्रदान करता है।

16.5 सीईआरएसएआई द्वारा आधार प्रमाणीकरण:

वित्त मंत्रालय (डीएफएस) द्वारा दिनांक 6.11.2025 को आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक, कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें सीईआरएसएआई को आरबीआई, सेबी, इरडाई, आईएफएसए और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित संस्थाओं से प्राप्त आधार संख्या धारक के जनसांख्यिकीय विवरणों को प्रमाणित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। यह प्रमाणीकरण धन

शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत 'हां/ना' प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके प्रदान की जाएगी। यह कदम नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने और संस्थाओं के लिए कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देता है।

16.6 प्रशिक्षण आयोजित:

➤ **मध्यस्थता प्रशिक्षण:** वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के सहयोग से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर में ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए 24 सितंबर, 2025 से 28 सितंबर, 2025 तक 40 घंटे का मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मध्यस्थता की अवधारणा, न्यायिक प्रक्रिया और विभिन्न एडीआर प्रक्रियाओं के बीच तुलना, मध्यस्थों की प्रक्रिया, चरण और भूमिका, मध्यस्थता में संचार के तरीके और साथ ही मध्यस्थता में बातचीत और सौदेबाजी सहित विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्यस्थता में विभिन्न हितधारकों जैसे रेफरल न्यायाधीशों, वकीलों और पक्षों की भूमिका को भी शामिल किया गया, जिसमें ऋण वसूली और शोधन अक्षमता (आरडीबी) अधिनियम और सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत डीआरटी के पीठासीन अधिकारियों द्वारा विचार किए गए और निपटाए गए मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया।

➤ ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों के लिए सेमिनार: 1 और 2 दिसंबर, 2025 को भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (एनजेए) में ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों के लिए एक आवासीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

इस सेमिनार के दौरान, ऋण वसूली और शोधन अक्षमता अधिनियम, 1993 (आरडीबी) की उत्पत्ति और अवलोकन, आरडीबी का क्षेत्राधिकार, डीआरटी के समक्ष कार्यवाही, डीआरटी की भूमिका, केस प्रबंधन: डीआरटी की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार के तरीके, निर्णय अधिकारी की भूमिका, ऑनलाइन निर्णय, निर्णय/आदेश तैयार करने की कला, शिल्प और विज्ञान, सरफेसी अधिनियम के बाद डीआरटी की भूमिका और जिम्मेदारियां, और ऋण वसूली अधिकरणों द्वारा सामना किए जाने वाले प्रक्रियात्मक मुद्दे और चुनौतियां सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

17. साइबर सुरक्षा और फिनटेक

क. वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की पहचान

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) को ऐसे कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके निष्क्रिय होने या नष्ट होने से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय सेवा क्षेत्र में सीआईआई की पहचान करने के उद्देश्य से, यह विभाग विनियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक

एवं विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण) और एनसीआईआईपीसी के साथ समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि विनियामकों के साथ-साथ उनकी विनियमित संस्थाओं के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की पहचान और अधिसूचना की जा सके। वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर सीआईआई की पहचान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और बैंकिंग, बीमा और पेंशन क्षेत्र में सीआईआई की पहचान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और पाइपलाइन बनाने के लिए, एनसीआईआईपीसी के परामर्श से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की गई है। आज तक, 33 संगठनों/बैंकों/विनियामक के संबंध में कुछ प्रणालियों/उत्पादों/सेवाओं को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (सीआईआई) के रूप में संरक्षित प्रणालियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिनमें से 10 संगठनों को वर्ष 2025 के दौरान अधिसूचित किया गया था।

ख. साइबर संकट प्रबंधन योजना

साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) का उद्देश्य किसी साइबर घटना से निपटने की तैयारी, प्रतिक्रिया और उससे उबरने के लिए समन्वय शुरू करने हेतु रणनीतिक अवसंरचना और कार्य योजना तैयार करना है। इस विभाग में सीसीएमपी को अक्टूबर 2020 में लागू किया गया था और इसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

ग. साइबर संकट प्रबंधन योजना

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (एनसीएसएम) अक्टूबर माह, 2025 के दौरान मनाया गया। डीएफएस के अंतर्गत आने वाले सभी विनियामकों और संगठनों से अनुरोध किया गया था कि वे साइबर सुरक्षा पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करके एनसीएसएम मनाएं। इसके अलावा, डीएफएस में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:-

- साइबर सुरक्षा जागरूकता पर डीएफएस के कार्यालय परिसर में स्टैंडी लगाई गई।
- इस महीने के दौरान इस विभाग के सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर साइबर सुरक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में भाग लें।
- डीएफएस के भूतल पर फव्वारे के पास एक फोटो बूथ लगाया गया है और सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया गया है कि वे बूथ में तस्वीरें लें और उन्हें हैशटैग #CyberJagrukNagrik के साथ सोशल मीडिया (X, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि) पर पोस्ट करें।
- इस माह के दौरान डीएफएस द्वारा एनआईसी के सहयोग से साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र आयोजित किया गया, जिसमें 60 से अधिक डीएफएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

- सभी कर्मचारियों से एनसीआईआईपीसी द्वारा आयोजित ऑनलाइन साइबर जागरूकता प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का अनुरोध किया गया था।
- कर्मचारियों के बीच साइबर जागरूकता की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक फिशिंग अभ्यास किया गया।
- प्रमुख क्षेत्रों में साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की (मास्टरकार्ड और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ), दिनांक 31.12.2025 तक 8-10 कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है, जिसमें महिला उद्यमियों के लिए साइबर जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल है। डीएफएस में साइबर सुरक्षा जागरूकता कॉमिक टूलकिट जारी किया गया।

घ. पीएसबी हैकाथॉन श्रृंखला वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों (पीएसबी) के सहयोग से शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में समावेशन, सुरक्षा और लचीलेपन से संबंधित प्राथमिकता वाली चुनौतियों का समाधान करने वाले अभिनव समाधानों को खोजना, मार्गदर्शन करना और उन्हें कार्यान्वित करना है।

इस कार्यक्रम ने पीएसबी द्वारा उत्पन्न 94 समस्या कथनों को 15 उच्च-प्रभाव वाली चुनौतियों में समेकित किया और देश भर में लगभग 2,438 छात्र टीमों (लगभग 10,000 प्रतिभागियों) को जुटाया, जो शिक्षा जगत और उद्योग में रुचि की गहराई और क्षेत्रीय प्रासंगिकता को दर्शाता है। हैकाथॉन के दो-चरण वाले डिजाइन में वर्चुअल/फिजिकल आइडिया स्क्रीनिंग को ऑन-ग्राउंड ट्रेनिंग, प्रोटोटाइपिंग और जूरी द्वारा चयनित प्रस्तुतियों के साथ जोड़ा गया था; एक मानकीकृत पुरस्कार संरचना (5 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 2 लाख रुपये; 1 लाख रुपये सांत्वना पुरस्कार) ने सभी समूहों में प्रदर्शन और गुणवत्ता मानकों को मजबूत किया।

इसके अलावा, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसबी) में से 12 टीमों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन्होंने निवेश के लिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट-2025 में वेंचर कैपिटलिस्ट/एंजल निवेशकों के सामने अपने समाधान प्रस्तुत कुल 12 चयनित टीमों में से पांच टीमों फिनटेक श्रेणी से थीं, जो वित्तीय समावेशन और पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रही थीं, और उनके समाधानों में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित कमजोर समूहों को महत्वपूर्ण रूप से लाभ पहुंचाने की क्षमता थी। शेष सात टीमों साइबर सुरक्षा श्रेणी से थीं, जिन्होंने बदलते डिजिटल खतरे के परिदृश्य के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों को विकसित करने के लिए एक समाधान प्रस्तावित किया।

ड. फिनटेक

विभाग फिनटेक इकोसिस्टम में हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर इस क्षेत्र में नवाचार, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नियमित अंतःक्रियाओं,

कार्यशालाओं और व्याख्यान श्रृंखलाओं के माध्यम से, इसने फिनटेक स्टार्टअप्स, वित्तीय संस्थानों, विनियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के साथ खुले संवाद के लिए एक मंच तैयार किया है। इन प्रयासों से विचारों के आदान-प्रदान में सुविधा हुई है, उद्योग की चुनौतियों का समाधान हुआ है और उभरते रुझानों और विनियामकीय ढांचों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिला है। इको सिस्टम के प्रतिभागियों के साथ मजबूत साझेदारी बनाकर, विभाग ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है कि भारत वैश्विक फिनटेक नवाचार में अग्रणी बना रहे।

विभाग ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण का समर्थन किया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के माननीय प्रधानमंत्री ने भाग लिया। विभाग फिनटेक भागीदारों के साथ निरंतर सहयोग करता है ताकि एक मजबूत फिनटेक इको सिस्टम के निर्माण में उपयोगी मुद्दों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया जा सके। इस दिशा में, सरकार ने फिनटेक क्षेत्र के विकास को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों पर विचार करने और इसके विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीति सुझाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी-उद्योग समिति (आईएमआईसीएफ) का गठन किया है। यह पैनाल फिनटेक क्षेत्र के विकास और बीएफएसआई क्षेत्र में इसके योगदान का विश्लेषण करेगा; फिनटेक क्षेत्र के मुद्दों और चुनौतियों को समझेगा; फिनटेक क्षेत्र में विनियामकीय और नीतिगत विकास का जायजा लेगा और एक फिनटेक विजन दस्तावेज तैयार करेगा। इस संबंध में समिति की तीन बैठकें दिनांक 11.04.2025, 12.06.2025 और 19.07.2025 को हो चुकी हैं।

यह अनुभाग भारत और सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और अमेरिका सहित कई देशों के बीच द्विपक्षीय फिनटेक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला में भी संलग्न है। यह अनुभाग अंतर-मंत्रालयी एआई समन्वय समिति (आईएमएसीसी) में विभाग का प्रतिनिधित्व भी करता है, और "राष्ट्रीय ब्लॉकचेन सेवाओं की पेशकश और ब्लॉकचेन ईको सिस्टम के निर्माण के लिए एकीकृत ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के डिजाइन और विकास" परियोजना में एमईआईटीवाई के साथ समन्वय किया है।

18. समन्वय

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने एक माह तक चलने वाला विशेष अभियान 5.0 सफलतापूर्वक संपन्न किया और लंबित भुगतानों को कम करने तथा स्वच्छता को संस्थागत रूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। डीएफएस ने 2 से 31 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला विशेष अभियान 5.0 शुरू किया, जिसमें बेहतर स्थान प्रबंधन, ग्राहक

केंद्रित पहल, पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना, अभिलेख प्रबंधन और स्क्रेप के निपटान पर विशेष बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, एनएचबी, आईआईएफसीएल आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य वित्तीय संस्थानों ने विशेष अभियान 5.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया।

विभाग ने सभी पहचाने गए सार्वजनिक शिकायतों, सार्वजनिक अपीलों और सांसद संदर्भों का 100% निपटान किया। स्क्रेप निपटान के माध्यम से 2.03 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई है और 3.20 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। यह अभियान देशभर में 41000 से अधिक स्थानों पर चलाया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों और 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पेंशन शिकायत निवारण सप्ताहों का आयोजन किया। इन शिविरों में, शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के अलावा, पेंशनभोगियों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने और घर बैठे बैंकिंग सुविधाओं के बारे में भी शिक्षित किया गया।

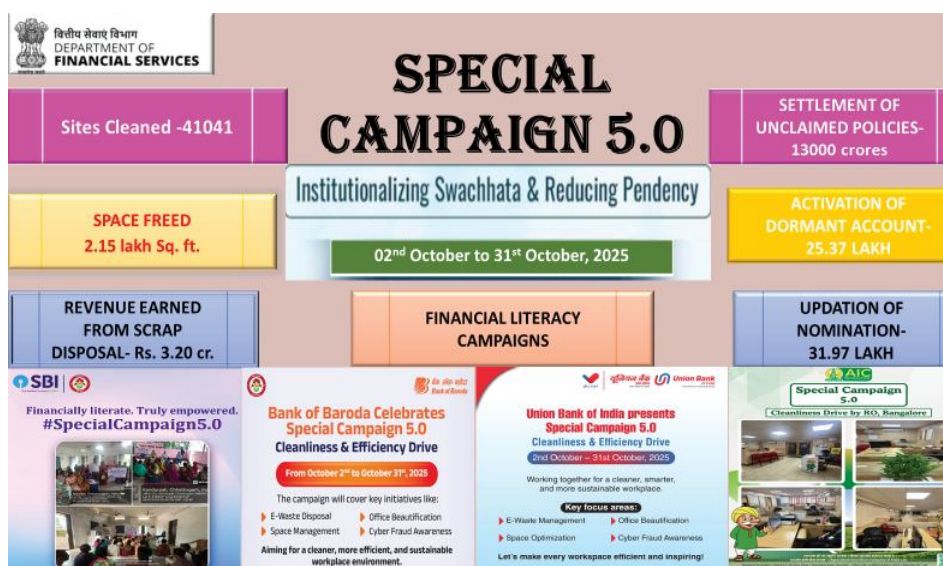
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और राष्ट्रीय आयकर बैंकों (आरआरबी) द्वारा साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न वीडियो और स्थिर सामग्री पोस्ट की गई। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए इन शैक्षिक पोस्टों के माध्यम से सुरक्षा संबंधी सुझाव और उपाय साझा किए गए। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा साइबर सुरक्षा पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई।

विभाग और संगठनों की प्रमुख बातें और उपलब्धियां:

1. स्वच्छता अभियान/स्वच्छ किए गए स्थल/कार्यालय: 41041
2. खाली हुई जगह: 2,15,965 वर्ग फुट।
3. स्क्रेप निपटान से अर्जित राजस्व: 3,20,58,911 रूपए
4. सार्वजनिक शिकायतों का निपटान: 6,207
5. सार्वजनिक शिकायतों और अपीलों का निपटान: 2,139

वित्तीय सेवा क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण, डीएफएस के संगठनों ने वित्तीय साक्षरता अभियान, बैंक खातों में नामांकन का पंजीकरण/अद्यतन, निष्क्रिय खातों को सक्रिय करना, लॉकर समझौतों का नवीनीकरण, लंबित दावों का निपटान आदि जैसी गतिविधियाँ कीं।

संगठनों द्वारा की गई सभी गतिविधियों को नियमित रूप से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट किया जाता था। इस अभियान के दौरान 500 से अधिक पोस्ट किए गए। संगठनों के ग्राहकों, कर्मचारियों, वरिष्ठ प्रबंधन और संगठनों के प्रमुखों ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अभियान के दौरान किए गए अच्छे कार्यों के बारे में अपने विचार साझा किए।



19. वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व

भारत सरकार में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और निशक्तजन (पीडब्ल्यूडी) (दिव्यांगजन) के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) नोडल विभाग है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) इन निर्देशों को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों (पीएसएफआई), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसआईसी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को परिचालित करता है। इसी प्रकार, अन्य नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा पूर्वोक्त वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों को भी सभी पीएसबी, पीएसएफआई, पीएसआईसी, आरबीआई आदि को लागू करने के लिए परिचालित किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों, पीएसएफआई, पीएसआईसी, आरबीआई, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े/ईडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध (I से IV) में दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के प्रतिनिधित्व का विवरण क्रमशः अनुबंध-III, IV, V और VI में दिया गया है।

20. राजभाषा

राजभाषा प्रभाग हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की निगरानी करता है तथा विभाग के सरकारी कामकाज में राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिपादित

राजभाषा नीति को लागू करता है। 2025-26 के लिए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

➤ हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

विभाग के तथा इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभिन्न संगठनों के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग की समीक्षा करने के लिए दिनांक 10 दिसंबर, 2025 को माननीय वित्त राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी जी की अध्यक्षता में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोग उद्यम विभाग की संयुक्त हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

➤ संसदीय राजभाषा समिति

वर्ष 2025-26 के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण का निरीक्षण किया जिसमें संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक (राजभाषा प्रभारी) और उप निदेशक (राजभाषा) उपस्थित रहे। इन बैठकों के दौरान जो आश्वासन दिए गए एवं जो निर्देश प्राप्त हुए उन्हें शीघ्रताशीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित संगठनों को संप्रेषित किया गया।

➤ हिंदी पखवाड़ा

वित्तीय सेवाएं विभाग में 14 से 30 सितंबर, 2025 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान 5 प्रतियोगिताओं अर्थात् हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं



आलेखन, राजभाषा ज्ञान एवं अनुवाद, हिंदी टंकण, तथा सामान्य हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि 5000/- (प्रथम), 3000/- (द्वितीय), 2000/- (तृतीय) एवं 1000/- (प्रोत्साहन) थी। विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ भाग लिया तथा 24 अधिकारियों / कर्मचारियों को कुल 30 पुरस्कार दिए गए। पखवाडा में आयोजित प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को सचिव, वित्तीय सेवाएं द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

➤ राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

दिनांक 14-15 सितंबर, 2025 को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा माननीय गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में दो दिवसीय हिंदी दिवस एवं पांचवे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु वित्तीय सेवाएं विभाग को हिंदी के क्षेत्र के शीर्ष पुरस्कार, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (द्वितीय पुरस्कार) प्रदान किया गया। इसी क्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग के बैंक/विनियामक आदि को भी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किए गए एवं उनके कार्यालयों द्वारा प्रकाशित हिंदी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का विमोचन किया गया।



➤ विशेष प्रोत्साहन योजना

अपना अधिकतम सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग में "वार्षिक विशेष प्रोत्साहन योजना" लागू है जिसके तहत प्रथम 5000/- रुपये, द्वितीय 4000/- रुपये और तृतीय 3000/- रुपये का नगद पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान विभाग के 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को इस योजना के तहत पुरस्कार दिया गया।

➤ हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

वित्तीय सेवाएं विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सरकारी कामकाज में हिंदी को बढ़ावा देने तथा हिंदी में काम करने में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समाधान करने में सहायता करने के लिए विभाग में नियमित आधार पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के कुल 63 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

➤ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन

वित्तीय सेवाएं विभाग में हिंदी में सरकारी काम-काज की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक तिमाही में संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। बैठक में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हिंदी के अनुभागों/कार्यालयों से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों की विस्तार से समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान कमियों को दूर करने और सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिए जाते हैं।

21. ऑडिट पैरा

सी एंड एजी कार्यालय द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित उपलब्ध कराई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश अनुबंध-VII में दिया गया है।

1. अटल पेंशन योजना

बैंकों का वर्गवार, वर्ष-दर-वर्ष एपीवाई का निष्पादन (लाख में)

बैंक की श्रेणी	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025- 26 30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार	स्थापना के बाद से – 30 नवंबर, 2025
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	86.61	88.22	78.46	57.13	588.90
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24.27	27.85	27.85	17.73	172.98
निजी बैंक	5.14	5.45	9.65	8.42	57.86
भुगतान बैंक	2.16	0.35	0.08	0.01	15.48
डाक विभाग	0.22	0.14	0.10	0.07	4.14
लघु वित्त बैंक	0.79	0.76	1.11	0.82	4.34
सहकारी बैंक	0.14	0.16	0.13	0.11	1.47
कुल	119.31	122.93	117.38	84.27	845.17

एपीवाई के अंतर्गत सकल नामांकन का सारांश

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार आयुवार

क्रम. सं.	आयु श्रेणी	कुल नामांकन	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्ष के बीच	1,52,86,229	18.08%
2	21 से 25 वर्ष के बीच	2,33,30,498	27.60%
3	26 से 30 वर्ष के बीच	2,03,96,052	24.14%
4	31 से 35 वर्ष के बीच	1,61,80,250	19.15%
5	35 वर्ष से अधिक	93,24,390	11.03%
	कुल	8,45,17,419	

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार लिंग-वार

क्रम. सं.	लिंग	कुल नामांकन	प्रतिशत
1	महिला	4,10,44,015	48.54%
2	पुरुष	4,34,48,444	51.43%
3	ट्रांसजेंडर	24,960	0.03%
	कुल	8,45,17,419	

*वित्तीय वर्ष 2024-25 में, कुल 1.17 करोड़ नामांकनों में से लगभग 54.64% महिलाएं थीं।

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार पेंशन स्लैब-वार

क्रम. सं.	पेंशन स्लैब	सकल नामांकन	प्रतिशत
1	1,000	7,34,79,553	86.91%
2	2,000	25,34,949	3.00%
3	3,000	11,86,898	1.41%
4	4,000	4,46,102	0.53%
5	5,000	68,69,917	8.15%
	कुल	8,45,17,419	

30 नवंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम में एपीवाई लिंग-वार सकल नामांकन					
क्रम.सं.	राज्य	महिला	पुरुष	ट्रांसजेंडर	एपीवाई की स्थापना से अब तक कुल नामांकन
1	अरुणाचल प्रदेश	19,462	20,776	13	40,251
2	असम	11,75,400	8,59,867	439	20,35,706
3	मणिपुर	39,674	35,194	62	74,930
4	मेघालय	50,136	40,561	9	90,706
5	मिजोरम	18,331	16,102	6	34,439
6	नगालैंड	21,433	22,212	8	43,653
7	सिक्किम	21,975	24,869	28	46,872
8	त्रिपुरा	1,68,989	1,42,277	27	3,11,293
कुल योग		15,15,400	11,61,858	592	26,77,850

II. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

30 नवंबर, 2025 तक एनपीएस क्षेत्र-वार ब्रेक-अप

क्षेत्र		सब्सक्राइबर की संख्या (लाखों में)	प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (करोड़ रुपये में)
केंद्र सरकार		28.01	4,31,005.49
राज्य सरकार		74.58	8,14,339.54
गैर-सरकारी क्षेत्र	निगमित	25.97	2,62,915.92
	सभी नागरिक मॉडल	46.65	80,041.27
	वात्सल्य	1.59	219.38
एनपीएस लाइट* (बंद हो गया)		33.50	6,387.97
कुल		210.30	15,94,909.57

अप्रैल-नवंबर 2025 के दौरान, निजी क्षेत्र (सभी नागरिक + कॉर्पोरेट) ने 8.13 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े, जो स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति बचत में लगातार तेजी को दिखाता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 3,138 नए कॉर्पोरेट्स के साथ कॉर्पोरेट सेक्टर पंजीकरण 22,957 को पार कर गया, जिससे लाखों फॉर्मल-सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट कवरेज मिला।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पंजीकरण (30 नवंबर, 2025 तक)

विशिष्ट	कुल
यूओएस (सभी नागरिक मॉडल)	5,32,496
ईएनपीएस मोड	1,03,400
कॉर्पोरेट मॉडल	1,77,889
कुल	8,13,785

अटल पेंशन योजना आउटरीच इवेंट की तस्वीरें

2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए:



राज्य स्तरीय एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम गुवाहाटी, असम (10.11.2025)



ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में जिला स्तरीय एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम (19.09.2025)

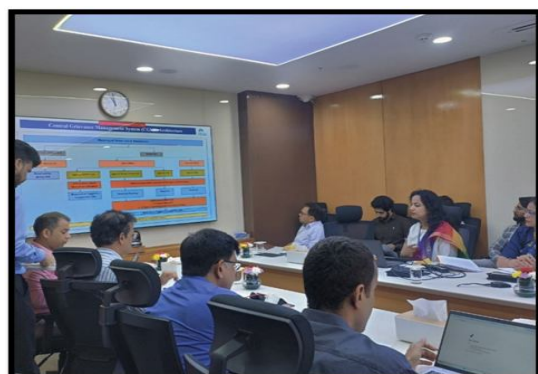
पूरे भारत में वास्तविक तौर पर राज्य स्तर और जिला स्तर पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।

		
अहिल्यानगर , महाराष्ट्र (13.08.2025)	कोलकाता, पश्चिम बंगाल (01.08.2025)	भोपाल, मध्य प्रदेश (03.09.2025)
		
भोपाल, मध्य प्रदेश (03.09.2025)	पटना, बिहार (29.08.2025)	पुणे, महाराष्ट्र (14.08.2025)
		
मदुरै, तमिलनाडु (26.09.2025)	मदुरै, तमिलनाडु (26.09.2025)	उदयपुर, राजस्थान (16.09.2025)
		
उदयपुर, राजस्थान (16.09.2025)	सिवनी , मध्य प्रदेश (09.09.2025)	शिमला, हिमाचल प्रदेश (31.10.2025)
		
शिमला, हिमाचल प्रदेश (31.10.2025)	वडोदरा, गुजरात (12.09.2025)	वडोदरा, गुजरात (12.09.2025)

एनपीएस आउटरीच इवेंट नई दिल्ली, बंगलुरु और असम में आयोजित किया गया



वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) की ओर से 4.8.2025 को पीएफआरडी में 'शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के उपाय' के संबंध में कार्यशाला



अनुबंध III

30.11.2025 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का समूहवार प्रतिनिधित्व-																		
समूह	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2024 की स्थिति के अनुसार)					(कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान की गई नियुक्तियों/ अर्थात् पदोन्नतियों की संख्या 1.1.2025 से 30.11.2025 तक)												
						सीधी भर्तों द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति			अन्य माध्यम से की गई नियुक्ति				
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यू.एस.	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यू.एस.	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यू.एस.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह क	488486	88935	40323	137410	5501	15164	2253	1048	4616	1279	26387	4754	1887	10	1	0	0	0
समूह ख	21715	3505	1595	5689	601	0	0	0	0	0	25	7	3	0	0	0	0	0
समूह ग	302978	54076	24029	84654	6574	293471	3589	1564	6527	2493	4427	1080	263	600	150	82	141	1
समूह घ- सफाई) कर्मचारियों को छोड़कर	73466	20453	5810	20049	428	203	21	3	106	0	32	15	1	321	148	42	73	0
समूह घ- (सफाई कर्मचारियों)	23180	11205	1696	6086	46	0	0	0	0	0	1	0	0	117	58	9	25	0
कुल	909825	178174	73453	253888	13150	308838	5863	2615	11249	3772	30872	5856	2154	1048	357	133	239	1

स्रोत: पीएसबी, पीएसआई, पीएसआईसी एवं विनियामक

अनुबंध IV

30.11.2025 तक दिव्यांग व्यक्तियों का समूहवार प्रतिनिधित्व

कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात् 1.1.2025 से 31.12.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की संख्या (31.12.2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2025 (अर्थात् 1.1.2025 से 31.12.2025 तक) के दौरान की गई नियुक्तियों/पदोन्नतियों की संख्या																			
						सीधी भर्तों द्वारा नियुक्ति										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति									
	आरक्षित रितियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रितियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या									
	कुल	वीएच	एएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एएच	ओएच	आईडी	कुल	वीएच	एएच	ओएच	आईडी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
समूह क	488486	4072	1384	7633	182	987	230	287	225	235	440	136	100	142	62	735	189	200	157	189	374	142	48	164	20
समूह ख	21715	14	2	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	
समूह ग	302978	2934	1035	4340	119	1207	330	336	290	251	395	172	21	176	26	983	324	239	290	130	79	26	5	47	1
स मू ह - घ (स फा ई कर्मचारी को छोड़कर)	73466	148	177	684	8	43	2	2	5	37	34	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
समूह- घ (स फा ई कर्मचारियों सहित)	23180	71	80	367	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	909825	7239	2678	13043	318	2237	562	625	530	523	869	308	123	319	88	1720	513	440	449	319	455	189	54	212	21

टिप्पणी:-

- वीएच का मतलब नेत्रहीन विकलांगता ((अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति है
- एएच का मतलब सुन्ने में अक्षम ((श्रवण अक्षमता से पीड़ित व्यक्ति) है।
- ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (लोकामोटर्स डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)
- आईडी का तात्पर्य बौद्धिक अक्षमता है।

स्रोत: पीएसबी, पीएसआई, पीएसआईसी एवं विनियामक

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मार्च 2026 तक भर्ती का अनुमान

समूह	अनुमान अवधि 01.12.2025 से 31.03.2026 तक												
	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति					पदोन्नति द्वारा नियुक्ति			अन्य तरीकों से नियुक्ति				
	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियों	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियों	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियों	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
समूह-क	10163	1670	936	2853	984	2765	511	306	2	0	1	0	0
समूह-ख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-ग	8141	1362	896	1936	714	6994	770	644	187	53	23	45	0
समूह-घ (सफाई को छोड़कर) कर्मचारी	3	0	3	0	0	10	1	0	41	17	7	10	0
समूह-घ (सफाई) कर्मचारी	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	1	2	0
कुल	18307	3032	1835	4789	1698	9769	1282	950	238	74	32	57	0

स्रोतपीएसबी : पीएफआई, पीएसआईसी एवं विनियामक

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मार्च 2026 तक भर्ती का अनुमान

समूह	अनुमान अवधि 01.12.2025 से 31.03.2026 तक																			
	सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति										पदोन्नति द्वारा नियुक्ति									
	आरक्षित रिक्रियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रिक्रियों की संख्या					की गई नियुक्तियों की संख्या				
	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	पहचान	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	पहचान	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	पहचान	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	पहचान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
समूह-क	366	99	102	83	82	288	77	82	69	60	180	52	45	42	41	50	18	11	20	1
समूह-ख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-ग	316	91	88	71	66	283	85	78	60	60	18	4	4	5	5	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई को छोड़कर) कर्मचारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
समूह-घ (सफाई) कर्मचारी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	682	190	190	154	148	571	162	160	129	120	198	56	49	47	46	50	18	11	20	1
टिप्पणी:-																				
(i) वीएच का तात्पर्य दृष्टिबाधित (अंधेपन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति) से है।																				
(ii) एचएच का तात्पर्य श्रवण विकलांग (श्रवण बाधा से पीड़ित व्यक्ति) से है।																				
(iii) ओएच का तात्पर्य आर्थोपेडिक रूप से विकलांग (लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति) है।																				
(iv) आईडी का तात्पर्य बौद्धिक अक्षमता है।																				
स्रोतपीएसबी : पीएफआई, पीएसआईसी एवं विनियामक																				

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल महत्वपूर्ण टिप्पणियों का सारांश

क्र.सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में लेखापरीक्षण पुनरीक्षा के पश्चात् पीएसी द्वारा एटीएन प्रस्तुत किया गया है	पैरा/पीए रिपोर्ट, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं, का ब्यौरा		
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए एटीएन की संख्या, जिन्हें टिप्पणी के साथ लौटाया गया तथा मंत्रालय द्वारा उन्हें पुनः लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना है	एटीएन की संख्या, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षा की जा चुकी है, परंतु इन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	1.4.2025 से 30.11.2025	10	14 (30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)	12 (30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)	5 (30.11.2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्टों की संख्या, जिनके संबंध में लेखापरीक्षण पुनरीक्षा के पश्चात् पीएसी द्वारा एटीएन प्रस्तुत किया गया है	पैरा/पीए रिपोर्ट, जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं, का ब्यौरा		
			मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजे गए एटीएन की संख्या	भेजे गए एटीएन की संख्या, जिन्हें टिप्पणी के साथ लौटाया गया तथा मंत्रालय द्वारा उन्हें पुनः लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाना है	एटीएन की संख्या, जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षा की जा चुकी है, परंतु इन्हें मंत्रालय द्वारा पीएसी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है
1	2014-15	1	शून्य	शून्य	शून्य
2	2015-16	1	शून्य	2	शून्य
3	2016-17	1	शून्य	1	शून्य
4	2017-18	1	शून्य	4	शून्य
5	2018-19	शून्य	शून्य	3	शून्य
6	2019-20	शून्य	शून्य	8	शून्य
7	2020-21	शून्य	शून्य	3	शून्य
8	2021-22	शून्य	2	शून्य	शून्य
9	2022-23	शून्य	1 (संपूर्ण रिपोर्ट) #	शून्य	शून्य
10	01.01.2023 से 31.03.2024 तक	3*	शून्य	13	4
11	01.04.2024 से 30.11.2024 तक	1	शून्य (30.11.2024 तक)	9 (30.11.2024 तक)	शून्य (30.11.2024 तक)

2022 की रिपोर्ट संख्या 1 (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में तृतीय पक्ष प्रशासकों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट)

* सी एंड एजी के लेखा परीक्षा पैरा 2 और वर्ष 2022 की सम्पूर्ण रिपोर्ट संख्या 1 शामिल है।

अध्याय - VI

लोक उद्यम विभाग (डीपीई)

1. लोक उद्यम सर्वेक्षण

लोक उद्यम विभाग केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के कार्य-निष्पादन पर लोक उद्यम (पीई) सर्वेक्षण प्रकाशित करता है, जिसे प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पीई सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 दिसम्बर, 2025 में संसद के दोनों सदनों में रखी गई।

पीई सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में 475 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इन 475 सीपीएसई में से 291 प्रचालनरत हैं, जिनमें से 226 सीपीएसई ने 2024-25 के दौरान लाभ दिखाया है। प्रचालनरत सीपीएसई का समग्र 'निवल लाभ' 2024-25 में 2.91 लाख करोड़ रुपये था। 2023-24 में सीपीएसई द्वारा केंद्रीय राजकोष में योगदान 4.84 लाख करोड़ रुपये था जो कि 2024-25 में बढ़कर 4.94 लाख करोड़ रुपये हो गया।

पिछले वर्ष अर्थात् 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 के दौरान सीपीएसई के कार्य-निष्पादन की तुलना अनुलग्नक-2 में दी गई है।

2. सीपीएसई का संगठन और स्वायत्तता

सरकार का प्रयास केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को स्वायत्त शासी बोर्ड प्रबंधित कंपनियां बनाना है। संस्था के अंतर्नियम के तहत, सीपीएसई के निदेशक मंडल को बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में स्वायत्तता प्राप्त है। सीपीएसई का निदेशक मंडल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए व्यापक नीतिगत दिशा-निर्देशों के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है।

2.1 सीपीएसई के बोर्ड्स की संरचना:

सीपीएसई के निदेशक मंडल (बोर्ड) में अनिवार्य रूप से तीन प्रकार के निदेशक होते हैं, अर्थात् सरकारी निदेशक, कार्यात्मक निदेशक और स्वतंत्र (गैर-सरकारी) निदेशक। बोर्ड की अध्यक्षता एक अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा की जाती है। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए और सरकार द्वारा नामित निदेशकों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी। कार्यकारी अध्यक्ष वाले सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, गैर-आधिकारिक निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल संख्या का कम से कम 50% होगी। गैर-कार्यकारी अध्यक्ष वाले गैर-सूचीबद्ध और सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में, बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी निदेशक होंगे।

2.1.1 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक:

सीपीएसई के बोर्ड में सीएमडी की नियुक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने और इस संबंध में यथोचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

2.1.2 सरकारी निदेशक:

सरकारी निदेशक आम तौर पर भारत सरकार, राज्य सरकारों या अन्य सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जिन्हें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा पदेन क्षमता में सीपीएसई के बोर्डों में नामित किया जाता है। एक सरकारी निदेशक की दोहरी भूमिका यानी कंपनी के निदेशक और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में स्पष्ट रूप से निर्धारित है। कंपनी के निदेशक के रूप में, वे कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यथोचित परिश्रम करने और कंपनी के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। चूंकि सरकार सीपीएसई में प्रमुख शेयरधारक होती है, इस नाते उन्हें उनके हितों की रक्षा करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा करने में, वे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार से औपचारिक निर्देश ले सकते हैं और कंपनी के बोर्ड की बैठकों में अपनी राय दे सकते हैं। उन्हें कंपनी द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन को समय पर फीडबैक देना होता है।

सरकार के लिए मूल रूप से वित्तीय और अन्य परिणामों वाले मामलों के संबंध में (क) एक शेयरधारक के रूप में और (ख) बोर्ड की बैठकों में उत्पन्न होने वाली सरकार की नीतियों के संबंध में, सरकारी निदेशक से अपेक्षा की जाती है कि वे संबंधित मंत्रालय तक इसे पहुंचाएं और औपचारिक रूप से मंत्रालय का एक दृष्टिकोण तैयार करने और निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत करने के लिए उनकी सलाह लें। सरकारी निदेशक को संबंधित सरकारी दिशानिर्देशों (डीपीई दिशानिर्देशों सहित) और उसके अनुपालन के बारे में बोर्ड को नियमित रूप से जागरूक बनाना चाहिए।

यदि सीपीएसई का बोर्ड सरकार की नीति के विपरीत निर्णय लेता है, तो सरकारी निदेशक को सरकार की ओर से पक्ष रखना चाहिए और बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त में अपनी अस्वीकृति या असहमति दर्ज करनी चाहिए और मंत्रालय/विभाग को इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। सरकारी निदेशक को बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिन पर उनके विचार में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है और जब कंपनी में अपेक्षानुरूप घटनाक्रम नहीं हो रहे हों तो अलर्ट जारी करना होता है।

2.1.3 कार्यात्मक निदेशक:

कार्यात्मक निदेशक सीपीएसई के संबंधित कार्यात्मक क्षेत्रों के कार्यकारी प्रमुख होते हैं और वे उनको नियत संबंधित क्षेत्रों जैसे प्रचालन, वित्त, विपणन, मानव संसाधन आदि में अपनी कार्यकारी भूमिका निभाते

हैं। सीपीएसई के निदेशक मंडल में कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशों के आधार पर और इस संबंध में समुचित औपचारिकताएं पूरी करने और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन प्राप्त के पश्चात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। पीईएसबी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में है। पीईएसबी विज्ञापन जारी करता है, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करता है और कार्यात्मक निदेशकों के पदों पर चयन के लिए चयन साक्षात्कार आयोजित करता है। कार्यात्मक निदेशकों को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति, जो भी पहले हो, तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

2.1.4 गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः -

सीपीएसई के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की उपस्थिति अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्यमों के सुचारु, पारदर्शी और जवाबदेह कार्यकाज के लिए उनका रचनात्मक योगदान आवश्यक है। आईडी बोर्ड समितियों जैसे ऑडिट समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीपीएसई के निदेशक मंडलों में आईडी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा शुरू किए जाते हैं, जो अपने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को नामों का एक पैलन प्रस्तुत करता है। डीपीई इन प्रस्तावों को सर्च समिति के समक्ष रखता है, जिसमें वर्तमान में सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अध्यक्ष के रूप में, सचिव (डीपीई), संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव और दो गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, सर्च समिति की सिफारिशों के आधार पर आईडी की नियुक्ति करता है। आईडी तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं। आईडी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पात्रता के लिए योग्यता मानक अनुलग्नक-3 में प्रदान किए गए हैं।

2.2 महारत्न योजना

महारत्न योजना जोकि 2010 में शुरू की गई का मुख्य उद्देश्य मेगा सीपीएसई को अपने प्रचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गज कंपनी के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाना है। ऐसे सीपीएसई के निदेशक मंडल को (i) पूंजीगत व्यय, (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, (iii) विलय और अधिग्रहण, (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में संवर्द्धित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। 14 महारत्न सीपीएसई हैं।

2.3 नवरत्न योजना

सरकार ने 1997 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की पहचान करने और वैश्विक दिग्गज कंपनी बनने के उनके अभियान में उनका समर्थन करने के लिए नवरत्न योजना शुरू की। इस स्कीम के अंतर्गत, नवरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडलों को (i) पूंजीगत व्यय, (ii) संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, (iii) विलय और अधिग्रहण, (iv) मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्रों में स्वायत्तता बढ़ाने वाली शक्तियां भी

प्रत्यायोजित की गई हैं। तीन सीपीएसई, नामतः इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी लिमिटेड), इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी लिमिटेड) और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड(एनआरएल) को 2025 को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इन तीन सीपीएसई को नवरत्न के रूप में शामिल करने के साथ, 27 नवरत्न सीपीएसई हैं।

2.4 मिनीरत्न योजना

अक्तूबर, 1997 में सरकार ने कुछ अन्य लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुछ पात्रता शर्तों और दिशानिर्देशों के अध्यक्षीन संवर्द्धित स्वायत्तता प्रदान करने और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का निर्णय लिया। मिनीरत्न कंपनियां दो श्रेणियों नामतः श्रेणी-I और श्रेणी-II में बांटा गया है। 54 मिनीरत्न-I और 10 मिनीरत्न-II श्रेणी के सीपीएसई हैं।

2.5 महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न योजना की मुख्य विशेषताएं और इन सीपीएसई की सूची क्रमशः अनुलग्नक-4 और अनुलग्नक-5 में दी गई है।

3. मजदूरी नीति और जनशक्ति का युक्तिकरण

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) बोर्ड स्तर के साथ-साथ बोर्ड स्तर से नीचे के सीपीएसई कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित नीति के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। डीपीई केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में कर्मकारों के मामले में वेतन निपटान संबंधी वार्ताओं के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करता है। यह विभाग प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई को कार्यपालकों के वेतनमानों में संशोधन और कर्मकारों की वेतन नीति संबंधी वार्ताओं के मामलों में सलाह देता है।

सीपीएसई काफी हद तक वेतनमान के औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) पैटर्न का पालन कर रहे हैं। तथापि, कुछ सीपीएसई में, केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमानों के पैटर्न का भी पालन किया जाता है। डीपीई आईडीए कर्मचारियों के संबंध में तिमाही महंगाई भत्ता (डीए) आदेश जारी करता है। सीपीएसई के सीडीए कर्मचारियों के लिए डीए आदेश छह माह की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं।

3.1 सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधनः

3.1.1 सीपीएसई में आईडीए पैटर्न के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए वेतन संशोधनः

(i) न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में तीसरी वेतन संशोधन समिति (पीआरसी) का गठन वेतनमान के आईडीए पैटर्न के तहत सीपीएसई के बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए वेतनमान पर विचार करने और सिफारिश करने के लिए किया गया था। तीसरे पीआरसी की सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों के आधार पर दिनांक 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी संशोधित वेतनमान दिशानिर्देश दिनांक 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापनों द्वारा जारी किए गए थे।

(ii) तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित संशोधित वेतनमान और भत्ते वहनीयता के मूल आधार पर आधारित थे। इन वेतनमानों और भत्तों को इस शर्त के अधीन कार्यान्वित किया जाएगा कि बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के लिए संशोधित वेतन पैकेज को कार्यान्वित करने के वर्ष में अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव कार्यान्वयन के वर्ष से पूर्व पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कर-पूर्व औसत लाभ (पीबीटी) के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस संबंध में सभी व्यय को संशोधित वेतनमान और भत्ते को लागू करने वाले सीपीएसई द्वारा वहन किया जाएगा और सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

3.1.2 सीपीएसई में सीडीए पैटर्न के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन:

सीडीए पैटर्न का पालन करते हुए सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए, डीपीई ने दिनांक 17.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिनांक 01.01.2016 से वेतनमान और भत्तों के संशोधन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वेतन संशोधन का लाभ उन सीपीएसई के कर्मचारियों को दिया जाता है जो घाटे में नहीं चल रहे हैं और सरकार से किसी भी बजटीय सहायता के बिना अपने स्वयं के संसाधनों से वेतन संशोधन के कारण होने वाले व्यय को अवशोषित करने की स्थिति में हैं। इसके अलावा, डीपीई ने दिनांक 21.05.2018 और 04.07.2019 के कार्यालय ज्ञापनों द्वारा सीपीएसई के सीडीए कर्मचारियों पर लागू भत्तों पर सरकार के निर्णय से अवगत कराया।

3.1.3 सीपीएसई में आईडीए पैटर्न के तहत कामगारों के लिए वेतन संशोधन:

डीपीई ने दिनांक 24.11.2017 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सीपीएसई के संघीकृत कार्यगारों के साथ वेतन वार्ता के 8वें दौर (01.01.2017 से प्रभावी) के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिनांक 24.11.2017 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 (xi) के अनुसार वेतन वार्ता की वैधता न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि की होगी और यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पांच वर्ष की आवश्यकता का विकल्प चुना है और उन लोगों के लिए जिन्होंने दिनांक 01.01.2017 से वेतन वार्ता की दस वर्ष की आवश्यकता का विकल्प चुना है, के लिए, अधिकतम दस वर्ष की अवधि होगी।

3.2 हाल ही में जारी किए गए दिशानिर्देश:

3.2.1 डीपीई ने दिनांक 06.02.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0030/2024-डीपीई (डब्ल्यूसी)/एफटीएस-14110 के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़ने वाले सीपीएसई अधिकारियों के लिए डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.12.2012 और 17.09.2019 में निहित वेतन निर्धारण सिद्धांतों की प्रयोज्यता को स्पष्ट किया है। इसके अलावा, डीपीई ने दिनांक 15.09.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0021/2020-डीपीई (डब्ल्यूसी)/एफटीएस-11378 के माध्यम से रक्षा सेवाओं में शामिल होने वाले अधिकारियों के लिए रक्षा सेवाओं पर लागू 'परिलब्धियों' की परिभाषा का विस्तार किया है।

3.2.2 डीपीई ने दिनांक 15.09.2025 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(23)/11-डीपीई (डब्ल्यूसी)/एफटीएस-1128 के माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में स्टाफ कारों की खरीद, उपयोग और पात्रता पर संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

3.2.3 सीपीएसई के लिए सतर्कता नीति के संबंध में समेकित और संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 28.10.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(2)/2001-डीपीई (जीएम) के माध्यम से जारी किए गए हैं।

4. सीपीएसई का वर्गीकरण

4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को चार अनुसूचियों अर्थात् 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' में वर्गीकृत किया गया है। सीपीएसई के वर्गीकरण के निहितार्थ मुख्य रूप से संबंधित सीपीएसई के बोर्ड स्तर के पदाधिकारियों की संगठनात्मक संरचना और वेतन से हैं। यह 'रत्न' योजना के तहत सीपीएसई के बोर्डस् को स्वायत्तता प्रदान करने में भी भूमिका निभाता है।

4.2 साठ के दशक के मध्य में सीपीएसई का प्रारंभिक वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में उनके महत्व और उनकी समस्याओं की जटिलताओं के आधार पर किया गया था। विगत वर्षों में लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसई के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ मानदण्ड विकसित किए हैं। वर्गीकरण मात्रात्मक कारकों जैसे निवेश, नियोजित पूंजी, निवल बिक्री, कर पूर्व लाभ, कर्मचारियों और इकाइयों की संख्या, क्षमता अभिवृद्धि, प्रति कर्मचारी राजस्व, नियोजित बिक्री / पूंजी, क्षमता उपयोग, प्रति कर्मचारी मूल्य संवर्धन और गुणात्मक कारकों जैसे राष्ट्रीय महत्व, कंपनी द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जटिलताएं, प्रौद्योगिकी का स्तर, गतिविधियों के विस्तार और विविधीकरण की संभावनाएं और अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा आदि दोनों पर आधारित है। अन्य कारक, जहां भी उपलब्ध हैं, शेयर मूल्य, समझौता ज्ञापन रेटिंग, महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न स्थिति और आईएसओ प्रमाणन से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीएसई के महत्वपूर्ण/रणनीतिक महत्व से संबंधित कारक को भी ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में 77 अनुसूची 'क', 64 अनुसूची 'ख', 46 अनुसूची 'ग' और 6 अनुसूची 'घ' सीपीएसई हैं। सीपीएसई की अनुसूची-वार सूची अनुलग्नक-6 में दी गई है।

4.3 वर्गीकरण की प्रक्रिया:

सीपीएसई के वर्गीकरण का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा शुरू किया जाता है और लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किया जाता है। लोक उद्यम विभाग ऐसे प्रस्तावों की जांच करता है और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आदेश जारी करता है। इसके अलावा, सीपीएसई को प्रारंभिक वर्गीकरण प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए, डीपीई ने दिनांक 11.12.2023 को दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार विनिवेश के अधीन सीपीएसई की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए सृजित सभी परिसंपत्ति धारक सीपीएसई और वे सीपीएसई जिन्हें अभी तक कार्यात्मक नहीं बनाया गया है, उन्हें कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुसूची 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। पश्चात्, दिनांक 20.05.2024 और दिनांक 08.08.2024 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से

वर्गीकरण की प्रक्रिया को और ज्यादा सरलीकृत किया गया। डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.05.2024 से सीपीएसई के मौजूदा वर्गीकरण के उन्नयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और उसमें स्पष्ट किया गया कि शुरू में वर्गीकृत सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की मंजूरी से अपने अनुसूची के उन्नयन के लिए डीपीई के पास आते रहेंगे। लोक उद्यम विभाग ऐसे प्रस्तावों की जांच करता है और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आदेश जारी करता है। ऐसे प्रस्तावों को पीईएसबी और मंत्रिमंडल सचिवालय को नहीं भेजा जाएगा। डीपीई कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.08.2024 से मौजूदा अर्गीकृत कार्यात्मक सीपीएसई के प्रारंभिक वर्गीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया और स्पष्ट किया गया कि सभी प्रारंभिक रूप से वर्गीकृत सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन से अपनी अनुसूची के उन्नयन के लिए डीपीई के पास आते रहेंगे। डीपीई ऐसे प्रस्तावों की जांच करता है और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आदेश जारी करता है। ऐसे प्रस्तावों को पीईएसबी और मंत्रिमंडल सचिवालय को नहीं भेजा जाएगा।

5. निगरानी और मूल्यांकन

5.1 समझौता ज्ञापन:

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच परस्पर वार्ता के पश्चात् तैयार किया गया हस्ताक्षरित समझौता है। इसके तहत, सीपीएसई समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का बीड़ा उठाता है। समझौता ज्ञापन मूल्यांकन में, सीपीएसई के कार्य-निष्पादन की तुलना पूर्व निर्धारित मापदंडों पर निर्धारित लक्ष्यों के साथ की जाती है। समझौता ज्ञापन उद्यम के प्रबंधन की सरकार के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।

5.1.1 दायरा:

सभी सीपीएसई (धारक के साथ-साथ सहायक कंपनियां) को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। धारक सीपीएसई अपने प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, जबकि सहायक कंपनियां अपनी संबंधित धारक कंपनियों के साथ इस पर हस्ताक्षर करती हैं।

5.1.2 समझौता ज्ञापन नीति के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था:

(क) **उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी):** उच्चाधिकार प्राप्त समिति नीति दिशानिर्देश तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन तंत्र का शीर्ष निकाय है। एचपीसी की अध्यक्षता (i) कैबिनेट सचिव करते हैं और इनमें: (ii) सीईओ (नीति आयोग), (iii) वित्त सचिव, (iv) सचिव (व्यय), (v) सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन), (vi) अध्यक्ष (लोक उद्यम चयन बोर्ड), (vii) मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक कार्य) और (viii) सचिव (लोक उद्यम) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

(ख) **अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी):** आईएमसी क्षेत्रीय

टेम्पलेट्स और सीपीएसई-वार समझौता ज्ञापन पैरामीटरों को अंतिम रूप देती है। क्षेत्रीय टेम्पलेट्स का उद्देश्य किसी क्षेत्र और/अथवा सीपीएसई से संबंधित मुख्य व्यवसाय गतिविधियों से संबंधित पैरामीटरों और उनके महत्व का चयन करना और उनकी पहचान करना है। अंतर-मंत्रालयी समिति बेंचमार्क लक्ष्यों के रूप में इस प्रकार निर्धारित प्रत्येक मापदंड के लिए निष्पादन के अपेक्षित स्तर भी निर्धारित करती है। आईएमसी में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सचिव (लोक उद्यम) अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि के रूप में (ii) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, (iii) व्यय विभाग और (iv) सदस्यों के रूप में मुख्य आर्थिक सलाहकार (आर्थिक कार्य) और (v) प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव/प्रतिनिधि और (vi) विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संबंधित सीपीएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और आवश्यकता के आधार पर सहयोजित कोई अन्य विशेषज्ञ।

5.1.3 समझौता ज्ञापन ढांचा (वर्ष 2021-22 और उसके आगे के वर्षों के लिए):

एचपीसी की सिफारिशों के आधार पर, सीपीएसई के लक्ष्य निर्धारण और कार्य-निष्पादन मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड का उपयोग करके एमओयू तंत्र के लिए रूपरेखा तैयार की गई है और वर्ष 2021-22 से लागू की गई है। संशोधित एमओयू तंत्र में शामिल मापदंड बाजार उन्मुख हैं, जो राजस्व में वृद्धि, ईबीआईटीडीए मार्जिन, निवल मूल्य पर आय, नियोजित पूंजी पर आय, परिसंपत्ति कारोबार अनुपात और बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में शेरधारकों की रुचि को दर्शाते हैं। सीपीएसई के मुख्य प्रचालनों से संबंधित उत्पादन से जुड़े मापदंडों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। सभी मापदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध दस्तावेजों से मात्रात्मक और सत्यापन योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ सरकारी प्राथमिकताओं/कार्यक्रमों जैसे एमएसई, सीएसआर से अधिप्राप्ति, आदि को भी सीपीएसई द्वारा अनुपालन के लिए शामिल किया गया है, जिसका अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप अंकों की कटौती होगी।

संशोधित समझौता ज्ञापन ढांचे में क्षेत्र के विकास और उभरते रुझानों, इस क्षेत्र के बारे में मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विज्ञान और प्रतिस्पर्धी कंपनी के निष्पादन के आधार पर बेंचमार्किंग भी प्रदान करता है।

5.1.4 एमओयू स्कोर और रेटिंग: सीपीएसई को प्रत्येक मापदंड के लिए लक्ष्य आंकड़े की उपलब्धि के लिए आनुपातिक रूप से अंक आवंटित किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन स्कोर पर पहुंचने के लिए सभी मापदंडों पर स्कोर जोड़ा जाएगा। एमओयू स्कोर के आधार पर सीपीएसई की रेटिंग प्रणाली इस प्रकार है:

संचयी अंक	रेटिंग
90 ≤ स्कोर	उत्कृष्ट
70 < स्कोर < 90	बहुत अच्छा
50 < स्कोर < 70	अच्छा
33 < स्कोर < 50	औसत
स्कोर < 33	खराब

6. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

6.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित लाभ अर्जित करने वाले सभी कारपोरेट जो 500 करोड़ रुपए निवल मूल्य; या 1000 करोड़ रुपए के कारोबार या 5 करोड़ रुपए के निवल लाभ के संदर्भ में नियम में निर्धारित नियत सीमा से अधिक हों, को पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए कम्पनी के औसत निवल लाभ (कर-पूर्व लाभ) का न्यूनतम 2% खर्च करना अधिदेशित हुआ है।

6.2 सीपीएसई से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निहित उपबंधों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा इसके अधीन अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति) नियमावली, 2014 एवं अधिनियम की अनुसूची-VII, जिनमें ऐसी गतिविधियां सूचीबद्ध हैं, जो सीएसआर के तहत की जा सकती हैं, का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

6.3 अप्रैल, 2018 में आयोजित सीपीएसई कॉन्क्लेव की सिफारिशों के आधार पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर प्रत्येक वर्ष एक विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई को दिनांक 10.12.2018 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान किया गया है कि ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60 प्रतिशत होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा पहचाने गये आकांक्षी जिलों को वरीयता दी जाए।

6.4 वित्त वर्ष 2025-26 (आदिनांक) के दौरान, डीपीई द्वारा निम्नलिखित सीएसआर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

- i. डीपीई और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से 31 जुलाई, 2025 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पर 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को उपरोक्त राज्यों के आकांक्षी जिलों (एडी) के 100 से अधिक प्रतिभागियों, सीपीएसई के सीएसआर नोडल अधिकारियों, राज्य सरकारों, नीति आयोग, कार्यान्वयन एजेंसियों, डीपीई और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ सभी हितधारकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
- ii. डीपीई और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से 19 सितंबर, 2025 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीएसआर पर 6वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला को पूर्वोत्तर राज्यों के आकांक्षी जिलों (एडी) के 100 से अधिक प्रतिभागियों, सीपीएसई के सीएसआर नोडल अधिकारियों, राज्य सरकारों के अधिकारियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, डीपीई और यूनिसेफ के अधिकारियों के साथ सभी हितधारकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

7. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनः स्थापना योजना (आरडीसीआर)

7.1.1 कार्यान्वयन को बढ़ाने और उपरिलागतों को घटाने के लिए योजनाओं को सुव्यवस्थित करने पर सरकार के फोकस के अनुरूप, प्रशिक्षण-उन्मुख दोनों योजनाओं (पृथक हुए कर्मचारियों के लिए सीआरआर और वर्तमान कर्मचारियों के लिए आरडीसी) का विलय कर दिया गया है। विलय की गई योजना, अनुसंधान, विकास, परामर्श और पुनर्विन्यास (आरडीसीआर), यह सुनिश्चित करती है कि सीआरआर और आरडीसी दोनों योजनाओं के उद्देश्यों को पूरा किया जाना जारी रहे और यह वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही से प्रभावी होगा।

7.1.2 आरडीसीआर योजना के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- क. **विषयगत अध्ययन:** तेजी से बदलते आर्थिक माहौल में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य/क्षेत्रीय मुद्दों पर अध्ययन करना।
- ख. **सम्मेलन और सेमिनार:** सहयोगात्मक शिक्षण और सर्वोत्तम प्रथा साझा करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, वेबिनार और अध्ययन पर्यटन का संचालन करना।
- ग. **क्षमता निर्माण:** सीपीएसई के निदेशक मंडल (बीओडी) के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम की पेशकश करना।
- घ. **निष्पादन में सुधार:** अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से सीपीएसई के लिए निष्पादन मूल्यांकन और प्रबंधन सुधार की सुविधा प्रदान करना।
- ङ. **सहयोग:** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की क्षमता निर्माण और निष्पादन में सुधार हेतु प्रयासरत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन करना।
- च. **प्रोत्साहन:** अनुदान और प्रोत्साहन राशि के माध्यम से कार्यात्मक क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए सीपीएसई को पुरस्कृत करना।
- छ. **पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण:** स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार की सुविधा के लिए वीआरएस विकल्प चुनने वालों या उनके आश्रितों के लिए कौशल वृद्धि और पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ज. **अन्य मुद्दे:** लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और सीपीएसई/एसएलपीई से संबंधित किसी भी अन्य प्रासंगिक मुद्दों का निवारण करना।

7.1.3 आरडीसीआर योजना के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. **विषयगत परामर्श और अध्ययन:** सीपीएसई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, मानव संसाधन, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, बेंचमार्किंग अध्ययन जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना। निष्पादन प्रबंधन, मुआवजा तथा मूल्यांकन प्रणाली और सीपीएसई से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी अध्ययन किया जा सकता है।

- ख. **सम्मेलन, सेमिनार और अध्ययन यात्राएं:** ज्ञान साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यशालाओं, उद्योग दौरों तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों के माध्यम से सहयोगात्मक शिक्षण के लिए विशेषज्ञ की सेवाएं ली जाएंगी।
- ग. **कौशल विकास और प्रशिक्षण:** सतत कौशल विकास कार्यक्रमों से समस्त सीपीएसई और एसएलपीई में कर्मचारी उत्पादकता को बढ़ाया जाएगा। प्रशिक्षण आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों से लोक उद्यम विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।
- घ. **निदेशक मंडल के लिए प्रेरण और क्षमता निर्माण:** सीपीएसई के निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए अल्पकालिक अभिविन्यास कार्यक्रम और जिसमें जोखिम प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, और नेतृत्व विकास, पदारोहण आयोजना, अनुपालन आदि जैसे विषयों को शामिल किया जाएगा ताकि बोर्ड विचार-विमर्श को बढ़ाया जा सके।
- ङ. **बहुपक्षीय निकायों को समर्थन:** डीपीई इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइजेज (आईसीपीई) जैसे संगठनों का समर्थन करना जारी रखेगा और सदस्यता अंशदान को शामिल करेगा।
- च. **वीआरएस/वीएसएस विकल्प चुनने वालों के लिए पुनः अभिमुखीकरण:** प्रशिक्षण और संबंधित लागतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो वीआरएस पैकेज का हिस्सा होगी।
- छ. **सीपीएसई और एसएलपीई को प्रोत्साहन/पुरस्कार:** सीपीएसई और एसएलपीई को भावी विकास के लिए नवाचार करने और महत्वपूर्ण सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में उत्कृष्ट निष्पादन करने वालों को पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें डीपीई मानदंड निर्धारित करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो विशेषज्ञ सहायता मांगेगा।
- ज. **आउटसोर्स की गई जनशक्ति सहायता और सॉफ्टवेयर विकास का भुगतान:** आरडीसीआर योजना का दायरा व्यापक होने और डीपीई में सीमित आंतरिक जनशक्ति होने के कारण, आउटसोर्स कर्मियों को कार्य पर रखा जाएगा और योजना से भुगतान किया जाएगा।

7.2.1 वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, डीपीई ने अब तक देश के प्रमुख संस्थानों आईआईएम, आईआईटी, एनपीसी, आईआईसीए, एनआईएसएम आदि के माध्यम से आवासीय मोड में आरडीसीआर योजना के तहत 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इन कार्यक्रमों के विषय कुल 493 प्रतिभागियों के साथ सृजनकारी एआई, सार्वजनिक खरीद, वित्त प्रबंधन, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, तनाव प्रबंधन, संगठनात्मक व्यवहार और नेतृत्व पर केंद्रित थे।

7.2.2 वर्ष 2025-26 के दौरान सीपीएसई के निदेशक मंडल के लिए 4 ओरिएंटेशन कार्यक्रम (सरकार के लिए 1, कार्यात्मक निदेशकों के लिए 2

और सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के लिए 1) भी निम्नलिखित विवरण के अनुसार आयोजित किए गए हैं:

- i. डीपीई ने ओएनजीसी लिमिटेड के सहयोग से देहरादून में 2 और 3 जून, 2025 को सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए एक गैर-आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसई के बोर्डों में नामित 31 स्वतंत्र निदेशकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें बोर्ड रूम एथिक्स, ऑडिट कमेटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वित्तीय विवरण और बोर्ड की बैठकों के लिए सचिवीय मानकों और शासन प्रक्रिया से संबंधित सत्र आयोजित किए गए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान भारत में सीपीएसई की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रस्तुति भी दी गई।
- ii. डीपीई ने एसजेवीएन लिमिटेड के सहयोग से धर्मशाला में 10-11 जुलाई, 2025 को सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न सीपीएसई के 22 कार्यात्मक निदेशकों ने भाग लिया, जिसमें बोर्ड की प्रभावशीलता और कार्यात्मक निदेशकों की भूमिका, सीपीएसई में मध्यस्थता, रणनीतिक प्रबंधन, परिवर्तनकारी बोर्ड नेतृत्व, लेखा परीक्षा कार्यों की प्रभावशीलता और एकीकृत शासन और जोखिम निरीक्षण से संबंधित सत्रों में डीपीई के महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों पर एक प्रस्तुति भी शामिल थी।
- iii. डीपीई ने बीईएलओपी लिमिटेड के सहयोग से 3 और 4 सितंबर, 2025 को औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सीपीएसई के सरकार द्वारा नामित निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। विभिन्न सीपीएसई के 12 सरकारी निदेशकों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें सरकारी निदेशकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, बोर्ड रूम को नेविगेट करना, शासन की अपेक्षाएं, कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन, व्यापार और टैरिफ, सचिवीय मानक, वित्तीय विवरण, वित्तीय भूमिकाएं और जिम्मेदारियां से संबंधित सत्र आयोजित किए गए। ओरिएंटेशन कार्यक्रम के दौरान डीपीई के ऑनलाइन पोर्टल (एमएमआरसीडी, सीएसआर, एमओयू, स्पैरो, सर्वे, बीओडी) पर भी प्रस्तुति दी गई।
- iv. डीपीई ने नाल्को लिमिटेड के सहयोग से 19 और 20 सितंबर, 2025 को पुरी में सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए आवासीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न सीपीएसई के 28 कार्यात्मक निदेशकों ने भाग लिया, जिसमें निदेशकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, वित्तीय विवरणों को समझने, परिवर्तनकारी बोर्ड नेतृत्व, आधुनिक बोर्ड शासन के सिद्धांतों, सीपीएसई में मध्यस्थता, रणनीतिक प्रबंधन से संबंधित सत्रों के साथ-साथ महत्वपूर्ण डीपीई दिशानिर्देशों पर एक प्रस्तुति भी आयोजित की गई।

7.2.3 वर्ष 2023-24 के लिए योजनावार व्यय का विवरण अनुलग्नक-7 में संलग्न है।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) की नई नीति का कार्यान्वयन

8.1 सरकार ने 4 फरवरी, 2021 को नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को अधिसूचित किया। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति में सीपीएसई के रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकरण की परिकल्पना की गई है और कुछ सीपीएसई जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गैर-लाभकारी कंपनियों के लिए स्थापित किए गए हैं या रुग्ण समूहों को सहायता प्रदान करने वाले या विकासात्मक/प्रचार भूमिकाओं आदि को नीति के दायरे से छूट दी गई है। नीति में प्रस्ताव है कि रणनीतिक क्षेत्र में, धारक कंपनी स्तर पर मौजूदा सीपीएसई की न्यूनतम उपस्थिति को सरकार के नियंत्रण में रखा जाएगा। सामरिक क्षेत्र के शेष उद्यमों के निजीकरण या विलय या किसी अन्य सीपीएसई के साथ सब्सिडी या बंद करने पर विचार किया जाएगा। गैर-रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई को निजीकरण के लिए विचार किया जाएगा, जहां संभव हो, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा।

8.2 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को मंत्रिमंडल सचिवालय की 6 जुलाई 2021 की अधिसूचना के माध्यम से वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया है। वित्त सचिव के 17 अगस्त 2021 के आदेश के माध्यम से, दीपम और डीपीई के बीच कुछ जिम्मेदारियों का सीमांकन किया गया है। डीपीई को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से गैर-रणनीतिक क्षेत्र में बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीपीई को बंद करने के लिए अनुमोदित सीपीएसई के लिए बंद करने की प्रक्रिया को चलाने की भी आवश्यकता है। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग में एक विनिवेश प्रभाग सृजित किया गया है।

8.3 गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति को लागू करने और बंद करने के लिए पहचाने गए सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया को चलाने के लिए, डीपीई ने व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, दीपम और नीति आयोग के परामर्श से दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ये दिशानिर्देश 13.12.2021 को जारी किए गए हैं और अनुलग्नक-8 में दिए गए हैं।

8.4 दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- गैर-रणनीतिक क्षेत्र में बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से की जाएगी। इस संबंध में, अधिकारियों के समूह (सीजीओ) की समिति का गठन किया गया है;
- गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में बंद करने और/या विनिवेश के लिए पहचाने गए सीपीएसई के संबंध में सीसीईए के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन की मांग करना;
- सीसीईए द्वारा विनिवेश के लिए अनुमोदित सीपीएसई के विवरण दीपम को इसकी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा। जबकि, डीपीई बंद करने के लिए अनुमोदित सीपीएसई के लिए प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा;
- बंद किए जा रहे सीपीएसई की पट्टे-पर ली गई भूमि का संबंधित राज्य सरकारों को अंतरण। फ्रीहोल्ड भूमि को राष्ट्रीय भूमि

मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को हस्तांतरित किया जाएगा, जो उनके निपटान के लिए स्थापित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है। बंद किए जा रहे सीपीएसई से भूमि के हस्तांतरण से बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)

9.1 कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सरकार ने अक्टूबर, 1988 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की घोषणा की थी। बाद में लोक उद्यम विभाग द्वारा मई, 2000 में एक विस्तृत योजना अधिसूचित की गई थी।

9.2 सीपीएसई, जो स्वयं अपने स्तर पर योजना का समर्थन कर सकते हैं, में वीआरएस वित्तीय रूप से सक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का व्यय स्वयं वहन कर सकते हैं, वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अपनी योजना स्वयं बना सकते हैं और इसका विकल्प लेने वाले कर्मचारियों के लिए इसे काफी आकर्षक बना सकते हैं। वे सेवा के पूरे हुए प्रत्येक वर्ष के लिए 60 दिन के वेतन (केवल मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के तुल्य क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। हालांकि, ऐसी क्षतिपूर्ति सेवा की शेष अवधि के वेतन से अधिक नहीं होगी।

9.3 मामूली लाभ अर्जित करने वाले अथवा घाटा उठाने वाले / रुग्ण / अलाभकारी सीपीएसई में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना मामूली रूप से लाभ अर्जित करने वाली / घाटा उठाने वाली साथ ही रुग्ण एवं अलाभकारी इकाइयां निम्नलिखित मॉडल में से किसी एक को अपना सकती हैं:

9.3 (i) गुजरात मॉडल जिसके अंतर्गत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 35 दिन का वेतन तथा सेवानिवृत्ति होने तक सेवा की शेष अवधि के प्रत्येक वर्ष के 25 दिनों के वेतन की प्रतिपूर्ति का आकलन किया जाता है, बशर्ते कि क्षतिपूर्ति, अधिवर्षिता का शेष बची अवधि के लिए कुल वेतन से अधिक नहीं होगी।

9.3 (ii) भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) मॉडल, जिसके अनुसार पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 45 दिनों के परिलाभों (वेतन + महंगाई भत्ता) अथवा सेवा की शेष अवधि के कुल परिलाभ, इनमें से जो भी कम हो, अनुग्रह राशि प्राप्त कर सकते हैं। जो कर्मचारी कम से कम 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 60 (साठ) माह का वेतन / मजदूरी प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे और बशर्ते यह शेष बची हुई सेवा अवधि के लिए वेतन / मजदूरी की राशि से अधिक न हो।

10. कार्यकारी विकास कार्यक्रम

10.1 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (ईसएपीसी) स्वयं के मानव संसाधन विकास कार्यक्रम तैयार करते हैं जिसके अंतर्गत वे मध्यम एवं वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों को स्वयं के प्रबंधन संस्थानों द्वारा या भारत के प्रमुख प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थानों की सेवाएं आउटसोर्स द्वारा प्राप्त करके, प्रबंधन विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास तथा उनके ज्ञान में वृद्धि करते हैं।

10.2 सचिव, लोक उद्यम विभाग, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजिस (स्कोप) नई दिल्ली के कार्यकारी बोर्ड और शासी परिषद के पदेन सदस्य हैं।

10.3 सचिव, लोक उद्यम विभाग, लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं।

11. रोजगार में आरक्षण

11.1 सीपीएसई में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्यो के लिए आरक्षण

i. बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक एवं भर्ती नीतियों को संबंधित सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि, सामान्य महत्व के मामलों में, भारत सरकार द्वारा उन उद्यमों को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं जिससे वे अपने स्वयं की कारपोरेट नीतियां तैयार करने में सक्षम बन सकें। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राष्ट्रपति के औपचारिक निर्देश संबंधित सीपीएसई को जारी किए जाते हैं ताकि वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु नियोजन के संबंध में आरक्षण उसी तर्ज पर करें जैसा कि केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों में लागू है। डीपीई ने दिनांक 25.02.2015 के अपने कार्यालय ज्ञापन के जरिए यह निर्धारित किया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निशक्त:जन तथा पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों को यथोचित परिवर्तन सहित सभी संबंधित सीपीएसई में लागू किया जाए, जब तक कि डीपीई द्वारा अन्य प्रकार से निर्दिष्ट न किया जाए।

ii. लोक उद्यम विभाग द्वारा एससी और एसटी हेतु आरक्षण पर सभी महत्वपूर्ण अनुदेश शामिल करके एक व्यापक राष्ट्रपति के निर्देश सभी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को 25 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें औपचारिक रूप से सीपीएसई को जारी किया जा सके। आवश्यक परिवर्तनों और आशोधनों को भी सीपीएसई को सूचना एवं अनुपालन हेतु उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के जरिए परिचालित किया जाता है।

iii. तत्पश्चात, दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल कमीशन) की सिफारिशों के आधार पर और इंदिरा साहनी मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) हेतु रिक्तियों में 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। ओबीसी के लिए आरक्षण दिनांक 08.09.1993 से आरंभ किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो सेवाओं में आरक्षण के संबंध में नीति तैयार करता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में आरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहता है। लोक उद्यम विभाग सीपीएसई को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों के जरिए अनुपालन हेतु इन अनुदेशों को

भेजता रहा है। एक व्यापक राष्ट्रपति जी के निदेश जिनमें ये सारे अनुदेश शामिल थे, को लोक उद्यम विभाग द्वारा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को दिनांक 27 जुलाई, 1995 के डीपीई का.ज्ञा. के तहत भेज दिया है ताकि वे अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसई को ये निदेश औपचारिक रूप से जारी कर सकें।

iv. इसके अतिरिक्त, डीपीई के दिनांक 25-10-2017 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में, सभी अधिकारी अर्थात बोर्ड स्तरीय और बोर्ड से निचले स्तरीय कर्मचारियों को इस परंतुक के अध्यक्षीय क्रीमी लेयर माना जाएगा कि उन अधिकारियों को, जिनकी वार्षिक आय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए मानदंड के अनुसार 8 लाख रु. (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-09-2017 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए यथासंशोधित) से कम है, वे क्रीमी लेयर के मानदंड के अंतर्गत नहीं आएंगे। यह संबंधित सीपीएसई का दायित्व है कि वह ऊपर उल्लिखित सिद्धांत के संबंध में क्रीमी लेयर के अंतर्गत शामिल पदों के लिए आवश्यक आदेश जारी करे।

v. लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसई में शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार देने के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों का अनुसरण करते हुए 11.03.1997 को सीपीएसई को राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए हैं। नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधिनियमन के साथ, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु आरक्षण, सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले अभिज्ञात समूह 'क' एवं 'ख' पदों पर भी लागू होगा। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कम से कम 4% पद दिव्यांग जन के लिए आरक्षित रहेंगे।

vi. लोक उद्यम विभाग ने प्रशासनिक मंत्रालयों / विभागों के जरिए सीपीएसई में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लिए ऐसी ही योजना के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं। भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि सीपीएसई में उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। ऐसे सीपीएसई, जो एजेंसी/डीलरशिप प्रदान करने की स्थिति में हैं, को सलाह दी गई है कि वे भूतपूर्व सैनिकों को ऐसी एजेंसियां/ डीलरशिप आबंटित करने के लिए कोटा आरक्षित करें।

vii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण देने के संबंध में डीओपीटी के दिनांक 19.1.2019 और 31.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन और दिनांक 21.1.2019 के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा जारी दिशानिर्देशों को यथोचित परिवर्तनों सहित लोक उद्यम विभाग के दिनांक 25.1.2019 और 1.2.2019 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में सभी सीपीएसई को भेजा गया है।

viii. आरक्षित पदों को समय पर भरने और बकाया रिक्तियों (बैकलॉग) को समाप्त करने की आवश्यकता पर समय-समय पर जारी विभिन्न अनुदेशों के जरिए बल दिया गया है। सभी प्रशासनिक

मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई को सलाह दें कि वे मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में भरे न गए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। इसके अतिरिक्त, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सीपीएसई में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने हेतु समय-समय पर आवश्यक अनुदेश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग ने सीपीएसई से संबंधित सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को भी ये अनुदेश दिए हैं कि वे समयबद्ध तरीके से इन रिक्तियों को भरें।

- ix. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु मौजूदा कोटा तथा रिक्तियों में आरक्षण हेतु पात्र अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों का कोटा निम्नानुसार है:

श्रेणी	आरक्षण के लिए कोटा
अनुसूचित जाति	15%
अनुसूचित जनजाति	7.50%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति	4%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	10%

भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध में मारे गए लोगों के आश्रितों के लिए आरक्षण की नीति के अनुसार, कुशल श्रमिकों के संबंध में 14.5% पद और अकुशल पदों के संबंध में 24.5% पद सीपीएसई में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं।

- x. पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अद्यतन समेकित अनुदेश सीपीएसई को सूचना और अनुपालन के लिए परिचालित किए गए थे।

11.2. लोक उद्यम विभाग में आरक्षण: डीपीई में आरक्षण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जो डीपीई में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की देखभाल करता है और डीपीई संवर्ग के संबंध में आरक्षण रजिस्टर/रोस्टर बनाए रखता है। लोक उद्यम विभाग के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में शिकायत रजिस्टर भी आरक्षण प्रकोष्ठ, डीपीई द्वारा रखा जा रहा है। एक निदेशक स्तर के अधिकारी को लोक उद्यम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। लोक उद्यम विभाग के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में शिकायत रजिस्टर भी आरक्षण प्रकोष्ठ, डीपीई द्वारा रखा जा रहा है। वर्ष 2025 में अब तक

डीपीई या संबंधित मामले में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह भी उल्लेख किया गया है कि आरक्षण रोस्टर के अनुसार निर्धारित एमटीएस पदों की नौ रिक्तियों के बारे में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सूचित कर दिया गया है। डीपीई कैडर के सीधी भर्ती पदों में विभिन्न आरक्षण श्रेणियों का प्रतिशत प्रतिनिधित्व अजा-5%, अजजा-10%, अपिव-25%, पीडब्ल्यूबीडी-5% और ईडब्ल्यूएस-5% है।

12. राजभाषा नीति

12.1 लोक उद्यम विभाग का हिन्दी अनुभाग मुख्यतः राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के विविध उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। हिन्दी अनुभाग उन दस्तावेजों के अनुवाद के लिए भी उत्तरदायी है, जिन्हें राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, विभाग में राजभाषा नीति/नियमों के सुचारु कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी अनुभाग राजभाषा नीति को कार्यान्वित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है।

12.2 वर्ष 2024-25 के दौरान कृत कार्रवाई नोट (एटीएन), अधिसूचनाएं, सूचनाएं, परिपत्र, संसद के दोनों सदनों के सभा-पटल पर रखे जाने वाले कागजातों आदि को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया है। हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाए जाने हेतु भी प्रयास किए गए। लोक उद्यम विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्य कर रही है।

12.3 राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा उसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग द्वारा 14-28 सितम्बर, 2025 तक आयोजित हिंदी पखवाड़ा: 2025 में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिसमें 1. हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता, (सभी के लिए) 2. निबंध लेखन प्रतियोगिता, (सामान्य वर्ग), 2(i) निबंध लेखन प्रतियोगिता (एमटीएस/संविदा वर्ग), 3. भाषा ज्ञान प्रतियोगिता, (सामान्य वर्ग), 3(i) भाषा ज्ञान प्रतियोगिता, (एमटीएस/संविदा वर्ग), 4. आशुभाषण प्रतियोगिता, (सभी के लिए) एवं 5. श्रुतलेखन प्रतियोगिता (सामान्य वर्ग), 5(i) श्रुतलेखन प्रतियोगिता, (एमटीएस/संविदा वर्ग) कुल 08 (आठ) प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

12.4 इस विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यचालन के सम्बन्ध में लोक उद्यम सर्वेक्षण नामक वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाती है। यह एक विशाल एवं विस्तृत प्रलेख है जिसे विभाग द्वारा अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में एक साथ प्रकाशित किया जाता है।

13. एमएसई से सीपीएसई द्वारा अधिप्रापण

13.1 भारत सरकार ने 2012 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति अधिसूचित की। इस नीति का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के विपणन में एमएसई का समर्थन करके उन्हें बढ़ावा देना और विकसित करना है। इस

नीति के प्रावधानों के अनुसार, 2012-13 से प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी उद्यम को तीन वर्षों की अवधि में एमएसई से कुल वार्षिक अधिप्राप्ति के न्यूनतम 20% के समग्र अधिप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। एमएसई से वार्षिक अधिप्राप्ति के 20% लक्ष्य में से, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से अधिप्राप्ति के लिए 4% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। तीन वर्षों के अंत में (अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2015-16 से), न्यूनतम 20% का समग्र अधिप्राप्ति लक्ष्य अनिवार्य होगा। इस नीति में दिनांक 9 नवंबर, 2018 को संशोधन किया गया था ताकि एमएसई से न्यूनतम वार्षिक अधिप्राप्ति को 20% से बढ़ाकर 25% किया जा सके और अजा/अजजा उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% की अधिप्राप्ति के अलावा महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से 25% में से न्यूनतम 3% की अधिप्राप्ति अनिवार्य रूप से की जा सके।

13.2 लोक उद्यम विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सीपीएसई के साथ कार्य कर रहा है कि सीपीएसई एमएसई से अधिप्राप्ति से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करें और जीईएम पोर्टल के माध्यम से अपनी अधिप्राप्ति को बढ़ाएं। एमएसई के लिए सरकार द्वारा घोषित समर्थन उपायों के अनुरूप, वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसई से सीपीएसई द्वारा अधिप्राप्ति अनिवार्य 37.90% की तुलना में लगभग 25% थी जो वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 43% हो गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीपीएसई द्वारा एमएसई से अधिप्राप्ति लगभग 43.57% है।

13.3 ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) - टीआरडीएस कई वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की व्यापार प्राप्य वस्तुओं के वित्तपोषण / छूट की सुविधा के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। ये प्राप्य वस्तुएं सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित कॉर्पोरेट्स और अन्य खरीदारों से प्राप्य हो सकती हैं। डीपीई टीआरडीएस पोर्टल पर सीपीएसई को पंजीकृत करने और टीआरडीएस पोर्टल के उपयोग को बढ़ाने के लिए सीपीएसई और उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के साथ लगातार कार्य कर रहा है। 177 सीपीएसई अब टीआरडीएस पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जो सीपीएसई द्वारा कुल अधिप्राप्ति का 98% खरीदारी करते हैं। सीपीएसई द्वारा टीआरडीएस पोर्टल के अधिक प्रभावी उपयोग को सुविधाजनक बनाने और एमएसएमई, अधिनियम, 2006 में व्यवस्था की गई है, इसे वर्ष 2022-23 से समझौता ज्ञापन ढांचे में एक मापदंड के रूप में शामिल किया गया है।

14. महत्वपूर्ण पहलें

14.1 मिशन भर्ती- सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई में रिक्त पदों को मिशन मोड यानी 'मिशन भर्ती' में भरने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया का समन्वय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा किया जा रहा है जिसने इस प्रयोजन के लिए एक समर्पित पोर्टल स्थापित किया है। लोक उद्यम विभाग कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्दिष्ट पोर्टल पर अपेक्षित सूचना अपलोड करने के लिए सीपीएसई के साथ नियमित रूप से

संपर्क करता रहा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित रोजगार मेले की 17 श्रृंखलाओं में अब तक सीपीएसई के 69,352 नवनियुक्त लोगों को शामिल किया गया है।

14.2 मिशन कर्मयोगी- डीपीई के सभी कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर जोड़ा गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान डीपीई की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना को भी मंजूरी दी गई थी और इसे कार्यान्वयन के लिए डीपीई के सभी कर्मचारियों को परिचालित किया गया था। **15 नवम्बर, 2025 तक सीपीएसई के 83 कर्मचारियों (वाईपी/वाईए सहित) ने आई-गॉट पोर्टल पर 3,276 पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं।**

14.3 मुक्त व्यापार वार्ता (एफटीए) में भागीदारी- भारत कई देशों के साथ एफटीए वार्ता कर रहा है और डीपीई के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित भारत-यूके एफटीए, भारत-यूरोपीय संघ एफटीए और भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की वार्ताओं में भाग लिया।

14.4 सीपीएसई में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाना: डीपीई ने सीपीएसई में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों (जिसे 4आईआर के रूप में भी जाना जाता है) को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक सक्रिय और दूरदर्शी कदम उठाया है। यह स्वीकार करते हुए कि डिजिटल परिवर्तन केवल एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता, परिचालन दक्षता और राष्ट्रीय लचीलेपन के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है, डीपीई ने कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की - 18 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में 2 और 11 नवंबर, 2025 को 2, 2 अगस्त 2025 को गुवाहाटी में 1, 22 अगस्त 2025 को मुंबई में 2। इन 7 कार्यशालाओं में 100 से अधिक सीपीएसई के वरिष्ठ प्रबंधन की भागीदारी थी।

15. साइबर सुरक्षा अनुपालन रिपोर्ट

15.1 साइबर सुरक्षा प्रक्रिया

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के पास साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) है, जिसे सीआईआरटी-इन द्वारा अनुमोदित किया गया है, जो सभी डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शासन संरचनाओं, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। अनुपालन को सत्यापित करने, नियंत्रण प्रभावशीलता में सुधार करने और विभाग की एक मजबूत साइबर सुरक्षा स्थिति बनाए रखने के लिए नियमित ऑडिट और प्रबंधन समीक्षा आयोजित की जाती है।

15.2 नेटवर्क सुरक्षा

विभाग के आंतरिक और बाहरी नेटवर्क बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, खतरों और कमजोरियों से बचाने के लिए नेटवर्क सुरक्षा नियंत्रण लागू किए गए हैं। इन उपायों में फायरवॉल, घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणाली (आईडीएस/आईपीएस), सुरक्षित वीपीएन एक्सेस, नेटवर्क विभाजन और निरंतर यातायात निगरानी शामिल हैं। बेसलाइन कॉन्फिगरेशन

की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है, और सुरक्षा पैच तुरंत लागू किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी नेटवर्क डिवाइस उभरते खतरों से सुरक्षित रहें।

15.3 अंतिम चरण सुरक्षा

अंतिम चरण सुरक्षा को यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) और एंड-पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) सिस्टम के मानकीकृत संस्करणों के माध्यम से लागू किया जाता है। यूईएम और ईडीआर के लिए डैशबोर्ड एंड-पॉइंट सुरक्षा की निगरानी में सहायक होते हैं। वास्तविक समय के आधार पर विभाग के सभी एंड-पॉइंट्स के स्वास्थ्य, अनुपालन स्थिति और सुरक्षा अलर्ट को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है।

15.4 अनुप्रयोग सुरक्षा

विभाग की वेबसाइटों/वेब एप्लिकेशन वैध साइबर सुरक्षा ऑडिट क्लीयरेंस और एसएसएल प्रमाणपत्रों से सुरक्षित हैं। नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट सरकारी नीति के अनुसार किए जाते हैं और वेबसाइटों/वेब अनुप्रयोगों में उनके ऑडिट वैधता अवधि समाप्त होने से पहले ही जब कभी प्रमुख कोड स्तर के परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, तब ही किया जाता है। साइबर

सुरक्षा ऑडिट आमतौर पर किसी भी सीईआरटी-इन पैनल में शामिल एजेंसी के माध्यम से आयोजित किया जाता है।

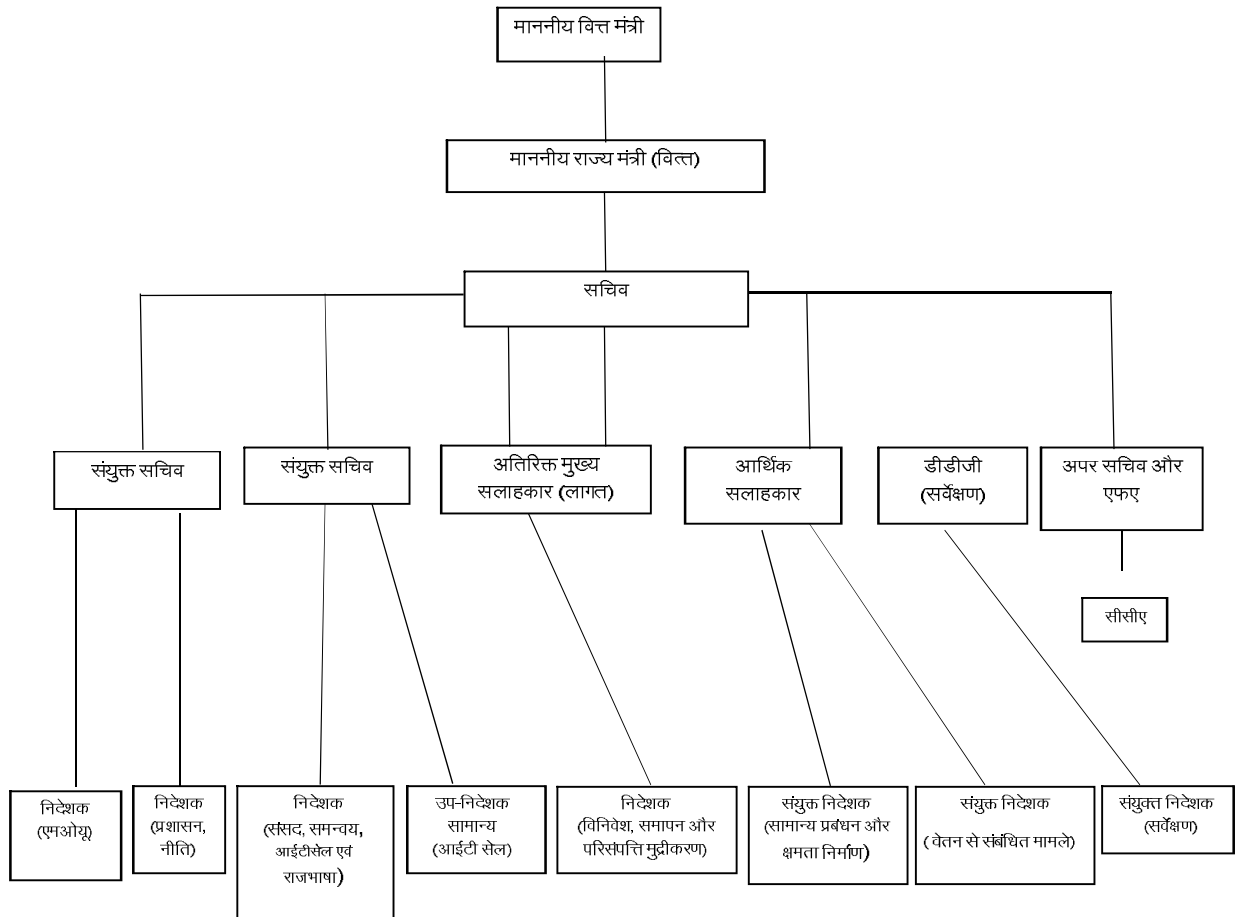
दिव्यांगजनों के लिए दिशा-निर्देशों सहित नवीनतम सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप डीबीआईएम अनुरूप फ्रेमवर्क का उपयोग करते हुए नई बहुभाषी डीपीई वेबसाइट लॉन्च की गई है।

सभी वेबसाइटों/वेब अनुप्रयोगों को सुरक्षित सरकारी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया जाता है, जहां वेब और डाटाबेस सर्वर की स्थिति की 24x7 आधार पर लगातार निगरानी की जाती है और किसी भी घटना के लिए नियमित लॉग और डाटा बैक-अप बनाए रखा जाता है।

15.5 साइबर सुरक्षा घटनाएं

समय पर प्रतिक्रिया और न्यूनतम व्यावसायिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सभी घटनाओं को गंभीरता के आधार पर लॉग, विश्लेषण और वर्गीकृत किया जाता है। घटना के बाद की समीक्षा मूल कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्यों को लागू करने, संगठन के लचीलेपन को बढ़ाने और पुनरावृत्ति की संभावना को कम करने के लिए आयोजित की जाती है। तथापि, लोक उद्यम विभाग में वर्ष के दौरान किसी साइबर सुरक्षा उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

लोक उद्यम विभाग
संगठन चार्ट



वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीपीएसई का कार्य-निष्पादन

क्र.सं .	मद/संकेतक	2023-24 (₹ लाख करोड़)	2024-25 (₹ लाख करोड़)	% परिवर्तन
1.	कुल सकल राजस्व [प्रचालनरत सीपीएसई का]	36.09	37.01	2.6%
2.	समग्र निवल लाभ [प्रचालनरत सीपीएसई का]	3.22	2.91	-9.8%
3.	लाभ कमाने वाले सीपीएसई का निवल लाभ [प्रचालनरत सीपीएसई का]	3.43	3.09	-10.1%
4.	सीपीएसई को होने वाली हानि का निवल घाटा [प्रचालनरत सीपीएसई का]	0.21	0.18	13.8%
5.	वित्तीय निवेश [सभी सीपीएसई का]	27.74	31.65	14.1%
6.	नियोजित पूंजी [सभी सीपीएसई की]	42.78	47.87	11.9%
7.	निवल संपत्ति [सभी सीपीएसई की]	19.96	22.33	11.9%
8.	घोषित लाभांश [सभी सीपीएसई का]	1.23	1.39	13.0%
9.	केंद्रीय राजकोष में अंशदान [सभी सीपीएसई का]	4.84	4.94	1.9%
10	बाजार पूंजीकरण [सूचीबद्ध सीपीएसई]	37.23 [66 सीपीएसई]	38.57 [66 सीपीएसई]	3.6%

गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड का ब्यौरा

अनुभव संबंधी मानदंड:

- i. संयुक्त सचिव स्तर या उससे ऊपर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी।
- ii. ऐसे व्यक्ति जो सीपीएसई के सीएमडी/सीईओ और अनुसूची 'ए' सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। सीपीएसई के पूर्व मुख्य कार्यकारी और पूर्व कार्यात्मक निदेशकों पर सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सीपीएसई के सेवारत मुख्य कार्यकारी/निदेशक किसी भी सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii. शिक्षाविदों / संस्थानों के निदेशकों / विभाग के प्रमुखों और प्रोफेसरों को संबंधित डोमेन जैसे प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन, या कानून में 10 से अधिक वर्षों का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव।
- iv. प्रख्यात पेशवरों को कंपनी के संचालन के क्षेत्र के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों में प्रासंगिक डोमेन का 15 से अधिक वर्षों का अनुभव।

- v. निजी कंपनियों के पूर्व सीईओ, यदि कंपनी (क) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है या (ख) असूचीबद्ध लेकिन लाभ कमा रही है और कम से कम 250 करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार है।
- vi. उद्योग, व्यापार या कृषि या प्रबंधन से प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- vii. स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध निजी कंपनियों के सेवारत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निदेशकों पर भी असाधारण परिस्थितियों में सीपीएसई के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

शैक्षिक अर्हता संबंधी मानदंड

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की उपाधि।

आयु संबंधी मानदंड

आयु सीमा 45-65 वर्ष (न्यूनतम / अधिकतम सीमा) के बीच होनी चाहिए

हालांकि, रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए प्रतिष्ठित पेशवरों के लिए, 70 वर्ष तक की सीमा के साथ इसमें छूट दी जा सकती है।

रत्न योजना की प्रमुख विशेषताएं (महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न)

1. महारत्न योजना

1.1 पात्रता मानदंड: निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करने वाले सीपीएसई महारत्न का दर्जा प्रदान करने पर विचार किए जाने के पात्र हैं :-

- (क) नवरत्न श्रेणी का उद्यम हो
- (ख) सेबी के विनियमों के अन्तर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता सहित भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो
- (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल वार्षिक कारोबार का औसत 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का हो
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान उसका औसत वार्षिक निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपये से अधिक हो
- (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान कर के पश्चात उसका औसत वार्षिक निवल लाभ 5000 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो
- (च) वैश्विक स्तर पर प्रभावी उपस्थिति हो या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचालनरत हो।

1.2 महारत्न दर्जा प्रदान करने/समाप्त करने की प्रक्रिया:- महारत्न दर्जा देने तथा साथ ही उनकी समीक्षा करने की प्रक्रिया नवरत्न दर्जे हेतु पालन की जाने वाली प्रचालित प्रक्रिया की भांति ही है।

1.3 महारत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियां: -

1.3.1 महारत्न सीपीएसई के बोर्ड, नवरत्न सीपीएसई को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ संयुक्त उद्यमों / सहायक कम्पनियों में निवेश तथा बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के सृजन की संवर्धित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। महारत्न सीपीएसई के बोर्ड के पास अधिकार हैं – (क) भारत में या विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम स्थापित करना तथा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में इक्विटी निवेश करना तथा (ख) भारत में या विदेश में विलयन या अधिग्रहण जो कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रु० (नवरत्न सीपीएसई के लिए 1,000 करोड़ रु०) की अधिकतम सीमा के साथ संबंधित सीपीएसई द्वारा एक परियोजना में उसके निवल मूल्य के 15% की अधिकतम सीमा के अध्यधीन होगा। सभी परियोजनाओं में ऐसे इक्विटी निवेश तथा विलयन एवं अधिग्रहण पर कुल मिलाकर अधिकतम सीमा संबंधित सीपीएसई के निवल मूल्य के 30% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, महारत्न सीपीएसई के बोर्डों के पास ई-9 स्तर तक के बोर्ड से नीचे के स्तर के पदों के सृजन का अधिकार है।

1.3.2 वित्तीय संयुक्त उद्यम और सहायक संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग महारत्न सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

2. नवरत्न योजना:

2.1 पात्रता मानदंड: सीपीएसई जो मिनीरत्न-I, अनुसूची 'क' हैं और जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में 'उत्कृष्ट' अथवा 'बहुत अच्छा' एमओयू रेटिंग प्राप्त की हैं और जिनका 6 चिन्हित कार्य-निष्पादन पैरामीटरों में कार्यनिष्पादन का 'संयुक्त अंक' 60 अथवा उससे अधिक है, नवरत्न दर्जा प्रदान किए जाने के लिए पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित सीपीएसई के कार्य-निष्पादन के आधार पर संयुक्त अंक का आकलन किया जाता है। सीपीएसई पर उनकी सामान्य प्रयोजनीयता पर छह (6) निष्पादन संकेतकों को चिन्हित किया गया है। निष्पादन संकेतकों का चयन इस प्रकार से किया गया है ताकि सीपीएसई के कार्य-निष्पादन का पता लगाया जा सके, चाहे वे विनिर्माण क्षेत्र से हों या सेवा क्षेत्र से। पहचान किए गए 6 कार्य-निष्पादन संकेतक इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	कार्य-निष्पादन संकेतक	अधिकतम (भारत)
1	निवल मूल्य की तुलना में निवल लाभ	25
2	उत्पादन की कुल लागत अथवा सेवा लागत की तुलना में जनशक्ति लागत	15
3	नियोजित पूंजी की तुलना में पीबीडीआईटी	15
4	कुल कारोबार की तुलना में पीबीआईटी	15
5	अर्जन प्रति शेयर	10
6	अंतर क्षेत्रीय कार्यनिष्पादन	20
	कुल	100

2.2 नवरत्न का दर्जा प्रदान करने/समाप्त करने की प्रक्रिया: प्रदान/समाप्त करने संबंधी प्रस्तावों पर प्रारंभ में अंतर-मंत्रालयी समिति और फिर शीर्ष समिति द्वारा विचार किया जाता है। नवरत्न का दर्जा प्रदान /समाप्त करने के लिए शीर्ष समिति की सिफारिशों को निर्णय के लिए मंत्री (डीपीई के प्रभारी) के समक्ष रखा जाना होता है।

2.3 नवरत्न सीपीएसई को प्रत्यायोजित शक्तियां:

2.3.1 **पूंजीगत व्यय:** - नवरत्न सीपीएसई के पास बिना किसी मौद्रिक सीमा के नई मदों की अधिप्राप्ति के लिए अथवा उन्हें बदलने के लिए पूंजीगत व्यय करने की शक्तियां हैं।

2.3.2 **प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन:** - नवरत्न सीपीएसई के पास प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यमों अथवा रणनीतिक गठबंधन में शामिल होने के और क्रय द्वारा अथवा अन्य व्यवस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी एवं जानकारी प्राप्त करने की शक्तियां हैं।

2.3.3 संगठन की पुनःसंरचना: - नवरत्न सीपीएसई के पास लाभ केन्द्रों, भारत और विदेश में कार्यालय खोलने, नए कार्यकलाप केन्द्र सृजित करने आदि सहित संगठनात्मक पुनर्संरचना करने की शक्तियां हैं।

2.3.4 मानव संसाधन प्रबंधन: - नवरत्न सीपीएसई को ई-6 स्तर तक के पदों का सृजन करने की और गैर निदेशक स्तर के निदेशकों तक सभी पदों को समाप्त करने की और इसी स्तर तक सभी नियुक्तियां करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इन सीपीएसई के बोर्डों को आंतरिक स्थानांतरण करने की और पदों को पुनः पदनामित करने के लिए और अधिक सशक्त किया गया है। नवरत्न सीपीएसई के निदेशक मंडल के पास, बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) से संबंधित शक्तियों को बोर्ड की उप-समितियों को अथवा सीपीएसई के कार्यपालकों को, जैसा भी सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, आगे प्रत्यायोजित करने की शक्तियां हैं।

2.3.5 संसाधनों की गतिशीलता: - इन सीपीएसई को घरेलू पूंजीगत बाजारों से ऋण लेने और अंतरराष्ट्रीय बाजार से ऋण लेने के लिए इस शर्त के अधीन शक्ति दी गई है कि भारतीय रिजर्व बैंक/ आर्थिक कार्य विभाग का अनुमोदन, जैसा भी आवश्यक हो, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए।

2.3.6 संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियां - :

- (क) नवरत्न सीपीएसई को भारत अथवा विदेश में वित्तीय संयुक्त उद्यम एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करने की शक्तियां इस शर्त के साथ प्रत्यायोजित की गई हैं कि सीपीएसई का इक्विटी निवेश निम्नलिखित तक सीमित रहना चाहिए:-
- किसी भी एक परियोजना में रु. 1000 करोड़,
 - किसी एक परियोजना में सीपीएसई के निवल मूल्य का 15%,
 - सभी संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों में सीपीएसई के निवल मूल्य का 30%।
- (ख) वित्तीय संयुक्त उद्यम और सहायक संस्थाओं की स्थापना के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग नवरत्न सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

2.3.7 विलयन और अधिग्रहण: नवरत्न सीपीएसई को विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (i) यह प्रगति योजना अनुसार हो और सीपीएसई के कार्यकरण के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो; (ii) शर्तें/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले में होती है (iii) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके अतिरिक्त, विलयनों और अधिग्रहणों से संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित सीपीएसई के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

2.3.8 सहायक कंपनियों में सृजन/निवेश: नवरत्न सीपीएसई को इस शर्त के अधीन परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटी लाने और सहायक कंपनियों में शेयर लेने हेतु शक्तियां प्राप्त हैं कि नवरत्न सीपीएसई को प्रदत्त

शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां प्रत्यायोजित होगी और इस परंतुक के साथ कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) सीपीएसई का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे नवरत्न सीपीएसई द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

2.3.9 कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे: सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरे, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

2.3.10 प्रत्यायोजित नवरत्न शक्तियों का प्रयोग कुछ कार्यात्मकताओं पर निर्भर करता है।

3. मिनीरत्न योजना:

3.1 पात्रता मानदंड

- श्रेणी-I सीपीएसई** द्वारा गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया होना चाहिए, इन तीन वर्षों में से कम से कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये या इससे अधिक कर पूर्व लाभ होना चाहिए और निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए।
- श्रेणी-II सीपीएसई** को गत तीन वर्षों में निरंतर लाभ अर्जित किया जाना चाहिए और उसका निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए। ये सीपीएसई और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करवाने के पात्र होंगे बशर्ते कि उन्होंने ऋणों के भुगतान/सरकार को बकाया ऋणों पर ब्याज भुगतान करने में कोई चूक नहीं की हो।
- ये केंद्रीय सरकारी उद्यम बजटीय सहायता या सरकार की गारंटी पर निर्भर नहीं होंगे।
- प्राधिकारी के संवर्द्धित प्रत्यायोजन का प्रयोग करने से पहले, पहली कार्रवाई के रूप में कम से कम 03 गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करके इन सीपीएसई के बोर्डों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।
- संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यह निर्णय लेगा कि संवर्द्धित शक्तियों का प्रयोग करने से पहले क्या सीपीएसई श्रेणी-I/श्रेणी-II कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

3.2 मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया: किसी विशेष सीपीएसई को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान करना संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा किया जाता है।

3.3 प्रत्यायोजित शक्तियां

3.3.1 पूंजीगत व्यय

क. श्रेणी-I में सीपीएसई हेतु: सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि

पर 500 करोड़ तक या निवल मूल्य के बराबर, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

- ख. श्रेणी-II में सीपीएसई हेतु सरकार के अनुमोदन के बिना नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण, उपकरणों की अधिप्राप्ति आदि पर 250 करोड़ तक या निवल मूल्य के 50% के बराबर, जो भी कम हो, पूंजी व्यय करने की शक्ति।

3.3.2 संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां:

- (क) **श्रेणी-I सीपीएसई:** इस शर्त पर भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी स्थापित करना कि सीपीएसई का किसी परियोजना में इक्विटी निवेश सीपीएसई के निवल मूल्य का 15% तक या 500 करोड़ रुपए तक, जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा सीपीएसई के निवल मूल्य की कुल 30% तक हो।
- (ख) **श्रेणी-II सीपीएसई:** इस शर्त पर भारत में संयुक्त उद्यम या सहायक कंपनी की स्थापना कि सीपीएसई का किसी परियोजना में निवेश सीपीएसई के निवल मूल्य का 15% तक या रुपए 250 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, होना चाहिए। सभी परियोजनाओं में ऐसे निवेश की समग्र सीमा सीपीएसई के निवल मूल्य की कुल 30% तक हो।
- (ग) वित्तीय संयुक्त उद्यम तथा सहायक निकायों की स्थापना करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग मिनीरत्न सीपीएसई के बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3.3.3 विलयन और अधिग्रहण: इन सीपीएसई के निदेशक मण्डलों के पास विलयन और अधिग्रहण की शक्तियां हैं बशर्ते कि (क) यह प्रगति योजना अनुसार हो और सीपीएसई के कार्यकरण के मुख्य कार्य क्षेत्र में हो: (ख) शर्त/सीमा ऐसी होगी जैसी संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम की स्थापना के मामले में होती है (ग) विदेश में निवेश के मामले में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति को सूचित करते रहना होगा। इसके साथ-साथ विलयनों और अधिग्रहणों से संबंधित शक्तियों का उपयोग इस प्रकार से किया जाना

चाहिए कि इससे संबंधित सीपीएसई के लोक उद्यम स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

3.3.4 मानव संसाधन विकास (एचआरडी) हेतु योजना: कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति योजनाओं आदि से संबंधित स्कीमें तैयार और क्रियान्वित करना। इन सीपीएसई के निदेशक मण्डलों के पास यह शक्तियां हैं कि वे बोर्ड से निचले स्तर के कार्यपालकों के मानव संसाधन प्रबंधन (नियुक्तियां, स्थानांतरण, तैनाती आदि) संबंधी शक्तियां सीपीएसई के बोर्ड के निर्णय के अनुसार बोर्ड की उप-समितियों या सीपीएसई के कार्यपालकों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

3.3.5 कार्यात्मक निदेशकों के विदेशी दौरे: इन सीपीएसई के मुख्य कार्यपालकों के पास ये शक्तियां हैं कि वे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव को सूचना देते हुए आपातकालीन स्थिति में कार्यात्मक निदेशकों हेतु 05 दिन के लिए व्यापारिक विदेशी दौरे (अध्ययन दौरों, सेमिनारों आदि को छोड़कर) अनुमोदित कर सकते हैं।

3.3.6 प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम और रणनीतिक गठबंधन: प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम, रणनीतिक गठबंधन करने और क्रय या अन्य व्यवस्थाओं के जरिए प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी ज्ञान की प्राप्ति समय-समय पर जारी सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार होगी।

3.3.7 सहायक कंपनियों का सृजन/विनिवेश: परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, नई इक्विटी लाने और सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी लेने हेतु यह शर्त है कि मिनीरत्न सीपीएसई को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत धारक कंपनी द्वारा स्थापित सहायक कंपनियों के संदर्भ में शक्तियां होगी और इसके अतिरिक्त यह प्रावधान है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना संबंधित (सहायक कंपनी सहित) सीपीएसई का स्वरूप नहीं बदलेगा और ऐसे मिनीरत्न सीपीएसई द्वारा अपनी सहायक कंपनी से निकलने से पहले सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा।

3.3.8 प्रत्यायोजित मिनीरत्न शक्तियों का प्रयोग कुछ कार्यात्मकताओं पर निर्भर करता है।

(महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न सीपीएसई की सूची)

महारत्न सीपीएसई

1. भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल इंडिया लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
9. पावर फाइनेंस कारपोरेशन
10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
12. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
13. ऑयल इंडिया लिमिटेड
14. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड

नवरत्न सीपीएसई

1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
4. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
5. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
6. नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. नेयवेली लिमनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8. एनएमडीसी लिमिटेड
9. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
10. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. रेल विकास निगम लिमिटेड
12. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
13. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड
14. इरकॉन
15. राइटस
16. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
17. केन्द्रीय भण्डारण निगम

18. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
19. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
20. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
21. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
22. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) लिमिटेड
23. एनएचपीसी लिमिटेड
24. एसजेवीएन लिमिटेड
25. इंडियन रेलवे कंटेनरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
26. भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड
27. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

मिनीरत्न I सीपीएसई

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2. एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड
4. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
5. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
6. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
7. बीईएमएल लिमिटेड
8. भारत संचार निगम लिमिटेड
9. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
10. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
11. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
12. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
13. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
14. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
16. भारतीय कपास निगम लिमिटेड
17. एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
18. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल)
19. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
20. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया)
21. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
22. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
23. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड

24. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
25. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
26. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
27. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
28. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
29. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
30. इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
31. भारत व्यापार संवर्धन संगठन
32. केआईओसीएल लिमिटेड
33. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
34. मॉयल लिमिटेड
35. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड
36. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
38. एमएमटीसी लिमिटेड
39. एमएसटीसी लिमिटेड
40. मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड
41. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड
42. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
43. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन
44. नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

45. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
47. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
48. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
49. भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम
50. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
51. टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
52. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
53. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
54. वापकोस लिमिटेड

मिनीरल ॥ सीपीएसई

1. आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफेक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
3. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
4. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड
5. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
6. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
7. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8. मेकॉन लिमिटेड
9. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
10. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अनुसूची-वार सूची

अनुसूची-क (77)

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	35. केआईओसीएल लिमिटेड
2. एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	36. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
3. आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	37. मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
4. बीईएमएल लिमिटेड	38. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
5. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	39. मेकॉन लिमिटेड
6. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	40. एमएमटीसी लिमिटेड
7. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	41. एमओआईएल लिमिटेड
8. भारत संचार निगम लिमिटेड	42. मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड
9. सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	43. मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड
10. चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
11. कोल इंडिया लिमिटेड	45. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
12. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	46. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
13. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	47. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड
14. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	48. एनएचपीसी लिमिटेड
15. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	49. नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल)
16. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	50. एनएमडीसी लिमिटेड
17. फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ब्रावनकोर)	51. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड
18. भारतीय खाद्य निगम	52. एनटीपीसी लिमिटेड
19. गेल (इंडिया) लिमिटेड	53. एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एनजीईएल)
20. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	54. एनएलसी इंडिया लिमिटेड
21. हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	55. नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
22. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	56. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
23. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	57. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
24. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58. ऑयल इंडिया लिमिटेड
25. एचएमटी लिमिटेड	59. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
26. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	60. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
27. आई टी आई लिमिटेड	61. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
28. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	62. पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	63. राइट्स लिमिटेड
30. भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	64. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
31. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	65. रेल विकास निगम लिमिटेड
32. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	66. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
33. कर्मयोगी भारत	67. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
34. कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	68. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

69. एसजेवीएन लिमिटेड
70. भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम
71. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
72. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
73. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
74. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
75. टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स (इंडिया) लिमिटेड
76. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
77. यंत्र इंडिया लिमिटेड

अनुसूची- ख (64)

1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
2. एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
3. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
4. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
5. भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
6. भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
7. भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
8. ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलिमर लिमिटेड
9. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
11. ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड
12. ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
13. ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14. बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड
15. सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
16. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
17. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
18. सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
19. भारतीय कपास निगम लिमिटेड
20. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
21. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
22. फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

23. ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
24. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड
25. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड
26. हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
27. हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
28. एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
29. हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड
30. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
31. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड
32. हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
33. एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड
34. एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
35. एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
36. इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
37. भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड
38. भारत व्यापार संवर्धन संगठन
39. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
40. इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड
41. इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
42. एम एस टी सी लिमिटेड
43. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
44. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
45. मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
47. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
48. राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
49. नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
50. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

51. नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
52. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
53. नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
54. उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
55. पीईसी लिमिटेड
56. पवन हंस लिमिटेड
57. प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
58. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
59. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
60. एसएफसीएल
61. टूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
62. यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
63. वापकोस लिमिटेड
64. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

अनुसूची-ग (46)

1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वन एवं पौध विकास निगम लिमिटेड
2. आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
3. ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
4. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
5. बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड (बीएलएएल)
6. भेल इलेक्ट्रिक मशीन्स लिमिटेड
7. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड
8. बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
9. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
10. सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
12. सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड
13. सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड
14. दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन
15. एडसिल (इंडिया) लिमिटेड
16. एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
17. फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
18. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड

19. एचआईएल (याडिड)लिमिटेड
20. हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
21. हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
22. हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
23. एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड
24. एचएमटी चिनार वॉचेस लिमिटेड
25. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड
26. एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
27. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
28. द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
29. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
30. नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
31. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
32. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम
33. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
34. नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
35. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
36. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम
37. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
38. नेपा लिमिटेड
39. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
40. उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड
41. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड
42. रिचर्डसन एंड कुडास (1972) लिमिटेड
43. रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड (आरएचएल)
44. एसटीसीएल लिमिटेड
45. एससीआईएलएएल
46. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

अनुसूची - घ (06)

1. बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
2. हिंदुस्तान फलोरोकार्बन लिमिटेड
3. इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4. उड़ीसा ड्रम्स एंड केमिकल्स लिमिटेड
5. राजस्थान ड्रम्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
6. बेल ऑप्टोनिक्स लिमिटेड

योजना-वार व्यय का विवरण

लोक उद्यम विभाग, मांग संख्या 33, 2025-26

लोक उद्यम विभाग (अनुदान संख्या 33)

(रुपये लाख में)

क्र.सं .	लेखा शीर्ष	योजना		
33-लोक उद्यम विभाग		2025-26		
		ब.अ.	सं.अ.	दिनांक 14.11.2025 तक व्यय
		2025-26	2025-26	2025-26
2852 उद्योग (मुख्य शीर्ष)				
	सीआरआर योजना			
1	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं (28.00.28)	100.00	100.00	3.54
2	सहायता अनुदान (31.00.28)	1.00	1.00	0.00
3	सीआरआर योजना एनईआर(31.00.01)	20.00	20.00	0.00
	कुल सीआरआर 121.00	121.00	121.00	3.54
	आरडीसी योजना			
1	घरेलू यात्रा व्यय (27.00.11)	5.00	5.00	0
2	विदेश यात्रा व्यय (27.00.12)	5.00	5.00	0
3	मुद्रण और प्रकाशन (27.00.16)	5.00	5.00	0
4	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं (27.00.28)	448.00	448.00	442.41
5	सहायता अनुदान (27.00.31)	1.00	1.00	47
6	अंशदान आईसीपीई (27.00.32)	0.00	0.00	0
	सीआरआर योजना एनईआर (02.00.31)	64.00	64.00	0
	कुल आरडीसी	528.00	528.00	489.41
	सकल योग	649.00	649.00	492.95

गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई)

के लिए नई नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश

1.1 सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 4 फरवरी, 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) के लिए नई नीति को अधिसूचित किया। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति में सीपीएसई के रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकरण की परिकल्पना की गई है और कुछ सीपीएसई जैसे कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गैर-लाभकारी कंपनियों या समाज के असुरक्षित और कमजोर वर्गों की सहायता करने वाली कंपनियों को नीति के दायरे से छूट दी गई है। नीति के अनुसार रणनीतिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- i) परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
- ii) परिवहन और दूरसंचार
- iii) विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज
- iv) बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं

1.2 सामरिक क्षेत्र/गैर-रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई के निजीकरण, विलय, किसी अन्य सीपीएसई के साथ सब्सिडी अथवा उन्हें बंद करने के लिए लिया जाना है। उपर्युक्त सामरिक क्षेत्र में सीपीएसई की न्यूनतम उपस्थिति ही बनाए रखी जानी है।

1.3 लोक उद्यम विभाग (डीपीई) को कैबिनेट सचिवालय की दिनांक 6 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया है और उसके बाद, वित्त सचिव ने 17 अगस्त, 2021 के आदेश के माध्यम से दीपम और डीपीई के मध्य कुछ जिम्मेदारियों को चिह्नित किया। डीपीई को प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से गैर-रणनीतिक क्षेत्र में बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करने और ऐसे चिन्हित सीपीएसई के संबंध में सीसीईए से सैद्धांतिक अनुमोदन लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, डीपीई को मंत्रिमंडल द्वारा एक बार एसपीवी को अनुमोदित किए जाने के बाद परिसंपत्ति मुद्रिकरण के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) स्थापित करने का कार्य भी सौंपा गया है। डीपीई को दीपम द्वारा चलाई जा रही विनिवेश प्रक्रिया की तर्ज पर बंद करने के लिए अनुमोदित सीपीएसई के लिए बंद करने की प्रक्रिया को चलाने की भी आवश्यकता है।

1.4 तदनुसार, निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। नीचे दिए गए अनुसार क्लोजर दिशानिर्देश पहले जारी किए गए सभी क्लोजर दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे।

2. डीपीई द्वारा नई पीएसई नीति का कार्यान्वयन:

2.1 बंद करने और विनिवेश के लिए गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के सीपीएसई की पहचान: नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति के तहत, डीपीई संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, नीति आयोग, व्यय विभाग और दीपम के परामर्श से गैर-

रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई को बंद करने या निजीकरण करने के लिए उसकी पहचान करेगा।

2.2 सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन लेने के लिए सीसीईए नोट तैयार करना: गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के तहत बंद करने या निजीकरण के लिए सीपीएसई की पहचान करने के बाद, डीपीई गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में बंद करने और/या विनिवेश के लिए पहचाने गए सीपीएसई के संबंध में सीसीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन लेने के लिए एक नोट तैयार करेगा। सीसीईए के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए इस तरह के नोट अधिमानतः नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के गैर-रणनीतिक क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से तैयार किए जाएंगे। सीपीएसई, जिन्हें विनिवेश के लिए सीसीईए द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है, उन्हें दीपम को इसकी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया जाएगा। सीपीएसई को बंद करने का कार्य पैरा 3 में नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3. सीपीएसई को बंद करने की संशोधित प्रक्रिया:

3.1 एक बार सीपीएसई को बंद करने का सैद्धांतिक निर्णय सीसीईए से प्राप्त हो जाने के बाद, सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया को चलाने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा एक आईएमसी का गठन किया जाएगा।

3.1.1 संबंधित मंत्रालय/विभाग बंद करने के विवरण पर कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीपीएसई को बंद करने के वित्तपोषण के लिए अपेक्षित बजटीय सहायता का अनुमान, समय-सीमा और केन्द्र सरकार से निधियों को जारी करने की समय-सीमा और चरणबद्ध तरीके से उन्हें जारी करने और सीपीएसई की चल और अचल परिसंपत्तियों के अभिलेखों को अद्यतन करना आदि शामिल होंगे। प्रारंभिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क. सांविधिक बकाया: केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों को राजस्व, करों, उपकरों और दरों के प्रति सांविधिक बकाया/देनदारियों का निर्धारण सीपीएसई द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की देखरेख में किया जाएगा।

ख. बंद करने की सूचना देना: कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को सीपीएसई बंद करने के इरादे के बारे में सूचित करने के लिए एक सामान्य नोटिस देगा और इसी के बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय को भी लिखेगा, जैसा कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत लागू है। प्रशासनिक मंत्रालय के अनुमोदन से सीपीएसई को भी वीआरएस योजना को अधिसूचित करना चाहिए।

- ग. **कर्मचारियों का बकाया:** वीआरएस/वीएसएस/छंटनी के माध्यम से उनकी कार्यमुक्ति के समय तक कर्मचारियों के संबंध में वीआरएस/वीएसएस/वेतन/वेतन के भुगतान और सांविधिक बकाया राशि का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि का निर्धारण किया जाएगा।
- घ. **सुरक्षित ऋणदाताओं के प्रति देनदारियां** न्यूनतम मूल्य पर निपटान के लिए सुरक्षित लेनदारों से मिलने वाले प्रस्तावों के आधार पर उन्हें वापस भुगतान की जाने वाली राशि का अनुमान। प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सुरक्षित लेनदारों के साथ भुगतान की अनुसूची, ब्याज की माफी और जुर्माने सहित सर्वोत्तम संभव निपटान की गंभीर रूप से जांच करेगा।
- ङ. **केंद्र सरकार को भुगतान की जाने वाली देय राशि:** समय-समय पर केंद्र सरकार ऋण के रूप ली गई राशि का भुगतान जिसे प्रमुख बकाया धनराशि तथा उस पर लगने वाले ब्याज की गणना की जाएगी।
- च. **मैट देयता:** यदि प्रस्ताव में बकाया भारत सरकार के ऋणों (और उस पर लगने वाले ब्याज) का त्याग शामिल है, तो इसी पर मैट देयता का भी पता लगाया जाना चाहिए।
- छ. **अन्य देनदारियां:** किसी भी असुरक्षित ऋणदाताओं सहित अन्य सभी देनदारियों पर कार्य किया जाना चाहिए।
- ज. **चल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन:** संयंत्रों और मशीनों सहित चल संपत्तियों के विवरण को अद्यतन करना और किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म से इन्वेंट्री का सत्यापन। इसके अलावा, चल संपत्तियों का बही मूल्य, वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य और उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाला वास्तविक मूल्य निकाला जाएगा। जहां भी चल संपत्तियां पट्टे पर हैं, सीपीएसई द्वारा पट्टेदाता के साथ बातचीत की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि पट्टेदाता इसे बाजार मूल्य पर वापस लेना चाहता है या नीलामी कराना चाहता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि क्या चल संपत्तियों का उपयोग इसकी होल्डिंग कंपनी (यदि कोई सहायक कंपनी है) द्वारा किया जाएगा या किसी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा। बंद की जा रही सीपीएसई के ब्रांड नाम, सद्भावना, ट्रेडमार्क आदि का बाजार मूल्य भी निकाला जा सकता है। यदि बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इसे सीपीएसई के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- झ. **प्राप्तियों का अनुमान:** व्यापार प्राप्तियों, प्रतिभूतियों, ऋणों और अग्रिमों आदि को सुनिश्चित करना।
- 3.1.2 **बंद करने के लिए आवश्यक बजटीय सहायता का अनुमान:** पैरा 3.1.1 के अनुसार किए गए कार्य के आधार पर, सीपीएसई को बंद करने हेतु वित्तपोषण के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाया जाएगा। सीपीएसई के अपने संसाधनों, चल परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि सहित, जो बंद होने के दौरान देनदारियों के निपटान के लिए उपलब्ध

हो सकती है, पर भी कार्य किया जाएगा। इसके बाद, केंद्र सरकार से बजटीय सहायता की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार के पास यह तय करने का अधिकार है कि वह बजटीय सहायता से निधियों की किस आवश्यकता की अनुमति देगी।

3.1.3 अचल परिसंपत्तियों के भूमि अभिलेखों का अद्यतनीकरण

करना: भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने जैसे कि मालिकाना हक विलेख, लीज होल्ड भूमि, फ्रीहोल्ड भूमि, पट्टे की शर्तें, पट्टे की शेष अवधि, वर्तमान भूमि उपयोग, एफएआर और भूमि के उपयोग से संबंधित अन्य अधिकार, क्या अधिग्रहण के समय भूमि मुआवजा (आंशिक/पूरी तरह से) का सीपीएसई/केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किया गया, भुगतान की गई मुआवजे की राशि, भूमि के कब्जे की स्थिति, अतिक्रमण, यदि कोई हो, की जियो-मैपिंग आदि की जाएगी।

3.1.4 एक बार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रारंभिक कार्यकलाप पूरे हो जाने के बाद, डीपीई द्वारा प्रारंभिक कार्यकलापों की जानकारी के आधार पर और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से सीपीएसई को बंद करने के लिए एक मसौदा नोट तैयार किया जाएगा ताकि सीपीएसई को मामला-दर-मामला आधार पर बंद किया जा सके। इसे आईएमसी के समक्ष रखा जाएगा, जो जांच के बाद नोट की विवीक्षा करेगा। इसके बाद, माननीय वित्त मंत्री (एफएम) की मंजूरी ली जाएगी।

3.1.5 यदि सीपीएसई के निदेशक सहयोग करने में विफल रहते हैं, तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने पर विचार कर सकते हैं और इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित संयुक्त सचिव को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार और संबंध में विस्तारित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यात्मक निदेशकों का प्रभार दे सकते हैं। प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों को हटाने के संबंध में यह सूचना पीईएसबी को प्रदान की जाएगी।

3.2 अचल परिसंपत्ति का निपटान

सीपीएसई को बंद करने और उसकी अचल संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया को पूरी तरह से पृथक कर दिया जाएगा। क्लोजर नोट के अनुमोदन पर, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/सीपीएसई अपनी बहियों से अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए एक साथ लेकिन अलग से कार्रवाई करेंगे।

3.2.1 अचल परिसंपत्तियों को नीचे निर्धारित तरीके से सीपीएसई से हस्तांतरित किया जाएगा:

- (क) **राज्यों को लीजहोल्ड भूमि की वापसी:** सीपीएसई की सभी प्रकार की लीजहोल्ड भूमि को किसी भी मुआवजे पर बल दिए बिना राज्य सरकार को वापस कर दिया जाएगा (यदि पट्टा समझौता के अनुसार देय हो)।
- (ख) **फ्रीहोल्ड भूमि का विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) को** हस्तांतरण एसपीवी (डीपीई में स्थापित किए जाने वाले) के प्रचालन के लिए लागू प्रक्रिया के अनुसार होगा।

3.2.2 भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के माध्यम से अंतरिम व्यवस्था: एसपीवी की स्थापना के लंबित मामलों में, बंद होने के मामले जिनमें एनबीसीसी जैसी भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) को पहले डीपीई बंद करने के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि के निपटान के लिए नियुक्त किया गया है, एलएमए भूमि का प्रबंधन करना जारी रखेगा और इसे किसी भी उपयुक्त एजेंसी को सर्वोत्तम पाए गए मूल्य पर बेच सकता है। अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए एलएमए या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीपीएसईएम या एमएसटीसी के अग्रिम नीलामी मंच का भी लाभ उठाया जा सकता है।

3.2.3 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव सीपीएसई से अचल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की प्रगति की निगरानी करेंगे।

3.3 वीआरएस/वीएसएस का कार्यान्वयन:

- (क) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सीपीएसई के बोर्ड के माध्यम से कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन और सांविधिक बकाया राशि का निपटान करेगा और कानून के अनुसार वीआरएस/वीएसएस प्रक्रिया और गैर-वीआरएस का विकल्प चुनने वालों को मुआवजे का भुगतान करेगा।
- (ख) वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन के दौरान सीपीएसई कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य सौंपे जाएंगे ताकि ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर सभी आधारभूत कार्य पूरे हो जाएं और बंद करने की बाद की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता न हो।

3.4 देनदारियों का निपटान

केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरणों को राजस्व, करों, उपकरों और दरों के लिए सांविधिक बकाया/देनदारियों के भुगतान का कार्य पहले पूरा किया जाना चाहिए।

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सुरक्षित ऋणदाताओं के साथ बातचीत करेंगे ताकि उनकी बकाया राशि को न्यूनतम मूल्य पर एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के रूप में निपटारा किया जा सके।

दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 की धारा 53 में यथा उल्लिखित अन्य देनदारियों के निपटान की प्राथमिकता का क्रम वितरण की प्राथमिकता में होगा।

3.5 चल परिसंपत्ति का निपटान:

- (क) सीपीएसई प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पर्यवेक्षण में सीपीएसई द्वारा जीईएम पर उपलब्ध नीलामी एजेंसी (जैसे एमएसटीसी) नियुक्त/अग्रिम नीलामी मंच के माध्यम से पारदर्शी तरीके से संयंत्र और मशीनरी सहित चल परिसंपत्तियों के निपटान की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा।
- (ख) बंद किए जा रहे सीपीएसई का ब्रांड नाम, सद्भावना, ट्रेडमार्क, बौद्धिक संपदा आदि जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अलग से निपटान के लिए सीपीएसई के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

- (ग) लीजहोल्ड चल परिसंपत्ति बाद के विकल्प पर पट्टेदार को वापस की जा सकती है।
- (घ) यदि किसी चल परिसंपत्ति की उसकी होल्डिंग कंपनी या प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा आवश्यकता होती है, तो उसे उन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है।
- (ङ) सीपीएसई, यदि अत्यंत आवश्यक हो, तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के परामर्श से चल परिसंपत्तियों के निपटान के साथ-साथ कारखाना भवन ढांचे का निपटान कर सकता है।
- (च) यदि सीपीएसई निर्धारित समय-सीमा के भीतर चल परिसंपत्तियों का निपटान करने में सक्षम नहीं है, तो इसे सीपीएसई द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के ध्यान में लाया जाना चाहिए। इसके बाद, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग 15 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करेगा और चल परिसंपत्तियों के निपटान पर निर्णय लेगा।

3.6 व्यय विभाग से बजटीय सहायता:

क्लोजर नोट के अनुसार निपटाई जाने वाली विस्तृत देनदारियों के आधार पर, डीपीई निपटाए जाने वाले देनदारियों के संबंध में डीओई को बजटीय सहायता के लिए अनुरोध करेगा। तथापि, यह निर्णय लेने का अधिकार कि बजटीय सहायता से निधियों की किन आवश्यकताओं की अनुमति दी जानी है, केन्द्र सरकार के पास निहित होगा।

4. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के समक्ष आवेदन दाखिल करना:

एक बार सभी देनदारियों और परिसंपत्तियों के निपटान से संबंधित अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी हो जाने के बाद, सीपीएसई का निदेशक मंडल कंपनी रजिस्ट्रार से नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा जैसा कि नीचे दिया गया है:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा दिनांक 29 जून, 2020 को जारी अधिसूचना द्वारा संशोधित प्रपत्र एसटीके-3ए और एमसीए द्वारा कंपनी (कंपनियों के नाम रजिस्ट्रार से हटाने) के नियम, 2016 के तहत निर्धारित अन्य प्रपत्रों (एसटीके-2 और 4) के साथ सीपीएसई का नाम कंपनी रजिस्ट्रार से हटाने के लिए आरओसी को आवेदन करें। यह संशोधन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि (अवर सचिव या उसके समकक्ष) को सीपीएसई के व्यक्तिगत निदेशकों की बजाय प्रशासनिक मंत्रालय/भारत सरकार (सीपीएसई के स्वामी) की ओर से किसी भी भविष्य की देनदारी के लिए क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।

कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष क्लोजर आवेदन दाखिल करने वाले प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और उनके सीपीएसई सभी कंपनियों के पंजीयक को दिनांक 1 जुलाई, 2020 को जारी एमसीए परिपत्र संख्या 1/2020 पर भी ध्यान देंगे, ताकि सेवा मामलों, कर्मचारियों के वीआरएस/वीएसएस से संबंधित लंबित मुकदमे वाले सीपीएसई के आवेदनों पर कार्यवाई की जा सके, ताकि इस तरह के बंद करने के आवेदनों को खारिज करने का आधार न हो।

5. नीतिगत सहायता:

बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसी भी मुद्दे पर किसी नीतिगत सहायता या स्पष्टीकरण के लिए, जैसा कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा आवश्यक है, उसे आईएमसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। सीसीईए का "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करते समय, माननीय वित्त मंत्री को सीसीईए के निर्णय से गैर-रणनीतिक क्षेत्र के सीपीएसई को बंद करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विचलन के मामलों के अनुमोदन के लिए भी अनुमोदन मांगा जाएगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग आईएमसी के समक्ष रखने के लिए डीपीई को स्पष्टीकरण/नीतिगत सहायता के लिए प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद आईएमसी की सिफारिशों को डीपीई द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्री को भेजा जाएगा। डीपीई वित्त मंत्री को भेजे जाने वाले नीतिगत मामलों के प्रसंस्करण के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

6. विशेष मामले:

संशोधित दिशानिर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 के तहत बंद करने की सिफारिश की गई है। विशेष रूप से अत्यधिक उच्च देनदारियों वाले जटिल मामलों में, डीपीई द्वारा सीसीईए अनुमोदन के लिए नोट में पर्याप्त औचित्य प्रदान करते हुए आईबीसी 2016 मार्ग का पालन किया जा सकता है। आईबीसी 2016 के तहत आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया संबंधित सीपीएसई बोर्ड और उसके प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सीसीईए के अनुमोदन का कार्यवृत्त प्राप्त होने के 3 माह के भीतर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के संबंध में, कंपनी रजिस्टर

से कंपनी का नाम हटाने के लिए आवेदन करने से पहले सेबी की सूची से बाहर किए गए विनियमन, 2009 और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन आईएमसी के पर्यवेक्षण के तहत किया जाएगा।

7. सीपीएसई की सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करना:

सीपीएसई की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/इकाइयों को बंद करने की प्रक्रिया धारक सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

8. चल रहे मामलों के लिए प्रक्रिया:

जिन मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ने बंद करने के लिए सीसीईए/कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग संशोधित तंत्र के अनुसार बंद करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इन दिशा-निर्देशों के जारी होने के 15 दिनों के भीतर वित्तीय सलाहकार (एफए) के माध्यम से व्यय विभाग से बजटीय सहायता की समीक्षा करेगा और बजटीय सहायता मांगेगा। तथापि, यह निर्णय लेने का अधिकार कि बजटीय सहायता से निधियों की किन आवश्यकताओं की अनुमति दी जानी है, केन्द्र सरकार के पास विहित होगा।

9. समय-सीमा: सीपीएसई को बंद करने की पूरी प्रक्रिया अनुलग्नक-1 में उल्लिखित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी।

10. वित्त मंत्री इन दिशानिर्देशों में कोई भी बदलाव करने का अनुमोदन प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

सीपीएसई को बंद करने के लिए गतिविधियों की समय-सीमा

क्र.सं.	महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ/ गतिविधियाँ	समय-सीमा
1	गैर-रणनीतिक क्षेत्र में सीपीएसई को बंद करने/विनिवेश को कैबिनेट/सीसीईए द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन। इस क्षेत्र के लिए आईएमसी की स्थापना जिसमें सचिव, डीपीई, अध्यक्ष के रूप में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय (मंत्रालयों), दीपम, नीति आयोग के प्रतिनिधि और सहयोजित सदस्य, यदि कोई हो, शामिल हैं	तैयारी की तारीख (टी ₀)
2	आईएमसी द्वारा प्रत्येक सीपीएसई के लिए सांविधिक देय राशियों, करों, उपकर, एमएटी जैसी देनदारियों, सुरक्षित और असुरक्षित ऋणदाताओं को देय राशियों, वीआरएस/वीएसएस के लिए आवश्यक निधियां, कर्मचारियों को देय वेतन वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्य मुक्त किए जाने तक, प्राप्य राशियों, चल और अचल संपत्तियों के मूल्य आदि के विनिश्चयन के बाद मसौदा समापन नोट तैयार करना।	टी ₀ + 3 माह
3	आईएमसी द्वारा मसौदा क्लोजर नोट का पुनरीक्षण और इसे मामला-दर-मामला आधार पर वित्त मंत्री के अनुमोदन के लिए अग्रेषित करना।	टी ₀ + 5 माह
4	राज्य सरकार को लीजहोल्ड भूमि की वापसी	टी ₀ + 7 माह
5	फ्रीहोल्ड भूमि का विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को हस्तांतरण	
6	बंद होने के संबंध में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सूचना देना	
7	व्यय विभाग से बजटीय सहायता के लिए अनुरोध।	
8	व्यय विभाग द्वारा बजटीय अनुदान जारी करना	
9	धारक कंपनी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	
10	कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस और कर्मचारियों की मजदूरी/वेतन तथा सांविधिक देय राशि का निपटान (यदि कर्मचारी वीएसआर/वीएसएस का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो कर्मचारियों की छंटनी)	
11	राज्य सरकार/केंद्र सरकार/नगर निकायों को देय राजस्व, करों आदि के लिए सांविधिक बकाया/ देनदारियों का निपटान	
12	एकमुश्त निपटान के रूप में सुरक्षित ऋणदाताओं का भुगतान	
13	चल संपत्ति का निपटान	
14	सीपीएसई का नाम हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को आवेदन	टी ₀ + 7 माह और 45 दिना

परिभाषा

- i. **प्रारंभिक तिथि (टी₀)** वह तारीख होगी जिस दिन सीसीईए द्वारा सीपीएसई को बंद करने का "सैद्धांतिक" अनुमोदन लिया गया है।
- ii. **सीपीएसई:** कुछ सांविधिक निगम और सभी सरकारी कंपनियां जिनमें केंद्र सरकार की 50% से अधिक इक्विटी या नियंत्रित हिस्सेदारी है, को सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन कंपनियों की सहायक कंपनियां, जिनमें किसी भी सीपीएसई की 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी है, को भी सीपीएसई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह भारत में पंजीकृत हैं।
- iii. **अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी):** बंद करने की प्रक्रिया चलाने के लिए डीपीई द्वारा गठित और इसमें सचिव, डीपीई, अध्यक्ष के रूप में और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय (यों), दीपम और नीति आयोग के प्रतिनिधि इसके सदस्यों के रूप में शामिल हैं। आईएमसी किसी अन्य सदस्य (सदस्यों) को भी सहयोजित कर सकता है। आईएमसी को सचिवीय सहायता डीपीई द्वारा प्रदान की जाएगी।
- iv. **स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी):** मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए डीपीई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी।
- v. **भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए):** यह सीपीएसई हो सकता है जैसे एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड (एनबीसीसी)/इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल) अथवा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के तहत एक सार्वजनिक एजेंसी हो सकती है जिसे नियुक्त किया गया है और जिसके पास अचल परिसंपत्तियों के प्रबंधन, विकास और निपटान/मुद्रीकरण का अनुभव है।
- vi. **फॉरवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म:** यह पारदर्शी तरीके से चल और अचल वस्तुओं की नीलामी के लिए जीईएम पर उपलब्ध एक सुविधा है।
- vii. **नीलामी एजेंसी (एए)** एक सीपीएसई जैसे मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एमएसटीसी), जिसे पारदर्शी तरीके से ई-नीलामी के माध्यम से चल और अचल परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए बंद होने के तहत सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/बोर्ड द्वारा नामित किया जा सकता है।
- viii. **बुक वैल्यू:** इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए, यह सीपीएसई की बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों का वहन मूल्य है।
- ix. **अचल संपत्ति:** अचल संपत्ति भूमि का टुकड़ा/भूमि से जुड़ी संपत्ति है, जैसे कि संपत्ति, भवन, परिसर आदि।
- x. **चल संपत्ति:** अचल संपत्ति जैसे संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, वाहन आदि के अलावा कोई परिसंपत्ति।

सार्वजनिक संपर्क हेतु

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

पांचवा तल, कर्तव्य भवन - 1, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष: 011-24012911

Website: <https://dea.gov.in>

व्यय विभाग

छट्टा तल, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष: 011- 24012124

Website: <https://doe.gov.in>

राजस्व विभाग

चौथा तल, कर्तव्य भवन, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष: 011-24012540, 24012541

Website: <https://dor.gov.in>

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ब्लॉक, 11 व 14, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: 011-24360163,

Website: <https://www.dipam.gov.in/dipam/home>

वित्तीय सेवाएं विभाग

जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष: 011-23748721, 23748734

Website: <https://www.financialservices.gov.in>

लोक उद्यम विभाग

ब्लॉक सं. 14, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

दूरभाष: 011-24362673

Website: <https://www.dpe.gov.in>

